



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052021-226826
CG-DL-E-03052021-226826

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2021/वैशाख 13, 1943

No. 139]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2021/VAISAKHA 13, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 3 मई, 2021

मामला सं. सीबीडी 06/2019

विषय: इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फाइबरबोर्ड के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच।

क. मामले की पुष्टभूमि

फा. सं. 6/17/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

- जबकि, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड और रूशिल डेकोर लिमिटेड (जिन्हें संयुक्त रूप से "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका,

थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से "फाइबरबोर्ड" (जिसे आगे "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने के लिए निर्धारित प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याम साक्ष्य के आधार पर तथाकथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी/प्रतिकारी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाती है और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याम होगी, की सिफारिश करने के लिए नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 05 नवंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 6/17/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- क) प्राधिकारी को, उपर्युक्त नियमावली के तहत इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम से फाइबरबोर्ड की सब्सिडी का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।
- ख) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्रवाई से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ग) प्राधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से और सब्सिडी तथा प्रतिकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार आपसी रूप से सहमत समाधान निकालने के लिए परामर्श हेतु इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम की सरकार को आमंत्रित किया। यद्यपि, मलेशिया सरकार (जीओएम), इंडोनेशिया सरकार (जीओआई) और वियतनाम सरकार (जीओवी) के साथ क्रमशः दिनांक 09, 10 और 11 अक्टूबर, 2019 को परामर्श किए गए थे, तथापि थाईलैंड सरकार ने परामर्श का अवसर प्राप्त नहीं किया और श्रीलंका सरकार ने लिखित अनुरोध किए। संबद्ध देशों की उत्तरदाता सरकार के प्रतिनिधियों के लिखित अनुरोध रिकॉर्ड में दिए गए हैं।
- घ) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 05 नवंबर, 2019 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- इ) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को दिनांक 05 नवंबर, 2019 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- च) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध करायी। साथ ही, वैश्विक महामारी और वास्तविक रूप से पहुँच से बाहर होने के मद्देनजर सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे ई-मेल के द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर साझा करें।
- छ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भेजी गई थी।
- ज) प्राधिकारी ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों की सरकारों, जहां सरकारों द्वारा प्रतिकार योग्य लाभ प्रदान किया जा सकता है, को प्रश्नावलियां भेजीं। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया की सरकारों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए जिनको भी ध्यान में रखा गया है।

ज) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

- i. मैसर्स मर्बोक एमडीएफ लंका प्राइवेट लिमिटेड, श्रीलंका
- ii. मैसर्स डोंगवा फाइबरबोर्ड एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- iii. मैसर्स डैकेन सरावक एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- iv. मैसर्स एवरग्रीन फाइबरबोर्ड (जेबी) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- v. मैसर्स एवरग्रीन फाइबरबोर्ड (ईएफबी), मलेशिया
- vi. मैसर्स रॉबिन रिसोर्स (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
- vii. मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी.
- viii. मैसर्स एडवांस फाइबर कं. लिमिटेड, थाईलैंड
- ix. मैसर्स खोकेन एमडीएफ बोर्ड, थाईलैंड
- x. मैसर्स वानाचई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- xi. मैसर्स सियाम फाइबरबोर्ड कं. लिमिटेड, थाईलैंड
- xii. मैसर्स मेट्रो फाइबर कं. लिमिटेड, थाईलैंड
- xiii. मैसर्स वानाचई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- xiv. मैसर्स मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- xv. मैसर्स अंदलनकार्य बेरसमा पीटी, इंडोनेशिया
- xvi. मैसर्स पीटी सुमात्रा प्राइमा फाइबर बोर्ड, इंडोनेशिया
- xvii. मैसर्स पीटी हिजाऊ लेसटारी राया फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया
- xviii. मैसर्स किम टिन एमडीएफ ट्रेडिंग कं, वियतनाम
- xix. मैसर्स एमडीएफ वीआरजी क्लांग ट्राई जेएससी, वियतनाम
- xx. मैसर्स हांग डोंग बम्बू एंड रतन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- xxi. मैसर्स वियतनाम वुडन बोर्ड, वियतनाम
- xxii. मैसर्स किम टिन ग्रुप जेएससी लिमिटेड, वियतनाम

ज) उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किएः

- i. मैसर्स पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री, इंडोनेशिया
- ii. मैसर्स पीटी सुमात्रा प्राइमा फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया
- iii. मैसर्स एडवांस फाइबर कं. लिमिटेड, थाईलैंड
- iv. मैसर्स मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- v. मैसर्स वाइजवुड्स कं. लि., थाईलैंड
- vi. मैसर्स ग्रीन फाइबर कं. लिमिटेड, थाईलैंड
- vii. मैसर्स एग्रो फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- viii. मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

- ix. मैसर्स पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - x. मैसर्स वानाचई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - xi. मैसर्स वानाचई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - xii. मैसर्स एस. किजचाई एंटरप्राइज, थाईलैंड
 - xiii. मैसर्स सेगामट पैनल बोडर्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - xiv. मैसर्स रॉबिन रिसोर्स (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - xv. मैसर्स एमडीएफ वीआरजी क्लांग ट्राई वुड ज्वाइंट स्टॉक कं., वियतनाम
 - xvi. मैसर्स किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
 - xvii. मैसर्स एफएससी वियतनाम कॉर्पोरेशन, वियतनाम
- ठ) जांच की शुरूआत की अधिसूचना के अनुसरण में, संबद्ध देशों से उपर्युक्त उत्पादकों/ निर्यातकों के अलावा, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया की सरकार ने भी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।
- ठ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजीं:
- i. मैसर्स प्लाई प्लाइंट
 - ii. मैसर्स जैक्सन वेनियर्स और पैनल्स प्रा. लि.
 - iii. मैसर्स लेबल सेल्स कारपो.
 - iv. मैसर्स कलिंग इम्पॉर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
 - v. मैसर्स श्रीवारी ट्रेडर्स
 - vi. मैसर्स विकट्री प्लाईवुड
 - vii. मैसर्स थामरापल्ली ब्रदर्स
 - viii. मैसर्स मैथ्यू संस इम्पॉर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
 - ix. मैसर्स आरजे मेटल्स
 - x. मैसर्स फेरोक बोडर्स लिमिटेड
 - xi. कृष्ण प्लाईवुड
- ड) उत्तर में, मैसर्स थमरापल्ली ब्रदर्स वीनर्स एंड पैनल प्रा. लि. ने उत्तर दिया और आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया।
- ढ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों/प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। बाद में, कोविड-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए सार्वजनिक फाइल के पहुँच से बाहर होने के कारण सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह कहा गया था कि वे ई-मेल के द्वारा सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने सभी अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर साझा करें।
- ण) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और लेन-देनों की जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

- त) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है ताकि कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कम प्रतिकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- थ) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संबद्ध सामानों का विभिन्न ग्रेडों/आकारों/रूपों में आयात किया जा रहा है, आवेदकों ने क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन-दर-पीसीएन तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 20 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/17/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित पीसीएन सिद्धांत को अपनाने का प्रस्ताव किया।
- द) वर्तमान सब्सिडीरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 है तथा क्षति की अवधि के रूप में जांच की अवधि और 2015-16, 2016-17, 2017-18 की अवधि के लिए आंकड़ों/सूचना के प्रयोजन के लिए है।
- ध) नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 जुलाई, 2020 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से उनके द्वारा व्यक्त विचारों को प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए, उन सभी पक्षकारों से उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों को अपने लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें और उसके बाद उनके प्रत्युत्तर अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को, जांच में संगत पाए, इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिया गया है।
- न) नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने मामले के उन अनिवार्य तथ्यों को प्रकट किया जो दिनांक 22 जनवरी, 2021 को प्रकटन विवरण के रूप में उनके जांच परिणामों का आधार बनेंगे और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की संगत सीमा तक टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और इन अंतिम जांच परिणामों में उन्हें हल किया गया है।
- प) तदनंतर, दिनांक 07.01.2011 को 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी बदल जाने के मद्देनजर दूसरी मौखिक सुनवाई दिनांक 17 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत किए, उन सभी पक्षकारों से उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों को अपने लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें और उसके बाद उनके प्रत्युत्तर अनुरोध करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को, जांच में संगत पाए, इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिया गया है।
- फ) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में सामानों और सेवाओं के लिए तथाकथित प्रावधानों के समूह में अगली सूचना मांगते हुए उत्तरदाता सरकारों और संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को दिनांक 24 मार्च, 2021 को पत्र जारी किया और उनसे यह कहा गया था कि वे दिनांक 31 मार्च, 2021 तक सूचना उपलब्ध कराएं जो कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तारीख आगे बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध के आधार पर दिनांक 05 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी।
- ब) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- भ) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया है।

- म) टेबल अध्ययन द्वारा आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधन, जहां लागू था, के साथ केवल उस सत्यापित सूचना पर इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।
- य) प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया गया था और इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उस पर विश्वास किया गया है।
- कक. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हैं, प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 26 अप्रैल, 2021 तक का समय देते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों के निमित्त दिनांक 21 अप्रैल, 2021 को हितबद्ध पक्षकारों को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- खख. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.82 रुपए है।
- गग. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और समितीरोधी नियमावली, 1995 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- ग. **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
4. जांच की शुरूआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:
- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रश्नक अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 44.11 के तहत वर्गीकृत "वुड अथवा अन्य लिगनियस सामग्री का फाइबरबोर्ड, रेसिन्स अथवा अन्य आँगौनिक तत्वों से बांडेड हो अथवा न हो" है।
- ग.1 **घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**
5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद "वुड अथवा अन्य लिगनियस सामग्री का फाइबरबोर्ड, रेसिन्स अथवा अन्य आँगौनिक तत्वों से बांडेड हो अथवा न हो" है।
 - ख. फाइबरबोर्ड एक इंजीनियर्ड वुड उत्पाद की किस्म है जो वुड फाइबर से बनाया जाता है। फाइबरबोर्ड की किस्मों में मीडियम डेनसिटी फाइबरबोर्ड (एमडीएफ), हार्डबोर्ड (हाई-डेनसिटी फाइबरबोर्ड, एचडीएफ) शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में लेमिनेटेड फाइबरबोर्ड भी शामिल है। इसका प्रयोग भवन एवं निर्माण, फर्नीचर, औद्योगिक, हस्तशिल्प प्रयोजनों आदि के लिए किया जाता है।
 - ग. निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है:
 - क. फ्लोरिंग बोर्ड्स
 - ख. सनमाइका
 - ग. इंसुलेशन बोर्ड
 - घ. कॉइर बोर्ड
 - ड. जूट फाइबर बोर्ड - घ. सरकार द्वारा निर्धारित माप की यूनिट "भार" है। विचाराधीन उत्पाद को संख्या, टुकड़ों, वर्गमीटर, घन मीटर (सीबीएम), किलोग्राम और मीट्रिक टन के संर्वग में मापा जाता है। भार माप की यूनिट के रूप में मीट्रिक टन के साथ अपनाया गया है।
 - ड. हार्डबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया है, जैसा कि जांच की शुरूआत की अधिसूचना से देखा जा सकता है। घरेलू उद्योग उसे हटाए जाने का सम्भव विरोध करता है। विचाराधीन उत्पाद में प्लाईबोर्ड शामिल नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न की गई उत्पाद किस्मों के संबंध में कोई

ब्यौरे नहीं दिए हैं। हुवाई टेक्नोलॉजी लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेसटेट आदेश पर विश्वास किया जाता है जिसमें यह माना गया था कि घरेलू उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक ग्रेड/किस्म का विनिर्माण करना आवश्यक नहीं है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. हार्डबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उसे अंतिम पीसीएन अधिसूचना अथवा जांच की शुरूआत की अधिसूचना में निर्धारित नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह उल्लेख किया कि हार्डबोर्ड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत है जो कि घरेलू उद्योग की स्थिति के विपरीत है। हार्डबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए पीसीएन से सिद्ध है। हार्डबोर्ड पीसीएन में अभिज्ञात उत्पादों की "समान" वस्तु नहीं है। यहां तक कि घरेलू उद्योग ने भी उसको स्वीकार किया है। इस संबंध में स्पष्टता अपेक्षित है।

ख. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में एमडीएफ, प्लाईवुड और ब्लॉकबोइर्स, जहां तक वे वुड फाइबर से बनाए जाते हैं, शामिल होंगे। ये तीनों सेंचुरी प्लाईबोइर्स द्वारा भी उत्पादित किए जाते हैं। प्लाईबोर्ड को भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि प्लाईबोर्ड फाइबरबोर्ड के उत्पाद के समान है और वह रेसिन्स तथा अन्य ऑर्गेनिक पदार्थों के साथ बांड किए गए वुड फाइबर से बनाया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न की गई फाइबरबोर्ड की इन उप-श्रेणियों को अलग किया जाना चाहिए।

ग. संबद्ध सामानों से संबंधित पूर्व जांच में भारतीय उत्पादकों तथा प्राधिकारी ने माप की यूनिट के रूप में भार को अपनाया है।

घ. यद्यपि निर्धारित यूनिट "भार" है, तथापि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने सामानों को भार की मात्रा में, घन मीटर (सीबीएम) में तथा भार में मंजूर किया है।

ङ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे वर्तमान जांच में माप की यूनिट के रूप में सीबीएम की पुष्टि करें।

च. यहां तक कि घरेलू उद्योग भी यूनिट के रूप में सीबीएम का प्रयोग करके घरेलू बाजार में बिक्री करता है। घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट यूनिट के रूप में सीबीएम दर्शाती हैं। विश्व भर में, सीबीएम को माप की यूनिट के रूप में माना जाता है।

छ. सीबीएम को मीट्रिक टन में बदलने से वास्तविक मात्रा तथा आयात की कीमतें प्रदर्शित नहीं होंगी क्योंकि सीबीएम और मीट्रिक टन में परिवर्तन के लिए सीधा संबंध नहीं है। परिवर्तन के परिणामस्वरूप टेढ़ा और गलत मूल्यांकन हो सकता है।

ज. प्राधिकारी द्वारा विधिवत जांचों में माप की यूनिट के रूप में घन मीटर का प्रयोग किया गया है।

झ. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में कोई यूनिट निर्धारित नहीं की है। प्राधिकारी को पूर्व जांचों की तरह माप की यूनिट के रूप में घन मीटर का प्रयोग करना चाहिए। यद्यपि सीमा प्रशुल्क अधिनियम भार का प्रयोग करता है, तथापि भारतीय सीमा शुल्क ने सीबीएम में भी सामान मंजूर किए। घरेलू उत्पादक घरेलू बाजार में सीबीएम में बिक्री करते हैं। घरेलू उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट उसी यूनिट का प्रयोग करती है। सीबीएम को वैश्विक रूप से स्वीकार किया जाता है और वाणिज्यिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। प्राधिकारी ने उत्पाद विशिष्टियों के आधार पर वर्तमान मामले में पीसीएन निर्धारित किया है न कि भार के आधार पर।

ग.३ प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है।
8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "वुड अथवा अन्य लिगनियस सामग्री का फाइबरबोर्ड, रेसिन्स अथवा अन्य ऑर्गेनिक तत्वों से बांडेड हो अथवा न हो" है। फाइबरबोर्ड एक इंजीनियर्ड वुड उत्पाद की किस्म है जो वुड फाइबर से बनाया जाता है। फाइबरबोर्ड की किस्मों में मीडियम डेनसिटी फाइबरबोर्ड (एमडीएफ), हाई-डेनसिटी फाइबरबोर्ड (एचडीएफ) शामिल हैं।
9. निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है:
 - 1) फ्लोरिंग बोर्ड्स
 - 2) सनमाइका
 - 3) इंसुलेशन बोर्ड
 - 4) कॉइर बोर्ड
 - 5) जूट फाइबर बोर्ड

10. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 44.11 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नलिखित एचएस कोडों के तहत वर्गीकरणीय उत्पाद है:

4411	वुड अथवा अन्य लिगनियस सामग्री का फाइबरबोर्ड, रेसिन्स अथवा अन्य ऑर्गेनिक तत्वों से बांडेड हो अथवा न हो
	- मीडियम डेनसिटी फाइबरबोर्ड (एमडीएफ)
4411 12	-- 5 एमएम से अनधिक मोटाई का
4411 13	-- 5 एमएम से अधिक मोटाई का परन्तु 9 एमएम से अनधिक मोटाई का
4411 14	-- 9 एमएम से अधिक मोटाई का
	- अन्य:
4411 92	-- 0.8 ग्राम/घन मीटर से अधिक घनत्व का
4411 93	-- 0.5 ग्राम/घन मीटर से अधिक परन्तु 0.8 ग्राम/घन मीटर से अनधिक घनत्व का
4411 94	-- 0.5 ग्राम/घन मीटर से अनधिक घनत्व का

11. संबद्ध सामान विभिन्न ग्रेडों/आकारों/रूपों में आयात किये जा रहे हैं, आवेदकों ने क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन-दर-पीसीएन तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत की अधिसूचना द्वारा पक्षकारों से अनुरोध किया कि वे आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में टिप्पणियां दें। पीसीएन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने दिनांक 20 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 6/17/2019-डीजीटीआर द्वारा निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया।

क्रम सं.	मानदंड	व्याख्या
1.	घनत्व	यह घनत्व से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित हैं: एम: मीडियम डेनसिटी फाइबरबोर्ड एच: हाई डेनसिटी फाइबरबोर्ड
2.	मोटाई	यह मोटाई की रेंज से संबंधित है: एक्स: 5 एमएम से अनधिक मोटाई का वाई: 5 एमएम से अधिक परन्तु 9 एमएम से अनधिक मोटाई का जेड: 9 एमएम से अधिक मोटाई का

3.	प्लेन और नॉन-प्लेन	यह चित्र प्लेन अथवा नॉन-प्लेन दर्शाता है: पी: प्लेन एन: नॉन प्लेन (लेमिनेटेड अथवा प्रिटेड अथवा पेटेड)
4.	अनुप्रयोग का प्रकार	यह क्षेत्र दर्शाता है कि इसका प्रयोग भीतरी अथवा बाहरी प्रयोजन के लिए किया जाता है: आई: भीतरी ई: बाहरी

12. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में प्लाईबोर्ड का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने फाइबरबोर्ड पर सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए वर्तमान जांच का आवेदन पत्र दायर किया है। आवेदकों ने प्लाईबोर्ड पर सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध कभी नहीं किया है और उससे संबंधित सूचना रिकॉर्ड में नहीं है। अतः, वह वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर है।
13. माप की यूनिट के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए माप के लिए यूनिट के रूप में सीबीएम पर विचार किया है।
14. समान वस्तु के संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 2(ग) में निम्नलिखित प्रावधान है:
- "समान वस्तु" का अर्थ उस वस्तु से है जो जांचाधीन वस्तु के समान अथवा हर प्रकार से समान हो अथवा उस वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है, परन्तु जांचाधीन वस्तुओं से बारीकी से मिलती-जुलती विशेषताओं वाली हो।"
15. यह नोट किया जाता है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से आयातित संबद्ध सामान भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय से क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है। तदनुसार, आवेदक कंपनियों का भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है और इसीलिए वे सीबीडी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं।

ख) आवेदकों सहित भारत में संबद्ध सामानों के केवल 9 उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने अपनी सूचना के अनुसार सभी 9 उत्पादकों के उत्पादन को लेते हुए कुल भारतीय उत्पादन निर्धारित किया है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के केवल निम्नलिखित उत्पादक हैं:

- i. ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ii. रुशिल डेकोर लिमिटेड
- iii. सेंचुरी प्लाईबोर्ड (इंडिया) लिमिटेड
- iv. एक्शन बिल्डवेल

- v. शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- vi. मंगलम टिम्बर
- vii. पायनियर पैनल प्रोडक्ट
- viii. मेट्रो पैनल्स
- ix. रंगा पार्टिकल बोर्ड

ग) आवेदक कंपनियों ने न तो संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा आयातक और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- क) उत्तरदाताओं द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार आवेदकों का उत्पादन केवल 230 के मीट्रिक टन है और उसका कुल भारतीय उत्पादन में 15-25 प्रतिशत हिस्सा है।
 - ख) एमडीएफ, प्लाईवुड और ब्लॉकबोर्ड के उत्पादकों को कुल भारतीय उत्पादन निर्धारित करने के लिए घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
 - ग) आवेदकों की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारतीय उद्योग बिखरा हुआ है और कई नए उत्पादक हैं। इसके अतिरिक्त, कई उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र में आते हैं, परन्तु आवेदकों ने भारत में कुल 9 उत्पादकों को ही सूचीबद्ध किया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग के क्षेत्र में अन्य उत्पादकों को भी शामिल करें।
 - घ) अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन की पुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। डीजीटीआर द्वारा जारी व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन परिपाठियों की नियम पुस्तक के पैरा 4.9.16 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना चाहिए। कुल उत्पादन वस्तुपरक रूप से निर्धारित करने में जांचकर्ता प्राधिकारी की भूमिका पर चीन-ब्रॉयलर उत्पाद मामले में जोर दिया गया था। कुल उत्पादन का निर्धारण निष्कर्षात्मक होना चाहिए न कि केवल अवधारणा तक। प्रचालनात्मक परिपाठियों की नियम पुस्तक पर विश्वास किया जाता है। विलंब से समर्थन का पत्र रिकॉर्ड में नहीं लिया जाना चाहिए।
 - ङ) थाईलैंड सरकार द्वारा एकत्रित सूचना के अनुसार, तीन घरेलू उत्पादकों का सामूहिक रूप से कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात नहीं है और वे घरेलू उद्योग के योग्य नहीं हैं। आवेदकों का हिस्सा रॉयल थाई सरकार के अनुसार केवल 24.45 प्रतिशत है।
 - च) आवेदकों की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि भारतीय उद्योग बिखरा हुआ है और उसमें कई एमएसएमई हैं। तथापि, आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में संबद्ध सामानों के केवल 9 उत्पादक हैं। आवेदक भारत में अन्य विभिन्न उत्पादकों का अनुपात बताने में विफल रहा है।
 - छ) चीन-ब्रॉयलर उत्पादों में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में कुल घरेलू उत्पादन तथा घरेलू उद्योग का क्षेत्र वस्तुपरक रूप से निर्धारित करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी की भूमिका स्पष्ट की गई। वह निष्कर्षात्मक होना चाहिए न कि केवल अवधारणात्मक। प्रचालन प्रक्रिया की नियम पुस्तक में यह उल्लेख है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को कुल घरेलू उत्पादन का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना चाहिए। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत अन्य घरेलू उत्पादकों को भी शामिल करें। यदि कोई समर्थन पत्र देरी से दायर किया गया है, तो उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया जाना चाहिए।
 - ज) प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल यह नहीं दर्शाती कि समर्थक उत्पादकों ने समर्थक उत्पादक प्रश्नावली दायर की है। इस संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि क्या प्राधिकारी ने वर्तमान आवेदन पत्र में समर्थकों पर विचार किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. यह आवेदन पत्र ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड और रुशिल डेकोर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित अन्य उत्पादक हैं जिन्होंने आवेदन पत्र का समर्थन किया है और अपने उत्पादन के ब्यौरे दिए हैं:
- क) एक्शन बिल्डवेल
 - ख) शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ग) मंगलम टिम्बर
 - घ) पायनियर पैनल प्रोडक्ट
 - ङ) मेट्रो पैनल
 - च) रंगा पार्टिकल बोर्ड
19. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदकों का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदकों का संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
20. अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और सीवीडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करते हैं।
- उ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे**
- उ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**
21. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क) प्रश्नावली के उत्तर के सार्थक अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना निर्यातकों और सरकारों के लिए अनिवार्य करने के प्राधिकारी के विशिष्ट अनुदेशों के बावजूद उन्हें उपलब्ध कराने में विफल होने पर सूचना की अनदेखी की जाएगी। कुछ मामलों में, जहां सूचना दी गई है, वह अत्यधिक गोपनीय है। कोई सार्थक सार भारतीय उद्योग को नहीं दिया गया है।
 - ख) पक्षकारों, मैट्रो और एडवांस द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर गोपनीयता के प्रावधान का उपयोग करने और पूरी तरह से उल्लंघन करने के संदर्भ में बाहर हो जाते हैं। यह देखा जाता है कि मानक प्रश्नावली में पूरे उत्तर गोपनीय होने का दावा किया गया है। घरेलू उद्योग सब्सिडी कार्यक्रम के संबंध में ब्यौरे देने में गोपनीयता की आवश्यकता को समझने में विफल है।
 - ग) उत्तरदाता निर्यातकों ने उस सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। निर्यातकों ने गोपनीय होने का दावा की गई सूचना का सार्थक अगोपनीय सार नहीं दिया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को रद्द करें और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण को आधार बनाएं।
 - घ) बाजार हिस्सा और उत्पादन व्यापार सूचना के अनुसार अगोपनीय रूपांतर में दिया गया है। याचिकाकर्ता अन्य उत्पादकों के उत्पादन को प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह तीसरे पक्षकार की सूचना है और घरेलू उद्योग उसे प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है।
 - ङ) डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को साझा करने के मुद्दे के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किए गए एक्सोटिक डेकोर प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य में निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हल्दौर टोपसो ए/एस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माने गए अनुसार संविधि में दिए गए प्राकृतिक न्याय के केवल वे सिद्धांत लागू हैं। न तो भारतीय नियमावली और न ही डब्ल्यूटीओ कानून किसी निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने वाले आंकड़ों, जहां तक वे हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध हैं, की अपेक्षा है।

- च) व्यापार सूचना 10/2018 के अनुपालन के मुद्रे के संबंध में, घरेलू उद्योग 2016-17 तक दो उत्पादकों को शामिल करता है। अब सभी आंकड़े देने से तीसरे पक्षकार के निष्पादन मानदंडों को समझने में मदद मिलेगी जो व्यापार संवेदी हैं।
- छ) बाजार हिस्सा और उत्पादन व्यापार सूचना के अनुसार अगोपनीय रूपांतर में दिया गया है। याचिकाकर्ता अन्य उत्पादकों के उत्पादन को प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह तीसरे पक्षकार की सूचना है और घरेलू उद्योग उसे प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है।
- ज) डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को साझा करने के मुद्रे के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किए गए एक्सोटिक डेकोर प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य में निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम हल्दौर टोपसो ए/एस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माने गए अनुसार संविधि में दिए गए प्राकृतिक न्याय के केवल वे सिद्धांत लागू हैं। न तो भारतीय नियमावली और न ही डब्ल्यूटीओ कानून किसी निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने वाले आंकड़ों, जहां तक वे हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध हैं, की अपेक्षा है।
- झ) व्यापार सूचना 10/2018 के अनुपालन के मुद्रे के संबंध में, घरेलू उद्योग 2016-17 तक दो उत्पादकों को शामिल करता है। अब सभी आंकड़े देने से तीसरे पक्षकार के निष्पादन मानदंडों को समझने में मदद मिलेगी जो व्यापार संवेदी हैं।
- ज) एस. किजन्चाई और थमारापल्ली द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर गोपनीयता के कानूनों के पूरे उल्लंघनों के कारण रद्द किए जाने चाहिए।
- ट) जारी किया गया प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने कई कार्यक्रमों का लाभ लिया है, परन्तु निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में अपने को छिपाया है। सूचना को छिपाने से उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों का प्रयोग करना होता है और दी गई सूचना की पर्याप्तता तथा परिशुद्धता के संबंध में प्रश्न उठाता है।
- ठ) माप की यूनिट निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्क पर बदली गई थी।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

22. गोपनीयता के मुद्रों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क) पाटनरोधी शुल्क के लिए गोपनीयता के संबंध में जारी व्यापार सूचना/दिशानिर्देश/ निर्णय सम्बिंदी जांचों में भी मूलतः लागू हैं और घरेलू उद्योग को पूर्णतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाए।
- ख) आवेदकों ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) में सूचना नहीं दी है।
- ग) याचिका का अगोपनीय रूपांतर आरोपों की उपर्युक्त समझ की अनुमति नहीं देता और निर्यातकों की खुद के हितों की रक्षा करने की क्षमता में बाधा डालता है।
- घ) व्यापार सूचना प्राधिकारी पर बाध्यकारी है, अतः आवेदकों को व्यापार सूचना के विपरीत कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- ङ) अत्यधिक गोपनीयता का दावा सीवीडी नियमावली के नियम 8, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सेसटेट के बाध्यकारी पूर्वोदाहरणों तथा अन्य न्यायिक मंचों के विपरीत है।
- च) याचिकाकर्ताओं ने याचिका के अनुबंध-2.2 में अपने उत्पादन अथवा बाजार हिस्से के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन और बाजार में हिस्सा नहीं दिया गया है।
- छ) पाटनरोधी शुल्क के लिए गोपनीयता के संबंध में जारी व्यापार सूचना/दिशानिर्देश/ निर्णय सम्बिंदी जांचों में भी मूलतः लागू हैं और घरेलू उद्योग को पूर्णतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाए। संदर्भः स्टरलाईट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, गोपनीयता स्वतः नहीं दी जानी चाहिए और पूरी जांच पर आधारित होनी चाहिए।

- ज) मांग, उत्पादन मात्रा, बिक्री मात्रा आदि जैसी सूचना गोपनीय होने का दावा किया गया है जिसके बिना अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए क्षति मानदंडों की जांच करना कठिन है।
- झ) वर्तमान मामले में, प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता उस सूचना के पूरे मूल्यांकन के बिना स्वतः प्रदान की गई है जिससे गोपनीयता के दावे का संबंध है। संदर्भ: एचाएंडआर जॉनसन (इंडिया) लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, निर्दिष्ट प्राधिकारी को विभिन्न कारकों के आधार पर सूचना की गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। डीएस 397 यूरोपीय समुदाय – सरटेन लौह एवं इस्पात फास्टनर्स, एडीए के अनुच्छेद 6.5 के तहत, गोपनीयता का दावा करने के लिए अच्छा कारण दर्शाना पक्षकार का काम है और प्राधिकारी के लिए तथाकथित अच्छे कारण का वस्तुपरक रूप से मूल्यांकन करना और उसके बाद दावों की जांच करना आवश्यक होता है।
- ज) व्यापार सूचना 10/2018 में उल्लिखित सिद्धांत आवश्यक संशोधनों सहित सब्सिडीरोधी जांचों पर भी लागू होते हैं। आवेदन पत्र व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है, जैसा कि तीन अथवा अधिक उत्पादकों पर लागू होता है। नियम पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी, दोनों के लिए समान है।
- ट) घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आंकड़ों का प्रयोग किया, परन्तु वे तथा अलग किए गए आंकड़े निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में नहीं रखे गए हैं। एक्सोटिक डेकोर प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य में यह माना गया था कि दिए गए आंकड़े प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए अनुसार उसी रूप और तरीके में दिए जाने होते हैं। एक्सल फॉर्मेट में आंकड़े दिए जाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि वे पहले ही रिकॉर्ड में हैं।
- ठ) याचिकाकर्ताओं ने जिन लेन-देन-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है, वे नहीं दिए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सभी लेन-देन विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पृथक्करण सिद्धांत देने में विफल रहे हैं।
- ड) इंडोनेशियाई उत्पादकों ने पूरी जांच में प्राधिकारी को सहयोग दिया है और सभी अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत की हैं।
- ढ) याचिकाकर्ताओं ने संशोधित आंकड़े दिए बिना अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच के अंत में आंकड़े मीट्रिक टन से सीबीएम में संशोधित किए हैं। याचिकाकर्ता ने कभी भी मात्रा तथा अन्य क्षति संबंधी सूचना घन मीटर में नहीं दी है।
- ण) राँयल थाई सरकार (आरटीजी) द्वारा गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दावे आधारहीन हैं। राँयल थाई सरकार ने जांच में पूरी तरह सहयोग किया है। मैट्रो ग्रुप ने सभी अपेक्षित ब्यौरे और गोपनीयता के कारण दिए हैं।
- त) किम टिन की आरोपित संबद्ध कंपनियां केवल प्रयोक्ता हैं और वे संबद्ध सामानों के उत्पादन अथवा बिक्री में नहीं लगी हैं।

उ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

24. प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
25. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उन्हें हल किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्यासता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्यास अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।
26. निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर मै. एस किंजचाई द्वारा प्रस्तुत किए जाने के संबंध में यह देखा गया है कि यह प्राधिकारी को प्रस्तुत अगोपनीय रूपांतर के रूप में गोपनीय अनुरोधों का एक सार्थक सारांश उपलब्ध नहीं करा पाया है। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीमित सारांश में, इसने अधिकांश विस्तृत सूचना के लिए गोपनीय रूपांतर का संदर्भ लेने के लिए कहा है। उसी प्रकार से, मै. थमारापल्ली ब्रादर्स वेनर्स एंड पैनल्स प्रा. लि. ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है लेकिन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय रूपांतर परिचालित नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रकार का सीमित अनुरोध और गैर-परिचालन से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपर्युक्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए निर्यातक और आयातक प्रश्नावली के उत्तरों के संबंध में सार्थक टिप्पणियां करने के लिए अवसर बाधित हुआ है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि सब्सिडीरोधी नियमावली 1995 के नियम 8 के उप नियम 2 के उल्लंघन को देखते हुए उपर्युक्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाए।
27. जहां तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को प्रकट करने का संबंध है, प्राधिकारी के 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 7/2018 में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए तथा घरेलू उद्योग के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े एकत्रित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार सूचना के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े लेने की पहुँच थी और वे अपने हितों की रक्षा कर सकते थे। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागू की जा रही प्रक्रिया सतत, सभी जांचों के लिए एक समान है तथा हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा के लिए पर्यास अवसर प्रदान करती है।

विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

क) वर्तमान मामले में निम्नलिखित कारणों से अंतरिम शुल्क लगाए जाने चाहिए:

- i. चूंकि उत्तरदाता सरकारों और उत्पादकों से आगे की सूचना मांगने और विस्तृत जांच करने में समय लगेगा, अतः अनुरोध है कि अंतरिम शुल्क लगाया जाए।
- ii. घरेलू उद्योग का औसत क्षमता उपयोग 2016-17 में 109 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में 60 प्रतिशत हो गया। इसमें कोविड की स्थिति के कारण और गिरावट आई है।

- iii. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई।
 - iv. मांग में उस मात्रा से 20 प्रतिशत तक गिरावट आई है जो जांच की अवधि में थी। कोविड की स्थिति से पूरी तरह से बाहर आने के बाद भी यह लगभग 40-60 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह इसलिए है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद अनिवार्य सामान नहीं है और क्रय शक्ति में गिरावट है।
 - v. प्रमुख निर्यातक देशों में संस्थापित क्षमता घरेलू मांग से काफी अधिक है।
 - vi. वे 30 प्रतिशत से अधिक काफी प्रतिकारी सब्सिडियों से भी लाभ लेते हैं और इस प्रकार कीमतें कम करने में सक्षम हैं। क्षमता उपयोग में गिरावट से घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में समग्र वृद्धि होने की उम्मीद है और लागत वसूल करने में भी उपयुक्त कीमत पर बिक्री करने की आवश्यकता होगी।
 - vii. आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग से सस्ते थे। यद्यपि घरेलू उद्योग को बढ़ती हुई लागतों को वसूल करने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ीं, तथापि घरेलू उद्योग आयातों से कीमत दबाव का सामना करता है।
 - viii. यदि छः माह के लिए संरक्षण नहीं दिया जाता तो उद्योग 1000 करोड़ रुपये के बकाया क्रहण और 750 करोड़ रुपये के संचयी मजदूरी बिल के कारण बीमार पड़ जाएगा।
 - ix. कम क्षमता उपयोग से कम आरएम प्रयोग होगा और इस प्रकार किसानों की आजीविका प्रभावित होगी।
- घ) श्रीलंकाई निर्यातकों को प्रश्नावली का उत्तर दायर करने में उनकी विफलता के कारण असहयोगी माना जाना चाहिए।
- ग) एएससीएम में आवेदक के लिए केवल आवेदन पत्र दायर करने के समय उपयुक्त रूप से उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है। चीन-यूएस से फ्लैट रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील (डीएस 414) में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट पर विश्वास किया जाता है। आवेदक ने सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तथा उनकी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी। संबद्ध देशों की सरकारों के साथ जांच की शुरूआत से पूर्व परामर्श भी किए गए थे।
- घ) एफएससी के इस दावे के संबंध में कि वे भारत को निर्यात नहीं करते और इसीलिए यह जांच उन पर लागू नहीं है, प्रश्नावली के अनुदेशों में उल्लेख है कि कंपनी को उस सीमा तक उत्तर देना है, जहां तक वे उनसे संबद्ध हैं।
- ङ) एक-दूसरे से संबद्ध अलग-अलग कंपनियों को एकल सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए। निम्नलिखित को एक समूह के रूप में माना जाना चाहिए: (क) वानाचाई ग्रुप और वानाचाई पैनल (थाईलैंड), (ख) पैनल प्लस कंपनी और पैनल प्लस एमडीएफ (थाईलैंड), (ग) किम टिन और एफएससी (वियतनाम), और (घ) ग्रीन फाइबर और एग्रो फाइबर (थाईलैंड)। यहां तक कि यदि एफएससी के लिए कोई मार्जिन की मात्रा नहीं निर्धारित की जाती है, तो किम टिन के मार्जिन को उसमें संचित किया जाना चाहिए।
- च) केवल एक आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया और उत्तर दायर करने के बाद जांच के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया। प्रयोक्ताओं से प्रतिभागिता और प्रश्नावली के उत्तर का अभाव यह दर्शाता है कि वे वर्तमान जांच से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हैं।
- छ) प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना घरेलू विनिर्माताओं के हित में है क्योंकि इससे उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुकेगी और हुई क्षति का समाधान होगा। यह उपभोक्ताओं के हित में भी होगा क्योंकि यह उपभोक्ताओं और कुल मिलाकर जनता के हित में है कि प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग विद्यमान है। घरेलू उद्योग को संरक्षित न करने से निवेश सीधे ही पंगु हो जाएगा और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अंतिम उत्पादों पर परिणामी प्रभाव काफी नहीं होगा। बढ़ते व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा रिजर्व के घटने के कारण घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर ज्यादा विश्वास करना महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से 20,000 से 25,000 का रोजगार सुरक्षित करता है और कृषकों की आय बढ़ाने की उसमें काफी क्षमता है।

- ज) घरेलू उद्योग को क्षति कम कीमत के आयातों के कारण है। घरेलू उद्योग उस सीमा के संबंध में स्पष्ट नहीं है जिस सीमा तक पाटन के कारण और समग्र क्षति मार्जिन के भीतर सब्सिडी के कारण कीमतें कम हैं। घरेलू उद्योग ने क्षति मार्जिन से अधिक राहत की मांग नहीं की है। पाटन अथवा सब्सिडी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक मात्र कारण होने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ पाटनरोधी और सीवीडी जांच पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सनसिटी शीट्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ में सेसटेट आदेश, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना, पर विश्वास किया जाता है।
- झ) वर्तमान जांच एक नई जांच होने के नाते केवल जांच की अवधि तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। प्राथिकारी जांच की अवधि के बाद जांच नहीं करते। इतनी देरी से जांच की अवधि के बाद के संबंध में तर्क उठाना हितबद्ध पक्षकारों का गलत इरादा दर्शाता है। मोटे एमडीएफ और पतले एमडीएफ के संबंध में पाटनरोधी जांचों में रिकॉर्ड में जांच की अवधि के बाद की सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के बाद भी क्षति हो रही है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदन पत्र में यह दर्शाते हुए किसी साक्ष्य का अभाव है कि तथाकथित सब्सिडी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा ली जा रही थी।
- ख. नीति संबंधी दस्तावेज उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा ली जा रही सब्सिडी की मौजूदगी की औचित्य बनाने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में निर्मित नहीं की जा सकती।
- ग. इस साक्ष्य के बिना सीवीडी जांच की शुरूआत एएससीएम के अनुच्छेद 11 और सीवीडी नियमावली के नियम 6 के विरुद्ध है।
- घ. कार्यक्रम की मौजूदगी प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी के रूप में तब तक नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसे प्रतिकार योग्य सिद्ध न किया जाए।
- ङ. याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि सब्सिडी मार्जिन काफी है और परिकलन का आधार स्पष्ट किए बिना प्रत्येक देश के लिए उनकी मात्रा बताता है। याचिकाकर्ता ने पृष्ठ 52 पर याचिका में स्वीकार भी किया है कि सब्सिडी मार्जिन की मात्रा स्पष्ट नहीं है।
- च. जांच की शुरूआत में व्यापार नीति संबंधी रिपोर्ट विशेष रूप से लांग निर्यात प्रतिबंध और निवेश तथा इंडोनेशियाई फाइबरबोर्ड उद्योग संबंधी कराधान विनियम के संबंध में गलत प्रदर्शित की गई है और उसकी गलत व्याख्या की गई है। जांच की शुरूआत एएससीएम के अनुच्छेद 11.1, 11.2 और 11.3 के तहत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती।
- छ. अन्य न्यायिक निर्णयों में विगत सब्सिडीरोधी जांचों से साक्ष्य इस जांच में विशेष रूप से उस समय स्वतः लागू नहीं हो सकते जब इस जांच में भिन्न उत्पाद हो।
- ज. आवेदक ने जांच की शुरूआत के लिए क्षति और कारणात्मक संपर्क का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था।
- झ. इंडोनेशियाई निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के नियम 10 के उल्लंघन के कारण अंतरिम शुल्कों के लिए अनुरोध आधारहीन और औचित्य के बिना हैं। कम क्षमता उपयोग के तहत दावा आधारहीन और भ्रामक है। बड़े हुए आयातों से संबंधित दावा भ्रामक और गलत है क्योंकि श्रीलंका को न्यूनतम से कम आयातों के बावजूद संचयी मूल्यांकन में गलत शामिल किया गया था और क्योंकि इंडोनेशियाई आयातों में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई। मांग में संभावित गिरावट के तहत दावा बिना किसी साक्ष्य के है और संभावित विश्लेषण संगत नहीं है। 30 प्रतिशत से अधिक पर्याप्त प्रतिकारी शुल्क का दावा बिना किसी तथ्य और साक्ष्य के समर्थन के है। कृषकों की निर्भरता के आधार पर दावा अनुपयुक्त है क्योंकि सब्सिडीरोधी नियमावली में कोई सार्वजनिक हित का खंड नहीं है।

- ज. अंतरिम शुल्कों के दावे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह भारी क्षमता अभिवृद्धि के कारण अस्थायी प्रतिकूलताओं के आधार पर है। उत्पादन में कोई कमी नहीं है। क्षमता उपयोग में कमी क्षमता अभिवृद्धि के कारण है और आयातों में प्रवृत्तियों का घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति से कोई सह-संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग आरोपित सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण कोई गंभीर क्षति दर्शने में विफल रहा है।
- ट. आवेदक अनंतिम शुल्कों की सिफारिश की जरूरत के लिए कोई अतिरिक्त तथा संगत तथ्य देने में विफल रहे हैं। आवेदक यह दर्शने में विफल रहे हैं कि वर्तमान मामला उसके लिए "उपयुक्त" है।
- ठ. वर्तमान जांच में आवेदक द्वारा किए गए सब्सिडी के दावे मात्र अवधारणाएं हैं जिन्हें दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सिद्ध नहीं किया गया है। यह एएससीएम के तहत जांच की शुरूआत के लिए अपेक्षा को पूरा नहीं करता। यूएस-लार्ज सिविल एयरक्राफ्ट (दूसरी शिकायत) में डब्ल्यूटीओ एबी रिपोर्ट पर विश्वास किया जाता है।
- ड. सब्सिडी मार्जिन मात्र अलग सब्सिडी मार्जिन जोड़कर संचित नहीं किए जाने चाहिए। वह भारित औसत पद्धति के आधार पर होना चाहिए।
- ढ. चूंकि एफएससी ने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। अतः मार्जिन संचित नहीं किए जाने चाहिए।
- ण. शुल्क लगाने से निचले स्तर के उद्योग के लिए उत्पादन लागत प्रभावित होगी और कोविड-19 महामारी के समय के दौरान उनके लाभ तथा निष्पादन को प्रभावित करेगा। वे वैश्विक उत्पादकों में निचले स्तर के भारतीय उत्पाद को गैर-प्रतिस्पर्धी भी बनाएंगे जिससे उनके आयातों की वृद्धि होगी।
- त. एनआईपी के परिकलन के लिए अनुबंध-III को लागू न करने का कोई कारण नहीं है।
- थ. कोई भी सीवीडी लगाना देश के हित के लिए घातक होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए अनुपयुक्त लाभ होंगे और भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
- द. समानांतर निर्णायक समीक्षा जांच में आवेदकों ने दावा किया कि क्षति चीन, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका से पाटित आयातों के कारण है। घरेलू उद्योग के अनुसार क्षति अकेले संबद्ध देशों से तथाकथित सब्सिडी के कारण नहीं है।
- ध. सीवीडी के बिना भी जांच के बाद की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से वृद्धि पर कारणात्मक संपर्क की जांच करते समय विचार किया जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पर दबाव रियल एस्टेट में मंदी के कारण था और वे कम होने शुरू हो गए हैं। जब स्थिति सुधर गई हो तो सीवीडी लगाना अनुचित और सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। प्राधिकारी पर जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच करने से कोई प्रतिबंध नहीं है। सेंचुरी एमडीएफ डिवीजन और ग्रीनप्लाई के तिमाही परिणामों पर विश्वास किया जाता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. जहां तक याचिका की पर्याप्तता तथा परिशुद्धता का संबंध है, प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत के स्तर पर उसका विश्वेषण किया है और प्राधिकारी ने पाया कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं तथा उन सब्सिडीयुक्त आयातों से उनकी मात्रा और कीमत प्रभावों के माध्यम से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।
31. जहां तक अंतरिम शुल्कों का संबंध है, वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों के महेनजर उनकी सिफारिश नहीं की गई है।
32. जहां तक समांतर पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी जांचें करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी समांतर जांचें करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
33. जहां तक जांच की अवधि के बाद के लिए सूचना पर विचार करने के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक नई जांच होने के नाते जांच की अवधि के बाद की सूचना पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

34. जहां तक संबद्ध कंपनियों के मार्जिन के संचयन से संबंधित तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि विभाग की यह सुस्थापित परिपाठी है कि अलग संबद्ध कंपनियों के मार्जिन समूह कंपनियों के लिए संचित किए जाते हैं।

सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

35. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में जांच की शुरूआत के लिए संबद्ध देशों में प्रतिकारी सब्सिडी की मौजूदगी के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य दिए गए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम सरकार के साथ क्रमशः 10 अक्टूबर, 2019, 09 अक्टूबर, 2019 और 11 अक्टूबर, 2019 को परामर्श किए गए थे। थाईलैंड सरकार ने परामर्श का अवसर नहीं लिया। श्रीलंका सरकार ने सिफ्ट लिखित अनुरोधों के रूप में जांच की शुरूआत से पूर्व परामर्शों का अवसर लिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम के उत्पादकों और निर्यातकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रश्नावली के उत्तर दायर करें तथा उस सब्सिडी, यदि कोई है, की मौजूदगी और मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए तथाकथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापनीय साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
36. सरकार के प्रश्नावली के उत्तर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और श्रीलंका सरकारों द्वारा दायर किए गए हैं।
37. इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- i. मैसर्स पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्रीज, इंडोनेशिया
 - ii. मैसर्स पीटी सुमात्रा प्राइमा फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया
 - iii. मैसर्स सीगमट पैनल बोइर्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - iv. मैसर्स रॉबिन रिसोर्स (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - v. मैसर्स एडटवांस फाइबर कं. लिमिटेड, थाईलैंड
 - vi. मैसर्स मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - vii. मैसर्स वाइजवुड्स कं. लि., थाईलैंड
 - viii. मैसर्स ग्रीन फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - ix. मैसर्स एग्रो फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - x. मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - xi. मैसर्स पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - xii. मैसर्स वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - xiii. मैसर्स वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - xiv. मैसर्स एस. किजचाई एंटरप्राइज, थाईलैंड
 - xv. मैसर्स एमडीएफ वीआरजी क्रांग ट्राई वुड ज्वाइंट स्टॉक कं., वियतनाम
 - xvi. मैसर्स किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
 - xvii. मैसर्स एफएससी वियतनाम कॉर्पोरेशन, वियतनाम
38. श्रीलंका से संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
- छ. तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रम का सामान्य अवलोकन
- छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
39. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:
- i. तथाकथित सब्सिडी कार्यक्रमों की प्रतिकारिता के लिए साक्ष्य विस्तृत एक पेजर में दिए गए हैं। एएससीएम और भारतीय सीवीडी नियमावली के अनुसार सभी मानदंड पूरे किए गए हैं।

- ii. विभिन्न जांचकर्ता प्राधिकारियों ने पाया है कि इंडोनेशिया में टिम्बर उद्योग का वानिकी क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में है और लकड़ी के उत्पादों की कीमतें इस सरकारी हस्तक्षेप के कारण अनुचित रूप से कम हैं। चूंकि पेपर उद्योग तथा फाइबरबोर्ड उद्योग, दोनों में प्रयुक्त कच्ची सामग्री समान है अर्थात् "टिम्बर" है, अतः पेपर उद्योग संबंधी मामले वर्तमान जांच में संगत हैं।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा एकत्रित साक्ष्य के अनुसार रबर वुड की कीमतें जांच की अवधि के दौरान 54.02 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन से कम नहीं हो सकतीं।
- iv. इंडोनेशिया से तथाकथित सब्सिडी के लिए "उपलब्ध तथ्यों" के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया जाना होता है। कार्यक्रम संख्या 1 और कार्यक्रम संख्या 2 के लिए इंडोनेशिया सरकार (जीओआई) ने अनिवार्य इनपुट अर्थात् बुड़ा/लॉग्स की कीमत सब्सिडीयुक्त की है। इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 1 और 2 के तहत "टिम्बर" शब्द लकड़ी की किसी विशिष्ट किस्म तक सीमित नहीं है। रबर वुड उसी के क्षेत्र में आता है।
- v. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अनुसार रबर वुड अपशिष्ट अथवा फाइबर अथवा पेपर का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। वे अपने अनुरोधों में संशोधन कर रहे हैं और भ्रामक एवं झूठे विवरण दे रहे हैं।
- vi. यद्यपि कच्ची सामग्री की खरीद निजी वृक्षारोपणों से की जा सकती है, तथापि सरकारी ह्वास का स्तर इंडोनेशिया में टिम्बर बाजार को ह्वास की स्थिति में छोड़ता है। सरकार द्वारा की गई प्रभावी भूमिका कृत्रिम रूप से बाजार कीमतों को कम करती हैं। "इंडोनेशिया से कोटेट फ्री शीट पेपर" और "इंडोनेशिया से कतिपय इनकोटेट पेपर" में यूएस डीओसी का विश्लेषण।
- vii. कार्यक्रम संख्या 3 सभी निर्यातकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना को कॉपर सीवीडी मामले में प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारयोग्य माना गया था। प्रकटन विवरण का पैरा 61 यह दर्शाता है कि पीटी बैंक नेगारा एक सार्वजनिक निकाय है। अन्य हितबद्ध पक्षकार झूठे और भ्रामक विवरण दे रहे हैं। इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 3 के लिए निर्यातक को उपयुक्त निर्धारण का सुझाव देने का अवसर था। तथ्यों को छिपाने की स्थिति पर विचार करते हुए, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्य लागू करने के हकदार हैं। अधिमान्य उधार मुद्रा पर ध्यान दिए बिना व्यवहार में लाया जाता है। ये व्याज दरें आईएमएफ, विश्व बैंक और देशों के सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित दरों से कम हैं।
- viii. प्राधिकारी ने कॉपर वायर रॉड्स, टेम्पर्स ग्लास, फ्लोट ग्लास और स्टेनलेस स्टील में पूर्व सीवीडी जांचों में एकिजम बैंक द्वारा दी गई निर्यात सुविधा को प्रतिकार योग्य पाया। कार्यक्रम का लाभ न लेने से वह गैर-प्रतिकारयोग्य नहीं हो जाता।
- ix. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वीकार किया है कि वे कार्यक्रम संख्या 5 के तहत लाभ ले रहे हैं। यह कार्यक्रम कॉपर सीवीडी मामले में प्रतिकारयोग्य माना गया था। कार्यक्रम संख्या 6 भी कॉपर सीवीडी मामले में पूर्व में प्रतिकारयोग्य माना गया था। इंडोनेशिया सरकार इस कार्यक्रम के लिए संगत कानून उपलब्ध कराने में विफल रही है।
- x. कार्यक्रम संख्या 7 एएससीएम की पाट टिप्पणी 1 के अनुसार अनुमति योग्य नहीं है और इसीलिए प्रतिबंधित है। वह कॉपर सीवीडी मामले में प्रतिकारयोग्य पाया गया था।
- xi. इंडोनेशिया सरकार तथा उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक यह स्वीकार करने में और एलटीएआर पर भूमि तथा विद्युत के प्रावधान के संबंध में संगत सूचना देने में विफल रहे हैं। आवेदकों ने उसके लिए संगत सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- xii. इंडोनेशिया के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने कार्यक्रम संख्या 1 के लिए मानक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। निजी पौधारोपणों का प्रयोग करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इंडोनेशिया सरकार की रबर सब्सिडी और एईटीएस भी कच्ची सामग्री अर्थात् लकड़ी को सस्ता करते हैं।

- xiii. किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने कार्यक्रम संख्या 2, 3, 4, 6, 8 और 9 के लिए मानक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। इन कार्यक्रमों को न लेना दर्शने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है।
- xiv. इंडोनेशिया सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे के अनुसार, कार्यक्रम संख्या 10 के लिए सुमात्रा ने मानक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। अतिरिक्त रूप से, मुक्ति इस कार्यक्रम के तहत लाभ लेने से इंकार करती है, जबकि इंडोनेशिया सरकार यह उल्लेख करती है कि उन्होंने लाभ लिया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे मुक्ति पैनल द्वारा किए गए दावे का सत्यापन करें कि इंडोनेशिया सरकार ने इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 10 को न लेना स्पष्ट किया है। उपर्युक्त पत्र घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- xv. इंडोनेशिया के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने लांग निर्यात प्रतिबंध से घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ने से इंकार किया है। यह सच नहीं हो सकता।
- xvi. इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यात प्रतिबंध की मौजूदगी से इंकार नहीं किया है। आवेदक यह दावा नहीं करते कि प्रतिबंध अपने आप में प्रतिकार योग्य समिक्षा हैं, परन्तु यह कि इसने घरेलू कीमतों का ह्लास किया है। इस प्रकार, एलटीएआर पर लांग प्रदान कर रहे हैं।
- xvii. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने कार्यक्रम संख्या 1 के संबंध में गलत सूचना दी है क्योंकि 88 प्रतिशत भूमि सरकार के स्वामित्व में है और आपूर्ति की गई लकड़ी समिक्षायुक्त है। अतः यह लगभग असंभव है कि कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया गया था। यूएस प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित जांचों में यह योजना प्रतिकार योग्य पाई गई थी: इंडोनेशिया से सरटेन लाइन्ड पेपर प्रोडक्ट्स और इंडोनेशिया से सरटेन अनकोटेड पेपर। पेपर उद्योग से संबंधित मामला वर्तमान मामले में संगत है क्योंकि कच्ची सामग्री समान है। इंडोनेशिया सरकार ने इंडोनेशिया से सरटेन अनकोटेड पेपर में स्वीकार किया कि खड़ा टिम्बर फर्नीचर उद्योग को दिया जाता है।
- xviii. इंडोनेशिया संविधान के अनुच्छेद 33(3) के अनुसार भूमि पर सरकार का नियंत्रण है जो कंपनियों को एलटीएआर पर दी जाती है।
- xix. इंडोनेशिया में बिजली पर वित्त मंत्रालय के 2017 के विनियम संख्या 44 द्वारा भारी समिक्षा दी जाती है जिससे उपभोक्ता एलटीएआर पर पीएलएन से बिजली खरीद सकते हैं। इंडोनेशिया सरकार के पास कोयले के निर्यात, निर्यात कर के अधिकार हैं और वह घरेलू बाजार दायित्वों का रख-रखाव करती है। कोयले के लिए निर्धारण कीमत भी पीएलएन के लिए लागू की जाती है। इंडोनेशिया से "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पाद" के आयातों के संबंध में सीबीडी जांच में अंतिम जांच परिणाम पर विश्वास किया जाता है।
- xx. घरेलू उद्योग ने निर्धारण के रूप में ट्रेड मैप के अनुसार 2018-19 में शेष विश्व के लिए बिटुमिनस कोयले की निर्यात कीमत का प्रयोग करके समिक्षा मार्जिन परिकलित किया।
- xxi. संयंत्र/विनिर्माण यूनिट के लिए भूमि पर समिक्षा इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 11 के तहत निर्धारित की जानी होती है। प्राधिकारी ने इसके लिए सर्वाधिक रूढिवादी निर्धारण पर विचार किया है।
- xxii. न्यूनतम नियम कार्यक्रम-वार आधार पर लागू न करके निर्यातक-वार आधार पर लागू किया गया है।
- xxiii. मलेशिया सरकार (जीओएम) मलेशिया एक्सटर्नल ट्रेड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (एमएटीआरएडीई), एक्सपॉर्ट-इम्पॉर्ट बैंक ऑफ मलेशिया बरहाड (एक्जिम बैंक) तथा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक रीजन डेवलेपमेंट काउंसिल को प्रशासक प्राधिकारियों के रूप में तथा इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों की पहचान के लिए स्रोत के रूप में सूची देने में विफल रही है। प्रश्नावली की अपेक्षा के अनुसार कई संगत सूचनाएं एवं अनुबंध मलेशिया सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं।
- xxiv. न तो मलेशिया सरकार और न ही उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वीकार किया है अथवा एलटीएआर के लिए खड़े टिम्बर हेतु प्रावधान, लांग निर्यातों पर सरकार प्रतिबंध और एलटीएआर पर भूमि एवं विद्युत के लिए प्रावधान के संबंध में कोई संगत सूचना दी है। आवेदकों ने उसके लिए संगत सूचना और साक्ष्य दिए हैं।

- xxv. मलेशिया के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने कार्यक्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/13, और 11 न लेने का कोई कारण नहीं दिया है।
- xxvi. इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम संख्या 5 के लिए सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी. (एसपीबी) ने कार्यक्रम न लेने का कोई कारण नहीं दिया है, जबकि रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने गलत कार्यक्रम का उत्तर दिया है।
- xxvii. मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 6 और 7 पहले ही कॉपर सीवीडी मामले में प्राधिकारी द्वारा प्रतिकारयोग्य माने गए हैं।
- xxviii. मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 9 उच्च पूंजी व्यय वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। कार्यक्रम संख्या 9 के लिए एसपीबी ने एनसीबी में मानक प्रश्नों के अनुबंध नहीं दिए हैं। उन्होंने औसत उपयोगी जीवनकाल अनुबंध और आवंटन अनुबंध का भी उत्तर नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, एसपीबी ने पात्र खर्चे करने के बावजूद कार्यक्रम संख्या 14 को न लेने के कारण नहीं दिए हैं।
- xxix. यद्यपि रॉबिन ने कार्यक्रम संख्या 16 को न लेने के कारण नहीं दिए हैं, तथापि रॉबिन ने मानक प्रश्नों के अनुबंध का उत्तर नहीं दिया है।
- xxx. एसपीबी कार्यक्रम संख्या 19 – निवेश कर भत्ता की मौजूदगी स्वीकार करने में भी विफल रहा है जिसके मलेशिया सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था।
- xxxi. मलेशिया के उत्तरदाता उत्पादकों की वेबसाइट सूचना के अनुसार, रबर वुड और ट्रॉफिकल मिश्रित वुड विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कद्दी सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।
- xxxii. रबर वुड प्लानटेशन और आश्रित उद्योगों की सहायता करने के लिए पुनः पौधारोपण सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार ने रबर वुड के निर्यातों पर प्रतिबंध भी बनाए रखा है।
- xxxiii. रबर वुड राष्ट्रीय वानिकी अधिनियम के अनुसार "बन उत्पाद" की परिभाषा के तहत विशेष रूप से अलग नहीं किया गया है। यदि हितबद्ध पक्षकार के अनुसार रबर वुड पर कोई रॉयलटी नहीं लगाई जाती है तो उससे भी सब्सिडी सिद्ध होती है।
- xxxiv. एलटीएआर पर विद्युत के संबंध में प्राकृतिक गैस की कीमतें जो कि मलेशिया में विद्युत का प्राथमिक स्रोत हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए सांविधिक रूप से विनियमित की जाती हैं। अतः विद्युत विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को एलटीएआर पर उपलब्ध है। इसकी जांच "फ्लोट ग्लास" और "टेम्पर्ड ग्लास" संबंधी पूर्व जांचों में की गई थी और प्रतिकार योग्य पाए गए थे।
- xxxv. घरेलू उद्योग ने निर्धारण के अनुसार ट्रेप मैप के अनुसार 2018-19 में शेष विश्व के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की निर्यात कीमत के साथ सब्सिडी मार्जिन परिकलित किया है।
- xxxvi. थाईलैंड सरकार ने कार्यक्रम संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, और 8 के तहत दिए गए वित्तीय अंशदान की राशि के संबंध में सूचना नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम संख्या 1, 2 और 3 के लिए संगत कर अनुबंध का भी उत्तर नहीं दिया गया है। कार्यक्रम संख्या 9 का थाईलैंड सरकार का उत्तर पूरी तरह अपूर्ण है। कार्यक्रम संख्या 10 और 11 के लिए थाईलैंड सरकार द्वारा पूर्ण मानक अनुबंध नहीं दिया गया है। संगत अनुबंधों का भी उत्तर नहीं दिया गया है।
- xxxvii. थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 1 संवर्धित क्रियाकलापों तक सीमित है और कॉपर सीवीडी मामले में प्रतिकार योग्य पाया गया।
- xxxviii. हॉट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट संबंधी सीवीडी जांच में यूएसडीओसी ने निवेश संवर्धन अधिनियम के तहत सभी सब्सिडियों को प्रतिकार योग्य पाया।
- xxxix. थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 2 के तहत लाभ बीओआई प्रमाण-पत्र धारित करने वाली सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कॉपर वायर रॉड संबंधी सीवीडी जांच में प्राधिकारी ने पाया कि थाईलैंड सरकार यह दर्शने के लिए कोई स्पष्टीकरण अथवा साक्ष्य नहीं दे पाई कि कोई अतिरिक्त लाभ

नहीं दिया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र कैसे प्रचालित होता है। डीजीटीआर उनके वास्तविक निष्कर्षों के आधार पर अन्य विदेशी प्राधिकारियों के विचारों से भिन्न हो सकते हैं।

- xli. थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 4 विशिष्ट है क्योंकि यह केवल संवर्धित क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध है। अग्रणीत करना एक वित्तीय अंशदान हो सकता है क्योंकि यदि किसी कंपनी को घाटा होता है तो लाभ बाद की अवधि में लिया जा सकता है। कार्यक्रम संख्या 6 भी केवल संवर्धित क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध है और इसीलिए विशिष्ट है। कार्यक्रम संख्या 8 में यह प्रावधान है कि लाभांश को आय कर से छूट है और इसीलिए वित्तीय अंशदान प्रदान किया जाता है।
- xlii. कार्यक्रम संख्या 1 से 8, जिनका संचालन थाईलैंड के निवेश बोर्ड द्वारा किया जाता है, को पूर्व में कॉपर सीवीडी मामले में प्राधिकारी द्वारा प्रतिकार योग्य माना गया है। ये कार्यक्रम भी विशिष्ट हैं क्योंकि केवल संवर्धित क्रियाकलाप के लिए दिए जाते हैं।
- xlii. एग्रोफाइबर, एडवांस फाइबर, मेट्रो एम.डी.एफ., पैनल प्लस एमडीएफ, एस.पी.बी. पैनल, एस किजचाई, वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज और वानाचाई ग्रुप के पास बीओआई प्रमाण-पत्र हैं। यद्यपि सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हैं, तथापि थाईलैंड सरकार द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- xliii. एडवांस फाइबर और वाइजवुड्स ने 2017 में अपनी क्षमताएं बढ़ाई। पैनल प्लस ग्रुप ने 2016 में अपनी क्षमताएं बढ़ाई। वानाचाई पैनल ने 2019 में अपनी क्षमताएं बढ़ाई। उन्हें संगत सब्सिडी लेनी चाहिए थी। वह या तो जांच की अवधि से संबंधित सूचना प्रतिबंधित कर रहे हैं अथवा प्राधिकारी को भ्रमित कर रहे हैं।
- xliv. न तो थाईलैंड सरकार और न ही थाईलैंड से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वीकार किया है अथवा एलटीएआर पर कच्ची सामग्री (वुड) और भूमि के लिए प्रावधान तथा एलटीएआर पर विद्युत के लिए प्रावधानों के संबंध में सूचना दी है। आवेदक ने इसके संबंध में संगत सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- xlv. थाईलैंड के उत्तरदाता निर्यातकों की वेबसाइट सूचना के अनुसार रबर वुड अथवा यूकेलिप्टस का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। थाईलैंड सरकार ने रबर वुड का पौधारोपण करने की जिम्मेदारी ली है और टिम्बर उत्पादन के लिए उपयुक्त क्लोन्स उत्पादित करने के लिए थाईलैंड और थाईलैंड के रबस अनुसंधान संस्थान तथा रायल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बन अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग किया है। प्राधिकारी को उन कीमतों की जांच करने की आवश्यकता है जिन पर उत्पादक/निर्यातक उनकी खरीद करते हैं।
- xlvi. टिम्बर के लिए घरेलू थाई बाजार का सरकारी नियंत्रण तथा रॉयल्टी लगाए जाने पर दिए गए लॉगिंग लाइसेंसों के कारण हास हुआ है जो कि बाजार सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और एलटीएआर पर कच्ची सामग्री की खरीद की अनुमति देता है। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि कच्ची सामग्री का स्रोत सरकारी बन अथवा निजी भूमि है।
- xlvii. "प्रतिबंधित वुड" शब्द नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट एक्ट, 1973 के तहत परिभाषित नहीं है। तथापि, "वुड" शब्द में "सभी प्रकार के वुड" शामिल हैं। इस प्रकार, रबर वुड कानून के क्षेत्र के अंतर्गत है।
- xlviii. थाईलैंड से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर सभी उत्तरों में से 184 मामलों में कोई सूचना दायर नहीं की गई थी और 9 मामलों में सूचना अपर्याप्त है।
- xlix. वानाचाई ग्रुप, वानाचाई पैनल, मेट्रो, एडवांस फाइबर, वाइजवुड्स, पैनल प्लस, एस. किजचाई, और एग्रोफाइबर के पास बीओआई प्रमाण-पत्र हैं। जब तक इसके विपरीत साक्ष्य नहीं दिया जाता है, तब तक यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने कार्यक्रम संख्या 1 से 8 प्राप्त किया है क्योंकि वे सभी बीओआई के तहत हैं। कार्यक्रम संख्या 1 से 7 कॉपर सीवीडी मामले में प्रतिकार योग्य माने गए थे।
- i. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने क्षमताएं बढ़ाई हैं अथवा एयूएल अवधि के दौरान नए संयंत्र जोड़े हैं और इसीलिए माना जाना चाहिए कि उन्होंने पूंजीगत सामानों पर आयात शुल्क की छूटें प्रदान करने वाले कार्यक्रम लिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम न लिए जाने का दावा गलत किया है। पैनल प्लस, वाइजवुड्स,

- एस किजचाई, एडवांस फाइबर, वानाचाई पैनल, एफएससी, किम टिन एमडीवाई ज्वाइंट स्टॉक कं. और सुमात्रा ने नए संयंत्र स्थापित किए हैं अथवा क्षमताएं बढ़ाई हैं।
- ii. यद्यपि थाईलैंड के उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक यह तर्क देते हैं कि सब्सिडी समग्र रूप से कंपनी के लिए प्राप्त की गई थी, न कि अकेले विचाराधीन उत्पाद के लिए, तथापि कार्यक्रम इस प्रकृति के हैं कि लाभ विचाराधीन उत्पाद को जाएगा। इसके अतिरिक्त, धन प्रतिमोच्य है और कंपनी उसका प्रयोग उस तरह से कर सकती है, जैसे वो चाहते हैं। एक सीवीडी जांच में कंपनी समग्र रूप से जांच का विषय है न कि उत्पाद। भारत के विश्व यूएस पीएसएफ मामले पर विश्वास किया जाता है।
 - iii. प्राधिकारी को थाईलैंड में विद्यमान भूमि के लिए प्रावधानों की जांच करने की आवश्यकता है। प्रकटन विवरण में कार्यक्रम संख्या 12 के लिए प्राधिकारी का विश्वेषण विरोधीभासी नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार एलटीएआर पर भूमि के साथ एलटीएआर पर वुड के विश्वेषण के संबंध में असमंजस में है।
 - iv. वियतनाम सरकार (जीओवी) जनरल डिपार्टमेंट ऑफ वियतनाम कस्टम्स, प्रोविंसियल टैक्स डिपार्टमेंट, लोकल टैक्स अथॉरिटीज और वियतनाम डेवलेपमेंट बैंक को संचालक प्राधिकारियों के रूप में उल्लिखित करने में विफल रहा। वियतनाम सरकार ने कुछ वेब पेजों को गोपनीय होने का दावा किया है। ये प्रश्नावली के तहत दिशानिर्देशों के खंड क, मद 5 का उल्लंघन है। विभिन्न प्रश्नावलियों से संबंधित सूचना वियतनाम सरकार द्वारा नहीं दी गई है।
 - v. कार्यक्रम संख्या 8 और 9 के लिए वियतनाम सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिए गए हैं। न तो वियतनाम सरकार और न ही उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वीकार किया है और एलटीएआर पर टिम्बर के लिए प्रावधान, लॉग निर्यातों पर सरकारी प्रतिबंध, प्रोत्साहित उद्योगों, डिक्री 142 के तहत प्रोत्साहित उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि प्राथमिकताओं और एलटीएआर पर भूमि के प्रावधान के संबंध में संगत सूचना दी है। आवेदक ने इस संबंध में संगत सूचना और साक्ष्य दिए हैं।
 - vi. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 1 और 2 के लिए किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने मानक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। कार्यक्रम संख्या 1 कॉपर सीवीडी के मामले में पहले ही प्रतिकार योग्य पाया गया था। कार्यक्रम संख्या 3 के लिए किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. और एफएससी ने मानक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं। किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. ने उन्हें प्राप्त न करने के लिए कारण नहीं दिए हैं। वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 3 में मशीनरी और उपस्कर, संघटक, हिस्से पुर्जों और अतिरिक्त हिस्से पुर्जों की खरीद भी शामिल है। इससे संबंधित सूचना का सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है।
 - vii. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 4 के लिए एफएससी और वीआरजी ने मानक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। एफएससी ने इन्हें प्राप्त न करने के कारण नहीं दिए हैं। प्राधिकारी द्वारा कॉपर सीवीडी मामले में इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य पाया गया था।
 - viii. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 5 के लिए किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/ निर्यातक ने मानक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. और एफएससी ने इन्हें न लेने के कारण नहीं दिए हैं।
 - ix. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 6 किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. और एफएससी ने मानक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये हैं अथवा इन्हें प्राप्त न करने के कारण नहीं दिए हैं।
 - x. कार्यक्रम संख्या 4 और 6 प्राधिकारी द्वारा कॉपर सीवीडी मामले में प्रतिकार योग्य पाए गए थे।
 - xi. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 8 और 9 के लिए किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने मानक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये हैं अथवा इन्हें प्राप्त न करने के कारण नहीं दिए हैं। निर्यातकों को यह दर्शाने के लिए साक्ष्य देने चाहिए कि अल्पकालिक क्रृष्ण पर दी गई व्याज दर निर्धारण के समान है।
 - xii. डब्ल्यूटीओ सचिवालय की व्यापार नीति समीक्षा देश के स्थानीय कानूनों के संबंध में अत्यधिक साक्ष्य वाले मूल्य की है।

- Ixiii. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 10 के लिए वानिकी क्षेत्र में वियतनाम सरकार का हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर उसकी खरीद की अनुमति देते हुए टिम्बर के लिए घरेलू बाजार का हास करता है।
- Ixiv. वियतनाम के उत्तरदाता निर्यातकों की वेबसाइट के अनुसार यूकेलिप्टस वुड का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के लिए कद्दी सामग्री के रूप में किया जाता है। खरीद के लिए कीमतों की प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
- Ixv. श्रीलंका सरकार (जीओएस) एलटीएआर पर सामान उपलब्ध कराती है और लॉग निर्यात प्रतिबंध लगाती है। जो उत्पादक अपनी कद्दी सामग्री के रूप में टिम्बर का प्रयोग करते हैं, उनको इन कार्यक्रमों से लाभ मिला है। रबर के पेड़ों का पौधारोपण करने के लिए दी गई सब्सिडी से रबर कृषक एलटीएआर पर रबर वुड बेचने के लिए सक्षम हो गए हैं। श्रीलंका से आयात 4 प्रतिशत से अधिक हैं और इसीलिए न्यूनतम से कम नहीं हैं।
- Ixvi. श्रीलंका के लिए कार्यक्रम संख्या 1 निर्यातों के संबंध में आकस्मिक है और इसीलिए प्रतिबंधित है। यह कार्यक्रम श्रीलंका से सरटेन न्यूमेटिक ऑफ-रोड टायर्स में यूएसडीओसी द्वारा प्रतिकार योग्य पाया गया था।
- Ixvii. श्रीलंका के कार्यक्रम संख्या 2 के संबंध में, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि मर्बोक जनवरी, 2019 तक बीओआई के तहत प्रचालन नहीं कर रहा था। श्रीलंका सरकार द्वारा अथवा मर्बोक द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है।
- Ixviii. कार्यक्रम संख्या 3 से 6 के संबंध में, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। श्रीलंका सरकार और संबद्ध सामानों के श्रीलंकाई उत्पादकों को असहयोगी माना जाना चाहिए।
- Ixix. श्रीलंका सरकार एलटीएआर पर सामान प्रदान करती है और लॉग निर्यात प्रतिबंध भी लगाती है। जो उत्पादक टिम्बर को कद्दी सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें इस कार्यक्रम से लाभ मिलता है।
- Ixx. प्राधिकारी को श्रीलंका सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए इन सब्सिडी कार्यक्रमों की प्रतिकार योग्यता की जांच करने की आवश्यकता है।
- Ixxi. संबद्ध देशों में विद्युत के सब्सिडी मार्जिन का परिकलन वेबसाइट "ग्लोबल पैट्रो प्राइसेस" से ली गई निर्धारित कीमतों के साथ किया गया है।
- Ixxii. न तो उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने और न सरकार ने "अन्य सब्सिडी" के शीर्ष के तहत उत्तर दिया है।
- Ixxiii. प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया निर्धारण अत्यधिक रूढ़िवादी है। निम्नलिखित वैकल्पिक निर्धारण अधिक उपयुक्त हो सकते हैं: (क) संबद्ध देश में उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त समान किस्म के वुड की निर्यात कीमत, (ख) कद्दी सामग्री (वुड) की घरेलू उद्योग द्वारा उनके खपत मानदंड के साथ उच्चतम/ औसत लागत, (ग) विश्व व्यापार एटलस से वुड/टिम्बर/लॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत, और (घ) संबद्ध देशों को छोड़कर भारत को संबद्ध सामानों के प्रमुख निर्यातकों से वुड/टिम्बर/लॉग की कीमतें।
- Ixxiv. एएससीएम के अनुच्छेद 14(घ) के अनुसार एलटीएआर पर लॉग/टिम्बर/वुड प्रदान करने वाली सब्सिडी योजनाओं की मात्रा निर्धारित करने के लिए न्यूजीलैंड एक उपयुक्त उदाहरण है। सरकारी सब्सिडी के कारण घरेलू बाजार के हास के कारण देश से बाहर के निर्धारण का प्रयोग "एक कीमत के कानून" के अनुसार उपयुक्त है। तदनुसार, न्यूजीलैंड अपनी अर्थव्यवस्था के खुलेपन और लॉग्स के निर्यात की काफी मात्रा के कारण उपयुक्त निर्धारण है।
- Ixxv. न्यूजीलैंड की सरकार द्वारा वानिकी क्षेत्र के तथाकथित नियंत्रण के बाद ही संबद्ध देशों में सब्सिडीकरण देखा जाता है। न्यूजीलैंड आर्थिक स्वतंत्रता के 2018 के सूचकांक में तीसरे स्थान पर था और वहां ओईसीडी देशों में सबसे कम सब्सिडी है। न्यूजीलैंड में 95 प्रतिशत आकर्षक वानिकी पौधारोपण निजी स्वामित्व में है और निर्यात नियंत्रण न्यूनतम है। क्राउन वन भूमि में फसलीकरण के लिए लगाया गया लाइसेंस शुल्क बाजार दर के अनुसार है।

- Ixxvi. घरेलू उद्योग को न्यूजीलैंड अथवा किसी उपयुक्त देश से थाईलैंड को लाँग कीमतों के प्रयोग के प्रति कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि निर्धारण यदि प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया जाए।
- Ixxvii. निर्धारण पर साक्ष्य प्रस्तुत करने से घरेलू उद्योग पर कोई सांविधिक प्रतिबंध नहीं है। हल्दौर टोपसे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जाता है।
- Ixxviii. प्राधिकारी के लिए किसी नई योजना के संबंध में उत्तरदाता सरकार अथवा उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित करना अनिवार्य नहीं है।
- Ixxix. हितबद्ध पक्षकारों के पास आवेदक द्वारा लगाए गए नए सब्सिडी आरोपों का प्रत्युत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था। अतः सीवीडी नियमावली अथवा एएससीएम का कोई उल्लंघन नहीं है।
- Ixxx. घरेलू उद्योग जांच प्रक्रिया के दौरान पाए गए एलटीएआर पर सामानों और सेवाओं की खरीद के संबंध में मात्र तथ्य लाया। यह इसलिए किया गया था क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों ने उपर्युक्त सूचना को छिपाया था।
- Ixxxi. प्राधिकारी ट्रेड मैप आंकड़ों के अनुसार रबर वुड की कीमतों का प्रयोग कर सकते हैं और सब्सिडी मार्जिन पुनः निर्धारित कर सकते हैं।
- Ixxxii. नए सब्सिडी आरोपों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के उत्तर सूचना को छिपाए जाने के रूप में माने जाने चाहिए।
- Ixxxiii. हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपेक्षित है कि वे यह दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराएं कि कझी सामग्री और यूटिलिटी उचित बाजार कीमत पर है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- याचिकाकर्ताओं ने केवल सांविधिक प्रावधान दिए हैं, परन्तु प्रकृति अथवा विशेषता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उसको सिद्ध करने का दायित्व याचिकाकर्ताओं पर है। भारत तब तक निर्यातक पर नहीं डाला जाए जब तक घरेलू उद्योग उसे सिद्ध न कर ले।
- इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 1 और 2 के लिए कार्यक्रम में केवल खड़ा टिम्बर शामिल है, परन्तु उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक रबर वुड/रबर वुड अपशिष्ट का प्रयोग करते हैं। इंडोनेशिया से उत्तरदाता उत्पादकों ने निजी पौधारोपण से ली गई कझी सामग्री से संबद्ध सामानों का उत्पादन किया। यह कार्यक्रम एएससीएम के अनुसार सब्सिडी नहीं है। पेपर उद्योग के संबंध में मामलों पर घरेलू उद्योग द्वारा किया गया विश्वास फाइबरबोर्ड उद्योग पर लागू नहीं है।
- इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 1 और 2 के लिए, याचिकाकर्ताओं के आरोप एएससीएम के अनुच्छेद 1.1(क), 1.1(ख) और 1.2 के तहत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। इंडोनेशियाई फाइबरबोर्ड उद्योग निजी पौधारोपण से रबर वुड का प्रयोग करता है, न कि राज्य सरकारी बनों से, जैसा कि इंडोनेशिया सरकार की प्रश्नावली में उल्लेख किया गया है और इसीलिए कार्यक्रम संख्या 1 भी लागू नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने गलत माना कि लाँग निर्यात प्रतिबंध से टिम्बर की अधिक आपूर्ति हुई जिससे इंडोनेशियाई घरेलू बाजार में टिम्बर की कीमत का ह्रास हुआ। वस्तुतः कोई अधिक आपूर्ति नहीं है और इंडोनेशिया काफी मात्राओं में टिम्बर का आयात करता है (2014 की तुलना में 2018 में 43 प्रतिशत तक बढ़ा)। निर्यात प्रतिबंध पर्यावरण के परिवर्तन की बातचीत पर प्रत्याशित है और देशों द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त एक उपाय है। यूएस-एक्सपोर्ट प्रतिबंधों में यह पाया गया था कि निर्यात प्रतिबंध प्रतिकार योग्य नहीं हैं क्योंकि कोई वित्तीय अंशदान नहीं है। इसी प्रकार, निर्यात प्रतिबंध में कोई वित्तीय अंशदान नहीं है और इस प्रकार कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।
- कार्यक्रम संख्या 1 के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि पीएनटी (स्टेमपेज वैल्यू रिप्लेसमेंट) शुल्क हटा दिया गया है। यह आरोप कि टिम्बर निर्यातकों को सस्ते स्टम्पेज शुल्क के कारण एलटीएआर पर

- उपलब्ध है, सिद्ध नहीं है क्योंकि एमडीएफ विनिर्माता एमडीएफ के विनिर्माण के लिए लॉग्स, अपशिष्ट पेपर, फाइबर आदि के अवशेष का प्रयोग कर रहे हैं।
- v. चूंकि एमडीएफ विनिर्माता वैश्विक रूप से लॉग्स, अपशिष्ट पेपर, फाइबर आदि के अवशिष्ट का प्रयोग कर रहे हैं, अतः कार्यक्रम संख्या 2 उन पर लागू नहीं है।
- vi. इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 2 का उद्देश्य अवनीकरण कम करना है और इंडोनेशिया में अवैध लॉगिंग का सामना करना है। यूएस-निर्यात अवरोधों में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह पाया कि निर्यात अवरोधों में एससीएम के तहत प्रतिकार योग्य सब्सिडी नहीं है।
- vii. एकिजम बैंक द्वारा दी गई निर्यात सुविधा प्राधिकारी द्वारा पूर्व में प्रतिकारित नहीं थी। इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 3 और 10, 2017-18 की प्रक्रिया में एकिजम बैंक और बैंक मंदिरी ने बीएआई (सेट्रल बैंक) दर से कम ब्याज दरें प्रदान नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पुष्टि की कि किसी भी इंडोनेशियाई फाइबरबोर्ड उत्पादक पर उनसे कोई ऋण नहीं है। अतः डीजीटीआर को इस आरोप को रद्द करना चाहिए। इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 3 के लिए पीटी बैंक नेगारा (बीएनआई) एक सरकारी निकाय नहीं है। बीएनआई में उपलब्ध ऋण अथवा कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है। यूएस (चीन) में पैनल रिपोर्ट के अनुसार केवल स्वामित्व सरकारी निकाय नहीं बनता। किसी भी मौजूद इंडोनेशियाई फाइबरबोर्ड उत्पादक पर एकिजम बैंक अथवा बैंक मंदिरी से कोई ऋण नहीं है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए निर्धारण के रूप में स्थानीय मुद्रा ब्याज दर का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- viii. इंडोनेशिया के कार्यक्रम संख्या 4 से 9 याचिकाकर्ताओं के दावों के अनुसार 2007 के इंडोनेशियाई कानून सं. 25 के तहत दिए जाते हैं। यह कानून सभी क्षेत्रों के लिए है। इंडोनेशियाई उत्पादकों ने 6 तथाकथित कार्यक्रमों में से 5 का प्रयोग नहीं किया। उनके द्वारा प्राप्त किया गया कार्यक्रम केवल कार्यक्रम 7 था जो न तो विशिष्ट है और न ही विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इंडोनेशियाई उद्योग को कोई लाभ प्रदान करता है। इंडोनेशिया सरकार ने यह दर्शाने के लिए अतिरिक्त सूचना दी है कि मुक्ति पैनल ने कार्यक्रम संख्या 10 नहीं लिया है।
- ix. यह अनुरोध है कि निर्यातकों ने कार्यक्रम संख्या 3 के तहत एकिजम बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। इस दावे की निर्यातकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई ऋण संबंधी सूचना से जांच की जा सकती है।
- x. चूंकि निर्यातकों ने न तो कम किए गए आय कर का कोई लाभ लिया है और न ही उन्हें इस प्रकार का कोई लाभ उपलब्ध है, अतः कार्यक्रम संख्या 4 के संदर्भ में कोई भी दावा गलत है।
- xi. आवेदक पीटी मुक्ति और पीटी सुमात्रा ने कड़ी सामग्री घरेलू तौर पर खरीदी है अर्थात् कड़ी सामग्री का आयात नहीं किया है। निर्यातकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट उनके दावे की सत्यता सत्यापित करने के लिए उनकी प्रश्नावली के उत्तर के साथ संलग्न की गई है।
- xii. निर्यातकों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनके प्रश्नावली के उत्तर में उन्होंने भूमि तथा भवन कर की कोई राहत नहीं ली है। अतः आवेदक द्वारा किया गया यह दावा कि पीटी मुक्ति और पीटी सुमात्रा ने कार्यक्रम के लिए मानक प्रश्नावली नहीं दी है/उत्तर नहीं दिया है, गलत है।
- xiii. पीटी सुमात्रा ने अपने प्रश्नावली के उत्तर के पृष्ठ संख्या 18 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने आय कर छूट का कोई लाभ नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, आयातों के पूरे व्यौरे तथा देय कर और उस पर प्रदत्त कर के पूरे व्यौरे दिए गए हैं।
- xiv. पीटी मुक्ति (निर्यातक) का अनुरोध है कि उसने अपने उत्तर के अनुबंध 8 में आयातों पर प्रदत्त करों के पूरे व्यौरे दिए हैं। यह बात दोहराई जाती है कि आयात सामग्री और पूंजीगत सामान के लिए आय कर (पीपीएच) की छूट प्रतिकार योग्य लाभ प्रदान नहीं करती क्योंकि आयात के लिए आय कर वार्षिक देय आय कर के लिए मात्र एक किश्त है।
- xv. टंगेरांग में कारखाना कीमतें कार्यक्रम संख्या 11 के लिए उपयुक्त निर्धारण नहीं हैं क्योंकि यह कार्यक्रम वन भूमि से संबंधित है और टंगेरांग भिन्न द्वीप अर्थात् जावा में स्थित है। घरेलू उद्योग की मात्र यह

धारणा कि इंडोनेशियाई संविधान अनुच्छेद 33(3) में यह प्रावधान है कि उनमें निहित भूमि, जल और प्राकृतिक समृद्धि की वस्तुएं सरकार द्वारा नियंत्रित होंगी, भी सिद्ध नहीं करती कि भूमि उत्तरदाताओं को एलटीएआर पर कैसे उपलब्ध है। डब्ल्यूएस स्तर पर उठाए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।

- xvi. इंडोनेशिया की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पीएलएन इंडोनेशिया में सभी कंपनियों को सेवा देती है और इसीलिए यह कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है। घरेलू उद्योग ने पहली बार सब्सिडीकरण का कोई आरोप लगाए बिना भी अपने अनुरोधों में विद्युत के सब्सिडी मार्जिन को शामिल किया है। इंडोनेशिया सरकार का अनुरोध है कि यह एएससीएम के अनुच्छेद 12.7 के विरुद्ध है। इंडोनेशिया में विद्युत सब्सिडीकरण के संबंध में किसी दावे अथवा साक्ष्य के अभाव में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए सब्सिडी मार्जिन का परिकलन सारहीन है और उसका कोई औचित्य नहीं बनता।
- xvii. "विद्युत" पर तथाकथित सब्सिडी के परिकलन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किया गया साक्ष्य वेबसाइट "ग्लोबलपैट्रोलप्राइसेस" से लिया गया है, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपर्युक्त दस्तावेज की प्रति देने में विफल रहा।
- xviii. जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है, उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा सूचना को नहीं द्विपाया गया है, यह अनुरोध है कि उन्होंने प्रश्नावली के उत्तरों के पूर्ण ब्यौरे दिए हैं और पूरी जांच में सहयोग किया है, अतएव उनके उत्तरों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।
- xix. श्रीलंका के लिए कार्यक्रम संख्या 1 के लिए एएससीएम की पाद टिप्पणी 1 को देखते हुए, एनबीटी का प्रेषण एएससीएम के तहत सब्सिडी नहीं है। यह प्रेषण उत्पाद को ध्यान में न रखते हुए सभी निर्यातकों के लिए लागू है। पाद टिप्पणी 1 में उल्लेख है कि पाद टिप्पणी 58 के तहत परिभाषित किए गए अनुसार निर्यातों को अप्रत्यक्ष करों से क्लूट वित्तीय अंशदान नहीं है। यही सिद्धांत जीएटीटी के अनुच्छेद XVI की एडी टिप्पणी में भी दिया गया है। एएससीएम के अनुबंध-1(छ) में यह उल्लेख है कि लगाए गए अप्रत्यक्ष कर का यह प्रेषण सब्सिडी नहीं है, यदि वह घरेलू खपत के लिए समान उत्पादों के उत्पादन और वितरण के लिए लगाए गए करों से अधिक नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत प्रेषण इस स्तर से अधिक नहीं होता है। अनुबंध-II(1) भी निर्यातित उत्पादों के उत्पादन के लिए उपभोग किए गए इनपुट पर लगाए गए अप्रत्यक्ष करों के प्रेषण की अनुमति देता है। एनबीटी दिसंबर, 2019 से समाप्त किया गया था।
- xx. श्रीलंका के लिए कार्यक्रम संख्या 2 के लिए, मर्बोक जनवरी, 2019 तक बीओआई अधिनियम के तहत प्रचालन कर रहा था। कंपनी को जनवरी, 2019 से इस योजना से लाभ मिला, न कि उससे पहले से।
- xxi. कार्यक्रम संख्या 3 के लिए, मर्बोक को 2014 से घाटे होते रहे हैं। इसीलिए वह आय कर का भुगतान करने के लिए देनदार नहीं है। अतः यह कार्यक्रम लागू नहीं है।
- xxii. कार्यक्रम संख्या 4 के लिए, मर्बोक को 2014 से घाटे होते रहे हैं। इसीलिए वह आय कर का भुगतान करने के लिए देनदार नहीं है। अतः यह कार्यक्रम लागू नहीं है।
- xxiii. कार्यक्रम संख्या 5 के लिए, यह एक सामान्य सब्सिडी है और किसी क्षेत्र को विशेष रूप से नहीं दी जाती है। यह कृषि क्षेत्र में लगे हुए सभी को उपलब्ध है। यह विशेष रूप से रबर उत्पादकों को लाभान्वित नहीं करती और निर्यातकों को नहीं दी जाती। अतः न तो कोई निर्यात सब्सिडी है और न एएससीएम के तहत मिलान योग्य है। मर्बोक इस कार्यक्रम के लिए उस तक पहुँच के लिए प्रशासन प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं है।
- xxiv. कार्यक्रम संख्या 6 के लिए, रबर डेवलेपमेंट बोर्ड द्वारा संचालित दो योजनाएं विशिष्ट रूप से रबर उपजकर्ताओं को प्रदान की जाती हैं। यह नए पौधारोपण और पुनः पौधारोपण के लिए प्रदान की जाती है। श्रीलंका से फाइबरबोर्ड उत्पादक रबर लॉग्स का प्रयोग करते हैं जो रबर उद्योग से अपशिष्ट होता है। फाइबरबोर्ड विनिर्माताओं द्वारा खरीदे गए आरा मिल डस्ट और अपशिष्ट वुड बाजार कीमतों पर हैं। इनकी खरीद पेड़ के जीवनकाल की समाप्ति पर बाहर फेंकने की कीमत पर की जाती है। यह खरीद इस योजना से प्रभावित नहीं होती है। लाभ बहुत दूर का है और वह फाइबरबोर्ड उत्पादकों तक नहीं जाता।

जांचकर्ता प्राधिकारी के पास यह दर्शने के लिए साक्ष्य होना चाहिए कि लाभ एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक गया है, यह मानने के लिए कि वह सब्सिडी दूसरे के पास मौजूद है। अतः जीओएसएल का अनुरोध है कि वह सब्सिडी मौजूद नहीं है।

- xxv. यदि कोई सब्सिडी केवल "कुछ उद्यमों" के लिए उपलब्ध है, तो वह विशिष्ट है। तथापि, जब वस्तुपरक मानदंड निर्धारित किया जाता है और ये शर्तें क्षेत्रिज रूप से लागू होती हैं, तो कोई विशिष्टता नहीं है। संवर्धन के लिए बीओआई द्वारा निर्धारित क्रियाकलाप अत्यधिक व्यापक हैं और थाईलैंड में लगभग प्रत्येक उद्योग क्षेत्र से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से शामिल करते हैं। आईपीए की धारा 17 के तहत कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है और संवर्धित क्रियाकलाप कर सकता है। मानदंड व्यापक हैं। उसके बाद, सभी कार्यक्रम पैकेज के रूप में दिए जाते हैं। यद्यपि कंपनियों ने लाभ का उपयोग करते समय अलग से आवेदन किया है।
- xxvi. थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 1 में भुगतान से छूट का प्रावधान है, न कि सीमा शुल्कों में कटौती का। कंपनी को किसी विशेष मशीनरी के लिए बीओआई से पहले अनुमोदन प्राप्त करना होता है। केवल उन्हीं मशीनों, जिन्हें थाईलैंड में असेंबल नहीं किया गया है, को अनुमोदन प्राप्त होता है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में उस तरीके को सिद्ध किए बिना जिसमें वह उद्यम विशिष्ट है, गलत उल्लेख किया है कि कार्यक्रम 1 "उद्यम विशिष्ट" है।
- xxvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कार्यक्रम संख्या 2 के अपने विशेषण में गलती की है। जैसा कि यूएसडीओसी जांच परिणाम में नोट किया गया है, बीओआई प्रभावी सत्यापन तंत्र लागू है और इस प्रकार कार्यक्रम संख्या 2 एक अनुमत्य कर छूट कार्यक्रम है। संदर्भ: थाईलैंड से ग्लाइसिन की प्रतिकारी शुल्क जांच (यूएसडीओसी), बीओआई में यह सुनिश्चित करने की प्रभावी प्रणाली है कि कोई अतिरिक्त लाभ न दिया जाए।
- xxviii. कार्यक्रम संख्या 4 में, याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि बीओआई कार्यक्रम के तहत अग्रणीत किए जाने के प्रावधान वित्तीय अंशदान क्यों हैं अथवा यदि वे वास्तव में हैं तो वे लाभ कैसे प्रदान करते हैं। विशिष्टतः का अभाव है क्योंकि मानदंड व्यापक हैं। "उद्यम विशिष्ट" के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
- xxix. कार्यक्रम संख्या 6 में, यह कार्यक्रम किसी विशेष उद्यम अथवा उद्योग के लिए सीमित नहीं है तथा व्यापक श्रेणी के आर्थिक क्रियाकलाप के लिए उपलब्ध है और इसीलिए विशिष्ट नहीं है।
- xxx. कार्यक्रम संख्या 8 में, लाभ, यदि कोई है, वास्तव में संवर्धित कंपनी को नहीं दिया जाता है बल्कि संवर्धित कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाता है।
- xxxi. कार्यक्रम संख्या 9 में, निर्यातित सामानों पर कर का प्रेषण वैट प्रणाली का पालन करने वाले विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में सामान्य एवं सुस्थापित परिपाठी हैं। उसे "कंटीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच में प्रतिकार योग्य नहीं माना गया था।
- xxxii. प्रश्नावली के उत्तर थाई सरकार द्वारा दायर किए जाने अपेक्षित हैं न कि उसकी एजेंसियों द्वारा। अतः यह सुन्नाव कि निवेश बोर्ड, जो कि सरकार की एक एजेंसी है, को उत्तर दायर करने चाहिए थे, कानून द्वारा समर्थित नहीं है।
- xxxiii. मैसर्स मैट्रो ग्रुप द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उसने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और वे सभी व्यौरे देते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर किए हैं जो संगत हो सकते हैं। मैट्रो ग्रुप ने पूर्ण प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और कार्यक्रम विशिष्ट अनुबंध भी दिए हैं तथा यथालागू संगत अतिरिक्त अनुबंध भी दिए हैं।
- xxxiv. याचिकाकर्ताओं ने एक अतिरिक्त कार्यक्रम की मौजूदगी का आरोप लगाया है, "पर्यास पारिश्रमिक से कम के लिए कञ्ची सामग्री (वुड) का प्रावधान" विद्यमान है, परन्तु उस कार्यक्रम की प्रकृति और अनुप्रयोग अस्पष्ट है। यह भी अस्पष्ट है कि क्या याचिकाकर्ता एक सब्सिडी कार्यक्रम का आरोप लगा रहे हैं अथवा कई भिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों का आरोप लगा रहे हैं। अंतिम रूप से यह भी अस्पष्ट है कि क्या ये तथाकथित कार्यक्रम विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों तथा/अथवा निर्यातकों को लाभ प्रदान करते हैं।

- xxxv. याचिकाकर्ताओं के लिखित अनुरोधों का अनुबंध 3.4, जिसमें थाईलैंड से सभी सब्सिडी कार्यक्रमों की सूची है, केवल 11 कार्यक्रमों की पहचान करता है, जैसा कि जांच की शुरूआत की अधिसूचना में निर्धारित है और उपर्युक्त अभिज्ञात कार्यक्रम के रूप में किसी अतिरिक्त कार्यक्रम का उल्लेख नहीं करता। याचिकाकर्ताओं ने इन कार्यक्रमों की मौजूदगी सिद्ध करने के लिए कानूनों अथवा विनियमों के उद्वरणों जैसे किसी अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- xxxvi. याचिकाकर्ताओं ने कुछ मानक और संगत कार्यक्रम विशिष्ट अनुबंधों (याचिकाकर्ताओं द्वारा एसए तथा आरए के रूप में उल्लिखित) को अपने दावे सिद्ध करने के लिए कोई कारण दिए बिना "कमीपूर्ण" के रूप में दावा किया है। एडवांस फाइबर ने वस्तुतः मानक कार्यक्रम विशिष्ट अनुबंध और संगत अनुबंध, जहां लागू हैं, दोनों प्रस्तुत किए हैं।
- xxxvii. मैट्रो ग्रुप ने विस्तृत प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण प्रस्तुत सूचना के आधार पर और मैट्रो ग्रुप द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर रखा जाना चाहिए।
- xxxviii. मैट्रो ग्रुप ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों के विपरीत क्षमताओं की अभिवृद्धि से संबंधित सभी संगत सूचनाएं प्रकट की हैं। मैसर्स एडवांस फाइबर कं. लि. ने क्षमताओं की अभिवृद्धि के संबंध में पर्याप्त सूचना प्रकट की है। उसका भी प्रपत्र ग से विश्लेषण किया जा सकता है जो यह दर्शाएगा कि क्षमताएं वर्ष 2016 में 100 सूचकांक से बढ़ाकर 2017 में 139 सूचकांक तक और वर्ष 2018 में 177 सूचकांक तक की गई थीं।
- xxxix. सब्सिडीरोधी नियमावली, 1995 के नियम 16(घ) के अनुसार, किसी भी विकासशील देश पर शुल्क लगाए जाने के लिए विचार नहीं किया जा सकता, यदि कुल आयातों में उसका हिस्सा 4 प्रतिशत से कम है, परन्तु श्रीलंका जिसके आयात 4 प्रतिशत से कम हैं, एक संबद्ध देश के रूप में विचार किया गया है।
- xl. प्रत्येक कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। कॉपर वायर रॉड मामले में पूर्व जांच परिणाम का बैंकेट आवेदन पत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में होगा।
- xli. थाई निर्यातकों ने या तो डब्ल्यूटीओ एससीएम के संदर्भ में कोई प्रतिकारी सब्सिडी नहीं ली है, या सब्सिडी की राशि, यदि कोई है, न्यूनतम स्तर से कम है।
- xlii. आवेदकों को अनिवार्य रूप से यह प्रदान करना चाहिए: (क) तथाकथित सब्सिडी की मौजूदगी का साक्ष्य, (ख) सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान का साक्ष्य, (ग) वित्तीय अंशदान लाभ प्रदान करना चाहिए, और (घ) तथाकथित कार्यक्रम एससीएम करार के संदर्भ में विशिष्ट है। तथापि, वर्तमान जांच में आवेदक उपर्युक्त 4 मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं और इसीलिए आवेदन पत्र रद्द किया जाना चाहिए।
- xliii. आरटीजी द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, तथाकथित कार्यक्रम संख्या 1-8 यथासंशोधित निवेश संवर्धन अधिनियम बी.ई. 2520 (1977) ("आईपीए") के अनुसार निवेश बोर्ड (बीओआई) के कार्यालय द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, आईपीए के अनुसार बीओआई द्वारा संचालित कार्यक्रम संख्या 1-8 थाईलैंड में लगभग प्रत्येक उद्योग के लिए उपलब्ध हैं।
- xliv. आरटीजी निर्यात के प्रयोजनों के लिए आयात शुल्क की छूट की अनुमति देता है क्योंकि उसके लिए अनुच्छेद 1 के तहत डब्ल्यूटीओ एससीएम करार द्वारा अनुमति है। आरटीजी यह बात भी दोहराना चाहता है कि बीओआई में कट्टी सामग्री के आयात, थाईलैंड से निर्यातित परिष्कृत सामानों के लिए इनपुट सामग्री की खपत का पता लगाने के लिए और यह पुष्टि करने के लिए कि संवर्धित क्रियाकलाप करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, एक प्रभावी प्रणाली है।
- xlv. थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 2 उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा नहीं लिया जाता है। केवल कार्यक्रम के तहत दिया गया अतिरिक्त लाभ पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जा सकता है, यदि कोई है। यह कार्यक्रम यूएसडीओसी द्वारा पूर्व में गैर-प्रतिकार योग्य माना गया था।

- xvi. कार्यक्रम संख्या 8 कंपनी के शेयरधारकों को लाभ देता है, न कि खुद कंपनी को। अतः कार्यक्रम संख्या 8 के लिए इस जांच को रह किया जाना चाहिए।
- xvii. आरटीजी का अनुरोध है कि कार्यक्रम संख्या 9 में उन निर्यातित सामानों पर कर के प्रेषण के लिए प्रावधान है जिसको अन्यथा उस समय समान उत्पाद द्वारा बहन किया जाता है जब एससीएम करार की पाद टिप्पणी के अनुसार घरेलू खपत के लिए हों। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने "इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" में नोट किया कि इस सब्सिडी कार्यक्रम में सामानों के निर्यात पर मूल्यवर्धित कर से छूट का प्रावधान है, अन्य व्यापार पर भी लागू होता है और इसीलिए किसी प्रतिकारी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई थी।
- xviii. किसी प्रतिकारी शुल्क जांच में लाभ की जांच प्राप्तकर्ता के परिप्रेक्ष्य से की जानी चाहिए। संदर्भ की आसानी के लिए, कनाडा – सिविलियन एयरक्राफ्ट के निर्यात को प्रभावित करने वाले उपाय तथा यूरोपीय समुदाय – लार्ज सिविल एयरक्राफ्ट में व्यापार प्रभावित करने वाले उपाय, शीर्षक वाले विवाद में डब्ल्यूटीओ डीएसबी का संदर्भ देखा जा सकता है।
- xlix. कार्यक्रम संख्या 2 के संदर्भ में संबद्ध सामानों के थाई निर्यातिकों को इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय अंशदान/सब्सिडी नहीं हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए, आरटीजी प्राधिकारी को अपना सहयोग देता है और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का इच्छुक है।
- i. आवेदकों ने दावा किया है कि आरटीजी ने कार्यक्रम संख्या 10 और 11 के लिए पूर्ण सूचना नहीं दी है। तथापि, प्रश्नावली के उत्तर का अवलोकन यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम एससीएम करार के अनुसार सब्सिडी वाले नहीं हैं।
- ii. थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 11 के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों को लागू करने के बावजूद केवल कुछ उत्पादकों पर प्रतिकारी शुल्क लगाया। उपलब्ध तथ्य थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 11 के लिए वर्तमान मामले में लागू नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि थाई निर्यातिकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है। डीजीटीआर नियम पुस्तक और ईसी – डीआरएएम चिप्स पर प्रतिकारी उपाय में पैनल रिपोर्ट के अनुसार एससीएम के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार सीवीडी नियमावली के नियम 7(8) के निर्वचन पर विश्वास किया जाता है। एक्जिम बैंक द्वारा दायर पत्र यह दर्शाता है कि वानाचई ग्रुप और पैनल प्लस ग्रुप द्वारा कोई लाभ नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त, एक्जिम बैंक कोई ऋण नहीं देता।
- iii. सब्सिडी होने के लिए ऋण के लिए, उसे सरकार तथा सार्वजनिक निकाय से शुरू होना चाहिए और लाभ बाजार में तुलनीय ऋण से कम व्याज दर के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। मैट्रो ग्रुप द्वारा लिए गए ऋण वाणिज्यिक बैंकों से और बाजार दरों पर हैं।
- iv. थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 12 के लिए, निजी भूमि को संगत अधिनियम के क्षेत्र से अलग किया गया है और रबर वुड तथा किसी किस्म का फायर वुड "प्रतिबंधित वुड" के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। सरकार वुड की कीमतों के विनियमन में नहीं लगी है।
- v. आवेदकों ने दावा किया है कि आरटीजी पर्यास पारिश्रमिक से कम पर कच्ची सामग्री दे रहा है। तथापि, उपर्युक्त दावा केवल अवधारणा है और सिद्ध नहीं है।
- vi. प्रकटन विवरण के पैरा 323 और 324 में प्राधिकारी का विश्वेषण विरोधाभासी है।
- vii. कार्यक्रम संख्या 13 के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा गलत और आधारहीन है। विद्युत की कीमत प्रकृति में एक समान है और सभी व्यापारों तथा उद्योगों को दी जाती है। अतः विशिष्ट नहीं है। कोई प्रतिकार योग्य लाभ नहीं लिया जाता है। मात्रा के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किया गया निर्धारण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें पीईए द्वारा केवल सस्ते समय की दरों पर विचार किया जाता है और सभी अतिरिक्त प्रभारों की अनदेखी की जाती है। चूंकि पीईए थाईलैंड के अस्थायी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिए विनियामक प्राधिकरण है, अतः कोई अन्य निर्धारण नहीं हो सकता।

- Ivii. कार्यक्रम का लाभ न लेने के कारण देने की एएससीएम के तहत कोई आवश्यकता नहीं है।
- Iviii. मलेशिया के उत्तरदाता निर्यातकों ने अनुरोध किया कि एएससीएम और सीबीडी नियमावली के अनुसार पक्षकारों को किसी जांच में ली गई सब्सिडी के ब्यौरे देने चाहिए और किसी कोई यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि विशेष कार्यक्रम का प्रयोग क्यों नहीं किया गया था, माना क्योंकि ऐसे सभी कार्यक्रमों को लेने के लिए पक्षकारों के लिए कोई अधिदेश था।
- Ix. प्रकटन विवरण में मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 7 के लिए सब्सिडी मार्जिन नगण्य है। उसके लिए किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम में किसी विशिष्टता की आवश्यकता नहीं है अथवा निर्यात आकस्मिक हैं और इसीलिए प्रतिकार योग्य नहीं हैं।
- Ix. प्रकटन विवरण में योजनाओं के प्रयोग के आधार पर मात्राकरण निहित है और जांच का प्रयोजन कार्यक्रम के वास्तविक प्रयोग को ध्यान में न रखते हुए मार्जिन का ब्लैकेट निर्धारण नहीं है।
- Ixi. मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 9 के लिए, पूँजी भत्ता न तो विशिष्ट है और न निर्यात आकस्मिक। मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 12 में विशिष्टता की आवश्यकता नहीं है अथवा निर्यात आकस्मिक है और इसीलिए प्रतिकार योग्य नहीं हैं। मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 9 और 12 के लिए, निर्धारित सब्सिडी मार्जिन कंपनी के दावे से अधिक है।
- Ixii. एएससीएम की पाद टिप्पणी 1 का अनुपालन करते हुए, कार्यक्रम संख्या 11 और 13 सब्सिडी होने के लिए मान्य नहीं होंगे।
- Ixiii. मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 20 के लिए, रबर वुड संगत कानून के तहत "वन उत्पाद" की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। रबर वुड पर कोई रॉयल्टी एकत्रित नहीं की जाती और इसीलिए कोई छूट संभव नहीं है।
- Ixiv. मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 22 के लिए, उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोई लाभ नहीं लिया जाता है। उत्तरदाता ने खरीद के मामले में विद्यमान दरों के अनुसार विद्युत दरों का भुगतान किया और वे कीमतें सब्सिडीयुक्त कीमतें नहीं हैं। कंपनी की यूटिलिटी खपत छूट हमारी लागत रिकॉर्ड का भाग है और हम अपनी विद्युत कीमत का संबंध उससे नहीं बना सकते, जिसका यहां दावा किया गया है। प्रकटन पश्चात स्तर मलेशियाई विद्युत प्रशुल्क संबंधी सूचना एकत्रित करने का स्तर नहीं है।
- Ixv. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 3 के लिए, ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी भी दशा में कार्यक्रम लेने के लिए अधिदेशित करे। वियतनाम के लिए कार्यक्रम 3 के तहत कोई प्रतिकारी शुल्क का लाभ नहीं दिया गया है। देय आयात शुल्क शून्य था और इसीलिए इस कार्यक्रम के तहत कोई राजस्व परित्यक्त नहीं है। एफटीए के तहत लाभ पर प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- Ixvi. एमडीएफ वीआरजी ने वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 4 के तहत कोई लाभ नहीं लिया है।
- Ixvii. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 6 के तहत किम टिन द्वारा कोई लाभ नहीं लिया गया था क्योंकि पूरे किराये का भुगतान किया गया था। प्रकटन विवरण में कार्यक्रम के लिए मार्जिन कंपनी के दावे से अधिक है।
- Ixviii. कार्यक्रम संख्या 8 के तहत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई लाभ नहीं लिया गया था। इस कार्यक्रम के तहत कोई लाभ नहीं लिया जाता है क्योंकि दीर्घावधि ऋण के लिए ब्याज दर वियतनाम में विद्यमान ब्याज दर के बराबर है और विश्व बैंक के अंकड़ों के अनुसार है। अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज दर वैश्विक रूप से कम है और कोई सब्सिडी नहीं मानी जा सकती। ब्याज पर कोई प्रतिपूरक व्यवस्थाएं विद्यमान नहीं हैं।
- Ixix. वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 8 और 10 के तहत कोई प्रतिकारी योग्य लाभ नहीं दिया जाता है। डब्ल्यूटीओ में वियतनाम की व्यापार नीति की समीक्षा सब्सिडी निर्धारित करने के लिए कानूनी आधार नहीं हो सकती। प्रस्तुत साक्ष्य का स्थानीय खरीद से कोई संदर्भ नहीं है।

- Ixx. डीजीटीआर वित्तीय अंशदान, सरकारी दायित्व और कार्यक्रम में विशिष्टता की मौजूदगी सिद्ध करने में विफल रहा है।
- Ixxi. जांच के अंतिम चरण में निर्धारण के संबंध में नए दावे और साक्ष्य लाना याचिकाकर्ताओं द्वारा उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है।
- Ixxii. उत्तरदाताओं को कभी सूचित नहीं किया गया था कि नए सब्सिडी आरोपों की जांच की जा रही है और इसीलिए उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। यह सीवीडी नियमावली के नियम 7(4) और एएससीएम के अनुच्छेद 12.1 का उल्लंघन है। यूएस – पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क (चीन) तथा चीन – ब्रॉयलर उत्पाद (अनुच्छेद 21.5 – यूएस) में पैनल रिपोर्टों पर विश्वास किया जाता है।
- Ixxiii. इस कार्यक्रमों के संबंध में सत्यापन के दौरान किसी सूचना की मांग नहीं की गई थी और आरोपों खंडन करने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया था। आरोप अस्पष्ट और असिद्ध हैं। कोई साक्ष्य नहीं दिए गए थे।
- Ixxiv. नए सब्सिडी आरोपों के संबंध में संबद्ध देशों की सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था जो कि एएससीएम के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन है।
- Ixxv. नए दावे शुरू करने के लिए लिखित अनुरोधों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- Ixxvi. उत्तरदाताओं ने ऐसी कोई सब्सिडी नहीं ली है और इसीलिए उन्होंने अपनी प्रश्नावली के उत्तरों में उन्हें शामिल नहीं किया।
- Ixxvii. न्यूजीलैंड को उपयुक्त निर्धारण चुनने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यूएस – कार्बन स्टील (इंडिया) में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के अनुरूप निर्धारण के विकल्प का कारण दें। उत्तरदाता संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए अपने इनपुट के रूप में टिम्बर का प्रयोग नहीं कर रहा है। रबर वुड/रबर वुड बेस्ट के लिए निर्धारण के रूप में टिम्बर कीमतों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड सरकार सभी फसली वन पर नियंत्रण रखती है और न्यूजीलैंड से भारत को वुड की निर्यात कीमत बाजार वनों के अनुसार निर्धारित नहीं की जाती है। न्यूजीलैंड वुड कीमतों की तुलना रबर वुड से नहीं की जा सकती क्योंकि गैर-बारीकी और वानिकी वुड भिन्न हैं। एमडीएफ विनिर्माता भी आरा मिलों से अपशिष्ट का प्रयोग करते हैं। रबर वुड हार्डवुड प्रजाति है जबकि न्यूजीलैंड का पाइन आदि सॉफ्टवुड प्रजाति है। याचिकाकर्ता अतुलनीय की तुलना करने का प्रयास कर रहा है।
- Ixxviii. भारतीय रबर वुड कीमतों का प्रयोग उपयुक्त निर्धारण नहीं होगा क्योंकि कमी के कारण कीमतें अधिक हैं। निर्धारण कीमत इस बात को ध्यान में रखते हुए समायोजित की जानी चाहिए कि उत्तरदाता ने रबर वुड के अपशिष्ट और/अथवा अवशेष का ही प्रयोग किया है। न्यूजीलैंड अथवा अन्य उपयुक्त देश से थाईलैंड को लाँग कीमतें थाईलैंड के लिए उपयुक्त निर्धारण होता।
- Ixxix. घरेलू उद्योग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक निर्धारण अपर्याप्त हैं। ये निर्धारण निर्यातक देश की विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुरूप होने चाहिए और किसी तीसरे देश में कड़ी सामग्री की कीमत के आधार पर नहीं होने चाहिए।
- Ixxx. उत्तरदाता को असहयोगी मानना और उपलब्ध तथ्यों को लागू करना सीवीडी नियमावली और एएससीएम के विरोध में है। यह व्यवहार तभी किया जा सकता है, यदि पक्षकार सूचना देने से इंकार करे जो स्थिति वर्तमान मामले में नहीं थी।
- Ixxxii. तथाकथित विद्युत सब्सिडी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए निर्धारण के लिए, जिस अवधि के लिए कीमतों का संबंध है, वह भी स्पष्ट नहीं है।
- Ixxxii. निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम होल्डर टोपसो में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर घरेलू उद्योग का विश्वास त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें उल्लेख है कि सूचना देने का दायित्व तभी लागू होता है, यदि पक्षकार के पास साक्ष्य हो। जब कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया है तो प्रकट किए जाने के लिए कोई सूचना नहीं है।

Ixxxiii. सब्सिडी मार्जिन का परिकलन और उसके लिए आधार प्रदान न करने के लिए कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वे कंपनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हैं। स्टरलाईट इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास किया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

41. यहां तक जांच प्रक्रिया के दौरान पता लगाई गई नई/अतिरिक्त सब्सिडी योजनाओं की जांच के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि मूल प्रश्नावली में विशेष रूप से "अन्य सब्सिडी योजनाओं" के संबंध में विस्तृत अनुबंध निहित था और यह भी अनुदेश दिया गया था कि "प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, यहां तक कि उनमें से कुछ आवेदक द्वारा सूची में नहीं दिए गए हैं, परन्तु संबद्ध देश में विद्यमान हैं, तो उत्तरदाता पक्षकार को प्रश्नों का पूरा उत्तर देना चाहिए, यहां तक कि यदि संबद्ध देश की सरकार यह माने कि वह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है।" यही बात अतिरिक्त प्रश्नावली में भी दोहराई गई थी जो तथाकथित अतिरिक्त/नई सब्सिडी योजनाओं के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। अतः, प्राधिकारी ने उचित प्रक्रिया अपनाई है और हितबद्ध पक्षकारों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए पूरा अवसर दिया गया था।
42. ऐसे अवसर हो सकते हैं जब प्राधिकारी संबद्ध देश (देशों) में कुछ अतिरिक्त सब्सिडी योजनाएं पाएं, यद्यपि जांच की शुरूआत की अधिसूचना में उनका विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। उत्तरदाता सरकारों और संबद्ध देशों के नियांत्रिकों/उत्पादकों का दायित्व वर्तमान जांच से संबंधित संबद्ध देशों में विद्यमान सभी योजनाओं के संबंध में प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना देना था, जिससे प्राधिकारी उचित निष्कर्ष पर पहुँच सकें, विशेष रूप से जब उपर्युक्त सूचना यह उल्लेख करते हुए विशेष रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में मूल प्रश्नावली के माध्यम से मांगी गई थी कि "प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, यहां तक कि उनमें से कुछ आवेदक द्वारा सूची में नहीं दिए गए हैं, परन्तु संबद्ध देश में विद्यमान हैं, तो उत्तरदाता पक्षकार को प्रश्नों का पूरा उत्तर देना चाहिए, यहां तक कि यदि संबद्ध देश की सरकार यह माने कि वह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है।" और "पूर्ण उत्तर के अभाव में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।" तथापि, सूचना प्रदान करने के बजाए हितबद्ध पक्षकारों ने इसका भार प्राधिकारी पर डालना सुविधाजनक पाया। ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना की ओर जाना पड़ा था और तदनुसार संबंधित देशों में विद्यमान वुड, भूमि, जल, कोयला, विद्युत आदि के रूप में एलटीएआर कार्यक्रमों के लिए संगत सब्सिडी मार्जिन परिकलित करते हैं।
43. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक निर्धारणों के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:
 - क) संबद्ध देशों से नियांत कीमतों को निर्धारण के रूप में विचार करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि उनकी घरेलू कीमत सरकारी नियंत्रण के कारण है, जैसा कि नीचे संगत पैराग्राफों में जांच की गई।
 - ख) इंडोनेशिया में निजी पक्षकारों द्वारा दी गई रबर वुड की कीमतें इस कारण नहीं अपनाई जा सकतीं कि उन्हें भी समान हास से ज्ञात होती है, जैसा कि अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में पाया जाता है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि इंडोनेशिया में घरेलू वानिकी बाजार का हास हुआ है।
 - ग) भारत में निर्धारण के रूप में रबर वुड की कीमतें उपयुक्त नहीं मानी गई थीं। भारत में इस प्रकार के वुड की उपलब्धता सीमित है और परिणामी कीमत अधिक है।
 - घ) वुड/टिम्बर/लॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें नहीं अपनाई जाती हैं क्योंकि निर्धारण को उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त वुड की किस्म की कीमतें दर्शानी चाहिएं।
44. न्यूजीलैंड में काफी वन हैं और वह पूरे विश्व में वुड की काफी मात्रा का नियांत भी करता है। न्यूजीलैंड में आर्कषक वानिकी पौधारोपण का 95 प्रतिशत निजी स्वामित्व में है और नियांत न्यूनतम है। क्राउन वन भूमि में फसलीकरण के लिए लगाया गया लाइसेंस शुल्क बाजार दर के अनुसार है। इसके अतिरिक्त, जिस कीमत पर न्यूजीलैंड ने वुड का नियांत किया है, वह अन्य उपलब्ध विकल्पों से तुलना करने पर उपयुक्त पाई गई है। इस प्रकार न्यूजीलैंड एएससीएम के अनुच्छेद 14(घ) के अनुसार एलटीएआर पर विदेशी उत्पादकों को उपलब्ध लॉग/टिम्बर/वुड में लाभ के मात्राकरण के लिए उपयुक्त निर्धारण माना जाता है।

परिकलन पद्धति

45. एएससीएम के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 1 के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में प्रदान किया गया प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए दिशानिर्देशों एवं पद्धति का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त कोई भी पद्धति पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगी। इसके अतिरिक्त, प्राप्तकर्ता को लाभ का परिकलन करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयुक्त किसी भी पद्धति में संबंधित सदस्य के कार्यान्वयन विनियम अथवा उनके राष्ट्रीय कानून में प्रावधान होगा तथा प्रत्येक विशेष मामले पर उसका अनुप्रयोग पारदर्शी और पर्याप्त रूप से स्पष्ट होगा। इस अपेक्षा के अनुसार, सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 में सब्सिडीकरण की मात्रा के निर्धारण की पद्धति निर्धारित है। इस जांच में निर्धारण इन दिशानिर्देशों के अनुसार है।

छ.3 याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

इंडोनेशिया

(i) कार्यक्रम संख्या 1 : पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए खड़े टिम्बर का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

46. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम का संचालन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंडोनेशिया सरकार लगभग पूरी (88 प्रतिशत) फसल योग्य वन भूमि पर नियंत्रण रखती है और कंपनियों को लॉगिंग अधिकारों पर पट्टे पर देती है जिस पर वुड की फसल करने के अधिकार के स्टम्पेज दर लगाई जाती है। इंडोनेशिया सरकार द्वारा लगाई गई स्टम्पेज दर स्टम्पेज के मूल्य से कहीं कम है।
47. इसके अतिरिक्त, "टिम्बर" शब्द किसी विशेष प्रकार के वुड तक सीमित नहीं है। रबर वुड जैसे ट्रोपिकल वुड इस शब्द के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के वुड टिम्बर हैं। हितबद्ध पक्षकार गलत प्रस्तावित कर रहे हैं कि टिम्बर का अर्थ बाजार फर्नीचर के लिए सीधे ही जाने वाला केवल हार्डवुड अथवा वुड है। वस्तुतः पर्यावरणीय चिंताओं के कारण टिम्बर उपकरणों के लिए रबर वुड सर्वोत्तम विकल्प है। फाइबर अथवा पेपर से उत्पाद का उत्पादन पूरी तरह से नकारा जाता है।
48. यद्यपि कच्ची सामग्री वुड/लॉग्स निजी पौधारोपण से खरीदे जा सकते हैं, तथापि सरकारी हस्तक्षेप का स्तर इंडोनेशिया में पूरे टिम्बर बाजार को हास की स्थिति में रखता है। निजी कंपनियों से टिम्बर की खरीद करना यह सिद्ध नहीं करता कि उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। यद्यपि इंडोनेशिया सरकार तथा उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने उल्लेख किया है कि वह अपनी कच्ची सामग्री लेने के लिए निजी पौधारोपण पर विश्वास करते हैं, तथापि इस कार्यक्रम के माध्यम से लॉगिंग उद्योग में सरकार द्वारा किया गया प्रभावी रोल कृत्रिम रूप से दरों को भी कम करता है। निजी पौधारोपण की कीमतें भी सब्सिडीयुक्त हैं, जब अधिकतर बिक्री सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाले पक्षकारों द्वारा हैं। "इंडोनेशिया से कोटेड फ्री शीट पेपर" और "इंडोनेशिया से सरटेन अनकोटेड पेपर" के मामले में यूएसडीओसी द्वारा किए गए विश्लेषण पर विश्वास करना उपयुक्त है।
49. इंडोनेशियाई टिम्बर बाजार की शर्तों के कारण उत्तरदाता निर्यातकों के लिए इस कार्यक्रम को न लेना लगभग असंभव है। पूर्ण बाजार में कीमत उस स्थिति में हास होने के लिए बाध्य है, जहां अधिकतर विक्रेता सरकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले हैं और ये लेवल वाले निजी पक्षकार इन इनपुट के अल्पसंख्यक आपूर्तिकर्ता हैं। ऐसी स्थिति में, देश से बाहर के निर्धारण अथवा अंतर्राष्ट्रीय निर्धारण पर विश्वास करना ही एकमात्र विकल्प है।
50. यह सब्सिडीरोधी जांचों के माध्यम से कई अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा पाया गया था। अतः फाइबरबोर्ड उद्योग के लिए कच्ची सामग्री पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर (एलटीएआर) दी जाती है। इस कार्यक्रम में एलटीएआर पर सामानों के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत लाभ उन निचले स्तर के उद्योगों को भी उपलब्ध कराया जाता है जो अपनी कच्ची सामग्री के रूप में टिम्बर/वुड का प्रयोग करते हैं।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

51. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि स्थायी टिम्बर नीति में किसी भी रूप में उत्तरदाता कंपनियों को कोई वित्तीय अंशदान अथवा लाभ दिए जाने का प्रावधान नहीं है और इसीलिए एएससीएम के तहत प्रतिकार योग्य नहीं है। खड़े टिम्बर का शुल्क केवल सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर लागू है, न कि निजी पौधारोपण पर जिससे उत्तरदाता कंपनियां अपनी कच्ची सामग्रियां लेती हैं।
52. निर्यातक निजी पौधारोपण से फसलीकृत छोड़ दिए गए/अपशिष्ट आदि का प्रयोग कर रहे हैं, न कि टिम्बर का। वे छोड़े गए अपशिष्ट का प्रयोग करते हैं। इंडोनेशिया में रबर वुड का प्रयोग फाइबरबोर्ड में किया जाता है। अतः यह कार्यक्रम लागू नहीं है। आवेदक द्वारा उल्लिखित कोई भी मामला एमडीएफ से संबद्ध नहीं है। टिम्बर का प्रयोग उच्च लागत के कारण एमडीएफ में नहीं किया जाता है। निर्यातक सरकारी वन की बजाए निजी पौधारोपणों पर ही उगाए गए आरएम (रबर वुड) की खरीद करते हैं।
53. वन अधिनियम के अनुसार स्थायी टिम्बर नीति में किसी भी रूप में उत्तरदाता कंपनियों को कोई वित्तीय अंशदान अथवा लाभ दिए जाने का प्रावधान नहीं है और इसीलिए एएससीएम के तहत प्रतिकार योग्य नहीं है। खड़े टिम्बर का शुल्क केवल सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर लागू है, न कि निजी पौधारोपण पर जिससे उत्तरदाता कंपनियां अपनी कच्ची सामग्रियां लेती हैं।
54. निर्यातकों ने अनुरोध किया कि वे टिम्बर वुड अथवा किसी संबद्ध उत्पाद का प्रयोग नहीं करते। यह कार्यक्रम केवल "खड़े टिम्बर" अथवा "टिम्बर वुड" से संबंधित है। उत्तरदाता पक्षकार ने निजी पौधारोपण से रबर वुड/रबर वुड अपशिष्ट की खरीद की है जो कि प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है और इसीलिए यह योजना लागू नहीं होगी।
55. मंत्री विनियम संख्या 66/मेनएलएचके/सेटजेन/कुम1/10/2019 के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन लाइसेंसधारक को प्राकृतिक वन से फसलीकृत वुड उत्पाद का रिकॉर्ड रखने और सूचित करने के लिए अधिदेशित करता है। वन उत्पादों के आयात व्यापार मंत्री के विनियम संख्या 82/2019, व्यापार मंत्री के विनियम 13/2018 के साथ पठित व्यापार मंत्री के विनियम संख्या 91/2017 के साथ पठित व्यापार मंत्री के विनियम संख्या 97/2015 द्वारा विनियमित किए जाते हैं। वन उत्पादों के आयात के लिए व्यक्ति को एसवीएलके प्रमाण-पत्र, संधारणीयता, और उत्पाद की वैधता से युक्त आयात घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। गैर-सरकारी वन से खपत एसवीएलके प्रमाणन और भूमि करार के माध्यम से दी जाती है जो कंपनियों द्वारा दी जाती है।
56. जांचाधीन उत्पादक के लिए फाइबरबोर्ड का उत्पादन करने के लिए इनपुट के रूप में रबर वुड अपशिष्ट/अवशेष के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आपूर्तिकर्ताओं की सूची इंडोनेशिया सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, सूची सहयोगी उत्पादकों से प्राप्त की जा सकती है जो आपूर्तिकर्ताओं के साथ कार्य करते हैं। रबर वुड अपशिष्ट की कीमतें रबर वुड अपशिष्ट संग्रहकर्ता/विक्रेता/क्रेता के बीच निर्धारित की जाती हैं और इसीलिए व्यापार-दर-व्यापार लेन-देन है। इंडोनेशिया सरकार निर्धारण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। रब वुड अपशिष्ट की कीमत विक्रेता और क्रेता के बीच वार्ता पर निर्भर करती है। कीमत संबंधी सूचना इंडोनेशिया सरकार द्वारा विनियमित नहीं की जाती है, अतः उत्तरदाता निर्यातक अपनी बातचीत के आधार पर तय अथवा निजी आपूर्तिकर्ताओं के साथ लेन-देन की गई कीमतों के संबंध में ही सूचना प्रदान कर सकते हैं।
57. इंडोनेशिया सरकार उपर्युक्त सामान/सेवाएं प्रदान नहीं करती और इसीलिए तुलनीय कीमतों का प्रश्न नहीं उठता।

(ii) कार्यक्रम संख्या 2 : लॉग निर्यातों का सरकारी प्रतिबंध

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

58. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम का संचालन वित्त मंत्रालय और उद्योग तथा व्यापार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दोनों मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से एक डिक्री जारी की जिससे इंडोनेशिया से लॉग्स का निर्यात प्रतिबंधित हुआ। इससे घरेलू बाजार और निर्माण वुड का ह्लास हुआ जो कि एलटीएआर पर निचले स्तर के उद्योगों को उपलब्ध फाइबरबोर्ड उद्योग में कच्ची सामग्री है। इस कार्यक्रम में एलटीएआर पर सामानों के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत लाभ उन निचले स्तर के उद्योगों को ही उपलब्ध कराया जाता है जो अपनी कच्ची सामग्री के रूप में टिम्बर/वुड का प्रयोग करते हैं।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

59. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि वन औद्योगिक उत्पादों के निर्यात संबंधी प्रावधान इंडोनेशियाई वनों की सुरक्षा और संधारण के उपाय के रूप में अधिक फसल और अवैध लॉगिंग को रोकने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए लागू किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यात प्रचलन में कोई वित्तीय अंशदान नहीं है, जैसा कि यूएस-निर्यात प्रतिबंध (डीएस 194) में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा माना गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता निर्यातकों ने अपनी कड़ी सामग्री निजी पौधारोपण से ली।
60. निर्यातक निजी पौधारोपण से फसलीकृत छोड़ दिए गए/अपशिष्ट आदि का प्रयोग कर रहे हैं, न कि टिम्बर का। अतः कार्यक्रम लागू नहीं है। आवेदक द्वारा उल्लिखित कोई भी मामला एमडीएफ से संबद्ध नहीं है। टिम्बर का प्रयोग उच्च लागत के कारण एमडीएफ में नहीं किया जाता है। इंडोनेशिया एक वन समृद्ध देश है और छोड़े गए लॉग्स, अपशिष्ट आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। निर्यात प्रतिबंध का प्रयोजन अवैध लॉगिंग को नियंत्रित करने, संसाधनों का संरक्षण करने और पर्यावरण की सुरक्षा करना था, न कि स्टम्पेज शुल्क एकत्रित करना था। बाजार ह्लास दर्शने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम संख्या 1 और 2 इंडोनेशिया में वन क्षेत्र को विनियमित करने, मॉनीटर करने और नियंत्रित करने के लिए इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए कई उपायों से संबंधित है। चूंकि इन कार्यक्रमों के प्रभाव से उपलब्ध कराए जा रही विचाराधीन उत्पाद की कड़ी सामग्री पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर हैं, अतः प्राधिकारी ने इन कार्यक्रमों को मिलाया है और वर्तमान जांच के लिए सामूहिक रूप से उसकी जांच की।
62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया सरकार के पास देश में अधिकतर फसल योग्य वन भूमि है और उसका खड़े टिम्बर के लिए बाजार में पूर्व प्रभावी भूमिका है। विनियम संख्या 09/एम-डीएजी/पीईआर/2/2012 के अनुसार, बुड़ के लिए मानक कीमत सरकार द्वारा आवधिक रूप से निर्धारित की जाती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध विभिन्न विनियम इंडोनेशिया में खड़े टिम्बर की फसल के लिए शुल्कों के प्रकार और निर्धारित रॉयल्टी उल्लिखित करते हैं। तथापि, कंपनियों को इन वनों से टिम्बर लेने के लिए लॉगिंग अधिकार दिए जाते हैं। इसके बदले सरकार दो प्रकार के स्टम्पेज शुल्क एकत्रित करती है; यथा प्रोविसी सुम्बर डाया हुटन (वन संसाधनों के लिए प्रावधान – पीएसडीएच) और डाना रेबोइसासी (पुनः पौधारोपण निधि – डीआर)। तथापि, उत्तरदाता निर्यातकों ने उल्लेख किया है कि स्टम्पेज शुल्क देना उनका दायित्व नहीं है क्योंकि वे कड़ी सामग्री की खरीद निजी पौध लगाने वालों से ले रहे हैं।
63. जहां तक लॉग निर्यातों के सरकारी प्रतिबंध का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उपर्युक्त कार्यक्रम का संचालन वित्त मंत्रालय और उद्योग तथा व्यापार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन दोनों मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से एक डिक्री जारी की जिससे इंडोनेशिया से लॉग्स का निर्यात प्रतिबंधित हुआ। सरकार और उत्तरदाता निर्यातकों ने उल्लेख किया है कि निर्यात प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण पर्यावरण और पारिप्रणाली का संरक्षण है ताकि अवैध लॉगिंग नियंत्रित की जा सके और संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। राउंड (अप्रसंस्कृत) लॉग निर्यातों पर प्रतिबंध प्रकट रूप से अधिक दोहन की समस्या हल करने के लिए 2001 में पुनः लगाया गया था।
64. इंडोनेशिया सरकार द्वारा किए गए अनुरोध यह सिद्ध करते हैं कि इंडोनेशियाई बुड़ उत्पाद की फसल प्राकृतिक वनों से की जाती है। इंडोनेशिया सरकार के कई विनियम यह बताते हैं कि वन सरकार के नियंत्रण में हैं। साथ ही, इंडोनेशियाई सरकार ने लॉग निर्यातों को हतोत्साहित करने अथवा प्रतिबंधित करने के लिए नीति संबंधी उपाय लगाए हैं। इसका उद्देश्य इंडोनेशिया के भीतर प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना रहा है।
65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि ये प्रतिबंध (और अन्य निर्यात प्रतिबंध) किसी हद तक इंडोनेशिया के वनों का अति दोहन रोक सकते हैं, परन्तु लॉग की घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण भी करते हैं जिससे उन उत्पादों के निचले स्तर के प्रसंस्करणकर्ताओं को सहायता मिलती है जिससे सब्सीडीकरण होता है।
66. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा लगाए गए लॉग्स निर्यात प्रतिबंध के माध्यम से इंडोनेशिया सरकार घरेलू वानिकी/फसल कंपनियों को निचले स्तर के उद्योगों में कंपनियों तथा निजी संस्थानों को कम कीमत वाले इनपुट (लॉग/बुड़) देने के लिए कार्य सौंप रही है/निर्देश दे रही है। विशेष रूप से लॉग निर्यात

प्रतिबंध से जांचाधीन कंपनियों को वानिकी/फसल कंपनियों से बाजार कीमतों से कम पर इनपुट (लॉग/वुड) खरीदने की अनुमति मिली है। जिस प्रतिबंध से लॉग आपूर्तिकर्ता न्यूनीकृत कीमतों पर घरेलू तौर पर लॉग बेचने के लिए प्रेरित हुए हैं, उससे इंडोनेशिया के निचले स्तर के वुड प्रसंस्करणकर्ता उद्योग लाभान्वित हुए हैं और लॉग की कीमतें कम हुई हैं।

67. इन कार्यक्रमों में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर सामानों के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। ये कार्यक्रम विशिष्ट भी हैं क्योंकि वे उन निचले स्तर के उद्योगों को लाभान्वित करते हैं जो अपनी प्राथमिक कद्दी सामग्री के रूप में लॉग्स/वुड का प्रयोग करते हैं। अतः ये कार्यक्रम यथा तथ्यतः सीमित उद्योगों को ही उपलब्ध हैं। अतः, प्राधिकारी उपर्युक्त दोनों कार्यक्रमों को प्रतिकार योग्य मानते हैं।
68. यद्यपि आवेदक ने उल्लेख किया है कि न्यूजीलैंड से भारत को लॉग्स के निर्यात का प्रयोग एक उपयुक्त निर्धारण है। तथापि उन्होंने वैकल्पिक निर्धारण का भी सुझाव दिया है, यथा - (क) संबद्ध देश में उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त समान किस्म के वुड की निर्यात कीमत, (ख) कद्दी सामग्री (वुड) की घरेलू उद्योग द्वारा उनके खपत मानदंड के साथ उच्चतम/औसत लागत, (ग) विश्व व्यापार एटलस से उपलब्ध वुड/टिम्बर/लॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अथवा (घ) संबद्ध देशों, जिनमें ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, को छोड़कर भारत को संबद्ध सामानों के प्रमुख निर्यातकों से वुड/टिम्बर/लॉग की कीमतें।
69. उत्तरदाता निर्यातक ने तर्क दिया है कि वो रबर वुड के छोड़े गए/अवशिष्ट का प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत में रबर वुड की कीमतों और अवशिष्ट/अवशेष की कीमत के अनुपात के आधार पर अवशिष्ट/अवशेष की अनुमानित कीमत तथा नए लॉग की कीमत पर विचार किया जाए। रबर वुड के अवशिष्ट/अवशेष का उचित बाजार मूल्य निकालने के लिए भारतीय रबर वुड की कीमतों पर वही अनुपात लागू किया जाए।
70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बचे हुए/शेष लकड़िया हैं जिन्हें प्रमुख रूप से बहुत अधिक उप्र के रबड़ के पेड़, जो एमडीएफ के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले और लेटेक्स, डीबार्क्ड किए जाने में अब सक्षम नहीं हैं, से प्राप्त किया जाता है। रबड़ की ऐसी लकड़ी का रबड़ के उद्योग में कोई उपयोग नहीं होता है लेकिन उसका उपयोग फाइबर बोर्ड उद्योग में किया जा सकता है। अतः इस प्रकार की अपशिष्ट/शेष/बचे हुए रबड़ की लकड़ी की कीमतें रबड़ की लकड़ी के लाग्स की तुलना में कम हैं। इंडोनेशिया के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि वे रबड़ की लकड़ी के अपशिष्ट/शेष हिस्से का उपयोग कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने इस तथ्य का उचित संज्ञान लिया है और नए लाग्स की कीमतों से अपशिष्ट/शेष लाग्स की कीमतों के अनुपात के आधार पर लाग्स की अनुमानित कीमत पर विचार किया है। उसके बाद इसकी तुलना प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई बेंचमार्क से की गई थी।
71. सब्सिडी की मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने उपयुक्त बेंचमार्क की तलाश की जिसके द्वारा यह पाया गया था कि न्यूजीलैंड वैश्विक स्तर पर लाग्स के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। प्राधिकारी ने न्यूजीलैंड से आयात कीमत की तुलना में एक अधिक उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में न्यूजीलैंड से लाग्स की निर्यात कीमत पर विचार किया। उपयुक्त परिवर्तन दरों पर विचार करते हुए, निर्धारित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

(iii) कार्यक्रम संख्या 3 : इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा निर्यात सुविधा के लिए लाभ

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

72. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम असुरांसी एक्सपोर इंडोनेशिया (एएसईआर्ड) और इंडोनेशिया एक्जिम बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, इंडोनेशिया सरकार अपने सरकारी स्वामित्व वाली बैंकों एएसईआर्ड और इंडोनेशिया एक्जिम बैंक के माध्यम से निर्यात ऋण गारंटी प्रदान करती है जो बैंकों को निर्यात वित्तपोषण के लिए लगाई गई दरों कम करने की अनुमति देते हैं। इस कार्यक्रम में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो कि निर्यात ऋण गारंटी लेते समय निर्यातकों को उपलब्ध कम उधार दरों और सामान्य उधार दरों के बीच अंतर होता है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल वही

उद्यम पात्र होते हैं जो निर्यात में लगे होते हैं। चूंकि यह कार्यक्रम निर्यात के संबंध में आकस्मिक है, अतः यह विशिष्ट माना जाता है। प्राधिकारी ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड", मलेशिया से "टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास", मलेशिया से "क्लीयर फ्लोट ग्लास", और इंडोनेशिया से "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पाद" के संबंध में सीवीडी जांचों में पूर्व में एकिजम बैंक द्वारा निर्यात सुविधा को प्रतिकार योग्य पाया था। किसी कार्यक्रम का लाभ न लेने से वह गैर-प्रतिकार योग्य नहीं हो जाता।

73. इसके अतिरिक्त, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या उधार स्थानीय मुद्रा में है अथवा विदेशी मुद्रा में है, देश के क्षेत्र में स्थित बैंकों द्वारा राष्ट्र के भीतर अधिमान्य उधार व्यवहार में लाया जाता है। उधार ब्याज दर कंपनी की क्रृष्ण रेटिंग पर निर्भर करती है जिससे उधार तथा निकाय विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं और अधिमान्य क्रृष्ण प्रदान करते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों यथा आईएमएफ अथवा विश्व बैंक द्वारा देश के लिए निर्धारित उधार दरों के साथ तुलना की जाए तो उधार ब्याज दरों हमेशा कम होती हैं। साथ ही, देशों के सेंट्रल बैंक का अधिक निर्धारण है जिसे बैंकों की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जबकि वास्तविक उधार दरों उससे कहीं कम हैं।
74. इस कार्यक्रम की जांच प्राधिकारी द्वारा पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में की गई थी और प्रतिकार योग्य पाया गया था।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

75. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि इंडोनेशिया एकिजम बैंक सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली विशेष वित्तीय संस्था है और अधिनियम संख्या 2/2009 के तहत स्वतंत्र रूप से प्रचालन करती है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 7 के अनुसार, परियोजना निष्पादन से संबंधित इंडोनेशिया निर्यातकों, विदेशी आयातकों और टेंडर्स को गारंटी प्रदान करना बैंक का एक प्रमुख क्रियाकलाप है। यह कार्यशील पूंजी और/अथवा निवेश के रूप में वित्तपोषण प्रदान करता है। पात्रता मानदंडों को शासित करने वाला कोई कानून अथवा विनियम नहीं है। पात्रता बैंक का एक आंतरिक प्रक्रियात्मक मामला है। इसके अतिरिक्त, 2017-18 की अवधि में एकिजम बैंक और बैंक मंत्री ने सेंट्रल बैंक से कम दर पर ब्याज दरों नहीं दी हैं।
76. यह अनुरोध किया गया है कि यह कार्यक्रम लागू नहीं है क्योंकि एकिजम बैंक से कोई क्रृष्ण नहीं लिए गए हैं। इस दावे की जांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों में क्रृष्ण सूचना से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एकिजम बैंक द्वारा निर्यात सुविधा प्राधिकारी द्वारा पूर्व में गैर-प्रतिकार योग्य मानी गई थी।
77. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि पीटी. बैंक नेगारा इंडोनेशिया (बीएनआई) एक वित्तीय संस्था है जो लाभ के आधार पर प्रचालन करती है और यह उपभोक्ताओं को विद्यमान बाजार दर पर ब्याज से स्वतंत्र रूप से क्रृष्ण प्रदान करती है जो कि बैंक ऑफ इंडोनेशिया की दर (सेंट्रल बैंक) से अधिक है।
78. प्रकटन विवरण के अनुसार प्राधिकारी ने दावा किया कि बीएनआई एक सार्वजनिक निकाय है, मात्र इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया सरकार का 2019 के अनुसार बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सा है। डब्ल्यूटीओ एबी जांच परिणाम – पाठनरोधी एवं प्रतिकारी शुल्क (चीन) के अनुसार "मात्र स्वामित्व अथवा नियंत्रण से सार्वजनिक निकाय नहीं बनता"। इंडोनेशिया सरकार ने उल्लेख किया कि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।
79. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना कि बीएनआई बैंक से लिया गया क्रृष्ण सब्सिडी नहीं माना जा सकता, यह अनुरोध है कि एमपीआई ने सभी क्रृष्ण बाजार निर्धारित वाणिज्यिक दरों पर लिए हैं। यह नोट किया जाए कि उत्तरदाता ने स्थानीय तथा विदेशी मुद्राओं, दोनों में क्रृष्ण बाजार निर्धारित वाणिज्यिक दरों पर लिए थे। यहां तक कि यदि इंडोनेशियाई बैंक को "सार्वजनिक निकाय" माना जाए तो माने गए निर्धारण केवल उन मुद्राओं के लिए है जिनमें क्रृष्ण लिया गया है। चूंकि उत्तरदाता द्वारा क्रृष्ण का काफी भाग अमेरिकी डॉलर में है, अतः स्थानीय मुद्रा क्रृष्ण के लिए लागू दर लागू नहीं की जा सकती। यह भी नोट किया जाए कि विदेशी मुद्रा क्रृष्णों के लिए ब्याज दर पूर्णतः विदेशी बैंक से लिए गए क्रृष्णों के लिए अन्य उत्तरदाता द्वारा दी गई ब्याज दर से तुलनीय है। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा क्रृष्ण में भी स्थानीय मुद्रा ब्याज दर लगाना पूर्णतः गलत और त्रुटिपूर्ण माना जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

80. यह नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम इंडोनेशिया गणराज्य की डिक्री सं. 366/के.एम.के.06/2009 तथा अधिनियम संख्या 2/2009 के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह बैंक पूर्णतः इंडोनेशिया सरकार के स्वामित्व में है और सरकारी प्राधिकार का प्रयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य इंडोनेशियाई निर्यातकों की सहायता करना है। कार्यशील पूँजी और/अथवा निवेश सुविधाओं के रूप में घरेलू वित्तपोषण सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
81. यह नोट किया जाता है कि उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा एकिजम बैंक से कोई ऋण नहीं लिया गया था, जैसा कि उनके द्वारा उनके प्रश्नावली के उत्तर में अनुरोध किया गया है।
82. उत्तरदाता निर्यातकों ने अपने अनुरोधों में स्पष्ट किया है कि ब्याज दरों के लिए माने गए निर्धारण उन मुद्राओं में ही होने हैं, जिनमें ऋण लिया गया है।
83. प्राधिकारी उत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों, दोनों द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में नोट करते हैं कि पीटी सुमात्रा ने पीटी बैंक नेगारा इंडोनेशिया (बीएनआई) तथा सिंगापुर में स्थित विदेशी बैंक से विदेशी मुद्रा में ऋण लिए हैं। सिंगापुर में बैंक द्वारा लगाए गए दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण की ब्याज दर की तुलना बीएनआई की ब्याज दर से करने पर यह देखा जाता है कि दोनों ब्याज दरें समान और तुलनीय हैं। जहां तक बीएनआई से दोनों उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा लिए गए स्थानीय मुद्रा ऋणों का संबंध है, यह देखा जाता है कि स्थानीय मुद्रा में अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण के लिए दोनों उत्तरदाता निर्यातकों के लिए बीएनआई द्वारा लगाई गई ब्याज दर प्राधिकारी द्वारा अपने पूर्व प्रकटन विवरण में अपनाए गए निर्धारण से तुलनीय है।
84. उपर्युक्त के मद्देनजर दोनों उत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा इंडोनेशियाई और अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों के लिए कोई सब्सिडी घटक नहीं पाया जाता है।
85. अतः, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(iv) कार्यक्रम संख्या 4 : आय कर की कटौती

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

86. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। निवेश के संबंध में इंडोनेशिया गणराज्य के 2007 के कानून संख्या 25 में निश्चित अवधि के भीतर किए गए कुल निवेशों की निर्धारित सीमा तक निवल आय की कटौती सहित विविध रूपों में निवेशों के लिए प्रोत्ताहनों का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 में कई पात्रता मानदंडों का प्रावधान है और उनमें से कम से कम एक का संतोषजनक होना लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल वह उद्यमी पात्र हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

87. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि कर अवकाश में कारपोरेट आय कर कटौती की सुविधा उस मुख्य व्यापारिक क्रियाकलाप से प्राप्त अथवा उस पर लगाए गए आय में प्रदान की जाएगी जो एक अग्रणी उद्योग है। "अग्रणी उद्योग" उस व्यापक अंतर संयोजन वाले उद्योग के रूप में परिभाषित है जो मूल्यवर्धित और उच्च बाह्यता प्रदान करे, नई प्रौद्योगिकी शुरू करे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जिसमें नीतिगत मूल्य हो। कर अवकाश अग्रणी उद्योग के स्तर के लिए पात्र है जिसमें 18 क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, यह सूची पूरी नहीं है। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के अनुमोदन पर कार्यक्रम में वर्तमान में निर्धारित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के लिए अवसर खोलता है। आरंभिक तौर पर पांच वर्ष से 15 वर्षों की अवधि में 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की कारपोरेट आय कर कटौती दी गई थी। अप्रैल, 2018 में उसमें 5 से 20 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत कटौती देने के लिए संशोधन किया गया था। इसमें नवंबर, 2018 में कुल निवेश मूल्य के आधार पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कटौती देने के लिए और संशोधन किया गया था।

88. यह अनुरोध किया गया है कि यह कार्यक्रम लाभ नहीं है क्योंकि कटौती किए गए आय कर से कोई लाभ नहीं लिया गया था। इसकी जांच लेखापरिक्षा रिपोर्ट से की जा सकती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

89. यह नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इंडोनेशिया गणराज्य के 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 के अनुसार पांच वर्षों से 15 वर्षों की अवधि के लिए 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक कारपोरेट आय कर पर कटौती को निवेश मूल्य के आधार पर "अग्रणी उद्योग" को प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में पेरातुरन मेट्रो किंगन रिपब्लिक इंडोनेशियनोमोर 150/पीएमके.010/201 के अनुसार वानिकी क्षेत्र शामिल है। इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान के रूप में देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट है क्योंकि लाभ केवल उन उद्यमों को प्रदान किया जाता है जो "अग्रणी उद्योग" के रूप में योग्य हैं। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य कार्यक्रम मानते हैं।
90. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि उत्तरादात उत्पादकों/नियातकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई अर्हक निवेश किया है। न ही इंडोनेशिया सरकार ने "अग्रणी उद्योग" के रूप में अर्हता प्राप्त कंपनियों के संबंध में कोई सूचना दी है। अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत उत्तरादात नियातकों/उत्पादकों के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(v) कार्यक्रम संख्या 5 : आयात शुल्क की छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

91. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। निवेश के संबंध में इंडोनेशिया गणराज्य के 2007 के कानून संख्या 25 में घर पर उत्पादित न किए गए पूंजीगत सामानों, मशीनों, अथवा उपस्करों पर आयात शुल्क में छूट अथवा राहत सहित विविध रूपों में निवेशों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 में कई पात्रता मानदंडों का प्रावधान है और उनमें से कम से कम एक का संतोषजनक होना लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल वह उद्यमी पात्र हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
92. इस कार्यक्रम की जांच प्राधिकारी द्वारा पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों के संबंध में सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में की गई थी और प्रतिकार योग्य पाया गया था।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

93. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि "मास्टरलिस्ट कार्यक्रम" मशीनों और कारखाना उपस्करों के रूप में पूंजीगत सामानों के आयात के लिए आयात कर कटौती तथा वैट छूट के रूप में प्रदान की जाने वाली निवेश सुविधा है। आयात शुल्क में कटौती वित्त मंत्रालय के निर्णय संख्या 135/केएमके.05/2000 के तहत प्रदान की जाती है। यह नए निवेशों अथवा विद्यमान निवेशों को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाती है। बीकेपीएम इस कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षण एजेंसी है और इस कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्रों की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। प्राधिकारी ने पूर्व में इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य नहीं पाया।
94. यह अनुरोध किया गया है कि वैट छूट सब्सिडीरोधी नियमावली के अनुसार प्रतिकार योग्य नहीं है और प्राधिकारी द्वारा यही दृष्टिकोण कॉपर की सब्सिडीरोधी जांच में लिया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

95. यह नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम उस "मास्टरलिस्ट कार्यक्रम" का भाग है जो मशीनों और कारखाना उपस्करों के रूप में पूंजीगत सामानों के आयातों पर लगाई आयात शुल्क कटौती और वैट छूट (कार्यक्रम संख्या 7 के भीतर लिया गया) प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। लाभ 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 के तहत

सूचीबद्ध मानदंडों के संतोषजनक होने के अध्यधीन प्रदान किया जाता है। यद्यपि इंडोनेशिया सरकार ने उल्लेख किया कि जांचारीन केवल एक कंपनी ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है, तथापि दोनों उत्तरदाता निर्यातकों ने अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल उन उद्यमों को लाभ प्रदान किया जाता है जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य मानते हैं।

96. अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत दोनों उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

(vi) कार्यक्रम संख्या 6 : आयात शुल्क की छूट – कच्ची सामग्री

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

97. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। निवेशों के संबंध में इंडोनेशिया गणराज्य के 2007 के कानून संख्या 25 में निश्चित अवधि के लिए और निर्धारित अपेक्षाओं के साथ कच्ची सामग्री अथवा घटकों के उत्पादन के आयात शुल्क पर छूट अथवा राहत सहित विविध रूपों में निवेशों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 में कई पात्रता मानदंडों का प्रावधान है और उनमें से कम से कम एक का संतोषजनक होना लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल वह उद्यमी पात्र हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
98. इस कार्यक्रम की जांच प्राधिकारी द्वारा पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों के संबंध में संस्थापित एवं प्रयुक्त होने के लिए मशीन और कारखाना उपस्कर शामिल हैं। यह प्रस्ताव बीकेपीएम द्वारा अनुमोदित किए जाने होते हैं। पात्रता मानदंड वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बीकेपीएम डिक्री है।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

99. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम के तहत उन नीतिगत सामानों के आयातों पर लगाए गए आयात शुल्क पर कटौती प्रदान की जाती है जिनमें अन्य के साथ नए स्थापित उद्योग और/अथवा विद्यमान उद्योग के विस्तार से उत्पादन के लिए संस्थापित एवं प्रयुक्त होने के लिए मशीन और कारखाना उपस्कर शामिल हैं। यह प्रस्ताव बीकेपीएम द्वारा अनुमोदित किए जाने होते हैं। पात्रता मानदंड वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बीकेपीएम डिक्री है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

100. यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत नए निवेशों में लगाई गई कच्ची सामग्री के आयातों पर लगाये गए शुल्क पर आयात शुल्क में कटौती प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक सीमा शुल्क द्वारा लागू एक सख्त निगरानी तंत्र है कि कार्यक्रम का दुरुपयोग न किया जाए और उल्लंघनों की स्थिति में पर्याप्त पेनलटी लगाई जाए। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह केवल उन उद्यमों को प्रदान किया जाता है जो बीकेपीएम डिक्री के अनुसार सख्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य मानते हैं।
101. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तरों में यह अनुरोध किया कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है क्योंकि पूरी कच्ची सामग्री की खरीद घरेलू तौर पर की गई थी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि वे इस प्राथमिक कच्ची सामग्री अर्थात् वुड की खरीद निजी पौधारोपणों से करते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह दर्शने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है कि उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी कच्ची सामग्री का आयात किया है। अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(vii) कार्यक्रम संख्या 7 : वैट की छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

102. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। निवेशों के संबंध में इंडोनेशिया गणराज्य के 2007 के कानून संख्या 25 में निर्यातित उत्पादों के उत्पादन के प्रयोजन के लिए घर पर न उत्पादित न किए गए पूंजीगत सामानों अथवा मशीनों अथवा उपस्करों के उत्पादन के आयातों पर निश्चित अवधि के लिए मूल्यवर्धित कर के आस्थगन अथवा छूटों सहित विविध रूपों में निवेशों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 में कई पात्रता मानदंडों का प्रावधान है और उनमें से कम से कम एक का संतोषजनक होना लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल वह उद्यमी पात्र हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
103. इस कार्यक्रम की जांच प्राधिकारी द्वारा पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" के आयातों के संबंध में सबिसडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में की गई थी और उसे प्रतिकार योग्य पाया गया था। यह कार्यक्रम भी एएससीएम की पाद टिप्पणी 1 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ब(ख) के तहत अनुमत्य शुल्क प्रेषण नहीं है।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

104. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि "मास्टरलिस्ट कार्यक्रम" मशीनों और कारखाना उपस्करों के रूप में पूंजीगत सामानों के आयातों के लिए आयात शुल्क कटौती और वैट छूट के रूप में प्रदान की गई निवेश सुविधा है। यह नए निवेशों अथवा विद्यमान निवेशों को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाती है। बीकेपीएम इस कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षण एजेंसी है और वह इस कार्यक्रम के लिए आवेदनों की समीक्षा एवं अनुमोदन करती है। यह कार्यक्रम न तो विशिष्ट है और न विचाराधीन उत्पाद के इंडोनेशियाई उत्पादकों को कोई लाभ प्रदान करता है। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम को पूर्व में प्रतिकार योग्य नहीं पाया।
105. यह अनुरोध किया गया है कि वैट छूट सबिसडीरोधी नियमावली के अनुसार प्रतिकार योग्य नहीं है और यही दृष्टिकोण प्राधिकारी द्वारा कॉपर की सबिसडीरोधी जांच में लिया गया है।
106. उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि पूंजीगत सामानों पर वैट छूट सबिसडीरोधी नियमावली, 1995 के तहत इन तथ्यों के कारण सबिसडी नहीं है कि वैट छूट न तो परित्यक्त राजस्व है और न ही निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है। इसके अतिरिक्त, यह एमडीएफ उद्योग के लिए विशिष्ट नहीं है, परन्तु पूरे क्षेत्रों में सभी उद्योगों के लिए उपलब्ध है। अतः यह सबिसडी तथा प्रतिकारी उपायों संबंधी करार (एएससीएम) के अनुच्छेद 2 के अनुसार विशिष्ट नहीं है। यह अनुरोध है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने पर समान उत्पादों के उत्पादन और वितरण के संबंध में लगाए गए करों से अधिक अप्रत्यक्ष करों के निर्यातित उत्पादों के उत्पादन और वितरण के संबंध में केवल छूट अथवा प्रेषण एएससीएम के अनुबंध-1 (निर्यात सबिसडियों की विस्तृत सूची) के पैरा छ के अनुसार निर्यात सबिसडी है। अतः निःसन्देह यह स्पष्ट है कि एएससीएम के तहत वैट छूट प्रतिकार योग्य सबिसडी नहीं है। वैट जमा करने योग्य अप्रत्यक्ष कर है। प्राधिकारी ने यह दृष्टिकोण भी लिया है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से 05 नवंबर, 2019 की "कन्टीन्यूस कास्ट कॉपर वायर रॉड" की हाल की सबिसडीरोधी जांच में वैट प्रतिकार योग्य सबिसडी नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में सामानों के निर्यात पर मूल्यवर्धित कर से छूट का प्रावधान है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सबिसडी कार्यक्रम में निर्यातित सामानों पर कर के प्रेषण का प्रावधान है जो एससीएम करार की पाद टिप्पणी 1 और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ब(ख)(i) के अनुसार घरेलू खपत के लिए भेजे जाने पर समान उत्पाद द्वारा वहन किया जाता है। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(viii) कार्यक्रम संख्या 8 : वर्धित मूल्यहास अथवा परिशोधन

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

108. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। निवेशों के संबंध में इंडोनेशिया गणराज्य के 2007 के कानून संख्या 25 में वर्धित मूल्यहास अथवा परिशोधन और परिणामस्वरूप कम आय कर की देता सहित विविध रूपों में निवेशों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 में कई पात्रता मानदंडों का प्रावधान है और उनमें से कम से कम एक का संतोषजनक होना लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल वह उद्यमी पात्र हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

109. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम का आशय कतिपय व्यापारिक क्षेत्रों और/अथवा कतिपय क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना है। सरकारी विनियम संख्या 9/2016 द्वारा संशोधित सरकारी विनियम संख्या 18/2015 (1) मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में निवेश के लिए 30 प्रतिशत (व्यापार प्रचालन के पहले छः वर्षों के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष) कर कटौती, (2) वर्धित मूल्यहास तथा परिशोधन, (3) गैर-आवासीय करदाताओं को लाभांश वितरण पर कम की गई कर दर और (4) हानि मुआवजा 77 सूचीबद्ध उद्योगों में कंपनियों को प्रदान करता है।
110. यह अनुरोध किया गया है कि यह कार्यक्रम लागू नहीं है क्योंकि निर्यातकों द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया था। यह दावा लेखापरीक्षा रिपोर्टों से सत्यापित किया जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम सरकारी विनियम संख्या 18/2015 के तहत प्रदान किया जाता है जिसमें बाद में सरकारी विनियम संख्या 9/2016 द्वारा संशोधन किया गया था। इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। इस विनियम के तहत दिया गया लाभ (1) मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में निवेश के लिए 30 प्रतिशत (व्यापार प्रचालन के पहले छः वर्षों के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष) कर कटौती, (2) वर्धित मूल्यहास तथा परिशोधन, (3) गैर-आवासीय करदाताओं को लाभांश वितरण पर कम की गई कर दर और (4) हानि मुआवजा 77 सूचीबद्ध उद्योगों को ही उपलब्ध है। अतः इस कार्यक्रम के तहत जांचाधीन कंपनियों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(ix) कार्यक्रम संख्या 9 : भूमि एवं भवन कर के रूप में राहत

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

112. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम इंडोनेशिया सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। निवेशों के संबंध में इंडोनेशिया गणराज्य के 2007 के कानून संख्या 25 में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों अथवा मंडलों में निर्धारित व्यापारिक क्षेत्रों के लिए भूमि और भवनों पर राहत सहित विविध रूपों में निवेशों के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। 2007 के कानून संख्या 25 के अनुच्छेद 18 में कई पात्रता मानदंडों का प्रावधान है और उनमें से कम से कम एक का संतोषजनक होना लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि केवल वह उद्यमी पात्र हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

113. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम अधिनियम संख्या 39/2009 के माध्यम से स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और इन क्षेत्रों में स्थित/ प्रचालन करने वाले मुख्य व्यापारों को रोजगार में कराधान से व्यापक सुविधाएं/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुसार क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्रीय कर में कटौती अथवा छूट निर्धारित कर सकते हैं जिसमें भूमि एवं भवन कर अथवा 50 प्रतिशत से प्रतिकार शामिल है।

114. यह अनुरोध किया गया है कि यह कार्यक्रम लागू नहीं है क्योंकि निर्यातकों द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया था। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट से सत्यापित किया जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

115. यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम में भूमि और भवन कर से छूट/कटौती का प्रावधान है और उन उद्यमों को प्रदान किया जाता है जो इंडोनेशिया सरकार द्वारा निर्धारित 13 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित हैं। सरकारी विनियम संख्या 96/2015 के अनुसार, क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्रीय कर में कटौती अथवा छूट निर्धारित कर सकते हैं जिसमें भूमि एवं भवन कर अथवा 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से प्रतिकार शामिल है। इस कार्यक्रम में परित्यक्त राजस्व के रूप में विनीय अंशदान का प्रावधान है जो अन्यथा देय है और इससे लाभ प्रदान किया जाता है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह भौगोलिक विशिष्ट है तथा कुछ उद्यमों तक सीमित है जो 13 एसईजेड क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य मानते हैं।
116. चूंकि कोई उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक इंडोनेशिया में किसी भी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित नहीं है, अतः वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(x) कार्यक्रम संख्या 10 : आयात आय कर अनुच्छेद 22 की छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

117. इंडोनेशिया सरकार ने अपनी सरकारी प्रश्नावली के उत्तर में यह उल्लेख किया था कि मुक्ति पैनल ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। यद्यपि उत्पादक यह दावा करता है कि सरकार ने बाद में स्पष्ट किया था कि उत्पादक ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया, अतः इसके संबंध में पत्र की प्रति घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। बाद में, पत्र की प्रति दूसरी मौखिक सुनवाई के प्रयोजन के लिए परिचालित पेपर बुक के माध्यम से की गई थी। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उत्पादक द्वारा किए गए दावे और प्रस्तुत पत्र के प्राधिकार का सत्यापन करें।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

118. इंडोनेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कराधान महानिदेशालय द्वारा शासित होता है। विनियम संख्या 1/पीजे/2011 के अंतर्गत अंतिम आयकर और आयात आयकर पर छूट ऐसे करदाताओं को दी जाती है जिन्हें (1) कतिपय कारणों की वजह से वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा हो जैसे (क) नया करदाता निवेश चरण में हो, (ख) करदाता वाणिज्यिक प्रचालन में नहीं हो, (ग) अप्रत्याशित घटना, (2) वित्तीय घाटे की अतिपूर्ति का पात्र हो और (3) प्रदत्त आयकर की राशि देय आयकर से अधिक हो जो कार्यक्रम पर लागू हो। सभी पात्र करदाताओं को छूट के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होता है और अनुमोदित होने पर वह 10 प्रतिशत के अंतिम आयकर या 2.5 प्रतिशत की दर से आयात आयकर से अधिक हो जो कार्यक्रम पर लागू हो। सभी पात्र करदाताओं को छूट के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होता है और अनुमोदित होने पर वह 10 प्रतिशत के अंतिम आयकर या 2.5 प्रतिशत की दर से आयात आयकर तथा दिए गए कर वर्ष के लिए आवेदन करेगा। यह कार्यक्रम सभी क्षेत्रों और प्रभागों पर उपलब्ध है और इसलिए ईएससीएम के अनुपालन में है।
119. यह बताया गया है कि यह कार्यक्रम लागू नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडीरोधी नियम के अनुसार प्रतिसंतुलन योग्य कोई लाभ नहीं लिया गया है। आयातों और देय तथा प्रदत्त कर के संपूर्ण ब्यौरे दिए गए हैं। आयात सामग्रियों और पूंजीगत वस्तुओं के लिए आयात आयकर की छूट से प्रतिसंतुलनकारी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि यह वार्षिक आयकर की एक किस्त मात्र है। आयात आयकर की छूट से कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वार्षिक आयकर देना अपेक्षित है।
120. इसके अलावा, जी ओ आई ने स्पष्ट किया है कि प्रदत्त साक्ष्य के अनुसार पीटी. मुक्ति पैनल इंडस्ट्री (एम पी आई) को 2.5 प्रतिशत आयात आयकर से छूट नहीं दी गई थी और इसलिए पी ओ आई के दौरान उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

121. यह नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के अधीन कराधान निदेशालय द्वारा शासित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विनियम संख्या 1/पीजे/2011 के अंतर्गत विहित पात्रता मापदंड के अधीन आयकर से छूट दी जाती है। जब कंपनी उसे पूरा भी करती है तो अनुमोदन के अधीन लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम गंवाए गए

राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान देता है जो अन्यथा देय होता तथा इस प्रकार, लाभ दिया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र उद्यम विभिन्न पात्रता मापदंडों के जरिए सीमित हैं और यह प्रशासनिक निकाय के अनुमोदन के अधीन भी है। उपर्युक्त के महेनजर प्राधिकारी मानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य है।

122. इंडोनेशिया सरकार ने यह खुलासा किया है कि मुक्ति पैनल ने कार्यक्रम के अधीन लाभ प्राप्त नहीं किया है। अन्य प्रतिवादी निर्यातक ने भी बताया है कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है और प्राधिकारी को रिकार्ड में यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि प्रतिवादी निर्यातक को उक्त स्कीम के अधीन कोई प्रोत्साहन मिला है।
123. अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अधीन प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(xi) कार्यक्रम संख्या 11ए: पर्याप्त मूल्य से कम कीमत पर भूमि का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

124. याचिकाकर्ता ने बताया है कि इंडोनेशिया में बागानों के लिए भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है जो रियायती धारकों के रूप में कंपनियों को भूमि के उपयोग के अधिकार देती है। यदि रियायत धारक अपनी प्रशासनिक अपेक्षाओं (उदाहरण के लिए पारिस्थितिकीय) को पूरा नहीं करते हैं तो सरकार रियायत धारक पर जुर्माना लगा सकती है और उसकी रियायत समाप्त भी कर सकती है। इस प्रकार भूमि इंडोनेशिया में उद्यमों को पर्याप्त मूल्य से कम पर उपलब्ध है। दो तरह की भूमि शामिल है – बागानों के लिए भूमि जो कार्यक्रम संख्या 1 और 2 में शामिल है और विनिर्माण इकाइयों के लिए भूमि। संयंत्र/विनिर्माण इकाइयों के लिए भूमि में सब्सिडी होना और वन भूमि पर नहीं होना इसकी अलग से मात्रा बताने की जरूरत है। प्राधिकारी ने इस स्कीम का सही ढंग से विश्लेषण किया है जिसके द्वारा निर्माण इकाइयों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर भूमि मिली है और यह बताया है कि इंडोनेशिया सरकार रियायती दर पर कंपनियों को भूमि देती है। इसे किसी कानून या विनियम द्वारा नियमित नहीं किया जाता है और यह सरकार के विवेक पर आधारित है। तथापि, प्राधिकारी ने टंगेरांग भूमि कीमतों को मानने में सर्वाधिक सीमित बैंचमार्क पर विचार किया है।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

125. जी ओ आई और प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने बताया है कि प्राधिकारी को नई कथित सब्सिडी को अस्वीकृत करना चाहिए जिन्हें लिखित अनुरोध के समय आरोपित किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उन्हें उक्त कार्यक्रमों से लाभ नहीं मिला है। टंगेरांग में कारखाना भूमि की कीमतें उचित बैंचमार्क नहीं हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम वन भूमि से संबंधित है और टंगेरांग एक अलग द्वीप अर्थात् जावा में पर स्थित है।
126. सहयोगी उत्पादकों ने जी ओ आई से कारखाना भूमि नहीं खरीदी है, परंतु उन्होंने अलग-अलग मालिकों से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों सहित इसे खरीदा है। इंडोनेशिया नेशनल लैंड एजेंसी (बी पी एन) विनियामक प्राधिकरण है जो भूमि की वैधता का प्रशासन करता है न कि भूमि के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार का।
127. निर्यातक ने निजी पक्षकारों से भूमि खरीदी है। निर्यातक ने नजदीकी आधार पर बाजार कीमत पर भूमि खरीदी है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि निर्यातक ने भूमि पट्टे पर नहीं ली है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

128. यह नोट किया गया है कि इंडोनेशिया सरकार वन के लिए भूमि रियायती दर पर प्रदान करती है। इंडोनेशिया सरकार लगभग समस्त फसल योग्य वन भूमि (88 प्रतिशत) को नियंत्रित करती है और लकड़ी कटाई के अधिकार हेतु कंपनियों को लार्गिंग के अधिकार पट्टे पर देती है। यह विधि या विनियम द्वारा शासित होता है और सरकार के विवेक पर आधारित है। यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर वानिकी क्षेत्र के लिए भूमि हेतु प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है, क्योंकि लाभ सरकार के निर्देश पर दिया जाता है और सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बागानों के लिए भूमि के अधीन लाभ कार्यक्रम संख्या 1 और 2 में शामिल हैं। हालांकि, कारखाने की भूमि का एल टी ऐ आर प्रावधान कार्यक्रम 1 और 2 में शामिल नहीं है।

129. औद्योगिक भूमि के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इंडोनेशिया गणराज्य का संविधान अनुच्छेद 33 के अधीन यह बताता है कि भूमि राज्य द्वारा नियंत्रित होगी और जनता के सर्वोच्च हित हेतु दोहित होगी। 1960 का कानून संख्या 5 जिसे इंडोनेशिया में भूमि के विनियम हेतु बनाया गया था। अनुच्छेद 20 के अधीन यह बताता है कि भूमि के स्वामित्व का अधिकार इंडोनेशिया के नागरिकों तक सीमित है। भूमि के स्वामित्व का अधिकार सामान्यतः कारपोरेट निकायों को नहीं दिया जाता है और इसे निर्धारित शर्तों के अधीन सरकार के विवेकाधिकार के अधीन ही प्रदान किया जाता है। भूमि पर प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए खर्च को प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्रस्तुत लेखा परीक्षक रिपोर्टों से लिया गया है। टंगेरांग में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि की औसत कीमत प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के कारखानों से उनकी निकटता के कारण भूमि कीमतों के लिए उचित बेंचमार्क के रूप में दिया गया है।

कार्यक्रम संख्या 11बी: पर्याप्त मूल्य से कम पर बिजली का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

130. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि 2017 के विनियम संख्या 44 के जरिए वित्त मंत्रालय द्वारा बिजली पर भारी सब्सिडी दी गई है। इससे उपभोक्ता सरकारी स्वामित्व वाली पाँवर जनरल कंपनी पीटी. पेरुसहान लिस्ट्रिक नगारा (पी एल एन) से पर्याप्त मूल्य से कम पर बिजली खरीद सकते हैं। इंडोनेशिया सरकार कोयले के निर्यात बहाल रखती है और कोयले के लिए घरेलू बाजार दायित्वों को पूरा करना अपेक्षित है। घरेलू बाजार दायित्व 2019 में उत्पादन के 25 प्रतिशत पर निर्धारित है। इस प्रकार कोयला उत्पादक/खननकर्ता सबसे पहले घरेलू मांग को पूरा करने हेतु कोयला देने के लिए बाध्य है। इसलिए इंडोनेशिया सरकार निर्यात कर, निर्यात प्रतिबंधों और कानूनी कार्यों की मौजूदगी की अनुमति द्वारा जिनमें कोयला उत्पादकों को इंडोनेशिया में घरेलू रूप से बिक्री करनी होती है, के माध्यम से निजी कंपनियों को पर्याप्त कीमत से कम पर कोयले के रूप में विद्युत जनरेटरों हेतु वित्तीय अंशदान प्रदान करती है। कोयले के लिए बेंचमार्क कीमत व्यवस्था भी कोयला कीमतों संबंधी मिनस्टर ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज संख्या 0617डब्ल्यू32[ईएम]2011 के जरिए कोयले के लिए 2011 में अधिनियमित की गई थी जो नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी (पी एल एन) द्वारा कोयले की खरीद पर लागू है। इंडोनेशिया की सरकार कोयले की अधिकतम बिक्री कीमत की सीमा निर्धारित करती है। बिजली के लिए कोयले की बिक्री कीमत 70 अमरीकी डॉलर प्रति एम टी तय की गई है। कोयले के उत्पादन में शामिल किसी कंपनी के लिए उसकी विधिक स्थिति पर विचार किये बिना जी ओ आई द्वारा जारी आदेश के पालन में ऐसे कोयले की बिक्री करना अपेक्षित है। चूंकि कोयला विद्युत उत्पादन के प्रयोजनार्थ कोयले पर अधिकतम कीमत सीमा लगाकर संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध है। इसलिए फाइबर बोर्ड उत्पादकों द्वारा खरीदी गई बिजली सब्सिडी प्राप्त है। आवेदक इंडोनेशिया से “स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पाद” के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच के मामले में प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा करता है। आवेदक अनुरोध करता है कि प्राधिकारी को पर्याप्त से कम मूल्य पर खरीदी गई बिजली में सब्सिडी की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए।

131. इसके अलावा, इंडोनेशिया के संविधान के अनुच्छेद 33(3) के अनुसार – भूमि, जल और उसमें निहित प्राकृतिक संसाधन सरकार द्वारा नियंत्रित दोहित होंगे।

इंडोनेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

132. सभी उद्योग पी एल एन द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए पात्र हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में उद्योगों के लिए वह एक मात्र प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। पी ओ आई के दौरान प्रत्येक प्रतिवादी को दी गई बिजली की मात्रा और मूल्य पी एल एन द्वारा रखे गए बिजली के बिलों में रिकार्ड है। ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय (एम ई एम आर) विनियम 28/2016 में बिजली टैरिफ आठ श्रेणियों में वर्गीकृत है।

- (क) लघु ग्रहस्थ/उद्योग कम वोल्टेज पर, 450 केवीए – 14 केवीए (आई-1/टीआर) पर विद्युत;
- (ख) कम वोल्टेज पर मध्यम उद्योग 14 केवीए – 200 केवीए (आई-2/टीआर) से अधिक विद्युत;
- (ग) मध्यम वोल्टेज पर मध्यम उद्योग 200 केवीए (आई-3/टीएम) से अधिक विद्युत; और
- (घ) उच्च वोल्टेज पर बड़े उद्योग 30000 केवीए से अधिक और (आई-4/टीटी) की विद्युत;

133. पी एल एन सार्वजनिक क्षेत्र से अलग विद्युत का एक वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ता है और सार्वजनिक सेवा के रूप में विद्युत उपलब्ध कराता है। चूंकि यह सभी क्षेत्रों को विद्युत देता है इसलिए डब्ल्यू टी ओ और एएससीएम के अनुसार यह विशिष्ट नहीं है। विद्युत का टैरिफ समायोजन प्रत्येक तीन महीने में प्रकाशित होता है और सरकारी वेबसाइट के जरिए इसे देखा जा सकता है। प्रतिवादी कंपनियों को 200 केवीए (आई-3/टीएम) की विद्युत सहित मध्यम वोल्टेज पर मध्यम उद्योग के टैरिफ समूह के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।
134. बिजली के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बिजली पर टैरिफ उपभोक्ता की क्रय शक्ति तथा प्रत्येक उपभोक्ता समूह की स्थापित विद्युत क्षमता पर विचार करते हुए तय किया जाता है।
135. पी टी बुकिट असम 1 मार्च, 1981 को स्थापित राज्य के स्वामित्व वाली एक लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम पी टी बुकिट असम (परसेरो) है या उसे व्यापक रूप से पी टी बीए के रूप में जाना जाता है। कंपनी कोयले के खनन, उत्खनन, दोहन, शुद्धिकरण और प्रसंस्करण पर फोकस करती है। पी टी बुकिट असम के अलावा, देश में 700 निजी खननकर्ता हैं जो विशुद्ध वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर इंडोनेशिया में उक्त गतिविधियां करने हेतु स्वतंत्र हैं। जी ओ आई कोयले के सौदों में हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि यह पक्षकारों के बीच वार्ताओं पर पूर्णतः निर्भर है। पीटीबीए 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। निजी क्षेत्रों को खनन करने हेतु लाइसेंस दिया जाता है (इजिन उसाहा पर्टम्बंगन – आईयूपी) जी ओ आई का सिरीज ए द्विवरना शेयर के जरिए प्रत्यक्ष रूप से या पीटी एनालम (परसेरो) के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से पीटीबीए पर नियंत्रण है।
136. कुल घरेलू खपत 2018 में लगभग 115 मिलियन टन (20,61 प्रतिशत) और 2019 में 138 मिलियन टन (22,40 प्रतिशत) पर पहुंच गई। जी ओ आई कोयले के आयातों को सीमित नहीं करती है।
137. कोयले की कीमत कैलोरीज तथा विक्रेताओं और क्रेताओं द्वारा सहमत वाणिज्यिक शर्तों पर निर्भर करती है। यह स्थिति पी टी बुकिट असम और निजी कोयला उत्पादक दोनों पर लागू होती है।
138. पी टी बुकिट असम के लिए निर्धारित अधिकतम कीमत उत्पादन लागत जमा, मार्जिन के सूत्र पर आधारित है जिसमें कुल उत्पादन लागत के 15 प्रतिशत की न्यूनतम राशि और 25 प्रतिशत की अधिकतम राशि में खनन कंपनी के लाभ और जोखिम शामिल हैं। अतः यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि पी एल एन को बाजार मूल्य से कम पर कोयला दिया जाता है।
139. न तो आवेदकों और न ही प्राधिकारी द्वारा यह दर्शने हेतु कोई साक्ष्य दिया है कि प्रयोक्ताओं को वास्तव में सब्सिडी प्राप्त दरों पर बिजली मिल रही है। निर्यातक दोहराता है कि उसे सब्सिडी प्राप्त दरों पर बिजली नहीं मिलती है। इस संदर्भ में अपने दावे को सही सिद्ध करने के लिए दिसंबर, 2018 बीजिक के अंग्रेजी अनुवाद सहित पी ओ आई के दौरान निर्यातक के नमूना बिजली बीजिक प्रस्तुत किए गए हैं और प्राधिकारी से इस कार्यक्रम के तहत किसी सब्सिडी की सिफारिश नहीं करने का अनुरोध किया गया है। इस असाक्षांकित आरोप के संबंध में कि पी एल एन को कोयला बाजार दर से कम पर उपलब्ध है। यह बताया गया है कि उक्त आदेश केवल उस कीमत को सीमित करता है जिस पर पी एल एन कोयला खरीदेगी। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोयला इसी कीमत पर आपूर्ति करना आवश्यक है। पी एल एन देश में हजारों निजी आपूर्तिकर्ताओं/खननकर्ताओं से कोयला खरीदने के लिए स्वतंत्र है। यह समझना आवश्यक है कि पी एल एन कोयले का एक बड़ा क्रेता है और बेहतर कीमतों पर कोयला लेने की स्थिति में है। प्रतिवादी निर्यातक द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि पी टी बुकिट असम के लिए निर्धारित अधिकतम कीमत भी उत्पादन लागत जमा मार्जिन के सूत्र पर आधारित है। इसमें कुल उत्पादन लागत के 15 प्रतिशत की न्यूनतम राशि और 25 प्रतिशत की अधिकतम राशि में खनन कंपनी का लाभ और जोखिम शामिल है। अतः यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि कोयला पी एल एन को बाजार मूल्य से कम पर उपलब्ध कराया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

140. यह नोट किया गया है कि इंडोनेशिया में बिजली कोयले से उत्पादित होती है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी (पीएलएन) द्वारा कोयले के लिए बेंचमार्क कीमत निर्धारण मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज संघ्या 0617के/32/एमईएम/2011 द्वारा होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया सरकार निर्यात कर, निर्यात प्रतिबंधों और कानूनी अधिनियमों की मौजूदगी जिनमें कोयला उत्पादकों को इंडोनेशिया में घरेलू रूप से बिक्री

करना अपेक्षित है, के माध्यम से पी एल एन को पर्याप्त से कम कीमत पर कोयला प्रदान करने के लिए सरकारी तथा निजी कंपनियों को निर्देश देती है। कोयला उत्पादक/बननकर्ताओं को पहले घरेलू मांग पूरी करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए पी एल एन को बाजार दरों से कम पर कोयला उपलब्ध है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि सस्ती दरों पर कोयले का लाभ इंडोनेशिया में केवल विद्युत आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध है जो अंततः पी एल एन के लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्राप्त दर पर बिजली देने में सक्षम बनाता है। जांच के अधीन कंपनियां सस्ती दरों पर ऐसी बिजली की लाभार्थी हैं। यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम दर पर बिजली देने के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ मिलता है। अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

141. सब्सिडी मार्जिन राशि निर्धारित करने हेतु प्राधिकारी ने उचित बेंचमार्क की तलाश की है। प्राधिकारी ने “ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस” की वेबसाइट के अनुसार प्रदत्त कीमतों पर भरोसा किया है। प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा वस्तुतः प्रदत्त बिजली टैरिफ पर प्रश्नावली के अतिरिक्त उत्तर के अनुसार सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। उक्त पद्धति पर विचार करते हुए प्रतिवादी निर्यातकों हेतु निर्धारित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

पीटी. मुक्ति पैनल इंडस्ट्रीज

142. पीटी. मुक्ति पैनल इंडस्ट्रीज इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक/निर्यातक है। मुक्ति पैनल ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों संबंधी सूचना प्रदान की है।
143. प्राधिकारी ने मुक्ति पैनल द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की है और जांच करने पर उनसे अतिरिक्त सूचना मांगी है तथा उत्तर में प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन भी किया है। मुक्ति पैनल ने प्रश्नावली के उत्तर में बताया है कि उसने आयात शुल्क में छूट प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भूमि, लकड़ी और बिजली के लिए एलटीएआर प्रावधान मुक्ति पैनल को प्राप्त हुए थे। परिणामस्वरूप विभिन्न सब्सिडियों के रूप में मुक्ति पैनल को लाभ मिला है।
144. प्राधिकारी ने मुक्ति पैनल द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन किया है और उन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है जिनके लिए पी ओ आई के दौरान लाभ प्राप्त हुआ या मिला था। जहां कहीं भी निर्यातक द्वारा संगत सूचना नहीं दी गई है, प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण हेतु उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
145. नीचे तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम और संगत सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 1 और 2	एलटीएआर पर स्थायी इमारती लकड़ी हेतु प्रावधान	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 5	आयात शुल्क से छूट	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 11क	भूमि सब्सिडी के रूप में अभिज्ञात योजना	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं. 11ख	पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान	***%	0-10
कुल सब्सिडी			***%	10-20

पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड

146. पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक/निर्यातक है। सुमातेरा ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों संबंधी सूचना प्रदान की है।
147. प्राधिकारी ने पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की है और जांच करने पर उनसे अतिरिक्त सूचना मांगी है तथा उत्तर में प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन भी किया है। पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड ने प्रश्नावली के उत्तर में बताया है कि उसने आयात शुल्क में छूट प्राप्त की है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भूमि, लकड़ी और बिजली के लिए एलटीएआर प्रावधान पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड को प्राप्त हुए थे। परिणामस्वरूप विभिन्न सब्सिडियों के रूप में पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड को लाभ मिला है।

148. प्राधिकारी ने पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन किया है और उन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है जिनके लिए पी ओ आई के दौरान लाभ प्राप्त हुआ या मिला था। जहां कहीं भी निर्यातक द्वारा संगत सूचना नहीं दी गई है, प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण हेतु उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
140. नीचे तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों के नाम और संगत सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 1 और 2	एलटीएआर पर स्थायी इमारती लकड़ी हेतु प्रावधान	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 5	आयात शुल्क से छूट	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 11क	भूमि सब्सिडी के रूप में अभिज्ञात योजना	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं. 11ख	पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान	***%	0-10
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

150. इंडोनेशिया से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहयोगी पक्षकारों हेतु उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडियों के लिए सब्सिडी मार्जिन के सर्वोच्च के आधार पर और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 1 और 2	एलटीएआर पर स्थायी इमारती लकड़ी हेतु प्रावधान	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 5	आयात शुल्क से छूट	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 11क	भूमि सब्सिडी के रूप में अभिज्ञात योजना	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं. 11ख	पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान	***%	0-10
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

मलेशिया

कार्यक्रम संख्या 1: बाजार विकास अनुदान

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

151. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उक्त कार्यक्रम मलेशिया विदेश व्यापार विकास कारपोरेशन (एमएटीआरएडीई) द्वारा शासित है। बाजार विकास अनुदान (एमडीजी), 2018 के दिशानिर्देशों में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) यह अनुमति है कि वह दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में भागीदारी करते समय हुई वास्तविक खर्चों पर 100 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु क्टिप्पय पात्रता मापदंडों को पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ निर्यात संबंधी उद्यमों के लिए उपलब्ध है और इसलिए विशिष्ट है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

152. मलेशिया सरकार ने बताया कि बाजार विकास अनुदान निर्यात संवर्धन गतिविधियों में एसएमई की भागीदारी बढ़ाने के प्रयोजनार्थ 11वीं मलेशियाई योजना (2016-2020) के अंतर्गत बनाए गए एसएमई मास्टर प्लान का हिस्सा है। मलेशियाई एसएमई को निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में भागीदारी के लिए आर एम 200,000 तक का प्रतिपूर्ति अनुदान मिलता है। यह अनुदान अनुमोदन के अधीन संवितरित होता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

153. यह नोट किया जाता है बाजार विकास अनुदान (एमडीजी) 11वीं मलेशियाई योजना (2016-2020) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य निर्यात संवर्धन गतिविधियों में एसएमई की भागीदारी बढ़ाना है। एमडीजी में निर्यात संवर्धन गतिविधियों में एसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें आर एम 200,000 तक की प्रतिपूर्ति योग्य अनुदान दिया जाता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, व्यापार और निवेश मिशन/निर्यात वृद्धि मिशन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मलेशिया में निर्मित उत्पादों के लिए लिस्टिंग शुल्क।
154. सब्सिडी कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप वित्तीय अंशदान शामिल है और इस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि निर्यात के प्रयोजनार्थ है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
155. कंपनी मलेशियाई लोगों के स्वामित्व में कम से कम 60 प्रतिशत इक्किटी वाली एसएमई ही लाभार्थी होगी। चूंकि प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों में से कोई भी इस मापदंड को पूरा नहीं करता है। इसलिए यह नोट किया जाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 2: निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

156. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि उक्त कार्यक्रम एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया बर्हड (एक्जिम बैंक) द्वारा प्रशासित होता है। एक्जिम बैंक द्वारा जारी निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण दिशानिर्देश में एक निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण (ई सी आर) स्कीम का प्रावधान है जिसे पोत लादान पूर्व और पोत लादान पश्चात वित्तपोषण के रूप में मलेशिया के निर्यातों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है। पोत लादान पूर्व वित्तपोषण पोत लादान से पूर्व मलेशियाई उत्पादों के निर्यात को सुकर बनाने हेतु एक्जिम बैंक द्वारा किया जाता है और पोत लादान पश्चात वित्त पोषण पोत लादान के पश्चात निर्यात के वित्त पोषण हेतु निर्यातकों के 100 प्रतिशत तक निर्यात बिल मूल्य पर दिया जाता है। यह कार्यक्रम निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान देता है और इस प्रकार लाभ मिला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ निर्यातों से जुड़े उद्यमों हेतु उपलब्ध है और इसलिए विशिष्ट माना गया है। इसके अतिरिक्त, ई सी आर दिशानिर्देशों में पात्र उत्पादों की पहचान के लिए एक नकारात्मक सूची दी गई है।
157. प्रतिवादी निर्यातक कार्यक्रम हेतु पात्र होने के बावजूद कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने के कारण बताने में असमर्थ रहे हैं।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

158. मलेशिया सरकार ने बताया है कि यह योजना पोत लादान पूर्व और पोत लादान पश्चात वित्तपोषण के रूप में मलेशिया के निर्यातों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन में प्रयुक्त होती है। यह कार्यक्रम इसी विनिर्माण और निर्यात व्यापार कंपनी के लिए उपलब्ध है जो (1) मलेशिया में अधिनियमित हो (2) निर्यात कार्यकलापों में शामिल हो।

प्राधिकारी द्वारा जांच

159. यह नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया (एक्जिम बैंक) द्वारा प्रशासित है। निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण कार्यक्रम उत्पादों के निर्यात के वित्तपोषण हेतु उद्यमों को ऋण देता है। यह कार्यक्रम

बैंक द्वारा जारी निर्यात ऋण पुनः वित्तपोषण दिशानिर्देशों द्वारा शासित है जिनमें इस कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ उत्पाद की पात्रता (बैंकों द्वारा रखी गई उत्पादों की नकारात्मक सूची) सहित पात्रता मापदंड प्रदान करते हैं। यह सब्सिडी कार्यक्रम किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है और मलेशिया में अधिनियमित सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है।

160. एक्जिम बैंक एक सरकारी स्वामित्व वित्तीय संस्थान है। यह वित्त मंत्रालय का पूर्ण स्वामित्व वाला अधीनस्थ संस्थान है। वित्त मंत्रालय के दायरे के अधीन एक एजेंसी के रूप में एक्जिम बैंक की प्रमुख भूमिका वस्तुओं, सेवाओं और गैर पारंपरिक बाजारों पर विशेष ध्यान सहित विदेशी परियोजनाओं के निर्यात और आयात का वित्तपोषण और सहायता करने, निर्यात ऋण बीमा सेवा, निर्यात वित्तपोषण बीमा, विदेशी निवेश बीमा और गारंटी सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करना है।
161. यह नोट किया जाता है कि एक्जिम बैंक एक सरकारी निकाय है क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व में है और सरकारी कार्यों को करने हेतु सरकारी प्राधिकार से युक्त है। तदनुसार, एक्जिम बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों से संबंधित है। प्राप्तकर्ता को मिला लाभ एक्जिम बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज राशि और तुलनीय वाणिज्यिक ऋण द्वारा प्रभारित ब्याज राशि के बीच के अंतर के रूप में है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। तथापि, जैसा की किसी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लिया है इसलिए यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन पर कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 3: क्रेता ऋण गारंटी

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

162. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि उक्त कार्यक्रम एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ मलेशिया बर्हड (एक्जिम बैंक) द्वारा प्रशासित है। इसमें बैंकर ट्रेड क्रेडिट तकाफुल (बीटीसीटी) प्रदान किया जाता है जो विदेशी क्रेताओं द्वारा चूक होने से उत्पन्न उनके निर्यातकों द्वारा गैर भुगतान के जोखिम के विरुद्ध इस्लामिक वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) के संरक्षण हेतु डिजाइन किया गया एक ऋण तकाफुल है। इस कार्यक्रम में निर्यात बिल के 70 प्रतिशत या अग्रिम और ऋण पत्र मूल्य के 95 प्रतिशत जोखिम शामिल है। इस कार्यक्रम में निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान मिलता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। इस कार्यक्रम के अधीन लाभ निर्यात से संबंधित उद्यमों के लिए उपलब्ध है और इसलिए इसे विशिष्ट माना गया है।
163. प्रतिवादी निर्यातक कार्यक्रम हेतु पात्र होने के बावजूद कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने के कारण बताने में असमर्थ रहे हैं।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

164. मलेशिया सरकार ने बताया कि बैंकर ट्रेड क्रेडिट तकाफुल (बीटीसीटी) जो विदेशी क्रेताओं द्वारा चूक होने से उत्पन्न उनके निर्यातकों द्वारा गैर भुगतान के जोखिम के विरुद्ध इस्लामिक वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) के संरक्षण हेतु डिजाइन किया गया एक ऋण तकाफुल है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

165. यह नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम एक्जिम बैंक द्वारा प्रशासित है। इस कार्यक्रम को शासित करने वाला कोई कानून या विधिक विनियम नहीं है। उक्त स्कीम में पहले ही निर्धारित है कि एक्जिम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक्जिम बैंक विदेशी क्रेताओं की चूक के कारण उनके निर्यातकों (उपभोक्ताओं) द्वारा भुगतान नहीं करने के जोखिम के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करता है।
166. यह कार्यक्रम संभावित प्रत्यक्ष निधि अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। प्राप्तकर्ता को प्रदत्त लाभ (i) एक्जिम बैंक से गारंटी लेने हेतु प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदत्त शुल्क और ऐसी गारंटी के लिए किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को प्रदत्त शुल्क के बीच के अंतर और (ii) जांच के अधीन ऋणदाता बैंक को ऋण भुगतान (एक्जिम गारंटी के कारण सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर से कम के कारण) और ऐसी गारंटी के अभाव में

देय होने वाली राशि (सामान्य वाणिज्यिक ब्याज पर आधारित) के बीच अंतर के बराबर होता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों से संबंधित है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

167. जैसा प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा बताया गया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं लिया है। इसलिए यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन पर कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 4: पायनियर का दर्जा

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

168. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि उक्त कार्यक्रम मलेशियन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अर्थारिटी (एम आई डी ए) और इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा शासित है। निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 5-25 ऐसी किसी कंपनी को पायनियर का दर्जा देती है जो किसी संवर्धित कार्यकलाप में भागीदारी करने या निवेश संवर्धन (संवर्धन कार्यकलाप और संवर्धित उत्पाद) आदेश, 2012 में यथा सूचीबद्ध है। इसी संवर्धित उत्पाद के उत्पादन का इरादा रखती हो। ऐसे उद्यमों को उन क्षेत्रों/उत्पादों में उनके निवेश के लिए कर प्रोत्साहन दिए जाते हैं और गैर संवर्धित कार्यकलापों से उन्हें घाटों से संवर्धित कार्यकलापों से प्राप्त सांविधिक आय से घटाया जाता है। इस कार्यक्रम में ऐसे गंवाए गए राजस्व के रूप में वित्तीय अनुदान मिलता है जो अन्यथा बकाया होता और इस प्रकार लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि केवल उन्हीं उद्यमों को लाभ देता है जो कानून के अनुसार संवर्धित कार्यकलाप/उत्पाद में शामिल हैं।
169. प्रतिवादी निर्यातक कार्यक्रम हेतु पात्र होने के बावजूद कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने के कारण बताने में असमर्थ रहे हैं।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

170. मलेशिया सरकार ने बताया है कि पायनियर दर्जा ऐसी कंपनी को दिया जा सकता है जो वित्त मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित किसी संवर्धित कार्यकलाप या किसी संवर्धित उत्पाद के उत्पादन में भागीदारी करना चाहती हो। इसमें कार्यकलाप/उत्पाद शामिल हैं जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के हों। इस कार्यक्रम के तहत लाभ अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन प्रदान किया जाता है।
171. सरकार ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे क्योंकि वह ओईसीडी के अधीन हानिकारक कर प्रथा कार्यक्रम संबंधी मंच को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
172. यह भी बताया गया है कि किसी कार्यक्रम हेतु पात्रता या किसी कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी को केवल स्वीकार करने से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि सभी पात्र उत्पादकों ने लाभ हेतु आवेदन और उसे प्राप्त किया होगा। इसके विपरीत सिद्ध करने का कोई दायित्व नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

173. यह नोट किया गया है कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 5-25 में पायनियर दर्जा कार्यक्रम का प्रावधान है। यह कार्यक्रम आयकर से छूट में कर प्रोत्साहन प्रदान करता है। छूट अवधि के दौरान हुए घाटे को आगामी वर्षों के लिए कर योग्य आय/निवल लाभ हेतु आगे लाया जा सकता है। यह कार्यक्रम संवर्धित उत्पादों/कार्यकलापों की पूर्व निर्धारित सूची हेतु उपलब्ध है।
174. यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए लाभ के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है जो अन्यथा बकाया होता और इस प्रकार लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह सूची में उल्लिखित संवर्धित कार्यकलाप/उत्पाद हेतु उपलब्ध है। सूची की जांच से पता चलता है कि संवर्धित उत्पाद में जांचाधीन उत्पाद शामिल हैं। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

175. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में केवल यह बताया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के अधीन लाभ नहीं लिया है। दोनों प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 5-25 और निवेश संवर्धन (संवर्धन कार्यकलाप और संवर्धित उत्पाद) आदेश, 2012 के अनुसार कार्यक्रम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
176. तथापि, प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के पठन से यह स्पष्ट है कि न तो मै० सेगमट पैनल बोर्ड और न ही मै० रोबिन रिसोर्सेज ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ लिया है। अतः यह नोट किया जाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 5: निवेश कर नीतियां

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

177. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उक्त कार्यक्रम मलेशियन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम आई डी ए), और इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा प्रशासित होता है। निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 26-29 ऐसी किसी कंपनी को निवेश कर भत्ता प्रदान करती है, जो संवर्धित कार्यकलाप में भागीदारी करने या निवेश संवर्धन (संवर्धन कार्यकलाप या संवर्धित उत्पाद) आदेश, 2012 में यथा सूचीबद्ध किसी संवर्धित उत्पाद के उत्पादन का इरादा रखती हो। केवल औद्योगिक भवनों, संयंत्रों और संवर्धित कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ सीधे प्रयुक्त मशीनरी या संवर्धित उत्पाद के उत्पादन पर हुए पूंजीगत खर्च के लिए भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता प्रदत् त पात्रता व्यय के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है और इसे देय कर से छूट प्राप्त है। यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है, जो अन्यथा बकाया होता और इस प्रकार लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह कानून के अनुसार संवर्धित कार्यकलाप/उत्पाद में शामिल उद्यमों को ही लाभ देता है।
178. इस कार्यक्रम की प्राधिकारी द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से “कान्टीन्यूअस कास्ट कापर वायर राइस” के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व में जांच की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था।
179. प्रतिवादी निर्यातक कार्यक्रम हेतु पात्र होने के बावजूद कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने के कारण बताने में असमर्थ रहे हैं। इसके अलावा, एक प्रतिवादी निर्यातक अर्थात् सेगमट पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. को कार्यक्रम का लाभ उठाने हेतु मलेशिया सरकार ने अनुमोदित किया है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

180. मलेशिया सरकार ने बताया है कि निवेश कर भत्ता ऐसी कंपनी को दिया जा सकता है जो वित्त मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित किसी संवर्धित कार्यकलाप या किसी संवर्धित उत्पाद के उत्पादन में भागीदारी करना चाहती हो। इसमें कार्यकलाप/उत्पाद शामिल हैं जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के हों। यह भत्ता संवर्धित कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ सीधे प्रयुक्त या संवर्धित उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त औद्योगिक भवनों, संयंत्रों और मशीनरी पर हुए पूंजीगत के लिए ही प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ अनुमोदन समिति के अधीन दिया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

181. यह नोट किया जाता है कि निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 26 से 29 में निवेश कर भत्ता कार्यक्रम की व्यवस्था है। संवर्धित कार्यकलाप और संवर्धित उत्पादों को पूंजीगत भत्ता दिया जाता है। कुल पूंजीगत व्यय में से 60 प्रतिशत पूंजीगत व्यय भत्ते के रूप में दिया जाता है और 5 वर्षों के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत के तहत घटाया जा सकता है। शेष आय पर सामान्य आयकर दर से कर लग सकता है। पात्रता खर्च करने वाली कंपनियों के लिए भी अनुमोदन समिति इस कार्यक्रम के तहत लाभ मांगने वाले आवेदक को अस्वीकृत करने का विवेकाधिकार रखती है।
182. मलेशिया सरकार के लिए डेस्क सत्यापन के स्तर पर प्राधिकारी ने निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 (कार्यक्रम सं. 5) की धारा 26-29 और आयकर अधिनियम, 1967 (कार्यक्रम सं. 19) की धारा 127 (3ए) के तहत स्पष्टीकरण मांगा था। प्रदत् त सूचना के अधार पर प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि मै० रोबिन रिसोर्सेज द्वारा संबंधित कार्यक्रम संख्या 5 के शीर्ष के अर्तर्गत प्रस्तुत उत्तर कार्यक्रम संख्या 19 से संबंधित है।

183. यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निवेश संवर्धन (संवर्धित कार्यकलाप और संवर्धित उत्पाद) आदेश, 2012 के अनुसार सांविधिक कार्यकलाप/संवर्धित उत्पादों में शामिल और अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित कितिपय उद्यमों तक सीमित है। कोई कंपनी जिसने पायनियर दर्जे से आयकर छूट प्राप्त की हो इस कार्यक्रम का लाभ नहीं ले सकती है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
184. तथापि, मै० सेगमत पैनल बोर्ड ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में बताया है कि मलेशिया सरकार ने 10 अगस्त, 2004 को मै० सेगमत पैनल बोर्ड के लिए कार्यक्रम अनुमोदित किया, परंतु पी ओ आई में कोई लाभ नहीं लिया गया और मै० रोबिन रिसोसेज ने भी बताया है कि इसने कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ नहीं लिया है। तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अधीन उनके विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 6: पुनः निवेश भत्ता

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

185. याचिकाकर्ता ने बताया कि उक्त कार्यक्रम इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा प्रशासित है आयकर अधिनियम, 1967 की अनुसूची 7ए और सार्वजनिक निर्णय संख्या 6/2012 कंपनी द्वारा किए गए पात्र पूंजीगत व्यय पर 60 प्रतिशत की दर से पुनः निवेश भत्ता प्रदान करती है और इसकी प्रतिपूर्ति आकलन वर्ष के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत से की जा सकती है। इसे किए गए पहले निवेश के वर्ष से आरंभ होकर 15 लगातार वर्षों की अवधि के लिए दिया जा सकता है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन्हीं उद्यमों के लिए उपलब्ध है जो कम से कम तीन वर्षों से प्रचालन में हैं और पात्र परियोजनाएं (विनिर्माण के संबंध में मौजूदा व्यवसाय के विस्तार, आधुनिकीकरण और आटोमेटिंग) के लिए उपलब्ध हैं।
186. इस कार्यक्रम की प्राधिकारी द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से “कांटीन्यूअस कास्ट कापर वायर राइस” के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व में जांच की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

187. मलेशिया सरकार ने बताया है कि कर छूट ऐसी कंपनी को दी जा सकती है जो वित्त मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित किसी संवर्धित कार्यकलाप या किसी संवर्धित उत्पाद के उत्पादन में भागीदारी करना चाहती हो। इसमें कार्यकलाप/उत्पाद शामिल हैं जो मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के हों। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए (1) व्यापार को 36 महीनों से प्रचालन में रहना होगा और (2) कंपनी/व्यक्ति को आकलन के वर्ष के लिए आधार वर्ष में पात्र परियोजना के प्रयोजनार्थ मलेशिया में प्रयुक्त कारखाना, संयंत्र या मशीनरी पर पूंजीगत व्यय का वहन करना होगा। यह भत्ता दावा किए जाने की अवधि के आधार के लिए आकलन के वर्ष से शुरू होकर आकलन के 15 लगातार वर्षों के लिए दिया जाएगा। चूंकि यह निर्यात दशाओं से संबंधित नहीं है और सामान्यतः उपलब्ध है। यह प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी योग्य नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

188. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया के निवासी किसी कंपनी या किसी व्यक्ति को पुनः निवेश भत्ता प्रदान किया जाता है यदि कंपनी तीन वर्षों से प्रचालन में हो और उसने पात्र परियोजना के लिए कारखाना, संयंत्र और मशीनरी पर पूंजीगत व्यय किया हो। ऐसे पूंजीगत व्यय के 60 प्रतिशत के लिए सांविधिक आय के 70 प्रतिशत से कटौती प्रदान की जाती है। पुनः निवेश भत्ते का दावा आकलन करने के वर्ष से शुरू होकर 15 वर्षों के लिए किया जा सकता है। इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड इस कार्यक्रम के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।
189. यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। यद्यपि सब्सिडी कार्यक्रम संवर्धित कार्यकलाप तक सीमित नहीं है। फिर भी सब्सिडी कार्यक्रम

विशिष्ट है क्योंकि यह उन्हीं उद्यमों हेतु उपलब्ध है जो कम से कम तीन वर्षों से प्रचालन में हों और पात्र परियोजना (विनिर्माण के संबंध में अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार, आधुनिकीकरण या आटोमेशन) कर रहे हों। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

190. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में बताया है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं लिया है। अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 7: वृद्धिशील पूंजीगत भत्ता

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

191. याचिकाकर्ता ने बताया कि उक्त कार्यक्रम इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा प्रशासित है। आयकर (वृद्धिशील पूंजी भत्ता) (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण) नियम, 2018 ऐसा अनुदान प्रदान करता है जो किसी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण की खरीद पर हुए पूंजीगत व्यय के पांचवें भाग के बराबर होगा। इस भत्ते के बराबर राशि को आगे कंपनी की कर योग्य आय से घटाया जाता है। यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन्हीं उद्यमों के लिए उपलब्ध है जो संगत कानून के अनुसार पात्र व्यय करते हैं और पात्रता की 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर पुनः निवेश भत्ते के लिए पात्र नहीं होते हैं।
192. इस कार्यक्रम की प्राधिकारी द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से “कांटीन्यूअस कास्ट कापर वायर राइस” के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व में जांच की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था।
193. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त लाभ ऐसे हैं कि ये पी यू सी तक जाएंगे इसके अलावा, धनराशि क्षयकारी है और कंपनी के पास इसका किसी व्यापार खंड में प्रयोग करने का विवेकाधिकार है। किसी सी वी डी जांच में जांच का विषय समग्र रूप से कंपनी होती हैं और न कि उत्पाद। न्यूनतम सीमा का नियम किसी कार्यक्रम पर नहीं अपितु, किसी निर्यातकवार आधार पर लागू होता है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

194. मलेशिया सरकार ने बताया कि वृद्धिशील पूंजीगत भत्ता ऐसा भत्ता प्रदान करता है जो किसी सूचना या संचार प्रौद्योगिकी उपकरण की खरीद के लिए किए गए पूंजीगत व्यय का पांचवां हिस्सा होता है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात दशाओं से संबंधित नहीं है, विशिष्ट नहीं है और सामान्यतः उपलब्ध है।
195. सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह निषिद्ध नहीं है और विशिष्ट नहीं है। लाभ समग्र रूप से कंपनी के लिए प्राप्त हुआ था और न कि पी यू सी के लिए विशिष्ट रूप से।
196. यह बताया गया है कि प्रतिसंतुलन योग्यता संबंधी याचिकाकर्ता का अनुरोध निराधार है। जी ओ एम ने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले लोग ए सी ए का दावा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत परिकलित सब्सिडी मार्जिन नगण्य है और किसी शुल्क की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए।
197. प्रकटन विवरण के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्जिन नगण्य है और किसी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

198. यह नोट किया गया है कि यह कार्यक्रम पूंजी भत्ता प्रदान करता है अर्थात् एक भत्ता जो किसी सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण की खरीद पर हुए पूंजीगत व्यय के पांचवें हिस्से के बराबर होगा। यह कार्यक्रम भत्ते को अपने कर योग्य आय से हटाने की अनुमति कंपनी को देता है।

199. यह भी नोट किया गया है कि यह कार्यक्रम पूँजीगत भत्ता अर्थात् पुनः निवेश भत्ता अवधि के 15 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संवर्धित कार्यकलाप की सांविधिक आय से पूँजीगत व्यय की कटौती प्रदान करता है। यह कार्यक्रम तीन वर्षों के भीतर कुल पूँजीगत व्यय को बढ़ाव खाते में डालने की अनुमति देता है अर्थात् पहले वर्ष में 20 प्रतिशत का आरंभिक भत्ता और अगले दो वर्षों में 40 प्रतिशत का वार्षिक भत्ता।
200. यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह संवर्धित कार्यकलाप करने वाले कनिपय उद्यमों जो इस भत्ते के पात्र हों, के लिए उपलब्ध है और जो 15 वर्ष की पात्रता अवधि जिनमें पात्रता व्यय हुआ हो, की समाप्ति पर पुनः निवेश भत्ते के लिए पात्र न हो, हेतु उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य कार्यक्रम मानते हैं।
201. यह नोट किया गया है कि लॉगिंग के प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार कंपनी ने उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है। जबकि मै० सेगमत पैनल बोर्ड ने लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी ने मै० सेगमत पैनल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है। निर्धारित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

कार्यक्रम संख्या 8: टैरिफ से जुड़े प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 13: कच्ची सामग्री/कलपुर्जों पर आयात कर की छूट

202. कार्यक्रम सं. 8 और कार्यक्रम सं. 13 के अंतर्गत प्रदत्त लाभ समान हैं इसलिए इन दोनों कार्यक्रमों का विश्लेषण एक साथ किया गया है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

203. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उक्त कार्यक्रम रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट (आर एम सी डी) और मलेशिया इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम आई डी ए) द्वारा प्रशासित होते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 14(2) कच्ची सामग्री/कलपुर्जों पर आयात शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करती है बशर्ते कि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध न हो और अनुमोदित विनिर्माता की परिसर (परिसरों) में अंतिम उत्पाद के उत्पादन में सीधे प्रयुक्त होते हों। यह छूट अंतिम उत्पाद के उत्पादन पर लागू है चाहे वह निर्यात के लिए हों या घरेलू बाजार के लिए। यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन उद्यमों तक सीमित है जो ऐसी कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

204. मलेशिया सरकार ने बताया कि इस कार्यक्रम में पात्र विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री/कलपुर्जों पर शुल्क छूट का मूल्यांकन करना शामिल है। यह कार्य एमओएफ, एमआईटीआई, आरएमसीडी और एमआईडीए से प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है इसका पात्र होने के लिए कच्ची सामग्री/कलपुर्जों स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होने चाहिए और उनका प्रयोग विनिर्माता के अनुमोदित परिसरों में अंतिम उत्पाद के उत्पादन में सीधे होना चाहिए। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह एएससीएम के अनुबंध I, II और III के उपबंधों के अनुरूप है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

205. यह नोट किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट (आर एम सी डी) और मलेशिया इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम आई डी ए) द्वारा प्रशासित होते हैं। इस कार्यक्रम में कच्ची सामग्री/कलपुर्जों पर आयात शुल्क से अनुमोदित विनिर्माताओं को छूट दी जाती है। छूट तब दी जाती है जब कच्ची सामग्री/कलपुर्जों स्थानीय रूप से उपलब्ध न हो और उनका उपयोग अनुमोदित विनिर्माता के परिसर (परिसरों) में अंतिम उत्पाद के उत्पादन में सीधा किया जाए।
206. यह भी नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह ऐसे उद्यमों तक सीमित है जो स्थानीय रूप से अनुपलब्ध कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य कार्यक्रम मानते हैं।

207. यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं दिया गया है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यक्रम संख्या 9: संयंत्र और मशीनरी हेतु भत्ता

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

208. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उक्त कार्यक्रम इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा प्रशासित है। आयकर अधिनियम, 1967 की अनुसूची तीन मशीनरी या संयंत्र पर कंपनी के पात्र खर्च के 20 प्रतिशत राशि का पूंजीगत भत्ता (सी ए) प्रदान करती है अर्थात् आकलन वर्ष में व्यापार के लिए स्थिर परिसंपत्ति के मूल्यहास में राहत देती है। सी ए को सांविधिक आय ज्ञात करने में व्यापार से समायोजित आय से घटाया जाता है। यह कार्यक्रम ऐसे राजस्व को गंवाए जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशिष्ट रूप से ऐसे क्षेत्रों हेतु लाभप्रद है जिनका उच्च पूंजीगत व्यय है और जो पात्रता मापदंड पूरे करते हैं।
209. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त लाभ ऐसे हैं कि ये पी यू सी तक जाएंगे। इसके अलावा, धनराशि क्षयकारी है और कंपनी के पास इसका किसी व्यापार खंड में प्रयोग करने का विवेकाधिकार है। किसी सी वी डी जांच में जांच का विषय समग्र रूप से कंपनी होती हैं और न कि उत्पाद।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

210. मलेशिया सरकार ने बताया कि पूंजीगत भत्ता मशीनरी या संयंत्र पर पात्र खर्च के लिए कटौतियां हैं इसे आकलन वर्ष हेतु परिकलित किया जाता है और सांविधिक आय ज्ञात करने में समायोजित आय से घटाया जाता है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात दशाओं से संबंधित नहीं है, विशिष्ट नहीं है और सामान्यतः उपलब्ध है।
211. मैं० सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. और रोबिन रिसोसेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह निर्विद्ध या विशिष्ट नहीं है। इसका लाभ समग्र रूप से कंपनी को प्राप्त हुआ था और न कि पी यू सी के लिए विशिष्ट रूप से।
212. निर्यातकों ने बताया कि यह कार्यक्रम न तो विशिष्ट है न ही निर्यातों से संबंधित है। जी ओ एम ने यह भी बताया कि कार्यक्रम सभी कंपनियों हेतु उपलब्ध है और पात्रता मापदंड पूरा करने वाली कंपनियां पूंजीगत भत्ते का दावा कर सकती हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

213. यह नोट किया गया है कि पूंजीगत भत्ते में मशीनरी या संयंत्र पर पात्र खर्च हेतु कटौतियां की जाती हैं। यह ऐसे उद्यम को दिया जाता है जो पात्र खर्च करता है इसे आकलन वर्ष हेतु परिकलित किया जाता है और सांविधिक आय ज्ञात करके व्यापार से समायोजित आय में से घटाया जाता है इसे भत्ते की विहित दर के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार परिकलित किया जाता है।
214. यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यद्यपि यह कानून के अनुसार सामान्यतः उपलब्ध है। तथापि, यह उन कंपनियों को लाभ देगा जिनका प्रक्रिया में उच्च पूंजीगत व्यय है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
215. मैं० सेगमत पैनल बोर्ड और मैं० रोबिन रिसोसेज दोनों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार यह नोट किया गया कि उन्होंने इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मैं० सेगमत पैनल बोर्ड तथा मैं० रोबिन रिसोसेज पर लगाये जाना चाहिए। प्राधिकारी ने मैं० सेगमत पैनल बोर्ड और मैं० रोबिन रिसोसेज द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत उनकी सूचना के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा ज्ञात की है।

कार्यक्रम संख्या 10: ईस्ट कोस्ट इकोनॉमी कोरिडोर में विनिर्माण से जुड़ी सेवाओं हेतु प्रोत्साहन याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

216. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उक्त कार्यक्रम इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया और ईस्ट कोस्ट इकोनॉमी रीजन डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा प्रकाशित होता है। आयकर (छूट) (संख्या 4) आदेश 2016 ईस्ट कोस्ट में स्थित कंपनियों और ऐसे उत्पादन प्रक्रिया में शामिल कंपनियों जो अनुमोदन समिति से अनुमोदन के अधीन मूल्यवर्धन करती हैं, को कर छूट प्रदान करता है। कर छूट प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर विशिष्ट प्रोत्साहन के रूप में या कंपनी द्वारा सांविधिक आय अर्जित करने के वर्ष से 10 वर्षों के लिए आयकर में 100 प्रतिशत की छूट या पांच वर्षों के लिए पात्र पूंजीगत व्यय (निवेश कर भत्ता) की राशि पर आयकर से 100 प्रतिशत छूट या विकास के लिए अधिग्रहीत भूमि या भवन पर स्टाम्प शुल्क से छूट के रूप में हो सकती है। यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह संवर्धित उत्पादों तक सीमित है और क्षेत्र विशिष्ट के लिए भी है अर्थात् ऐसे उद्यमों जिनकी परियोजना ईस्ट कोस्ट इकोनॉमी कोरिडोर में स्थित हो।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

217. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि कर छूटें ऐसी किसी कंपनी को दी जा सकती हैं जिसका इरादा किसी संवर्धित कार्यकलाप में भागीदारी करने या वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसी संवर्धित उत्पाद का उत्पादन करने का हो जिसमें मलेशिया के राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के कार्यकलाप/उत्पाद शामिल हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए (1) परियोजना को ईस्ट मलेशिया के पूर्वी तट पर स्थित होना चाहिए (2) मूल्यवर्धन होना चाहिए और (3) प्रबंधकीय, तकनीकी और पर्यवेक्षण (एमटीएस) सूचकांक द्वारा यथा मापित उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का होना चाहिए यह लाभ अगे अनुमोदित समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
218. सरकार ने यह भी अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे क्योंकि यह ओ ई सी डी के अंतर्गत हानिकारक कर प्रथा कार्यक्रम संबंधी मंच को अपनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

219. यह नोट किया गया है कि ऐसी कंपनी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयकर से पूरी छूट दी जाती है जिसकी परियोजना ईस्ट कोस्ट आर्थिक कोरिडोर में स्थित हो और जो संवर्धित कार्यकलाप में भागीदारी या संवर्धित उत्पाद के उत्पादन का इरादा रखती हो जिसमें मलेशिया के लिए राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के कार्यकलाप/उत्पाद शामिल हैं।
220. यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह संवर्धित उत्पादों तक सीमित है और क्षेत्र विशिष्ट के लिए भी है अर्थात् ऐसे उद्यमों जिनकी परियोजना ईस्ट कोस्ट आर्थिक कोरिडोर में स्थित हो। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
221. तथापि, संबद्ध वस्तु का कोई भी उत्पादक ईस्ट कोस्ट आर्थिक कोरिडोर में स्थित नहीं पाया गया है इसलिए यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवादी नियांतकों के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 11: आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रा बैक

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

222. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट (आर एम सी डी) द्वारा प्रशासित है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 93,95 और 99 ऐसे आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रा बैक प्रदान करती है जिनके भुगतान पर किसी भी विनिर्माता द्वारा दावा किया जा सकता है। यदि उसके हिस्से, कच्ची सामग्री या पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग अधिनियम में निर्धारित स्थितियों के आधार पर वर्ष के भीतर निर्यात हेतु वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाए। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड,

वियतनाम से “कान्टीन्यूअस कास्ट कापर वायर राड्स” संबंधी सी बी डी जांच के अंतिम जांच परिणामों में डी ए द्वारा विशिष्ट और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

223. मलेशिया सरकार ने बताया कि इस कार्यक्रम में आयातित और बाद में पुनः निर्यातित वस्तु पर आयात शुल्क वापसी प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह एएससीएम के अनुबंध I, II और III के प्रावधानों के अनुरूप है। पाकिस्तान से कतिपय पोलिथाईलीन ट्रेफेलेट (डीएस 486) पर इंयू-प्रतिसंतुलनकारी उपायों में पैनल की रिपोर्ट जिसे बाद में अपीलीय निकाय द्वारा माना गया था, में यह माना गया कि उत्पाद को उस सीमा तक प्रतिसंतुलित किया जा सकता है जिसमें किसी कंपनी द्वारा प्राप्त शुल्क की वापसी आयातित निविष्टि पर लगे शुल्क से अधिक हो।

प्राधिकारी द्वारा जांच

224. यह नोट किया गया है कि यह कार्यक्रम रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट (आर एम सी डी) द्वारा शासित है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1967 की धारा 93,95 और 99 में आयात शुल्क बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर तब ड्रा बैक किया गया है जबकि इनके भुगतान का दावा विनिर्माता द्वारा किया जाए यदि उसके हिस्से, कच्ची सामग्री या पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग अधिनियम में निर्धारित शर्तों पर आधारित किसी वर्ष के भीतर निर्यात हेतु वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाए। यह कार्यक्रम ऐसी वस्तुओं पर आयात शुल्क वापसी प्रदान करता है जिन्हें बाद में पुनः निर्यातित किया जाए। यह दर्शाने के किसी साक्ष्य के अभाव में कि इस कार्यक्रम में अनुमति प्राप्त शुल्क वापसी है। यह निर्धारित किया गया है कि यह सबिसडी कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम निर्यात विशिष्ट है अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य कार्यक्रम मानते हैं।
225. तथापि, यह नोट किया गया है कि किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं लिया गया है। इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यक्रम संख्या 12: बिक्री कर से छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

226. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट (आर एम सी डी) द्वारा प्रशासित है। बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश 2018 इस आदेश में सूचीबद्ध विशिष्ट व्यक्तियों को बिक्री कर भुगतान से छूट देता है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल आदेश के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
227. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त लाभ ऐसे हैं कि ये पी यू सी तक जाएंगे। इसके अलावा, धनराशि क्षयकारी है और कंपनी के पास इसका किसी व्यापार खंड में प्रयोग करने का विवेकाधिकार है। किसी सी बी डी जांच में जांच का विषय समग्र रूप से कंपनी होती हैं और न कि उत्पाद।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

228. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश 2018 के अंतर्गत आयात पर और स्थानीय रूप से विनिर्मित वस्तुओं की खरीद पर व्यक्तियों या विनिर्माताओं को बिक्री कर से छूट प्राप्त है। ये छूटें आदेश के अधीन तीन अनुसूचियों में वर्गीकृत हैं।
229. मैं० सेगमट पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. और रोबिन रिसोसेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह निषिद्ध या विशिष्ट नहीं है और न ही निर्यात से संबंधित है। कंपनी को समग्र रूप से लाभ प्राप्त हुआ है और न कि पी यू सी विशिष्ट के लिए।

230. जी ओ एम ने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध है और पात्रता मापदंड पूरा करने वाली कंपनियां बिक्री कर से छूट का दावा कर सकती हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

231. यह नोट किया जाता है कि यह कार्यक्रम रॉयल मलेशियन कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा प्रशासित है। बिक्री कर (कर के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्ति) आदेश 2018 इस आदेश में सूचीबद्ध विशिष्ट व्यक्तियों को बिक्री कर भुगतान से छूट देता है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल आदेश के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी इसे प्रतिसंतुलन योग्य कार्यक्रम मानते हैं।
232. मैं० सेगमत पैनल बोर्ड और मैं० रोबिन रिसोसेज दोनों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार यह नोट किया गया कि उन्होंने इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मैं० सेगमत पैनल बोर्ड तथा मैं० रोबिन रिसोसेज पर लगाये जाना चाहिए। प्राधिकारी ने मैं० सेगमत पैनल बोर्ड और मैं० रोबिन रिसोसेज द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत उनकी सूचना के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा ज्ञात की है।

कार्यक्रम संख्या 14: निर्यातों के संवर्धन हेतु दोहरी कटौती

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

233. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा प्रशासित है। आयकर (निर्यातों का संवर्धन) नियम 1986 के नियम 4(2) के साथ पठित निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 41 में मलेशियाई विनिर्मित वस्तुओं या कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अवसर बनाने या मांग सूजित करने अथवा उसे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ हुए व्यय पर आयकर से छूट दी गई है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह निर्यात कार्य निष्पादन से संबंधित है और निर्यात संवर्धन कार्यकलाप में शामिल उद्यमों तक सीमित है।
234. इस कार्यक्रम की प्राधिकारी द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से “कांटीन्यूअस कास्ट कापर वायर राइस” के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व में जांच की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था।
235. मैं० सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. कार्यक्रम के लिए पात्र होने के बावजूद इसका लाभ नहीं लेने के कारण बताने में विफल रहा है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

236. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम मलेशियाई विनिर्मित वस्तुओं या कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अवसर बनाने या मांग सूजित करने अथवा उसे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ हुए व्यय के संबंध में सभी निवासी व्यापारी, विनिर्माण या कृषि कंपनियों पर लागू है।
237. रोबिन रिसोसेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह निषिद्ध या विशिष्ट नहीं है। लाभ कंपनी को समग्र रूप से प्राप्त होते हैं न कि पी यू सी के लिए विशिष्ट रूप से।
238. यह भी बताया गया है कि लाभ स्वचालित नहीं है और उसके लिए एक आवेदन अपेक्षित है। मैं० सेगमत पैनल बोर्ड को इससे कभी भी लाभ नहीं मिला है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

239. यह नोट किया गया है कि यह कार्यक्रम निवेश संवर्धन अधिनियम, 1986 की धारा 41 और आयकर (निर्यात संवर्धन) नियम 1986 की धारा 4(2) द्वारा शासित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयकर से ऐसे उद्यमों को दोहरी कटौती दी जाती है जो निर्यात संवर्धन के लिए हुए खर्च हेतु विनिर्माण, व्यापार और किसी कार्यकलापों में शामिल है।

240. यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह लाभ दोहरी कटौती के पश्चात प्रदत्त आयकर की राशि और ऐसी दोहरी कटौती के अभाव में देय आयकर की राशि के बीच का अंतर है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात कार्य निष्पादन से संबंधित है और निर्यात संवर्धन कार्यकलाप में शामिल उद्यम तक सीमित है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
241. मैं० रोबिन रिसोर्सेज द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार यह नोट किया गया कि इस कंपनी ने सब्सिडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तथापि, मैं० सेगमत बोर्ड द्वारा ऐसा कोई लाभ नहीं लिया गया है। तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मैं० रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत उनकी सूचना के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा ज्ञात की है।

कार्यक्रम संख्या 16: लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

242. याचिकाकर्ता ने बताया कि उक्त कार्यक्रम इनलैंड रिवेन्यू मलेशिया द्वारा प्रशासित है। आयकर अधिनियम 1967 की अनुसूची एक किसी रेसीडेंट कंपनी को आधार अवधि की शुरूआत पर आर एम 2.5 मिलियन और उससे कम की प्रदत्त पूंजी वाली किसी रेसीडेंट कंपनी के लिए विशेष कर दर प्रदान करता है। ऐसी कंपनियों के लिए पहले आर एम 500,000 प्रभार योग्य आय पर 18 प्रतिशत और तत्पश्चात प्रभार योग्य आय पर 24 प्रतिशत की आयकर दर है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह लघु और मध्यम उद्यमों तक सीमित है।
243. मैं० सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के बावजूद इसका लाभ नहीं लेने के कारण बताने में विफल रहा है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

244. मलेशिया सरकार ने बताया कि पहली आर एम 500,000 प्रभार योग्य आय के लिए 18 प्रतिशत और तत्पश्चात प्रभार योग्य आय के लिए 24 प्रतिशत की विशेष कर की दर की आधार अवधि की शुरूआत में आर एम 2.5 मिलियन और उससे कम की किसी रेसीडेंट कंपनी को प्रदान की जाती है। यह कंपनी किसी कंपनी समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए जिसमें किसी संबंधित पक्षकार के पास आर एम 2.5 मिलियन से अधिक प्रदत्त पूंजी हो।

प्राधिकारी द्वारा जांच

245. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत एसएमई अर्थात आर एम 2.5 मिलियन या उससे कम के प्रदत्त पूंजी वाले उद्यम के लिए आयकर की अधिमानी दर है। आर एम 500,000 तक आय पर 18 प्रतिशत और उससे अधिक आर एम 500,000 पर 24 प्रतिशत की दर से आयकर प्रभार योग्य है।
246. यह कार्यक्रम गंवाए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह लघु और मध्यम उद्यमों तक सीमित है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
247. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षक रिकार्ड दर्शाता है कि आयकर का भुगतान सामान्य आयकर दर पर किया गया है इसलिए उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। इसके मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाना जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 17: निर्यात में वृद्धि के लिए भत्ता

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

248. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उक्त कार्यक्रम इनलैंड रिवेन्यू मलेशिया द्वारा प्रशासित है। आयकर (बढ़े हुए निर्यातों हेतु भत्ता) नियम 1999 भत्ता प्रदान करता है जो विनिर्मित उत्पादकों के बढ़े हुए निर्यात के मूल्य के 10 प्रतिशत

के बराबर है जहां निर्यातित उत्पादों ने कम से कम 30 प्रतिशत मूल्यवर्धन प्राप्त किया हो या जहां उत्पादों का निर्यात हुआ हो, वहां 15 प्रतिशत कम से कम 50 प्रतिशत के मूल्यवर्धन पर या कंपनी द्वारा किसी उत्पाद के बढ़े हुए निर्यात के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर है। ऐसा भत्ता कंपनी की सांविधिक व्यापार आय के 70 प्रतिशत के तहत दिया जाता है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों से संबंधित है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

249. मलेशिया सरकार ने बताया कि कोई रेसीडेंट विनिर्माण कंपनी या कृषि कंपनी जो आकलन वर्ष के लिए आधार वर्ष में निर्यात करती है, को बढ़े हुए निर्यात हेतु भत्ता दिया जाता है। यदि उत्पाद विनिर्मित है तो भत्ता निम्नानुसार निर्धारित होता है:

- कंपनी के विनिर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यात से मूल्य का 10 प्रतिशत जहां निर्यातित उत्पादों में कम से कम 30 प्रतिशत मूल्यवर्धित हुआ हो।
- कंपनी के विनिर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यातों के मूल्य के 15 प्रतिशत जहां निर्यातित उत्पादों का कम से कम 50 प्रतिशत मूल्यवर्धित हुआ हो।

प्राधिकारी द्वारा जांच

250. यह नोट किया गया है कि कोई रेसीडेंट विनिर्माण कंपनी या कृषि कंपनी जो विनिर्मित उत्पादों का निर्माण करती है, को बढ़े हुए निर्यातों के लिए भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बढ़े हुए निर्यातों से मूल्य के 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत के बराबर होता है। यह भत्ता सांविधिक व्यापार आय के 70 प्रतिशत के तहत दिया जाएगा।

251. यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात कार्य निष्पादन से संबंधित है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

252. तथापि, किसी भी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा इस कार्यक्रम के तहत लाभ नहीं लिया गया है। इसलिए यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवादी निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाए जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 18: मुक्त व्यापार जोनों में निर्यातकों के लिए कर में छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

253. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम फ्री जोन अथारिटी और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रशासित होता है। फ्री जोन अधिनियम 1990 और फ्री विनियम 1991 ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को कर/शुल्क के भुगतान से छूट देता है जो फ्री जोन अधिनियम 1990 की धारा 3(1) के अंतर्गत घोषित किसी फ्री जोन में लाई जाएं। उत्पादित विनिर्मित या दी जाएं। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है जो अन्यथा बकाया होता और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह संवर्धित उत्पादों तक सीमित है और क्षेत्र अर्थात् वह उद्यम जिसकी परियोजना फ्री जोन में स्थित है, तक विशिष्ट भी है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

254. मलेशिया सरकार ने बताया कि ऐसे विवरण की वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से या समग्र रूप से कानून द्वारा निषिद्ध हों, किसी शुल्क/कर के भुगतान के बिना फ्री जोन में लाई जा सकती हैं। उत्पादित विनिर्मित या प्रदान की जा सकती हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

255. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम फ्री जोन अधिनियम 1990 और फ्री जोन अधिनियम 1991 द्वारा प्रशासित होता है। फ्री जोन वित्त मंत्री द्वारा नियुक्त फ्री जोन प्राधिकारियों द्वारा फ्री जोन के प्रशासन, रखरखाव और प्रचालन के जरिए प्रबंधित होते हैं। ऐसे विवरण की वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से या

समग्र रूप से कानून द्वारा निषिद्ध हों, किसी शुल्क/कर के भुगतान के बिना फ्री जोन में लाई जा सकती हैं। उत्पादित विनिर्मित या प्रदान की जा सकती हैं।

256. यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और उसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह फ्री जोन में स्थित उद्यमों हेतु उपलब्ध है। प्राधिकारी ने पहले ही निर्धारित किया है कि आयात शुल्कों से छूट प्रदान करने वाले सभिसडी कार्यक्रम के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
257. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक फ्री ट्रेड जोन में स्थित नहीं है इसलिए वे इस कार्यक्रम के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। इसके मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि इस सभिसडी कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम संख्या 19: निवेश कर भत्ता

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

258. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उक्त कार्यक्रम मलेशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमआईडीए) और इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा प्रशासित है। आयकर अधिनियम 1967 की धारा 127(3ए) कतिपय मामलों के तथ्यों पर प्रदत्त निवेश कर भत्ता (आटीए) प्रदान करती है जैसे पूंजी प्रधान काफी लिंकेज बनाने में सक्षम आयात प्रतिस्थापन, उच्च मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन, विनिर्माण सहायता सेवाओं के विकास में योगदान और देश पर परवर्ती प्रभाव। आईटी ए को आगे कंपनी की कर योग्य आय से घटाया जाता है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है जो अन्यथा बकाया होता और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह ऐसे उद्यमों तक सीमित है जो पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं और अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित हैं।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

259. मलेशिया सरकार ने अनुरोध किया है कि निवेश कर भत्ता कतिपय मामलों के तथ्यों पर किसी कंपनी को प्रदान किया जा सकता है जैसे पूंजी प्रधान काफी लिंकेज बनाने में सक्षम आयात प्रतिस्थापन, उच्च मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन, विनिर्माण सहायता सेवाओं के विकास में योगदान और देश पर परवर्ती प्रभाव। कंपनियां एमआईडीए को प्रस्तुत अपने आवेदन से अनुमोदन के अधीन कार्यक्रम का लाभ उठा सकती हैं। सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करने के बावजूद अनुमोदन समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।
260. मैरी रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है क्योंकि यह निषिद्ध या विशिष्ट नहीं है। इसका लाभ कंपनी को समग्र रूप से प्राप्त हुआ था और न कि पी यू सी के विशिष्ट रूप से।

प्राधिकारी द्वारा जांच

261. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम मलेशियन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमआईडीए) और इनलैंड रिवेन्यू बोर्ड मलेशिया द्वारा प्रशासित है। कार्यक्रम के अंतर्गत कतिपय मामलों के तथ्यों के आधार पर निवेश कर भत्ता (आटीए) प्रदान किया जाता है जैसे पूंजी प्रधान काफी लिंकेज बनाने में सक्षम आयात प्रतिस्थापन, उच्च मूल्यवर्धन प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन, विनिर्माण सहायता सेवाओं के विकास में योगदान और देश पर परवर्ती प्रभाव। इस भत्ते को आगे कंपनी की कर योग्य आय से घटाया जाता है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है जो अन्यथा बकाया होता, और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल ऐसे उद्यमों तक उपलब्ध है जो पात्रता व्यवहार करते हैं। मलेशिया सरकार के अनुसार उक्त लाभ सहयोगी निर्यातकों को प्राप्त हुआ है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
262. कार्यक्रम संख्या 5 शीर्ष के अंतर्गत मैरी रोबिन रिसोर्सेज द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार यह नोट किया गया कि इस कंपनी ने सभिसडी कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया है। तदनुसार, यह नोट किया जाता है कि इस

सब्सिडी कार्यक्रम के तहत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क मै० रोबिन रिसेंसेज के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने रोबिन रिसेंसेज द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत उनकी सूचना के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा ज्ञात की है।

कार्यक्रम संख्या 20: पर्याप्त से कम मूल्य पर स्थायी इमारती लकड़ी का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

263. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम राज्य वानिकी विभाग द्वारा प्रकाशित होता है। मलेशिया सरकार लगभग मलेशिया के समस्त बनों का नियंत्रण करती है और ये लॉगिंग हेतु कंपनियों को पट्टे पर दिए जाते हैं जिस पर स्टंपेज की दर लगती है। राष्ट्रीय वानिकी अधिनियम 1984 की धाराओं 60, 61 और 75 तथा राज्य बन नियम के नियम 22 और 23 में स्टंपेज के लिए बाजार बेंचमार्क से कम प्रभार पर स्टंपेज का प्रावधान है। सरकार रबड़वुड, बागान और आश्रित उद्योगों की सहायता हेतु पुनः रोपण सब्सिडी भी प्रदान करती है। सरकार ने रबड़वुड के निर्यातों पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तुओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्राथमिक रूप से उन उद्यमों के लिए लाभप्रद है जो कच्ची सामग्री के रूप में इमारती लकड़ी का प्रयोग करते हैं।
264. मलेशिया से प्रतिवादी उत्पादकों की वेबसाइट सूचना के अनुसार पी यू सी के उत्पादन हेतु रबड़वुड और ट्रापिकल मिश्रित वुड का कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होता है।
265. राष्ट्रीय वानिकी अधिनियम के अनुसार “बन उत्पाद” एक समावेशी परिभाषा है और इसमें कहीं भी रबड़वुड को स्पष्टतः अलग नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकार के अनुसार यदि रबड़वुड पर कोई रायलटी प्रभारित नहीं होती है तो इससे और अधिक सब्सिडी सिद्ध होती है।
266. राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रभारित रायलटी विवेकाधीन है और बाजार सिद्धांतों की अनदेखी करती है। इसलिए लॉगिंग हेतु बदले में रायलटी प्रभारित करना अपने आप में मलेशिया में वानिकी क्षेत्र की विकृति है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

267. जी ओ एम और प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने बताया है कि प्राधिकारी को नई कथित सब्सिडियों को अस्वीकृत करना चाहिए जिनका आरोप लिखित अनुरोध के समय लगाया गया जो एएससीएम के विरुद्ध हैं। रबड़वुड संगत विधान के अंतर्गत बन उत्पाद की परिभाषा के भीतर नहीं आती है। रबड़वुड पर कोई रायलटी संग्रहीत नहीं होती है और इसलिए कोई माफी संभव नहीं है।
268. रबड़वुड संगत विधान के अंतर्गत ‘बन उत्पाद’ की परिभाषा के भीतर नहीं आती है।
269. रबड़वुड पर कोई रायलटी संग्रहीत नहीं होती है और इसलिए कोई माफी संभव नहीं है।
270. एसपीबी ने लकड़ी/विद्युत/भूमि/गैस खुले बाजार से और निजी कंपनियों से खरीदी थी।

कार्यक्रम संख्या 21: लॉग के निर्यातों का सरकारी निषेध

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

271. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम बागान उद्योग और वस्तु मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। राष्ट्रीय टिंबर उद्योग नीति, 2009-2020 के अंतर्गत 2018 से सबाह में और 1985 से पेनिनसुलर मलेशिया में लॉग के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध मौजूद है। सारावाक में 1988 से लॉग के निर्यात पर इसके उत्पादन के 80 प्रतिशत तक प्रतिबंध है। रबड़वुड की निर्यात पर 2017 से एक अस्थायी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध है। निर्यात बाधाओं के लगाने से लॉग का घरेलू बाजार विकृत हो गया है और ये पर्याप्त से कम मूल्य पर डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं। अतः यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तुओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और उसके द्वारा लाभ हुआ है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्राथमिक रूप से ऐसे उद्यमों के लिए लाभकारी है जो कच्ची सामग्री के रूप में टिंबर का प्रयोग करते हैं।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

272. जी ओ एम और प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने बताया है कि प्राधिकारी को नई कथित सब्सिडियों को अस्वीकृत करना चाहिए जिनका आरोप लिखित अनुरोध के समय लगाया गया जो एएससीएम के विरुद्ध हैं। किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने लाभ नहीं उठाया है।
273. मैं० रोबिन रिसोर्सेज ने बताया कि सभी प्रकार की लकड़ी खुले बाजार से खरीदी जाती है और वह तत्समय बाजार मूल्य को बिल्कुल सही प्रदर्शित करती है। लकड़ी के विक्रेता निजी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं और सरकारी एजेंसियां नहीं हैं। उन्हें सरकार से कोई अनुदान या सब्सिडी नहीं मिलती है। इसके अलावा, खरीदी गई लकड़ी वन से प्राप्त टिंबर आकार के लॉग जैसी नहीं होती है। लकड़ी को मुख्यतः रबड़वुड, बागानों से लिया जाता है जहां बागान मालिक अपने रबड़ के पेड़ों को पुनः लगाना चाहते हैं या मिक्स बुड़ को विभिन्न सॉमिल्क कारखानों से खरीदा जाता है, जहां वे टिंबर लॉग का प्रसंस्करण करते हैं और उनके उत्पादन लाइनों से समस्त अपशिष्ट को फाइबर बोर्ड उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री के रूप में बेचा जाता है। इस प्रकार ऐसे संसाधन में कोई सरकारी हस्तक्षेप पूर्णतः गलत है।
274. एसपीबी ने लकड़ी/विद्युत/भूमि/गैस खुले बाजार से और निजी कंपनियों से खरीदी थी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

275. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सं. 20 और 21 मलेशिया में वन क्षेत्र को विनियमित, उसकी निगरानी और नियंत्रण हेतु मलेशिया सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों से संबंधित है। चूंकि इन कार्यक्रमों का प्रभाव पर्याप्त से कम मूल्य पर टिंबर प्रदान करना है। इसलिए इन कार्यक्रमों को मिलाना और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संचयी रूप से उनकी जांच करना उचित समझा गया है।
276. जी ओ एम और प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने बताया है कि प्राधिकारी को नई कथित सब्सिडियों को अस्वीकृत करना चाहिए जिनका आरोप लिखित अनुरोध के समय लगाया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी संबद्ध देशों से ऐसे किसी अन्य कार्यक्रम की जांच कर सकते हैं जिसका खुलासा कार्रवाई योग्य सब्सिडी के रूप में जांच की प्रक्रिया के दौरान हो सकता हो।
277. आवेदकों ने दलील दी है कि मलेशिया सरकार राष्ट्रीय वानिकी अधिनियम 1984 के जरिए मलेशिया से लगभग समस्त हरित वनों को नियंत्रित करती है। अधिनियम की धारा 19 में राज्य प्राधिकारियों को वन उत्पाद लेने हेतु कंपनियों को लाइसेंस देने की अनुमति है जिनमें स्थायी आरक्षी वन और राज्य भूमि से पेड़ और उसके हिस्से शामिल हैं। इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र सहित लाइसेंस प्रदान करना और लाइसेंस का नवीकरण राज्य प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर है। अधिनियम की धारा 61 के अनुसार वन उत्पाद के संग्रहण पर लाइसेंस धारक को राज्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दर पर रायल्टी का भुगतान करना अपेक्षित है। यह अधिनियम राज्य प्राधिकारियों को किसी वन उत्पाद जो अन्यथा अलाभकारी है, की प्रजाति के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए रायल्टी को माफ करने, परिवर्तित करने या छूट देने की शक्ति भी प्रदान करता है।
278. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जी ओ एम का उचित विधान के जरिए वानिकी क्षेत्र पर नियंत्रण दर्शाता है कि नए बाजार भागीदारों के प्रवेश पर काफी अवरोध है और यह कि जी ओ एम के पास बाजार हिस्से को बनाये रखने और उसमें वृद्धि करने दोनों की क्षमता थी। निर्यात प्रतिबंध राष्ट्र के भीतर उत्पाद को सीमित करता है और तदनुसार, मलेशिया में लकड़ी की कीमत नियंत्रित करता है।
279. राष्ट्रीय वानिकी अधिनियम के अनुसार परिभाषा खंड में “वन उत्पाद” शामिल हैं जिसमें (i) पेड़ और सभी हिस्से या उत्पाद जिन्हें इसके बाद पेड़ नहीं बताया गया है (ii) पौधे जिनमें लता, बेल और धास तथा ऐसे पौधों के सभी हिस्से या उत्पाद शामिल हैं। (iii) रेशम, कोकून, शहद और वैक्स तथा पक्षियों के खाद्य घोसले समाहित हैं। इसके अलावा, इसमें बताया गया है (ग) निम्नलिखित जिन्हें किसी थाई आरक्षित वन, राज्य भूमि, खनन भूमि, आरक्षित भूमि या पृथक भूमि में पाया गया या वहां से लाया गया है: इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चारकोल, गेटाह टबन, पत्तियां, लकड़ी का तेल, छाल, छाल का सारतत्व, डामर और अटाप। इसके अलावा, राष्ट्रीय वानिकी अधिनियम की धारा 61 और 62 (1) के अनुसार, “समस्त वन उत्पाद जिन्हें राज्य प्राधिकरण द्वारा राजपत्र में प्रकाशित रायल्टी दर सूची में निर्धारित दरों पर लिया गया है, के संबंध में राज्य प्राधिकारी को रायल्टी

देय होगी और धारा 61 के होते हुए भी राज्य प्राधिकरण किसी वन उत्पाद या लिए गए वन उत्पाद की श्रेणी के लिए रायल्टी में कटौती, परिवर्तन या उसे माफ या उसमें छूट प्रदान कर सकता है”।

280. इस अधिनियम में टिंबर को भी परिभाषित किया गया है। “टिंबर में ऐसे पेड़ शामिल हैं जो गिर गए या गिरा दिए गए हैं और समस्त लकड़ी चाहें काटी गई हो अथवा नहीं या किसी प्रयोजनार्थ तरासी गई या बनाई गई हो अथवा नहीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम में न तो विशेष रूप से रबड़वुड का उल्लेख है न ही टिंबर से रबड़वुड को स्पष्टतः निकाला गया है। इसलिए प्राधिकारी के पास यह विचार करने का कोई कारण नहीं है कि रबड़वुड मलेशिया के वन में शामिल नहीं है।
281. जहां तक लॉग के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध का संबंध है याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उक्त कार्यक्रम को मलेशिया सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। गोल (अप्रसंस्कृत) लॉग के निर्यातों पर 2001 में अधिक कटाई की समस्या का समाधान करने के लिए पुनः प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि मलेशिया सरकार ने रबड़वुड के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। निर्यात प्रतिबंध/निषेध लगाने के माध्यम से सरकार ने घरेलू वानिकी/कटाई कंपनियों को डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए कम कीमत की निविष्टियों (लट्टे/लकड़ी) प्रदान करने का कार्य सौंपा है/निदेश दिया है। विशिष्ट रूप से लॉग के निर्यात पर प्रतिबंध से जांच के अधीन कंपनियों को बाजार कीमत से कम पर वानिकी/कटाई कंपनियों से निविष्टियों (लॉग/लकड़ी) की खरीद की अनुमति मिली है।
282. यह नोट किया गया है कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रभारित रायल्टी विवेकाधीन में और बाजार सिद्धांतों की अनदेखी है। मलेशिया के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने बताया है कि वे रबड़वुड को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। प्राधिकारी ने पाया कि मलेशिया में भी लॉग के निर्यात पर प्रतिबंध है। ऐसे लक्षित निर्यात प्रतिबंध लगाकर जी ओ एम घरेलू डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को आर्थिक रूप से आयुक्ति संगत स्थिति में ला देती है जिससे उन्हें कम कीमत पर ऐसी कम कीमत पर अपनी वस्तु बेचने को बाध्य होना पड़ता है जो वह इस नीति के अभाव में प्राप्त कर सकते थे। इस उपाय से संबद्ध देश के लकड़ी के घरेलू बाजार में विकृति का वांछित प्रभाव मिला है और इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग के लाभार्थी कीमतों को कृत्रिम रूप से निचले स्तर पर लाया गया है।
283. यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर लकड़ी के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि इससे उन डाउनस्ट्रीम उद्योगों को लाभ मिलता है जो अपने प्राथमिक कच्ची सामग्री के रूप में लकड़ी प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त के महेनपजर प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
284. सब्सिडी मार्जिन की राशि निर्धारित करने हेतु प्राधिकारी ने उपयुक्त बेंचमार्क की तलाश की है जिसके द्वारा यह पाया गया कि न्यूजीलैंड वैश्विक रूप से लॉग के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। प्राधिकारी ने न्यूजीलैंड से लॉग के निर्यातों दरों को न्यूजीलैंड से आयात कीमत की तुलना में प्रतिनिधि रूप में उचित बेंचमार्क के रूप में माना है। लकड़ी की वास्तविक खरीद दर निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार मानी गई है। उचित परिवर्तन दर पर विचार करते हुए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

कार्यक्रम संख्या 22एः पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

285. भूमि के संबंध में यह कार्यक्रम जी ओ एम द्वारा प्रशासित है। कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि प्रीमियम के लिए 30 प्रतिशत छूट दी जाती है यदि वह परियोजना जिसके लिए भूमि दी गई है पूरी हो जाती है और प्रचालन भूमि देने की तारीख से 36 महीने के भीतर शुरू हो जाते हैं और भूमि के प्रीमियम पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती यदि भूमि देने की तारीख से 36 महीनों के भीतर परियोजना पूरी हो जाती है और प्रचालन शुरू हो जाता है। यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में लाभ प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उद्यम विशेष हेतु है। प्राधिकारी ने कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा ज्ञात की है। यह माना जा सकता है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय रिकार्ड लाभ उठाया जाना दर्शाते हैं। अतः प्राधिकारी से इसके समर्थन का अनुरोध है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

286. जी ओ एम ने इस स्कीम को बाहर रखने का अनुरोध किया है क्योंकि यह जांच के दायरे से बाहर है। फेडरल कांस्टीट्यूशन की नौवीं अनुसूची के अनुसार भूमि और भू-मार्ग संसाधन राज्य के दायरे में आते हैं जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राज्य सरकार के पास राज्य सचिव के कार्यालय के अधीन भूमि मामलों संबंधी मामलों विधान का प्राधिकार है। भूमि की बिक्री दर किसी समय विशेष के दौरान वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित होगी। कोई अलग कंपनी/पक्षकार भूमि खरीद को रद्द कर सकता है।
287. प्रतिवादी निर्यातकों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने खरीद के समय प्रचलित बाजार दरों पर निजी कंपनी से भूमि खरीदी है।
288. 1994 में मै० रोबिन रिसोसेज ने खुले बाजार की कीमत पर खुले बाजार माहौल में निजी मालिक से फ्री होल्ड भूमि खरीदी स्थानीय रूप से किसी सौदे के लिए बिक्री कीमत सरकारी प्राधिकरण के किसी हस्तक्षेप के बिना विक्रेता और क्रेता द्वारा निर्धारित होती है। मै० रोबिन रिसोसेज एसे राज्य में स्थित है जो पेनिनसुलर मलेशिया पूर्वी क्षेत्र में है तथा कम विकसित और सुविकसित शहरों से काफी दूर है। इसके अलावा, जनसंख्या भी सुविकसित जगहों से कम है तथा अवसंरचना भी अच्छी नहीं है। इन कारकों के साथ इस क्षेत्र में भूमि की कीमत निश्चित रूप से अच्छी अवसंरचना वाली को-विकसित भूमि से सस्ती है जो पेनिनसुलर मलेशिया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
289. किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने लाभ नहीं लिया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

290. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम मलेशिया के राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रशासित है। राष्ट्रीय भूमि संहिता, 1965 की धारा 76 में वार्षिक किराया/प्रीमियम के रूप में राशि की भुगतान पर राज्य की भूमि को देने की अनुमति है। तथापि, धारा 76 (सी) राज्य प्राधिकारियों को उपयुक्त मामलों में प्रीमियम से छूट देने की अनुमति देता है। प्रीमियम से छूट देने की शक्ति किसी कानून या विनियम द्वारा विनियमित नहीं होती है और यह राज्य प्राधिकारी के विवेक पर आधारित है।
291. यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर औद्योगिक भूमि के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि लाभ सरकारी/प्राधिकारियों के विवेक पर प्रदान किया जाता है और किसी कानून या विनियम से शासित नहीं होता है। अतः प्राधिकारी इस स्कीम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
292. सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के सब्सिडी प्राप्त प्रावधान के मामले में फर्म द्वारा प्रदत्त राशि तथा प्रचलित बाजार दशाओं से संबंधित पर्याप्त मूल्य के बीच का अंतर सब्सिडी की राशि होगा। भूमि पर प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किया गया खर्च प्रश्नावली के उनके उत्तर के साथ प्रस्तुत लेखा परीक्षक रिपोर्टों से लिया गया है। मलेशिया में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक भूमि की औसत कीमत को उचित बेंचमार्क के रूप में लिया गया है। परिकलित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

कार्यक्रम संख्या 22बी: पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

293. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम मलेशिया सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम द्वारा प्रशासित है। सरकार विद्युत खरीद करारों और भूमि प्रीमियम पर छूट के जरिए सब्सिडी प्राप्त बिजली प्रदान करती है। एलटीएआर पर बिजली के संबंध में प्राकृतिक गैस की कीमतें जो मलेशिया में विद्युत का प्राथमिक स्रोत हैं। बिजली क्षेत्र के लिए सांविधिक रूप से विनियमित होती है इसलिए एलटीएआर पर पी यू सी के उत्पादकों को विद्युत उपलब्ध है। इसकी जांच फ्लोट ग्लास और टेंपर्ड ग्लास संबंधी पूर्ववर्ती जांच में की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पायी गई थी। यह कार्यक्रम गंवाए गए एसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और जिसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशिष्ट उद्यमों और क्षेत्रों तक सीमित है।

मलेशिया सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

294. जी ओ एम ने इस स्कीम को बाहर रखने का अनुरोध किया है क्योंकि यह जांच के दायरे से बाहर है। ट्रांस्मिशन खंड में (उच्च दबाव) अंतिम प्रयोक्ता को प्राकृतिक गैस पेट्रोनास द्वारा आपूर्ति की गई है जबकि वितरण खंड (कम दबाव) में गैस मलेशिया बीएचडी. द्वारा आपूर्ति है। पेट्रोनास एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जबकि गैस मलेशिया बीएचडी. एक निजी कंपनी है।
295. ये स्कीम लागू नहीं है क्योंकि दोनों प्रतिवादी उत्पादक मै० सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. और रोबिन रिसोसेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. जांच अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस के उपभोक्ता नहीं हैं।
296. अंतिम ग्राहकों को (अर्थात् घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक) विद्युत की आपूर्ति पेनिनसुलर मलेशिया के लिए तेंगा नेशनल बर्हड के जरिए होती है तेंगा नेशनल बर्हड एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। जी ओ एम ने बताया कि मलेशिया में विद्युत के तीन उत्पादक (सुरुहानजाया तेंगा क्षेत्र के अंतर्गत) हैं : क. पेनिनसुलर मलेशिया के लिए तेंगा नेशनल बर्हड (टीएनबी); ख. कुलीम हाईटेक इंडस्ट्रीयल पार्क, केदाह के लिए एनयूआर पॉवर एसडीएनबीएचडी (एन यू आर), और ग. और ग. और डब्ल्यूबी लेबुआन के लिए सबाह इलेक्ट्रिसिटी एसडीएनबीएचडी (एसईएसबी)। टीएनबी एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है। एनयूआर एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है और एसपीएसबी निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। बिजली सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। तथापि, बिजली कीमत सरकार द्वारा विनियमित होती है। प्रोत्साहन आधारित विनियमित (आईबीआर) समग्र विद्युत नीति के अंतर्गत कार्य ढांचा है। इस कार्य ढांचे का उद्देश्य पेनिनसुलर मलेशिया में बिजली सुविधा के राजस्व और टैरिफ़ को विनियमित करने हेतु ऊर्जा आयोग के लिए सुविधा करना है। आईबीआर कार्य ढांचे के अंतर्गत विनियमित सेवाओं (बिजली) के प्रावधान हेतु बिजली टैरिफ़ प्रभारित किया जाता है। यह कार्य ढांचा बिजली सुविधा को अनुमति प्राप्त राजस्व की वसूली की अनुमति देता है जो विनियमित सेवाएं देने के लिए उसकी अनुमानित कारगर लागत (वित्तीय लागत सहित) को दर्शाती हो।
297. तथापि, प्रतिवादी निर्यातक ने अनुरोध किया है कि तेंगा नेशनल बीएचडी (टीएनबी) मलेशिया में बिजली का एक मात्रा आपूर्तिकर्ता है। उत्पादन में मुख्य सुविधा में बिजली/विद्युत है। पेनिनसुलर मलेशिया में एक मात्र बिजली आपूर्तिकर्ता स्टॉक मार्केट में एक सूचीबद्ध कंपनी है अर्थात् तेंगा नेशनल बीएचडी (टीएनबी) है। इसका कोई विकल्प नहीं है और औद्योगिक उपभोक्ताओं से उनके द्वारा प्रभारित दरें कारखाना परिसर या खान पर विचार किए बिना समान हैं। स्टील मिल जैसे बिजली के बड़े ग्राहकों के लिए हुए विशेष करारों में शामिल होकर विशेष टैरिफ़ों हेतु टीएनबी से बात करने की स्थिति में हैं। काफी कम बिजली खपत वाली कंपनियां टीएनबी के साथ विशेष करार नहीं करती हैं। अतः प्रतिवादी निर्यातकों को बिजली आपूर्तिकर्ता से कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है।
- प्राधिकारी द्वारा जांच**
298. मलेशिया में विद्युत की आपूर्ति मुख्यतः प्राकृतिक गैस और कोयले के माध्यम से होती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैस की आपूर्ति गैस आपूर्ति अधिनियम 1993 द्वारा शासित होती है। यह कार्यक्रम विद्युत क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की विनियमित और अधिक अनुकूल दरों की अनुमति देता है। यह नोट किया गया है कि जी ओ एम ने गैस के आपूर्तिकर्ता कंपनियों अर्थात् पेट्रोनास और गैस मलेशिया बर्हड (जीएमबी) की कीमतों को विनियमित करना स्वीकार किया है जो बाद में कम दरों पर अंतिम प्रयोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करते हैं। इस अंतर की वसूली उक्त कंपनी द्वारा जी ओ एम से की जाती है। इस प्रकार प्राधिकारी का विचार है कि जी ओ एम द्वारा प्रत्येक वित्तीय अंशदान होता है। इसके अलावा, जी ओ एम का उत्तर स्वयं बताता है कि :
- “सरकार ने प्रोत्साहन आधारित विनियमन (आईबीआर) कार्य ढांचे को भी विहित किया है जो जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2019 तक तीन वर्षों के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु मूल टैरिफ़ निर्धारित करता है। यह आईबीआर कार्य ढांचा प्रत्येक 6 महीने में गैस लागत पास श्रू (जीसीपीटी) तंत्र के जरिए गैस की लागत में परिवर्तन को स्वीकृत करने की अनुमति देता है। जीसीपीटी गैस लागत अंतर के जरिए पास करने का एक तंत्र है जो मूल टैरिफ़ में पूर्वानुमानित गैस लागत और वार्षिक गैस लागत के बीच अंतर के कारण होता है। जीसीपीटी को जनवरी और जुलाई में प्रत्येक 6 महीने में कार्यान्वित किया जाता है। यह दर रिबेट या सरचार्ज के रूप में होगी”।

299. जी ओ एम की इस दलील के संबंध में कि प्रतिवादी निर्यातक जांच अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस के उपभोक्ता नहीं हैं और उन्हें कार्यक्रम का लाभ उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं। जी ओ एम ने ही गैस कीमत निर्धारण तंत्र में सब्सिडी तत्व की मौजूदगी से इंकार किया है जिसे औद्योगिक उत्पादकों से आपूर्ति किया जाता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई सब्सिडी उसे प्रतिसंतुलनयुक्त बनाने के लिए सीधे संबंधित उद्यम को उपलब्ध करायी जाए। इस संदर्भ में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 1(क) के अंतर्गत सब्सिडी की परिभाषा का उल्लेख करना उचित होगा जिसका पाठ निम्नानुसार है।

9(1) जहाँ कोई देश या क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें विनिर्माण या उत्पादन या वहाँ से निर्यात के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सब्सिडी देता या प्रदान करता है जिसमें ऐसी वस्तु के परिवहन पर सब्सिडी शामिल है, तो भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात पर चाहें उसे विनिर्माण उत्पादन या अन्यथा के देश से सीधे आयात किया गया हो और चाहें उसे विनिर्माण या उत्पादन के देश से निर्यात के समय उसी दशा में आयात किया गया हो या विनिर्माण, उत्पादन या अन्यथा द्वारा उसकी स्थिति बदली गई हो तो केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाएगी जो ऐसी सब्सिडी की राशि से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनार्थ सब्सिडी को मौजूद माना जाएगा यदि –

- (क) सरकार या किसी सरकारी निकाय द्वारा (निर्यातक अथवा उत्पादक देश या क्षेत्र में) वित्तीय अंशदान दिया जाता है अर्थात जहाँ -
- i. सरकार की प्रक्रिया में निधियों का सीधा हस्तांतरण (अनुदान, क्रृष्ण और इक्किटी निवेश सहित) या निधि अथवा देयताओं का सीधा संभावित अंतरण या ये दोनों शामिल हों।
- ii. सरकारी राजस्व जो गंवाया या संग्रहीत नहीं किया गया और अन्यथा बकाया होता (राजकोषीय प्रोत्साहन सहित);
- iii. कोई सरकार सामान्य अवसंरचना से इतर वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है या वस्तुएं खरीदती हैं।
- iv. कोई सरकार किसी वित्त पोषण तंत्र हेतु भुगतान करती है या किसी निजी निकाय को उक्त खंड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट कार्यों के एक या उससे अधिक प्रकारों को करने का कार्य सौंपती है या उसका निदेश देती है जो सामान्यतः सरकार में निहित हैं और व्यवहार में वस्तुतः सरकार द्वारा आमतौर पर अपनाई गई प्रक्रिया से अलग हैं; या

300. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यदि कोई सरकार किसी निजी निकाय को बिंदु (i), (ii) और (iii) में वर्णित कार्यों में से कोई एक या उससे अधिक सरकार के कार्य सौंपती या उनका निर्देश देती है तो सामान्यतः सरकार द्वारा किए जाते हैं और इनका कार्यकरण वास्तविक रूप से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 1(क) के पैराग्राफ (i)-(iii) के अनुसार सामान्यतः सरकार द्वारा किए जोन वाले कार्यों से अलग हैं तो उसे सब्सिडी माना जाता है। ये प्रावधान एएससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क)(1)(iv) और (iii) के अनुसरण में हैं। अतः कोई कार्यक्रम जो निजी निकायों को भी उद्योग को पर्याप्त से कम कीमत पर गैस देने की अनुमति देता है वह उक्त प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी की परिभाषा में शामिल है।

301. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया में बिजली गैस से उत्पादित होती है। गैस की आपूर्तिकर्ता कंपनियों अर्थात पेट्रोनास और गैस मलेशिया बर्हड (जीएमबी) की कीमतें जी ओ एम द्वारा विनियमित होती हैं। इस प्रकार पेट्रोनास गैस मलेशिया बर्हड को बाजार दर से कम कीमत पर गैस उपलब्ध है।

302. इसके अलावा, मलेशिया में विद्युत का वितरण विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1990 के अधीन विनियमित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा आयोग द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही विद्युत की आपूर्ति करेंगे। इस प्रकार ऐसे निकायों को सरकारी कार्य सौंपे जाते हैं और यह सरकारी निकाय के रूप में कार्य करते हैं। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार बिजली के आपूर्तिकर्ता संगत मन्त्रालय द्वारा यथा अनुमोदित टैरिफ प्रभारित कर सकते हैं। तथापि, उक्त अधिनियम की धारा 29 के अनुसार विद्युत के ग्राहक बिजली के आपूर्तिकर्ताओं के साथ विशेष कारार में शामिल हो सकते हैं जिनके द्वारा करारों के अनुसार टैरिफ में विनिर्दिष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा, जी ओ एम द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मलेशिया में बिजली की कीमतें विनियमित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया

सरकार गैस तथा बिजली की कीमतों को विनियमित करती हैं जो औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए बाजार कीमतों से अलग है। इसके अलावा, यह स्कीम ऐसे उद्यमों को लाभ देती है जो गैस से उत्पादित बिजली खरीदते हैं।

303. जांच के अधीन कंपनियों ऐसे सब्सिडीकरण के लाभार्थी हैं। यह कार्यक्रम विशिष्ट है और पर्याप्त से कम कीमत पर बिजली के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं और यह भी नोट किया जाता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवादी निर्यातकों के विरुद्ध लगाया जाना चाहिए।
304. सब्सिडी मार्जिन राशि निर्धारित करने हेतु प्राधिकारी ने उचित बेंचमार्क की तलाश की है। प्राधिकारी ने "ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस" की वेबसाइट के अनुसार प्रदत्त कीमतों पर भरोसा किया है। प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा वस्तुतः प्रदत्त बिजली टैरिफ पर प्रश्नावली के अतिरिक्त उत्तर के अनुसार सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। उक्त पद्धति पर विचार करते हुए प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों हेतु निर्धारित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी.

305. रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक/निर्यातक है। रोबिन रिसोर्सेज ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और उन्हें प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की है।
306. प्राधिकारी ने रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की है और जांच करके उनसे सूचना मांगी है और उत्तर में प्रस्तुत सूचना का आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया है। रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में बताया था कि उसने संयंत्र और मशीनरी संबंधी भत्ता, बिक्री कर छूट, निर्यात संवर्धन हेतु दोहरी कटौती और निवेश कर भत्ते का लाभ लिया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि ऐसे सब्सिडी कार्यक्रम जिनके परिणामस्वरूप एलटीएआर पर भूमि, लकड़ी और विद्युत का प्रावधान रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. द्वारा प्राप्त किया गया है। परिणामस्वरूप रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. को विभिन्न सब्सिडियों के रूप में लाभ मिला है।
307. प्राधिकारी ने रोबिन रिसोर्सेज (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी. द्वारा प्रदत्त सूचना सत्यापित की है और ऐसे कार्यक्रमों के सब्सिडी मार्जिन निर्धारित की है जिनके लिए पी ओ आई के दौरान लाभ प्राप्त हुआ या मिला है। जहां निर्यातक द्वारा संगत सूचना नहीं दी गई थी, प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
308. नीचे तालिका में सब्सिडी कार्यक्रम का नाम और संगत सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 9	संयंत्र और मीशीनरी के लिए भत्ता	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 12	बिक्री कर से छूट	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 14	निर्यात संवर्धन के लिए दोहरी कटौती	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं. 19	निवेश कर भत्ता	***%	0-10
5	कार्यक्रम सं. 20	एलटीएआर पर खड़ी इमारती लकड़ी के लिए प्रावधान	***%	0-10
6	कार्यक्रम सं. 22क	पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि का प्रावधान	***%	0-10
7	कार्यक्रम सं. 22घ	पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान	***%	0-10
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी.

309. सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक/निर्यातक है। सेगमत ने प्रश्नावली का उत्तर दिया और उन्हें प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना प्रदान की है।
310. प्राधिकारी ने सेगमत द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच की है और जांच करके उनसे सूचना मांगी है और उत्तर में प्रस्तुत सूचना का आवश्यक सीमा तक सत्यापन भी किया है। सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में बताया था कि उसने वृद्धिशील पूँजी भत्ता, संयंत्र मशीनरी संबंधी भत्ता और बिक्री कर छूट का लाभ लिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि ऐसे सब्सिडी कार्यक्रम जिनके परिणामस्वरूप एलटीएआर पर भूमि, लकड़ी और विद्युत का प्रावधान सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. द्वारा प्राप्त किया गया है। परिणामस्वरूप सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. को विभिन्न सब्सिडियों के रूप में लाभ मिला था।
311. प्राधिकारी ने सेगमत पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी. द्वारा प्रदत्त सूचना सत्यापित की है और ऐसे कार्यक्रमों के सब्सिडी मार्जिन निर्धारित की है जिनके लिए पी ओ आई के दौरान लाभ प्राप्त हुआ या मिला है। जहां निर्यातक द्वारा संगत सूचना नहीं दी गई थी, प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
312. नीचे तालिका में सब्सिडी कार्यक्रम का नाम और संगत सब्सिडी मार्जिन दिया गया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 7	वृद्धिशील पूँजी भत्ता	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 9	संयंत्र मशीनरी संबंधी भत्ता	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 12	बिक्री कर से छूट	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं. 20	एलटीएआर पर खड़ी इमारती लकड़ी के लिए प्रावधान	***%	0-10
5	कार्यक्रम सं. 11क	पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि का प्रावधान	***%	0-10
6	कार्यक्रम सं. 11ख	पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान	***%	0-10
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

313. मलेशिया से सभी अन्य उत्पादकों के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहयोगी पक्षकार हेतु उन्हें प्राप्त हुई सब्सिडियों के लिए सब्सिडी मार्जिन के उच्चतम स्तर और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 7	वृद्धिशील पूँजी भत्ता	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 9	संयंत्र मशीनरी संबंधी भत्ता	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 12	बिक्री कर से छूट	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं. 14	नियात संवर्धन के लिए दोहरी कटौती	***%	0-10
5	कार्यक्रम सं. 19	निवेश कर भत्ता	***%	0-10
6	कार्यक्रम सं. 20	एलटीएआर पर खड़ी इमारती लकड़ी के लिए प्रावधान	***%	0-10
7	कार्यक्रम सं. 22क	पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि का प्रावधान	***%	0-10
8	कार्यक्रम सं. 22ख	पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली का प्रावधान	***%	0-10
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

श्रीलंका

च.7. याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम सं. 1: राष्ट्रीय भवन कर से छूट (अप्रत्यक्ष कर)

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

314. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम श्रीलंका सरकार द्वारा प्रशासित है। नेशनल बिल्डिंग टैक्स अधिनियम 2009 की धारा 3 और अनुसूची एक में मशीनरी के आयात पर लागू कर से तब छूट दी जाती है जब उनका आयात निर्यात हेतु वस्तुओं के विनिर्माण के प्रयोजनार्थ हुआ हो। छूट की राशि निर्यातों का लागू कारोबार या प्रयुक्त मशीनरी के आयातों के मूल्य के बराबर होती है। यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान मिलता है और इस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों से जुड़ा है। यूएसबीओसी द्वारा इस कार्यक्रम का विशेषण किया गया है और श्रीलंका से “कतिपय न्यू न्यूमेटिक ऑफ द रोड टायर (ऑफ रोड टायर)” संबंधी सब्सिडीरोधी जांच में प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया।

श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

315. नेशनल बिल्डिंग टैक्स (एनबीटी) वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत पर लागू एक अप्रत्यक्ष कर है इसे 2009 के नेशनल बिल्डिंग टैक्स अधिनियम संख्या 9 द्वारा लगाया गया था और तत्पश्चात कई बार संशोधित किया गया। एनबीटी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्ति, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय) या भागीदारी द्वारा देय है जो (i) श्रीलंका में किसी वस्तु (यदि छूट प्राप्त न हो) का आयात करते हैं, (ii) छूट प्राप्त से इतर किसी वस्तु के विनिर्माण का कारोबार करते हैं (iii) किसी वस्तु (पूर्ववर्ती शीर्ष के अंतर्गत लागू से इतर) का थोक या खुदरा व्यापार करते हैं और (iv) कोई सेवा प्रदान करने का व्यापार करते हैं।
316. अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-I के (i) और (ii) के अनुसार ऐसी वस्तु के विनिर्माता द्वारा निर्यातित कोई वस्तु और निर्यात किए जाने के लिए वस्तु के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री का आयात एनबीटी से छूट प्राप्त है। यह बात निर्यातित उत्पाद पर विचार किए बिना लागू है।
317. यह कार्यक्रम करार के फुटनोट 1 के कारण एएससीएम के अंतर्गत सब्सिडी नहीं माना जाता है। यह राशि उत्पाद पर विचार किए बिना सभी निर्यातकों पर लागू है। फुटनोट 1 में बताया गया है कि फुटनोट 58 के अंतर्गत यथापरिभाषित अप्रत्यक्ष करों से निर्यातों को छूट वित्तीय अंशदान नहीं है। यही सिद्धांत जी ए टी टी के अनुच्छेद XVI की टिप्पणी में भी प्रदत्त एएससीएम का अनुबंध I (जी) बताता है कि अप्रत्यक्ष कर में ऐसी छूट सब्सिडी नहीं है। यदि वह समान उत्पाद की घरेलू खपत के लिए उत्पादन और वितरण पर लागू कर से अधिक न हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह छूट इस स्तर से अधिक नहीं है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी नहीं है क्योंकि इससे किसी उद्योग या क्षेत्र विशेष को लाभ नहीं मिलता है। श्रीलंका में पी यू सी का उत्पादक एनबीटी के भुगतान का उत्तरदायी नहीं क्योंकि यह केवल वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत पर लागू है। इसके अतिरिक्त, नेशनल बिल्डिंग टैक्स को 1 दिसंबर, 2019 से समाप्त कर दिया गया।

प्राधिकारी द्वारा जांच

318. नेशनल बिल्डिंग टैक्स (एनबीटी) वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत पर लागू एक अप्रत्यक्ष कर है इसे 2009 के नेशनल बिल्डिंग टैक्स अधिनियम संख्या 9 द्वारा लगाया गया था। एनबीटी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्ति, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय) या भागीदारी द्वारा देय है जो (i) श्रीलंका में किसी वस्तु (यदि छूट प्राप्त न हो) का आयात करते हैं, (ii) छूट प्राप्त से इतर किसी वस्तु के विनिर्माण का कारोबार करते हैं (iii) किसी वस्तु (पूर्ववर्ती शीर्ष के अंतर्गत लागू से इतर) का थोक या खुदरा व्यापार करते हैं और (iv) कोई सेवा प्रदान करने का व्यापार करते हैं।
319. अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-I के (i) और (ii) के अनुसार ऐसी वस्तु के विनिर्माता द्वारा निर्यातित कोई वस्तु और निर्यात किए जाने के लिए वस्तु के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री का आयात एनबीटी से छूट प्राप्त है। यह दर्शाने वाले किसी साध्य के अभाव में कि यह कार्यक्रम अनुमति प्राप्त कर छूट प्रदान करता है। यह निर्धारित किया गया है कि सब्सिडी कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान

करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात से जुड़ी है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

320. तथापि, चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु से किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी मार्जिन की राशि ज्ञात नहीं की है।

(ii) कार्यक्रम संख्या 2: पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

321. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम उद्योग और सेवा निदेशालय, श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। स्कीम टीआईईपी - iv ऐसी पूंजीगत या मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर लागू सीमा शुल्क से छूट देता है जो निर्यात हेतु वस्तुओं के विनिर्माण के प्रयोजनार्थ आयात की जाती हैं। यह कार्यक्रम ऐसे गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि निर्यातों से जुड़ा है।
322. यद्यपि श्रीलंका सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने का दावा किया गया है। तथापि, सरकार तथा श्रीलंकाई निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है और यह दावा किसी समर्थक साक्ष्य के बिना किया गया है।

श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

323. निर्यातों हेतु उत्पादों और सेवाओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट निर्यात प्रसंस्करण हेतु अस्थायी आयात (टीआईईपी-IV) स्कीम के अंतर्गत उद्योग और सेवा निदेशालय द्वारा प्रदान की जाती है। यह उत्पादन प्रक्रिया, मध्यवर्ती वस्तुओं, अन्य अनिवार्य उपकरण, परिवहन उपकरण और संभलाई उपकरण में शामिल पूंजीगत वस्तुओं पर लागू है। यह कार्यक्रम निर्यातकों को ऐसे मामले में सीधा शुल्क 100 प्रतिशत छूट प्रदान करता है जो अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत या उससे अधिक निर्यात करते हैं और ऐसे अप्रत्यक्ष निर्यातक जो अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष निर्यातों को आपूर्ति करते हैं।
324. श्रीलंका सरकार ने बताया कि भारत में पी यू सी का एक मात्रा निर्यातक अर्थात् मरबोक जनवरी, 2019 तक बी ओ आई अधिनियम के अधीन प्रचालनरत था और तत्पश्चात् टीआईईपी-IV स्कीम के अंतर्गत कार्यरत था। बी ओ आई व्यवस्था के अंतर्गत मरबोक कच्ची सामग्रियों के आयात की शुल्क मुक्त पहुंच का हकदार था और यह छूट बी ओ आई दर्जा धारक सभी कंपनियों को उपलब्ध थी। कंपनी को जनवरी, 2019 से इस स्कीम का लाभ मिला और उससे पहले नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

325. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम उद्योग और सेवा निदेशालय, श्रीलंका द्वारा टीआईईपी-IV स्कीम के अनुसार प्रशासित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया, मध्यवर्ती वस्तुएं अन्य अनिवार्य उपकरण परिवहन उपकरण और संभलाई उपकरण में शामिल पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर लागू सीमा शुल्क से तब छूट मिलती है जब उनका आयात निर्यात के लिए विनिर्माण के प्रयोजनार्थ किया जाए। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु से किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी मार्जिन की राशि ज्ञात नहीं की है।

(iii) कार्यक्रम संख्या 3: विशिष्ट उपकरणों के लिए आयकर रियायत

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

326. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम श्रीलंका सरकार द्वारा प्रशासित है। अंतर्राष्ट्रीय राजस्व अधिनियम 2006 की अनुसूची 5 के साथ पाठित धारा 51 अधिनियम के अधीन अभिज्ञात गैर पारंपरिक उत्पादों के निर्यात में शामिल कंपनियों को आयकर की रियायती दर प्रदान करती है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो

अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों से जुड़ा है।

327. यद्यपि श्रीलंका सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने का दावा किया गया है। तथापि, सरकार तथा श्रीलंकाई निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है।

श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

328. 2006 के अंतर्राष्ट्रीय राजस्व अधिनियम संख्या 10 की धारा 51 और 52 के अनुसार कोई कंपनी जो कोई विशिष्ट उपक्रम करती है और उस कंपनी की कर योग्य आय किसी आकलन वर्ष के लिए निर्यात लाभों या आय को शामिल करती है तो उस कंपनी की कर योग्य आय का ऐसा भाग उस आकलन वर्ष के लिए जिसमें ऐसे पात्र निर्यात लाभ और आय शामिल हैं, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उचित दर पर आयकर के लिए प्रभार योग्य होगा।
329. श्रीलंका सरकार ने बताया कि भारत में पी यू सी का एकमात्र निर्यातक अर्थात मरबोक 2014 से घाटा उठा रहा है और इसलिए आयकर का भुगतान देय नहीं है। इससे यह कार्यक्रम अप्रयोज्य हो जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

330. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 51 अधिनियम की अनुसूची 5 के अधीन अभिज्ञात गैर पारंपरिक उत्पादों के निर्यात में शामिल कंपनियों को आयकर की रियायती दर प्रदान करती है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। इस कार्यक्रम को विशिष्ट भी माना गया है क्योंकि यह निर्यातों से जुड़ा है और विशेष रूप से अधिनियम के अनुसार गैर पारंपरिक उत्पादों के विनिर्माताओं को प्रदान किया जाता है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। तथापि, चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु से किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी मार्जिन की राशि ज्ञात करने में असमर्थ हैं।

(IV) कार्यक्रम संख्या 4: उच्च निवेश वाले उपक्रमों हेतु आयकर से छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

331. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम श्रीलंका सरकार द्वारा प्रशासित है अंतर्राष्ट्रीय राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 17ए अधिनियम के अधीन अभिज्ञात गैर पारंपरिक उत्पादों के उत्पादन और निर्यात के लिए किए गए निवेश की राशि के अनुसार किसी अवधि के लिए आयकर भुगतान से छूट प्रदान करती है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इस प्रकार लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों से जुड़ा है।
332. यद्यपि श्रीलंका सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने का दावा किया गया है। तथापि, सरकार तथा श्रीलंकाई निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है।

श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

333. अंतर्राष्ट्रीय राजस्व अधिनियम की धारा 17 उपक्रमों द्वारा किए गए निवेश के अनुसार आयकर अवकाश प्रदान करती है। इस धारा को बाद में अनेक बार संशोधित किया गया है। तदनुसार, निर्यात हेतु गैर पारंपरिक वस्तुओं के विनिर्माण उत्पादन या प्रसंस्करण को ऐसे कार्यकलापों में शामिल किया गया है जिनमें निवेश कानून के अनुसार कर अवकाश को बढ़ा सकता है।
334. श्रीलंका सरकार ने बताया कि भारत में पी यू सी का एकमात्र निर्यातक अर्थात मरबोक 2014 से घाटा उठा रहा है और इसलिए आयकर का भुगतान देय नहीं है। इससे यह कार्यक्रम अप्रयोज्य हो जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

335. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 17ए अधिनियम के अधीन अभिज्ञात गैर पारंपरिक उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में शामिल कंपनियों को आयकर से छूट प्रदान करती हैं। प्रदान की

जाने वाली छूट की अवधि किए गए निवेश की राशि पर निर्भर करती है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। इस कार्यक्रम को विशिष्ट भी माना गया है क्योंकि यह निर्यातों से जुड़ा है और विशेष रूप से अधिनियम के अनुसार गैर पारंपरिक उत्पादों के विनिर्माताओं को प्रदान किया जाता है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। तथापि, चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु से किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी मार्जिन की राशि ज्ञात करने में असमर्थ हैं।

(v) कार्यक्रम संख्या 5: राष्ट्रीय उर्वरक सब्सिडी स्कीम

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

336. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उक्त कार्यक्रम श्रीलंका सरकार के बागान उद्योग मंत्रालय द्वारा शासित है। यह स्कीम रबड़ बागानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर फर्टिलाइजर प्रदान करती है। यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तुओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह रबड़ बागान क्षेत्र तक सीमित है।
337. यद्यपि श्रीलंका सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का लाभ नहीं लेने का दावा किया गया है। तथापि, सरकार तथा श्रीलंकाई निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है।

श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

338. श्रीलंका ने कृषि का संवर्धन करने के लिए कृषि सब्सिडियां शुरू की और यह सभी फसल क्षेत्रों और उक्त क्षेत्रों को प्रदान की है। यह सब्सिडी सामान्यतः सभी फसल क्षेत्रों और उक्त क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और दी जाती है। अतः यह कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है। यह कृषि क्षेत्र में शामिल सभी के लिए उपलब्ध है। इससे विशेष रूप से रबड़ उत्पादकों को लाभ नहीं मिलता है और निर्यातकों को नहीं दी जाती है। इसलिए सब्सिडी न तो निर्यात सब्सिडी है न ही एएससीएम के अनुसार कार्रवाई योग्य है। यह लाभ काफी सुदूर भी है और फाइबर बोर्ड उत्पादकों तक नहीं पहुंचता है। भारत में पी यू सी का एक मात्र निर्यातक मरबोक कार्यक्रम तक पहुंच के लिए प्रशासन प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

339. प्राधिकारी नोट करते हैं कि श्रीलंका सरकार का बागान उद्योग मंत्रालय उर्वरक सब्सिडी के रूप में रबड़ बागानों को काफी मात्रा में सब्सिडी प्रदान करता है। पी यू सी के उत्पादन एक प्राथमिक कच्ची सामग्री होने के कारण यह कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी प्राप्त दरों पर रबड़वुड की खरीद की अनुमति देता है।
340. यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तु के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशेष रूप से किसी क्षेत्र हेतु उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं। तथापि, चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी मार्जिन की राशि ज्ञात करने में असमर्थ हैं।

(vi) कार्यक्रम संख्या 6: रबड़ बागान के लिए सब्सिडियां

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

341. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम श्रीलंका सरकार के बागान उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रबड़ विकास रोड द्वारा प्रशासित है। यह स्कीम आकार के आधार पर किसी बागान के विभिन्न स्तरों पर किस्तों में अनुदान प्रदान करती है और गारंटीड समर्थन कीमत भी सुनिश्चित करती है। यह कार्यक्रम निधियों के सीधे हस्तांतरण के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह रबड़ बागान क्षेत्र तक सीमित है।
342. यद्यपि श्रीलंका सरकार द्वारा इस कार्यक्रम का गैर मौजूदगी का दावा किया गया है। तथापि, सरकार तथा श्रीलंकाई निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है।

श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

343. रबड़ विकास बोर्ड द्वारा दो स्कीमें प्रशासित की जाती हैं और नए बागान तथा पुनरोपण के लिए विशेष रूप से रबड़ उत्पादकों को दी जाती हैं। श्रीलंका में फाइबर बोर्ड उत्पादक रबड़ के लट्टों का प्रयोग करते हैं जो रबड़ उद्योग का अपशिष्ट है। उन्हें पेड़ की आयु समाप्त होने पर बहुत कम कीमत पर खरीदा जाता है, परंतु यह खरीद स्कीम से प्रभावित नहीं होती है।
344. सब्सिडी रबड़ के तेल के आरंभिक स्तर पर दी जाती है जिसका आर्थिक जीवन 25-30 वर्ष का होता है। रबड़ के पेड़ उक्त आर्थिक जीवन के अंत में परिकलित करने पर प्राप्त सब्सिडी का मूल्य इस समय के दौरान मुद्रा के मूल्यहास के कारण नगण्य हो जाता है। यह लाभ काफी सुदूर है और फाइबर बोर्ड उत्पादकों तक नहीं पहुंचता है अतः सब्सिडी मौजूद नहीं है।
345. जहां सब्सिडी किसी अलग (अपस्ट्रीम) कंपनी को दी जाती है वहां जांचकर्ता प्राधिकारी के पास साझ्य होना चाहिए और उसके आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि पहली कंपनी को प्राप्त कोई सब्सिडी निर्यातक कंपनी तक पहुंची है अन्यथा निर्यातक कंपनी के लिए कोई सब्सिडी मौजूद नहीं हो सकती है।

(vii) कार्यक्रम संख्या 7: लॉग के निर्यातों पर सरकारी प्रतिबंध

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

346. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम श्रीलंका सरकार द्वारा प्रशासित है। श्रीलंका सरकार ने 1990 से लट्टों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। निर्यात बाधाओं के लगते से लट्टों का घरेलू बाजार विकृत हो गया है और वह पर्याप्त से कम मूल्य पर डाउनस्ट्रीम उद्योगों को उपलब्ध हो जाते हैं। अतः यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तुओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्राथमिक रूप से ऐसे उद्यमों के लिए लाभकारी है जो कच्ची सामग्री के रूप में टिंबर का प्रयोग करते हैं।

क. श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

347. श्रीलंका सरकार ने टिंबर लट्टों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। लट्टों का निर्यात करने के लिए एकमात्र जरूरत लाइसेंस प्राप्त करने की है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

348. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सं. 6 और 7 श्रीलंका सरकार द्वारा रबड़ बागान और लकड़ी प्रतिबंध को विनियमित, की निगरानी और नियंत्रण के लिए किए गए अनेक उपायों से संबंधित है। चूंकि ऐसे कार्यक्रमों का प्रभाव पर्याप्त से कम मूल्य पर लकड़ी प्राप्त होना है इसलिए प्राधिकारी ने इन कार्यक्रमों को जोड़ दिया है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संचयी रूप से इनकी जांच की है।
349. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रबड़ बागान सब्सिडी रबड़ विकास बोर्ड द्वारा प्रशासित की जाती है जैसा श्रीलंका सरकार ने माना है। रबड़ विकास बोर्ड वर्तमान में दो स्कीमें कार्यान्वित करता है जो रबड़ उपजकर्ताओं के लाभार्थ हैं। पहली पुनरोपण के लिए और दूसरी नए रोपण के लिए है। फाइबर बोर्ड विनिर्माण में रबड़ लॉग प्रविष्ट होते हैं जो रबड़ के आर्थिक जीवन (25-30 वर्ष) की समाप्ति पर बहुत कम कीमत पर रबड़ उद्योग के अपशिष्ट होते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 1953 का रबड़ पुनरोपण सब्सिडी अधिनियम संख्या 16 (समय समय पर यथासंशोधित) रबड़ संपदाओं और रबड़ की छोटी जोतों के पुनरोपण और कच्चे रबड़ के प्रसंस्करण में प्रयुक्त मशीनरी और उपकरण की खरीद सहित कच्चे रबड़ के प्रसंस्करण को सब्सिडी प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक निधि की स्थापना करने वाला अधिनियम है। ऐसे तघु धारक यह रबड़ बागान कंपनियां जो अपनी जोतों को रबड़ विकास विभाग (आरडीडी) में पंजीकृत करते हैं, सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। तदनुसार, जोतधारकों को विभाग के साथ पंजीकृत होने से पहले भूमिका स्वामित्व सिद्ध करना अपेक्षित है। समस्त रबड़ बागान श्रीलंका सरकार द्वारा नियंत्रित हैं।
350. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि श्रीलंका सरकार ने वनों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय वन नीति बनायी है जो समय समय पर संशोधित की गई है। बाद में वन कटाई की बढ़ती चिंताओं के कारण 1986 में श्रीलंका का वन क्षेत्र

मास्टर प्लान और वन अध्यादेश विनियम या विशेष विधिक प्रावधान लॉग पर प्रतिबंध के लिए लागू करने हेतु बनाया गया था। वन विभाग वन क्षेत्रों के प्रमुख हिस्सों के प्रशासन को संभालने वाला प्रमुख संस्थान है। श्रीलंकाई सीमा शुल्क वेबसाइट के अनुसार टिंबर अर्थात् लकड़ी (लॉग तथा सौनै टिंबर सहित) जो एचएच अध्याय 44 के अधीन वर्गीकृत हैं तथा जिसमें नारियल के खोल का चारकोल लकड़ी और रबड़वुड के घरेलू बर्तन शामिल नहीं हैं, के लिए निर्यात नियंत्रण लाइसेंस अपेक्षित है।

351. प्राधिकारी ने श्रीलंका से संबद्ध वस्तु के अग्रणी निर्यातक मै० मरबोक एमडीएफ लंका (प्रा०) लि० की वेबसाइट सूचना को नोट किया है जिसमें वर्णित है ”सभी लकड़ी प्रसंस्करण उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन संसाधनों पर निर्भर हैं। बुड़ फाइबर के रूप में वन संसाधन एमडीएफ के विनिर्माण हेतु मूल कच्ची सामग्री प्रदान करते हैं। मरबोक की अपशिष्ट लकड़ी सुविधाएं, 100 मिल अपशिष्ट और अवशिष्ट बागान लॉग जिन्हें काटा और चक्रीय रूप से पुनरोपित किया जाता है”। प्राधिकारी ने यह भी पाया कि मरबोक अपनी अत्यधिक सफल छोटी जोत पौधा रोपण कार्यक्रम के जरिए बागान कार्यक्रम में भी शामिल रहा है। प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित कड़े पर्यावरण विनियमों को पूरा करने और उनका पालन करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
352. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि ऐसे निर्यात नियंत्रण (और अन्य निर्यात प्रतिबंध) श्रीलंका के जंगलों के अधिक दोहन में कटौती कर सकते हैं, परंतु इससे लॉग की घरेलू कीमतें कम भी हो सकती हैं, उसके द्वारा ऐसे उत्पादों के डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण में सहयोग मिलता है जिससे सब्सिडीकरण होता है।
353. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि श्रीलंका सरकार निर्यात नियंत्रण लागू करके डाउनस्ट्रीम उद्योगों में कंपनियों को कम कीमत की निविष्टियां (लॉग/बुड) देती है। निर्यात नियंत्रण जिससे लॉग आपूर्तिकर्ताओं को कम कीमत पर घरेलू रूप से लॉग बेचने पड़े, से श्रीलंकाई डाउनस्ट्रीम लकड़ी प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ हुआ है।
354. यह कार्यक्रम पर्याप्त से कम मूल्य पर वस्तु उपलब्ध कराकर वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और उसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि इससे उन डाउनस्ट्रीम उद्योगों को लाभ हुआ है जो अपनी प्राथमिक कच्ची सामग्री के रूप में लॉग / लकड़ी का प्रयोग करते हैं। अतः यह कार्यक्रम वस्तुतः सीमित संख्या में उद्योगों को ही उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
355. तथापि, चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी मार्जिन की राशि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ज्ञात की है।

कार्यक्रम संख्या 8: पर्याप्त मूल्य से कम पर बिजली

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

356. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि श्रीलंका में पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली दी जाती है।

श्रीलंका सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

357. श्रीलंका सरकार ने पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली देने के आरोप संबंधी कोई अनुरोध नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

358. जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी को आवेदकों द्वारा उनके अनुरोधों में लगाए गए आरोप के अनुसार एलटीएआर पर बिजली दिए जाने का पता चला है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त प्रश्नावली के रूप में अपेक्षित सूचना मांगी है।
359. विद्युत उपक्रम विभाग विद्युत के उत्पादन और श्रीलंका में ट्रांस्मिशन के लिए सरकार द्वारा 1926 में स्थापित किया गया था। बाद में संसद के एक अधिनियम द्वारा 1969 में सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सी ई बी) स्थापित किया गया जो देश में बिजली के उत्पादन, ट्रांस्मिशन और वितरण के लिए उत्तरदायी है। बाद में 1983 में सरकार ने कोलंबो और देश पश्चिमी और दक्षिणी भाग से चुनिंदा क्षेत्रों में बाहरी उपनगरों में बिजली का वितरण करने हेतु लंका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लि० (एलईसीओ) स्थापित किया था। 2009 के विद्युत अधिनियम से पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन ऑफ श्रीलंका (पीयूसीएसएल) द्वारा इस क्षेत्र के कारगर विनियम मार्ग प्रशस्त हुआ।

360. वर्तमान में सीईबी और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक विद्युत के उत्पादन में शामिल हैं। यद्यपि सीईबी देश में प्रमुख प्रणाली प्रचालक है। तथापि, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित विद्युत ही खरीद करारों के अंतर्गत सीईबी द्वारा खरीदी जाती है। जल विद्युल संयंत्र और कोयला विद्युत संयंत्र श्रीलंका में विद्युत उत्पादन में प्रमुख योगदान देते हैं। लघु जल, पवन जैसे अन्य अपारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा (एनसीआरई) विद्युत संयंत्र ही विद्युत उत्पादन में योगदान देते हैं। राष्ट्रीय विद्युत आपूर्ति में तापीय विद्युत का अंशदान जल विद्युत से अधिक है।
361. विद्युत कानून 2009, धारा 5(2) (घ) के अनुसार – कीमत निर्धारण नीति श्रीलंका मंत्री द्वारा निर्धारित होती है। सीईबी देश का प्रमुख प्रणाली प्रचालक है। स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित बिजली भी खरीद करारों के अंतर्गत सीईबी द्वारा खरीदी जाती है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रीलंका में औद्योगिक टैरिफ दर सब्सिडी प्राप्त है और बाजार कीमत से कम है।
362. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय ने अपना प्राधिकार संबद्ध संस्थानों अर्थात् सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) और लंका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिंग (एलईसीओ) ने निहित किया है। एलईसीओ श्रीलंका सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली सुविधा है जो इस द्वीप में सामान्य ऊर्जा सुविधाओं की देखरेख करती है। विद्युत, ऊर्जा और व्यापार विकास मंत्रालय एलईसीओ के ऊपर उत्तरदायी मंत्रालय है। सरकार ने अपने कार्य करने के लिए सरकारी नियंत्रण के औपचारिक संकेत के आधार पर शक्तियां निहित की हैं और यह देखा जाता है कि इसका प्रयोग सार्थक ढंग से होता है। इसलिए ये सार्वजनिक निकाय हैं। अतः प्राधिकारी पाते हैं कि श्रीलंका में विद्युत क्षेत्र विकृत है और बाजार सिद्धांतों पर आधारित नहीं है जिससे पीयूसी के उत्पादकों को पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली मिल जाती है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
363. तथापि, चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी मार्जिन की राशि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ज्ञात की है।

श्रीलंका से सब्सिडी कार्यक्रमों का सारांश

364. चूंकि श्रीलंका से किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी ने श्रीलंका से संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क निर्धारित किया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेज %
1	कार्यक्रम सं. 2	आयात शुल्क से छूट	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 6 और 7	एलटीएआर पर खड़ी इमारती लकड़ी के लिए प्रावधान	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 13	एलटीएआर पर बिजली के लिए प्रावधान	***%	0-10
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

शाईलेंड

1. कार्यक्रम संख्या 1: मशीनरी पर आयात शुल्कों से छूट/कटौती

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

365. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (“बोओआई”) द्वारा प्रशासित है। निवेश संवर्धन अधिनियम 2002 (आईपीए) की धारा 28 और 29 और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 2018 की गाइड आयातित मशीनरी पर लागू आयात शुल्क पर छूट/कटौती प्रदान करती है। यह लाभ ऐसा है कि यह पीयूसी तक पहुंचेगा धनराशि क्षयकारी है और इसलिए कंपनी अपनी किसी भी व्यापार खंड पर इस लाभ के प्रयोग का निर्णय ले सकती है। यह कार्यक्रम गंवाए गए ऐसे राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उद्यमियों की उस सीमित संख्या को उपलब्ध जिनके पास समान विधान के अधीन एक भी पात्रता मापदंडों को पूरा करने पर जारी किया गया संवर्धन प्रमाणपत्र है। निवेश परियोजना को भी निवेश संवर्धन के लिए पात्र कार्यकलापों की सूची में आना चाहिए।

366. इस कार्यक्रम की प्राधिकारी द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कांटीन्यूअस कास्ट कापर वायर राइस" के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व में जांच की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था। वर्तमान मामले में भी इसे मानने का अनुरोध है।
367. अनेक प्रतिवादी निर्यातकों जिनमें मै० वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लि०, मै० वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि०, मै० मेट्रो एम डी एफ कं. लि०, मै० एडवांस फाइबर कं. लि०, मै० वाइजवुड कं. लि०, मै० पैनल प्लस एम डी एफ कं. लि०, मै० एस. किजचाई इंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लि० और एग्रो फाइबर कं. लि० को बीओआई से निवेश संवर्धन प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं और इसलिए वे कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाने के कारण नहीं बताए हैं। इसके अलावा, मै० पैनल प्लस कं. लि०, मै० एस. किजचाई इंटरप्राइज, मै० एडवांस फाइबर कं. लि० और मै० वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लि० सभी ने एयूएल अवधि में क्षमताएं बढ़ायी हैं या नए संयंत्र जोड़े हैं। अतः इन्होंने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ लिया होगा।

थाईलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

368. थाईलैंड सरकार द्वारा अधिनियमित निवेश संवर्धन अधिनियम 1977 (आईपीए) ने एक निवेश संवर्धन कार्यक्रम सृजित किया और बीओआई को निवेश संवर्धन प्रोत्साहन प्रदान करने का अधिकार दिया जिनमें धारा 28 के अंतर्गत बीओआई संवर्धित परियोजनाओं में प्रयुक्त मशीनरी पर आयात शुल्क के भुगतान से छूट शामिल है। यह खंड अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के अधीन मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करता है। जनवरी, 2015 में बीओआई द्वारा शुरू की गई नई निवेश संवर्धन स्कीम के अंतर्गत निवेश जोन के बजाय निवेश कार्यकलाप के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया गया है। 2015 में किए गए परिवर्तन से 2015 के पहले जोनिंग प्रणाली के अंतर्गत जांचाधीन कंपनियों को प्राप्त होने वाले लाभ सहित किसी कंपनी का प्रोत्साहन पैकेज प्रभावित नहीं हुआ है। बीओआई प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता इस वक्त नहीं है क्योंकि यह कतिपय उद्योगों या कतिपय उद्यमों तक सीमित नहीं है। यह लाभ निर्यात वस्तुओं के उत्पादन हेतु मशीनरी के आयात या आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर नहीं मिलता है। इस कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार की जानी चाहिए। कांटीन्यूअस कापर अंतिम जांच परिणाम में पूर्ववर्ती निष्कर्षों को एक समान रूप से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।
369. प्राधिकारी ने एएससीएम करार के निवंधनों की जांच नहीं की है। कार्यक्रम के दायरे से किसी उद्योग या बाजार खंड को बाहर नहीं किया गया है या बीओआई के अनुमोदन के अनुरोध हेतु पात्र नहीं है। यह कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है।
370. मै० मेट्रो एम डी एफ कं. लि० और मै० एडवांस फाइबर कं. लि० ने बताया कि छूट केवल थाईलैंड में नहीं संयोजित की गई मशीनरी के आयात पर दी जाती है। इसके अलावा, पैनल प्लस एम डी एफ ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ समग्र रूप से कंपनी को दिया जाता है और न कि पीयूसी को विशिष्ट रूप से।
371. यह अनुरोध किया गया है कि कनाडा-सिविलियन, विमान के निर्यात को प्रभावित करने वाले उपाय में डब्ल्यूटीओ पैनल के रिपोर्ट के अनुसार सीवीडी लाभ में जांच प्राप्तकर्ता के परिप्रेक्ष्य में जांचा जाना चाहिए। पीसी-बड़े सिविल वायुयान में व्यापार को प्रभावित करने वाले उपाय में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है। यह एएससीएम और और सीवीडी नियमों के अनुसार प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है। वानाचाई ग्रुप का लाभ शून्य है क्योंकि मशीनों ने पीओआई से पहले अपना मूल्यहास चक्र पूरा कर लिया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

372. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम 2002 (अधिनियम) संवर्धित कंपनियों/परियोजनाओं/कार्यकलापों को कतिपय अधिकार और लाभ प्रदान करता है, (निवेश संवर्धन पैकेज स्कीम)। अधिनियम की धारा 16 में विहित है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (बी ओ आई) अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लाभ के लिए पात्र निवेश कार्यकलापों के प्रकार और आकार दर्शाती हुई एक घोषणा करेगा।
373. निवेश संवर्धन अधिनियम 2002 की धारा 28 अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनरी पर आयात शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 30 कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क की कटौती (90 प्रतिशत से अधिक नहीं) का प्रावधान करती है और मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट/कटौती का प्रावधान नहीं

करती है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। सब्सिडी विशिष्ट है क्योंकि यह संवर्धित कार्यकलाप करने वाले संवर्धित उद्यमों तक सीमित है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

374. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेट्रो एम डी एफ कं. लि०, वाइजवुड और एस. किजचाई द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर दर्शनी हैं कि कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें लाभ मिला था। प्राधिकारी मानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोक्त उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। किसी भी अन्य प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हुआ नहीं पाया गया।
375. प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड प्रदत्त सूचना के आधार पर सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है। इस प्रकार परिकलित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में मे दिया गया है।

कार्यक्रम संख्या 2: निर्यात हेतु उत्पादन में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क से छूट

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

376. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ("बी ओ आई") द्वारा प्रशासित है। निवेश संवर्धन अधिनियम 2002 (आईपीए) की धारा 36 और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की गाइड निम्न पर लागू आयात शुल्क से छूट देती है (i) निर्यात के लिए विशिष्ट रूप से उत्पादन, मिश्रण या उत्पादकों के संयोजन या वस्तुओं में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची और अनिवार्य सामग्रियां तथा (ii) पुनः निर्यात के लिए आयातित मद्दें। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह केवल उन उद्यमों तक सीमित है जिनके पास समान विधान में प्रदत्त सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करने पर जारी संवर्धन प्रमाणपत्र है। इसके अलावा, ये निर्यात से भी जुड़ा है। अतः विशिष्ट माना गया है।
377. थाईलैंड से कतिपय हॉट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात संबंधी सीबीडी जांच में अंतिम सकारात्मक निर्धारण में यूएसडीओसी ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट द्वारा प्रशासित निवेश संवर्धन अधिनियम 1977 से संवर्धित सभी कार्यक्रमों को प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था। इस कार्यक्रम की प्राधिकारी द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कांटीन्यूअस कास्ट कापर वायर राइस" के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व में जांच की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था। वर्तमान मामले में भी इसे मानने का अनुरोध है। प्राधिकारी ने उक्त जांच में पाया था कि थाईलैंड सरकार यह दर्शने का कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य नहीं दे पायी थी कि यह सुनिश्चित करने का तंत्र कैसे कार्य करता है कि कार्यक्रम के तहत कोई अतिरिक्त लाभ न मिले। यूएसडीओसी के पूर्ववर्ती के निष्कर्ष डीजीटीआर पर बाध्यकारी नहीं हैं। प्राधिकारी अपने तथ्यात्मक निष्कर्षों के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं।
378. मै० वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लि०, मै० वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि०, मै० मेट्रो एम डी एफ कं. लि०, मै० एडवांस फाइबर कं. लि०, मै० वाइजवुड कं. लि०, मै० पैनल प्लस एम डी एफ कं. लि०, मै० एस. किजचाई इंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लि० और एग्रो फाइबर कं. लि० सहित अनेक प्रतिवादी निर्यातकों को बीओआई से निवेश संवर्धन प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं और इसलिए वे कार्यक्रम का लाभ लेने के पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने लाभ नहीं लेने के कारण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

थाईलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

379. थाईलैंड सरकार द्वारा बनाया गया निवेश संवर्धन अधिनियम 1977 (आईपीए) में निवेश संवर्धन कार्यक्रम सृजित किए और बीओआई को निम्नलिखित विशेष अधिकार और धारा 36 के अधीन लाभ सहित निवेश संवर्धन प्रोत्साहन प्रदान करने के प्राधिकृत किया: (1) निर्यात के लिए विशिष्ट रूप से उत्पादन, मिश्रण या उत्पादकों के संयोजन या वस्तुओं में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क में छूट तथा (2) पुनः निर्यात के लिए आयात हेतु संवर्धित मद्दों पर आयात शुल्क से छूट।
380. इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीओआई – संवर्धित परियोजनाओं में प्रयुक्त कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क में छूट देकर धारा 36 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की हकदार कंपनियों को सुविधा देना है। जनवरी, 2015

में बीओआई द्वारा शुरू की गई नई निवेश संवर्धन स्कीम के अंतर्गत निवेश जोन के बजाय निवेश कार्यकलाप के अनुसार प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया गया है। 2015 में किए गए परिवर्तन से 2015 के पहले जोनिंग प्रणाली के अंतर्गत जांचाधीन कंपनियों को प्राप्त होने वाले लाभ सहित किसी कंपनी का प्रोत्साहन पैकेज प्रभावित नहीं हुआ है। बीओआई प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता इस वक्त नहीं है क्योंकि यह क्तिपय उद्योगों या क्तिपय उद्यमों तक सीमित नहीं है। यह निर्यात निष्पादन या घरेलू वस्तुओं के उपयोग से जुड़ा हुआ नहीं है।

381. बीओआई के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक कारगर प्रणाली है कि कच्ची या अनिवार्य समिग्रियों की आयात मात्रा चक्रीय अधिकतम स्टॉक से अधिक न हो और यह सुनिश्चित करना कि ये कंपनियां आयातित कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों का तैयार वस्तुओं के रूप में निर्यात करें।
382. निर्यातों के प्रयोजनार्थ आयात शुल्क में छूट अनुच्छेद 1 के अंतर्गत एएससीएम द्वारा अनुमति प्राप्त है। बीओआई के पास अतिरिक्त लाभ नहीं देना सुनिश्चित करने की एक कारगर प्रणाली है। थाईलैंड से ग्लाइसिन संबंधी सीवीडी जांच में यूएसडीओसी द्वारा यही संमुक्ति की गई थी। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त लाभ प्रतिसंतुलन योग्य नहीं है। प्राधिकारी ने कापर मामले में इस कार्यक्रम को गलत ढंग से प्रतिसंतुलित किया था। केवल इस कार्यक्रम के तहत प्रदत्त कोई अतिरिक्त लाभ यदि कोई हो तो, उसे एएससीएम के अनुसार प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम किसी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा नहीं लिया गया है। इस कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार किए जाने चाहिए। कांटीन्यूअस कापर अंतिम जांच परिणाम में पूर्ववर्ती निष्कर्षों को एक समान रूप से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

383. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम 2002 की धारा 36 बीओआई संवर्धित परियोजनाओं में प्रयुक्त कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क से छूट प्रदान करती है। इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत शुल्क मुक्त निविष्टि के प्रयोग से उत्पादित उत्पादों को मिश्रण, संयोजन और उत्पादन कार्यकलाप के पश्चात पुनः निर्यातित या निर्यातित करना अपेक्षित है। यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्धन पैकेज स्कीम का एक हिस्सा है।
384. थाईलैंड सरकार ने अनुरोध किया है कि बीओआई के पास यह सुनिश्चित करने की कारगर प्रणाली है कि कंपनियां आयातित कच्ची सामग्री को तैयार वस्तु के रूप में निर्यात करें और संवर्धित कार्यकलाप करने वाले उत्पादक/निर्यातक को कोई अतिरिक्त लाभ न मिले।
385. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैं० वाइजवुड कं. लि० ने अपने ईक्यूआर अनुरोध में पीयूसी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर सब्सिडी लेना स्वीकार किया था। तदनुसार, प्राधिकारी ने मैं० वाइजवुड कं. लि० के लिए इसकी मात्रा ज्ञात की थी। तथापि, बाद के अनुरोध के जरिए कंपनी ने सूचित किया कि उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर देते समय कच्ची सामग्री के आयात पर लाभ की सूचना अंजाने में दी थी जो वस्तुतः उन्होंने कभी नहीं लिया था। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए जो दर्शाते हैं कि मैं० वाइजवुड कं. लि० ने द्वारा कच्ची सामग्रियां शुल्क की शून्य दर के अधीन थीं और इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैं० वाइजवुड कं. लि० को कच्ची सामग्री की आयात के लिए कोई सब्सिडी/ और लाभ नहीं मिला था।
386. निर्यातों के प्रयोजनार्थ आयात शुल्क से छूट की एएससीएम द्वारा अनुच्छेद 1 के अधीन अनुमति है। तथापि, कार्यक्रम के तहत प्रदत्त केवल किसी अतिरिक्त लाभ यदि कोई हो, को एएससीएम के अनुसार प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। थाईलैंड सरकार ने बताया है कि बीओआई के पास यह सुनिश्चित करने की कारगर प्रणाली है कि कंपनियां आयातित कच्ची सामग्री को तैयार वस्तु के रूप में निर्यात करें और संवर्धित कार्यकलाप करने वाले उत्पादक/ निर्यातक को कोई अतिरिक्त लाभ न मिले। थाईलैंड सरकार ने कोई स्पष्टीकरण या यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि बीओआई स्कीम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने वाला तंत्र कैसे कार्य करता है कि कोई अतिरिक्त लाभ न मिले और शुल्क मुक्त रूप से आयातित कच्ची सामग्री निर्यातित उत्पाद में प्रयुक्त हो। यह प्रदर्शित करने के किसी साक्ष्य के अभाव में कि इस कार्यक्रम अनुमत कर छूट दी जाती है, यह निर्धारित किया गया है कि यह सब्सिडी कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ हुआ है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों से जुड़ी है और संवर्धित कार्यकलाप करने वाले संवर्धित उद्यमों तक सीमित भी है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।

387. चूंकि किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक लाभ प्राप्त करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिवादी निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाने का निर्णय लिया है।

कार्यक्रम संख्या 3: कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों के लिए आयात शुल्क में कटौती

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

388. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ("बी ओ आई") द्वारा प्रशासित है। निवेश संवर्धन अधिनियम 2002 (आईपीए) की धारा 30 और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 2018 की गाइड में संवर्धित कार्यकलाप में उत्पादन, मिश्रण या संयोजन के प्रयोजनार्थ कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर लागू आयात शुल्क पर 90 प्रतिशत तक कटौती की गई है। यह कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान देता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल ऐसे सीमित उद्यमों को उपलब्ध है जिनके पास समान विधान में प्रदत्त सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करने पर उसके अधीन जारी संवर्धन प्रमाणपत्र है।
389. इस कार्यक्रम की प्राधिकारी द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "कांटीन्यूअस कास्ट कापर वायर राइस" के आयातों संबंधी सब्सिडीरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में पूर्व में जांच की गई थी और प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया था। वर्तमान मामले में भी इसे मानने का अनुरोध है।
390. मै० वानाचार्ड ग्रुप पब्लिक कंपनी लि०, मै० वानाचार्ड पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि०, मै० मेट्रो एम डी एफ कं. लि०, मै० एडवांस फाइबर कं. लि०, मै० वाइजवुड कं. लि०, मै० पैनल प्लस एम डी एफ कं. लि०, मै० एस. किजचार्ड इंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लि० और एग्रो फाइबर कं. लि० सहित अनेक प्रतिवादी निर्यातकों को बीओआई से निवेश संवर्धन प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं और इसलिए वे कार्यक्रम का लाभ लेने के पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने लाभ नहीं लेने के कारण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

थाईलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

391. थाईलैंड सरकार द्वारा निर्मित निवेश संवर्धन अधिनियम 1977 (आईपीए) ने निवेश संवर्धन कार्यक्रम सृजित किया और संवर्धित परियोजनाओं में उत्पादन, मिश्रण या संयोजन के प्रयोजनार्थ आयातित कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर सामान्य दर के 90 प्रतिशत तक के आयात शुल्क की कटौती सहित निवेश संवर्धन प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु बीआईओ को प्राधिकृत किया जिसकी अवधि प्रत्येक बार बीओआई द्वारा विहित तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि ऐसी कच्ची या अनिवार्य सामग्रियां ऐसी परियोजनाओं में प्रयोग के लिए जी जानी वाली प्रयोग्यता मात्रा में घरेलू रूप से उत्पादित या उद्भूत न हो रही हों।
392. इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीओआई – संवर्धित परियोजनाओं में प्रयुक्त कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर आयात शुल्क में कटौती करके धारा 30 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की हकदार कंपनियों को सुविधा देना है। थाईलैंड सरकार ने बताया कि यह कार्यक्रम घरेलू बाजार में बेची गई वस्तुओं के उत्पादन के लिए आयातित कच्ची और अनिवार्य सामग्रियों पर लाभ प्रदान करता है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम से भारतीय घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है और इसलिए यह जांच से असंगत है। इस कार्यक्रम की पात्रता विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह शैक्षिक आधार पर उपलब्ध है और इसका लाभ लेने की इच्छुक कंपनियों को इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, जांच के अधीन किसी भी कंपनी को धारा 30 के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है।
393. यह बताया गया है कि थाईलैंड से किसी उत्पादक ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय अंशदान/लाभ नहीं मिला है। इस कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार की जानी चाहिए। कांटीन्यूअस कापर अंतिम जांच परिणाम में पूर्ववर्ती निष्कर्षों को एक समान रूप से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

394. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्धन अधिनियम 2002 की धारा 30 संवर्धित परियोजनाओं में उत्पादन, मिश्रण या संयोजन के प्रयोजनार्थ थाईलैंड में आयातित कच्ची या अनिवार्य सामग्रियों पर सामान्य दर के 90

प्रतिशत तक के आयात शुल्क की कटौती का प्रावधान करती है जिसकी अवधि प्रत्येक बार बीओआई द्वारा विहित तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि ऐसी कच्ची या अनिवार्य सामग्रियां गुणवत्ता में तुलनीय हों और ऐसी परियोजनाओं में प्रयोग के लिए ली जानी वाली पर्याप्त मात्रा में थाईलैंड के भीतर उत्पादित या उद्भूत न हो रही हों। यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्धन प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है।

395. यह सब्सिडी कार्यक्रम गंवाए गए राजस्व जो अन्यथा बकाया होता, के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान करता है और इसके द्वारा लाभ मिला है। सब्सिडी विशिष्ट भी है क्योंकि यह संवर्धित कार्यकलाप करने वाले संवर्धित उद्यमों तक सीमित है। अतः प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिसंतुलन योग्य मानते हैं।
396. तथापि क्योंकि उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों में से किसी ने भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ नहीं लिए हैं, इसलिए यह नोट किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत उनके विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 4: बीओआई-संवर्द्धित कार्यकलापों के लिए कॉर्पोरेट आय कर में छूट

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

397. याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम निवेश बोर्ड (“बीओआई”) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 (आईपीए) की धारा 31 और निवेश बोर्ड, 2018 की निर्देशिका में आठ वर्ष तक की अवधि के लिए किसी संवर्द्धित कार्यकलाप से अर्जित निवल लाभ पर लागू कॉर्पोरेट आय कर में छूट दी गई है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यदि किसी कंपनी को नुकसान हो रहा है तो कार्यक्रम में नुकसान को आगे ले जाने का प्रावधान है और इस प्रकार बाद की अवधि में लाभ लिया जा सकता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह केवल कुछ सीमित उद्यमों को उपलब्ध है जिनके पास संबंधित कानून के तहत निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इस कानून के अंतर्गत जारी किया गया संवर्द्धन प्रमाण-पत्र है।
398. इस कार्यक्रम की पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और वियतनाम से “सतत कास्ट कॉपर वायर रॉड्स” के आयात के सब्सिडी-रोधी अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और इसे प्रतिकारी पाया गया था। मौजूदा मामले में भी इसे बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है।
399. बनचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, बनचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड, वाइजवुड्स कंपनी लिमिटेड, पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एस. किजचाई एंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, और एग्रोफाइबर कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न उत्तरदाता निर्यातकों को बीओआई से निवेश संवर्द्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार वे कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसका लाभ न लेने के कारण नहीं बताए हैं।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

400. थाईलैंड सरकार द्वारा अधिनियमित निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 1977 (आईपीए) द्वारा निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया था और इसके द्वारा बीओआई को धारा 31 के तहत व्यावसायिक कार्यकलाप से पहली बार आय अर्जित किए जाने की तारीख से आठ वर्ष तक की अवधि के लिए बीओआई-संवर्द्धित परियोजनाओं से होने वाले निवल लाभ पर कॉर्पोरेट आय कर में छूट सहित निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। यदि नुकसान होता है तो बीओआई, छूट की अवधि समाप्त होने के बाद से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए ऐसे वार्षिक नुकसान को अर्जित निवल लाभ में से कम करने की अनुमति दे सकता है। बीओआई द्वारा जनवरी, 2015 में जारी की गई नई निवेश संवर्द्धन स्कीम के तहत प्रोत्साहन पैकेज निवेश जोन के बजाय निवेश कार्यकलाप के अनुसार जारी किया जाता है। वर्ष 2015 में किए गए परिवर्तन से 2015 से पहले जोनिंग प्रणाली के अंतर्गत अन्वेषणाधीन कंपनियों सहित अन्य कंपनियों को प्राप्त हुआ प्रोत्साहन पैकेज प्रभावित नहीं होगा। कार्यक्रम के लिए पात्रता विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध करवाया गया है और इसका लाभ लेने की इच्छुक इकाइयां इसके लिए आवेदन करेंगी। इस कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। सतत कॉपर के अंतिम निष्कर्ष में पूर्व निष्कर्ष को सबके लिए समान

रूप से लाभ करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। वनचार्ई समूह ने थाईलैंड के लिए कार्यक्रम सं. 4 का लाभ नहीं लिया है।

401. मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड और एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड ने कहा कि कार्यक्रम विशिष्ट नहीं है क्योंकि पात्रता मानदंड व्यापक हैं। पैनल प्लस एमडीएफ द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें बीओआई संवर्द्धित कार्यकलापों में नुकसान हुआ और कार्यक्रम का उपयोग नहीं किया गया। मैसर्स वनचार्ई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने भी उल्लेख किया है कि उनके बीओआई के तीन प्रमाण-पत्रों में से दो की मियाद बहुत पहले क्रमशः 1998 और 1999 में समाप्त हो चुकी हैं और एक बीओआई प्रमाण-पत्र की मियाद 2022 में समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने यह भी कहा है कि क्योंकि उन्हें पीओआई में बीओआई संवर्द्धित कार्यकलापों में नुकसान हुआ है इसलिए वे उपर्युक्त स्कीम के तहत कॉर्पोरेट आय कर में छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

402. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्द्धन पैकेज स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों में से एक है। निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 की धारा 31 के अनुसार पात्र इकाइयों को कॉर्पोरेट आय कर में छूट दी जाती है। आय कर में छूट ऐसे कार्यकलाप से पहली बार आय के अर्जन की तारीख से आड़ वर्ष से अधिक अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कॉर्पोरेट आय कर में छूट उपलब्ध होने की पात्र अवधि के दौरान नुकसान होता है तो बीओआई को लाभार्थी व्यक्ति को कॉर्पोरेट आय कर में छूट की पात्र अवधि समाप्त होने के बाद से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए ऐसे वार्षिक नुकसान को अर्जित निवल लाभ में से कम करने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है। लाभार्थी व्यक्ति किसी एक वर्ष या विभिन्न वर्षों के निवल लाभ में से ऐसे नुकसान को कम कर सकता है।
403. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल संवर्द्धित कार्यकलाप करने वाले संवर्द्धित उद्यमों तक सीमित है। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकारी मानते हैं।
404. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स वाइजवुड कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के दाखिल किए गए उत्तर में यह दर्शाया गया है कि उनके द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया था और उन्होंने पीओआई के दौरान प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि के संबंध में सूचना प्रदान की है।
405. यह भी नोट किया गया है कि मैसर्स मेट्रो एमडीएफ द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि उनके द्वारा वर्ष 2016 में कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया था परंतु इसका प्रयोग पीओआई के दौरान किया गया था।
406. मैसर्स वनचार्ई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी को तीन बीओआई प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे जिनमें से दो की मियाद क्रमशः 1998 और 1999 में समाप्त हो चुकी हैं जबकि एक बीओआई प्रमाण-पत्र की मियाद 2022 में समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने यह भी कहा है कि क्योंकि उन्हें पीओआई के दौरान बीओआई संवर्द्धित कार्यकलापों में नुकसान हुआ है इसलिए वे उपर्युक्त स्कीम के तहत कॉर्पोरेट आय कर में छूट के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हें आय कर में छूट प्राप्त हुई हालांकि बीओआई प्रमाण-पत्र के तहत नहीं।
407. इसी प्रकार मैसर्स ग्रीन फाइबर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि उन्हें आय कर में छूट प्राप्त हुई है हालांकि बीओआई प्रमाण-पत्र के तहत नहीं।
408. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स एडवांस फाइबर ने उपर्युक्त स्कीम के तहत प्रदान किए गए लाभों का उपयोग नहीं किया है चूंकि बीओआई प्रमाण-पत्र की मियाद समाप्त हो चुकी है और कंपनी द्वारा पीओआई के दौरान आय कर में कोई अतिरिक्त छूट प्राप्त नहीं की गई।
409. इसके अतिरिक्त वनचार्ई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि उत्तरदाता निर्यातक द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया गया।

410. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स के अनुसार मैसर्स पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड, मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, मैसर्स एग्रो फाइबर कंपनी लिमिटेड ने इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।
411. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड्स में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है। इस प्रकार परिकलित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

कार्यक्रम सं. 5: निवेश संवर्द्धन जोनों में आय कर में छूट

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

412. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम निवेश बोर्ड ("बीओआई") द्वारा प्रबंधित किया जाता है। निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 (आईपीए) की धारा 35 और निवेश बोर्ड की निर्देशिका, 2018 में संवर्द्धित कार्यकलापों में संलग्न और संवर्द्धित स्थल/जोन में स्थित उद्यमों को धारा 31 के तहत उल्लिखित अवधि के बाद पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए कॉर्पोरेट आय कर में 50% की छूट प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह केवल कुछ सीमित उद्यमों को उपलब्ध है जिनके पास संबंधित कानून के तहत निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इस कानून के अंतर्गत जारी किया गया संवर्द्धन प्रमाण-पत्र है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र विशिष्ट भी है क्योंकि लाभ केवल संवर्द्धित स्थलों/जोनों में स्थित उद्यमों को उपलब्ध है।
413. इस कार्यक्रम की पूर्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और वियतनाम से "सतत कास्ट कॉपर वायर रॉड्स" के आयात के सब्सिडी-रोधी अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और इसे प्रतिकारी पाया गया था। मौजूदा मामले में भी इसे बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है।
414. वनचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, वनचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड, वाइजवुइस कंपनी लिमिटेड, पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एस. किजचाई एंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, और एग्रो फाइबर कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न उत्तरदाता निर्यातकों को बीओआई से निवेश संवर्द्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार वे कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसका लाभ न लेने के कारण नहीं बताए हैं।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

415. थाईलैंड सरकार द्वारा अधिनियमित निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 1977 (आईपीए) द्वारा निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया और बीओआई को धारा 35(1) के तहत संवर्द्धित कार्यकलापों से अर्जित निवल लाभ पर कॉर्पोरेट आय कर में 50 प्रतिशत की छूट सहित निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन देने के लिए प्राधिकृत किया गया। यह प्रोत्साहन धारा 31 के पैरा एक या दो के अंतर्गत उल्लिखित समय-समाप्ति तारीख से या किसी लाभार्थी व्यक्ति को कॉर्पोरेट आय कर में छूट नहीं प्रदान करने के मामले में संवर्द्धित क्रियाकलाप से पहली बार आय अर्जित करने की तारीख से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।
416. इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ स्थलों या जोनों में आय कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करके उन कंपनियों को सुविधा उपलब्ध कराना है जो धारा 35(1) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। बीओआई प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्रता विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह कुछ उद्योगों या कुछ उद्यमों तक सीमित नहीं है। यह न तो निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर है और न ही घरेलू वस्तुओं के प्रयोग पर। अन्वेषणाधीन कंपनियों में से किसी ने भी पीओआई के दौरान धारा 35(1) के तहत लाभ नहीं लिया।
417. यह उल्लेख किया गया है कि थाईलैंड के किसी भी उत्पादक ने इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय अंशदान/लाभ प्राप्त नहीं किया। इस कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। सतत कॉपर के अंतिम निष्कर्ष में पूर्व निष्कर्ष को सबके लिए समान रूप से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

418. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संवर्द्धित कार्यकलाप से अर्जित निवल लाभ पर कॉर्पोरेट आय कर की सामान्य दर में 50% की छूट उपलब्ध है। प्राधिकारी द्वारा अन्य कार्यक्रमों में कॉर्पोरेट आय कर में छूट को पहले ही प्रतिकारी करार दे दिया गया है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत उत्तरदाता के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 6: सुविधाओं के संस्थापन या निर्माण की लागत में अतिरिक्त 25 प्रतिशत की कटौती

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

419. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम निवेश बोर्ड (“बीओआई”) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 (आईपीए) की धारा 35 और निवेश बोर्ड, 2018 की निर्देशिका में कंपनी की करयोग्य आय से किसी संवर्द्धित कार्यकलाप के लिए सुविधाओं के संस्थापन या निर्माण पर आने वाली लागत के 25% की कटौती का लाभ दिया गया है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह केवल कुछ सीमित उद्यमों को उपलब्ध है जिनके पास संबंधित कानून के तहत निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इस कानून के अंतर्गत जारी किया गया संवर्द्धन प्रमाण-पत्र है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र विशिष्ट भी है क्योंकि लाभ केवल संवर्द्धित स्थलों/जोनों में स्थित उद्यमों को संवर्द्धित कार्यकलाप करने के लिए ही उपलब्ध है।
420. प्राधिकारी द्वारा पूर्व में इस कार्यक्रम की इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और वियतनाम से “सतत कास्ट कॉपर वायर रॉड्स” के आयात के सब्सिडी-रोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में जांच की गई थी और इसे प्रतिकारी पाया गया था। मौजूदा मामले में भी इसे बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है।
421. वनचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, वनचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड, वाइजवुड्स कंपनी लिमिटेड, पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एस. किजचई एंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, और एग्रोफाइबर कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न उत्तरदाता निर्यातकों को बीओआई से निवेश संवर्द्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार वे कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसका लाभ न लेने के कारण नहीं बताए हैं।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

422. थाईलैंड सरकार द्वारा अधिनियमित निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 1977 (आईपीए) द्वारा निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया था और इसके द्वारा बीओआई को धारा 35(3) के तहत संवर्द्धित कार्यकलाप में प्रयुक्त सुविधाओं के संस्थापन या निर्माण की लागत के 25 प्रतिशत तक की राशि निवल लाभ में से घटाने की अनुमति सहित निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। सामान्य मूल्यहास के अतिरिक्त संवर्द्धित कार्यकलाप से पहली बार आय प्राप्त होने की तारीख से 10 वर्ष के अंदर किसी एक वर्ष या विभिन्न वर्षों के निवल लाभ में से कटौती की जा सकती है। बीओआई द्वारा जनवरी, 2015 में जारी की गई नई निवेश संवर्द्धन स्कीम के तहत प्रोत्साहन पैकेज निवेश जोन के बजाय निवेश कार्यकलाप के अनुसार जारी किया जाता है। वर्ष 2015 में किए गए परिवर्तन से 2015 से पहले जोनिंग प्रणाली के अंतर्गत अन्वेषणाधीन कंपनियों सहित अन्य कंपनियों को प्राप्त हुआ प्रोत्साहन पैकेज प्रभावित नहीं होगा। बीओआई प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह कुछ उद्योगों या कुछ उद्यमों तक सीमित नहीं है। यह न तो निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर है और न ही घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर।
423. मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड और एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड ने कहा कि कार्यक्रम किसी विशेष उद्यम या उद्योग के लिए सीमित नहीं है और आर्थिक कार्यकलापों की व्यापक श्रेणी को उपलब्ध है और इस प्रकार यह विशिष्ट नहीं है। इस कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। सतत कॉपर के अंतिम निष्कर्ष में पूर्व निष्कर्ष को सबके लिए समान रूप से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

424. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 की धारा 35(3) के तहत संवर्द्धित कार्यकलाप में प्रयुक्त सुविधाओं के संस्थापन या निर्माण की लागत के 25 प्रतिशत तक की राशि निवल लाभ में से घटा कर आय कर में छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ ऐसी कटौती की गैर-मौजूदगी में देय कर की राशि और वास्तव में भुगतान किए गए आय कर के बीच के अंतर के समान होगा। यह सब्सिडी कार्यक्रम निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है।
425. सब्सिडी कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। सब्सिडी विशिष्ट भी होती है क्योंकि यह संवर्द्धित कार्यकलाप करने वाले संवर्द्धित उद्यम तक सीमित है। प्राधिकारी ने यह पहले ही नोट किया है कि आय कर में छूट देने वाले सब्सिडी कार्यक्रम पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदाता निर्यातकों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 7: निवेश संवर्द्धन जोन में कंपनियों को उपलब्ध दोहरी कटौती

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

426. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम, निवेश बोर्ड (“बीओआई”) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 (आईपीए) की धारा 35 और निवेश बोर्ड, 2018 की निर्देशिका में किसी संवर्द्धित स्थल/जोन में स्थित संवर्द्धित कार्यकलाप के संबंध में परिवहन, बिजली और जलापूर्ति पर आई लागत की दोहरी राशि को आय कर में से घटाने का लाभ दिया गया है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह केवल कुछ सीमित उद्यमों को उपलब्ध है जिनके पास संबंधित कानून के तहत निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इस कानून के अंतर्गत जारी किया गया संवर्द्धन प्रमाण-पत्र है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र विशिष्ट भी है क्योंकि लाभ केवल संवर्द्धित स्थलों/जोनों में स्थित उद्यमों को संवर्द्धित कार्यकलाप करने के लिए ही उपलब्ध है।
427. प्राधिकारी द्वारा पूर्व में इस कार्यक्रम की इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और वियतनाम से “सतत कास्ट कॉपर वायर रॉड्स” के आयात के सब्सिडी-रोधी अन्वेषण के अंतिम जांच परिणामों में जांच की गई थी और इसे प्रतिकारी पाया गया था। मौजूदा मामले में भी इसे बनाए रखने का अनुरोध किया जाता है।
428. बनचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, बनचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड, वाइजवुड्स कंपनी लिमिटेड, पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एस. किजचाई एंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, और एग्रोफाइबर कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न उत्तरदाता निर्यातकों को बीओआई से निवेश संवर्द्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार वे कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसका लाभ न लेने के कारण नहीं बताए हैं।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

429. थाईलैंड सरकार द्वारा अधिनियमित निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 1977 (आईपीए) द्वारा निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया था और इसके द्वारा बीओआई को धारा 35(2) के तहत संवर्द्धित कार्यकलाप के प्रचालन में संवर्द्धित व्यक्ति द्वारा परिवहन, बिजली और जलापूर्ति पर आई लागत की दोहरी राशि को कॉर्पोरेट आय कर के आकलन के उद्देश्य से घटाने की अनुमति सहित निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। बीओआई प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह कुछ उद्योगों या कुछ उद्यमों तक सीमित नहीं है। यह न तो निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर है और न ही घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर। किसी भी अन्वेषणाधीन कंपनी ने धारा 35(2) के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया।
430. बीओआई द्वारा प्रबंधित कार्यक्रम एएससीएम के अनुसार विशिष्ट नहीं हैं। ये मोटे तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हैं और किसी विशेष इकाई, भौगोलिक क्षेत्र, या उद्योग के सेगमेंट तक सीमित नहीं हैं। अमेरिका में डब्ल्यूटीओ एबी रिपोर्ट – अपलैंड कॉटन एंड यूएस – पाटन-रोधी और प्रतिकारी शुल्क (चीन) को आधार बनाया गया है। इस कार्यक्रम की जांच प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर की जानी चाहिए। सतत

कॉपर के अंतिम जांच परिणाम में पूर्व निष्कर्ष को सबके लिए समान रूप से लागू करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

431. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत लाभ आय कर के उद्देश्य से कुल आय की गणना के लिए परिवहन, बिजली और जलापूर्ति व्यय पर आई लागत की दोहरी राशि को घटाने का लाभ दिया जाता है। यह सबिसडी कार्यक्रम निवेश संवर्द्धन प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है।
432. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सबिसडी कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। इस सबिसडी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ ऐसी कटौती की गैर-मौजूदगी में देय कर की राशि और वास्तव में भुगतान किए गए आय कर के बीच के अंतर के समान होगा। यह सबिसडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह संवर्द्धित कार्यकलाप करने वाले संवर्द्धित उद्यम तक सीमित है। प्राधिकारी ने यह पहले ही नोट किया है कि आय कर में छूट देने वाले सबिसडी कार्यक्रम पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सबिसडी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदाता नियंत्रितकों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 8: आय कर में छूट – लाभांश

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

433. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम, निवेश बोर्ड (“बीओआई”) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 (आईपीए) की धारा 34 और निवेश बोर्ड, 2018 की निर्देशिका में किसी कानूनी रूप से मान्य इकाई को किसी संवर्द्धित कार्यकलाप से अर्जित लाभांश पर लगाए जाने वाले आय कर में छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह लाभ अन्वेषणाधीन कंपनियों द्वारा लिया जा सकता है और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचा सकता है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह केवल कुछ सीमित उद्यमों को उपलब्ध है जिनके पास संबंधित कानून के तहत निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर इस कानून के अंतर्गत जारी किया गया संवर्द्धन प्रमाण-पत्र है और जिन्हें संवर्द्धित कार्यकलापों से लाभांश आय प्राप्त होती है।
434. बनचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, बनचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड, वाइजवुड्स कंपनी लिमिटेड, पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, एस. किजचई एंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, और एग्रोफाइबर कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न उत्तरदाता नियंत्रितकों को बीओआई से निवेश संवर्द्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार वे कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसका लाभ न लेने के कारण नहीं बताए हैं। मैसर्स एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड, मैसर्स मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, मैसर्स वाइजवुड्स कंपनी लिमिटेड, और मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड ने स्वयं बताया है कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

435. थाईलैंड सरकार द्वारा अधिनियमित निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 1977 (आईपीए) द्वारा निवेश संवर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया था और इसके द्वारा बीओआई को धारा 34 के तहत संवर्द्धित कार्यकलाप से अर्जित लाभांश पर आय कर में छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। चूंकि धारा 34 कंपनी के शेयरधारकों को लाभ पहुँचाती है, न कि कंपनी को, इसलिए यह किसी भी प्रकार से भारतीय घरेलू बाजार को नुकसान नहीं पहुँचाती। इसलिए धारा 34 का लाभ इस अन्वेषण के लिए प्रासंगिक नहीं है। बीओआई द्वारा जनवरी, 2015 में जारी की गई नई निवेश संवर्द्धन स्कीम के तहत प्रोत्साहन पैकेज निवेश जोन के बजाय निवेश कार्यकलाप के अनुसार जारी किया जाता है। वर्ष 2015 में किए गए परिवर्तन से 2015 से पहले जोनिंग प्रणाली के अंतर्गत अन्वेषणाधीन कंपनियों सहित अन्य कंपनियों को प्राप्त हुआ प्रोत्साहन पैकेज प्रभावित नहीं होगा। बीओआई प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्रता विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह कुछ उद्यमों या कुछ उद्यमों तक सीमित नहीं है। यह न तो नियंत्रित प्रदर्शन पर निर्भर है और न ही घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर। मैसर्स मेट्रो एमडीएफ कंपनी लिमिटेड और मैसर्स

एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड ने उल्लेख किया कि लाभ, यदि कोई है, कंपनी को प्राप्त नहीं होता बल्कि कंपनी के शेयरधारकों को प्राप्त होता है। मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि इस कार्यक्रम से कंपनी के शेयरधारकों को लाभ होता है और कंपनी को नहीं। मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ को पीओआई में लाभ नहीं हुआ चूंकि बीओआई संवर्द्धित कार्यकलाप नुकसान में था और लाभांश शून्य था। थाई निर्यातकों ने या तो किसी प्रतिकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है या सब्सिडी राशि, यदि कोई है, नगण्य से भी कम है। उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

436. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निवेश संवर्द्धन अधिनियम, 2002 की धारा 34 के तहत बीओआई को संवर्द्धित कार्यकलाप से अर्जित लाभांश पर आय कर में छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। संगत कानूनी प्रावधान के अनुसार लाभ कानूनी रूप से मान्य इकाइयों को प्रदान किया जाता है और इस प्रकार शेयरधारक कंपनियों को प्रदान किया जाता है। थाईलैंड सरकार के तर्क के विपरीत कि यह कार्यक्रम घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, चूंकि यह लाभ शेयरधारकों/व्यक्तियों को प्राप्त होता है, इसलिए कोई भी अन्वेषणाधीन कंपनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ ले सकती है। प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि उपर्युक्त कार्यक्रम प्रतिकारी है। तथापि चूंकि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है, इसलिए यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 9: निर्यात पर वैट में छूट

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

437. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम थाईलैंड सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। राजस्व कोड, 2016 की धारा 80 में निःशुल्क जोनों में स्थित अनुबद्ध गोदामों या उद्यमों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात और वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर वैट की दर शून्य निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम निर्यात निर्भर है और इसलिए इसे विशिष्ट माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र विशिष्ट भी है।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

438. राजस्व कोड की धारा 80/1 के अनुसार कुछ अन्य के बीच निम्नलिखित व्यवसायों में मूल्य वर्धित कर की गणना के लिए शून्य दर का प्रयोग किया जाएगा: (1) ऐसी वस्तुओं का निर्यात जो धारा 81(3) के तहत मूल्य वर्धित कर से छूट प्राप्त नहीं हैं; (2) सीमा-शुल्क मुक्त जोन में अनुबद्ध गोदामों के बीच, व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के बीच, चाहे वे एक ही जोन में हों या नहीं, या महानिदेशक द्वारा निर्धारित सीमा-शुल्क मुक्त जोन में अनुबद्ध गोदामों के बीच और व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के बीच वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं का प्रावधान।
439. थाईलैंड सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि प्राधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम की इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और वियतनाम से “सतत कास्ट कॉपर वायर रॉड्स” के आयात के सब्सिडी-रोधी अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों में जांच की गई थी और इसे प्रतिकारी नहीं पाया गया था।
440. यह उल्लेख किया गया है कि इस कार्यक्रम में निर्यात की गई वस्तुओं पर कर में छूट प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम एससीएम और सीटीए के अनुसार प्रतिकारी नहीं है। कॉपर मामले में भी इस पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

441. यह नोट किया गया है कि राजस्व कोड, 2016 की धारा 80 में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में संलग्न व्यवसायियों द्वारा मूल्य वर्धित कर के भुगतान का प्रावधान किया गया है।
442. यह नोट किया गया है कि इस सब्सिडी कार्यक्रम में वस्तुओं के निर्यात पर मूल्य वर्धित कर में छूट का प्रावधान किया गया है। इस सब्सिडी कार्यक्रम में निर्यात की गई वस्तुओं पर एससीएम समझौते के फुटनोट 1 और सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 9बी(बी)(i) के अनुसार घरेलू उपभोग के लिए भेजे जाने वाले समान उत्पाद पर अन्यथा लगने वाले कर में छूट प्रदान की जाती है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदाता निर्यातकों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 10: लघु अवधि निर्यात क्रेडिट बीमा

याचिकाकार्ताओं का अनुरोध

443. याचिकाकार्ताओं ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम थाईलैंड के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस कार्यक्रम में निर्यातकों की विदेश में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को भुगतान नहीं किए जाने के जोखिम से सुरक्षित किया जाता है। भुगतान में चूक होने पर नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी में उल्लिखित शर्तों के अनुसार की जाती है। यह कार्यक्रम केवल एसएमई के लिए जारी किया गया है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है चूंकि इसमें रियायती प्रीमियम दर पर बीमा प्रदान किया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम निर्यात निर्भर है और इसलिए इसे विशिष्ट माना जाता है।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

444. निर्यात क्रेडिट बीमा सुविधाओं से निर्यातकों की विदेश में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को भुगतान नहीं किए जाने के जोखिम से सुरक्षित किया जाता है। विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में एकिजम थाईलैंड बीमा पॉलिसी में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। इसमें शामिल किए गए जोखिमों में व्यावसायिक जोखिम और राजनैतिक जोखिम शामिल हैं।
445. यह उल्लेख किया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत थाईलैंड के किसी उत्पादक को वित्तीय अंशदान/लाभ प्राप्त नहीं हुआ और कोई प्रतिकारी लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

446. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम थाईलैंड के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ थाईलैंड (एकिजम बैंक) सरकार की निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित वित्त मंत्रालय के पर्यवेक्षण में एक राज्य के स्वामित्व वाली विशेषीकृत वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ थाईलैंड अधिनियम, 1993 (बी.ई. 2536) द्वारा की गई थी जो 7 सितंबर, 1993 को लागू हुआ। एकिजम बैंक वैश्विक व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में थाई उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सहयोग करने और इसे बढ़ाने वाला सरकारी तंत्र है। वित्त मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के थाई निर्यातों, आयातों और निवेशों को बढ़ावा दें और इनमें सहयोग करने के अधिदेश के साथ एक राज्य-संचालित विशेषीकृत वित्तीय संस्था के रूप में अपने मिशन को पूरा करने की बैंक की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें पूंजी डाली। सितंबर, 2009 में वित्त मंत्रालय ने बैंक की पूंजी बढ़ा दी जिसे स्ट्रॉग थाईलैंड स्कीम 2012 के तहत निर्यात क्रेडिट बीमा के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया था। इस सेवा से निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के जोखिम से सुरक्षित करने में सहायता मिलती है जिससे निर्यातकों में प्रमुख या उभरते हुए बाज़ारों में अपना व्यवसाय बढ़ाने का विश्वास बढ़ता है। एकिजम बैंक वर्तमान में मास्टर प्लान 2017-2027 का अनुसरण कर रहा है जिसे थाई निर्यातों को 'उच्च आर्थिक वृद्धि वाले नए सीमा-प्रदेशों,' जिनमें भारत शामिल है, के साथ पुनः अनुकूलित करने के थाई सरकार के एजेंडा के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। सरकार की विशेषीकृत वित्तीय संस्था के रूप में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ थाईलैंड (एकिजम थाईलैंड), थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश कार्यनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख प्रणाली के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ थाईलैंड ने वैश्विक व्यापार और निवेश में थाई उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सहयोग करने और इसे बढ़ाने में एक सरकारी तंत्र के रूप में कार्य करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ बदलते व्यापार एवं निवेश वातावरण के अनुसार संगठन को विकसित करना जारी रखा।
447. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एकिजम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है जिसे सरकारी कार्य सौंपे गए हैं और जिसे सरकारी कार्यों के निष्पादन का प्राधिकार दिया गया है, सरकारी नियंत्रण के औपचारिक संकेतों और यह दर्शने वाले साक्ष्य के आधार पर कि इसे एक सार्थक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, यह एक सार्वजनिक निकाय है। एकिजम बैंक निर्यातकों की विदेश में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को भुगतान नहीं किए जाने के जोखिम से सुरक्षित करने के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

448. इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। प्राप्तिकर्ता को दिए जाने वाला लाभ एकिजम बैंक से गारंटी प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए शुल्क और ऐसी गारंटी के लिए किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को अन्यथा भुगतान किए जाने वाले शुल्क के अंतर के समान है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है। प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकारी मानते हैं। तथापि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 11: मध्यम और दीर्घ-अवधि निर्यात क्रेडिट बीमा

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

449. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त कार्यक्रम थार्डलैंड के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस कार्यक्रम में निर्यातकों की विदेश में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को भुगतान नहीं किए जाने के जोखिम से सुरक्षित किया जाता है। भुगतान में चूक होने पर नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी में उल्लिखित शर्तों के अनुसार की जाती है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है चूंकि इसमें रियायती प्रीमियम दर पर बीमा प्रदान किया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम निर्यात निर्भर है और इसलिए इसे विशिष्ट माना जाता है।
450. उत्तरदाता निर्यातकों ने देश के अंदर रियायती दरों पर बैंकों से ऋण प्राप्त किए हैं। ऋण की व्याज दर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करती है जिसमें ऋण देने वाले निकाय अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और रियायती दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। प्राधिकारी को सब्सिडी आधार पर दिए जाने वाले ऋणों का संज्ञान लेना चाहिए और इसे निर्धारित करना चाहिए।

थार्डलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

451. मध्यम तथा दीर्घ-अवधि निर्यात क्रेडिट बीमा में विदेशों में किए जाने वाले व्यापार लेन-देन अर्थात् विदेशी क्रेताओं/उथारकर्ताओं को क्रेडिट तथा ऋण सहित वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात से संबंधित व्यावसायिक तथा राजनैतिक नुकसान के कारण भुगतान में चूक किए जाने से सुरक्षा प्रदान की जाती है। एकिजम बैंक द्वारा कोई ऋण नहीं दिए जाते। यह उल्लेख किया गया है कि थार्डलैंड के किसी भी उत्पादक ने इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय अंशदान/लाभ प्राप्त नहीं किया है। एकिजम बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्र में विशेष रूप से दर्शाया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनचाई गुप या पैनल प्लस गुप द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया। यह मामला उपलब्ध तथ्यों का संदर्भ लेने के लिए उचित नहीं है जब थाई निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है। डीजीटीआर मैनुअल के अनुसार सीवीडी नियमों के नियम 7(8) और ईसी-डीआरएम चिप्स के संबंध में प्रतिकारी उपायों में पैनल रिपोर्ट के अनुसार एएससीएम के अनुच्छेद 12.7 को आधार बनाया गया है।
452. किसी ऋण को सब्सिडी के रूप में मानने के लिए यह किसी सरकारी या सार्वजनिक निकाय से दिया जाना चाहिए और लाभ, बाजार की तुलना में निम्न व्याज दर पर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। मेट्रो गुप द्वारा लिए गए ऋण व्यावसायिक बैंकों से बाजार दरों पर लिए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

453. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम थार्डलैंड के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जैसा कि कार्यक्रम सं. 10 में देखा गया है, एकिजम बैंक एक सार्वजनिक निकाय है जिसे सरकारी कार्य सौंपे गए हैं और जिसे सरकारी कार्यों के निष्पादन का प्राधिकार दिया गया है, सरकारी नियंत्रण के औपचारिक संकेतों और यह दर्शाने वाले साक्ष्य के आधार पर कि इसे एक सार्थक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, यह एक सार्वजनिक निकाय है। एकिजम बैंक निर्यातकों की विदेश में प्राप्त होने वाली वस्तुओं को भुगतान नहीं किए जाने के जोखिम से सुरक्षित करने के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
454. इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। प्राप्तिकर्ता को दिए जाने वाला लाभ एकिजम बैंक से गारंटी प्राप्त करने के लिए भुगतान किए

गए शुल्क और ऐसी गारंटी के लिए किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को अन्यथा भुगतान किए जाने वाले शुल्क के अंतर के समान है। यह सब्सिडी कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यात पर निर्भर है और यह उद्यम विशिष्ट है चूंकि वसूल किए जाने वाला शुल्क उपभोक्ता कंपनी की क्रेडिट पात्रता पर भी निर्भर करेगा। प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकारी मानते हैं। तथापि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

अन्य सब्सिडी-ऋण

455. तथापि अन्वेषण के दौरान प्राधिकारी ने यह पाया कि मैसर्स ग्रीन फाइबर, मैसर्स एग्रो फाइबर, मैसर्स पैनल प्लस, मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ, मैसर्स वनचाई ग्रुप, और मैसर्स वनचाई पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कंपनियों द्वारा केंद्रीय बैंक के निर्देशों पर परिचालित वित्तीय संस्थाओं से प्रचलित बाजार दर की तुलना में कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने इसे नोट किया है और यह पाया कि ये ऋण छोड़े गए राजस्व के रूप में वित्तीय अंशदान की प्रकृति के हैं। ये ऋण उद्यम विशिष्ट हैं चूंकि ये ऋण प्राप्तिकर्ताओं द्वारा बास्तव में बाजार से प्राप्त किए जा सकने वाले ऋण की शर्तों की तुलना में अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रदान किए गए हैं। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकारी मानते हैं।
456. भुगतान की गई ब्याज दर और सामान्य ब्याज दर के बीच अंतर है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादकों/निर्यातकों मैसर्स ग्रीन फाइबर कंपनी लिमिटेड, मैसर्स एग्रो फाइबर कंपनी लिमिटेड, मैसर्स पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड, मैसर्स पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, मैसर्स वनचाई ग्रुप कंपनी लिमिटेड, और मैसर्स वनचाई पैनल कंपनी लिमिटेड पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 12ए: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

457. याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया कि यह कार्यक्रम थार्डलैंड सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। थार्डलैंड में फसल योग्य लगभग संपूर्ण वन भूमि का स्वामित्व थार्डलैंड सरकार के पास है और यह रॉयल्टी वसूल करने के बाद कंपनियों को लकड़ी काटने के अधिकार प्रदान करती है और यह रॉयल्टी बाजार के सिद्धांतों के आधार पर परिकलित की जाती है। थार्डलैंड सरकार लकड़ी सहित वस्तुओं पर उच्च सांविधिक निर्यात कर भी लगाती है। इससे घरेलू बाजार खराब होता है और लकड़ी, जो एलटीएआर में पीयूसी के उत्पादकों के लिए अनिवार्य कच्चा माल है, उपलब्ध कराई जाती है। परिणामस्वरूप इससे कोई अंतर नहीं आता कि कच्चा माल किसी राज्य के स्वामित्व वाले वन से खरीदा गया है या निजी भूमि से। थार्डलैंड में लकड़ी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मानक कीमतों से कम है।
458. थार्डलैंड के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार संदर्भाधीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए रबड़ वुड या यूकेलिप्टस का प्रयोग किया जाता है। रबड़ वुड प्राप्त करने के उद्देश्य से थार्डलैंड सरकार ने वन विभाग के साथ मिल कर पौधारोपण के लिए अधिक ज़िम्मेदारी ली है। इसके अतिरिक्त रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ थार्डलैंड और रॉयल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस उद्देश्य से साथ मिल कर काम करने के लिए समन्वय किया है।
459. ‘प्रतिबंधित लकड़ी’ शब्द को राष्ट्रीय आरक्षित वन अधिनियम, 1971 में परिभाषित नहीं किया गया है, जैसा कि इच्छुक पक्षों द्वारा उल्लेख किया गया है। तथापि ‘लकड़ी’ शब्द की परिभाषा में “सभी प्रकार की लकड़ी” को शामिल किया गया है। इस प्रकार रबड़ वुड और अन्य प्रकार की जलाने की लकड़ी इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आती है।

थार्डलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

460. लकड़ी की कीमत और आपूर्ति थार्डलैंड सरकार द्वारा विनियमित नहीं की जाती। लकड़ी काटने की मिल या लकड़ी के प्रोसेसिंग संयंत्र से अपशिष्ट के रूप में मिलने वाले बुरादे/लकड़ी के बुरादे का प्रयोग पीयूसी के उत्पादन में किया जाता है। राष्ट्रीय आरक्षित वन अधिनियम, 1964 में 2019 में मंत्रिमंडल के आवश्यक अनुमोदन के बाद संशोधन किया गया था और इसमें ‘प्रतिबंधित लकड़ी’ को पुनः परिभाषित करते हुए इस प्रकार की सभी लकड़ियों को

बाहर कर दिया गया है जो निजी भूमि पर उगाई जाती हैं या सार्वजनिक भूमि पर उगाई जाती हैं। धारा 9 के अनुसार रबड़ वुड या किसी भी प्रकार की जलाने की लकड़ी 'प्रतिबंधित लकड़ी' के अंतर्गत नहीं आती। थाईलैंड सरकार ने लकड़ी की कीमतों पर कोई विनियम लागू नहीं किए हैं।

461. मेट्रो ग्रुप द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि इसने पीयूसी के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले रबड़ वुड को ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जो सरकार से संबंधित नहीं थे या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं थे और इसे निजी भूमि पर उगाया गया था। थाईलैंड में फाइबरबोर्ड निर्माता लकड़ी के लद्दों के अवशेष, बेकार कागज, फाइबर आदि का प्रयोग कर रहे हैं। पैनल प्लस 100% रबड़ वुड का प्रयोग करता है और इसे खुले बाजार से बाजार मूल्य पर खरीदा जाता है। वनचाई ग्रुप द्वारा लकड़ी का कच्चा माल सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों के बीच निर्धारित बाजार मूल्य पर खरीदा जाता है। एग्रो फाइबर और ग्रीन फाइबर मासिक बोली के माध्यम से बाजार की शक्तियों के अनुसार लकड़ी के टुकड़ों (यूकेलिप्टस के टुकड़े, जिसमें छाल भी शामिल है जो 20% से अधिक नहीं होती और आकार 25-40 मिमी का होता है) का प्रयोग करते हैं। वाइजवुड ने रबड़ वुड की आपूर्ति की खरीद घरेलू आपूर्तिकर्ता से की। इसकी कीमतें भी बाजार की शक्तियों के अनुसार हैं और अन्य उद्योगों से भी इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। एलटीएआर कार्यक्रम के लिए सबसिडी का निर्धारण सीवीडी नियमों के अनुलग्नक-IV के अनुसार किया जाना चाहिए।
462. न्यूजीलैंड के आधार पर बेंचमार्क कीमत के प्रयोग पर आपत्ति की जाती है क्योंकि इसे चुनने के कोई कारण नहीं दिए गए हैं। इसमें सभी प्रकार की लकड़ियाँ और लट्टे शामिल हैं, और रबड़ वुड को उल्लिखित श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड सरकार काटे जाने वाले सम्पूर्ण जंगल को नियंत्रित करती है। न्यूजीलैंड से भारत को निर्यात की जाने वाली लकड़ी की कीमत बाजार की कीमतों के अनुसार निर्धारित नहीं की जाती। न्यूजीलैंड की लकड़ी की कीमतों की तुलना रबड़ वुड से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। प्राधिकारी को यूएस में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट – कार्बन स्टील (भारत) के अनुसार बेंचमार्क के चयन के संबंध में प्रश्न पूछने चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक बेंचमार्क भी अपर्याप्त हैं। पर्याप्त पारिश्रमिक, यदि कोई हो, निर्यात करने वाले देश की उस समय की बाजार स्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए न कि किसी तृतीय देश में कच्चे माल की कीमत के आधार पर। बेंचमार्क, प्रावधान से संबंधित देश में उस समय की बाजार स्थितियों के अनुसार होना चाहिए। यूएस – कोटेड पेपर (इंडोनेशिया) पर विश्वास किया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

463. थाईलैंड सरकार थाईलैंड के लगभग संपूर्ण काटे जा सकने वाले वन को नियंत्रित करती है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से लद्दों का प्रयोग करने वाले नीचे के स्तर के उद्योगों के लाभार्थी लद्दों के लिए थाई घरेलू बाजार को खराब हो गया है।
464. आवेदकों ने उल्लेख किया है कि थाईलैंड सरकार राष्ट्रीय आरक्षित वन अधिनियम, 1964 के माध्यम से थाईलैंड के लगभग संपूर्ण काटे जाने योग्य वन को नियंत्रित करती है। इस अधिनियम की धारा 15 में उल्लेख किया गया है कि इन वनों में लकड़ी काटने का कार्य अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। लाभार्थी और लाइसेंसों की वैधता अवधि सहित लाइसेंस जारी करना सक्षम अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। अधिनियम के अनुसार लाइसेंसधारी को प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना होता है। तथापि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार मंत्रालयी विनियमों के माध्यम से समय-समय पर प्रकाशित की जाने वाली यह रॉयल्टी अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित 40 बाट प्रति क्यूबिक मीटर की सीमा से अधिक नहीं हो सकती।
465. यह नोट किया गया है कि संबंधित मंत्रालय द्वारा वसूली जाने वाली रॉयल्टी विवेक पर आधारित है और इसमें बाजार सिद्धांतों को महत्व नहीं दिया जाता। सांविधिक रूप से रॉयल्टी पर ऊपरी सीमा लगाना दर्शाता है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू थाई बाजार में लकड़ी की कीमत को कम करना है। इसलिए लकड़ी, जो फाइबरबोर्ड उद्योग में प्राथमिक कच्चा माल है, अन्वेषणाधीन कंपनियों को बाजार दर से कम दर पर खरीद के लिए उपलब्ध कारबाई जाती है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदक ऐसी इकाइयां होंगी जो या तो सीधे लकड़ी बेचती हैं या उनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में करती हैं। इसलिए कार्यक्रम का कार्यक्रम वास्तव में कम संघया में उद्योगों तक सीमित है।

466. इस कार्यक्रम में पर्यास पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं के रूप में वित्तीय अंशदान प्रदान किया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि लाइसेंस विवेक के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदाता निर्यातकों पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
467. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड सरकार ने दूसरी मौखिक सुनवाई के बाद अपने लिखित वक्तव्य में उल्लेख किया है कि फाइबरबोर्ड निर्माता संदर्भाधीन वस्तुओं के निर्माण के लिए लद्दों के अवशेषों, बेकार कागज, फाइबर आदि का प्रयोग कर रहे हैं। तथापि अतिरिक्त प्रश्नावली के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया है कि निर्यातक पीयूसी के उत्पादन के लिए बुरादे/लकड़ी के बुरादे का प्रयोग कर रहे हैं। तथापि ईक्यूआर में उत्तरदाता निर्यातकों की टिप्पणियाँ और उत्तरदाता निर्यातकों की वेबसाइटों पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चा माल रबड़ वुड, नवीकरणीय रबड़ वुड और यूकेलिप्टस वुड है।
468. सब्सिडी अंतर की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने उचित बेंचमार्क का पता लगाया जिसमें यह पाया गया कि न्यूजीलैंड वैश्विक स्तर पर लद्दों के सबसे बड़े निर्यातकों में से है। प्राधिकारी ने न्यूजीलैंड से भारत में निर्यात किए जाने वाले लद्दों को एक उचित बेंचमार्क माना जो संदर्भाधीन देशों में न्यूजीलैंड की आयात कीमत की तुलना में प्रतिनिधित्व है। जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया है उनके लिए न्यूजीलैंड में लकड़ी के टुकड़ों की घरेलू कीमतों को उचित बेंचमार्क माना गया है। लकड़ी की वास्तविक खरीद दर पर निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के अनुसार विचार किया गया है। उचित रूपांतरण दरों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

कार्यक्रम सं. 12बी: पर्यास पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान

याचिकाकर्ताओं का अनुरोध

469. थाईलैंड सरकार कठिन सामाजिक-आर्थिक स्थितियों वाले क्षेत्रों में स्थापित और किसी संवर्द्धित क्षेत्र में संलग्न तथा विशेषीकृत जोनों या क्षेत्रों में स्थित उद्यमों को भूमि के किराये के भुगतान से छूट/कमी के रूप में भूमि-आधारित प्रोत्साहन भी देती है। इस प्रकार यह कार्यक्रम प्रतिकारी है। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी का विश्लेषण कच्चे माल (लकड़ी) और एलटीएआर में भूमि, दोनों से संबंधित है। प्रकटन विवरण में प्राधिकारी के विश्लेषण में कोई विरोधाभास नहीं है।

थाईलैंड सरकार/अन्य इच्छुक पक्षों की टिप्पणियाँ

470. थाईलैंड सरकार एलटीएआर पर भूमि उपलब्ध नहीं कराती। राज्य की संपत्ति के प्रबंधन, देखरेख, और रखरखाव के लिए कोष विभाग जिम्मेदार है। सरकार मूलभूत अवसंरचना विकसित करने, अवसंरचना में सहयोग करने में निवेश और सेज में प्रचालन के लिए भूमि के आवंटन के लिए सहायक उपाय और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करती है। कोष विभाग निर्धारित मानदंडों के अनुसार सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोनों में भूमि आवंटित करने के लिए नीलामी प्रक्रिया का प्रयोग करता है। अब तक विशेष आर्थिक जोनों के तहत किसी भी स्थान पर कोई व्यावसायिक प्रचालन नहीं है। पीयूसी का कोई भी उत्पादक/निर्यातक सेज या किसी अन्य विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है।
471. मेट्रो ग्रुप द्वारा अधिप्राप की गई भूमि सरकार द्वारा जारी कीमत संबंधी दिशानिर्देश से काफी ऊँची कीमत पर थी। सरकार से कोई भूमि खरीदी या लीज पर नहीं ली गई। पैनल प्लस ग्रुप और वनचाई ग्रुप द्वारा खरीदी गई भूमि सामान्य खरीद कीमत पर है। एग्रो फाइबर, ग्रीन फाइबर, और वाइजवुड्स द्वारा खरीदी गई भूमि सरकार से नहीं ली गई है बल्कि निजी इकाइयों से प्रचलित बाजार कीमतों पर खरीदी गई है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

472. विनिर्माण इकाइयों द्वारा पर्यास पारिश्रमिक से कम पर खरीदी गई भूमि के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाईलैंड सरकार का कोष विभाग 6 प्रान्तों में विशेष आर्थिक विकास जोनों में निवेश करने वाले उद्यमों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराता है। लाभार्थी को थाईलैंड के निवेश बोर्ड द्वारा निर्धारित किराये का भुगतान करना होता है और बाजार सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किराये का भुगतान नहीं करना होता है। इस कार्यक्रम में अन्यथा देय राजस्व को छोड़ने के रूप में वित्तीय अंशदान दिया जाता है और इस प्रकार लाभ प्रदान किया जाता है। यह

कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि यह उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो थाइलैंड सरकार द्वारा निर्धारित विशेष अर्थिक विकास जोनों में निवेश करती हैं। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकारी मानते हैं। तथापि ऐसा कोई भी प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि उत्तरदाता उत्पादकों ने भूमि के किराये में कोई छूट/कमी प्राप्त की है। इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यक्रम सं. 13: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए विद्युत का प्रावधान:

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

473. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि कार्यक्रम राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद (एनईपीसी) और ऊर्जा नियामक आयोग (ईआरसी) द्वारा शासित होता है। ऊर्जा उद्योग अधिनियम, 2007 से शक्ति-प्रदन कार्यक्रम में प्रोविन्सियल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (पीईए) सेवा क्षेत्रों में अवस्थित उद्यमियों के लिए ई.आर.सी. द्वारा प्रारंभ की गई समान मूल्य-निर्धारण नीति के परिणामस्वरूप विद्युत की आपूर्ति करने में अन्तनिहित लागत संबंधी भिन्नता की ई.आर.सी. के द्वारा पूर्णतः उपेक्षा की गई है। अतः टैरिफ निर्धारण करने की प्रक्रिया बाजार सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है तथा विद्युत की घरेलू आपूर्ति को विकृत कर देती है। इस कार्यक्रम में एल.टी.ए.आर. में वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए प्रावधान करने के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है तथा उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट इसलिए है क्योंकि यह कतिपय प्रोत्साहित क्षेत्रों तथा कतिपय क्षेत्रों में अवस्थित उद्यमियों के लिए ही है।

थाइलैंड सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

474. दावा गलत और आधारहीन है। विद्युत की कीमत समान स्वरूप की होती है और इसलिए विशिष्ट नहीं होती है। यह कार्यक्रम एएससीएम के अनुसार अनुदान के रूप में सीमित नहीं है। कोई समतुल्य लाभ नहीं दिया जाता है। यह कार्यक्रम इसलिए भी विशिष्ट नहीं है क्योंकि यह सभी व्यवसायों एवं उद्योगों के लिए उपलब्ध है।
475. पीईए, जो विनिर्माता कम्पनियों के लिए विद्युत का वितरण एवं विक्रय करता है, वह लाभ के आधार पर कार्य कर रहा है तथा एलटीएआर पर विद्युत की व्यवस्था नहीं कर रहा है। राज्य के स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ता अर्थात एफजीएटी, एमईए और पीईए आपूर्ति करने के लिए विशिष्ट अन्तिम प्रयोक्ताओं के साथ द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं।
476. तीनों कम्पनियों द्वारा ली गई दरों के बारे में ईआरसी से अनुमोदित कराना होता है। इसके लिए ईआरसी टैरिफ निर्धारण नीति का अनुपालन करता है। ईआरसी के अनुमोदन के पश्चात् दर प्रकाशित की जाती है।
477. टैरिफ निर्धारण नीति के अनुसार जांच की अवधि के दौरान एक समान टैरिफ नीति का पालन किया जाता है जिसमें स्थान को ध्यान में न रखते हुए समान दर का प्रावधान है। एमईए और पीईए के लिए उसी मूल्य थोक टैरिफ ढांचे का पालन किया जाता है। एमईए और पीईए द्वारा प्रभारित खुदरा टैरिफ वही होते हैं, इसके लिए स्थान अथवा क्षेत्र को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
478. प्रभारित कीमतों में सरकार की प्रचालन लागतें शामिल होती हैं और उचित लाभ सुनिश्चित होता है।
479. विद्युत टैरिफ में आधार टैरिफ (विद्युत संयंत्रों, पारेषण और वितरण लाइनों आदि में लागत समेत निवेश लागत), ऑटोमैटिक टैरिफ समायोजन तंत्र (ईथन की लागत और विद्युत की क्रय लागत) और वैट शामिल होता है।
480. मैट्रो ग्रुप, पैनल प्लस ग्रुप और वानाभाई ग्रुप द्वारा पीईए से उनके अनुरोध के अनुसार विद्युत की खरीद की जाती है और न कि अर्थिक सहायता देकर दर से खरीदी जाती है। व्यस्ततम अवधि प्रभारों, अव्यस्ततम प्रभारों, मांग प्रभारों आदि के बारे में विचार करने के उपरान्त पीईए के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। कम्पनी के स्वरूप, सेवा की प्रकृति और उपयोग अवधि पर टैरिफ निर्भर करता है।
481. इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग के द्वारा जिस बैंचमार्क पर भरोसा किया है, वह गलत है क्योंकि इसने पीईए द्वारा जारी की गई अव्यवस्ततम घंटे की दरों पर ही विचार किया है एवं सभी अतिरिक्त दरों की इसने उपेक्षा की है। चूंकि थाइलैंड के प्रान्तीय क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करने के लिए पीईए चूंकि केवल नियामक प्राधिकरण है, इसलिए कोई अन्य बैंचमार्क नहीं हो सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

482. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऊर्जा उद्योग अधिनियम, 2007 के तहत थाइलैंड में विद्युत की आपूर्ति मैट्रापोलिटन एनर्जी अथॉरिटीज (एमईए) और प्रोविन्सियल एनर्जी अथॉरिटीज (पीईए) द्वारा की जाती है तथा ऊर्जा नियामक आयोग (ईआरसी) द्वारा विनियमित की जाती है। थाइलैंड में विद्युत की आपूर्ति करने के लिए ईआरसी ने समान टैरिफ नीति आरंभ की है। यद्यपि, ईआरसी द्वारा टैरिफ का निर्धारण करते समय समस्त निहित लागतों को सांविधिक रूप से ध्यान में रखना होता है, परन्तु ईआरसी ने महानगरीय एवं प्रान्तीय क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करने में अन्तर्निहित लागत संबंधी भिन्नता की उपेक्षा की है। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टैरिफ निर्धारण करने की प्रक्रिया बाजार सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है और विद्युत की घरेलू आपूर्ति को विकृत कर देती है। इस कार्यक्रम में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। प्राधिकारी नोट करता है कि कोई समान टैरिफ नहीं है और टैरिफ इकाई के प्रकार पर निर्भर करता है और इसलिए कार्यक्रम विशिष्ट है। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को समतुल्य रूप में मानते हैं। अतः प्राधिकारी ने नीचे सारणी में प्रत्युत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों के प्रति उक्त स्कीम के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया है।

एडवांस फाइबर कं. लि.

483. एडवांस फाइबर कं. लि., थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। एडवांस फाइबर ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा ली गई अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
484. प्राधिकारी ने एडवांस फाइबर द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि एल.टी.ए.आर. में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने के परिणामस्वरूप अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का एडवांस फाइबर द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप, एडवांस फाइबर को विभिन्न राज-सहायताओं के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।
485. प्राधिकारी ने एडवांस फाइबर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कही प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी, वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
486. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत राज-सहायता मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 1	मशीनरी के आयात शुल्कों पर छूट/कमी	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कञ्च माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	0-10

मैट्रो एमडीएफ कं. लि.

487. मैट्रो एमडीएफ कं. लि., थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। मैट्रो ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा लिए गए अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
488. प्राधिकारी ने मैट्रो द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। मैट्रो ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह प्रकट किया है कि इसने कारपोरेट आयकर पर छूट ले ली है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि एलटीएआर. में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने के परिणामस्वरूप अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का मैट्रो द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप, मैट्रो के लिए विभिन्न अनुदानों के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।

489. प्राधिकारी ने मैट्रो द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी, वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
490. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत राज-सहायता मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सम्बिंदी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 4	बीओआई के लिए कारपोरेट आयकर की छूट	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	0-10
		कुल राजसहायता	***%	0-10

वाइजवुड्स कं. लि.

491. वाइजवुड्स कं. लि., थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। वाइजवुड्स ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा ली गई अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
492. प्राधिकारी ने वाइजवुड्स द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। वाइजवुड्स ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह प्रकट किया है कि इसने मशीनरी पर आयात-शुल्क तथा कारपोरेट आयकर पर छूट ले ली है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि एलटीएआर में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने के परिणामस्वरूप अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का वाइजवुड्स द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप, वाइजवुड्स को विभिन्न अनुदान के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।
493. प्राधिकारी ने वाइजवुड्स द्वारा उपलब्ध कायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
494. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत राज-सहायता मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सम्बिंदी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 1	मशीनरी के आयात शुल्कों पर छूट/कमी	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 4	बीओआई के लिए कारपोरेट आयकर की छूट	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	10-20

ग्रीन फाइबर कं. लि.

495. ग्रीन फाइबर कं. लि., थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। ग्रीन फाइबर ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा लिए गए अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
496. प्राधिकारी ने ग्रीन फाइबर द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि कारपोरेट आयकर अधिमान्य ऋणों की छूट तथा एलटीएआर में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने के परिणामस्वरूप अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का ग्रीन फाइबर द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप, ग्रीन फाइबर को विभिन्न अनुदान के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।
497. प्राधिकारी ने ग्रीन फाइबर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
498. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत अनुदान मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सभिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 4	बीओआई के लिए कारपोरेट आयकर की छूट	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कम्बे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	10-20
3	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	0-10
4	अन्य राजस्वायताएं	ऋण	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	10-20

एग्रो फाइबर कं. लि.

499. एग्रो फाइबर कं. लि., थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। एग्रो फाइबर ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा लिए गए अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
500. प्राधिकारी ने एग्रो फाइबर द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। एग्रो फाइबर ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह बताया है कि उन्होंने किसी समतुल्य अनुदान का लाभ नहीं लिया है। तथापि प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि अधिमान्यतः ऋणों में परिणामतः अनुदान कार्यक्रमों तथा एलटीएआर में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने का एग्रो फाइबर द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप, एग्रो फाइबर को विभिन्न अनुदानों के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।
501. प्राधिकारी ने एग्रो फाइबर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी, वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
502. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत अनुदान मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	0-10
3	अन्य अनुदान	ऋण	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	10-20

पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि.

503. पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि., थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। पैनल प्लस एमडीएफ ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा ली गई अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
504. प्राधिकारी ने पैनल प्लस एमडीएफ द्वारा दायर किए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि अधिमान्यतः ऋणों तथा एलटीएआर में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने के परिणामस्वरूप अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का पैनल प्लस एमडीएफ द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप पैनल प्लस एमडीएफ को विभिन्न राजसंघायताओं के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।
505. प्राधिकारी ने पैनल प्लस एमडीएफ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी, वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
506. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत अनुदान मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	0-10
3	अन्य अनुदान	ऋण	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	10-20

पैनल प्लस कं. लि.

507. पैनल प्लस कं. लि., थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। पैनल प्लस एमडीएफ ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा ली गई अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
508. प्राधिकारी ने पैनल प्लस कं. द्वारा दायर किए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। पैनल प्लस कं. लि. ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह प्रकट किया था कि कोई भी अनुदान कार्यक्रम उनके लिए लागू नहीं है क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं करती हैं। तथापि, पैनल प्लस कं. इसके संबद्ध पक्षकार से फाइबर बोर्ड खरीदती है, उनका लेमीनेशन करती है तथा उस उत्पाद की बिक्री करती है। यह नोट किया है कि लेमीनेटेड फाइबर बोर्ड विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्रमों में आते हैं। अतः प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि अधिमान्यतः ऋणों के परिणामस्वरूप अनुदान कार्यक्रमों एवं एलटीएआर में लकड़ी के लिए प्रावधान का पैनल प्लस कं. द्वारा लाभ लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप पैनल प्लस कं. को विभिन्न अनुदानों के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।

509. प्राधिकारी ने पैनल प्लस कं. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी, वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

510. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत राज-सहायता मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सम्बिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	0-10
2	अन्य अनुदान	ऋण	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	0-10

वानाचाई ग्रुप पब्लिक कं. लि.

511. वानाचाई ग्रुप पब्लिक कं. लि., शाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। एडवांस फाइबर ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा ली गई अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।

512. प्राधिकारी ने वानाचाई ग्रुप द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को सत्यापित भी किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि कारपोरेट आयकर की छूट, अधिमान्यतः ऋणों एल.टी.ए.आर. में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने के परिणामस्वरूप अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का वानाचाई ग्रुप द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप, वानाचाई ग्रुप को विभिन्न अनुदानों के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।

513. प्राधिकारी ने वानाचाई ग्रुप द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी, वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

514. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत राज-सहायता मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सम्बिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 4	बीओआई के लिए कारपोरेट आयकर की छूट	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	10-20
3	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	0-10
4	अन्य अनुदान	ऋण	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	10-20

वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि.

515. वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि., शाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। एडवांस फाइबर ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा लिए गए अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।

516. प्राधिकारी ने वानाचाई पैनल द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर की जांच की और जांच करने के बाद उनसे और सूचना देने के लिए अनुरोध किया तथा यथा आवश्यक समझी गई सीमा तक प्रत्युत्तर में उपलब्ध करायी सूचना को

सत्यापित भी किया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि अधिमान्यतः ऋणों तथा एलटीएआर में लकड़ी और बिजली के लिए प्रावधान करने के परिणामस्वरूप अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का वानाचाई पैनल द्वारा लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप वानाचाई पैनल को विभिन्न अनुदानों के रूप में लाभ प्रदान किया गया था।

517. प्राधिकारी ने वानाचाई पैनल द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना की जांच की है और उन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मार्जिन का निर्धारण किया जिनके लिए जांच की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त अथवा उपार्जित किए गए थे। निर्यातक द्वारा जहां कहीं प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई थी, वहां पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।
518. नीचे दी गई सारणी में अनुदान कार्यक्रमों के नाम तथा संगत अनुदान मार्जिनों के बारे में बताया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	10-20
2	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली के लिए प्रावधान	***%	0-10
3	अन्य अनुदान	ऋण	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	10-20

एस. किजचाई एंटरप्राइज

519. एस.किजचाई एंटरप्राइज, थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। किजचाई ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और उनके द्वारा ली गई अनुदान के कार्यक्रमों के बारे में सूचना उपलब्ध करायी गई।
520. हालांकि, यह नोट किया जाता है कि एस किजचाई इंटरप्राइज प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए अगोपनीय पाठ के रूप में गोपनीय अनुरोधों का एक सार्थक सारांश उपलब्ध कराने में असफल रहा है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रकार के सीमित अनुरोध से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपर्युक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में सार्थक टिप्पणियां करने के लिए अवसर बाधित हुआ है। इस कारण से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि उपर्युक्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को अस्वीकार किया जाए। तदनुसार, कोई अलग-अलग सब्सिडी मार्जिन की दर का निर्धारण एस.किजचाई एंटरप्राइज के लिए नहीं किया जा सकता है। थाईलैंड से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन एस.किजचाई एंटरप्राइज के लिए लागू किया जा रहा है।
521. थाइलैंड से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। थाइलैंड से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए समतुल्य शुल्क का उपलब्ध तथ्यों और संबंधित कार्यक्रम की समतुल्य क्षमता के आधार पर निर्धारण किया गया है। अनुदान मार्जिन नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

क्र.सं.	कार्यक्रम सं.	स्कीमों का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज %
1	कार्यक्रम सं. 1	मशीनरी पर आयात शुल्क की छूट/कमी	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं. 4	बीओआई के लिए कारपोरेट आयकर की छूट	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं. 12क	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्चे माल (लकड़ी) के लिए प्रावधान	***%	10-20
4	कार्यक्रम सं. 13	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर विद्युत के लिए प्रावधान	***%	10-20
5	अन्य अनुदान	ऋण	***%	0-10
		कुल अनुदान	***%	20-30

वियतनाम

(I) कार्यक्रम सं. 1: वस्तुओं का निर्यात करने के लिए कच्चे माल के आयातों पर

आयात शुल्क छूट:

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

522. याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन किया है कि उक्त कार्यक्रम जनरल डिपार्टमेंट ऑफ वियतनाम कस्टम्स (जीडीबीसी) द्वारा शासित होता है। दि लॉ ऑफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट झूटी, 2016, डिक्री सं. 134/2016/एनडी-सीपी, डिक्री सं. 8/2015/एनडी-सीपी, और परिपत्र सं. 38/2015/टी.टी.-बीटीसी, निर्यातों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लायी गई वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए आयात शुल्क के भुगतान पर छूट प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में, जो अन्यथा देय होता है, वित्तीय योगदान देने का प्रावधान होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों पर आश्रित होता है।
523. इस कार्यक्रम की इण्डोनेशिया से “कन्टीन्यूयस कास्ट कॉपर वायर राइस” के आयातों के बारे में अनुदानरोधी जांच के अन्तिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा पहले जांच की गई थी और यह समतुल्य योग्य पाया गया था।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

524. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया था कि यह उत्पादन का निर्यात करने के लिए प्रयोग में लाए गए आयातित कच्चे-माल के छूट की नीति को जारी रखता है। इस नीति को लॉ ऑन एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट झूटी द्वारा विनियमित किया जाता है और पूरे देश में हर किस्म और स्वरूप के व्यापार के लिए लागू होती है।
525. छूट की राशि निर्यात किए गए तैयार माल के उत्पादन में वास्तव में प्रयोग में लायी गई आयातित सामग्री के मूल्य के बराबर शुल्क राशि के बराबर होती है। इस राशि के बारे में डिक्री 08/2015/एनडी-सीपी और परिपत्र 38/2015/टीटी-बीटीसी के अनुसार आयातित कच्चे माल का उपयोग करने पर सीमा-शुल्क की सूचना देते समय निर्धारण अथवा घोषणा की जाती है। यद्यपि, वियतनाम से जांचाधीन कई कम्पनियों ने मलेशिया, चीन, थाइलैण्ड, भारत और कोरिया सहित कई देशों से कच्चे माल का आयात किया था, परन्तु चीन -एशिया मुक्त व्यापार समझौते तथा एशिया - भारत मुक्त व्यापार समझौते के अनुसार कोई शुल्क देय नहीं था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

526. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम लॉ ऑन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट झूटी, 2016, डिक्री 8/2015/एनडी-सीपी और परिपत्र 38/2015/टीटी-बीटीसी के अधीन शासित होता है। इस कार्यक्रम में निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर आयात-शुल्क पर छूट का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। अनुदान कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों पर आश्रित होता है। इसलिए प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम को समतुल्य माना है।
527. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तरों में यह बताया है कि उन्होंने कोई कच्चा माल या तो आयात नहीं किया है अथवा ऐसे किसी एफटीए के तहत उनका आयात किया है, जहां पर देय शुल्क शून्य हो। यह नोट किया जाता है कि किसी भी सहकारी उत्पादक/निर्यातक ने कोई लाभ नहीं लिया है, अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों पर कोई भी समतुल्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(ii) कार्यक्रम सं. 2: नॉन टैरिफ जोन में आयातित कच्चे माल पर आयात शुल्क की छूट:

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

528. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि उक्त कार्यक्रम जनरल डिपार्टमेंट ऑफ वियतनाम कस्टम्स (जीडीबीसी) द्वारा शासित होता है। प्रधानमंत्री के निर्णयों से स्थापित नॉन टैरिफ जोनों में कच्चे माल के आयात पर लगाए गए आयात शुल्क के भुगतान पर दि लॉ ऑफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट झूटी, 2016 छूट प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में, जो अन्यथा देय होता है, वित्तीय योगदान देने का प्रावधान होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों पर आश्रित होता है।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

529. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया कि दि लॉ ऑन एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट ब्यूटी के अनुच्छेद 16 के अनुसार आयातित कच्चे माल अथवा संघटकों का उपयोग किए बिना किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्मित संसाधित, रिसाइकल्ड, एसेम्बल किए गए माल पर लगाए गए आयात शुल्क की छूट उस स्थिति में होगी जब उनका घरेलू बाजार में आयात किया जाता है। यह भी अनुरोध किया है कि वियतनाम से जांचाधीन कोई भी कम्पनी नॉन टैरिफ क्षेत्रों में अवस्थित नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

530. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम लॉ ऑन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ब्यूटी 2016 के तहत शासित होता है। इस कार्यक्रम में किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्मित संसाधित, रिसाइकल्ड, एसेम्बल किए गए माल पर लगाए गए आयात शुल्क की छूट उस स्थिति में होगी जब उनका घरेलू बाजार में आयात किया जाता है। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय योगदान का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। अनुदान कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह नॉन-टैरिफ क्षेत्रों में अवस्थित उद्यमों के लिए उपलब्ध है। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को समतुल्य योग्य मानते हैं।
531. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तरों में यह बताया है कि उन्होंने कोई कच्चा माल या तो आयात नहीं किया है अथवा ऐसे किसी एफटीए के तहत उनका आयात किया है, जहां पर देय शुल्क शून्य हो। यह नोट किया जाता है कि किसी भी सहकारी उत्पादक/निर्यातक ने कोई लाभ नहीं लिया है, अतः यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवादी निर्यातकों/उत्पादकों पर कोई भी समतुल्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(iii) कार्यक्रम सं. 3: औद्योगिक क्षेत्रों में कम्पनियों के लिए फुटकर पुर्जे एवं उपकरणों के आयातों पर आयात शुल्क की छूट

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

532. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि उक्त कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ वियतनाम कस्टम्स (जीडीवीसी) द्वारा शासित होता है। दि लॉ ऑफ इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ब्यूटी, 2016, लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट सं. 67/2014/क्यूएच13, डिक्री सं. 134/2016/एनडी/सीपी और डिक्री सं. 118/2015/एनडी-सीपी के परिशिष्ट। और || में निवेश अधिमान्य एवं भौगोलिक क्षेत्रों के अध्यधीन कम्पनियों के लिए परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वस्तुओं के आयात पर लगाए गए आयात शुल्क के भुगतान पर छूट है। इन आयातित वस्तुओं में ये शामिल हैं- मशीनरी और उपस्कर, संघटक, पुर्जे, मशीनरी एवं उपस्करों के फुटकर पुर्जे, विनिर्माण परियोजना के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लायी गई प्रौद्योगिकी में विशिष्ट उपयोग वाहन और भवन सामग्रियां, जिनका घरेलू स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है, जो अन्यथा देय होता है औनर उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल उन्हीं कम्पनियों के लिए ही उपलब्ध है जो अधिमान्य निवेश कार्यकलापों में लगी हों और लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट सं. 67/2014/क्यूएच 13 के तहत अभिज्ञात क्षेत्रों/जोनों में अवस्थित हैं।
533. एफएससी कारपोरेशन और किम टिन ने एयूएल अवधि के दौरान क्षमताओं में विस्तार किया है अथवा नए संयंत्रों की अभिवृद्धि की है। अतः उनको पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क छूट देते हुए कार्यक्रम का लाभ लेना चाहिए।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

534. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया कि आयात शुल्क छूट औद्योगिक क्षेत्रों में कम्पनियों तक सीमित नहीं है। तथापि, निवेश अधिमान्य के अध्यधीन स्थिर परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपस्कर और मशीनरी के आयात पर आयात शुल्क की सामान्य छूट होती है। डिक्री 118/2015/एनडी-सीपी के परिशिष्ट। में पात्र क्षेत्रों की पहचान की जाती है और परिशिष्ट || में निवेश अधिमान्य हेतु पात्र भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की जाती है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें किसी मामले में कार्यक्रमों का लाभ लेने का अधिदेश हो।

535. कोई भी समतुल्यनीय लाभ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है क्योंकि प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए आयात एफटीए के अधीन होते हैं और देय आयात शुल्क शून्य होता है। अतः ऐसे आयातों के लिए सरकार द्वारा कोई राजस्व छोड़ा नहीं जाता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

536. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ वियतनाम कस्टम्स (जीडीवीसी) द्वारा शासित होता है। इस कार्यक्रम के तहत, स्थिर परिसम्पत्तियों का सूजन करने के लिए उपस्कर और मशीनरी के आयात पर लगाये गए आयात शुल्क पर छूट प्रदान की जाती है। यह छूट डिक्री 118/2015/एनडी-सीपी के परिशिष्ट I के अन्तर्गत सूचीबद्ध पात्रों तथा डिक्री 118/2015/एनडी-सीपी के परिशिष्ट II के अन्तर्गत सूचीबद्ध पात्र निवेश कार्यक्रमों को प्रदान की जाती है।
537. इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है, जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है, क्योंकि यह केवल उन्हीं कम्पनियों के लिए उपलब्ध है जो पात्र क्षेत्रों में लगी हुई हैं और सरकार की निवेश संबंधी अधिमान्यताओं के अध्यधीन हैं। इसलिए, प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकारिता के रूप में मानते हैं।
538. मै. एमडीएफ वीआरजी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रश्नावली प्रत्युत्तर यह देशीता है कि उनके द्वारा इस अनुदान कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त किया जाता है और इसलिए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अनुदान कार्यक्रम के प्रति मै. एमडीएफ वीआरजी पर प्रतिकारिता शुल्क लगाया जाना चाहिए।
539. मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह बताया है कि उन्होंने कोई फुटकर पुर्जा एवं उपकरण आयात नहीं किया है। अतः यह नोट किया जाता है कि किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. लि. द्वारा कोई लाभ नहीं लिया गया था और यह नोट किया जाता है कि इस कार्यक्रम के तहत उन पर कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

(iv) कार्यक्रम सं. 4: कारपोरेट आयकर में कमी:

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

540. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम अस्थायी कर विभागों से शासित होता है। लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट सं. 67/2014/क्यूएच 13, लॉ ऑफ एन्टरप्राइज आयकर सं. 14/2008/क्यूएच 12 और डिक्री सं. 124/2008/एनडी-सीपी और डिक्री सं. 12/2015/एनडी-सीपी में सूची “क” अथवा डिक्री सं. 164/2003/एनडी-सीपी के परिशिष्ट में अभिज्ञात अथवा डिक्री सं. 8/2006/एनडी-सीपी के तहत अभिज्ञात किसी भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित किसी निवेश परियोजना के कार्यान्वयन की एक निश्चित अवधि अथवा संपूर्ण अवधि के लिए कारपोरेट आयकर के भुगतान में कमी अथवा छूट प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है, जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है, क्योंकि यह केवल उन्हीं कम्पनियों के लिए उपलब्ध है, जो निवेश परियोजनाओं में लगी हुई हैं अथवा प्रासंगिक कानूनों के तहत सूचीबद्ध भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित हैं।
541. इस कार्यक्रम की इण्डोनेशिया से “कन्टीन्यूयस कास्ट कॉपर वायर राइस” के आयातों के बारे में राजसहायता’रोधी जांच के अन्तिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा पहले जांच की गई थी और यह प्रतिसंतलनीय योग्य पाया गया था।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

542. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया था कि वर्ष 2009 से कारपोरेट आयकर के विधिक प्रावधान लॉ ऑन एन्टरप्राइज इनकम टैक्स सं. 14/2008/क्यूएच-12 में दिए हैं तथा इनके कार्यान्वयन का ब्यौरा डिक्री सं. 124/2008/एनडी-सीपी (उसी आवेदन के साथ डिक्री सं. 218/2013/एनडी-सीपी से बदल कर) दिया है। डिक्री के अनुच्छेद 15 के तहत 10 प्रतिशत की दर अनुच्छेद 15.1 (क) के अन्तर्गत अभिज्ञात भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्यमों के लिए 15 वर्षों के लिए तथा 20 प्रतिशत की दर अनुच्छेद 15.4 के तहत अभिज्ञात भौगोलिक क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्यमों के लिए 10 वर्षों के लिए लागू हैं। इसके अलावा, अनुच्छेद 16 में कर छूट और कमी के बारे में निम्नानुसार प्रावधान होता है:-

- (1) सामाजिक व्यवस्था वाले क्षेत्रों के (2) विशेष कठिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों में अथवा अनुच्छेद 16.2 के तहत सूचीबद्ध भौगोलिक क्षेत्रों में अवस्थित नए-नए स्थापित उद्यमों के लिए 4 वर्षों के लिए कर की छूट और अगले 9 वर्षों के लिए देय आयकर में 50 प्रतिशत की कमी।
- (1) सामाजिक व्यवस्था वाले क्षेत्रों के (2) विशेष कठिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों में अथवा अनुच्छेद 16.2 के तहत सूचीबद्ध भौगोलिक क्षेत्रों में अवस्थित नए-नए स्थापित उद्यमों के लिए 4 वर्षों के लिए कर की छूट और अगले 5 वर्षों के लिए देय आयकर में 50 प्रतिशत की कमी।
- अनुच्छेद 16.3 के तहत सूचीबद्ध भौगोलिक क्षेत्रों में नए-नए स्थापित किए गए उद्यमों के लिए 2 वर्षों के लिए कर में छूट और अगले 4 वर्षों के लिए देय आयकर में 50 प्रतिशत कमी।

543. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने यह अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम न तो वर्जित है और न ही विशिष्ट है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

544. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत कारपोरेट आयकर के भुगतान को कम किया अथवा छूट दी जाती है। कमी/छूट देने की अवधि और सीमा भौगोलिक स्थल और किए गए निवेश के अध्यधीन होती है। जबकि डिक्री 124/2008/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 15 में नए-नए स्थापित/हाई-टैक उद्यमों के भौगोलिक स्थल पर निर्भर करते हुए अधिमान्य आयकर दर प्रदान की जाती है, पर डिक्री 124/2008/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 16 में भी नए-नए स्थापित उद्यम के भौगोलिक स्थल पर निर्भर करते हुए आयकर में छूट/कमी प्रदान की जाती है। पात्र भौगोलिक क्षेत्रों को विशेष रूप से कठिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में डिक्री के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए किसी आवेदन अथवा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि इसमें उन कम्पनियों के लिए प्रावधान किया जाता है जो यथा सूचीबद्ध निर्दिष्ट क्षेत्रों/जोनों में अवस्थित होते हैं तथा निवेश देते हैं। इसलिए प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि इस कार्यक्रम को समतुल्य योग्य माना जाना चाहिए।
545. मै. एमडीएफ वीआरजी ब्रांग ट्री बुड ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह प्रकट किया है कि इसका एक संयंत्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ का दावा करने के लिए पात्र है, परन्तु कोई लाभ नहीं लिया था। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड यह प्रकट करते हैं कि उनके द्वारा रियायती आयकर का भुगतान किया गया था। किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तर से यह नोट भी किया है कि कम्पनी ने इस अनुदान कार्यक्रम के तहत लाभ लिया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों पर प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
546. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने अनुदान मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है। निर्धारित अनुदान मार्जिन नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है।

(v) कार्यक्रम सं. 5: आयात की छूट अथवा कमी

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध

547. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम, वियतनाम सरकार द्वारा शासित होती है। लॉ संख्या 67/2015/क्यूएच 13 और लॉ ऑफ इन्वेस्टमेंट सं. 67/2014/क्यूएच.13 के अनुच्छेद 15 से स्थिर परिसम्पत्तियों, कच्चे माल, आपूर्तियों और फुटकर पुर्जों के आयातों पर लगाए गए आयात-शुल्क के भुगतान में कमी अथवा छूट प्रदान की जाती है। यह लाभ इन निवेश परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं (i) लॉ के अनुच्छेद 16 के खण्ड 1 के तहत सूचीबद्ध हैं अथवा (ii) कम से कम वीएनडी 6,000 बिलियन के निवेश उनके पास हों; (iii) लॉ के अनुच्छेद 16 के खण्ड 2 के तहत सूचीबद्ध प्रशासनिक प्रभागों में अवस्थित हों अथवा (iv) कम से कम 500 कामगारों को नियोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हों अथवा (v) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगे हुए हों। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। क्योंकि यह केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो परियोजना कार्यों में लगी हों अथवा संगत कानूनों के तहत सूचीबद्ध भौगोलिक क्षेत्रों में अवस्थित हों।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

548. मै. एमडीएफ वीजीआर क्लांग ट्री वुड ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी ने यह अनुरोध किया कि मुक्त व्यापार समझौतों के तहत शुल्क छूट नॉन-काउन्टरएवल होती है जैसाकि थाइलैंड से “साइट्रिक एसिड और कतिपय साइट्रिक साल्ट” के आयातों पर राजसहायता-रोधी जांच में अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा निर्णय किया था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

549. प्राधिकारी ने उन कार्यक्रमों के बारे में पहले ही यह निर्धारण किया है कि आयात शुल्क पर छूट/कमी समतुल्य शुल्कों के अध्यधीन होनी चाहिए। इसलिए, यह नोट किया जाता है कि इस अनुदान कार्यक्रम के प्रति कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
550. मै. एमडीएन वीआरजी ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह बताया कि कम्पनी द्वारा किए गए आयात शुल्क मुक्त थे, मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह अनुरोध किया है कि इस कार्यक्रम के तहत किसी लाभ का दावा नहीं किया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के तहत किसी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक पर प्रतिकारी शुल्क न लगाने का निर्णय लिया गया है।

(vi) कार्यक्रम सं. 6: भूमि और पानी किराए की छूट और कमी

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

551. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम स्थानीय कर प्राधिकारियों द्वारा शासित होता है। वियतनाम में भूमि पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में है। वैलिड पाइप और ट्रॉब्स तथा कन्टीन्यूयस कॉस्ट कॉपर वायर राइस के बारे में हुए अन्तिम जांच परिणाम विश्वसनीय हैं। लॉ ऑन लैण्ड सं. 3/2003/क्यूएच-II, लॉ ऑन लैण्ड सं. 45/2013/क्यूएच-13 तथा डिक्री सं. 46/2014/एनडी-सीपी के द्वारा भूमि और पानी सस्ती दरों पर प्रदान किया जाता है तथा बाद में इसकी कम अथवा छूट दी जाती है। लाभ उन उद्यमों के लिए उपलब्ध होता है जो (i) कठिन सामाजिक – आर्थिक परिस्थितियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों/जोनों में अवस्थित होते हैं अथवा (ii) विशेष मामलों अथवा उत्साहित उद्योगों में निवेश परियोजनाओं में लगे होते हैं। इस कार्यक्रम में छोड़ दिए गए राजस्व के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है जो अन्यथा देय होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल उन कम्पनियों के लिए उपलब्ध है, जो परियोजना कार्यों में लगी हों अथवा संगत कानूनों के तहत सूचीबद्ध भौगोलिक क्षेत्रों में अवस्थित हों।
552. कार्यक्रम की इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से “कन्टीन्यूयस कॉस्ट कॉपर वायर राइस” के आयातों पर सभिंडी-रोधी जांच के अन्तिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा पहले भी जांच की गई थी और वे समतुल्य शुल्क योग्य पाए गए थे।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

553. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया कि यह उन कम्पनियों के लिए भूमि किराए की छूट तथा कमी करने की नीति को जारी रखती है जिनकी विशेष तौर पर कठिन सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश परियोजनाएँ हैं, जिससे ऐसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया जा सके। यह गरीब कामगारों के लिए आवास निर्माण जैसे विशेष मामलों में तथा प्रोत्साहित उद्योगों में निवेश परियोजनाओं के लिए भी लागू होती है। ऐसे प्रोत्साहित भौगोलिक क्षेत्र, प्रोत्साहित उद्योग तथा विशेष मामले डिक्री सं. 46/2014/एनडी-सीपी के तहत विनिर्दिष्ट हैं। यह कार्यक्रम निर्यात निष्पादन अथवा घरेलू आयातित वस्तुओं पर आश्रित नहीं है।
554. किम टिन पट्टे वाली भूमि का उपयोग करता है, जिसके किराए का पूर्ण भुगतान जांच की अवधि के दौरान कर दिया गया है। यह कम्पनी के पास भूमि के 4 कब्जे हैं तथा प्रत्येक के किराए का भुगतान डिसीजन ऑफ दि पीपल्स कमेटी ऑफ बिडन फाउक प्रोविन्स के द्वारा निर्धारित किए अनुसार कर दिया गया था। चूंकि किम टिन विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए शुष्क प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, इसलिए पानी का प्रयोग नगण्य होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए भू-जल संसाधनों से पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर, एमडीएफ वीआरजी द्वारा पट्टे की भूमि का उपयोग किया जाता है और क्लांग ट्री इरीगेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बन मेम्बर लि. कम्पनी से पानी खरीदा गया था जो एक औद्योगिक पानी का आपूर्तिकर्ता और सामान्य सेवा उद्यम

तथा डांग हा क्लीन वाटर एन्टरप्राइजेज है। जल प्रभारों की छूट की कोई स्कीम नहीं है। एमडीएफ वीआरजी ड्रांग ट्री वुड ज्वाइंट स्टॉक कं. ने यह अनुरोध किया कि यह कार्यक्रम न तो वर्जित है और न ही विशेष है। इसके लिए प्रतिवादी उत्पादकों के द्वारा कोई अनुदान नहीं लील गई थी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

555. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कार्यक्रम लॉ ऑन लैण्ड सं. 3/2003/क्यूएच-II, डिक्री 142/2005/एनडी-सीपी, दिनांक 14 नवम्बर, 2005, लॉ ऑन लैण्ड सं. 45/2013/क्यूएच-13, और डिक्री सं. 46/2014/एनडी-सीपी से शासित होता है। उन कम्पनियों को भूमि और किराए में छूट अथवा कमी की सुविधा दी जाती है जिन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों अथवा निर्दिष्ट क्षेत्रों/जोनों में निवेश किया अथवा वहां पर अवस्थित हैं जो डिक्री 46/2014/एनडी-सीपी के अनुसार हैं।
556. प्राधिकारी ने जीओवी और प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों से भूमि और जल वितरण तंत्र के बारे में और सूचना मांगी थी, जिसके द्वारा यह बताया गया था कि.....
557. एमडीएफ वीआरजी ने यह अनुरोध किया है कि कम्पनी के पास पट्टे की जमीन है और भूमि किराए के भुगतान संबंधी कुछ छूट का ब्यौरा संबंधित कार्यक्रम के तहत ईक्यूआर में पहले ही उपलब्ध करा दिया है। कम्पनी ने यह भी बताया है कि इसने जांच की अवधि का पानी किराए का भुगतान कर दिया है और अन्य सभी अवधियों का भी भुगतान कर दिया है तथा ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें जल प्रभारों के बारे में छूट हो। जल किराए पर दावा करने का कोई आधार नहीं है। पानी के बिनों का भुगतान संबंधी ब्यौरा एक अलग अनुबंध के रूप में ईक्यूआर के साथ उपलब्ध करा दिया गया है।
558. किम टिन ने प्रत्युत्तर दिया है कि इसके पास पट्टे पर भूमि है और कम्पनी ने जांच की अवधि के दौरान पूरे किराए का भुगतान कर दिया है। ऐसे भुगतान का ब्यौरा तथा विगत में भूमि किराया भुगतान पर कुछ छूट संबंधी ब्यौरा संबंधित कार्यक्रम 6 के तहत ईक्यूआर में पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है जिसका वर्तमान जांच में कोई औचित्य नहीं है। किम टिन एमडीएफ जेएससी द्वारा उपयोग में लायी गई जमीन 4 कब्जों की मार्फत ली है तथा प्रत्येक कब्जे के लिए भूमि का किराया अलग-अलग है। ऐसे किराये डिसीजन ऑफ दि पीपल्स कमेटी ऑफ बिन्ह फाओक प्रोविन्स पर आधारित हैं।
559. किम टिन का पानी की अनुदान के बारे में आरोप है। संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने में कम्पनी शुष्क प्रक्रिया को अपनाती है और संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने में पानी का उपयोग शून्य अथवा नगण्य होता है। यहां तक कि परिसर में सामान्य प्रयोजनों के लिए पानी उपयोग अपने भू-जल संसाधनों से होता है तथा यह सरकार के किसी छूट कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आता है।
560. मै. एमडीएफ वीआरजी ड्रांग ट्री वुड ज्वाइंट स्टॉक कं. द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तर से यह नजर आता है कि कंपनी इस अनुदान कार्यक्रम के तहत भूमि किराए पर कमी का लाभ ले रही है। तथापि, पानी किराए के बारे में ऐसी छूट का दावा नहीं किया गया था। मै. किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कं. ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर में यह बताया है कि जांच की अवधि के दौरान उनकी पानी की खपत नगण्य/शून्य है और जांच की अवधि के दौरान भूमि किराए में कमी/छूट नहीं ली गई थी। तथापि, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि उनके द्वारा रियायती दर से भूमि के किराए का भुगतान कर दिया गया था।
561. वियतनाम में भूमि के प्राइवेट स्वामित्व की अनुमति नहीं है तथा प्रशासक के रूप में सरकार के सभी स्वामित्व अधिकार जनता के होते हैं। तथापि, वियतनाम के कानून भूमि का उपयोग करने के लिए स्वामित्व के अधिकार की अनुमति देता है। इस अधिकार को लैण्ड यूज राइट (एलयूआर) कहा जाता है। भूमि और जल की साधारण किराया छूट और कमियां बहुत से निवेश परियोजनाओं पर लागू होती हैं जो प्रोत्साहित क्षेत्रों अथवा व्यापार के क्षेत्रों और/अथवा प्रोत्साहित भौगोलिक स्थलों में निवेश जैसी कतिपय शर्तों को पूरा करती हैं।
562. भूमि की कीमत का जहां तक संबंध है, बाजार चूंकि विकृत हो गया है, इसलिए प्राधिकारी देश में भूमि की प्रचलित कीमत को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।
563. इसलिए प्राधिकारी ने वियतनाम के भौगोलिक समीक्ष्य के भीतर आर्थिक विकास के तुलनीय स्तर पर एक अन्य देश में तुलनीय बाजार कीमतों का विश्लेषण किया है।

564. कार्यक्रम में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम है। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम समतुल्यनीय के रूप में मानते हैं और यह नोट भी करते हैं कि इस अनुदान कार्यक्रम के तहत प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों पर समतुल्य शुल्क लगाना चाहिए।

565. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने राजसहातया मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है। निर्धारित किया गया अनुदान मार्जिन नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है।

(vii) कार्यक्रम सं. 8: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा निवेश ऋण।

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

566. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा शासित है। वित्त मंत्रालय के परिपत्रों के साथ डिक्री सं. 75/2011/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 5 में ऐसे निवेशकों को अधिमान्य दर पर निवेश करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिनकी ऋण के लिए पात्र परियोजनाओं की सूची में परियोजना हो, जिन्होंने निवेश प्रक्रिया को कार्यान्वित किया हो, जिन्होंने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए स्वामी की 20 प्रतिशत इक्विटी और पर्याप्त पूँजी नियोजित की हो। इस कार्यक्रम में निधियों के प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करके वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना होता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल उन्हीं उद्यमों के लिए ही उपलब्ध होता है जो संगत कानूनों के अनुसार पात्रता का मानदण्ड पूरा करते हैं।

567. प्रतिवादी निर्यातकों ने अधिमान्य दरों पर देश के भीतर के बैंकों से ऋण भी प्राप्त किया है। प्राधिकारी द्वारा वित्तीय सहायता देने वाले ऋणों का लाभ लेने के बारे में संज्ञान लेना चाहिए और उसकी मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। यद्यपि अल्पकालिक ऋण पर ब्याज की दर सार्वभौमिक रूप से कम होती है, परन्तु निर्यातकों के द्वारा यह प्रमाण देना होता है कि निर्यातकों द्वारा जिस ऋण का भुगतान किया गया था वह सेंट्रल अथवा वर्ल्ड बैंक अथवा आईएमएफ के अनुसार विहित बैंचमार्क के अनुसार है तथा विवेक अथवा अधिमान्य व्यवहार की कोई बात नहीं है।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

568. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया कि डिक्री 75/2011/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 5 में उन निवेशकों के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराने के लिए वियतनाम डेवलपमेंट बैंक को अधिकृत किया जाता है जिनकी डिक्री के परिशिष्ट । में पात्र परियोजनाओं की सूची में निवेश परियोजनाएं हैं। इस डिक्री को दिनांक 15 मई 2017 को बदल कर डिक्री 32/2017/एनडी-सीपी कर दिया गया था।

569. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने कार्यक्रम के तहत कोई लाभ नहीं लिया था। दीर्घकालिक ऋण के लिए प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भुगतान की गई ब्याज की दरें विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम में प्रचलित ब्याज की दर के बराबर हैं। अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज की दरें सार्वभौमिक रूप से कम हैं और किसी भी अनुदान के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ब्याज पर कोई क्षतिपूर्ति व्यवस्था नहीं होती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

570. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा शासित होता है जो दिनांक 19 मई, 2006 के निर्णय सं. 108/2006/क्यूडी-टीटीजी द्वारा स्थापित राजकीय नीतिगत बैंक है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा यथा विनियमित राजकीय विकास निवेश एवं निर्यात ऋण नीतियों का निष्पादन करने के लिए की गई थी। वी.डी.बी के संगठनात्मक एवं प्रचालनात्मक विनियम प्रधानमंत्री के निर्णय सं. 1515/क्यूडी-टीटीजी के अनुसार हैं। वीडीबी के वित्तीय तंत्र का दिनांक 30 मार्च के निर्णय सं. 44/2007/क्यूडी-टीटीजी के अनुसार निष्पादन किया जाता है। वियतनाम डेवलपमेंट बैंक को विधिक कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। वीडीबी का प्रचालन अलागोन्मुख प्रयोजनों के लिए है। वियतनाम में वीडीबी और अन्य राज्य-स्वामित्व वाले बैंक सार्वजनिक निकाय होते हैं क्योंकि यह वियतनाम सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है और सरकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

571. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिमान्य दर पर निवेश करने के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बशर्ते निवेश परियोजना ऋण के लिए पात्र होने के लिए सूचीबद्ध हो। इस कार्यक्रम में निधियां सीधे अन्तरण करने के रूप में वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह लाभ एक ही परियोजना के लिए एक साधारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली गई ब्याज की तुलना में बीडीबी द्वारा ली गई ब्याज के अन्तर के बराबर होता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह उन्हीं कम्पनियों के लिए उपलब्ध होती हैं जो प्रासंगिक कानून के तहत सूचीबद्ध परियोजनाओं में निवेश कर रही हैं। इसलिए प्राधिकारी इस कार्यक्रम को समतुल्य योग्य मानते हैं।
572. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तरों में केवल यह बताया कि उन्होंने बीडीबी से कोई निवेश ऋण नहीं लिया है। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि उनके द्वारा बीडीबी से कोई ऋण नहीं लिया गया था।
573. तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने वियतनाम ज्वाइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक फॉर इण्डस्ट्री एंड ट्रेड ("वियतिनबैंक") से ब्याज की रियायती दर पर ऋण लिए हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मिनिस्टर्स काउन्सिल द्वारा डिक्री सं. 53/एचडीबीटी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम से इसके अलग होने के बाद वियतिनबैंक की दिनांक 26 मार्च 1988 को स्थापना की गई थी। वियतिनबैंक अधिकांश रूप से स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के स्वामित्व में है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को सरकारी कार्य करने का अधिकार होता है जो सरकारी नियंत्रण और प्रमाणों के औपचारिक रूप से यह दर्शाते हुए कार्य करते हैं कि इसका सार्थक रूप से प्रयोग किया गया है और इस प्रकार यह एक सार्वजनिक निकाय है। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों पर समतुल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए।
574. सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर समतुल्य शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त ऋणों के मामले में, लाभ की राशि उन राशियों के बीच अन्तर होती है जो ऋण प्राप्त करने वाली फर्म वियतिनबैंक को भुगतान करती है और राशि, जो एक फर्म ऐसे तुलनात्मक ऋण पर भुगतान करेगी और जिसे फर्म बाजार से वास्तव में प्राप्त कर सकेगी। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा वास्तव में भुगतान किए ऋण की राशि और ब्याज की राशि उस रिकॉर्ड से ली गई है जो उनके प्रश्नावली प्रत्युत्तरों के साथ उन्होंने उपलब्ध कराए थे। विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार जांच की अवधि के लिए वियतनाम में उधार देने की ब्याज दर एक वाणिज्यिक ऋण के लिए उचित बैंचमार्क ब्याज दर के रूप में ली गई है। उसके द्वारा सब्सिडी मार्जिन को नीचे दी गई सारणी में गणना की गई है।

(viii) कार्यक्रम सं. 9: वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा निर्यात ऋण

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

575. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम वियतनाम डेवलपमेंट बैंक द्वारा शासित होता है। वित्त मंत्रालय के परिपत्रों के साथ डिक्री सं. 32/2017/एनडी-सीपी में ऐसे निर्यातकों और विदेशी आयातकर्ताओं को अधिमान्य दर पर ऋण का प्रावधान है जिन्होंने इसके लिए पात्र मदों की सूची में सूचीबद्ध किसी वस्तु में व्यापार करने की संविदा की है। कार्यक्रम में निधियों के प्रत्यक्षतः अन्तरण के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह निर्यातों पर आश्रित होता है।
576. निर्यातकों ने अधिमान्य दरों पर देश के भीतर के बैंकों से ऋण भी प्राप्त किया है। प्राधिकारी द्वारा वित्तीय सहायता देने वाले ऋणों का लाभ लेने के बारे में संज्ञान लेना चाहिए और उसकी मात्रा का निर्धारण करना चाहिए।

वियतनाम सरकार/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

577. वियतनाम सरकार ने यह अनुरोध किया कि डिक्री सं. 75/2011/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 5 में पात्र निर्यातकों को निर्यात ऋण देने के लिए वियतनाम डेवलपमेंट बैंक अधिकृत है। तथापि, डिक्री को दिनांक 15 मई, 2017 को बदल कर डिक्री 32/2017/एनडी-सीपी कर दिया गया था और संपूर्ण निर्यात ऋण कार्यक्रम का समापन कर दिया था। तथापि समापन से पूर्व की गई वे संविदाएं अभी वैध हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

578. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा शासित होता है और विशिष्ट कितिपय उद्यम क्रेडिट ऋण के लिए पात्र होते हैं। वियतनाम डेवलपमेंट, वियतनाम की वस्तुओं के निर्यात/आयात पर निवेश परियोजनाओं तथा संविदाओं के लिए ऋणों का प्रावधान करता है, जिसका पूँजी पर प्रभाव पड़ा है। बैंक द्वारा स्थापित की गई पूर्व अपेक्षा यह है कि उनके द्वारा वित्तीय योजनाओं और पुनर्भुगतान करने संबंधी योजनाओं के बारे में पहले से सूचित करना होगा। प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्धारित किया है कि वीडीबी एक सार्वजनिक निकाय है। यह भी निर्धारित किया गया है कि वीडीबी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण पर समतुल्य शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए कोई भी अतिरिक्त समतुल्य शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।
579. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तरों में केवल यह बताया कि उन्होंने वीडीबी से कोई निवेश ऋण नहीं लिया है। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड यह दर्शाते हैं कि उनके द्वारा वीडीबी से कोई ऋण नहीं लिया गया था।
580. वियतनाम बैंक से लिए गए ऋण को पहले ही समतुल्यनीय मान लिया गया है और ऊपर बताए गए कार्यक्रम सं. 8 के तहत मात्रा का निर्धारण किया गया है।

अन्य कार्यक्रम

(ix) कार्यक्रम सं. 10: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए स्टेपिंग टिम्बर की व्यवस्था

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध

581. याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया कि उक्त कार्यक्रम राज्य वन विभाग और वित्त मंत्रालय के अधीन सामान्य कर विभाग द्वारा शासित होता है। वियतनाम सरकार का वियतनाम के लगभग सभी पैदावार योग्य वनों पर स्वामित्व है और लट्ठा बनाने के लिए उनको उन कम्पनियों को पट्टे पर दिया जाता है, जिन पर भारी दर लगायी जाती है। संकल्प सं. 928/2010/डीबीटीवीक्यूएच 12 के साथ लॉ ऑन रायलटीज सं. 45/2009/जीएच 12, डिक्री सं. 50/2010/एनडी-सीपी तथा परिपत्र सं. 105/2010/टीटी/बीटीसी और 32/2009/टीटी-बीटीसी में स्टम्पेजेज के लिए बाजार बेंचमार्क से कम स्टम्पेज प्रभारों का प्रावधान है। विनियम के माध्यम से वन क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से कम कीमतों पर कद्दा माल अर्थात् लकड़ी खरीदने के लिए वियतनाम में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को अनुमति देकर टिम्बर का घरेलू बाजार विकृत हो जाता है। इस कार्यक्रम में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए वस्तुओं का प्रावधान करने के रूप में वित्तीय सहयोग करने का प्रावधान है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह प्रमुख रूप से उन उद्यमों के लिए लाभप्रद है जो कद्दे माल के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं। वियतनाम के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों की वेबसाइट पर दी गई सूचना के अनुसार वे अपने कद्दे माल के रूप में यूक्लिप्ट्स (सफेदा) का उपयोग करते हैं। इसको प्राप्त करने की कीमत के बारे में इसी किस्म की लकड़ी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के साथ तुलना करनी चाहिए।
582. व्यापार नीति समीक्षा जो घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत कर दी थी, वह वियतनाम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा तैयार की जाती है। अतः इसकी अधिक प्रामाणिक कीमत है।
583. एएससीएम का अनुच्छेद 14(घ) आउट ऑफ कन्ट्री बेंचमार्कों का उपयोग करने की अनुमति देता है। सरकारी कदमों की वजह से बाजार विकृत होने के मामले में बेंचमार्क के रूप में घरेलू कीमत का उपयोग करना अनुचित है। उच्च स्तर की आर्थिक स्वतंत्रता, विवेकी एवं पारदर्शी वित्तीय विनियमों, कम सब्सिडी और निजी सम्पत्ति अधिकारों की वजह से एलटीएआर पर उपलब्ध कराए गए लट्टे/टिम्बर/लकड़ी के लिए न्यूजीलैंड एक उपयुक्त बेंचमार्क है। न्यूजीलैंड वर्ष 2009 में गोल लकड़ी (राउन्ड वुड) का सबसे बड़ा निर्यातक भी रहा है, जबकि भारत इस वर्ष में आठवां सबसे बड़ा आयातकर्ता था। तथापि, बेंचमार्क अत्यधिक सन्तुलित है जो ज्यादा उचित हो सकता है।

वियतनाम सरकार / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

584. डब्ल्यूटीओ के लिए वियतनाम की व्यापार नीति की समीक्षा, सब्सिडी निर्धारण करने का कानूनी आधार नहीं हो सकती क्योंकि यह केवल एक प्रमाण है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणों में भी स्थानीय खरीद का कोई संदर्भ नहीं है। मेसर्स एमडीएफ वीआरजी क्रांग ट्राई वुड जॉइंट स्टॉक कंपनी अपना प्रमुख कच्चा माल अर्थात्, लकड़ी की खरीद स्थानीय बाजार से असंबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से करती है। वियतनाम में उत्पादक अपने इनपुट के रूप में लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं।
585. किम टिन ने निजी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से अपने कच्चे माल (लकड़ी) की खरीद की। एमडीएफ वीआरजी ने मौजूदा स्थितियों के आधार पर उपयुक्त कीमत पर अलग-अलग स्थानीय निर्माताओं से कच्चे माल (लकड़ी) की खरीद की। इस खरीद के लिए उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया गया।
586. न्यूजीलैंड पर आधारित बेंचमार्क कीमत के उपयोग पर आपत्ति की जाती है क्योंकि उसका चयन करने के लिए कोई भी कारण प्रदान नहीं किया गया है। इसमें सभी प्रकार की लकड़ी और लॉग शामिल हैं, और रबड़ वुड को शामिल की गई किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, न्यूजीलैंड सरकार सभी कटे हुए जंगल को नियंत्रित करती है। न्यूजीलैंड से भारत में लकड़ी का निर्यात कीमत बाजार की कीमतों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड की लकड़ी की कीमतों की तुलना रबर वुड के कीमत से बिल्कुल नहीं की जा सकती। प्रावधान देश में मौजूदा बाजार की स्थितियों के अनुसार बेंचमार्क होना चाहिए। यू एस- कोटेड पेपर (इंडोनेशिया) में डब्ल्यूटीओ के निर्णय विश्वसनीय हैं। जैसा कि यू एस- सॉफ्टवुड लम्बर IV में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में पाया गया है, देश के बेंचमार्क को केवल तभी अपनाया जा सकता है जब इस तरह के सामान को प्रदान करने में सरकार की प्रमुख भूमिका के कारण संसाधन की कीमत सम्बद्ध देश में विकृत हो।

(x) कार्यक्रम संख्या 11: लॉग के निर्यात का सरकारी निषेध

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

587. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि उक्त कार्यक्रम, उद्योग और व्यापार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। परिपत्र संख्या 88/2011 / टीटी-बीएनएनपीटीएनटी में कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी उत्पादों को निर्यात निषेध के अधीन करने के लिए सूचीगत किया गया है। वियतनाम सरकार भी रबर और लकड़ी पर निर्यात कर अधिरोपित करती है। निर्यात प्रतिबंधों का अधिरोपण लॉग के घरेलू बाजार को बिगाड़ता है और उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर डाउनस्ट्रीम उद्योगों को उपलब्ध कराता है। अतः कार्यक्रम, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत के लिए माल के प्रावधान के रूप में एक वित्तीय योगदान प्रदान करता है और जिसके कारण लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह मुख्य रूप से उन उद्यमों के लिए लाभकारी है जो लकड़ी का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं।

वियतनाम सरकार / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

588. इस कार्यक्रम के संबंध में वियतनाम सरकार / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

589. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कार्यक्रम सं 10 और 11 वियतनाम सरकार द्वारा वियतनाम में वानिकी क्षेत्र को विनियमित करने, निगरानी और नियंत्रण के लिए किए गए अनेक उपायों से संबंधित है। चूंकि इन कार्यक्रमों के प्रभाव के परिणामस्वरूप लकड़ी को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर प्रदान किया जाता है, इसलिए इन कार्यक्रमों को संयोजित करने और वर्तमान जांचों के उद्देश्य से उनकी जांच सामूहिक रूप से करने के लिए उपयुक्त माना गया है।
590. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि कार्यक्रम सं 10 वित्त मंत्रालय के तहत राज्य वन विभाग और सामान्य कर विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। वियतनाम के फसल योग्य वन मुख्य रूप से वन प्रबंधन बोर्ड और राज्य वन कंपनियों के माध्यम से वियतनाम सरकार के स्वामित्व में हैं। रॉयलटी कानून संख्या 45/2009 / जीएच12 के अनुसार, उद्यमों को इन राज्य के जंगलों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की अनुमति है और आउटपुट पर कर एकत्रित किया जाता है। एकत्र किए गए कर की दर कानून के तहत निर्धारित है। उत्तर देने वाले सहकारी

उत्पादकों / निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली उत्तर में स्पष्ट किया है कि वे अपने कच्चे माल के रूप में जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं। जलाऊ लकड़ी पर एकत्रित कर, उत्पादन का 1-5% है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित मंत्रालय द्वारा एकत्रित कर विवेकाधीन है और बाजार सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। एकत्र किया गया कर, लकड़ी की बाजार दरों से अन्यथिक कम है।

591. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि कार्यक्रम सं 11 को उद्योग और व्यापार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। परिपत्र नंबर 88/2011 / टीटी -बीएनएनपीटीएनटी कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी उत्पादों को निर्यात निषेध के अधीन करने के लिए सूचीगत किया गया है। निर्यात प्रतिबंध लगाने के माध्यम से, वियतनाम सरकार ने घरेलू वानिकी / कटाई करने वाली कंपनियों को डाउनस्ट्रीम उद्योगों में कंपनियों को कम कीमत के इनपुट (लॉग / लकड़ी) प्रदान करने का कार्य सौंपा / निर्देश दिया। इस मुद्दे पर उपायों ने सम्बद्ध देश में लकड़ी / टिम्बर / लॉग के घरेलू बाजार को विकृत करने और डाउनस्ट्रीम उद्योग के लाभ के लिए कीमत को कृत्रिम रूप से कम करने के लिए वांछित प्रभाव प्राप्त किया है।
592. प्रस्तुत की गई और साथ ही उत्तर देने वाले उत्पादकों / निर्यातकों की वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे पीयूसी के उत्पादन के लिए अपने कच्चे माल के रूप में नीलगिरी (जलाऊ लकड़ी) का उपयोग करते हैं।
593. अतः, लकड़ी, जो फाइबरबोर्ड उद्योग में प्राथमिक कच्चा माल है, को जांच के तहत कंपनियों को, उसे खरीदने के लिए, बाजार दर से कम दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत के लिए माल के प्रावधान के रूप में एक वित्तीय योगदान प्रदान करता है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह उन डाउनस्ट्रीम उद्योगों को लाभ देता है जो लॉग / लकड़ी का उपयोग अपने प्राथमिक कच्चे माल के रूप में करते हैं। अतः कार्यक्रम वास्तविक तौर पर केवल उद्योगों की एक सीमित संख्या के लिए उपलब्ध है। इसलिए, प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि उत्तर देने वाले निर्यातकों / उत्पादकों के विरुद्ध इस सब्सिडी कार्यक्रम के तहत प्रतिकारी शुल्क अधिरोपित किया जाना चाहिए।
594. सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उचित बेंचमार्क की खोज की, जिसमें यह पाया गया कि न्यूजीलैंड विश्व स्तर पर लॉग के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। प्राधिकारी ने न्यूजीलैंड से सम्बद्ध देशों में आयात मूल्य की तुलना में न्यूजीलैंड से भारत में लॉग के निर्यात को एक उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में प्रतिरूप माना है। निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, लकड़ी की वास्तविक खरीद दर पर विचार किया गया है। उपयुक्त रूपांतरण दरों को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम संख्या 10 और 11 के लिए सब्सिडी मार्जिन को नीचे दी गई तालिका में निर्धारित और प्रदान किया गया है।

(xi) कार्यक्रम संख्या 12: डिक्री 142 के तहत प्रोत्साहित उद्योगों या औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों के लिए भूमि प्राथमिकताएं याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

595. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उन्हें कार्यक्रम वियतनाम सरकार की पीपुल्स समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। वियतनाम में भूमि, पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में है। वेलडेड पाइप और ट्यूबों के साथ-साथ कॉन्टीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स में अंतिम निष्कर्ष पर भरोसा किया जाता है। डिक्री नंबर 142/2005 / एनडी-सीपी, पीपुल्स कमेटी ऑफ कैन थो से लीज पर ली गई जमीन को बाजार दरों से कम दरों पर किराया देना प्रदान करता है। कार्यक्रम राजस्व माफी में वित्तीय योगदान प्रदान करता है जो अन्यथा देय है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थित उद्यमों के लिए उपलब्ध है।

वियतनाम सरकार / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

596. इस कार्यक्रम के संबंध में वियतनाम सरकार / अन्य पक्षों द्वारा कोई अनुरोध नहीं की गई।

प्राधिकारी द्वारा जांच

597. प्राधिकारी ने नोट किया कि कार्यक्रम डिक्री 142/2005 / एनडी-सीपी द्वारा शासित है। जैसा कि डिक्री 142/2005 डिक्री और बाद के 46/2014 के तहत निर्दिष्ट है, प्रोत्साहित उद्योगों के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों और निवेश परियोजनाओं में निवेश करने वाली कंपनियों को भूमि किराए में छूट या कमी प्रदान की जाती है।
598. कार्यक्रम, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर माल या सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान प्रदान करता है। कार्यक्रम विशिष्ट भी है क्योंकि यह विशिष्ट क्षेत्र है और कुछ प्रोत्साहित क्षेत्रों तक सीमित है। अतः, प्राधिकारी इस कार्यक्रम को प्रतिकार योग्य मानते हैं। हालाँकि, सब्सिडी को कार्यक्रम 6 में शामिल किया गया है जिसे प्राधिकारी द्वारा पहले ही परिमाणित कर लिया गया है।

(xii) कार्यक्रम संख्या 13: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत और भूमि तथा पानी किराए में छूट अथवा कटौती के लिए सरकारी प्रावधान

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

599. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उक्त कार्यक्रम का प्रबंधन डोंग नाई राज्य सरकार और उसके नागरिक प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। वियतनाम में भूमि पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में है। वेल्डेड पाइप और घूब्रों के साथ-साथ कॉन्टीन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स में अंतिम निष्कर्ष पर भरोसा किया जाता है। डिक्री नंबर 46/2014 / एनडी-सीपी, डिक्री नंबर 123/2017 / एनडी-सीपी, और विधिक संख्या 45/2013 / क्यूएच13 में भूमि और किराए में छूट या कमी प्रदान किया गया है। भूमि और पानी के किराए में छूट तब दी जाती है जब इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए घरों के निर्माण के लिए किया जाता है, जो सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित होते हैं। छूट, निवेश प्रोत्साहन के हकदार क्षेत्र के लिए 3 साल के लिए और विशेष निवेश प्रोत्साहन हकदार के क्षेत्र के लिए 11 वर्ष है। व्यवसाय और उत्पादन सम्बंधी गतिविधियों के लिए परिसर का उपयोग करने वाली सहकारी समितियों को भूमि किराए पर 50% की कटौती प्रदान की जाती है। कृषि, वानिकी, जलीय कृषि या नमक बनाने के लिए पट्टे पर दी गई भूमि और पानी के लिए भूमि और पानी का किराया तब एक अनुरूप दर से कम हो जाता है जब उपज का 40%, आपदा या आग से क्षतिग्रस्त हो जाता है। कार्यक्रम राजस्व माफी में एक वित्तीय योगदान प्रदान करता है जो अन्यथा देय है और उसके द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम भी विशिष्ट है क्योंकि यह केवल उन उद्यमों के लिए उपलब्ध है जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

वियतनाम सरकार / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

600. इस कार्यक्रम के संबंध में वियतनाम सरकार / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा कोई अनुरोध नहीं की गई।

प्राधिकारी द्वारा जांच

601. प्राधिकारी पहले ही यह मान चुके हैं कि पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर भूमि के प्रावधान के लिए प्रतिकारी शुल्क अधिरोपित किया जाना चाहिए। अतः, प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत उत्तर देने वाले निर्यातकों / उत्पादकों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क अधिरोपित करने की आवश्यकता नहीं है।
602. अतः उत्तर देने वाले उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सब्सिडी मार्जिन नीचे दी गई तालिका में निर्धारित की गई है।

कार्यक्रम संख्या 14: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम बिजली

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध

603. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वियतनाम में पर्याप्त पारिश्रमिक से भी कम कीमत में बिजली प्रदान की जाती है।

वियतनाम सरकार / अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

604. किम टिन और एमडीएफ वीआरजी, दोनों द्वारा बिजली की खरीद उनके द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर क्षेत्र के निजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई थी। इस खरीद के लिए उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया गया। वियतनाम सरकार ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर बिजली के आरोपों पर कोई प्रस्तुतियां नहीं की हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

605. जांच के दौरान, प्राधिकारी को आवेदकों द्वारा अपनी प्रस्तुतियों में लगाए गए आरोपों के अनुसार एलटीएआर में उपलब्ध कराई गई बिजली की जानकारी प्राप्त हुई। प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों से अतिरिक्त प्रश्नावली के रूप में अपेक्षित जानकारी मांगी। वियतनाम सरकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। उत्तर देने वाले निर्यातकों ने, अपनी प्रश्नावली उत्तर में, प्रस्तुत किया है कि उन्होंने बाजार कीमत पर बिजली की खरीद की है।
606. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम में विद्युत क्षेत्र को विद्युत कानून द्वारा विनियमित किया जाता है जिसे समय-समय पर संशोधित और परिशोधित किया जाता है। विद्युत नियामक प्राधिकरण वियतनाम (ईआरएवी) 2005 में स्थापित किया गया था, जो अन्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ, देश में बिजली दरों पर सलाह देता है। विधि एक औसत खुदरा शुल्क (एआरटी) निर्धारित करती है जिसके आधार पर बिजली प्रशुल्क लगाया जाता है। हालांकि, विगत में एआरटी में अनेक बार संशोधन किया गया है, प्राधिकारी का मानना है कि उत्तर प्रशुल्क, लागत और मुद्रास्फीति में उत्तर-चढ़ाव के साथ समान अनुपात में नहीं है। मार्च 2020 में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में एआरटी लगभग 8 अमेरिकी सेंट / किवा था, जबकि लागत की पूर्ण रूप से वसूली करने के लिए उसे 12 अमेरिकी सेंट / किवा होना चाहिए था।
607. इसके अतिरिक्त, वियतनाम में बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण लगभग पूरी तरह से राज्य के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट समूह, बिजली वियतनाम (ईवीएन) के साथ-साथ इसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ईवीएन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और इसमें नई इक्किटी जारी करने की स्वतंत्रता नहीं है। ईवीएन की वार्षिक रिपोर्ट 2018 के अनुसार, कंपनी को "राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करने के मिशन के साथ" (सरकार द्वारा) सौंपा गया है ... और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मैक्नो विनियामक उपकरण के रूप में सरकार के लिए कार्य करता है।" बिजली प्रशुल्क के सरकारी विनियमन के कारण इन कंपनियों द्वारा अर्जित उप-इष्टतम रिटर्न को आंशिक रूप से राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों से अनुकूल शर्तों के साथ कर प्रोत्साहन, गारंटी, ऋण के रूप में ईवीएन और रणनीतिक परियोजनाओं के लिए सब्सिडी द्वारा राज्य की सहायता से पूरा किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम, ईवीएन में सरकारी कार्यों का उपयोग करने के अधिकार निहित किया गया है, जो सरकारी नियंत्रण के औपचारिक संकेत तथा प्रमाण पर आधारित है और यह दर्शाता है कि इसका प्रयोग सार्थक तरीके से किया गया है, इसलिए यह एक सार्वजनिक निकाय है। अतः प्राधिकारी ने पाया कि वियतनाम में बिजली क्षेत्र विरुपित है और बाजार के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है जो कि पीयूसी के उत्पादकों को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर बिजली खरीदने में सक्षम बनाता है। इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि उत्तर देने वाले उत्पादकों / निर्यातकों के विरुद्ध इस कार्यक्रम के तहत प्रतिकारी शुल्क अधिरोपित की जानी चाहिए।
608. सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उचित बेंचमार्क की तलाश की। प्राधिकारी ने 'ग्लोबलपेट्रोलप्राईसेस' की वेबसाइट के अनुसार प्रदान की गई कीमतों पर भरोसा किया है। अतिरिक्त प्रश्नावली उत्तर के अनुसार उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक बिजली दरों को सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए माना गया है। उपरोक्त कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए, उत्तर देने वाले निर्यातकों के लिए निर्धारित सब्सिडी मार्जिन नीचे तालिका में दी गई है।

किम टिन एमडीएफ ज्याइंट स्टॉक कं

609. किम टिन एमडीएफ संयुक्त स्टॉक कंपनी वियतनाम में संबद्ध वस्तु का निर्माता / निर्यातक है। किम टिन ने प्रश्नावली उत्तर दर्ज किया और उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्रदान की।
610. प्राधिकारी ने किम टिन द्वारा दर्ज किए गए उत्तर की जांच की और जांच में उनसे अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया और आवश्यक समझी गई सीमा के उत्तर में प्रदान की गई जानकारी को भी सत्यापित किया। किम टिन ने अपनी प्रश्नावली उत्तर में स्पष्ट किया है कि उसने कॉर्पोरेट आयकर पर कटौती का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरी ने निर्धारित किया कि सब्सिडी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भूमि किराए में कमी, वियतनाम विकास बैंक द्वारा प्राप्त ऋण, और एलटीएआर में लकड़ी और बिजली के प्रावधान का लाभ किम टिन द्वारा उठाया गया था। परिणामस्वरूप, विभिन्न सब्सिडी के रूप में किम टिन को लाभ प्रदान किया गया।

611. प्राधिकारी ने किम टिन द्वारा प्रदान की गई जानकारी की पुष्टि की है और उन कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है जिनके लिए पीओआई के दौरान लाभ प्राप्त किया गया था अथवा अर्जित किया गया था। जहां निर्यातक द्वारा सुसंगत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

612. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों का नाम और तदनरूप सब्सिडी मार्जिन दी गई है।

क्रम.स	कार्यक्रम सं	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज%
1	कार्यक्रम सं 4	कॉर्पोरेट आयकर में कमी	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं 6, 12 एवं 13	भूमि और जल किराए में छूट और कमी	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं 8	वियतनाम विकास बैंकों द्वारा निवेश क्रेडिट	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं 10 एवं 11	कम पारिश्रमिक से कम कीमत पर कच्चे माल (लकड़ी) का प्रावधान	***%	0-10
5	कार्यक्रम सं 14	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर बिजली का प्रावधान	***%	0-10
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

एमडीएफ वीआरजी क्लांग ट्राई वुड जॉइंट स्टॉक कंपनी

613. एमडीएफ वीआरजी क्लांग ट्राई वुड जॉइंट स्टॉक कंपनी वियतनाम में सम्बद्ध वस्तु का उत्पादक / निर्यातक है। एमडीएफ वीआरजी ने प्रश्नावली उत्तर दर्ज किया और उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्रदान की है।

614. प्राधिकारी ने एमडीआर वीआरजी द्वारा दर्ज की गई प्रतिक्रिया की जांच की और जांच में उनसे आगे की जानकारी का अनुरोध किया और आवश्यक समझी गई प्रतिक्रिया के जवाब में प्रदान की गई जानकारी को भी सत्यापित किया। एमडीएफ वीआरजी ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में स्पष्ट किया है कि उसने भूमि के किराए में कमी का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि सब्सिडी कार्यक्रम कॉर्पोरेट आय कर में कमी, वियतनाम विकास बैंक द्वारा प्राप्त ऋण, और एलटीएआर में लकड़ी और बिजली के प्रावधान का लाभ एमडीएफ वीआरजी द्वारा उठाया गया था। परिणामस्वरूप, विभिन्न सब्सिडी के रूप में एमडीएफ वीआरजी को लाभ प्रदान किया गया।

615. प्राधिकारी ने एमडीआर वीआरजी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया है, जिसके लिए पीओआई के दौरान लाभ प्राप्त हुआ अथवा अर्जित किया गया। निर्यातक द्वारा सुसंगत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, जहां प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

616. नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी कार्यक्रमों का नाम और तदनरूप सब्सिडी मार्जिन दी गई है।

क्रम.स	कार्यक्रम सं	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज%
1	कार्यक्रम सं 3	स्पेयर पाटर्स के आयात की छूट	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं 4	कॉर्पोरेट आयकर में कमी	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं 6, 12 एवं 13	भूमि और जल किराए की छूट और कमी	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं 8	वियतनाम विकास बैंकों द्वारा निवेश क्रेडिट	***%	0-10
5	कार्यक्रम सं 10 एवं 11	कम पारिश्रमिक से कमकीमत पर कच्चे माल (लकड़ी) का प्रावधान	***%	0-10

6	कार्यक्रम सं 14	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर बिजली का प्रावधान	-	-
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

617. वियतनाम से अन्य सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए प्रतिकारी शुल्क, सहकारी पार्टी के उच्चतम सब्सिडी, उनके द्वारा प्राप्त सब्सिडी और अन्य सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

क्रम.स	कार्यक्रम सं	योजनाओं का नाम	सब्सिडी मार्जिन %	रेंज%
1	कार्यक्रम सं 3	स्पेयर पार्टर्स के आयात की छूट	***%	0-10
2	कार्यक्रम सं 4	कॉर्पोरेट आयकर में कमी	***%	0-10
3	कार्यक्रम सं 6, 12 एवं 13	भूमि और जल किराए में छूट और कमी	***%	0-10
4	कार्यक्रम सं 8	वियतनाम विकास बैंकों द्वारा निवेश क्रेडिट	***%	0-10
5	कार्यक्रम सं 10 एवं 11	कम पारिश्रमिक से कम कीमत पर कञ्च माल (लकड़ी) का प्रावधान	***%	0-10
6	कार्यक्रम सं 14	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम कीमत पर बिजली का प्रावधान	-	-
		कुल सब्सिडी	***%	10-20

ज. क्षति आंकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

618. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार है:

- क) निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस तरह के आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करें (क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में सब्सिडी की राशि यथा मूल्य से एक प्रतिशत से अधिक है;(ख) प्रत्येक देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है और (ग) आयातित उत्पादों और इस तरह के घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है।
- ख) संचयी आंकलन में थाईलैंड और इंडोनेशिया को आयात में इसके हिस्से और मात्रा, आयात में समान रुक्षान, पीयूसी के समान ग्रेड, उत्पादों की विनियेता, बिक्री चैनल की तुलना, और उनके और अन्य सम्बद्ध देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण उचित रूप से शामिल किया गया हैं ।
- ग) भारत में क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ गई है।
- घ) क्षति की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से आयात में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयात भी बढ़ा है। सम्बद्ध देशों के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।
- ड) उत्पादन लागत की तुलना, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयात माल की कीमत दर्शाता है कि संबद्ध आयात की माल की कीमत प्रस्तावित पीओआई में घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, जबकि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत को कम करने के लिए बाध्य किया गया। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित और निराशाजनक बना रहे हैं।
- च) देश में उत्पाद के लिए वर्तमान और संभावित मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन में सुधार हुआ।
- छ) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग अत्यधिक कम हो गया था। कोविड की स्थिति के कारण क्षमता उपयोग में और अधिक गिरावट आई है।

- ज) क्षमता संवर्धन के कारण ग्रीनपेनल के इष्टतम उत्पादन को प्राप्त नहीं करने के संबंध में, कंपनी ने प्राप्त औसत उपयोग की तुलना में उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त किया।
- झ) वर्ष 2016-17 में घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई, इसके बाद 2017-18 में सुधार हुआ और पीओआई में क्षमताओं में वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग की दरें कम रहीं। क्षमता संवर्धन और उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए, डीआई अधिक बेच सकता था, किंतु सब्सिडीकृत आयात के कारण ऐसा नहीं कर सका था। क्षमता उपयोग में गिरावट सब्सिडीकृत आयात के कारण अधिक मात्रा में बिक्री करने की असमर्थता के कारण है।
- ञ) क्षमताओं और उत्पादन में वृद्धि से घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में मामूली सुधार हुआ।
- ट) क्षति की अवधि के दौरान प्रति यूनिट लाभ आधा से अधिक हो गया है। यह संबद्ध आयात द्वारा कीमत में कमी होने के कारण बिक्री कीमतों में गिरावट हुई है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में लाभप्रदता में सुधार हुआ, उसके बाद पीओआई में अत्यधिक रूप से गिरावट आई।
- ठ) क्षति की अवधि में पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर रिटर्न, सभी में अत्यधिक रूप से गिरावट आई। पीओआई से पहले मूल्यहास स्तर पर विचार करने पर भी, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में अभी भी गिरावट है।
- ड) क्षमताओं में वृद्धि होने से प्रति दिन उत्पादकता, रोजगार संख्या और मजदूरी, सभी में सुधार हुआ। घरेलू उद्योग के साथ मालसूची वास्तव में बाजार की स्थिति को दर्शाती है, जिससे संबद्ध वस्तुओं की अत्यधिक मांग के बावजूद, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के स्टाक्स में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
- ण) पीओआई के दौरान सभी मूल्य मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग क्षति उठा रही है। गैर-क्षतिकारक के निर्धारण के लिए सीबीडी जांच में एडी नियम के अनुबंध III को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- त) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। नतीजतन, आयात की मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। चूंकि आयात कम कीमतों पर हो रहा है, इसिलिए घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई मात्रा में बेचने के लिए इसकी कीमतों को कम करना पड़ा था। घरेलू उद्योग द्वारा महसूस किया जा रहा मूल्य का दबाव सब्सिडीकृत आयात के कारण है। सब्सिडीकृत आयातों के कारण मूल्य का कम होना, घरेलू उद्योग को इसकी कीमतें बढ़ाने से रोक रहा है।
- थ) संबद्ध देशों से सब्सिडीकृत आयातों के कीमतों में प्रतिबंध और मंदी के प्रभाव ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्णरूप से ह्यास किया है। लाभ, नियोजित पूँजी पर रिटर्न और नकद लाभ में ह्यास, प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडीकृत आयात का परिणाम है। कई आर्थिक मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई है। देश में सब्सिडीकृत आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। सब्सिडी-रोधी शुल्क का अधिरोपण अनिवार्य है।
- द) घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपने निष्पादन के रूप में आगे असफलताओं को लेने में समर्थ नहीं है।
- ध) इस तर्क के संबंध में कि दूसरों की तुलना में ग्रीनपेनल एपी संयंत्र और सेंचुरी में उत्पादन की उच्च लागत के कारण एनआईपी में वृद्धि हुई है, संयंत्र की उम्र को देखते हुए, अन्य संयंत्रों की लागत प्रतिरूप नहीं हैं।
- न) इस तर्क के संबंध में कि सभी भारतीय उत्पादकों, यदि वे सभी आयात से प्रभावित होते हैं, के लिए एनआईपी समान होना चाहिए, में कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं है।
- प) इस तर्क के संबंध में कि क्षति विश्लेषण के लिए बिक्री लागत को मानक बनाया जाना चाहिए, में कोई कानूनी आधार नहीं है।
- फ) सब्सिडीकृत आयात क्षति का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। यह तथ्य कि इसके अन्य कारण हैं, जो कारणात्मक संबंध को प्रभावित नहीं करते हैं। जबकि याचिकाकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्ट केवल पीओआई पर केंद्रित है, प्राधिकारी क्षति की पूर्ण अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के समग्र निष्पादन से सम्बंधित है जबकि डीए केवल अपने घरेलू प्रचालनों से सम्बंधित है।
- ब) यदि डीआई को केवल आंतरिक प्रतिस्पर्धा ने प्रभावित किया है, तो इसके बाजार हिस्सेदारी में गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एमडीएफ प्लाईवुड की जगह ले रहा है, न कि दूसरे तरीके से।

- भ) त्रहण बकाया में वृद्धि क्षति पहुंचाने वाले "अन्य कारकों" की प्रकृति में नहीं है,
- म) यह दावा कि क्षति आंतरिक कमी के कारण है, अप्रमाणित है।
- य) एडीडी और सीवीडी अनुचित प्रथाओं का समाधान करने के लिए हैं। विगत जांचों के लिए पीयूसी भिन्न थे।
- कक) हालांकि पीयूसी पर एक समानांतर एसएसआर जांच है, डीआई द्वारा उठाई गई क्षति कम कीमत पर आयात के कारण है जो पाटन और / या सन्सिडी का परिणाम है। डीआई ने क्षति मार्जिन से अधिक राहत की मांग नहीं की है और एक समय में होने वाली जांच पर कोई रोक नहीं है। रिलायंस को सनसिटी शीट्स प्रा.लि. बनाम यूओआई में सीईएसटीएटी के आदेश पर रखा गया है।
- खख) घरेलू उद्योग की क्षति को वह जैसा है वैसा ही देखा जाना चाहिए न कि आदर्श परिस्थितियों में। मेसर्स निपोल ज़िओन कंपनी लिमिटेड, जापान बनाम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में सीईएसटीएटी आदेश को संदर्भित किया जाता है और उस पर भरोसा किया जाता है।

ज .2 अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अनुरोध

619. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा की गई अनुरोध इस प्रकार है :
- क) आवेदक 2009 से संरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि क्षति आंतरिक कमियों के कारण है न कि आयात के कारण। आयात की मात्रा में गिरावट आई है और आयात की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी बीच, डीआई की लागत में वृद्धि हुई, कीमत और लाभप्रदता में गिरावट आई। यह दर्शाता है कि क्षमता विस्तार के कारण, लागत में वृद्धि है।
- ख) क्षमता परिवर्धन, क्षमता उपयोग का विवेकपूर्ण स्तर, और उत्पादन तथा बिक्री में वृद्धि, प्रभाव और क्षति की मात्रा की अनुपस्थिति को दर्शाती है। कीमत और लाभप्रदता में मामूली गिरावट को संबद्ध आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है।
- ग) आधार वर्ष से पीओआई तक क्षति विश्लेषण करने के लिए सीवीडी नियम में नामित प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं है।
- घ) याचिकाकर्ताओं ने पीसीएन पर विचार किए बिना सभी उत्पादों की कीमतों की तुलना आयात कीमतों से करके प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ताओं को किसी भी मूल्यहास या गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा है।
- इ) एनसीवी में आर्थिक संकेतक, पीओआई में उत्पादक क्षमता में 174% की वृद्धि को दर्शाता है, जिसने इसी अवधि में उत्पादन में 61% की वृद्धि की। पीओआई में बिक्री में 49% सुधार हुआ। याचिकाकर्ताओं ने आधार वर्ष की तुलना में 181% अधिक कर्मचारियों को काम पर रखा है। प्रति दिन उत्पादकता में सुधार बना रहा और पीओआई में सबसे अधिक के 171 सूचकांक पर पहुंच गया।
- च) हालांकि लाभप्रदता 59% कम हो गई है, किंतु यह कमी इंडोनेशिया से आयात के कारण नहीं है। दूसरी ओर, यह लागत (मूल्यहास और परिशोधन व्यय तथा ब्याज / वित्त लागत में वृद्धि के कारण था जो कि क्षमता परिवर्धन के कारण पीओआई में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है) के कारण था। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मूल्य वृद्धि में कथित वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। पीओआई के दौरान लाभप्रदता में गिरावट मुख्य रूप से उच्च वित्त लागत और मूल्यहास व्यय के कारण हुई है।
- छ) घरेलू मांग में 35 अनुक्रमित अंकों की वृद्धि हुई है और भारतीय उत्पादक बाजार पर कब्जा करने और अपनी बिक्री को 44 अनुक्रमित बिंदुओं तक बढ़ाने में सक्षम हुए हैं।
- ज) याचिकाकर्ता पीसीएन की कीमतों में अंतर पर विचार किए बिना कुल आयात मूल्य से बिक्री कीमतों की तुलना करके, कीमत कम करने और मूल्य हास / गिरावट पर प्राधिकारी को भ्रमित कर रहे हैं।
- झ) मूल्य और लाभप्रदता मापदंडों में मामूली गिरावट को संबद्ध देशों से आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसका कारण घरेलू उत्पादकों के बीच महत्वपूर्ण क्षमता परिवर्धन और असाधारण मूल्य प्रतिस्पर्धा है।

- ज) डीआई और पीओआई ने वर्षों में महत्वपूर्ण क्षमता परिवर्धन किए। पीओआई में क्षमता उपयोग में गिरावट को क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ माना जाना चाहिए। पीओआई के माध्यम से उत्पादन और बिक्री (घरेलू और निर्यात दोनों) में वृद्धि हुई है।
- ट) क्षमता परिवर्धन से डीआई में अतिरिक्त लागत की वृद्धि हुई है, और आरओसीई को प्रभावित किया है। घटती उत्पादकता के परिणामस्वरूप ब्याज लागत और मजदूरी में वृद्धि के कारण लागत में भी वृद्धि हुई।
- ठ) 2 वित्तीय वर्षों में वित्त की लागत में 80 अनुक्रमित बिंदुओं की वृद्धि हुई, उसी अवधि के दौरान मूल्यहास और परिशोधन के व्ययों में 114 अनुक्रमित बिंदुओं की वृद्धि हुई। वित्त और मूल्यहास व्ययों के कारण पीओआई के अलावा क्षति की पूरी अवधि में नकद लाभ में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है।
- ड) डीआई की बिक्री कीमत और आयात कीमत के बीच एक प्रतिकूल संबंध है। पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान संबद्ध देशों के आयात में गिरावट आई (11% की दर से) और कीमतों में (4% की दर से) वृद्धि हुई। आयात कीमत का डीआई पर कोई दमनकारी प्रभाव नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में संबद्ध देशों से आयात के बाजार हिस्सेदारी में 6% की गिरावट आई है जिसने डीआई को लाभान्वित किया है।
- ढ.) भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में थाईलैंड से आयात की मात्रा में गिरावट आई है। थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं का आयात मूल्य 2017-18 के दौरान 24,206 रुपये / मीट्रिक टन से बढ़कर पीओआई के दौरान 26,274 रुपये / मीट्रिक टन हो गया है। इसकी तुलना में, डीआई की लागत में केवल 5 अनुक्रमित बिंदुओं की वृद्धि हुई है। इसलिए, कीमत कम नहीं हुई है। थाईलैंड डीआई की लागत से अधिक मूल्य बढ़ाने का आशय रखता है, किंतु डीआई की कम बिक्री कीमत और अन्य आयात स्रोतों से कीमतों ने संभावित कीमत वृद्धि को प्रभावित किया है।
- ण) इंडोनेशिया का आयात मूल्य थाईलैंड की तुलना में 23-25% कम है। इसके अलावा, नए प्रवेशकों की घरेलू बिक्री कीमत कम है। थाईलैंड के आयात में गिरावट आई है क्योंकि यह बाजार में कम कीमतों के कारण भारतीय बाजार को अस्थिर पाता है।
- त) यूएस-लैम्ब में एबी रिपोर्ट ने "गंभीर क्षति" को "बहुत उच्च मानक वाली क्षति" बताया था। यूएस - व्हीट ग्लूटेन में एबी रिपोर्ट ने फैसला दिया कि गंभीर क्षति का मतलब है कि डीआई की स्थिति में समग्र हानि और डीआई की समग्र स्थिति के लिए सुसंगत सभी कारकों को प्राधिकारी के निर्धारण में शामिल किया जाना चाहिए।
- थ) क्षति, यदि कोई हो, तो मलेशिया और वियतनाम जैसे अन्य स्रोतों से होती है, जिससे आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- द) पैनल प्लस एमडीएफ और पैनल प्लस कंपनी, वानाचाई पैनल और वानाचाई समूह द्वारा प्राप्त लाभ महत्वहीन हैं और इससे क्षति नहीं हो सकती है।
- ध) सीवीडी नियमों के अनुबंध । के तहत संचयी आंकलन नहीं किया जा सकता है। पीओआई में आयात में गिरावट और बढ़ती कीमत वाला थाईलैंड एकमात्र देश है। इंडोनेशिया से आयात में सम्पूर्ण और तुलनात्मक दोनों ही स्थितियों में काफी गिरावट आई है। क्षति का संचयन उपयुक्त नहीं है।
- न) मर्बोक एमडीएफ लंका प्राइवेट लिमिटेड श्रीलंका से भारत में पीयूसी का केवल एक ज्ञात निर्यातक है और कंपनी हाल के वर्षों में घाटे में चल रही है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा घट रही है।
- प) अनुलग्नक - एनआईपी की ॥। गणना, लागू की जानी चाहिए।
- फ) श्रीलंका के आयात का हिस्सा कुल आयात का 3.97% है, नियमों के नियम 16 (डी) के अनुसार, कुल आयात के 4% से कम हिस्सेदारी रखने वाले किसी भी विकासशील देश को शुल्क के अधिरोपण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। कम कीमतों के बावजूद 3.23% के साथ ब्राजील के विरुद्ध आरम्भ नहीं की गई है।
- ब) प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह न केवल एनआईपी के लिए बिक्री की लागत को बढ़ाए, किंतु क्षति के विश्लेषण के लिए भी खर्च करे क्योंकि क्षमता परिवर्धन के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है।

- भ) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह ग्रीन पैनल के दूसरे संयंत्र की परियोजना रिपोर्ट और वित्तीय क्रृष्णदाताओं को दिए गए अनुमानों का मूल्यांकन करें।
- म) घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज याचिका विभिन्न कारकों को दर्शाती है जो कारणात्मक संबंध के उल्लंघन का संकेत देती है:
- (i) पीओआई के दौरान आयात में गिरावट आई और आयात की कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि डीआई के लिए प्रमात्र मापदंडों में सुधार हुआ।
 - (ii) डीआई की कीमत पर आयातों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। डीआई के विक्रय कीमत और आयात कीमत के बीच एक प्रतिकूल संबंध है। डीआई की कीमत, आंतरिक मूल्य प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुई थी।
 - (iii) क्षमता में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि हुई। क्षमता संवर्धन के कारण भी ब्याज लागत और मजदूरी में वृद्धि हुई।
 - (iv) लाभप्रदकता में गिरावट का कारण उत्पादकता में गिरावट है।
 - (v) डीआई की क्षति आंतरिक प्रतिस्पर्धा और प्लाईवुड से प्रतिस्पर्धा के कारण है जो पीयूसी के लिए एक विकल्प है। सेंचुरी प्लाईवुड की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के उद्धरण में असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और अंत में, विदेशी प्रतियोगिता को दर्शाया गया है।
 - (vi) कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में मुद्दे हैं, जो लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं। भारतीय रियल एस्टेट उद्योग आदि में गिरावट का असर घरेलू उत्पादकों पर भी पड़ा।
 - (vii) प्राधिकारी ने नई उत्पादन क्षमता को आरम्भ करना, बाजार के नए निर्माताओं द्वारा गहन प्रतिस्पर्धा और वार्षिक रिपोर्ट में उजागर किए गए अन्य कारकों जैसे मूलभूत कारणों के चलते घरेलू उद्योग को क्षति को पृथक करने का अनुरोध किया।
 - (viii) वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, रशिल ने पीओआई में इष्टतम स्तर पर काम किया और लैमिनेट्स व्यवसाय में हानि उठाई।
 - (ix) सेंचुरी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एमडीएफ व्यवसाय का सबसे बड़ा संचालक था। कंपनी के उत्पादन का स्तर कम था, किंतु राजस्व में 161% की वृद्धि हुई। क्षमता में वृद्धि हुई और पीओआई के दूसरे भाग में उत्पादन आरम्भ हुआ। उत्पादन के इष्टतम स्तर तक पहुंचने की आशा नहीं है।
 - (x) आवेदक उत्पादकों की वार्षिक रिपोर्ट, जांच के लिए एक अभिन्न दस्तावेज है। यह व्यक्त किया गया है कि भारतीय उत्पादकों को कच्चे माल की कमी, भारतीय उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और अन्य कारकों के कारण क्षति हो रही है।
 - (xi) ग्रीनपैनल रुद्रपुर सन्यंत्र और रशिल ने असाधारण स्टार्ट-अप लागत के बिना अच्छी तरह से उत्पादन स्थापित किया है जबकि एपी प्लांट और सेंचुरी के उत्पादन की लागत अनुपातहीन रूप से बहुत अधिक है। इस प्रकार से कि बड़ी हुई लागतों ने इन दोनों संयंत्रों के लिए एनआईपी को बढ़ा दिया है। अगर आयात भारतीय उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, तो सभी भारतीय उत्पादकों का एनआईपी सभी घरेलू उत्पादकों के लिए समान होना चाहिए था।
 - (xii) आगे की कीमतों में कटौती के लिए डीलरों / वितरकों की अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप डीआई की मद सूची में वृद्धि हुई। उसे आयात के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।
 - (xiii) प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वह प्रतिस्थापन योग्य उत्पादों के प्रभाव का विश्लेषण करे, जिसका संबद्ध वस्तुओं की विक्री और बिक्री की कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
 - (xiv) संबद्ध वस्तुओं (एक मामूली बदलाव के साथ) पर एक समानांतर समापक समीक्षा जांच में, घरेलू उद्योग ने चीन, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका से पाठित किए गए आयात के कारण क्षति का दावा किया है।
- य) आवेदकों ने गैर-मौजूद क्षति को प्रमाणित करने के लिए श्रीलंका को एक सम्बद्ध देश के रूप में शामिल किया है। क्षति का संचयन सब्सिडी-रोधी नियमों के उल्लंघन में आता है। सब्सिडी-रोधी नियमों के अनुसार पर्याप्तता और सटीकता की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है। श्रीलंका के आयात का हिस्सा **न्यूनतम सीमा से कम है** और इसलिए अयोग्य है। प्राधिकारी ने कुछ देशों की तुलना में कम कीमतों के बावजूद ब्राजील (क्योंकि यह केवल 3.23% आयात के लिए उत्तरदायी है) के विरुद्ध जांच आरम्भ नहीं की है।

- कक) इंडोनेशियाई आयातों में तुलनात्मक के साथ-साथ समग्र रूप के संदर्भों में महत्वपूर्ण गिरावट है। क्षति का संचयन उपयुक्त नहीं है।
- खख) बिक्री की लागत को मानक बनाया जाना चाहिए क्योंकि क्षमता परिवर्धन के कारण वास्तविक लागत में वृद्धि होती है। क्षमता विस्तार ने पूरी स्थिति को विकृत कर दिया है। उसी का विश्लेषण करना है। ग्रीन पैनल के दूसरे संयंत्र की परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाना है।
- गग) पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में संबद्ध देशों के आयात में गिरावट आई और समान अवधि में आयात की कीमतों में वृद्धि हुई। कथित सब्सिडीकृत आयात डीआई को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं थे। लाभ और लाभप्रदता में मामूली गिरावट को आयात से नहीं जोड़ा जा सकता है। डीआई अपने वॉल्यूम मापदंडों को बढ़ाने में सक्षम है और इसलिए, बाजार में उसकी हिस्सेदारी है।
- घघ) डीआई को कोई क्षति नहीं हुई जैसा कि मात्रा और कीमत पैरामीटर्स से देखा जा सकता है। अत्यधिक क्षमता संवर्धन के कारण कुछ अस्थायी प्रतिकूलताओं को अनुमानित किया गया है जो सीवीडी उपायों को न्याय संगत नहीं बताते हैं।
- ङङ) थाईलैंड से आयात के कारण डीआई के मात्रा में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि भारत में मांग में वृद्धि और उत्पादन में सुधार, क्षमता उपयोग और आवेदकों की बाजार हिस्सेदारी के कारण थाईलैंड से आयात की मात्रा में तुलनात्मक गिरावट आई है। थाईलैंड से आयात की मात्रा में सम्पूर्ण अथवा तुलनात्मक रूप से वृद्धि नहीं हुई है।
- चच) थाईलैंड से आयात के कारण डीआई को कीमत में कोई क्षति नहीं हुई है। थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है और उस के कारण कीमत में कोई कमी नहीं हुई है। भारतीय उत्पादकों की कम कीमतों और अन्य स्रोतों से आयात के कारण थाई निर्यातकों को कीमतें बढ़ाने से रोका गया था। यहां नकारात्मक मूल्यह्यास और गिरावट है।
- छछ) संबद्ध देशों के बीच थाईलैंड ही एकमात्र स्रोत है जहां से कुल आयात, उत्पादन, बिक्री के साथ-साथ बाजार हिस्सेदारी के तुलना में आयात की मात्रा घट गई है। इंडोनेशिया से आयात मूल्य थाईलैंड की तुलना में काफी कम है और इसलिए, उन्होंने बाजार कीमत निर्धारित किया है।
- जज) डीआई ने वृद्धि हुई एनाईपी का दावा किया है। सेंचुरी प्लायबोर्ड और ग्रीनपैनल एपी प्लांट के लिए उत्पादन की लागत असमान रूप से और असाधारण रूप से अधिक है। यह वृद्धि समान पीओआई के दौरान उत्पादन क्षमता के प्रारंभ / परिवर्धन के कारण है न कि आयात के कारण। उन्हें अन्य उत्पादकों के एनआईपी के अनुरूप तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।
- झझ) याचिकाकर्ता का तर्क कि एनआईपी की गणना एडी नियमों के अनुसार नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह दोषपूर्ण इसिलिए एनआईपी निर्धारित करने के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए, सीवीडी नियमों में आवश्यक है कि डीआई को क्षति को हटाने के लिए सीवीडी की पर्याप्त मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए, और प्राधिकारी की पिछली प्रक्रिया एडी नियमों के अनुप्रयोग को दर्शाता है।
- जज) यदि आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी के लिए लांग का उपयोग किया है, तो वही क्षति का कारण है क्योंकि लकड़ी अवशेषों की तुलना में बहुत अधिक महंगी है।
- टट) आवेदकों की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाता है कि (i) महत्वपूर्ण क्षमता परिवर्धन के परिणामस्वरूप कीमतों में कटौती हुई, (ii) उसने उद्योग की कीमतों को भी अत्यधिक रूप से प्रभावित किया है क्योंकि डीलर कीमतों में कटौती की आशंका कर रहे थे, (iii) उन्होंने एमडीएफ सेगमेंट में निम्न प्राप्ति और महत्वपूर्ण मार्जिन दबाव को ट्रिगर किया। (iv) मार्जिन दबाव अल्पकालिक है, और (iv) प्लाईवुड एमडीएफ का एक विकल्प है।
- ठठ) वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय उत्पादकों को आरएम की कमी, भारतीय उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और अन्य आंतरिक कारकों के कारण क्षति हो रही है।
- डड) ग्रीनपैनल ने निर्यात बाजार को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश में नई उत्पादन क्षमता स्थापित की है। आंध्र प्रदेश में उत्पादन की उच्च लागत के कारण ग्रीनपैनल की क्षति को घरेलू प्रचालन या कथित आयात के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए।

- ठृ) महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि के कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आई। क्षमता परिवर्धन को अवशोषित करने में बाजार को समय लगता है। अतः, क्षमता में वृद्धि के कारण क्षति हुई है।
- णण) घरेलू उत्पादकों के बीच गंभीर प्रतिस्पर्धा और भारतीय रियल एस्टेट उद्योग में कम समय के कारण बिक्री कीमत में कमी हुई है।
- तत) कंपनियों को आरएम उपलब्धता में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डीलरों / वितरकों द्वारा मूल्य में कमी की आशा के कारण कीमत में कटौती हुई जिसके परिणामस्वरूप मदसूची में वृद्धि हुई।
- थथ) क्षमता में वृद्धि के कारण वित्त लागत और मूल्यहास लागत में वृद्धि हुई है।
- दद) क्षमताओं के संवर्धन ने लाभप्रदता और आरओसीई को प्रभावित किया है।
- धध) लागत वृद्धि व्याज लागत में वृद्धि, खराब उत्पादकता के परिणामस्वरूप मजदूरी कारक में वृद्धि से प्रेरित है।

ज .3 प्राधिकारी द्वारा जांच

620. संबद्ध देश से सब्सिडिकृत आयात के कारण घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करने के लिए इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का विश्लेषण किया गया है।
621. क्षति मापदंडों के विश्लेषण के मुद्दों के संबंध में, यह ध्यान दिया गया है कि क्षति का विश्लेषण करते समय बाद के पैराग्राफ में भी इसका समाधान किया जाए।
622. क्षमता विस्तार के मुद्दे के संबंध में, यह ध्यान दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
623. जैसा कि प्रस्तुति के संबंध में है कि घरेलू उद्योग को कथित रूप से क्षति अन्य कारणों से हुई है और घरेलू उद्योग के घटकों के वार्षिक रिपोर्ट में विवरण के अनुसार कोई क्षति नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां पर किया गया क्षति विश्लेषण यह स्थापित करने के लिए स्व व्याख्यात्मक है कि सम्बद्ध देशों से सब्सिडिकृत आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।
624. सब्सिडी नियमों के नियम 13 क्षति निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित हैं जो निम्नानुसार है:

“13. क्षति निर्धारण

(1) निर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में, नामित प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष निकलेंगे कि भारत में इस प्रकार के वस्तुओं के आयात से भारत में स्थापित किसी भी उद्योग को सामग्री की क्षति होती है या जोखिम होता है, अथवा भारत में एक उद्योग की स्थापना को रोकता है।।

(2) उप-नियम (3) के तहत क्षति की स्थिति को छोड़कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ साथ, नियम के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये क्षति, क्षति के जोखिम, किसी उद्योग की स्थापना के लिए सामग्री की कमी और सब्सिडिकृत आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे।

(3), विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अपवादात्मक मामलों में, क्षति होने के लिये निष्कर्ष निकालेंगे हैं, जहां घरेलू उद्योग का एक महत्वपूर्ण भाग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है -

- (i) एक पृथक बाजार में सब्सिडिकृत आयात की अधिकता है, और
(ii) सब्सिडिकृत आयात से ऐसे बाजार के लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति हो रही है। ”

ज्ञ.संचयी आंकलन

625. नियमों के अनुलग्नक- । पैरा (4) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से एक उत्पाद के आयात पर एक साथ सब्सिडी-रोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आंकलन इस स्थिति में करेंगे यदि यह निर्धारित होता है कि:
- (क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित सब्सिडी की राशि एक प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा नगण्य नहीं है और

(ख) आयात के प्रभावों का एक संचयी मूल्यांकन आयातित उत्पादों और इस तरह के घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के प्रकाश में उचित है।

626. यह नोट किया गया है कि:

- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित सब्सिडी की राशि एक प्रतिशत से अधिक है और
- ख. प्रत्येक सम्बद्ध देश से आयात की मात्रा डि-मिनिमिस से अधिक है और
- ग. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि सम्बद्ध देशों से नियंत न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत किए गए समान वस्तुओं की तरह बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए वस्तुओं की तरह ही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करता है। यह नोट किया गया है कि जो उपभोक्ता घरेलू उद्योग से खरीदी कर रहे हैं वे संबद्ध देशों से भी आयात कर रहे हैं।

627. उपरोक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से सम्बन्धित वस्तुओं के सब्सिडिकृत आयात के प्रभावों का संचयी रूप से मूल्यांकन करना उचित माना जाता है।

II. सब्सिडिकृत आयातों का प्रमात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

I. मांग का आकलन

628. भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्री और सभी देशों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में मांग बढ़ी है। इस प्रकार आंकलन की गई मांग इस प्रकार है-

भारत में मांग	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
घरेलू उद्योग की विक्री	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	119	149
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	104	119
सम्बद्ध देशों से आयात	सीबीएम	1,79,805	2,19,031	3,44,199	2,95,472
इंडोनेशिया	सीबीएम	47,051	37,905	35,953	36,343
मलेशिया	सीबीएम	23,869	46,049	53,447	73,707
श्रीलंका	सीबीएम	23,263	17,247	20,590	13,854
थाईलैंड	सीबीएम	38,764	27,208	70,922	48,352
वियतनाम	सीबीएम	46,859	90,622	1,63,287	1,23,216
अन्य देशों से आयात	सीबीएम	40,015	38,584	40,055	35,855
भारत में कुल मांग	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	132	140

ii. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और आयातों का हिस्सा

629. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, इस तथ्य पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा इसमें उत्पादन या खपत की तुलना में सब्सिडी युक्त आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उसका सारांश में स्थिति नीचे दी गई है:-

आयात की मात्रा	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
संबद्ध देश से आयात	सीबीएम	1,79,805	2,19,031	3,44,199	2,95,472
इंडोनेशिया	सीबीएम	47,051	37,905	35,953	36,343

मलेशिया	सीबीएम	23,869	46,049	53,447	73,707
श्रीलंका	सीबीएम	23,263	17,247	20,590	13,854
थाइलैंड	सीबीएम	38,764	27,208	70,922	48,352
वियतनाम	सीबीएम	46,859	90,622	1,63,287	1,23,216
अन्य देशों से आयात	सीबीएम	40,015	38,584	40,055	35,855
कुल आयातों की मात्रा	सीबीएम	2,19,820	2,57,615	3,84,254	3,31,327
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
आयात	%	81.80	85.02	89.58	89.18
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	164	114
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	145	118

630. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की कुल मात्रा में 2017-18 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान उसमें आंशिक रूप से गिरावट आई है। हालांकि, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2015-16 और 2016-17 की तुलना में वृद्धि हुई है। उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में भी आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

III. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर संबद्ध पर प्रभाव

631. कीमतों पर सब्सिडी-युक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में सब्सिडी-युक्त आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे सब्सिडी-युक्त आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हृद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हृद तक हुई होती।

I. कीमत में कटौती

632. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, कीमत में कटौती क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों की पहुंच कीमत से तुलना करते हुए निर्धारित की गई है। कीमत में कटौती का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक पीसीएन के लिए पृथक रूप से जांच की अवधि के लिए किया गया है और उसके बाद संपूर्ण रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है। उसका सारांश में स्थिति नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./सीबीएम	***	***	***	***
संपूर्ण रूप में संबद्ध देश					
आयात की पहुंच कीमत	रु./सीबीएम	17,061	14,415	13,828	14,294
कीमत में कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	25-35	45-55	55-65	35-45
इंडोनेशिया					
आयात की पहुंच कीमत	रु./सीबीएम	17,824	15,584	14,734	14,821
कीमत में कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	20-30	35-45	50-60	30-40

मलेशिया					
आयात की पहुंच कीमत	रु./सीबीएम	17,076	14,654	15,680	15,907
कीमत में कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	25-35	45-55	40-50	25-35
श्रीलंका					
आयात की पहुंच कीमत	रु./सीबीएम	19,498	18,005	17,511	17,803
कीमत में कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	10-20	15-25	25-35	10-20
थाईलैंड					
आयात की पहुंच कीमत	रु./सीबीएम	15,805	14,001	12,911	12,982
कीमत में कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	35-45	50-60	70-80	50-60
वियतनाम					
आयात की पहुंच कीमत	रु./सीबीएम	16,117	13,246	12,955	13,292
कीमत में कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	35-45	50-60	70-80	50-60

633. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों में से प्रत्येक देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं जो जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से सब्सिडी-युक्त उत्पादों द्वारा उत्पन्न की जा रही कीमत में कटौती को दर्शाता है।

ii. कीमत न्यूनीकरण और ह्रास

634. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या सब्सिडी-युक्त आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा वह कम हो रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी हद तक कीमतें कम होंगी अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएंगी जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में बदलाव पर विचार किया गया है। उसकी स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्रियों की लागत	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	100	107
बिक्री कीमत	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	102	93
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	101	91
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./सीबीएम	17,061	14,415	13,828	14,294
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	81	84

635. उत्पादन की लागत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत से कम है।

इसके अलावा, जबकि घरेलू उद्योग की लागतों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, हालांकि लागतों में वृद्धि के अनुपात में बिक्री कीमत को बढ़ाने की बजाए, घरेलू उद्योग देश में आयातों की कमतर कीमतों पर बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण बिक्री कीमत को कम करने के लिए विवश था। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं और उन पर दबाव पड़ रहा है।

iii. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन

636. संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतों का निर्धारण किया गया है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय करने के लिए आयात की गई वस्तुओं की पहुंच मूल्य से की गई है। कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन का निर्धारण प्रत्येक पीसीएन के लिए और उसके बाद संपूर्ण रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए की गई है।
637. नीचे दी गई तालिका से यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन सकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि आयात क्षतिकारक कीमतों पर बाजार में हुए हैं।
638. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य के लिए क्षति मार्जिन का मूल्यांकन नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

देश	विवरण	क्षति रहित कीमत(एनआईपी)	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		यूएसडॉ./सीबीएम	यूएसडॉ./सीबीएम	यूएसडॉ./सीबीएम	%	%, रेंज
थाईलैंड	वानाचाई ग्रुप पब्लिक कं. लि. और वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि.	***	***	***	***	50-60
	पैनल प्लस कं. लि. और पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि.	***	***	***	***	25-35
	मैट्रो एमडीएफ कं. लि. और एडवांस फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	25-35
	एग्रो फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	1-10
	ग्रीन फाइबर कं. लि.	***	***	***	***	नकारा त्मक
	वाइजवुड्स कं. लि.	***	***	***	***	25-35
	कोई अन्य	***	***	***	***	55-65
मलेशिया	सेगमेट पैनल वोइर्स एसडीएन. वीएचडी	***	***	***	***	30-40
	रोबिन रिसार्सेज (मलेशिया) एसडीएन. वीएचडी	***	***	***	***	35-45
	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50
वियतनाम	एमडीएफ वीआरजी क्यूआंग ट्राई वुड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	15-25
	किम टिन एमडीएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	***	***	***	***	40-50
	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50
इंडोनेशिया	पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबर बोर्ड	***	***	***	***	20-30
	पीटी. मुक्ति पैनल इंडस्ट्री	***	***	***	***	35-45
	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50
श्रीलंका	कोई अन्य	***	***	***	***	15-25

IV. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

639. इस नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, इस नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों, जिसका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, नकदी प्रवाह, मालसूचियों, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का एक वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच क्षति की अवधि के दौरान की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

640. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्रियां और निर्यात के संबंध में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स्थापित क्षमता	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	137	273
उत्पादन मात्रा	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	128	167
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	94	61
घरेलू बिक्रियां	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	119	149

641. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने 2017-18 में और जांच की अवधि में अपनी क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि देश में इस उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को देखते हुए क्षमताएं बढ़ाई गई थी।
- ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्रियों में भी उनकी क्षमताओं में वृद्धि के साथ बढ़ोतरी हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में 2016-17 में वृद्धि हुई, लेकिन 2017-18 और आगे जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई।

ii. बाजार हिस्सा

642. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और क्षति की अवधि के दौरान आयात नीचे दिया गया है:

	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	90	107
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	79	85
संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
अन्य देश	%	***	***	***	***
कुल मांग	सूचीबद्ध	100	100	100	100

643. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में इसकी क्षमता और उत्पादन में वृद्धि के साथ मामूली रूप से सुधार आया है।

iii. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

644. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभ की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्रियों की लागत	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	100	107
बिक्री कीमत	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	102	93
कर पूर्व लाभ	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	107	39
कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	127	58
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	122	71
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	138	86
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	66	24

645. उपरोक्त सारणी से यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग के लाभ में 2016-17 में सुधार आया और तब 2017-18 में उसमें आंशिक रूप से गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई।
- ख. घरेलू उद्योग की पीबीआईटी और नकद लाभ में 2017-18 तक वृद्धि हुई और उसमें जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई।
- ग. निवेश पर लाभ की वही प्रवृत्ति रही जो लाभ की थी। लगाई गई पूंजी पर घरेलू उद्योग का लाभ 2015-16 *** प्रतिशत से 2018-19 में *** प्रतिशत तक कमी आई है। इस कारण से लगाई गई पूंजी पर लाभ में क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

iv. मालसूचियां

646. संबद्ध वस्तुओं की मालसूचियों के संबंध में आंकड़ा नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मालसूची— औसत	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	344	448

उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूचियों में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि के बावजूद क्षति की अवधि के दौरान चार गुना से अधिक वृद्धि हुई है।

V. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

648. क्षति की अवधि के दौरान रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	202	281
प्रतिदिन उत्पादकता	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	119	146
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	64	60
मजदूरी	लाख रु;	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	146	244

649. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

vi. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

650. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने पूंजी निवेश करते हुए इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता में वृद्धि की है। हालांकि, मांग में वृद्धि के बावजूद, इन क्षमताओं का कम उपयोग हुआ है जो संबद्ध आयातों का प्रभाव है। इसने आवेदकों की अपनी पूंजी जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है।

क्षति संबंधी निष्कर्ष

651. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों में स्वतंत्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक हृद तक वृद्धि हुई है। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इसका घरेलू उद्योग की कीमतों पर हासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देशों से उत्तर देने वाले उत्पादकों में से प्रत्येक उत्पादक की कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन भी सकारात्मक है। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को मांग में वृद्धि के बावजूद कम उपयोग की गई क्षमताओं से हानि हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर लाभ में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हृद तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हृद तक वृद्धि हुई है। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

V. कारणात्मक संबंध

652. इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी और वह नीचे दी गई है:-

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

653. अन्य देशों से आयात या तो मामूली मात्रा में अथवा उच्चतर कीमतों पर हुआ है।

ख. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

654. यह नोट किया गया है कि मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत, संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग में क्षति की अवधि के दौरान सुधार दर्शाया है। इसके अलावा, खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ग. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनमें प्रतिस्पर्धा

655. ऐसी कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती थी।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

656. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उस प्रौद्योगिकी, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, में किसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

657. क्षति से संबंधित सूचना पर विचार घरेलू और निर्यातों के लिए पृथक रूप से विचार किया गया है, जिस सीमा तक उसे अलग-अलग किया जा सकता था।

च. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

658. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है।

VI. कारणात्मक संबंध के लिए संगत कारक

659. यह नोट किया जाता है कि:

क. देश में संबद्ध वस्तुओं का आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में कम कीमत पर हुए हैं।

ख. संबद्ध देशों से सब्सिडीयुक्त आयात भारत में बहुत अधिक मात्राओं में हो रहे हैं।

ग. इन आयातों के कारण, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

घ. संबद्ध देशों से सब्सिडीयुक्त आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

ड. लाभ, लगाई गई पूंजी पर लाभ और नकद लाभ में गिरावट सब्सिडी-युक्त आयातों का नतीजा है।

कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

660. नीचे दिए गए अनुसार नोट किया जाता है:

क. संबद्ध देशों से सब्सिडी-युक्त आयातों का आयात भारत में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्राओं में किया गया है।

ख. आयातों के कारण क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है।

ग. घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में क्षमता का उपयोग, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

661. इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को सब्सिडी दिए जाने और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

662. प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण मामले के अनिवार्य तथ्य प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से उन पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए, दिनांक 21.04.2021 को जारी किया गया था। प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हो गए हैं। अधिकतर उठाए गए मुद्दे पुनरावृत्ति के हैं और उन्हें पहले ही उठा दिया गया है तथा उपयुक्त रूप से हल भी कर दिया गया है। संगत मानी गई सीमा तक अतिरिक्त अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

663. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. श्रीलंका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। अतः सब्सिडी मार्जिन पूर्ण प्रकटन के स्तरों पर पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. एफएससी वियतनाम के लिए सब्सिडी मार्जिन प्रकटन विवरण में निर्धारित नहीं किया गया है।

- iii. एस. किजचाई इंटरप्राइज ने प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों की अनदेखी की है और "गोपनीय रूपांतर देखें" कहकर अगोपनीय उत्तर दायर किया। एडवांस तथा मैट्रो द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर बिना उपयुक्त तर्क के अत्यधिक गोपनीय हैं। थमरापल्ली द्वारा आयातक प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर कभी भी घरेलू उद्योग को नहीं दिया गया था। एस. किजचाई, वाइजवुड्स कं. लि. और थमरापल्ली का उत्तर 6 एमएम से कम एमडीएफ के आयातों के विरुद्ध तथा अत्यधिक गोपनीयता के कारण हाल के पाटनरोधी शुल्क जांच परिणामों में रह किया गया था। उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने कुछ कार्यक्रमों का लाभ लिया था और उन्हें भी अपनी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में द्विपाया था।
- iv. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे न्यूजीलैंड से भारत को लॉग्स के निर्यातों की कीमतों को छोड़कर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित विकल्पों पर विचार करें।
- v. केवल थमरापल्ली ने उत्तर दायर किए हैं और उन्होंने अपने उत्तर दायर करने के बाद जांच के प्रति भी कोई प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रयोक्ता ने जांच में भाग नहीं लिया है। भारत में प्रयोक्ताओं से विरोध का अभाव यह दर्शाता है कि वे वर्तमान जांच परिणामस्वरूप अपने ऊपर काफी प्रतिकूल प्रभाव नहीं मानते। इसके अतिरिक्त, उचित कीमत वाले आयातों में प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करना, प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग की क्षमता लेना ग्राहकों के हित में है।
- vi. एनआईपी के बजाए वास्तविक उत्पादन लागत पर विचार करना सीबीडी मामले में यह विचार करते हुए उपयुक्त है कि विचाराधीन मुद्दा निर्यातक देशों द्वारा प्रदान किया जा रहा प्रतिकार योग्य लाभ है।
- vii. विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सब्सिडीरोधी उपाय लगाना घरेलू विनिर्माताओं के हित में होगा। सशक्त, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन लेना अंततः लोक हित में है। संबद्ध सामानों का विनिर्माता उद्योग श्रम गहन, पूंजी गहन है और भारी रोजगार देता है। अंतिम उत्पादों की लागत पर शुल्क का परिणामी प्रभाव काफी नहीं होगा।
- viii. बढ़ते हुए व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा रिजर्व की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर अधिक विश्वास करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, कृषि आधारित होने के नाते इस उत्पाद में कृषक की आय बढ़ाने की काफी क्षमता है।
- ix. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 4, 6, 8, 9 और 10, मलेशिया के लिए कार्यक्रम संख्या 1-6, 8, 10, 11, 16, 17 और 18, श्रीलंका के लिए कार्यक्रम संख्या 1, 3, 4 और 5, थाईलैंड के लिए कार्यक्रम संख्या 2, 3, 8, 10, 11 और 12 तथा वियतनाम के लिए कार्यक्रम संख्या 1 और 2 निर्धारित करें।
- x. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इंडोनेशिया के लिए कार्यक्रम 3 को प्रतिकार योग्य मानें।
- xi. समूह कंपनियों के लिए शुल्क संचित किया जाना चाहिए।
- xii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से सब्सिडी युक्त आयातों के कारण क्षति हुई है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

664. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. कार्यक्रम संख्या 1 और 2 एससीएम करार के तहत प्रतिकार योग्य नहीं हैं क्योंकि डीजीटीआर दोनों प्रकटन विवरणों में यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि इन दोनों कार्यक्रमों में कोई वित्तीय अंशदान शामिल है अथवा क्या उससे जांच की अवधि में इंडोनेशियाई उत्पादकों को कोई लाभ प्रदान किया गया। इंडोनेशिया सरकार की नीतियां इन दो कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत ही सामान्य प्रकृति की हैं क्योंकि इंडोनेशिया सरकार अपने कार्य सरकार के रूप में लागू करती है। इंडोनेशिया सरकार कभी यह निर्धारित नहीं करती कि निजी विक्रेता को अपने रबर वुड किसे बेचने चाहिए, भले ही अकेले कीमत निर्धारित करे। इंडोनेशिया सरकार किसी लेन-देन को पूरा करने में किसी विफलता के लिए कोई प्रतिबंध लागू नहीं करती है, यदि वह वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य न हो; यह संभव है कि कोई लेन-देन न किया जा सके। एलटीएआर एससीएम करार पर सामानों के प्रावधान में एक सरकारी निकाय का अस्तित्व अपेक्षित है जिसे एलटीएआर पर उत्पादन सामग्री प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया जाए अथवा निर्देशित किया जाए, जिसे डीजीटीआर द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता।

- ii. जिसे प्रकटन विवरण में भी इस तथ्य से संबंधित एक भी कारक मूल्यांकन नहीं किया गया कि (1) लॉग्स और वुड्स, (2) लॉग्स और छोड़े गए वुड्स, (3) लॉग और छोड़े गए रबर वुड के बीच अंतर है।
- iii. चूंकि निजी पक्षकारों से रबर वुड की काफी उपलब्धता विद्यमान है, अतः डीजीटीआर को उनकी कीमत पर ही विश्वास करना चाहिए और इसीलिए न्यूजीलैंड को निर्धारण के विकल्प के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकता। अतः डीजीटीआर यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि ये कीमतें इंडोनेशिया सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी अथवा लाभ के परिणाम हैं।
- iv. कार्यक्रम संख्या 3 और 4 में इंडोनेशिया सरकार डीजीटीआर से सहमत हैं कि इन दो कार्यक्रमों के तहत उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों को विरुद्ध कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- v. कार्यक्रम संख्या 5 में मास्टर लिस्ट कार्यक्रम पूरे क्षेत्रों में उपलब्ध है। यह क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अतः विशिष्ट नहीं है और प्रतिकार योग्य नहीं है।
- vi. कार्यक्रम संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 में इंडोनेशिया सरकार डीजीटीआर के इस निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत है कि किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने इन प्रमुख कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है।
- vii. कार्यक्रम संख्या 11क में जांचावधि में इंडोनेशियाई उत्पादकों ने निजी पक्षकारों से अपनी भूमि अर्जित की और इसका इंडोनेशिया सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अतिरिक्त, टंगेरांग में कारखाना कीमतों का निर्धारण उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह जांचाधीन कंपनियों के स्थान से बहुत दूर है जो कि सुमात्रा द्वीप में है। सहयोगी उत्पादकों ने इंडोनेशिया सरकार से कारखाना भूमि नहीं ली और न ही वे इंडोनेशिया सरकार की है।
- viii. कार्यक्रम संख्या 11ख में इंडोनेशिया सरकार का यह अनुरोध है कि जांचावधि में इंडोनेशिया के उत्पादक अपनी उत्पादन प्रक्रिया में कोयले का प्रयोग नहीं करते। पीएलएन पूरे इंडोनेशिया उद्योग और समाज को सार्वजनिक सेवा दे रहा है। यह विशिष्ट उद्योग की सेवा नहीं करता।
- ix. प्राधिकारी अच्छी तरह मानते हैं कि इंडोनेशिया के उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक अपनी उत्पादन प्रक्रिया में कोयले का प्रयोग नहीं करते। तथापि, पीएलएन के लिए कोयला बाजार दरों से कम दर पर उपलब्ध है। यह कार्यक्रम विशिष्ट है क्योंकि कोयले का लाभ केवल इंडोनेशिया में विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध है जिससे अंततः पीएलएन के लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी की दरों पर बिजली देना संभव हो जाता है।
- x. सब्सिडी परिकलन पद्धति पारदर्शी रूप से की जानी चाहिए और डीजीटीआर द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णित की जानी चाहिए और यहां प्रत्येक कार्यक्रम के लिए केवल एक सब्सिडी दर होनी चाहिए।
- xi. संगत आर्थिक मानदंडों की वस्तुपरक जांच यह दर्शाती है कि भारत के घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।
- xii. प्रतिकार उपाय तब तक नहीं लगाए जाने चाहिए जब तक यह निर्धारित न किया जाए कि सब्सिडीयुक्त आयात, घरेलू उद्योग को क्षति और सब्सिडीकृत आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है जिसे साक्ष्यों के साथ दिया जाएगा।
- xiii. बिना कोई प्रक्रिया अपनाए हुए जिस तरीके से नए कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, वह उचित प्रक्रियात्मक पहलुओं का गंभीर उल्लंघन है।
- xiv. कार्यक्रम संख्या 20, 21 और 22 आरंभिक तौर पर याचिका में जांच की शुरूआत की सूचना में सूचीबद्ध नहीं था। मलेशिया सरकार और मलेशियाई घरेलू उद्योग के साथ सही स्पष्टीकरण प्रक्रिया के बिना अतिरिक्त कार्यक्रमों को जोड़ना बाद की बात है।
- xv. डीजीटीआर ने मलेशिया सरकार के उत्तरों की पूर्णतः अनदेखी की और याचिकाकर्ता के टेढ़े-मेढ़े आरोपों और भ्रामक साक्ष्यों का सहारा लिया।
- xvi. मलेशिया सरकार का उत्तर भी यह दर्शाता है कि डीजीटीआर ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सहयोग और उत्तरों की अनदेखी करते हुए मामले के परिणाम में पूर्व निर्णय लिया था।

- xvii. याचिका में पर्याप्त और परिशुद्ध साक्ष्य का अभाव है और डब्ल्यूटीओ एससीएम के तहत निर्धारित कानूनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती।
- xviii. याचिकाकर्ताओं को हुई क्षति स्व-प्रभावित हो सकती है और उसका मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से कोई संबंध नहीं है।
- xix. संबंधित क्षेत्र से विशिष्ट कोई अन्य सब्सिडी योजना नहीं है, अतः अन्य सब्सिडी योजनाओं के तहत उत्तर देने के लिए मलेशिया सरकार के लिए कोई वैध कारण नहीं है।
- xx. इस प्रयोजन के लिए स्थापित 1953 का रबर पुनः पौधारोपण सब्सिडी अधिनियम संख्या 36 स्थानीय रबर उद्योग का विकास करता है और यह कानून श्रीलंका में फाइबरबोर्ड उद्योग की स्थापना से काफी लंबे समय पूर्व शुरू किया गया था। अतः श्रीलंका सरकार इस तथ्य से इंकार करती है कि वर्तमान में प्रचालन में फाइबरबोर्ड उद्योग तथाकथित रबर पौधारोपण सब्सिडी से लाभान्वित है।
- xxi. रबर लॉगस निर्यात करने की लाइसेंस प्रक्रिया 1969 के आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम संख्या 01 के अनुसार श्रीलंका में स्थापित है और श्रीलंका सरकार के आयात एवं निर्यात नियंत्रक द्वारा प्रचालित की जाती है। उपर्युक्त कानून फाइबरबोर्ड उद्योग को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लागू नहीं किए गए थे।
- xxii. इस कानून से श्रीलंका सरकार का एक इरादा देश में अवनीकरण कम करना था, न कि फाइबरबोर्ड उद्योग को लाभ प्रदान करना।
- xxiii. विद्युत को श्रीलंका में एक सार्वजनिक यूटिलिटी माना जाता है और इसीलिए यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को विद्युत की पहुँच हो।
- xxiv. सरकार द्वारा विद्युत का प्रावधान विशिष्ट होना बंद हो गया क्योंकि यह पूरी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त एवं व्यापक रूप से उपलब्ध है, न कि कुछ उत्पादों के उत्पादकों के विशेष सीमित समूहों को लाभ प्रदान करने के लिए।
- xxv. प्राधिकारी ने आरटीजी द्वारा अपने प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना को न तो रिकॉर्ड किया है और न उसका मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी ने जांच के क्षेत्र के अंतर्गत "अन्य सब्सिडी-ऋण" शामिल कर एससीएम करार का उल्लंघन भी किया है क्योंकि प्राधिकारी ने नए सब्सिडी आरोप प्रश्नावली में न तो जांच शुरू की है और न उसे शामिल किया है।
- xxvi. प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण/मात्रा के लिए अपनाई गई निर्धारण कीमत नहीं दी है।
- xxvii. कार्यक्रम संख्या 1-8 विशिष्ट नहीं हैं और इसीलिए एससीएम करार के अनुसार सब्सिडी के रूप में पात्र नहीं हैं।
- xxviii. कार्यक्रम संख्या 1, 3 और 4 में, प्रदान करने के लिए मानदंड पूरी तरह सुरक्षित आधार पर हैं, चुनिंदा युक्तिसंगतता पर नहीं हैं और उद्योग-वार कवर करने के तरीके सभी उद्योगों के लिए खुले हैं तथा विशिष्ट नहीं हैं, अतः प्रतिकार योग्य नहीं हैं।
- xxix. कार्यक्रम संख्या 2 में आरटीजी सशक्त रूप से पुष्टि करता है कि धारा 36 के तहत लाभ एससीएम करार के तहत लागू/उसके अनुसार है। यह प्रतिकार योग्य नहीं है क्योंकि धारा 36 शुल्क वापसी की तरह लागू होती है।
- xxx. कार्यक्रम संख्या 5, 9 और 12 ख में प्राधिकारी ने शुल्क लगाए जाने की सिफारिश न करना प्रस्तावित किया। आरटीजी प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे अंतिम जांच परिणामों में उसकी पुष्टि करें। आरटीजी प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार सूचना/आंकड़े देने के लिए सहयोग एवं प्रतिबद्धता भी प्रदान करता है।
- xxxi. कार्यक्रम संख्या 6 और 7 विशिष्ट नहीं हैं। कंपनियां स्वैच्छिक आधार पर बीओआई निवेश संवर्धन के लिए आवेदन करती हैं। प्राधिकारी ने इन कार्यक्रमों के तहत शुल्क की सिफारिश न करने का प्रस्ताव किया।
- xxxii. कार्यक्रम संख्या 8 भारतीय घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँचाता क्योंकि धारा 34 के तहत संवर्धित क्रियाकलाप से प्राप्त लाभों पर आय कर की छूट का लाभ कंपनी के शेयरधारकों को ही दिया जाता है, न कि कंपनी को। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत शुल्क की सिफारिश न करने का प्रस्ताव किया।

- xxxiii. कार्यक्रम संख्या 10 में एकिजम बैंक बिना किसी विशिष्ट उद्योग के सूक्ष्म उद्यमों, एमएसएमई और थाईलैंड में पंजीकृत बड़े निगमों सहित सभी आकारों के व्यापारों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करता है। प्राधिकारी ने इस कार्यक्रम के तहत शुल्क की सिफारिश न करने का प्रस्ताव किया।
- xxxiv. कार्यक्रम संख्या 11 में प्राधिकारी का मूल्यांकन/समझ पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है क्योंकि एकिजम बैंक इस कार्यक्रम के तहत ऋण प्रदान नहीं करता। इसके बजाए, इस कार्यक्रम में निर्यातों के लिए दीर्घावधि ऋण का प्रावधान है और एकिजम बैंक के कोई भारतीय क्रेता नहीं हैं। प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिकार योग्य नहीं है। आरटीजी प्राधिकारी द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार सूचना/आकड़े देने के लिए सहयोग/वचनबद्धता प्रदान करता है।
- xxxv. निजी स्वामित्व वाले वन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम संख्या 12क में स्टम्पेज/बुड़े टिम्बर का शुल्क देने का दायित्व नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन/निर्यात के लिए वुड/कच्ची सामग्री के रूप में आरटीजी द्वारा कोई वित्तीय अंशदान नहीं है। रबर वुड, नवीकरणीय रबर वुड और यूकेलिप्टस वुड प्रतिबंधित वुड नहीं हैं।
- xxxvi. चूंकि न्यूजीलैंड में वुड और फसल की कीमत सरकार द्वारा विनियमित की जाती है, अतः न्यूजीलैंड से भारत को वुड की निर्यात कीमत एक उपयुक्त निर्धारण नहीं मानी जा सकती।
- xxxvii. कार्यक्रम संख्या 13 में थाईलैंड का प्रान्तीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत उत्पादन प्राधिकरण लाभ पर प्रचालन कर रहा है और इसीलिए लागत से कम पर विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
- xxxviii. प्लाईबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह फाइबरबोर्ड का समान उत्पाद है और यह रेसिन्स एवं अन्य ऑर्गेनिक पदार्थों के साथ बांड करके वुड फाइबर से बनाया जाता है।
- xxxix. याचिकाकर्ताओं ने अपने उत्पादन और बाजार हिस्से के संबंध में कोई समझने योग्य सूचना नहीं दी है और प्राधिकारी ने भारत के घरेलू उत्पादन में उनका हिस्सा भी प्रकट नहीं किया है।
- xli. याचिकाकर्ताओं ने मांग-उत्पादन मात्रा, बिक्री मात्रा आदि जैसे सभी सूचनाओं को गोपनीय होने का दावा किया है और केवल सूचीबद्ध संख्याएं दी हैं।
- xlii. सीबीएम को एमटी में परिवर्तन आयातों की वास्तविक मात्रा और कीमतें नहीं दर्शा सकता क्योंकि सीबीएम और एमटी में परिवर्तन के लिए समरूप संबंध नहीं है।
- xlii. याचिकाकर्ताओं को थाईलैंड से निर्यातों के कारण कोई मात्रात्मक क्षति अथवा कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता बिक्री लागत के अनुरूप घरेलू बिक्री कीमतें करने में सक्षम रहे हैं।
- xliii. प्राधिकारी को एग्रो फाइबर कं. लि. और ग्रीन फाइबर कं. लि. के लिए समेकित मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।
- xliv. प्राधिकारी ने या तो उत्तर से उठाए गए विभिन्न महत्वपूर्ण तर्कों और अनुरोधों पर विचार नहीं किया है या उनके संबंध में कार्रवाई नहीं की गई है।
- xlv. न्यूजीलैंड से लॉग/प्रीमियम वुड की कीमतों का "इंडोनेशिया में रबर वुड वेस्ट" की उपयुक्त कीमतों के निर्धारण के रूप में प्रयोग करने की अनुपयुक्तता, वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में राष्ट्रीय रबर नीति, 2019 वाले शीषिक के अपने दस्तावेज में रबर वुड और टिम्बर वुड में खुद अंतर करने का अनुरोध कराधान होने के नाते कार्यक्रम संख्या 1 की प्रकृति और इस प्रकार वित्तीय अंशदान न होना।
- xlvi. कार्यक्रम संख्या 11 के तहत कृषकों से उत्तरदाताओं द्वारा भूमि की खरीद लागू न होना।
- xlvii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को भारत के डब्ल्यूटीओ दायित्वों, भारतीय सीबीडी नियमावली और प्राकृतिक न्याय के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार उनके अधिकारों और हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने का उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिया।
- xlviii. प्राधिकारी ने वुड भूमि और विद्युत के लिए सब्सिडी मार्जिन का परिकलन करने के लिए विविध उदाहरणों में निर्धारण का प्रयोग किया है। तथापि, उत्तरदाताओं के लिए सब्सिडी मार्जिन का परिकलन करने हेतु प्रयुक्त कोई भी निर्धारण विशिष्ट और बार-बार किए गए अनुरोधों के बावजूद उन्हें प्रदान नहीं किया गया है।

- xlix. प्राधिकारी ने पैरा 41 और 42 में यह उल्लेख किया है कि वे जांच के किसी स्तर पर जांच की शुरूआत की अधिसूचना में शामिल न की गई एक नई योजना जोड़ सकते हैं। यह अनुरोध है कि प्राधिकारी जांच में इस प्रकार की नई योजनाओं को शामिल करने के बाद कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य हैं जिसका वर्तमान जांच में पालन नहीं किया गया था। यहां तक कि नई योजना शामिल करने के बाद भी प्राधिकारी ने निर्यातकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना प्रस्तुत करने, इन योजनाओं के तहत तथाकथित सब्सिडी का खंडन करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया और इन सभी नए शामिल मुद्दों का समाधान करने के लिए सुनवाई का अवसर नहीं दिया।
- i. कार्यक्रम संख्या 1 और 2 प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 70 और 71 में नोट किया है कि चूंकि उत्तरदाता रबर वुड अवशिष्ट/अवशेष का प्रयोग कर रहे हैं, अतः रबर वुड अवशिष्ट/अवशेष की कीमतों की बजाए रबर वुड की कीमतें भास्मक होंगी और इससे गलत परिकलन होंगे। इस करार के बाद भी प्राधिकारी ने न्यूजीलैंड में विद्यमान टिम्बर कीमतों का प्रयोग करने का विरोधाभासी कार्य किया। इस स्वीकृति और बाद में उसके प्रयोग के बावजूद, प्राधिकारी द्वारा परिकलित अनुपात और उस परिकलन का उत्तरदाताओं के साथ साझा नहीं किया गया है।
- ii. प्रकटन विवरण में अपेक्षित देश-वार कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन विश्लेषण निहित नहीं हैं जिसे नियमावली के अनुसार तथा प्राधिकारी की सतत परिपाठी के अनुसार प्रकटन विवरण का भाग होने की जरूरत होती है।
- iii. प्राधिकारी कुछ तर्कहीन, अवैध और गलत समझी गई सोच के आधार पर उत्तरदाताओं के लिए अत्यधिक बढ़े हुए और टेंडर-मेडे सब्सिडी शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। सब्सिडी परिकलन के लिए योजना 1 और 2 को मिलाने का प्राधिकारी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण, अवैध और एएससीएम के विशिष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है क्योंकि योजना 1 और 2 एक-दूसरे से अलग हैं और प्रचालन तथा कार्य में भिन्न हैं, यद्यपि योजना संख्या 1 "एलटीएआर पर खड़े टिम्बर के लिए प्रावधान" के संबंध में याचिकाकर्ता के आरोप से संबंधित है, तथापि योजना संख्या 2 इंडोनेशिया में लॉग निर्यातों पर सरकारी प्रतिबंध के संबंध में है। याचिकाकर्ता द्वारा अगोपनीय रूपांतर में योजना संख्या 1 और 2 को पृथक योजनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उत्तरदाताओं ने भी उनके उत्तर पृथक रूप से दिए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी के लिए सब्सिडी निर्धारण के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त सभी योजनाओं को मिलाने का अवसर नहीं था।
- iv. प्राधिकारी ने उत्तरदाताओं की तुलना में योजना 1 और 2 की प्रतिकार योग्यता का निष्कर्ष गलत निकाला है और गलत निर्धारण की है।
- v. कार्यक्रम संख्या 1 और 2 उन पर लागू नहीं हैं क्योंकि उपर्युक्त योजना टिम्बर प्रयोक्ताओं के लिए विशिष्ट है और उत्तरदाता विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए कर्तव्य खड़े टिम्बर का प्रयोग नहीं करते तथा निजी पौधारोपणों से कच्ची सामग्री अर्थात रबर वुड अवशिष्ट/अवशेष की खरीद नहीं करते।
- vi. इसके अतिरिक्त, इस योजना में इंडोनेशिया सरकार द्वारा किसी वित्तीय लाभ का प्रावधान नहीं है बल्कि इसकी अपेक्षा यह योजना "स्टम्पेज शुल्क" के रूप में कर अथवा राजस्व एकत्रित करने के लिए सरकार को प्राधिकृत करती है। इंडोनेशिया सरकार को देय "स्टम्पेज शुल्क" इंडोनेशिया सरकार द्वारा कराधान है, न कि सब्सिडी का मामला।
- vii. यहां तक लॉग पर निर्यात प्रतिबंध तथा अन्य निर्यात प्रतिबंधों का संबंध है, किसी भी दबाव में निर्यात प्रतिबंध/निषेध को सब्सिडी नहीं माना जा सकता। डब्ल्यूटीओ पैनल में यूनाइटेड स्टेट्स-मीजर्स को निर्यात प्रतिबंधों को सब्सिडी के रूप में मानते हुए इसे पहले ही स्पष्ट किया है (डब्ल्यूटी/डीएस194(आर) जिसमें पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस विवाद में परिभाषित किए गए अनुसार निर्यात प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए अथवा सरकार द्वारा निर्देशित सामानों के प्रावधान उप-पैराग्राफ (iv) के अर्थ में नहीं हो सकते और इसीलिए एससीएम करार के अनुच्छेद 1.1(क) के अर्थ में वित्तीय अंशदान नहीं हैं।
- viii. यहां तक कार्यक्रम संख्या 5 का संबंध है, प्राधिकारी ने यह नोट करने के बावजूद कि ये कार्यक्रम केवल उन उद्यमों के लिए विशिष्ट हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, प्राधिकारी द्वारा यह

- बताने के लिए ऐसी कोई जांच नहीं की गई है कि उत्तरदाता इन मानदंडों को पूरा करते हैं और/ अथवा इस प्रकार के लाभ के लिए पात्र हैं।
- ix. जहां तक कार्यक्रम संख्या 11क का संबंध है, प्राधिकारी ने इस मूलभूत आधार पर प्रतिकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है कि उत्तरदाताओं को "कारखाना भूमि" एलटीएआर पर दी गई थी। इस प्रकार का आरोप जांच के किसी भी स्तर पर आवेदकों द्वारा कभी नहीं लगाया गया था। अतः वर्तमान कार्यक्रम को शामिल करना और उस पर प्रतिकारी शुल्क का प्रस्ताव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सीधे-सीधे उल्लंघन में है।
- ix. उत्तरदाताओं ने निजी पक्षकारों से सीधे ही भूमि की खरीद की है, न कि सरकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। किसानों से भूमि की खरीद का साक्ष्य उत्तरदाताओं द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों के भाग के रूप में पहले ही रिकॉर्ड में रखा गया है। अतः उत्तरदाता के लिए इस स्कीम को प्रतिकार योग्य मानने के लिए प्राधिकारी का पूरा आधार गलत है और योजना संख्या 11क के लिए किसी सब्सिडी मार्जिन की सिफारिश नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, प्रकटन विवरण में इसका कोई कारण नहीं दिया गया है कि कार्यक्रम संख्या 11क किसी उद्यम अथवा उद्योग अथवा उद्यमों के समूह अथवा उद्योगों के लिए कैसे विशिष्ट है। अतः प्रकटन विवरण वर्तमान कार्यक्रम की प्रतिकार योग्यता के संबंध में एएससीएम के अनुच्छेद 2 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करता।
- ix. जहां तक कारखाना भूमि कीमत निर्धारित करने का संबंध है, यह अनुरोध है कि टंगेरांग में कुछ स्वैच्छिक रूप से चुनी गई औद्योगिक भूमि की कीमत उपयुक्त निर्धारण नहीं माना जा सकता। स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों (एफपीएसएस) की हाल में की गई जांच में प्राधिकारी ने भूमि की खरीद के संदर्भ में किसी सब्सिडी मार्जिन की सिफारिश नहीं की है।
- ix. प्राधिकारी ने योजना संख्या 11ख को प्रतिकार योग्य गलत माना है और सब्सिडी मार्जिन का सुझाव दिया जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदकों ने सब्सिडी युक्त दरों पर विद्युत का कोई लाभ नहीं लिया है। इस संबंध में कोई साक्ष्य अथवा औचित्य नहीं है और प्राधिकारी किसी भी साक्ष्य में अपनी टिप्पणी सिद्ध करने में विफल भी रहे हैं।
- ix. एएससीएम के अनुच्छेद 2 के तहत कानूनी मानदंड पूरे नहीं किए गए हैं जिनमें यह अपेक्षित है कि प्रतिकार युक्त किए जाने के लिए किसी कार्यक्रम को "किसी उद्यम अथवा उद्योग अथवा उद्यमों के समूह अथवा उद्योगों के लिए" विशेषतः की जांच प्रणाली की आवश्यकता है। इस संबंध में पैरा 141 में प्राधिकारी का निष्कर्ष यह उल्लेख करते हुए कि कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि कोयला इंडोनेशिया (पीएलएन) में केवल विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, विशेषता के कोई जांच परिणाम नहीं हैं, यथा "कोई उद्यम अथवा उद्योग अथवा उद्यमों का समूह अथवा उद्योग"। जैसा कि अनुच्छेद 2 के तहत अपेक्षित है। इस संबंध में यूएस-अपलैंड कॉटन में डब्ल्यूटीओ पैनल ने उल्लेख किया कि कुछ सब्सिडी व्यापक रूप से उपलब्ध है और पूरी अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है तथा इसीलिए करार के सब्सिडी विषयों के अध्यधीन नहीं है।
- ix. प्रकटन विवरण सब्सिडी मार्जिन का परिकलन करने के लिए निर्धारण कीमतों के स्वैच्छिक स्रोत पर विश्वास करता है और "ग्लोबल पैट्रो प्राइसेस" की वेबसाइट के अनुसार दी गई कीमतों पर विश्वास किया गया। यह दर्शाने के लिए प्रकटन विवरण में कुछ नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना की अधिकृतता और सत्यता का सत्यापन करने के लिए कोई कदम उठाया गया है।
- ix. प्राधिकारी ने जांच की कि पीएलएन को बाजार दरों से कम कीमत पर कोयला उपलब्ध है, यह अनुरोध किया जाता है कि केवल कीमतों पर एक सीमा है जिस पर पीएलएन बिना कोई वित्तीय लाभ प्राप्त किए कोयले की खरीद करेगा। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि कोयले की इस कीमत पर आवश्यक रूप से आपूर्ति की जानी हो। पीएलएन देश में हजारों निजी आपूर्तिकर्ताओं/खननकर्ताओं से कोयला खरीदने के लिए स्वतंत्र है। यह माने जाने की आवश्यकता है कि पीएलएन कोयले का बड़ा क्रेता है और बेहतर कीमतों पर कोयला प्राप्त करने की स्थिति में है। कृपया यह भी नोट करें कि पीटी बुकिट असम के लिए निर्धारित सीमा कीमत भी उत्पादन लागत और मार्जिन के फॉर्मूले पर आधारित है जिसमें 15 प्रतिशत की न्यूनतम राशि और कुल उत्पादन लागत की 25 प्रतिशत अधिक धनराशि में खनन कंपनी का लाभ एवं जोखिम शामिल है। अतः कोयला पीएलएन को बाजार मूल्य से कम पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

- Ixvi. आवेदक को इंडोनेशिया से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है और आवेदक को हुई कोई भी क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है।
- Ixvii. आवेदन पत्र में दी गई क्षति संबंधी सूचना जांच की अवधि के लिए रूशिल डेकर लि. की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए उद्योग अवलोकन से संबंध रखती है जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण आवेदक को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि आवेदकों के क्षमता उपयोग में जांच की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई काफी क्षमता अभिवृद्धि (आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 173 प्रतिशत तक वृद्धि) के कारण गिरावट आई। दूसरे शब्दों में, 180000 सीबीएम से 540000 सीबीएम तक की क्षमता अभिवृद्धि अर्थात् विद्यमान क्षमता के दोगुने से कम उपयोग हुआ है।
- Ixviii. क्षमता की अत्यधिक अभिवृद्धि से मालसूची में भी वृद्धि हुई है।
- Ixix. घरेलू उद्योग की निवल विक्री वसूली में कोई गिरावट आंतरिक प्रतिस्पर्धा तथा बाजार में अत्यधिक आपूर्ति के कारण है। भारतीय उद्योग द्वारा काफी अभिवृद्धि से अंततः एमडीएफ क्षेत्र में कम वसूलियां और काफी मार्जिन दबाव हुआ। तथापि, यह स्थिति प्रकृति में अल्पकालिक है और स्थिति शीघ्र ही स्थिर हो जाएगी।
- Ixx. प्राधिकारी ने सब्सिडी मार्जिन निकालने के लिए परिकलन सिद्धांत और परिकलनों के संबंध में कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं। मैट्रो ग्रुप ने 21 अप्रैल, 2021 के ई-मेल पत्र द्वारा डीजीटीआर से अनुरोध किया कि वे उन परिकलनों को साझा करें। डीजीटीआर ने मैट्रो ग्रुप के लिए पहुँच मूल्य के आंकड़े और वास्तविक सब्सिडी मार्जिन के आंकड़े ही दिए हैं, परन्तु कार्यक्रम संख्या 12(क) के लिए न्यूजीलैंड से वास्तविक बुड उत्पाद, कार्यक्रम 12(क) और कार्यक्रम 13 के लिए सब्सिडी मार्जिन का परिकलन करने हेतु पूरी परिकलन शीट (एक्सल) के साथ सूचना का स्रोत के लिए निर्धारण आंकड़ों के संबंध में सूचना नहीं दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य में यह नोट किया है कि डीजीटीआर के लिए खुद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर गणना किए गए परिकलनों के ब्यौरे प्रकट करना अपेक्षित है और उस सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा नहीं कर सकते। यह सिद्धांत उन मामलों पर भी लागू होता है जहां डीजीटीआर ने इस मामले में, निर्धारण कीमतों और सब्सिडी मार्जिन के परिकलन संबंधी सूचना जैसे अन्य सार्वजनिक स्रोतों से सूचना पर विश्वास करने के लिए मांग की है।
- Ixxi. थाई कार्यक्रम 12(क) पर गलती से प्रतिकार लगाया गया है: कार्यक्रम 12(क) के संबंध में डीजीटीआर का विश्लेषण पहले प्रकटन विवरण की तरह है, मैट्रो ग्रुप ने पहले प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों के पैरा 63-68 में अपने अनुरोधों को दोहराया है। डीजीटीआर पहले प्रकटन विवरण पर मैट्रो ग्रुप की टिप्पणियों में उनके अनुरोधों पर विचार करने में विफल रहा है। मैट्रो ग्रुप ने विशेष रूप से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय रिजर्व बन अधिनियम, 1964 की अनुसूची में निर्धारित 40 भट प्रति क्यूबिक मीटर की सीमा से अनधिक थाईलैंड में रॉयल्टी के संबंध में दूसरे प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 466 (जो पहले प्रकटन विवरण के पैरा 322 के समान है) में डीजीटीआर की टिप्पणी गलत है क्योंकि राष्ट्रीय रिजर्व बन अधिनियम, 1964 में 2016 में संशोधन किया गया था और वर्तमान में टिम्बर रॉयल्टी दर 400 भट प्रति क्यूबिक मीटर है।
- Ixxii. डीजीटीआर अपने विवरण के लिए कोई स्रोत नहीं देता कि न्यूजीलैंड में कीमतें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हैं। किसी भी स्थिति में डीजीटीआर इसका कोई आधार नहीं बताता कि न्यूजीलैंड की बुड चिप्स की कीमतें क्यों थाईलैंड के लिए रबर बुड और यूकेलिप्टस बुड के लिए निर्धारण के रूप में ली जा सकतीं हैं। विशेषकर डीजीटीआर (i) दो देशों के आर्थिक विकास के भिन्न स्तरों के बावजूद उपयुक्त निर्धारण के रूप में न्यूजीलैंड को क्यों लिया जा सकता है; (ii) डीजीटीआर ने रबर बुड के लिए बुड चिप्स की कीमत समायोजित करने हेतु क्या-क्या समायोजन, यदि कोई है, किए हैं, का कोई विश्लेषण नहीं देते हैं।
- Ixxiii. प्राधिकारी 31 मार्च, 2021 को मैट्रो ग्रुप द्वारा दायर उनके अतिरिक्त प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना पर विचार करने में विफल रहे हैं जिसमें खरीदी गई मात्रा, मूल्य और यूनिट कीमत सहित जांच की अवधि के दौरान रबर बुड और यूकेलिप्टस बुड की पूरी खरीद के ब्यौरे हैं और सिद्ध किया कि वह सरकार से अथवा किसी सरकार द्वारा नियंत्रित प्राधिकरण से रबर बुड/यूकेलिप्टस बुड की खरीद नहीं करता तथा उनकी खरीद बाजार दरों पर करता है। प्राधिकारी सीबीडी नियमावली के नियम 18 के अनुसार दूसरे प्रकटन विवरण के भाग के रूप में इस अनिवार्य तथ्य को स्वीकार करने अथवा प्रकट करने में भी विफल रहे हैं। डीजीटीआर ने

सालाना रूप से एक निष्कर्षात्मक विवरण दिया है और कार्यक्रम संख्या 12(क) को प्रतिकार योग्य घोषित किया है तथा परिकलन पद्धति भी नहीं दी है जिसके आधार पर उन्होंने सब्सिडी मार्जिन परिकलित किया।

- Ixxiv. थार्ड कार्यक्रम 13 का गलती से प्रतिकार किया गया है: पहले प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों से अपने अनुरोधों को दोहराता है और यह कि डीजीटीआर सब्सिडी मार्जिन निकालने के लिए अपनाए गए परिकलन सिद्धांत को प्रकट करने में विफल रहा है। कार्यक्रम संख्या 13 के संबंध में डीजीटीआर का विश्लेषण निम्नलिखित कारणों से गलत है:
- Ixxv. डीजीटीआर ने प्रतिकार योग्य सब्सिडी होने के लिए कार्यक्रम 13 के संबंध में कोई साक्ष्य अथवा विश्लेषण नहीं दिया है। उदाहरण के लिए डीजीटीआर ने यह गलत नोट किया है कि लाभ विशिष्ट है क्योंकि लाभ उन उपभोक्ताओं द्वारा लिया जाता है जिन्हें प्रोविंसियल सेवा क्षेत्रों में समान प्रशुल्क नीति दी जाती है। यह गलत है। वस्तुतः कोई समान प्रशुल्क नहीं है और प्रशुल्क कंपनी की किस्म, सेवा की किस्म और व्यस्ततम प्रभारों पर विचार करने के बाद प्रयोग के समय, गैर-व्यस्ततम प्रभारों, मांग प्रभारों आदि पर निर्भर करता है।
- क) प्रोविंसियल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ("पीईए") थार्डलैंड में प्रमुख प्रांतों में विद्युत के सभी प्रयोक्ताओं को विद्युत का एक मात्र आपूर्तिकर्ता और वितरक है तथा रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य यह नहीं दर्शाता कि पीईए से प्रशुल्क सब्सिडी युक्त दरों पर है।
- ख) डीजीटीआर ने अतिरिक्त प्रश्नावली के उत्तर में मैट्रो ग्रुप द्वारा दी गई सूचना सहित उनके पूर्व अनुरोधों पर विचार नहीं किया है कि मैट्रो ग्रुप आस-पास की कीमतों पर विद्युत की खरीद करता है और भारत सहित कई अन्य देशों की परिपाटी की तरह थार्डलैंड में विद्युत प्रशुल्क सांविधिक निकायों अथवा सरकारी प्राधिकारियों द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं तथा प्रशुल्क बाजार दरों पर निर्धारित किए जाते हैं।
- ग) डीजीटीआर इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रयुक्त निर्धारण कीमत को प्रकट करने में भी विफल रहा है कि विद्युत की खरीद बाजार दरों से कम कीमत पर की जाती है अथवा सब्सिडी मार्जिन परिकलित करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है।
- Ixxvi. नए-नए आरोपित सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में सूचना मांगने का नोटिस प्रक्रिया उल्लंघनों का उपचार करने का स्पष्ट रूप से विफल प्रयास था जो कि उन्होंने पूर्व निर्धारित निष्कर्ष में पहले ही किया।
- Ixxvii. मैट्रो ग्रुप ने 31 मार्च, 2021 के अपने उत्तर में डीजीटीआर के दृष्टिकोण को दर्शाया और उल्लिखित किया कि अतिरिक्त प्रश्नावली केवल अंतर्निहित कमी वाली जांच के संबंध में उचित प्रक्रिया की झलक रखने के लिए ही जारी किया गया था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन टोकन के माध्यम से अथवा प्रक्रियाओं का पालन करने की झलक के माध्यम से उपचार नहीं किया जा सकता, जब अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी का पहले ही निपटान हो गया हो। डीजीटीआर का पूर्व निर्धारित दृष्टिकोण इस तथ्य से भी पुष्ट है कि दूसरा प्रकटन विवरण व्यापक रूप से पहले प्रकटन विवरण की पुनरावृत्ति है (कुछ सीमित वृद्धिकारक परिवर्तनों के साथ) और यह कि डीजीटीआर ने मैट्रो ग्रुप द्वारा उनके अतिरिक्त प्रश्नावली के उत्तर में दी गई किसी सूचना पर ध्यान नहीं दिया है।
- Ixxviii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में हार्ड बोर्ड शामिल नहीं है।
- Ixxix. कार्यक्रम संख्या 2: एससीएम करार के अनुबंध-I(i) तथा सीबीडी नियमावली के अनुबंध-3 के भाग-1 के पैरा (i) के अनुसार अनुमति योग्य कर छूट कार्यक्रम है। तदनुसार, कार्यक्रम संख्या 2 प्रतिकार योग्य नहीं है।
- Ixxx. डीजीटीआर को याचिकाकर्ताओं के आधार के संबंध में आधार पर सार्थक टिप्पणी करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए कुल भारतीय उत्पादन आंकड़े और याचिकाकर्ताओं के उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा प्रकट करना चाहिए।
- Ixxxii. डीजीटीआर क्यूबिक मीटर (अर्थात् सीबीएम) में किए जा रहे क्षति मूल्यांकन और थार्डलैंड से विचाराधीन उत्पादों के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति न होने के संबंध में मैट्रो ग्रुप के अनुरोधों को हल करने में विफल रहा।

- Ixxxii. रॉबिन ने रबर वुड का प्रयोग किया और वह एक अधिसूचित वन उत्पाद नहीं है। कंपनी ने बाजार द्वारा निर्धारित कीमत के अनुसार रबर वुड की खरीद की और एससीएम में परिकल्पित कोई सरकारी हस्तक्षेप सिद्ध नहीं था। उचित मूल्य से कम पर वुड एक सिद्ध न की गई टिप्पणी है और प्राधिकारी से कार्यक्रम 20 के तहत मार्जिन रिजर्व करने का अनुरोध करते हैं।
- Ixxxiii. किम टिम के संबंध में, कार्यक्रम संख्या 6, 12 और 13 काफी मार्जिन दर्शाते हैं जिसका इस परिकलन के लिए कोई आधार नहीं है, केवल यही अनुरोध है कि प्राधिकारी परिकलनों की जांच करें। कार्यक्रम संख्या 10 और 11 ने भी कंपनी को कोई लाभ नहीं दिया।
- Ixxxiv. एमडीएफ वीआरजी के संबंध में, कार्यक्रम संख्या 10 और 11 ने कंपनी को कोई लाभ नहीं दिया और वुड बाजार दरों पर खरीदी गई थी।
- Ixxxv. पैनल प्लस और पैनल प्लस एमडीएफ के संबंध में, कार्यक्रम संख्या 12 के तहत पाए गए मार्जिन का कोई आधार नहीं है।
- Ixxxvi. वानाचई ग्रुप और वानाचई पैनल के संबंध में, कार्यक्रम संख्या 12क के तहत पाए गए मार्जिन औचित्यपूर्ण नहीं हैं। कंपनियों ने बाजार दरों पर वुड की खरीद की और किसी सरकार ने उचित मूल्य से कम पर वुड की आपूर्ति नहीं की, जैसा कि एससीएम में परिकल्पित है।
- Ixxxvii. घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के बाद भारी सुधार हुआ है। संबद्ध देशों से आयातों में कीमत में वृद्धि सहित पूर्व वर्ष में जांच की अवधि में गिरावट आई जो सकारात्मक कीमत वृद्धि के साथ आयातों की प्रवृत्ति में गिरावट दर्शाता है।
- Ixxxviii. घरेलू उद्योग द्वारा काफी क्षमता अभिवृद्धि, क्षमता उपयोग का बहुत विवेकपूर्ण स्तर, उत्पादन में वृद्धि, बिक्री में वृद्धि, किसी मात्रात्मक प्रभाव तथा क्षति का अभाव दर्शाते हैं।
- Ixxxix. जांच की अवधि के दौरान कीमत और लाभप्रदता मानदंडों में थोड़ी सी गिरावट किसी भी तरीके से संबद्ध देशों से आयातों की कीमत से नहीं जोड़ी जा सकती।
- xc. याचिका विभिन्न कारक दर्शाती हैं जो कारणात्मक संपर्क के उल्लंघन का साक्ष्य है जिसे प्रकटन में समुचित रूप से हल न करने में विचार नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

665. जहां तक घरेलू उद्योग के इस विवाद का संबंध है कि श्रीलंका के लिए सब्सिडी मार्जिन को पिछले प्रकटीकरण के स्तरों पर फिर से तय किया जाना चाहिए, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उसने समान सिद्धांतों का पालन करते हुए श्रीलंका सहित सभी संबद्ध देशों के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित की है।
666. जहां तक क्षति रहित कीमत (एन आई पी) के बजाय उत्पादन की वास्तविक लागत पर विचार करने का संबंध है, प्राधिकारी ने पिछले एंटी-सब्सिडी जांचों में लागू कार्यप्रणाली के अनुरूप यथासंशोधित अनुबंध-III में एंटी डंपिंग नियमों में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना उचित समझा।
667. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने न तो विभिन्न महत्वपूर्ण तर्कों और अनुरोधों जिन्हें प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए हैं, पर विचार किया है अथवा न ही उसका निपटारा किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान निर्धारण इस अन्तिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में जांच के विभिन्न चरणों में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों के उचित और उपयुक्त विचार पर आधारित हैं। प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से अपर्याप्त सूचना को देखते हुए अनेक स्थानों पर उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करने के लिए विवरण हुए हैं।
668. रबड़ की लकड़ी और टिम्बर की लकड़ी के बीच अंतर के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इंडोनेशिया से उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों ने राष्ट्रीय नीति दस्तावेज़ के संगत पाठ का गलत अर्थ निकाला है। “टिम्बर” शब्द का उपयोग रबड़ की लकड़ी सहित विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के लिए किया गया है। इसके अलावा, उत्तर देने वाले निर्यातकों ने उसे सिद्ध किए बिना अनुमान लगाया है, मानो उनका समग्र उत्पादन रबड़ की लकड़ी के अपशिष्ट/शेष हिस्सों से होता है।

669. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिपोर्ट, राष्ट्रीय कानून, विभिन्न देशों का नीतिगत दस्तावेज़ यह सुझाव देता है कि रबड़ की लकड़ी को टिम्बर के एक हिस्से के रूप में माना जाता है और इसका उपयोग डाउनस्ट्रीम उद्योगों जिसमें फाइबर बोर्ड भी शामिल है, में किया जा रहा है।
670. इंडोनेशिया से “निजी पेड़ों से रबड़ की लकड़ी का अपशिष्ट/शेष हिस्से” के उपयोग के संबंध में उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों के अनुरोध पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने खपत के रिकॉर्ड के रूप में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि इसकी समग्र खरीद निजी पेड़ों से है और इसका समग्र उत्पादन रबड़ की लकड़ी के अपशिष्ट/शेष हिस्से से होता है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि यदि खरीद निजी पक्षकारों से भी होती तब भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक उपाय ऐसे हैं कि वे निजी पक्षकारों को उचित लाभ से कम पर लॉग/लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए निदेश देने/उसे यह कार्य सौंपने के बराबर है।
671. कार्यक्रम सं. 11 के अंतर्गत भूमि की खरीद के संबंध में इंडोनेशिया के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पहले ही उपर्युक्त जांच परिणाम में यह रिकॉर्ड किया है कि कार्यक्रम सं. 11 के अंतर्गत पौधारोपण के लिए भूमि की खरीद पर प्राप्त लाभ को पहले ही कार्यक्रम सं. 1 और 2 में मिला दिया गया है।
672. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किए जाने के दावे के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने तथा अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए जांच के प्रत्येक चरण में पर्याप्त अवसर दिए गए थे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दो मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में दो प्रकटन विवरण जारी किए गए थे। निर्यातकों को अतिरिक्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रथम प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद एक अन्य प्रश्नावली भी जारी की गई थी और उस पर वर्तमान निर्धारण में विधिवत् विचार किया गया है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि नई योजनाओं को जोड़ने के संबंध में सूचना हितबद्ध पक्षकारों को पहली मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोधों के चरण से उपलब्ध थे। हालांकि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उक्त योजनाओं का लाभ उठाने के संबंध में आरोप का उत्तर देने का विकल्प नहीं चुना। हितबद्ध पक्षकारों को दूसरी मौखिक सुनवाई में भी उसके संबंध में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अवसर मिला।
673. प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की वास्तविक सूचना पर आवश्यक सीमा तक विश्वास किया है और उसे प्रकटन विवरण में प्रकट नहीं किया है। प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से प्रकटन विवरण में सभी संगत सूचना और आधार के बारे में बताया है और हितबद्ध पक्षकारों के पास उसके संबंध में टिप्पणी देने के लिए पर्याप्त अवसर था।
674. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया कि अतिरिक्त प्रश्नावलियों को नई योजनाओं पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए दिया जाना चाहिए था। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को जारी की गई मूल प्रश्नावली में अपने आप विशिष्ट रूप से “अन्य सबिसडी योजनाओं” के संबंध में विस्तृत अनुबंध निहित था और यह भी अनुदेश दिया गया था कि यदि कुछ कार्यक्रमों को आवेदक द्वारा सूचीबद्ध भी नहीं किया गया हो लेकिन संबद्ध देश में मौजूद है, उत्तर देने वाला पक्षकार को उनके संबंध में प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर देना चाहिए।
675. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह हितबद्ध पक्षकारों का दायित्व है कि वे अपने आप, इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में संगत सूचना को रिकॉर्ड पर लाएं। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से यह उपर्युक्त नहीं है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों पर टिप्पणी नहीं करते हुए स्वयं संगत सूचना को रोकें और तब उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाएं।
676. इसके बावजूद, प्राधिकारी ने प्रत्येक कार्यक्रम का उत्तर देने के लिए आगे अवसर उपलब्ध कराया, यदि उनमें से कुछ को आवेदक द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया हो और अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के अनुसार संगत अनुबंध के साथ अतिरिक्त प्रश्नावली नहीं भेजी गई थी।
677. इंडोनेशिया के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि वे रबड़ की लकड़ी का अपशिष्ट/शेष हिस्से का उपयोग कर रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसने उस तथ्य का उचित संज्ञान लिया है और नए लॉग की कीमतों से अपशिष्ट/शेष लकड़ी की कीमत के अनुपात के आधार पर लॉग की अनुमानित कीमत पर विचार करने के लिए ऐसे मामलों में इसे उपर्युक्त पाया। इसके बाद इसकी तुलना प्राधिकारी द्वारा

अपनाई गई बेंचमार्क से की गई थी जिसके द्वारा प्राधिकारी ने सब्सिडी का तत्व पाया और इस कारण से उपयुक्त सब्सिडी मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया गया है। जहां कहीं भी निर्यातकों ने चिप का उपयोग एक कद्दे माल के रूप में किया है, प्राधिकारी ने उचित तुलना करने के लिए चिप की बेंचमार्क कीमत का उपयोग किया है।

678. गणना संबंधी पद्धति को प्रकट नहीं किए जाने के तर्के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने किसी विशेष उत्पादक/निर्यातक द्वारा उपयोग किए गए लकड़ी के प्रकार और रूप पर विधिवत् विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एलटीएआर पर लकड़ी का प्रावधान वास्तविक और बेंचमार्क कीमत के बीच अंतर के बराबर लाभ प्रदान करता है जिसके माध्यम से लकड़ी की प्रजातियों का वास्तविक लागत और खपत कारक को अपनाया जाता है, जिसे सब्सिडी मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए उनकी प्रश्नावली के उत्तर में उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
679. देश-वार कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन के संबंध में उठाए गए मुद्दे के बारे में, यह नोट किया जाता है कि उसे पहले ही उपर्युक्त जांच-परिणामों में उपलब्ध कराया गया है।
680. इस आरोप के संबंध में कि प्राधिकारी ने कुछ अतार्किक, गैर-कानूनी और गलत अनुमान के आधार पर प्रतिवादियों के लिए बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर और गलत सब्सिडी शुल्कों का निर्धारण करने का प्रस्ताव किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीवीडी मार्जिन इन जांचों के दौरान गणनाओं और सिद्ध किए गए तथ्यों पर आधारित हैं। तथ्य की गई सब्सिडी मार्जिन वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों से बहुत कमतर है।
681. इंडोनेशिया के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों के इस अनुरोध के संबंध में कि निर्यात प्रतिबंध/रोक को सब्सिडी के रूप में नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया से डायनामिक रेंडम ऐक्सेस मेमोरी सेमिकंडक्टर्स (डीआरएएमएस) पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच-संयुक्त राज्य में अपीलीय निकाय ने इस बात का उल्लेख किया है कि यदि सरकार के पास वित्तीय अंशदान की संभावना अथवा प्रोत्साहन राशि सृजित करने के लिए केवल हस्तक्षेप की तुलना में अधिक सक्रिय और निश्चयात्मक भूमिका हो, तब इसके परिणामस्वरूप इस कार्य को सौंपा अथवा निदेश दिया जा सकता है और फलस्वरूप प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी दी जा सकती है। इस प्रकार यह देखा गया है कि सब्सिडी के रूप में यूएस-निर्यात प्रतिबंधों का निवारण करने के लिए उपाय में विश्व व्यापार संगठन के पैनल का दृष्टिकोण संकीर्ण है जबकि अपीलीय निकाय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिक संगत और उपयुक्त हैं।
682. करखाने की भूमि के लिए भुगतान की गई कीमत की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इंडोनेशिया के निर्यातक तथा सरकार ने न तो प्रतिसंतुलनकारणीयता अथवा कोई तर्क दिया है। हितबद्ध पक्षकारों को भूमि के लिए रियायती कीमत के रूप में सब्सिडी की पहले से ही पूर्ण जानकारी थी। यह निर्यातक द्वारा उपयोग की गई भूमि का केवल एक परिवर्तित रूप है। प्रश्नावली का उत्तर देते समय निर्यातकों ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। घरेलू उद्योग ने सुनवाई पश्चात अपने लिखित अनुरोधों में इस चिंता को प्रकट किया था। निर्यातकों ने अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद किसी भी चरण में कार्यक्रम का लाभ उठाने के संबंध में उपयुक्त रूप से संगत सूचना प्रकट नहीं की है। इस प्रकार, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन जांच परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए विवर हैं।
683. इस तर्क के संबंध में कि पीएलएन को बाजार मूल्य से कम पर कोयला उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह नोट किया जाता है कि इंडोनेशिया की सरकार ने इस बात को माना है कि वह पीएलएन को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। इसके अलावा, बेंचमार्क के साथ कीमत पर विचार करना यह दर्शाता है कि लाभ हुआ है।
684. सब्सिडी मार्जिन की गणना करने के लिए बेंचमार्क कीमतों के लिए एकपक्षीय स्रोत पर विश्वास करने के तर्के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार (घरेलू उद्योग को छोड़कर) ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जिसका उपयोग वर्तमान जांचों के उद्देश्य से बेंचमार्क के रूप में किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों ने अपने आप को प्रतिसंतुलनकारणीयता अथवा लाभ के न होने पर केवल तर्कों तक अपने आप को सीमित रखा। हितबद्ध पक्षकारों से किसी बेंचमार्क सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संगत इनपुट्स के लिए सबसे अधिक उपयुक्त बेंचमार्क पर विश्वास किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्लोबलपेट्रोलप्राइसेस.कॉम वेबसाइट के अनुसार, यह सबसे अधिक व्यापक, विश्वसनीय और अद्यतन सूचना विश्व में खुदरा एनर्जी कीमतों जिसमें मोटर ईंधन कीमत और बिजली की कीमतें शामिल हैं, को प्रकाशित करता है।

बिजली की कीमतों के लिए, ग्लोबलपेट्रोलप्राइसेस.कॉम लगभग 150 देशों में राष्ट्रीय औसत का पता लगाता है। यह बिजली/विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियों/संगठन के कीमत भाव से अंकड़े संकलित करता है और एक राष्ट्रीय औसत निकालता है जिसमें उन कंपनियों/संगठनों के बाजार हिस्से और देश के भीतर क्षेत्रों की सापेक्ष जनसंख्या पर विचार किया जाता है।

685. थाइलैंड के उत्तर देने वाले निर्यातकों के इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान टिम्बर रॉयलटी दर 400 बीएएचटी प्रति घन मीटर है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टंकण संबंधी गलती हुई थी और उसे अब ठीक कर लिया गया है। हालांकि, यह किसी भी प्रकार से इस तथ्य को नहीं बदलता है कि विनियमन और कीमत की उच्चतम सीमा के माध्यम से वानिकी क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप टिम्बर के लिए घरेलू बाजार को गलत तरीके से पेश करता है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कमतर कीमतों पर कच्चे मालों अर्थात् लकड़ी की खरीद करने के लिए थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को अनुमति दी गई है जिसकी चर्चा प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच परिणाम में की गई है।
686. थाइलैंड के उत्तर देने वाले उत्पादक/निर्यातक के इस तर्क के संबंध में कि लकड़ी की खरीद बाजार दरों पर की गई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने सब्सिडी मार्जिन की गणना करने के लिए अतिरिक्त प्रश्नावली के अपने उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़े/सूचना पर विधिवत् विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योगों, जो लाँग का उपयोग करते हैं, के लाभ के लिए लाँग के वास्ते थाई घरेलू बाजार को गलत तरीके से पेश किया है। इस कारण से, लकड़ी जो फाइबर बोर्ड उद्योग में प्राथमिक कच्चा माल है, बाजार दर से कम दरों पर जांच के अधीन कंपनियों को खरीद के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
687. एनटीएआर पर बिजली के लिए उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि थाइलैंड सरकार द्वारा तथा उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उचित लाभ से कम पर बिजली की आपूर्ति के संबंध में किए गए अनुरोधों में विरोधाभास है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अनुसार अपनी जांच को आधारित किया है। इसके अलावा, यह पाया गया है कि प्रांतीय बिजली प्राधिकरण (“पीईए”) थाइलैंड के प्रमुख प्रांतों में बिजली के सभी प्रयोक्ताओं के लिए विद्युत का एकमात्र आपूर्तिकर्ता और वितरक है और प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया बाजार के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और बिजली की घरेलू आपूर्ति को गलत तरीके से पेश करता है। यह कार्यक्रम उचित लाभ से कम पर बिजली के रूप में वित्तीय अंशदान उपलब्ध कराता है।
688. इस तर्क के संबंध में कि एडवांस फाइबर जिसने कार्यक्रम सं. 1 के अंतर्गत लाभ लिया, प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों के संगत पैरा में उसे विधिवत् ठीक कर लिया है।
689. इस तर्क के संबंध में कि वास्तविक सब्सिडी मार्जिन उन कार्यक्रमों के लिए पाया गया है, जिन्हें इन कंपनियों द्वारा विशेषकर लकड़ी, भूमि और बिजली जैसे इनपुट्स पर कथित लाभों के संबंध में कभी भी लाभ नहीं लिया गया है, यह नोट किया जाता है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी ने यह पाया कि लकड़ी, भूमि और बिजली जैसे इनपुट्स उचित लाभ से कम पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कारण से उपर्युक्त बेंचमार्क पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा उसकी मात्रा का निर्धारण किया गया है।
690. उचित लाभ से कम पर भूमि के संबंध में वियतनाम के निर्यातकों/उत्पादकों के तर्क के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह कार्यक्रम वियतनाम में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा खरीदी गई भूमि की बाजार दर और वास्तविक दर के बीच अंतर के बराबर लाभ प्रदान करता है। प्रति वर्गमीटर लाभ की गणना करने के लिए प्राधिकारी ने प्रतिवर्ग मीटर की तुलना बेंचमार्क से की है और इसे किसी विशेष निर्यातक की कारखाना की भूमि के क्षेत्र से प्रति वर्ग मीटर लाभ का गुणा किया है।
691. इस तर्क के संबंध में कि वियतनाम के उत्पादकों/निर्यातकों ने लकड़ी की खरीद बाजार दर पर की है, प्राधिकारी ने यह पाया कि वियतनाम की सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण लकड़ी/टिम्बर/लाँग की घरेलू कीमत को गलत तरीके से पेश करने के लिए अपेक्षित प्रभाव प्राप्त किया और डाउनस्ट्रीम उद्योग के लाभ के लिए इस कीमत को न्यूनतम स्तर तक लाने के अपेक्षित प्रभाव को प्राप्त किया। इस कारण से, लकड़ी जो फाइबर बोर्ड उद्योग में प्राथमिक कच्चा माल है, जांच के अधीन कंपनियों को खरीद के लिए बाजार दर से कम दरों पर उपलब्ध कराया गया है।

692. इस तर्के के संबंध में कि थाइलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार कीमत पर लकड़ी की खरीद की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लकड़ी जो फाइबर बोर्ड उद्योग में प्राथमिक कच्चा माल है, जांच के अधीन कंपनियों को बाजार दर से कम दरों पर खरीदे जाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है।
693. थाइलैंड की सरकार का जांच के क्षेत्र के अधीन “अन्य सब्सिडी – कृष्ण” को शामिल किए जाने के संबंध में तर्के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जांच की प्रक्रिया के दौरान सामने आई किसी सब्सिडी योजना को शामिल करने के लिए इसके पूर्ण अधिकार क्षेत्र में है।
694. क्षति के संबंध में तर्के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अनुरोधों में तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करते हुए, क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है। क्षति के सभी मानदंडों को गिरावट दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि कुछ मानदंड गिरावट को दर्शा सकते हैं जबकि कुछ में सुधार देखा जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति संबंधी सभी मानदंडों पर विचार किया है और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं। घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों जिनका उन उद्योग की स्थिति पर प्रभाव हो, के आलोक में किया गया है।

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

695. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश समानांतर पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद के भाग के लिए किया गया है। इस कारण से प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि (i) सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख(1)(क) और गैट 1994 के अनुच्छेद VI:5 के अनुसार पाटन अथवा निर्यात के लिए सब्सिडी देने की उसी स्थिति की प्रतिपूर्ति करने के लिए किसी भी वस्तु पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क, दोनों नहीं लगाए जाएंगे और (ii) पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दोनों को एक साथ लगाने से क्षति मार्जिन से यह अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत एक कमतर शुल्क नियमावली का अनुसरण करता है, जिसमें यह प्रावधान है कि पाटनरोधी शुल्क और/अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क क्षति मार्जिन के बराबर होगा, यदि इस प्रकार का क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन और/अथवा सब्सिडी मार्जिन से कमतर हो।
696. अतः, उपर्युक्त दोनों अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी ने उसी उत्पाद के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क जांचों के अंतिम जांच परिणामों में नोट किया कि “लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा और भुगतान की जाने वाली प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, यदि कोई हो, के बीच अंतर के समतुल्य है। यदि पाटनरोधी शुल्क भुगतान की जाने वाली प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से कम हो तब अंतर राशि नकारात्मक होगी और ऐसे मामले में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं वसूली जाएगा।
697. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि क्या प्रस्तावित सीवीडी लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह निर्धारण इस उत्पाद के घरेलू उद्योग, आयातकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर सूचना पर विचार किए जाने पर आधारित है।
698. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आमतौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य सब्सिडी लेने की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है, जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।
699. यह मान लिया गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं की लागत प्रभावित हो सकती है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के लगाए जाने, विशेषकर यदि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से सब्सिडी-युक्त संबद्ध वस्तुओं के आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो, कम नहीं होगी। इसके विपरीत, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से सब्सिडी के द्वारा अनुचित लाभ समाप्त होगा और समान अवसर सृजित होगा।

निष्कर्ष और सिफारिश

700. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड(इंडिया) लि. और रुशिल डेकोर लिमिटेड नियम 2(घ) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और वे सीवीडी नियमावली के नियम 6(3) के संबंध में स्थिति के मानदंड को पूरा करते हैं।
 - घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।
 - आवेदकों ने फाइबरबोर्ड पर सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने के लिए वर्तमान जांच दायर की है। आवेदकों ने प्लाईबोर्ड पर सब्सिडीरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए कभी भी अनुरोध नहीं किया है और उसकी सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इस कारण से, वह वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर है।
 - संबद्ध देशों में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी के स्तर पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों में से एक देश की सब्सिडी मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और वह बहुत अधिक है।
 - घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देशों से उत्तर देने वाले उत्पादकों में से प्रत्येक की कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन भी सकारात्मक है। घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को मांग में वृद्धि के बावजूद कम उपयोग की गई क्षमताओं के कारण हानि हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर लाभ में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
 - घरेलू उद्योग को अन्य कारकों की वजह से जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं को सब्सिडी दिए जाने के कारण क्षति हुई है।
 - किसी भी प्रयोक्ता ने सीवीडी शुल्क के प्रभाव के संबंध में कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई है। इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर सीवीडी के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है।
701. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच आरंभ की गई थी और संबद्ध देशों की सरकार सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और सब्सिडी दिए जाने, क्षति और कारणात्मक संबंधों के पहलुओं पर उनके पक्ष में अथवा उनके विरुद्ध सूचना/साक्ष्य देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्धारित नियमावली के संबंध में सब्सिडी दिए जाने, क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच की शुरुआत करने तथा उसे पूरा करने तथा घरेलू उद्योग को इस प्रकार के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण हुई वास्तविक क्षति तथा सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन को सिद्ध करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि सब्सिडी दिए जाने और क्षति के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। इस कारण से, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाए।
702. प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जा रही कमतर शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए सब्सिडी की मार्जिन और क्षति की मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में यथा-

उल्लिखित दरों पर गणना किए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और पाटन रोधी शुल्क, यदि कोई देय है, के बीच के अंतर के बराबर राशि को निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार के द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से ब्रगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	उत्पत्ति का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	मै. वानाचाई ग्रुप पब्लिक कं. लि. और मै. वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि.	18.54
2.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	मै. पैनल प्लस कं. लि. और मै. पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि.	11.47
3.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	मै. मैट्रो एमडीएफ कं. लि. और मै. एडवांस फाइबर कं. लि.	8.29
4.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	मै. एग्रो फाइबर कं. लि. और मै. ग्रीन फाइबर कं. लि.	नगण्य
5.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	मै. वाइजवुइस कं. लि.	13.90
6.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड	थाइलैंड सहित कोई देश	क्र. सं. 1 से 5 के अलावा कोई उत्पादक	27.52
7.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका के अलावा कोई देश	थाइलैंड	कोई उत्पादक	27.52
8.	4411	फाइबर बोर्ड*	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	मै. सेरमेट पैनल बोर्ड्स एसडीएन वीएचडी	10.52
9.	4411	फाइबर बोर्ड*	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	मै. रोविन रिसोर्सिज (मलेशिया) एसडीएन वीएचडी	15.95
10.	4411	फाइबर बोर्ड*	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई देश	क्र. सं. 8 और 9 के अलावा कोई उत्पादक	18.08
11.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका के अलावा कोई देश	मलेशिया	कोई उत्पादक	18.08
12.	4411	फाइबर बोर्ड*	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	मै. एमडीएफ वीआरजी क्यूआंग ट्राई वुड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	14.46
13.	4411	फाइबर बोर्ड*	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	मै. किम टिन एमडीएएफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	12.36
14.	4411	फाइबर बोर्ड*	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई देश	क्र. सं. 12 और 13 के अलावा कोई उत्पादक	19.13

15.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका के अलावा कोई देश	वियतनाम	कोई उत्पादक	19.13
16.	4411	फाइबर बोर्ड*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	मै. पीटी. सुमातेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड	14.77
17.	4411	फाइबर बोर्ड*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	मै. पीटी. मुक्ति पैनल इंडस्ट्री	13.69
18.	4411	फाइबर बोर्ड*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई देश	क्र.सं. 18 और 19 के अलावा कोई अन्य उत्पादक	15.78
19.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका के अलावा कोई देश	इंडोनेशिया	कोई उत्पादक	15.78
20.	4411	फाइबर बोर्ड*	श्रीलंका	श्रीलंका सहित कोई देश	कोई उत्पादक	12.37
21.	4411	फाइबर बोर्ड*	थाइलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और श्रीलंका के अलावा कोई देश	श्रीलंका	कोई उत्पादक	12.37

* तदनुसार विचाराधीन उत्पाद “लकड़ी अथवा अन्य लिग्नियस सामग्री का फाइबर बोर्ड बोर्ड चाहे रेसिन अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थों से जुड़ा हुआ हो अथवा नहीं” है। फाइबर बोर्ड एक प्रकार का इंजीनियर्ड लकड़ी उत्पाद है, जो लकड़ी फाइबर से बनता है। फाइबर बोर्ड के प्रकारों में मध्यम घनत्व के फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) और उच्च घनत्व के फाइबरबोर्ड (एचडीएफ) शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित को बाहर रखा गया है:

- क) फ्लोरिंग बोर्ड्स
- ख) सनमाइका
- ग) इन्सुलेशन बोर्ड
- घ) कयर बोर्ड्स
- ड) जूट फाइबर बोर्ड
- च) मोलडेड डोर स्किन

अ. आगे की प्रक्रिया

703. केन्द्र सरकार के इस आदेश जो इस सिफारिश के कारण हो सकती है, के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 3rd May, 2021

(CASE No. CVD 06/2019)

Subject : Anti-subsidy investigation concerning imports of “Fiberboards” originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam and Sri Lanka.

A. BACKGROUND

F. No. 6/17/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time thereof:

1. Whereas, Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited (collectively referred as “Applicants”), have filed an application on behalf of Domestic Industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for imposition of Countervailing Duty on imports of “Fiberboards (hereinafter referred to as subject goods) from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as subject countries).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/17/2019 - DGAD dated 05th November 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants on behalf of the Domestic Industry, alleging subsidy of ‘Fiberboards’ from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam.
 - b) The Authority notified the Embassies of subject countries in India about the receipt of the anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 6 supra.
 - c) The Authority invited the Government of Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. While consultations were held with the Government of Malaysia (GOM), Government of Indonesia (GOI) and Government of Vietnam (GOV) on 9th, 10th and 11th October 2019 respectively, the Government of Thailand did not avail the opportunity for consultations and Government of Sri Lanka made written submissions. The written submission of representatives of the responding Government of subject countries have been taken on record.
 - d) The Authority issued a public notice dated 05th November 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating countervailing duty/anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - e) The Authority sent a copy of the initiation notification dated 05th November 2019 to the Embassies of subject countries, known producers/exporters from subject countries, known importers/users and the domestic

industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with Rule 7(2) of the Rules.

- f) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of subject countries in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra. Also, in view of the global pandemic and physical inaccessibility, request was made to all the interested parties to share the non-confidential versions of their submissions with other interested parties via email.
- g) The Embassies of subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- h) The Authority sent questionnaires to the Governments of subject countries in order to seek relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred by the Governments. Governments of Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam and Indonesia filed a questionnaire response, which has also been taken into account.
- i) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in subject countries, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - i. M/s. Merbok MDF Lanka Pvt Ltd, Sri Lanka
 - ii. M/s. Dongwa Fibreboard Sdn. Bhd., Malaysia
 - iii. M/s. Daiken Sarawak Sdn. Bhd., Malaysia
 - iv. M/s. Evergreen FibreBerhad (JB) Sdn. Bhd., Malaysia
 - v. M/s. Evergreen FibreBerhad (EFB), Malaysia
 - vi. M/s. Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia
 - vii. M/s. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd.
 - viii. M/s. Advance Fibre Co. Ltd., Thailand
 - ix. M/s. KhonKaen MDF Board, Thailand
 - x. M/s. Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Thailand
 - xi. M/s. Siam Fiberboard Co. Ltd., Thailand
 - xii. M/s. Metro Fiber Co. Ltd., Thailand
 - xiii. M/s. Vanachai Group Public Co. Ltd., Thailand
 - xiv. M/s. Metro MDF Co. Ltd., Thailand
 - xv. M/s. AndalanKarya Bersama PT, Indonesia
 - xvi. M/s. PT Sumatera Prima Fibre Board, Indonesia
 - xvii. M/s. PT Hijau Lestari Raya Fibreboard, Indonesia
 - xviii. M/s. Kim Tin MDF Trading Co., Vietnam
 - xix. M/s. MDF VRG Quang Tri JSC, Vietnam
 - xx. M/s. Hong Duong Bamboo and Rattan Co. Ltd., Vietnam
 - xxi. M/s. Vietnam Wooden Board, Vietnam
 - xxii. M/s. Kim Tin Group JSC Ltd., Vietnam
- j) In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response in the prescribed format:

- i. M/s. PT Mukti Panel Industri, Indonesia
 - ii. M/s. PT Sumatera Prima Fiberboards, Indonesia
 - iii. M/s. Advance Fiber Co. Ltd., Thailand
 - iv. M/s. Metro MDF Co. Ltd., Thailand
 - v. M/s. Wisewoods Co. Ltd., Thailand
 - vi. M/s. Green Fiber Co. Ltd., Thailand
 - vii. M/s. Agro Fiber Co. Ltd., Thailand
 - viii. M/s. Panel Plus MDF Co. Ltd., Thailand
 - ix. M/s. Panel Plus Co. Ltd., Thailand
 - x. M/s. Vanachai Group Public Co. Ltd., Thailand
 - xi. M/s. Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Thailand
 - xii. M/s. S. Kijchai Enterprise, Thailand
 - xiii. M/s. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd., Malaysia
 - xiv. M/s. Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia
 - xv. M/s. MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Co., Vietnam
 - xvi. M/s. Kim Tin MDF Joint Stock Co., Vietnam
 - xvii. M/s. FSC Vietnam Corporation, Vietnam
- k) Pursuant to the initiation notification, apart from the above producers/ exporters from the subject countries, Government of Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam and Indonesia have also filed the questionnaire response.
- l) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
- i. M/s. Ply Point
 - ii. M/s. Jacsons Veneers and Panels P. Ltd.
 - iii. M/s. Label Sales Corp.
 - iv. M/s. Kalinga Imports & Exports P. Ltd.
 - v. M/s. Srivari Traders
 - vi. M/s. Victory Plywood
 - vii. M/s. Thamarappally Brothers
 - viii. M/s. Mathew Sons Exports & Imports P. Ltd.
 - ix. M/s. RJ Metals
 - x. M/s. Feroke Boards Ltd.
 - xi. Krishna Plywoods
- m) In response, M/s Thamarappally Brothers Veneers and Panels Pvt. Ltd. have responded and filed importer's questionnaire response.
- n) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/ submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Later on, due to inaccessibility of public file in the wake of global pandemic of COVID-19, all interested parties were asked to share the non-confidential versions of all their submissions with all other interested parties via emails.

- o) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- p) The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the Anti-Dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- q) Considering the fact that the subject goods are being imported in various grades/sizes/forms, the applicants have proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN-to-PCN comparison for computing the injury margin. After receiving comments on proposed PCN methodology from the interested parties including domestic industry Authority proposed to adopt the PCN methodology as published vide notification 6/17/2019-DGTR dated 20th December, 2019.
- r) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from April, 2018 to March, 2019 as the investigation period, and data/information for the period 2015-16, 2016-17, 2017-18 and the period of investigation as the injury period.
- s) In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 30th July, 2020. All the parties who attended and presented their views in the oral hearings were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to circulate non-confidential versions of their written submissions to opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders thereafter.
- t) In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 22nd January 2021 and the interested parties were allowed time up to 28th January 2021 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in these Final Findings.
- u) Subsequently, another oral hearing was held on 17th February, 2021 in view of the change of the Designated Authority, as per the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07.01.2011. All the parties who attended and presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to circulate non-confidential versions of their written submissions to opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders thereafter. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have also been addressed in these Final Findings.
- v) The Authority issued a letter on 24th March, 2021 to the responding Governments and producers/exporters from subject countries seeking further information on the alleged provisions for goods and services in the subject countries and were asked to provide the information by 31st March, 2021 which was later on extended till 5th April based on the request for extension by few interested parties.
- w) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- x) Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these Final Findings on the basis of the facts available.
- y) Verification of the information provided by the Applicant Domestic Industry by way of table study, to the extent deemed necessary, was carried out. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these Final Findings.

- z) Desk Verification of the information provided by the producers/ exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of these Final Findings.
- aa) A Disclosure Statement was issued to interested parties on 21st April 2021 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 26th April 2021 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.
- bb) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹70.82.
- cc) In these Final Findings ‘***’ represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Anti- Subsidy Rules, 1995.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

The product under consideration in the present investigation is “fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances”, classifiable under classified under heading 44.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
- a) The product under consideration is “fiberboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances”.
 - b) Fiberboards is a type of engineered wood product that is made out of wood fibers. Types of fiberboard include medium-density fiberboard (MDF), and hardboard (high-density fiberboard, HDF). The scope of the product under consideration also includes laminated fiberboard. It is used in building and construction, furniture, industrial, handicrafts purposes, etc.
 - c) Following are excluded from the scope of the product under consideration -
 - a. Flooring boards
 - b. Sunmica
 - c. Insulation board
 - d. Coir boards
 - e. Jute fibre board
 - d) The unit of measurement prescribed by the Govt. is “weight”. The product under consideration is measured in terms of numbers, pieces, Square Meter, Cubic Meter (CBM), Kgs. and MT. Weight has been adopted, with MT as the unit of measurement.
 - e) Hardboard is included in the PUC as seen from the initiation notification. The domestic industry strongly objects to its exclusion. The PUC does not include plyboard. The interested parties have not provided any details on product types not manufactured by the domestic industry. The CESTAT order in Huawei Technologies Ltd. v. Designated Authority is relied on where it was held that it is not necessary for the domestic industry to manufacture each and every grade/type of the PUC.
 - f) There is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The product manufactured by domestic industry is like article to the product imported from subject countries.

C.2. Submissions made by the other interested parties

6. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
 - a) The hardboard is not included within the scope of the PUC since it has not been specified in the Final PCN notification or the Initiation Notification. The Authority stated in the Disclosure Statement that hardboard is within the scope of the PUC which is contrary to the Domestic Industry's position. Hardboard is excluded from the scope of the PUC as evident from the PCN finalized by the Authority. Hardboard is not "like" article to products identified in the PCN. Even the domestic industry has acknowledged the same. A clarity on the same is required.
 - b) The scope of the PUC will include MDF, plywood, and blockboards as long as it is made up of wood fiber. These three are produced by Century Plyboards also. Plyboard should also be included within the scope of PUC as plyboard is like the product to fibreboard and the same is made up of wood fibres bonded with resins and other organic substances. Those sub-categories of fibreboard not produced by the Domestic Industry should be excluded.
 - c) In the previous investigation concerning subject goods, the Indian producers as well as the Authority has adopted weight as the unit of measurement.
 - d) Although prescribed unit is 'weight', custom authorities have cleared goods quantified in weight, cubic meters ('CBM') as well as in weight.
 - e) Authority is requested to confirm CBM as unit of measurement in the present investigation.
 - f) Even the Domestic Industry sells in domestic market using CBM as a unit. Annual Reports of the Domestic Industry show CBM as the unit. Worldwide, CBM is recognized as the unit of measurement.
 - g) Conversion of CBM into MT may not reflect the actual volume and prices of imports since CBM and MT do not have a linear relationship for conversion. Conversion may result into skewed and incorrect assessment.
 - h) Cubic meters have been used as the unit of measurement in a plethora of past investigations by the Authority.
 - i) The Authority has not prescribed any unit in the present investigation. The Authority should use cubic metric as the unit of measurement as in the previous investigations. Although Customs Tariffs Act uses weight, the Indian Customs cleared goods in CBM as well. The domestic producers undertake sales in domestic market in CBM. The Annual Report of the domestic producers uses the same unit. CBM is globally recognized and commercially used. The Authority has prescribed PCN in the present case based on product specifications and not on weight.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority has noted the submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry.
8. The product under consideration (PUC) in the present investigation, is "fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances", Fibreboards is a type of engineered wood product that is made out of wood fibers. Types of fibreboard include medium-density fiberboard (MDF) and high-density fiberboard (HDF).
9. Following are excluded from the scope of the product under consideration
 - a) Flooring boards
 - b) Sunmica
 - c) Insulation board
 - d) Coir boards
 - e) Jute fibre board
 - f) Moulded Door Skin

10. The product is classified under heading 44.11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). The scope of the product under consideration is the products classifiable under following HS codes:

<i>4411</i>	<i>Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances</i>
	<i>- Medium density fibre board (MDF)</i>
<i>4411 12</i>	<i>-- Of a thickness not exceeding 5mm</i>
<i>4411 13</i>	<i>-- Of a thickness exceeding 5mm but not exceeding 9mm</i>
<i>4411 14</i>	<i>-- Of a thickness exceeding 9mm</i>
	<i>- Other:</i>
<i>4411 92</i>	<i>-- Of a density exceeding 0.8 gm/cm³</i>
<i>4411 93</i>	<i>-- Of a density exceeding 0.5 gm/cm³ but not exceeding 0.8 gm/cm³</i>
<i>4411 94</i>	<i>-- Of a density not exceeding 0.5 gm/cm³</i>

11. The subject goods are being imported in various grades/sizes/forms, the applicants have proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN-to-PCN comparison for computing the injury margin. The Authority vide initiation notification requested parties to provide comments on the PCN proposed by the Applicants. After considering the views of the interested parties on the PCN, the Authority vide notification 6/17/2019-DGTR dated 20th December, 2019 finalized the following PCN.

SN	Parameter	Explanation
1.	Density	This refers to the density which belongs to : M : Medium Density Fiberboard H : High Density Fiberboard
2.	Thickness	This refers to range of thickness X : of a thickness not exceeding 5mm Y : of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9mm Z : of a thickness exceeding 9 mm
3.	Plain and Non-Plain	This field represents whether plain and non-plain: P : Plain N : Non-Plain (Laminated or Printed or Painted)
4.	Application Type	This field represents whether it is used for interior or exterior purpose: I : Interior E : Exterior

12. As regards Plywood in the scope of product under consideration, it is noted that the Applicants have filed the present investigation for imposition of anti-subsidy duty on Fibreboard. The Applicants have never requested imposition of anti-subsidy duty on Plyboard and the information of the same is not on records. Therefore, the same is outside the scope of the present investigation.
13. With regard to the argument of Unit of measurement, the Authority for the purpose of present investigation has considered CBM as a unit for measurement.
14. With regard to like article, Rule 2(ca) of the Anti-subsidy Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation."

15. It is noted that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry, and product under consideration exported from subject countries. Subject goods produced by the Indian industry and imported from Malaysia are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-subsidy Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

16. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

- a) Applicant companies' production constitutes more than 50% of Indian production. Accordingly, the applicant companies account for "a major proportion" of Indian production and therefore constitute "Domestic Industry" within the meaning of Rule 2 (b) of the CVD Rules.
- b) Including applicants there are only 9 producers of the subject goods in India. The domestic industry has determined the total Indian Production taking into accounts production of all the 9 producers as per their own information. Following are the only producers of the product under consideration in India.
 - i. Greenply Industries Limited
 - ii. Rushil Decor Limited
 - iii. Century Plyboards (India) Ltd.
 - iv. Action Buildwell
 - v. Shirdi Industries Limited
 - vi. Mangalam Timber
 - vii. Pioneer Panel Product
 - viii. Metro Panels
 - ix. Ranga Particle Board
- c) The applicant companies have neither imported the subject goods nor are related to any exporter or importer of the subject goods in the subject countries and importers in India either directly or indirectly.

D.2. Submission of other interested parties

17. The submissions made by interested parties with regard to the scope and standing of the domestic industry are as follows:
- a) As per the data collected by the Respondents, the production of Applicants is 230k MT only and accounts for 15-25% of the total Indian production.
 - b) The producers of MDF, plywood, and blockboards should be included in the scope of the domestic industry to determine total Indian production.
 - c) Annual Reports of the applicants shows that Indian industry is fragmented and there are multiple new producers. Moreover, certain producers fall in MSME sector, but Applicants have only listed total of 9 producers in India. Authority is requested to include other producers in the scope of DI as well.
 - d) No evidence has been provided to confirm production of other Indian producers. As per para 4.9.16 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations issued by DGTR, the Designated Authority

should independently verify the total domestic production of subject goods in India. The role of the investigating authority in objectively determining total production was emphasized in China – Broiler Products case. Determination of total production should be conclusive and not mere assertion. The Manual of Operating Practices is relied on. Letter of support at a belated stage should not be taken on record.

- e) According to information collected by Thai Government, three domestic producers collectively do not account for a major proportion of total domestic production and does not qualify as Domestic Industry. Applicants' share is only 24.45% as per the Royal Thai Government.
- f) The Annual Report of the Applicants state that the Indian industry is fragmented and has numerous MSMEs. However, the Applicant has claimed that there are only 9 producers of the subject goods in India. The Applicant has failed to account for production of various other producers in India.
- g) The WTO Panel report in China – Broiler Products explained on the role of the investigative authority to objectively determine the total production as well as scope of the DI. The same should be conclusive and not mere assertion. The Manual of Operating Procedures states the DA should independently verify the total domestic production. The Authority is requested to include other domestic producers within the scope of DI. Belated filing of support letters if any should not be taken on record.
- h) Public file maintained by the Authority does not show that the supporting producers have filed the supporting producer's questionnaire. Clarification is required on whether the Authority has considered supporters in the present application.

D.3. Examination by the Authority

- 18. The application has been filed by Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited. As per the evidence available on record, following are the other producers of the product under consideration, who have supported the application and provided details of their production.
 - a) Action Buildwell
 - b) Shirdi Industries Limited
 - c) Mangalam Timber
 - d) Pioneer Panel Product
 - e) Metro Panels
 - f) Ranga Particle Board
- 19. As per the evidence available on record, production of the applicants account for ***% of the total domestic production. Further, as per the available information, the applicants have neither imported the subject goods from subject countries nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in subject countries or any importer in India. Further, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods.
- 20. The Authority, therefore, determines that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rules 2(b) and satisfy the criteria of standing in terms of Rules 6(3) of the CVD Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

- 21. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

- a) Despite the specific instructions, by the Authority mandating exporters and governments to provide a meaningful non-confidential version of the questionnaire response. On failure to provide the same, the information shall be disregarded. In the few cases where information has been provided, the same is excessively confidential. No meaningful summary has been provided to the Domestic Industry.
- b) Questionnaire Responses submitted by parties, Metro and Advance, stand out in terms of exploiting and grossly violating the confidentiality provision. It is seen that entire replies in standard questionnaire have

been claimed as confidential. Domestic Industry fails to understand need for confidentiality in providing details about a subsidy program.

- c) The responding exporters have claimed excessive confidentiality on information which is publicly available. The exporters have not provided meaningful non-confidential summaries to the information claimed confidential. It is requested to the Authority to reject the questionnaire response filed by the above opposing interested parties and base the determination on facts available.
- d) Market share and production have been provided in the NCV as per Trade Notice. The Petitioners are unable to produce production of other producers as it is third party information and DI is not authorised to disclose the same.
- e) On the issue of sharing the DGCI&S data, the decision in Exotic Décor Pvt. Ltd. v DA and Ors, relied on by interested parties, is not applicable to the present case. As held by the SC in DA v. Haldor Topsoe A/S, only those principles of natural justice provided in the statute are applicable. Neither Indian Rules nor WTO law requires data to be given in any prescribed format as long as it is available to interested parties.
- f) On issue of compliance with the Trade Notice 10/2018, the DI includes two producers till 2016-17. Now giving all data would help understand performance parameters of the third producer which is business sensitive.
- g) Market share and production have been provided in the NCV as per Trade Notice. The Petitioners are unable to produce production of other producers as it is third party information and DI is not authorised to disclose the same.
- h) On the issue of sharing the DGCI&S data, the decision in Exotic Decor Pvt. Ltd. v DA and Ors, relied on by interested parties, is not applicable to the present case. As held by the SC in DA v. Haldor Topsoe A/S, only those principles of natural justice provided in the statute are applicable. Neither Indian Rules nor WTO law requires data to be given in any prescribed format as long as it is available to interested parties.
- i) On issue of compliance with the Trade Notice 10/2018, the DI includes two producers till 2016-17. Now giving all data would help understand performance parameters of the third producer which is business sensitive.
- j) The questionnaire responses filed by S. Kijchai and Thamarapally Brothers should be rejected for gross violations of the laws of confidentiality.
- k) The Disclosure Statement issued shows that the responding producers/exporters have availed certain programs but suppressed them in the EQRs. The extend of suppression of information warrants application of adverse facts available and raises questions on adequacy and accuracy of information provided.
- l) The unit of measurement was changed by the designated authority on the argument raised by the interested parties.

E.2. Submissions by other interested parties

22. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

- a) Trade Notice/guidelines/judgments issued on confidentiality for ADD are also squarely applicable in subsidy investigations and the DI be compelled to follow the said guidelines in totality
- b) Applicants have not provided information in the non-confidential version (NCV) as per the Trade Notice 10/2018.
- c) The NCV of the Petition does not allow for a reasonable understanding of the allegations and impairs the ability of the exporters to defend their interests.
- d) Trade Notice is binding on Authority; therefore, Applicants cannot be allowed to act in contradiction to the Trade Notice.
- e) The claim of excessive confidentiality is contrary to Rule 8 of the CVD Rules, principles of natural justice, and binding precedents of the CESTAT and other judicial forums.

- f) Petitioners have not provided any information with respect to their production or market share in Annexure 2.2 of the petition. Aggregate production of DI and share in the market has not been provided.
- g) Trade Notice/guidelines/judgements issued on confidentiality for ADD are also squarely applicable in subsidy investigations and the DI be compelled to follow the said guidelines in totality. Ref: Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority, confidentiality should not be granted automatically and should be based on thorough scrutiny.
- h) Information like demand, production quantity, sales quantity etc has been claimed confidential without which it is difficult for other interested parties to examine the injury parameters.
- i) In present case, confidentiality has been granted by Authority automatically without a thorough evaluation of the information to which the confidentiality claim pertains. Ref: H&R Johnson (India) Ltd. v. Designated Authority, Designated Authority should be satisfied about the confidentiality of the information on the basis of various factors. DS 397 European Communities – Certain Iron and Steel Fasteners, under Article 6.5 of ADA, it is for the party to show good cause for claiming confidentiality and the Authority needs to objectively assess the good cause alleged and further scrutinize the claims.
- j) The principles laid down in Trade Notice 10/2018 shall mutatis mutandis apply to the anti-subsidy investigations as well. The Application is not as per the Trade Notice as applicable for 3 or more producers. The Rules are identical for both Anti-Dumping and Anti-subsidy.
- k) DI used DGCI&S transaction wise data, but the same, as well as segregated data has not been placed in the Public file for inspection. In Exotic Décor Pvt. Ltd. v DA and Ors., it was held that data provided is to be supplied in the same form and manner as filed before the Authority. It has been requested to provide data in excel format as the same is already on record.
- l) Petitioners have not provided the transaction wise import data relied upon. It is unclear whether all the transactions have been included as PUC and non-PUC. Further, the Petitioners have failed to provide segregation methodology.
- m) The Indonesian producers have cooperated with the Authority throughout the investigation and submitted all required information.
- n) Petitioners have revised data from MT to CBM at the fag end of the investigation without providing the non-confidential revised data to other interested parties. Petitioner have never provided volumes and other injury related information in cubic meters.
- o) The claims by the domestic industry on confidentiality claims by the Royal Thai Government (RTG) is baseless. RTG has completely cooperated with the investigation. Metro Group has provided all requisite details and reasons for confidentiality.
- p) The alleged related companies of Kim Tin are only users and not involved in the production or sale of the subject goods.

E.3. Examination by the Authority

23. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

24. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.
25. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
26. As regards M/s S Kijchai's submission of Exporter's Questionnaire Response, it is seen that it has failed to provide a meaningful summary of the confidential submissions in the form of Non-confidential version submitted to the Authority. In the limited summary provided by the company, it has asked to refer to Confidential version for most of the detailed information. Similarly, M/s Thamarappally Brothers Venners and Panels Pvt. Ltd has filed the Importer's Questionnaire Response but has not circulated the non-confidential version to the other interested parties. The Authority notes that such a limited submission and non-circulation has impeded the opportunity for the other interested parties to make meaningful comments on the Exporter and Importer Questionnaire responses filed by the above companies. The Authority, therefore, holds to reject the response filed by the aforementioned companies in view of violation of sub rule 2 of Rule 8 of Anti-Subsidy Rules, 1995.
27. As regards disclosure of DGCI&S data, the Authority's Trade Notice No. 7/2018 dated 15th March, 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for Domestic Industry as well as for other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data by following the procedure prescribed as per the Trade Notice and defend their interests. The Authority thus notes that the procedure being applied is consistent, uniform across investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSION

F.1 Submissions by domestic industry

28. The following submissions were made by the domestic industry:
 - a) Interim duties should be imposed in the instant case for the following reasons:
 - i. Since seeking further information from responding governments and producers and a detailed investigation will be time consuming, it is requested that interim duties be imposed.
 - ii. Average capacity utilisation of the DI declined to 60% in the POI from 109% in 2016-17. It has declined further due to the COVID situation.
 - iii. Imports from the subject countries increased during the POI.
 - iv. Demand has declined to 20% of what it was in the POI. Even after a full recovery from the COVID situation, it is expected to be around 40-60%. This is because the PUC is not an essential good and the decline in buying power.
 - v. Installed capacity in major exporting countries is substantially higher than domestic demand.
 - vi. They also benefit from significant countervailable subsidies exceeding 30% and thus able to reduce prices. With decline in capacity utilisation, the DI is expected to suffer an overall increase in cost of production and will be required to sell at a reasonable price even to recover costs.

- vii. The imports were cheaper than the DI during the POI. Though the DI has to increase prices to recover increasing costs, the DI faces a price pressure from the imports.
- viii. If unprotected for 6 months, the industry will fall into sickness due to outstanding loan of Rs. 1000 crores and cumulative wage bill of Rs. 750 crores.
- ix. Low capacity utilisation will lead to low RM usage and thus impact livelihood of farmers.
- b) The Sri Lankan exporters should be held non-cooperative due to their failure to file Questionnaire Responses.
- c) The ASCM only requires the Applicant to produce reasonably available evidence at the time of filing Application. WTO Panel Report in China- Flat rolled electrical steel from US (DS 414) is relied on. The Applicant has produced all evidence available in the public domain and the same was scrutinised by the DA. Pre-initiation consultation with governments of subject countries was also conducted.
- d) With regard to FSC's claim that they do not export to India and hence the investigation is not applicable to them, the questionnaire instructions state that the Company is supposed to reply to the extent it relates to them.
- e) A single subsidy margin and injury margin should be granted to individual companies related to each other. The following should be treated as a group: (a) Vanachai Group and Vanachai Panel (Thailand), (b) Panel Plus Co. and Panel Plus MDF (Thailand), (c) Kim Tin and FSC (Vietnam), and (d) Green Fiber and Agro Fiber (Thailand). Even if no margin is quantified for FSC, Kim Tin's margin should be cumulated with it.
- f) Only one importer filed a questionnaire response and showed no commitment to the investigation post filing of response. Further, no users participated in the investigation. The absence of participation and questionnaire response from users show that they are not adversely impacted by the present investigation.
- g) The imposition of countervailing duty is in the interest of the domestic manufacturers as it will arrest the decline in performance of the industry and redress injury suffered. It would also be in the interest of consumers as it is in the interest of consumers and public at large that a competitive domestic industry exists. Not protecting the domestic industry would directly jeopardize investments and lead to unemployment of many. The eventual impact on end products will be insignificant. Due to widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to rely more on domestic production capacities. The domestic industry directly and indirectly creates 20,000 to 25,000 employment and has significant potential to increase farmers' income.
- h) The injury to the domestic industry is due to low priced imports. The domestic industry is unclear on the extent to which low prices is due to dumping and due to subsidies within the overall injury margin. The domestic industry has not sought relief beyond the injury margin. Dumping or subsidy need not be the only cause of injury suffered by the domestic industry. There is no bar on simultaneous AD and CVD investigations. The CESTAT order in Suncity Sheets Pvt. Ltd. v. Union of India, later upheld by the Supreme Court, is relied on.
- i) The present investigation being a fresh investigation should be restricted to the POI only. The Authority does not examine post-POI. Raising arguments on post-POI at such a belated stage shows malafide intention of the interested parties. The post-POI information on record in the AD investigations on Thick MDF and Thin MDF shows domestic industry is suffering injury even in post-POI.

F.2 Submissions by other interested parties

29. The following submissions have been made by other interested parties;
 - a) Application lacked any evidence showing that the alleged subsidies were being availed by the producers/ exporters.
 - b) Policy documents alone cannot be construed as reliable evidence to justify the existence of a subsidy being availed by the producers/ exporters.
 - c) Initiation of CVD investigation without such evidence goes against Article 11 of the ASCM and Rule 6 of the CVD Rules.

- d) Existence of a program cannot be treated as existence of countervailable subsidy unless countervailability is proven.
- e) The Petitioner claims the subsidy margin is substantial and quantifies them for each country without explaining the basis of the calculation. The Petitioner has also admitted in the petition on p. 52 that the subsidy margins are not precisely quantified.
- f) The initiation of the investigation has mischaracterized and misinterpreted the Trade Policy Report especially with regard to log export ban and investment and taxation regulation on the Indonesian fiberboards industry. The initiation does not satisfy the requirements under Article 11.1, 11.2 and 11.3 of the ASCM.
- g) Evidence from past anti-subsidy investigations in other jurisdictions cannot automatically apply in this investigation especially when there is a different product in this investigation.
- h) The applicant had not submitted sufficient evidence of injury and causal link for initiation of investigation.
- i) Request for interim duties due to violation of Rule 10 of Questionnaire by Indonesian exporters is baseless and without merit. The claim under low-capacity utilization is baseless, and misleading. The claim on increased imports is misleading and wrong since Sri Lanka was wrongly included in cumulative assessment despite de minimis imports and since Indonesian imports declined significantly in the POI. The claim under likely decline in demand is without any evidence and likelihood analysis has no relevance. The claim of significant countervailable subsidy exceeding 30% is without any support of facts and evidence. The claim based on dependence of farmers is not appropriate since there is no public interest clause in the anti-subsidy rules.
- j) The claim for interim duties is not warranted since it is based on temporary adversities due to huge capacity additions. There is no reduction in production. Reduction in capacity utilization is due to capacity additions, and trends in imports have no correlation to the financial situation of the DI. DI has failed to show any serious injury on account of alleged subsidized imports.
- k) The Applicants have failed to provide any additional and relevant fact warranting recommendation of provisional duties. The Applicants have failed to demonstrate the instant case is “appropriate” for the same.
- l) The subsidy claims made by the Applicant in the present investigation are mere assertions which are unsubstantiated with documentary evidence. The same does not meet the requirement for initiation under the ASCM. The WTO AB Report in US – Large Civil Aircraft (2nd complaint) is relied on.
- m) The subsidy margins should not be cumulated by merely adding individual subsidy margins. The same should be on the basis of weighted average method.
- n) Since FSC has not exported the subject goods to India, the margins should not be cumulated.
- o) Imposition of duties will impact cost of production for downstream industry and affect their profits and performance during time of COVID-19 pandemic. They also make the downstream Indian product uncompetitive to global producers leading to increase of their imports.
- p) There is no reason for the non-application of Annexure III for the calculation of NIP.
- q) Any imposition of CVD would be harmful to the interest of the country as it will result in unreasonable profits for the DI and the burden will fall on the consumers.
- r) In a parallel SSR investigation, the Applicants claimed that injury is due to dumped imports from China, Malaysia, Thailand and Sri Lanka. As per DI, injury is not attributable to the alleged subsidy from subject countries alone.
- s) The steep increase in the profits of DI during the post POI period even without CVD should be considered while examining causal link. This shows that the pressure on the DI was due to slowdown in real estate and the same has started to mitigate. It would be unfair and against public interest to impose CVD when the situation has improved. The Authority is not barred from examining post-POI data. The quarterly results of Century MDF Division and Greenply are relied on.

F.3 Examination of the Authority

30. As regards adequacy and accuracy of the petition, the same has been analysed by the Authority at the stage of initiation and the Authority found that there is *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject countries and such subsidized imports are causing material injury to the domestic industry through their volume and price effects.
31. As regards interim duties, the same has not been recommended in view of the facts and circumstances of the present case.
32. As regards conducting parallel anti-dumping and anti-subsidy investigations, the Authority notes that there is no bar in conducting such parallel investigations.
33. As regards argument of considering information for post period of investigation, it is noted that the present investigation being a fresh investigation, there is no requirement of considering post period of investigation information.
34. As regards argument regarding cumulation of margins of related companies, it is noted that it is an established practice of the Department that margins of the individual related companies are cumulated for the Group Companies.

DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

35. The petition filed by Domestic Industry provided *prima facie* evidence of existence of countervailable subsidies in the subject countries to initiate the instant investigation. Consultations were held with the Government of Indonesia, Malaysia, and Vietnam on 10th Oct 2019, 9th Oct 2019 and 11th Oct 2019 respectively. The Government of Thailand did not avail the opportunity for consultation. The Government of Sri Lanka availed the opportunity for pre-initiation consultations by only making written submissions. The producers and exporters from Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, and Vietnam were advised to file responses to the questionnaire and were given adequate opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
36. The Government Questionnaire Responses have been filed by Governments of Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and Sri Lanka.
37. The following producers/exporters from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam have filed Exporter's Questionnaire Responses:
 - i. M/s. PT Mukti Panel Industries, Indonesia
 - ii. M/s. PT Sumatera Prima Fiberboards, Indonesia
 - iii. M/s. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd., Malaysia
 - iv. M/s. Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia
 - v. M/s. Advance Fiber Co. Ltd., Thailand
 - vi. M/s. Metro MDF Co. Ltd., Thailand
 - vii. M/s. Wisewoods Co. Ltd., Thailand
 - viii. M/s. Green Fiber Co. Ltd., Thailand
 - ix. M/s. AgroFiber Co. Ltd., Thailand
 - x. M/s. Panel Plus MDF Co. Ltd., Thailand
 - xi. M/s. Panel Plus Co. Ltd., Thailand
 - xii. M/s. Vanachai Group Public Co. Ltd., Thailand
 - xiii. M/s. Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Thailand
 - xiv. M/s. S. Kijchai Enterprise, Thailand
 - xv. M/s. MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Co., Vietnam

- xvi. M/s. Kim Tin MDF Joint Stock Company, Vietnam
- xvii. M/s. FSC Vietnam Corporation, Vietnam
38. None of the producers/exporters of the subject goods from Sri Lanka have filed Exporter Questionnaire's Response.

G. General overview of the alleged Subsidy Programs

G.1. Submissions made by domestic industry

39. The following submissions were made by the domestic industry:

- i. The evidences for countervailability of the alleged subsidy programs have been provided in the detailed one pager. All parameters as per the ASCM and Indian CVD Rules have been met.
- ii. Various investigating authorities have found that the forestry sector of the timber industry in Indonesia is within the control of the government and prices of wood products are unfairly low due to this government intervention. Since the raw material used in both the paper industry as well as fiberboard industry are similar, i.e., "timber", the cases on paper industry are relevant to the present investigation.
- iii. As per evidence collected by the domestic industry, rubber wood prices cannot be less than USD 54.02/MT during the POI.
- iv. The following are to be considered as "facts available" for the alleged subsidies from Indonesia. For Program No. 1 and Program No. 2, the Government of Indonesia (GOI) have subsidised the price of the essential input, i.e., wood/ logs. The term "timber" under Program No. 1 & 2 for Indonesia is not limited to any specific type of wood. Rubber wood falls within the scope of the same.
- v. The PUC cannot be produced using rubber wood waste or fiber or paper as claimed by interested parties. They are revising their submissions and making misleading and false statements.
- vi. Though raw materials may be purchased from private plantations, the level of government distortion leaves the timber market in Indonesia distorted. The dominant role played by the government artificially lowers the market prices. The US DOC's analysis in 'Coated Free Sheet Paper from Indonesia' and 'Certain Uncoated Paper from Indonesia'.
- vii. Program No. 3 is available to all exporters. The scheme was held countervailable by the Authority in the Copper CVD case. Para 61 of the Disclosure Statement shows PT Bank Negara is a public body. The other interested parties are making false and misleading statements. For Program No. 3 for Indonesia, the exporter had the opportunity to suggest appropriate benchmark. Considering the suppression of facts, the Authority is entitled to apply facts available. Preferential lending is practiced irrespective of the currency. Such interest rates are lower than those prescribed by IMF, World Bank and Central Bank of the countries.
- viii. The Authority in previous CVD investigations in copper wire rods, tempered glass, float glass, and stainless steel found export facilitation provided by the EXIM bank to be countervailable. Non-availment of a program does not make it non-countervailable.
- ix. The responding producers/exporters have acknowledged that they are availing the benefit under Program No. 5. The program was held countervailable in the Copper CVD case. Program No. 6 was also previously held countervailable in the Copper CVD case. The GOI has failed to provide relevant legislations for the program.
- x. Program No. 7 is not permissible as per footnote 1 to the ASCM and hence, prohibited. The same was found countervailable in the Copper CVD case.
- xi. The GOI as well as the responding producers/exporters have failed to acknowledge and provide relevant information on the provision of land and electricity at LTAR. The Applicants have submitted relevant information and evidences for the same.

- xii. The responding producers/exporters from Indonesia have not responded to the Standard Questions for Program No. 1. No evidence has been provided for using private plantations. The GOI rubber subsidies and AETS also makes raw material, i.e., wood cheaper.
- xiii. None of the responding producers/exporters have responded to the Standard Questions for Programs No. 2, 3, 4, 6, 8, and 9. No evidence has also been produced to show non-availment of these programs.
- xiv. For Program No. 10 as raised by the GOI, Sumatera has not responded to the Standard Questions. Additionally, Mukti denies availing the benefit under the program while GOI states that they have availed the benefit. The Authority is requested to verify the claim by Mukti Panel that Government of Indonesia has clarified the non-availment of Program No. 10 for Indonesia. The said letter was not provided to the domestic industry.
- xv. The responding producers/exporters from Indonesia have denied any impact on domestic prices by the log export ban. This cannot be true.
- xvi. GOI and responding producers/exporters from Indonesia have not denied the existence of the export ban. The Applicant does not claim the ban itself is a countervailable subsidy but that it has distorted domestic prices, thus providing logs at LTAR.
- xvii. The responding producers/exporters have provided incorrect information about Program No. 1. Since 88% of land is owned by the government and wood supplied is subsidised, it is nearly impossible that the program was not availed. The scheme was found countervailable in the following investigations by the US Authority: Certain Lined Paper Products from Indonesia and Certain Uncoated Paper from Indonesia. The case regarding the paper industry is relevant to the instant case since the raw material is the same. The GOI acknowledged in Certain Uncoated Paper from Indonesia that standing timber is provided to the furniture industry.
- xviii. As per Article 33(3) of the Indonesia Constitution, the land is controlled by the government which is provided to companies at LTAR.
- xix. Electricity in Indonesia is heavily subsidized by Ministry of Finance Regulation No. 44 of 2017 which allows consumers to purchase electricity from PLN at LTAR. The Government of Indonesia retains the right of export of coal, export tax, and maintains domestic market obligations. A benchmark price for coal was also put in place for PLN. The final finding in the CVD investigation on imports of “flat products of stainless steel” from Indonesia is relied on.
- xx. The domestic industry calculated the subsidy margin using export price of bituminous coal for the rest of the world in 2018-19 as per trade map as the benchmark.
- xxi. The subsidy on land for plant/manufacturing unit is required to be quantified under Program No. 11 for Indonesia. The Authority has considered the most conservative benchmark for the same.
- xxii. The *de-minimis* rule is not applied on a program-wise basis but on an exporter-wise basis.
- xxiii. The Government of Malaysia (GOM) has failed to list out Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), the Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank), and the East Coast Economic Region Development Council as administering authorities and the source for identification of producers/ exporters of the PUC from Malaysia. Several relevant information and annexures as required by the Questionnaire has not been provided by the GOM.
- xxiv. Neither the GOM nor the responding producers/exporters have acknowledged or provided any relevant information regarding the provision for standing timber for LTAR, the Government prohibition on log exports, and the Provision for Land and Electricity at LTAR. The Applicants have provided relevant information and evidence for the same.
- xxv. The responding producers/exporters from Malaysia have not provided any reasons for the non-availment of Programs No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/13, and 11.
- xxvi. Additionally, for Program No. 5, Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. (SPB) has not provided reasons for non-availment while Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. has replied to the wrong program.

- xxvii. Programs No. 6 and 7 for Malaysia has already been held countervailable by the Authority in the Copper CVD case.
- xxviii. Program No. 9 for Malaysia is specifically beneficial to sectors having high capital expenditure. For Program No. 9, SPB has not provided Standard Questions Annexure in NCV. They have also not answered Average Useful Life Annexure and the Allocation Annexure. Further, SPB has not provided reasons for the non-availment of Program No. 14 despite incurring eligible expenses.
- xxix. While Robin has not provided reasons for non-availment of Program No. 16, Robin has not replied to the Standard Questions Annexure.
- xxx. SPB has failed to even acknowledge the existence of Program No. 19 – Investment Tax Allowance that was acknowledged by the GOM.
- xxxi. As per the website information of responding producers from Malaysia, rubber wood & tropical mixed wood are used as raw material for the production of the PUC.
- xxxii. The government provides a replanting subsidy to support rubberwood plantation and dependent industries. The government has also maintained a ban on exports of rubberwood.
- xxxiii. Rubberwood is not specifically excluded under the definition of “forest produce” as per the National Forestry Act. If no royalty is charged on rubberwood, as per the interested party, it further proves subsidies.
- xxxiv. With regard to electricity at LTAR, the prices of natural gas, which is the primary source of power in Malaysia, are statutorily regulated for electricity sector. Hence, power is available to producers of the PUC at LTAR. The same was examined in previous investigations on “float glass” and “tampered glass” and found countervailable.
- xxxv. The domestic industry has calculated the subsidy margin with export price of liquified natural gas for rest of the world in 2018-19 as per trade map as the benchmark.
- xxxvi. The Government of Thailand has not provided information on amount of financial contribution provided under Programs No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 8. Additionally, for Programs No. 1, 2, and 3, the relevant Tax Annexure has also not been answered. The GOT response to Program No. 9 is grossly incomplete. A complete Standard Annexure has not been provided by the GOT for Programs No. 10 and 11. The relevant Annexures are also not answered.
- xxxvii. Program No. 1 for Thailand is limited to promoted activities and found countervailable in the Copper CVD case.
- xxxviii. The USDOC in the CVD investigation on Hot Rolled Carbon Steel Flat found all subsidies under the Investment Promotion Act to be countervailable.
- xxxix. The benefit under Program No. 2 for Thailand is available to all companies holding a BOI certificate. Moreover, the Authority in the CVD investigation on Copper wire rod found that the Government of Thailand could not provide an explanation or evidence to show how the mechanism to ensure no excess benefit is provided operates. The DGTR may diverge from views of other foreign authorities based on their factual conclusions.
- xl. Program No. 4 for Thailand, is specific because it is available only for promoted activities. Carry forward can be a financial contribution because if a company makes a loss, the benefit can be availed in the subsequent periods. Program No. 6 is also only available for promoted activity and hence specific. Program No. 8 provides that dividend is exempted from income tax and hence, a financial contribution is provided.
- xli. Programs No. 1 to 8, which are administered by the Board of Investment of Thailand, have been previously held countervailable by the Authority in the Copper CVD case. The programs are specific as it is provided only for promoted activity.

- xlii. Agro Fiber, Advance Fiber, Metro M.D.F., Panel Plus MDF, S.P.B. Panel, S. Kijchai, Vanachai Panel Industries and Vanachai Group hold BOI certificates. Though available in public domain, it is claimed confidential by the GOT.
- xliii. Advance Fiber, and Wisewoods expanded their capacities in 2017. Panel Plus Group expanded their capacities in 2016. Vanachai Panel expanded its capacity in 2019. They should have availed the relevant subsidies. It is either restricting information to the POI or misleading the Authority.
- xliv. Neither the GOT nor the responding producers/exporters from Thailand have acknowledged or provided information on the provision for raw material (wood) and land at LTAR, and provisions for electricity at LTAR. The Applicant has submitted relevant information and evidences regarding the same.
- xlv. As per the website information of responding exporters from Thailand, rubber wood or eucalyptus is used as raw material for the PUC. The government of Thailand has taken the responsibility of planting rubberwood and collaborated with the Rubber Research Institute of Thailand and Royal Forest Department's Forest Research Institute to produce clones suited for timber production. The Authority needs to investigate the prices at which the producers/exporters procure the same.
- xlvi. The domestic Thai market for timber is distorted due to government control and logging licenses provided on levy of royalty which is not based on market principles and allows procurement of raw material at LTAR. Hence, it doesn't matter if the source of the raw material is state forest or private land.
- xlvii. The term ‘prohibited wood’ is not defined under National Reserve Forest Act, 1971. However, the term “wood” includes “all kinds of wood”. Thus, rubberwood is within the scope of the legislation.
- xlviii. Out of all the responses filed by the responding producers/exporters from Thailand, no information was filed in 184 cases and information is inadequate in 9 cases.
- xlix. Vanachai Group, Vanachai Panel, Metro, Advance Fiber, Wisewoods, Panel Plus, S. Kijchai, and Agro Fiber hold BOI certificates. Unless evidence to the contrary is provided, it should be held that they have availed Programs No. 1 to 8 as they are all under the BOI. Programs No. 1 to 7 were held countervailable in the Copper CVD case.
- l. The responding producers/exporters have expanded capacities or added new plants during the AUL period and hence should be held that they have availed programs providing import duty exemptions on capital goods. They have maliciously claimed to be not availing them. Panel Plus, Wisewood, S. Kijchai, Advance Fibre, Vanachai Panel, FSC, Kim Tin MDF Joint Stock Co., and Sumatera have all set up new plants or expanded capacities.
- li. Though the responding producers/exporters from Thailand argue that the subsidy was received for the Company as a whole and not the PUC alone, the programs are of such a nature that the benefit would flow to the PUC. Further, money is fungible and the company can use how they desire. In a CVD investigation, the company as a whole is the subject of investigation and not just the product. The US PSF case against India is relied on.
- lii. The Authority needs to investigate provisions for land prevailing in Thailand. The analysis of the Authority for Program No. 12 in the Disclosure Statement is not contradictory. The other interested parties are confused on the analysis of wood at LTAR with land at LTAR.
- liii. The Government of Vietnam (GOV) failed to mention the General Department of Vietnam Customs, the Provincial Tax Departments, the Local Tax Authorities, and the Vietnam Development Bank as administering authorities. GOV has claimed certain webpages as confidential. These are violations of Section A, Point 5 of the guidelines under the Questionnaire. Relevant information to various questionnaires has not been provided by the GOV.
- liv. No specific replies have been provided by the GOV for Programs No. 8, and 9.
- lv. Neither the GOV nor the responding producers/exporters have acknowledged and provided relevant information on provision for timber at LTAR, Government prohibition on log exports, land

- preferences for encouraged industries or industrial zones under Decree 142, and provision for land at LTAR. The Applicant has provided relevant information and evidences in this regard.
- lv. For Programs No. 1 and 2 for Vietnam, none of the responding producers/exporters have responded to the Standard Questions. Program No. 1 was already found countervailable in the Copper CVD case. For Program No. 3, Kim Tin MDF Joint Stock Co. and FSC have not responded to the Standard Questions. Kim Tin MDF Joint Stock Co. has not provided reasons for non-availment of them. Program No. 3 for Vietnam also includes procurement of machinery and equipment, component, parts and spare parts. The information on the same is required to be verified.
- lvii. For Program No. 4 for Vietnam, FSC and VRG have not responded to the Standard Questions. FSC has not provided reasons for non-availment. The Program was found countervailable by the Authority in the Copper CVD case.
- lviii. For Program No. 5 for Vietnam, none of the responding producers/exporters have responded to the Standard Questions. Kim Tin MDF Joint Stock Co. and FSC have not provided reasons for non-availment.
- lix. For Program No. 6 for Vietnam, Kim Tin MDF Joint Stock Co. and FSC have not responded to the Standard Questions or provided reasons for non-availment.
- lx. Programs No. 4 and 6 were found countervailable by the Authority in the Copper CVD case.
- lxi. For Programs No. 8 and 9 for Vietnam, none of the responding producers/exporters have responded to the Standard Questions or provided reasons for non-availment. The exporters should provide evidence to show that the interest rates paid on short-term loan is on par with the benchmark.
- lxii. Trade Policy Review of the WTO Secretariat has high evidentiary value regarding the local laws of a country.
- lxiii. For Program No. 10 for Vietnam, the intervention of the Government of Vietnam in the forestry sector distorts the domestic market for timber allowing its procurement at prices below international prices.
- lxiv. As per the website of the responding exporters of Vietnam, eucalyptus wood is used as raw material for the PUC. The prices for the procurement should be investigated by the Authority.
- lxv. The Government of Sri Lanka (GOS) provides goods at LTAR and imposes a log export ban. The producers who use timber as their raw material have benefited from these programs. Subsidies provided for planting rubber trees have enabled rubber farmers to sell rubber wood at LTAR. Imports from Sri Lanka is above 4% and hence not below de-minimis.
- lxvi. Program No. 1 for Sri Lanka is contingent on exports and hence, prohibited. The program was found countervailable by the USDOC in Certain New Pneumatic Off-Road Tires from Sri Lanka.
- lxvii. With regard to Program No. 2 of Sri Lanka, no evidence has been submitted to show that Merbok was operating under the BOI Act till January 2019. No response has been filed by the Government of Sri Lanka or Merbok.
- lxviii. No responses were received on Programs No. 3 to 6. The Government of Sri Lanka and Sri Lankan producers of the subject goods should be held non-cooperative.
- lxix. The Government of Sri Lanka provides goods at LTAR and also imposes a log export ban. The producers who use timber as raw material is benefited from the program.
- lxx. The Authority needs to examine countervailability of the subsidy programs initiated against Sri Lanka.
- lxi. The subsidy margin of power in the subject countries have been calculated with benchmark price taken from the website ‘globalpetrolprices’.
- lxxii. Neither the responding producers/exporters or the government have responded under the head of “other subsidies”.

- lxxiii. The benchmark adopted by the Authority is too conservative. The following alternative benchmarks may be more appropriate: (a) export price of similar type of wood used by responding exporters in the subject country, (b) highest/average cost of raw material (wood) by the DI together with their consumption norm, (c) international price for wood/timber/log from World Trade Atlas, and (d) prices of wood/timber/log from major exporters of the subject goods to India apart from subject countries.
- lxxiv. New Zealand is an appropriate benchmark for quantifying subsidy schemes providing log/timber/wood at LTAR as per Article 14(d) of the ASCM. Due to distortion of domestic market due to government subsidies, the use of out-of-country benchmark is appropriate as per the “law of one price”. Accordingly, New Zealand is an appropriate benchmark due to openness of its economy and significant volumes of export of logs.
- lxxv. Even after the alleged control of forestry sector by government of New Zealand, subsidization is seen in the subject countries. New Zealand was ranked 3rd in the 2018 Index of Economic Freedom and has lowest subsidies among the OECD countries. 95% of the exotic forestry plantations in New Zealand are privately owned and export controls are minimal. The license fee charged for harvesting in Crown forest land is as per market rate.
- lxxvi. The domestic industry has no objection to usage of log prices from New Zealand or another appropriate country to Thailand as benchmark if found appropriate by the Authority.
- lxxvii. There is no statutory restriction on the domestic industry from presenting evidences on benchmark. The Supreme Court decision in Haldor Topsoe is relied on.
- lxxviii. The Authority is not obliged to intimate the responding Govt. or producers/exporters about any new schemes.
- lxxix. The interested parties had enough time to counter the new subsidy allegations made by the applicant. Hence, there is no violation of the CVD Rules or the ASCM.
- lxxx. The domestic industry merely brought the fact regarding procurement of goods and services at LTAR found during the course of investigation. The same was done because the interested parties suppressed the said information.
- lxxxi. The Authority may use rubber wood prices as per trade map data and re-determine the subsidy margin.
- lxxxii. The response of the interested parties on the new subsidy allegations should be treated as suppression of information.
- lxxxiii. The interested parties are required to provide evidence to show raw materials and utilities are at fair market price.

G.2. Submissions made by other interested parties

40. The following submissions were made by the other interested parties:

- i. The Petitioners have only provided statutory provisions but have not offered any explanation on nature or specificity. The onus to establish the same lies on the petitioners. Burden is not shifted on the exporter unless DI establishes the same.
- ii. For Program No. 1 & 2 for Indonesia, the program covers only standing timber but the responding producers/exporters use rubber wood/rubber wood waste. The responding producers from Indonesia produced the subject goods from raw materials procured from private plantations. The program is not a subsidy as per the ASCM. The cases on the paper industry, relied on by the domestic industry, are not applicable to the fiberboard industry.
- iii. For Programs No. 1 and 2 for Indonesia, the Petitioner's allegations do not satisfy the requirements under Article 1.1(a), 1.1(b) and 1.2 of the ASCM. The Indonesian fibreboard industry uses rubber wood from private plantations and not state forests, as stated in the GOI questionnaire, and hence, Program 1 is not even applicable. The Petitioners wrongly assumed that the log export ban caused

an oversupply of timber which led to distortion of timber price in the Indonesian domestic market. In fact, there is no oversupply and Indonesia imports timber in significant quantities (also increased by 43% in 2018 compared to 2014). The export ban is intended at conservation of the environment and is a measure widely used by countries. In *US- Export restraints*, it was found that export restraints are not countervailable as there is no financial contribution. Similarly, in export ban there is no financial contribution and as such no benefit is conferred.

- iv. On Program No. 1 it is submitted that PNT (Stumpage Value Replacement) fees has been revoked. The allegation that timber is available to the exporters at LTAR on account of the Cheaper stumpage fees is unsustainable as the MDF manufactures are using residue of logs, waste paper, fibres etc. for the manufacture of MDF.
- v. Since MDF manufactures globally are using residue of logs, waste paper, fibres etc., Program No.2 is not applicable on them.
- vi. The objective of Program No. 2 for Indonesia is to reduce deforestation and combat illegal logging in Indonesia. The WTO Panel in US – Export Restraints found that export restraints do not constitute countervailable subsidies under the ASCM.
- vii. Export facilitation provided by the EXIM bank was previously not countervailed by the Authority. For Programs No. 3 and 10 for Indonesia, over the course of 2017-18, the EXIM Bank and Bank Mandiri have not provided interest rates below the BI (Central Bank) rate. Moreover, they confirmed that none of the Indonesian fibreboard producers have any loan from them. Hence, DGTR should reject this allegation. For Program No. 3 for Indonesia, PT Bank Negara (BNI) is not a public body. The loan or program available in BNI is not specific. As per Panel report in US (China), mere ownership does not constitute public body. None of the existing Indonesian fiberboard producers has any loan from the EXIM Bank and Bank Mandiri. Local currency interest rate cannot be used as a benchmark for foreign currency lending.
- viii. Programs No. 4 to 9 for Indonesia are provided under Indonesia's Law No. 25 of 2007 as per the Petitioner's claims. The law is for all sectors and for all regions. The Indonesian producers did not use 5 out of the 6 alleged programs. The only program availed was Program 7 which is neither specific nor confer any benefit to the Indonesian industry on the PUC. The Government of Indonesia provided additional information to show Mukti Panel has not availed Program No. 10.
- ix. It is submitted that the exporters have not taken any loan from EXIM bank under Programme No. 3. This claim can be cross-checked from the loan information provided in the audit reports of the exporters.
- x. As the exporters have neither taken any benefit of reduced income tax nor any such benefit is available to them, any claims with reference to Program No. 4 are incorrect.
- xi. The applicant that PT Mukti and PT Sumatera have procured the raw materials domestically i.e., not imported the raw materials. The audit reports of the exporters have been enclosed with their questionnaire response to verify the correctness of their claim.
- xii. The exporters have categorically mentioned that in their questionnaire response that they have not taken any relief of land and building tax. Therefore, the claim made by the applicant that PT Mukti and PT Sumatera, have not provided/answered the Standard Questionnaire for the Program is incorrect.
- xiii. PT Sumatera has categorically mentioned on page no 18 of its questionnaire response that it has not availed any benefit of income tax exemption. Further, complete details of the imports as well as the tax payable and paid on the same are provided.
- xiv. PT Mukti (Exporter) submits that it has provided complete details of the taxes paid on the imports in Annexure 8 of its response. It is reiterated that the exemption of income tax (PPH) for import materials and capital goods does not confer countervailable benefit as income tax for import is merely an instalment for annual payable income tax.

- xv. Factory prices in Tangerang is not an appropriate benchmark for Program No. 11 as the program pertains to forest land and Tangerang is located in a different island, i.e., Java. The mere assertion of the DI that Indonesian constitution, Article 33 (3) provides that land, water and natural riches contained therein shall be controlled by the state also does not substantiate as to how land is available to the respondents at LTAR. The submissions which were raised at WS stage should not be considered by the Authority.
- xvi. Indonesia's state-owned company, PLN serves all companies in Indonesia and hence, the program is not specific. The DI has, for the very first time included the subsidy margin of power in their submissions without even making any allegation of subsidization. GOI submits that it's against Article 12.7 of ASCM. In the absence of any claim or evidence with respect to power subsidization in Indonesia, the computation of subsidy margin provided by the DI is frivolous and does not hold any merit.
- xvii. The evidence relied by the DI for computation of alleged subsidies on "electricity" is sourced from website "globalpetrolprices", should not be considered because DI failed to supply a copy of the said document to other interested parties.
- xviii. There is no suppression of information by the responding producers/exporters as claimed by DI it is submitted that they have provide complete details to that of questionnaire responses and cooperated throughout the investigation hence their responses should not be rejected.
- xix. For Program No. 1 for Sri Lanka, remittance of NBT is not a subsidy under the ASCM by virtue of footnote 1 of the ASCM. The remittance is applicable to all exporters irrespective of the product. Footnote 1 states that exemption of exports from indirect taxes, as defined under footnote 58, is not a financial contribution. The same principle is also provided in the Ad Note to Article XVI of the GATT. Annex I(g) of the ASCM states that such remittance of indirect tax levied is not a subsidy if it does not exceed those levied for production and distribution of like products for domestic consumption. The remittance under this Program does not exceed this level. Annex II (1) also allows remittance of indirect taxes levied on inputs consumed for the production of exported products. NBT was abolished w.e.f. 1 Dec 2019.
- xx. For Program No. 2 for Sri Lanka, Merbok was operating under the BOI Act until Jan 2019. The Company benefited from the scheme from Jan 2019 and not before that.
- xxi. For Program No. 3, Merbok, since 2014, have been incurring losses and hence not liable to pay income tax. Hence, the program is not applicable.
- xxii. For Program No. 4, Merbok, since 2014, have been incurring losses and hence not liable to pay income tax. Hence, the program is not applicable.
- xxiii. For Program No. 5, it is a general subsidy and not provided to any sector specifically. It is available to all engaged in the agricultural sector. It does not benefit rubber producers specifically and not provided to exporters. Hence, neither an export subsidy nor actionable under ASCM. Merbok is not registered with the administering authority for the program to access it.
- xxiv. For Program No. 6, two schemes administered by the Rubber Development Board are provided exclusively to rubber growers. It is provided for new planting and replanting. The fiberboard producers from Sri Lanka use rubber logs which is a waste from the rubber industry. The waste wood and saw mill dust purchased by the fiberboard manufacturers are at market prices. It is purchased at a throw away price at the end of the lifetime of the tree. This purchase is not influenced by the scheme. Benefit is too remote and does not pass on to the fiberboard producers. The investigating authority must have evidence to show that the benefit has passed on from the first entity to the second to hold that such a subsidy exists for the latter. Hence, GOI submits such a subsidy does not exist.
- xxv. If a subsidy is available to only "certain enterprises", it is specific. However, when an objective criterion is laid out and these conditions apply horizontally, there is no specificity. Activities designated by the BOI for promotion are extremely broad and include effectively business activities pertaining to almost every industry sector in Thailand. Any person can apply under Section 17 of

- IPA and undertake promoted activity. The criteria are broad. Thereafter, all programs are provided as a package. Although the companies have to separately apply when utilizing benefit.
- xxvi. Program No. 1 for Thailand provides exemption from payment, and not reduction in custom duties. Company has to first seek approval from BOI for a particular machinery. Only those machines not assembled in Thailand get the approval. Petitioners have incorrectly stated in the petition that Program 1 is “enterprise specific” without establishing the manner in which it is enterprise specific.
 - xxvii. Designated Authority has erred in its analysis of Program No. 2. As has been noted in the USDOC finding, the BOI has an effective verification mechanism in place and thus, Program No. 2 is a permissible tax exemption program. Ref: Countervailing Duty Investigation of Glycine from Thailand (USDOC), BOI has an effective system to ensure no excess benefit is provided.
 - xxviii. In Program No. 4, Petitioners have failed to substantiate why carry forward provisions under the BOI program are financial contribution or if they indeed are, how do they confer benefit. Specificity is absent as criteria is wide. No explanation for “enterprise specific”.
 - xxix. In Program No. 6, the program is not limited to any particular enterprise or industry and is available for a wide range of economic activity and hence is not specific.
 - xxx. In Program No. 8, the benefit, if any, is not actually granted to the promoted company but to the shareholders of the promoted company.
 - xxxi. In Program No. 9, remission of tax on exported goods, is a common and well established practice among various jurisdictions that follow the VAT system. The same was held to be not countervailable in Anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods”.
 - xxxii. The questionnaire responses are required to be filed by the Thai Government and not its agencies. Therefore, the suggestion that the Board of Investment, which is an agency of the Government, should have filed the responses is unsupported by law.
 - xxxiii. It has been submitted by M/s Metro Group that it has cooperated with the Authority and filed its response to the questionnaire within the prescribed deadline providing all details as may be relevant. Metro Group submitted a complete questionnaire response and has also provided program specific annexures and relevant additional annexures, as applicable.
 - xxxiv. Petitioners have alleged the existence of an additional program “Provision of raw material (wood) for Less Than Adequate Remuneration” exists but, the nature and application of such program is unclear. It is also unclear whether the Petitioners are alleging one subsidy program or several different subsidy programs. Lastly, it is unclear whether such alleged program(s) even confers a benefit on producers and/or exporters of the PUC.
 - xxxv. Annexure 3.4 of the Petitioners’ written submissions, that lists all the subsidy programs from Thailand only identifies the 11 programs as specified in the Initiation Notification and does not mention any additional programs such as the ones identified above. The Petitioners have not provided any evidence for any additional program such as extracts of laws or regulations to establish the existence of such program(s).
 - xxxvi. Petitioners have claimed certain standard and relevant program specific annexures (referred to by the Petitioners as SA and RA) as ‘deficient’, without providing any reasons to substantiate its claims. Advance Fiber has in fact, submitted both the standard program specific annexure and relevant annexures, where applicable.
 - xxxvii. Metro Group has submitted detailed questionnaire response and the determination of subsidy margin must be made on the basis of the information submitted and records maintained by Metro Group.
 - xxxviii. Metro Group has disclosed all relevant information concerning addition of the capacities contrary to the claims made by the Petitioners. M/s Advance Fiber Co., Ltd, has disclosed adequate information on addition of the capacities. The same may also be analyzed from Format C, which would reflect

- that capacities were increased from 100 indexed points in year 2016 to 139 indexed points in 2017 to 177 indexed points in year 2018.
- xxxix. Rule 16(d) of the Anti-subsidy Rules 1995, no developing country can be considered for imposition of duties in case its share in the total imports is less than 4% but still Sri Lanka who's import are less than 4% has been considered as one of the subject countries.
- xli. Each program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of previous finding in Copper wire rod case will be a violation of principles of natural justice.
- xlii. Thai exporters have either not availed any countervailable subsidy in terms of the WTO ASCM or the amount of subsidy, if any, is below de-minimis level.
- xliii. The Applicants should mandatorily provide (a) evidence of the existence of alleged subsidy; (b) evidence of financial contribution by a public body; (c) financial contribution should confer benefit; and (d) the alleged program is specific in terms of the SCM Agreement. However, in the present investigation, the Applicants have failed to fulfil the abovementioned four criteria's and therefore, the Application should be rejected.
- xliii. As per the questionnaire response filed by RTG, alleged program nos. 1-8 are administered by the Office of the Board of Investment (BOI) in terms of the Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977) ("IPA") as amended. Further, Program No. 1- 8 administered by the BOI in terms of IPA is available to almost every industry in Thailand.
- xliv. RTG allows exemption of import duty for the purpose of exports, as the same is permitted by the WTO SCM Agreement under Article 1. RTG also wishes to reiterate that BOI has an effective system to track import of raw material, consumption of input material for finished goods exported from Thailand; and to confirm that there is no excess benefit to the producer/exporters carrying out the promoted activity.
- xlv. Program No. 2 for Thailand is not availed by the responding producers/exporters. Only an excess benefit provided under the program can be countervailed, if any. The program was previously held non-countervailable by the USDOC.
- xlvi. Program No. 8 benefits the shareholders of the company, not the company itself. Therefore, the investigation should be terminated for Program No. 8.
- xlvii. RTG submits that Program No. 9 provides for remission of tax on exported goods which is otherwise borne by the like product when destined for domestic consumption in accordance with footnote 1 of the SCM Agreement. Further, the Authority in "Continuous Cast Copper Wire Rods" from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam" noted that this subsidy program provides for exemption from value-added tax on export of goods, applies to other business as well and therefore, no countervailing duty was recommended.
- xlviii. The benefit in a countervailing duty investigation should be examined from the perspective of the recipient. For ease of reference, the WTO DSB in the dispute titled Canada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft and European Communities - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft can be referred.
- xlix. With reference to Program No. 2 there is no financial contribution/subsidy under this program to Thai exporters of subject goods. To confirm the same, RTG extends its cooperation to the Authority and is willing to submit all necessary documents.
- i. The Applicants have claimed that RTG has not furnished complete information for the Program No. 10 and 11. However, a perusal of the questionnaire response reflects that these programs do not constitute subsidy in terms of the SCM Agreement.
- ii. For Program No. 11 for Thailand, the Authority countervailed only a few producers despite applying facts available. Facts available should not be applied in the present case for Program No. 11 for Thailand since the Thai exporters have cooperated with the Authority. Interpretation of Rule 7(8) of

the CVD Rules as per the DGTR Manual and Article 12.7 of the ASCM as per the Panel Report in EC – Countervailing Measures on DRAM Chips are relied on. The letter filed by the EXIM bank shows that no benefit was availed by the Vanachai Group or Panel Plus Group. Moreover, the EXIM bank does not offer any loans.

- iii. For a loan to be a subsidy, the same should originate from a government or public body and benefit should be conferred through a lower interest rate than comparable loan in the market. No evidence on the same is produced by the domestic industry. The loans taken by Metro Group are from commercial banks and at market rates.
- liii. For Program No. 12 for Thailand, private land is excluded from the scope of the relevant act and rubberwood or any kind of firewood does not fall under the scope of ‘prohibited woods.’ The government is not engaged in the regulation of wood prices.
- lv. The Applicants have claimed that RTG is providing raw material at less than adequate remuneration. However, the said claim is merely assertions and unsubstantiated.
- lv. The analysis of the Authority in paras 323 and 324 of the Disclosure Statement is contradictory.
- lvii. The claim of the domestic industry regarding Program No. 13 is incorrect and baseless. The price of electricity is uniform in nature and provided to all businesses and industries. Hence, not specific. No countervailable benefit is provided. The benchmark relied on by the domestic industry for quantification is erroneous as it takes into consideration only off-peak hour rates by the PEA and ignores all additional charges. Since PEA is the only regulatory authority for electricity supply in provisional areas of Thailand, there cannot be any other benchmark.
- lvii. There is no requirement under the ASCM to provide reasons for non-availment of a program.
- lviii. Responding exporters from Malaysia submitted that as per the ASCM and the CVD Rules the parties should provide the details of subsidy availed in an investigation and it does not require one to explain why a particular program was not used as if there was some mandate on parties to avail all such programs.
- lix. The subsidy margin for Program No. 7 for Malaysia in the Disclosure Statement is negligible. No duty should be recommended against the same. The program does not meet the specificity requirement or is export contingent and hence, is not countervailable.
- lx. The disclosure statement contained quantification based on usage of schemes and the purpose of the investigation is not blanket determination of margin irrespective of the actual usage of the program.
- lxi. For Program No. 9 for Malaysia, capital allowance is neither specific nor export contingent. Program No. 12 for Malaysia does not meet the specificity requirement or is export contingent and hence, is not countervailable. For Program No. 9 & 12 for Malaysia, the subsidy margin quantified is more than the company’s claim.
- lxii. Following footnote 1 of the ASCM, Program No. 11 & 13 shall not be deemed to be a subsidy.
- lxiii. For Program No. 20 for Malaysia, rubberwood is not covered within the definition of ‘forest produce’ under the relevant legislation. There is no royalty collected on rubberwood and hence, no waiver is possible.
- lxiv. For Program No. 22 for Malaysia, the benefit is not availed by responding producer/exporter. The respondent paid electricity rates as per the prevailing rates in case of purchase and those prices are not subsidized prices. The utility consumption exemption of the company is part of our cost records and we cannot relate our power price to what is been claimed here. Post disclosure stage is not the stage to collect information on Malaysian power tariffs.
- lxv. For Program No. 3 for Vietnam, there is no law which mandated availment of programs in any case. There is no countervailable benefit provided under Program No. 3 for Vietnam. The import duty payable was NIL and hence no revenue is forgone under the program. Benefit under FTAs should not be countervailed.

- lxvi. MDF VRG has not availed any benefit under Program No. 4 for Vietnam.
- lxvii. No benefit was availed by Kim Tin under Program No. 6 for Vietnam since full rents were paid. The margin for the program in the Disclosure Statement is higher than the company's claim.
- lxviii. No benefit was availed by the responding producers/exporters under Program No. 8. No benefit is provided under the program as interest rate for long-term loan is on par with prevailing interest rate in Vietnam and as per World Bank data. The interest rate for short-term loans is universally lower and no subsidy can be presumed. There exist no compensatory arrangements on interests.
- lxix. No countervailable benefit is provided under Program No. 8 & 10 for Vietnam. The Trade Policy Review of Vietnam to the WTO cannot be the legal basis for determining subsidy. The evidence submitted has no reference to local procurement.
- lxx. The DGTR has failed to establish existence of a financial contribution, government entrustment and specificity in the program.
- lxi. Introduction of new claims and evidences on benchmark at the fag end of the investigation is a violation of due process by the petitioners.
- lxxii. The respondents were never intimated that the new subsidy allegations were being investigated and hence, is a violation of due process. The same violates Rule 7(4) of the CVD Rules and Article 12.1 of the ASCM. Panel Reports in US – Anti-dumping and countervailing duties (China) and China – Broiler Products (Article 21.5 – US) are relied on.
- lxxiii. No information on these programs were sought during verification and no opportunity was given to rebut the allegations. The allegations are vague, unclear and unsubstantiated. No evidences were provided.
- lxxiv. The governments of the subject countries were not consulted regarding the new subsidy allegations which is a violation of Article 9 of the ASCM.
- lxxv. Written submissions cannot be used to introduce new claims.
- lxxvi. The respondents have not availed any such subsidy and hence, did not include them in their questionnaire responses.
- lxxvii. No reason has been provided for choosing New Zealand as the appropriate benchmark. The Authority is required to reason the choice of benchmark in lines with the Appellate Body report in US – Carbon Steel (India). The respondent is not using timber as their input for producing subject goods. Timber prices cannot be used as a benchmark for Rubber Wood/Rubber Wood Waste. The Government of New Zealand controls all of the harvested forest and export price of wood from New Zealand to India are not determined as per market forces. New Zealand wood prices cannot be compared to rubber wood since non forestry and forestry wood are different. MDF manufacturers also use waste from saw mills. Rubber wood is hardwood species while New Zealand pine etc. is softwood species. The petitioner is trying to compare the incomparable.
- lxxviii. Usage of Indian rubberwood prices will not be an appropriate benchmark as prices are high due to scarcity. The benchmark price should be adjusted taking into account that the respondent has only used waste and/or residue of rubber wood. Log prices from NZ or another appropriate country to Thailand would have been the appropriate benchmark for Thailand.
- lxxix. The alternative benchmarks suggested by the domestic industry are inadequate. The benchmark should be on the lines of prevailing market conditions of the exporting country and not based on price of raw materials in any third country.
- lxxx. Treatment of the respondents as non-cooperative and applying facts available is in contravention to CVD Rules and the ASCM. Such treatment can be given only if a party refuses to provide information which was not the case in the present case.
- lxxxi. For the benchmark relied on by the domestic industry for alleged electricity subsides, not even the period for which the prices pertain to is not clear.

- Ixxxii. The domestic industry's reliance on the Supreme Court decision in Designated Authority v. Holdor Topsoe is erroneous as it states that the obligation to provide information applies only if the party is in possession of the evidence. When a program is not availed, there is no information to be disclosed.
- Ixxxiii. There is no justification for not providing the calculation of subsidy margin and the basis for the same as they are based on the information provided by the company. The SC decisions in Sterlite Industries v. Designated Authority and Reliance Industries v. Designated Authority are relied on.

Examination by the Authority

41. As regards the contention of the other interested parties regarding investigation of new/additional subsidy schemes discovered during the course of investigation, it is noted that the original questionnaire specifically contained a detailed annexure with respect to 'other subsidy schemes' and it was also instructed that "for each program, even if some of them are not listed by the applicant but are existing in the subject country, the responding party should respond fully to the questions, even if Government of subject country believes that the program is not countervailable". The same was reiterated in the additional questionnaire that was sent to the interested parties with respect to the alleged additional/new subsidy schemes. Therefore, the Authority has followed the due process and the interested parties were given ample opportunities to submit the requisite information.
42. There may be occasions when the Authority finds some additional subsidy schemes in the subject country(ies), though not specifically mentioned in the initiation notification. The obligation of the responding governments and exporters/producers of subject countries was to equip the Authority with requisite information on all schemes existing in the subject countries concerned with the present investigation which could have led the Authority to reach a fair conclusion especially when the said information was solicited through original questionnaire in the form of Provision of Goods and Services specifically mentioning that "*for each program, even if some of them are not listed by the applicant but are existing in the subject country, you should respond fully to the questions, even if Government of subject country believes that the program is not countervailable.*" And "*in the absence of a complete response, a decision will be based on the best information available.*" However, instead of providing information, the interested parties found it convenient to shift the burden on the Authority. In such a scenario, the Authority had to move with the best information available and accordingly compute the relevant subsidy margins for LTAR programmes in form of wood, land, water, coal, power, etc. existing in the respective countries.
43. With regard to the alternative benchmarks proposed by the interested parties, the Authority notes as follows.
- Considering export prices from the subject countries as benchmarks will not be appropriate as the same are also equally distorted as the domestic price is due to government control as examined in the relevant paragraphs below.
 - The prices of rubberwood provided by private parties in Indonesia could not be adopted, for the reason that the same also suffers from the similar distortion as is found in respect of other suppliers. The Authority has determined that the domestic forestry market in Indonesia is distorted.
 - The prices of rubberwood in India as a benchmark were not considered appropriate. The availability of this type of wood in India is limited and the resultant price is high.
 - International prices for wood/timber/log are not adopted since the benchmark should reflect the prices of the type of wood used by the responding producers.
44. New Zealand has significant forest and also exports significant volumes of wood across the globe. 95% of the exotic forestry plantations in New Zealand are privately owned and export controls are minimal. The license fee charged for harvesting in Crown forest land is as per market rate. Further, the price at which NZ has exported wood is found reasonable when compared with other options available. New Zealand is thus considered an appropriate benchmark for quantifying benefits in log/timber/wood available to foreign producers at LTAR as per Article 14(d) of the ASCM.

Calculation Methodology

45. Article 14 of ASCM, provides guidelines and methodology for calculating the benefit to the recipient conferred pursuant to paragraph 1 of Article 1 and further provides that any method used by the investigating authority to

calculate the benefit to the recipient shall be transparent and adequately explained. Further, any method used by the investigating authority to calculate the benefit to the recipient shall be provided for in their national legislation or implementing regulations of the Member concerned and its application to each particular case shall be transparent and adequately explained. In accordance with the requirement, the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 lays down the methodology of determination of quantum of subsidization. The determination in this investigation is in accordance with these guidelines.

G.3.Examination of the Subsidy programs alleged by the Petitioners

Indonesia

(i) Program No. 1: Provision of Standing Timber for Less Than Adequate Remuneration

Submissions by the Petitioners

46. The petitioners submitted that the said program is administered by the Ministry of Finance. The Government of Indonesia controls nearly all (88%) the harvestable forest land and leases logging rights to companies on which a stumpage rate is levied for the right to harvest wood. The stumpage rate charged by the Government of Indonesia is far less than the value of the stumpage.
47. Further, the term “timber” is not limited to any specific type of wood. Tropical wood such as rubber wood falls within the scope of the term. All kinds of wood are nothing but timber. The interested parties are incorrectly projecting that timber means only Hardwood or wood directly going for making furniture. In fact, rubberwood is the best alternate for timber appliances due to environmental concerns. The production of product from fiber or paper is completely ruled out.
48. Though the raw material, i.e., wood/logs might be purchased from private plantations, the level of government intervention leaves the entire timber market in Indonesia distorted. Purchasing the timber from the private entities does not establish that there is no subsidy therein. Though the Government of Indonesia as well as the responding producers/exporters have stated that they rely on private plantations for sourcing their raw materials, the dominant role played by the Government in the logging industry through this program artificially lowers the prices. Prices of private plantation are also subsidized when majority sale is by Govt. owned/controlled parties. The reliance upon the analysis made by USDOC in the matter of ‘Coated Free Sheet Paper from Indonesia’ & ‘Certain Uncoated Paper from Indonesia’ is appropriate.
49. Because of the conditions of the Indonesian timber market, it is nearly impossible for the responding exporters not to have availed the program. The price in the entire market is bound to be distorted in a situation where majority of sellers are govt. owned or controlled and these so labelled private parties are minority suppliers of these inputs. Such being the case, the only option is to rely on outside country benchmark or international benchmark.
50. The same was found by several other investigative authorities through anti-subsidy investigations. Hence, raw material for the fiberboard industry is provided at less than adequate remuneration (LTAR). The program provides a financial contribution in the form of goods at LTAR and a benefit is thereby conferred. The program is specific because the benefit under the program is only made available to the downstream industries that use timber/wood as its raw material.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

51. The Government of Indonesia submitted that the standing timber policy does not provide any financial contribution or benefit to the responding companies in any form and hence, not countervailable under the ASCM. The standing timber fee is only applicable to government owned land and not to private plantations from which the respondent companies sourced their raw materials.
52. The exporters are using left over/waste etc. harvested from private plantations and not timber. They use leftover waste rubberwood is used in fiberboard in Indonesia. Hence, program is not applicable. None of the cases referred by the Applicant relates to MDF. Timber is not used in MDF due to high cost. The exporters procure RM (rubber wood) grown only on private plantations instead of state forest.
53. As per the Forest act the standing timber policy does not provide any financial contribution or benefit to the responding companies in any form and hence, not countervailable under the ASCM. The standing timber fee is

- only applicable to government owned land and not to private plantations from which the respondent companies sourced their raw materials.
54. The exporters submitted that they do not use timber wood or any other product related. The program pertains only to “standing timber” or “timber wood”. The responding party has purchased Rubber Wood/ Rubber Wood waste from private plantations which has been recognized by the Authority in the disclosure statement and hence the scheme will not be applicable.
 55. The Ministry of Environment and Forestry through Minister Regulation no 66/MenLHK/Setjen/Kum1/10/2019 mandates the forest license holder to record and report wood product harvested from natural forest. Imports of forestry products are regulated by Minister of Trade Regulation number 82/2019, Minister of Trade Regulation 97/2015 read together with Minister of Trade Regulation 91/2017 read together with Minister of Trade Regulation 13/2018. Import’s forestry products, one must obtain import declaration consisting of SVLK certificate, sustainability, and the legality of the product. Consumption from Non-State Forest is provided through SVLK certification and Land deed, which are provided by the Companies.
 56. There is no provision for rubberwood waste/residue as input to produce fiberboard for the producers under investigation. List of the suppliers are not maintained by GOI. Further list can be obtained from the cooperating producers who dealt with the suppliers. Rubberwood waste prices are determined between rubberwood waste collector/seller/buyer and hence, it is a business-to-business transaction. The GOI is not involved in the determination process. The price of rubber woods waste depends on the negotiation between the seller and the buyer. Pricing information is not regulated by GOI, hence responding exporters can only provide information regarding to their own negotiated or transacted prices with private suppliers.
 57. GOI does not provide the said goods/services and, therefore, the question of comparable prices does not arise.

(ii) Program No. 2: Government Prohibition of Log Exports

Submissions by the Petitioners

58. The petitioners submitted that the said program is administered by the Ministry of Finance and the Ministry of Industry and Trade. The two Ministries jointly issued a decree that banned export of logs from Indonesia. This distorts the domestic market and makes wood, which is a raw material in the fiberboard industry, available to downstream industries at LTAR. The program provides a financial contribution in the form of goods at LTAR and a benefit is thereby conferred. The program is specific because the benefit under the program is only made available to the downstream industries that use timber/wood as its raw material.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

59. The Government of Indonesia submitted that the provisions on export of forest industrial products are applied to deter and control over-harvest and illegal logging as means to protect and sustain Indonesian forests. Moreover, export ban does not constitute a financial contribution as held by the WTO Panel in US-Export Restraints (DS 194). Further, the responding exporters sourced their raw materials from private plantations.
60. The exporters are using left over/waste etc. harvested from private plantations and not timber. Hence, program is not applicable. None of the cases refereed by the Applicant relates to MDF. Timber is not used in MDF due to high cost. Indonesia is a forest rich country and left-over logs, waste etc. are available in abundance. The purpose of the export ban was to control illegal logging, preserve the resources and protect environment and not to collect stumpage fees. No evidence has been produced to show market distortion.

Examination by the Authority

61. The Authority notes that program no. 1 & 2 relates to the series of the measure taken by Government of Indonesia to regulate, monitor and control forestry sector in Indonesia. Since effect of these programs results in raw material of PUC being provided at less than adequate remuneration, the Authority has combined these programs and examined them collectively for the purpose of present investigation.
62. The Authority notes that the Government of Indonesia owns majority of the harvestable forest land in the country and has a predominant role in the market for standing timber. As per Regulation No. 09/M-DAG/PER/2/2012, the standard price for wood is periodically determined by the government. Various regulations on record outline the types of fees and royalties assessed for the harvest of standing timber in Indonesia. Companies are, however, granted logging rights to collect timber from these forests. The Government, in return, collects two kinds of stumpage fees; namely Provisi Sumberdaya Hutan (provision for forestry resources – PSDH) and Dana Reboisasi (replanting fund – DR). The responding exporters have, however, mentioned that they have no obligation to pay stumpage fees as they are procuring raw material from the private planters.

63. As far as Government prohibition of log exports is concerned, the petitioners have alleged that the said program is administered by the Ministry of Finance and the Ministry of Industry and Trade. The two Ministries jointly issued a decree that banned export of logs from Indonesia. The Government and responding exporters have stated that the main reason of imposing export restriction is for conservation of environment and ecosystem so as to control illegal logging and preserve the resources. A ban on round (unprocessed) log exports was re-introduced in 2001, ostensibly to address the problem of over-exploitation.
64. The submissions made by GOI proves that the Indonesian wood product is harvested from natural forests. Various regulations of the GOI suggest that forests are under the control of the state. Also, the Indonesian government has instituted policy measures to discourage or ban log exports. The aim has been to encourage processing industry within Indonesia.
65. The Authority notes that while, such bans (and other export restrictions) may somewhat curtail over-exploitation of Indonesia's forests these measures also depress the domestic prices of logs, thereby assisting downstream processors of such products which leads to subsidization.
66. The Authority further notes that measures undertaken by the Government of Indonesia through the imposition of export prohibition on logs amounts to entrusting/directing domestic forestry/harvesting companies including private entities to provide low priced inputs (logs/wood) to companies in the downstream industries. Specifically, the log export ban allowed the companies under investigation to purchase inputs (log/wood) from forestry/harvesting companies below market prices. The ban which has induced log suppliers to sell logs domestically at suppressed prices has benefited Indonesia's downstream wood processing industries and reduced the price of logs.
67. The programs provide a financial contribution in the form of goods at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The programs are also specific since they benefit those downstream industries that use logs/wood as their primary raw material. Hence, the programs are *de facto* available only to a limited number of industries. Therefore, the Authority holds the above two programs as countervailable.
68. Though the applicant has stated that the usage of export of logs from New Zealand to India is an appropriate benchmark. However they have also suggested alternate benchmarks such as (a) Export price of similar type of wood used by the responding exporters in the subject country, (b) The highest/average cost of raw material (wood) by the domestic industry together with their consumption norms, (c) International prices for wood/timber/log available from World Trade Atlas or (d) Prices of wood/timber/log from major exporters of the subject goods to India apart from the subject countries which include Brazil and South Africa.
69. The responding exporters have contended that they are using leftover/residue of rubberwood and have suggested to consider prices of rubber wood in India and the estimated price of the waste/residue wood on the basis of the ratio of the price of the waste/residue and the price of fresh logs. Responding exporters have submitted that the same ratio may be applied to the Indian rubber wood prices to arrive at a fair market value of the waste/residue of rubber wood.
70. The Authority notes that the leftover/residues are woods that are mainly obtained from old age rubber tree, which is no more capable of producing latex, debarked and used in production of MDF. Such rubberwood is not of any use in rubber industry but can be used in Fiberboard industry. Hence the prices of such waste/residue/leftover rubberwood are lower compared to rubberwood logs. With regard to the submission by responding exporters/producers from Indonesia that they are using rubberwood waste/residue, the Authority notes that it has taken due cognizance of this fact and has considered the estimated price of the logs on the basis of the ratio of the prices of the waste/residue to the prices of fresh logs. This was then compared with the benchmark adopted by the Authority.
71. To determine the quantum of the subsidy margin, the Authority looked for the appropriate benchmark whereby it was found that New Zealand is one of the largest exporters of logs globally. The Authority considered exports price of log from New Zealand as a more appropriate benchmark as compared to import price from New Zealand. Considering the appropriate conversion rates, the subsidy margin determined has been provided in the table below.

(iii) Program No. 3: Benefits for Export Facilitation by Indonesia EXIM Bank**Submissions by the Petitioners**

72. The petitioners submitted that the said program is administered by the AsuransiEkspor Indonesia (ASEI) and the Indonesia EXIM Bank. Under the program, the Government of Indonesia through their state-owned banks, ASEI and the Indonesia EXIM Bank provide export credit guarantees that permit banks to lower the rates charged for export financing. The program provides a financial contribution that is the difference between the lower lending rates and the normal lending rates available to exporters while availing export credit guarantees. Thus, the program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because only those enterprises are eligible that are engaged in exports. Since the program is contingent on exports, it is deemed specific. The Authority had previously found export facilitation by the EXIM bank countervailable in CVD investigations on “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam, “Textured Tempered Glass” from Malaysia, “Clear Float Glass” from Malaysia, and “Flat Products of Stainless Steel” from Indonesia. Non-availment of a program does not make it non-countervailable.
73. Further, preferential lending is practiced within the nation by the banks located in the territory of the country irrespective of whether the lending is in local currency or foreign currency. The lending interest rate depends upon the credit rating of the company whereby the lending bodies exercise discretion and provide preferential loans. If compared with the prescribed lending rates for the country by the international authorities such as IMF or World bank, the lending interest rates are always at the lower side. Also, the central bank of the countries has higher benchmark which can be seen at the website of the banks whereas the actual lending rates are far below than that.
74. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

75. The Government of Indonesia submitted that the Indonesia Exim bank is a special financial institution 100% owned by the government and operates independently under the Act No. 2/2009. As per Article 7 of the Act, it is one of the key activities of the bank to provide guarantees to Indonesia exporters, overseas importers and tenders related to project performance. It provides financing in the form of working capital and/or investment. There is no law or regulation governing the eligibility criteria. Eligibility is an internal procedural matter of the bank. Moreover, over the course of 2017-18, the EXIM Bank and Bank Mandiri have not provided interest rates below the Central Bank rate.
76. It has been submitted that the program is not applicable since no loans are taken from EXIM Bank. The claim can be cross checked with loan information in the audit reports. Further, export facilitation by the EXIM bank was previously held non-countervailable by the Authority.
77. The interested parties have also submitted that PT. Bank Negara Indonesia (BNI) is a financial institution that operates based on profit and it independently provides loans to customers with interest at the prevailing market rate which is above the Bank of Indonesia's rate (central bank).
78. As per the disclosure statement the Authority claimed that BNI is a public body merely because the GOI holds a 60% share in the bank as of 2019. As per WTO AB Findings - Anti-Dumping and Countervailing Duties (China) “mere ownership or control does not constitute public body”. GOI stated that none of the responding producers/exporters has received any benefit.
79. Without prejudice to the above that loan taken from BNI bank cannot be considered as subsidy, it is submitted that MPI has taken all loans at market determined commercial rates. It may be noted that the respondent had taken loans both in local as well foreign currencies at market determined commercial rates. Even if the Indonesian Bank is considered to be a “Public Body”, the benchmarks considered have to be only for the currencies in which the loans have been taken. Since a substantial part of the loans by the respondent is USD denominated, the rate applicable for the local currency loans cannot be applied. It may also be noted that the interest rate for foreign currency loans is totally comparable to the interest rate paid by other respondent for loans taken from a foreign

bank. Thus, applying the local currency interest rate even to the foreign currency loans, is completely ill-conceived and erroneous.

Examination by the Authority

80. It is noted that the program is administered by the Ministry of Finance as per the Decree of the Republic of Indonesia no. 366/KMK.06/2009 and the Act No. 2/2009. The bank is wholly owned by Government of Indonesia and exercises Government Authority. Its main objective is to support the Indonesian exporters. Domestic financing services are provided in the form of working capital and/or investment facilities.
81. It is noted that no loans have been procured from Exim Bank by the responding producers/exporters as has been submitted by them in their questionnaire response.
82. The responding exporters have clarified in their submissions that the benchmarks considered for the interest rates have to be only for the currencies in which the loans have been taken.
83. The Authority notes with regard to the loans taken from other banks by both the responding exporters/producers that Pt. Sumatera has taken foreign currency denominated loans from Pt. Bank Negara Indonesia (BNI) as well as from a foreign bank situated in Singapore. While comparing the interest rate of long-term foreign currency loans charged by the bank in Singapore with that of BNI, it is seen that both the interest rates are at par and comparable. As far as local currency loans procured by both the responding exporters from BNI are concerned, it is seen that the interest rate charged by the BNI for both the responding exporters for short term and long-term loan in local currency is comparable to the benchmark adopted by the Authority in its earlier disclosure statement.
84. In view of the aforementioned, no element of subsidy is found for the loans taken from the Indonesian and other banks by both the responding exporters/producers.
85. Therefore, the Authority notes that no countervailing duty should be imposed under this program.

(iv) Program No. 4: Reduction of Income Tax

Submissions by the Petitioners

86. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Indonesia. The Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investments provides incentives for investments in a variety of forms including reduction of net income to a specified extent of the total investments made within a definite period. Thus, the program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Article 18 of the Law No. 25 of 2007 provides several eligibility criteria and satisfaction of at least one of them is essential to avail the benefit. The program is, hence, specific because only those enterprises are eligible that meet the eligibility criteria.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

87. The Government of Indonesia submitted that the corporate income tax reduction facility in tax holiday shall be granted to income received or accrued from main business activity which constitutes a Pioneer Industry. A “Pioneer Industry” is defined as an industry “with extensive interconnection that provided added value and high externality, introduces new technology, and has strategic value for national economy. The Tax Holiday is eligible for pioneer industry status which covers 18 sectors. However, the list is not exhaustive. The program opens the opportunity for other sectors other than currently stipulated in the program upon the approval of the Minister of Finance. Initially, the corporate income tax reduction of 10% to 100% over a period of five to fifteen years was provided. In April 2018 it was amended to provide 100% reduction for five to twenty years. It was further amended in November 2018 to provide 50% to 100% reduction depending on the total investment value.
88. It has been submitted that the program is not applicable since no benefit from reduced income tax was availed. The same can be cross checked with the audit reports.

Examination by the Authority

89. It is noted that the program is administered by the Government of Indonesia. As per Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007, a reduction on corporate income tax to the extent of 50% to 100% for a period of five to fifteen years is provided to a “Pioneer Industry” depending on the total investment value. The program covers the forestry sector as per Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

150/Pmk.010/201. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. It is specific since the benefit is provided only to enterprises that qualified as a “Pioneer Industry”. Therefore, Authority holds this program as countervailable program.

90. However, the Authority notes that there is no evidence on record to show that the responding producers/exporters have made any qualifying investment to avail the benefit under the program. Nor the Government of Indonesia has provided any information on the companies’ eligibility as “Pioneer Industry”. Therefore, it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this program.

(v) Program No. 5: Exemption of Import Duty

Submissions by the Petitioners

91. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Indonesia. The Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investments provides incentives for investments in a variety of forms including exemptions or relief on import duty on capital goods, machines, or equipment not yet produced at home. Thus, the program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Article 18 of the Law No. 25 of 2007 provides several eligibility criteria and satisfaction of at least one of them is essential to avail the benefit. The program is, hence, specific because only those enterprises are eligible that meet the eligibility criteria.

92. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

93. The Government of Indonesia submitted that the “Masterlist program” is an investment facility granted in the form of import duty reduction and VAT exemption for import of capital goods in form of machineries and factory equipment. The reduction in import duty is granted under Ministry of Finance Decision No. 135/KMK.05/2000. It is granted to new investments or expansion of existing investments. The BKPM is the supervising agency for the program and reviews and approves applications for the program. The Authority had previously found the program to be not countervailable.

94. It has been submitted that VAT exemption is not countervailable as per anti-subsidy rules and the similar view has been taken by the Authority in the anti-subsidy investigation of copper.

Examination by the Authority

95. It is noted that the program is part of the “Masterlist program” that provides an import duty reduction and VAT exemption (dealt with in Program No. 7) levied on imports of capital goods in form of machineries and factory equipment. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The benefit is provided subject to the satisfaction of criteria enlisted under Article 18 of the Law No. 25 of 2007. While the Government of Indonesia stated that only one of the companies under investigation has availed the benefit under the said program, both the responding exporters, however, have accepted availing the benefits under the program in their exporter’s questionnaire response. The program is specific since only those enterprises are granted the benefit that meets the eligibility criteria prescribed. Hence, the Authority holds this program as countervailable.

96. Accordingly, it is noted that countervailing duty should be imposed against both the responding producers/exporters under this program.

(vi) Program No. 6: Exemption of Import Duty- Raw Materials

Submissions by the Petitioners

97. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Indonesia. The Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investments provides incentives for investments in a variety of forms including exemptions or relief on import duty of production raw materials or components for a definite period and with specified requirements. Thus, the program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Article 18 of the Law No. 25 of 2007 provides a number of eligibility criteria and satisfaction of at least one of them is essential to avail the benefit. The program is, hence, specific because only those enterprises are eligible that meet the eligibility criteria.

98. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

99. The Government of Indonesia submitted that under the program, a reduction is provided on import duty levied on import of strategic goods, which among others include machineries and factory equipment to be installed and used for production by newly established industry and/or expansion of existing industry. The proposals are to be approved by the BKPM. The eligibility criterion is the BKPM Decree issued on behalf of the Minister of Finance.

Examination by the Authority

100. It is noted that under this program, a reduction in import duty granted on the duty levied on import of raw material employed in new investments. There is a strict surveillance mechanism put in place by DG Customs to ensure that the program is not misused, and adequate penalty is put in place in case of violations. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is provided to only those companies that meet the strict eligibility criteria as per the BKPM Decree. The Authority, therefore, holds this program as countervailable.

101. The responding producers/exporters submitted in their Questionnaire Responses that they have not availed the benefit under the program since all raw materials were procured domestically. They have further submitted that they procure their primary raw material, i.e., wood, from private plantations. The Authority also notes that there is no evidence on record to show that the responding producers/exporters have imported their raw materials to avail the benefit under the program. Hence, it is noted that no countervailing duty should be imposed against responding producers/exporters under this program.

(vii) Program No. 7: Exemption of VAT

Submissions by the Petitioners

102. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Indonesia. The Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investments provides incentives for investments in a variety of forms including exemptions or deferment of Value Added Tax for a definite period on import of production capital goods or machines or equipment not yet produced at home for the purpose of production of exported products. Thus, the program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Article 18 of the Law No. 25 of 2007 provides several eligibility criteria and satisfaction of at least one of them is essential to avail the benefit. The program is specific because it is contingent on exports and hence, prohibited.

103. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The program is also not a permissible duty remission under footnote 1 of the ASCM and section 9B(b) of the Custom Tariffs Act.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

104. The Government of Indonesia submitted that the “Masterlist program” is an investment facility granted in the form of import duty reduction and VAT exemption for import of capital goods in form of machineries and factory equipment. It is granted to new investments or expansion of existing investments. The BKPM is the supervising agency for the program and reviews and approves applications for the program. The program is neither specific nor confer any benefit to the Indonesian producers of the PUC. The Authority had previously found the program to be not countervailable.

105. It has been submitted that VAT exemption is not countervailable as per Anti-subsidy rules and the similar view has been taken by the Authority in the Anti-subsidy investigation of copper.

106. It has been further submitted by the responding exporters that VAT exemption on capital goods does not constitute a subsidy under the Anti-subsidy Rules, 1995 on account of the facts that VAT exemption is neither revenue forgone nor contingent upon export performance. Moreover, it is not specific to the MDF industry but is available to all industries across sectors. Therefore, it is not specific in terms of Article 2 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). It is submitted that only the exemption or remission, in respect of the production and distribution of exported products, of indirect taxes in excess of those levied in respect of the production and distribution of like products when sold for domestic consumption is an export subsidy in terms of

para (g) of Annex I (Illustrative List of Export Subsidies) of ASCM. Therefore, it is clear without any doubt that VAT exemption is not a countervailable subsidy under the ASCM. VAT is creditable indirect tax. The Authority has also taken the view that VAT is not countervailable subsidy in the recent anti-subsidy investigation of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam dated 05 November, 2019.

Examination by the Authority

107. Authority notes that this subsidy program provides for exemption from value added tax on export of goods. The Authority notes that the subsidy program provides for remission of tax on exported goods which is otherwise borne by the like product when destined for domestic consumption in accordance with footnote 1 of the SCM Agreement and Section 9B(b)(i) of the Customs Tariff Act. Therefore, Authority holds that no countervailing duty should be imposed against this subsidy program.

(viii) Program No. 8: Accelerated Depreciation or Amortization

Submissions by the Petitioners

108. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Indonesia. The Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investments provides incentives for investments in a variety of forms including accelerated depreciation or amortization and resultantly a lower income tax liability. Thus, the program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Article 18 of the Law No. 25 of 2007 provides several eligibility criteria and satisfaction of at least one of them is essential to avail the benefit. The program is, hence, specific because only those enterprises are eligible that meet the eligibility criteria.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

109. The Government of Indonesia submitted that the program intends to stimulate investment in certain business fields and /or certain regions. Government Regulation No. 18/2015, amended by Government Regulation No. 9/2016, grants companies in 77 listed industries (1) 30% (5% per year for first six years of business’ operation) tax deduction for investment in the form of tangible assets, (2) accelerated depreciation and amortization, (3) lowered tax rate on dividend distributions to non-residential taxpayers, and (4) loss compensation.

110. It has been submitted that this program is not applicable since no benefit was availed by the exporters. The claim can be verified from the audit reports.

Examination by the Authority

111. The Authority notes that the program is granted under the Government Regulation No. 18/2015 which was later amended by Government Regulation No. 9/2016. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The benefit provided under the regulation is available only to 77 listed industries (1) 30% (5% per year for first six years of business’ operation) tax deduction for investment in the form of tangible assets, (2) accelerated depreciation and amortization, (3) lowered tax rate on dividend distributions to non-residential taxpayers, and (4) loss compensation. However, the producers of the subject goods are not enlisted under the 77 eligible industries. Hence, no benefit is provided to the companies under investigation under this program. Therefore, it is noted that no countervailing duty should be imposed under this program.

(ix) Program No. 9: Relief from Land and Building Tax

Submissions by the Petitioners

112. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Indonesia. The Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investments provides incentives for investments in a variety of forms including relief on Land and Buildings Tax, particularly for specified business sectors in specified regions or areas or zones. Thus, the program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Article 18 of the Law No. 25 of 2007 provides several eligibility criteria and satisfaction of at least one of them is essential to avail the benefit. The program is, hence, specific because only those enterprises are eligible that meet the eligibility criteria.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

113. The Government of Indonesia submitted that the program is available to Special Economic Zones established through Act No. 39/2009 and allows companies located and operating main business in such areas to obtain wide range of facilities and incentives from taxation to employment. There are 13 such zones designated in Indonesia.

As per the Government Regulation No. 96/2015, the regional governments may determine a reduction or exemption of regional tax, which includes the Land and Building Tax, or retribution from 50% and 100%.

114. It has been submitted that this program is not applicable since no benefit was availed by the exporters. The claim can be verified from the audit reports.

Examination by the Authority

115. It is noted that the program provides exemption or reduction from Land and Building Tax to those enterprises which are located in 13 Special Economic Zones as designated by Government of Indonesia. As per the Government Regulation No. 96/2015, the regional governments may determine a reduction or exemption of regional tax, which includes the Land and Building Tax, or retribution from 50% and 100%. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Hence, the program is specific as it is geographical specific and limited to certain enterprises which are located in 13 SEZ zones. Therefore, Authority holds this program as countervailable.

116. However, since none of the responding producers/exporters is located in any of the Special Economic Zones in Indonesia, they are not eligible to avail the benefit under the program. Hence, it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this program.

(x) Program No. 10: Exemption of Import Income Tax Article 22

Submissions by the Petitioners

117. The Government of Indonesia had stated in their Government Questionnaire Response that Mukti Panel had availed the benefit under the program. Though the producer claims that the Government had later clarified that the producer had not availed the program, a copy of the letter regarding the same was not provided to the Domestic Industry. Later on, the copy of the letter was served through a Paper-book circulated for the purpose of second oral hearing. The Authority is requested to verify the claim made by the producer and the authenticity of the letter submitted.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

118. The Government of Indonesia submitted that the program is administered by the Directorate General of Taxation under the Ministry of Finance. Under the Regulation No. 1/PJ/2011, an exemption on final income tax and import income tax is granted to taxpayers who (1) facing fiscal loss due to certain causes such as a) new taxpayer is in investment phase; b) the taxpayer is not in commercial operation; c) Force majeure, (2) eligible for fiscal loss compensation, and 3) the amount of paid income tax is greater than the payable income tax may apply for the program. All eligible taxpayers have to submit an application seeking an exemption and if approved, would apply for final income tax at 10% or income import tax at 2.5% rate and for the given tax year. The program is available to all sectors or regions and hence in compliance with the ASCM.

119. It has been submitted that this program is not applicable since no benefit construed as countervailable as per the anti-subsidy rules has been availed under this program. Complete details of imports and tax payable and paid have been provided. Mukti Panel has provided complete details of the taxes paid. The exemption of import income tax for import materials and capital goods does not confer a countervailable benefit since it is merely an instalment of annual income tax. No benefit is provided from exemption of import income tax since annual income tax is required to be paid.

120. Further, GOI clarified that as per the evidence submitted, PT. Mukti Panel Industry (MPI) was not exempted from paying 2.5% import income tax and hence no benefit has been received by them during the POI.

Examination by the Authority

121. It is noted that the program is administered by the Directorate General of Taxation under the Ministry of Finance. Under the program, an exemption is granted on income tax subject to eligibility criteria prescribed under Regulation No. 1/PJ/2011. Even when a company meets them, the benefit is provided subject to approval. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific since the enterprises eligible for the benefit under the program is limited through various eligibility criteria and further on the approval of the administering body. In view of the above, the Authority holds the program countervailable.

122. The Government of Indonesia has disclosed that Mukti Panel has not availed the benefit under the program. The other responding exporter has also stated that they have not received any benefit and Authority has not found any evidence on record to show that the responding exporters have received any incentives under the said scheme.

123. Therefore, the Authority notes that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this program.

(xi) Program No. 11a: Provision for Land at Less Than Adequate Remuneration

Submissions by the Petitioners

124. The petitioners submitted that in Indonesia, the land for plantations is owned by the government which provides the rights to utilize the land to companies as concessionary holders. If the concession holders do not perform their administrative requirements (e.g., ecological), the government can fine the concession holder and even revoke the concession. Thus, land is available to enterprises in Indonesia at less than adequate remuneration. There are two kinds of land involved – land for plantation which is subsumed in Program no. 1 & 2 and land for manufacturing units. The subsidy in the land for the plant/ manufacturing unit and not the forest land which needs to be quantified separately. The Authority has rightly analyzed the scheme whereby the manufacturing units have received land at subsidized rate and stated that Government of Indonesia provides land to companies on the levy of a concessionary rate. The same is not regulated by any law or regulation and is based on the discretion of the government. However, the Authority has considered most conservative benchmark in considering Tangerang land prices.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

125. The GOI and responding producers/exporters has stated that the Authority should reject the new alleged subsidies which were alleged at the time of written submissions. Further they stated that they have not benefit from the said programs. Factory land prices in Tangerang is not appropriate benchmark as the program pertains to forest land and Tangerang is located in a different island, i.e., Java.

126. Cooperating producers did not procure the factory land from GOI but they procured it from individual owners with full ownership rights. Indonesia National Land Agency (BPN) is the regulating authority which administers the legality of the land, not trade the land, directly or indirectly.

127. The exporter has purchased the land from private parties. The exporter has purchased the land at market price on arm's length basis. Further, it is submitted that the exporter has not taken the land on lease.

Examination by the Authority

128. It is noted that the Government of Indonesia provides land for forests on the levy of a concessionary rate. The Government of Indonesia controls nearly all (88%) the harvestable forest land and leases logging rights to companies levied for the right to harvest wood. The same is regulated by law or regulation and is based on the discretion of the government. The program provides a financial contribution in the form of provision for land for the forestry sector at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is specific since the benefit is provided at the direction of the government and is not available to all. Therefore, it is noted that countervailing duty should be imposed against this program. The Authority notes that the benefit under the land for plantations is subsumed in program no 1 & 2. However, the provision of factory land at LTAR is not included in Program 1 & 2.

129. With regard to the industrial land, it is noted that the Constitution of the Republic of Indonesia, under Article 33, states that land shall be controlled by the state and exploited for the greatest benefit of the people. Law No. 5 of 1960 which was brought into force for the regulation of land in Indonesia, under Article 20, states that the right to ownership of land is limited to Indonesian citizens. The right to ownership of land is not generally provided to corporate bodies and is granted only on the discretion of the government subject to the conditions laid down. The expense incurred by the responding producers/exporters on land has been taken from the Audit Reports filed along with their questionnaire responses. The average land prices for the industrial areas in Tangerang has been taken as the appropriate benchmark for land prices considering its proximity to the factory establishments of the responding producers/exporters.

Program No. 11b: Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration

Submissions by the Petitioners

130. Petitioner submits that electricity is heavily subsidized by the Ministry of Finance through Regulation No. 44 of 2017. This enables customers to purchase electricity from the government owed power general company, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), at less than adequate remuneration. The Government of Indonesia retains the right of exports of Coal and the domestic market obligations are required to be met for Coal. The domestic market

obligation was set at 25% of the production in 2019. Thus, the coal producers/miners are forced to first provide coal to meet the domestic demand. Thus, the Government of Indonesia by means of export tax, export restrictions and by allowing existence of the legal acts requiring Coal producers to sell domestically in Indonesia is directing private entities to provide financial contribution to electricity generators in the form of Coal at less than adequate remuneration. The benchmark price settings for coal were also enacted in 2011 through Minister of Energy and Mineral Resources No. 0617 W32[EM] 2011 on Coal Price which applied for coal purchased by National Electric Company (PLN). Indonesian Government determines the capping of maximum selling price for coal. Selling price for coal for electricity is set at US\$ 70 per MT. Any company engaged in production of coal is required to sell such coal following the decree issued by GOI, irrespective of its legal status. Coal is being made available at a cheaper rate to the domestic producers of subject goods by putting a maximum price cap on coal for purpose of electricity generation. Hence the power purchased by the fibreboard producers is subsidised. Applicant relies upon the final findings issued by the Authority in the matter of anti-subsidy investigation concerning imports of "Flat Products of Stainless Steel" from Indonesia. The applicant submits that the Authority should quantify subsidy in electricity procured at less than adequate remuneration.

131. Further, as per Indonesia Constitution Article 33 (3) - The land, the waters and the natural riches contained therein shall be controlled by the State and exploited.

Submissions by Government of Indonesia/other interested parties

132. All industries are eligible for the electricity supplied by PLN because it is only major supplier to industries in Indonesia. The quantity and value of electricity provided to each respondent during the POI are recorded in the electricity bills maintained by PLN. Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) Regulation 28/2016 electricity tariff is classified into 8 categories.

- (a) Small households/industry at low voltage, power at 450 VA – 14 kVA (I-1/TR);
- (b) medium industry at low voltage, power above 14 kVA – 200 kVA (I-2/TR);
- (c) medium industry at medium voltage, power above 200 kVA (I3/TM); and
- (d) big industry at high voltage, power of 30000 kVA and above (I4/TT),

133. PLN is a commercial supplier of electricity apart from public sector and provides electricity as public service. Since it provides electricity to all sectors hence not specific as per WTO and ASCM. Tariff adjustment of electricity is published every three months and can be accessed through the official website. The responding companies are classified under the tariff group of the Medium scale industry at medium voltage, with the power of over 200 kVA (I-3/TM).

134. There is no restriction on the importation of electricity. Electricity tariffs are set by taking into account the customer's purchasing power as well as the installed power capacity of each customer group.

135. PT Bukit Asam is the state-owned company established on March 1, 1981, a Limited Company under the name of PT Bukit Asam (Persero) or widely known as PTBA. The company focus on coal mining, exploration, exploitation, purification and processing. Apart from PT Bukit Asam there are 700 private miners in the country who are free to carry out the said activities in Indonesia based on purely commercial principles. GOI does not intervene in the transaction of coals as it is fully dependent on the negotiation between the parties. PTBA is a 100% state-owned company. Private sectors are given licenses to conduct mining (Ijin Usaha Pertambangan – IUP). The GOI has control over PTBA, either directly through the Series A Dwi Warna shares, or indirectly through PT Inalum (Persero).

136. Total domestic consumption reached approximately 115 million tonnes in 2018 (20,61%) and 138 million tonnes in 2019 (22,40%). The GOI does not limit imports of Coal.

137. The price of coal depends on the calories and commercial terms agreed upon by the sellers and the buyers. This situation applies to both PT Bukit Asam and private coal producer.

138. The ceiling price fixed for the PT Bukit Asam is based on the formula of production cost plus margin which covers profit and risk of the mining company in the minimum amount of 15% and the maximum amount of 25% of total production cost. Therefore, it would be completely incorrect to assume that coal is made available to PLN at less than market value.

139. No evidence has been provided either by the applicants or by the Authority to show that the users are actually getting electricity at subsidized rates. The exporter reiterates that electricity is not provided to it at subsidized rates. In order to substantiate their claim in this context, the sample electricity invoices of the exporter during the POI along with English translation of December 2018 invoice have been submitted and a request has been made

to the Authority not to recommend any subsidy under this program. As regards the unsubstantiated allegation that the coal is available to PLN at prices below the market rates, it is submitted that the said decree merely puts a ceiling on the price at which PLN shall procure coal. There is no compulsion that coal has to be necessarily supplied at this price. PLN is free to procure coal from thousands of private suppliers /miners in the country. It needs to be appreciated that PLN is a huge buyer of coal and is in a position to get coal at better prices. It has been further submitted by the responding exporters that even the ceiling price fixed for the PT Bukit Asam is based on the formula of production cost plus margin which covers profit and risk of the mining company in the minimum amount of 15% and the maximum amount of 25% of total production cost. Therefore, it would be completely incorrect to assume that coal is made available to PLN at less than market value.

Examination by the Authority

140. It is noted that electricity in Indonesia is produced from coal. The benchmark price setting for coal purchased by the National Electric Company (PLN) is fixed by the Minister of Energy and Mineral Resources No. 0617 K/32/MEM/2011. The Authority notes that the Government of Indonesia by means of export tax, export restrictions and by allowing existence of the legal acts requiring coal producers to sell domestically in Indonesia is directing government as well as private entities to provide coal at less than adequate remuneration to PLN. The coal producers/miners are forced to first provide coal to meet the domestic demand. Hence, coal is available to PLN at a rate below the market rates. The program is specific since the benefit of coal at cheaper rates is available to the only power supplier in Indonesia which ultimately makes it possible for PLN to provide electricity to consumers at a subsidized rate. The companies under investigation are beneficiaries of such electricity at cheap rates. The program provides a financial contribution in the form of provision for electricity at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. Therefore, it is noted that countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this program.

141. To determine the quantum of the subsidy margin, the Authority looked for the appropriate benchmark. The Authority has relied upon the prices provided as per the website of ‘globalpetrolprices’. The actual electricity tariffs paid by the responding producers as per the additional questionnaire response has been considered to determine the subsidy margins. Considering the methodology above, the subsidy margin determined for the responding exporters has been provided in the table below.

PT. Mukti Panel Industries

142. PT Mukti Panel Industries is a producer/exporter of subject goods in Indonesia. Mukti Panel filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

143. Authority examined the response filed by Mukti Panel and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Mukti Panel has disclosed in its questionnaire response that it has availed exemption on import duty. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in provision for land, wood and electricity at LTAR were availed by Mukti Panel. As a result, benefit was conferred to Mukti Panel in the form of various subsidies.

144. Authority has verified the information provided by Mukti Panel and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

145. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 1 & 2	Provision for standing timber at LTAR	***%	0-10
2	Program No 5	Exemption of Import Duty	***%	0-10
3	Program No 11a	Schemes identified in the form of Land Subsidy	***%	0-10
4	Program No 11b	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

PT. Sumatera Prima Fiberboards

146. PT Sumatera Prima Fiberboards is a producer/exporter of subject goods in Indonesia. Sumatera filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

147. Authority examined the response filed by PT Sumatera Prima Fiberboards and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. PT Sumatera Prima Fiberboards has disclosed in its questionnaire response that it has availed exemption on import duty. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in provision for land, wood and electricity at LTAR were availed by PT Sumatera Prima Fiberboards. As a result, benefit was conferred to PT Sumatera Prima Fiberboards in the form of various subsidies.

148. Authority has verified the information provided by PT Sumatera Prima Fiberboards and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

149. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 1 & 2	Provision for standing timber at LTAR	***%	0-10
2	Program No 5	Exemption of Import Duty	***%	0-10
3	Program No 11a	Schemes identified in the form of Land Subsidy	***%	0-10
4	Program No 11b	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

150. Countervailing duty for all other producers/exporters from Indonesia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating party, for the subsidies availed by them and based on facts available for other subsidy programs.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 1 & 2	Provision for standing timber at LTAR	***%	0-10
2	Program No 5	Exemption of Import Duty	***%	0-10
3	Program No 11a	Schemes identified in the form of Land Subsidy	***%	0-10
4	Program No 11b	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Malaysia

Program No. 1: Market Development Grant

Submissions by the Petitioners

151. The petitioners submitted that the said program is administered by the Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE). The Guidelines for Market Development Grant (MDG), 2018 allows Small and

Medium Enterprises (SMEs) that meet certain eligibility criteria to claim up to 100% reimbursement on actual expenses incurred while participating in a number of export promotional activities listed in the guidelines. The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds and a benefit is thereby conferred. The benefit under the program is available to enterprises contingent on exports and hence, is deemed specific.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

152. The Government of Malaysia submitted that the Market Development Grant is part of the SME masterplan structured under the 11th Malaysia Plan (2016-2020) for the purpose of increasing the SME's participation in export promotional activities. Malaysian SMEs are provided a reimbursement grant up to RM 200,000 for participation in export promotional activities. The grants are disbursed subject to approval.

Examination by the Authority

153. It is noted that Market Development Grant (MDG) is a part of the 11th Malaysian Plan (2016-20). It is intended to increase participation of SMEs in export promotional activities. The MDG provides SMEs a reimbursable grant up to RM 200,000 for their participation in export promotional activities such as International Trade Fairs, Trade & Investment Missions /Export Acceleration Missions, International Conferences Overseas and Listing Fees for Made-in-Malaysia Products.

154. The subsidy program provides for financial contribution in the form of direct transfer of funds and benefit is thereby conferred to the recipient. The subsidy program is also specific because is contingent on export. Therefore, the Authority holds this program countervailable.

155. SME with at least 60% of the equity owned by Malaysians is only eligible for the program. . Since none of the responding producers/exporters meet this criterion, therefore, it is noted that no countervailing duty should be imposed against responding producers/exporters under this subsidy program.

Program No. 2: Export Credit Refinancing

Submissions by the Petitioners

156. The petitioners submitted that the said program is administered by the Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank). The Export Credit Refinancing Guideline issued by the EXIM Bank provides an Export Credit Refinancing (ECR) scheme that is used to promote Malaysia's exports and international trade in the form of Pre-shipment and Post- shipment financing. Pre-shipment financing is an advance by EXIM Bank to facilitate the export of Malaysian products prior to shipment and post-shipment financing is an advance unto 100% export bill value provided to exporters to finance the export after shipment. The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds and a benefit is thereby conferred. The benefit under the program is available to enterprises contingent on exports and hence, is deemed specific. Additionally, the ECR Guidelines contain a negative list to identify eligible products for the program.

157. The responding exporters have failed to provide reasons for non-availment of the program despite being eligible for the same.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

158. The Government of Malaysia submitted that the scheme is used to promote Malaysia's exports and international trade in the form of pre-shipment and post-shipment financing. The program is available to any manufacturing and export trading companies (1) incorporated in Malaysia, and (2) involved in export activities.

Examination by the Authority

159. It is noted that the program is administered by Export-Import Bank of Malaysia (EXIM Bank). Export credit refinancing program provides loan to enterprise to finance export of products. The program is governed by Export Credit Refinancing guidelines issued by the Bank, which provides for eligibility criteria including eligibility of product (negative list of products which is maintained by bank) for the purpose of the program. The subsidy program is not restricted to any particular sector and is available to all companies incorporated in Malaysia.

160. EXIM Bank is a government-owned financial institution. It is a wholly owned subsidiary of the Minister of Finance. As an agency under the purview of the Ministry of Finance, the major role of the Exim Bank is to provide credit facilities to finance and support exports and imports of goods, services and overseas projects with

emphasis on non-traditional markets, providing export credit insurance services, export financing insurance, overseas investments insurance and guarantee facilities.

161. It is noted that the EXIM Bank is a public body because it is owned by Government and is vested with the Government Authority to carry out governmental functions. Accordingly, the loan provided by EXIM Bank is financial contribution in the form of direct transfer of funds by a public body. The program is also specific because it is contingent on export. The benefit conferred on the recipient is in the form of difference between the amount of interest charged by the EXIM bank and the amount of interest charged by the comparable commercial bank. Therefore, based on the above facts the Authority holds this program as countervailable. However, since none of the responding producers/exporters have availed benefit under this program, it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

Program No. 3: Buyer Credit Guarantee

Submissions by the Petitioners

162. The petitioners submitted that the said program is administered by the Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank). The provides extends a Bankers Trade Credit Takaful (BTCT) which is a Credit Takaful designed to protect the Islamic Financial Institutions (IFIs) against risk of non-payment by their exporters arising from default by the overseas buyers. The program covers risk to the tune of 70% of the Export Bill or Advances and 95% of Letter of Credit Value. The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds and a benefit is thereby conferred. The benefit under the program is available to enterprises contingent on exports and hence, is deemed specific.

163. The responding exporters have failed to provide reasons for non-availment of the program despite being eligible for the same.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

164. The Government of Malaysia submitted that the Bankers Trade Credit Takaful (BTCT) which is a Credit Takaful designed to protect the Islamic Financial Institutions (IFIs) against risk of non-payment by their exporters arising from default by the overseas buyers.

Examination by the Authority

165. It is noted that the program is administered by EXIM Bank. There is no law or legal regulation governing the program. It has already been determined in the above scheme that EXIM Bank is a public body. Under this program, EXIM Bank provides guarantee to financial institutions against risk of non-payment by their exporters (customers) because of default arising from overseas buyers.

166. The program provides for financial contribution in the form of potential direct transfer of funds and benefit is thereby conferred. The benefit conferred on the recipient is equivalent to (i) the difference between the fee paid by the recipient for availing guarantee from EXIM Bank and the fee that would have been paid to any other commercial bank for such guarantee and (ii) the difference between the loan repayment to the lending bank in question (owing to less than normal commercial interest rate because of EXIM bank guarantee) and the amount that would have been payable in absence of such guarantee (based on normal commercial interest rate). The subsidy program is also specific because it is contingent on export. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

167. As submitted by the responding producers/exporters that they have not availed any benefit under this program, hence it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

Program No. 4: Pioneer Status

Submissions by the Petitioners

168. The petitioners submitted that the said program is administered by the Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), and the Inland Revenue Board Malaysia. Sections 5-25 of the Promotion of Investment Act, 1986 grants a Pioneer Status to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product as listed in the Promotion of Investments (Promoted Activities and Promoted Products) Order, 2012. Such enterprises are provided tax incentives for their investments in those sectors/products and losses incurred from non-promoted activity is reduced from the statutory income raised from the promoted activity. The

program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it provided the benefit only to enterprises engaged in promoted activity/product as per the law.

169. The responding exporters have failed to provide reasons for non-availment of the program despite being eligible for the same.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

170. The Government of Malaysia submitted that the Pioneer Status may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product, as determined by the Minister of Finance and the Minister of International Trade and Industry, including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. The benefit under the program is provided subject to approval by the Approval Committee.

171. The Government also submitted that changes will be made to the program since it is committed to adopt the Forum on Harmful Tax Practices program under the OECD.

172. It has been submitted that eligibility for a program or mere admission of existence of an alleged subsidy program does not show all eligible producers ought to have applied and availed the benefit. There is no obligation to prove the negative.

Examination by the Authority

173. It is noted that Sections 5 to 25 of the Promotion of Investment Act, 1986 provides for the Pioneer Status program. The program provides for tax incentives in the form of exemption from income tax. Losses incurred during the exemption period can be carried forward for subsequent years to offset taxable income/net profit. The program is available for pre-specified list of promoted products/activities.

174. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to promoted activity/product mentioned in the list. Examination of the list shows that the promoted product includes the product under investigation. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

175. The responding producers/exporters merely submitted in their Questionnaire Response that they have not availed the benefit under the program. Both the responding producers/exporters are eligible to receive the benefits under the program as per sections 5 to 25 of the Promotion of Investments Act, 1986 and the Promotion of Investments (Promoted Activities and Promoted Products) Order, 2012.

176. However, on perusal of the documents submitted along with the Questionnaire Responses, it is evident that neither M/s Segamat Panel Boards nor M/s Robin Resources availed the benefit under the program. Therefore, it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this subsidy program.

Program No. 5: Investment Tax Policies

Submissions by the Petitioners

177. The petitioners submitted that the said program is administered by the Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), and the Inland Revenue Board Malaysia. Sections 26-29 of the Promotion of Investment Act, 1986 grants an Investment Tax Allowance to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product as listed in the Promotion of Investments (Promoted Activities and Promoted Products) Order, 2012. The allowance is only given on capital expenditure incurred on industrial buildings, plants and machinery directly used for the purpose of the promoted activities or the production of the promoted products. The allowance of not more than 100% of the qualifying expenditure is granted and the same is exempt from the tax payable. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it provided the benefit only to enterprises engaged in promoted activity/product as per the law.

178. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and was found countervailable.

179. The responding exporters have failed to provide reasons for non-availment of the program despite being eligible for the same. Moreover, one of the responding exporters, i.e. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd., has been approved by the Government of Malaysia to avail the program.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

180. The Government of Malaysia submitted that the Investment Tax Allowance may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product, as determined by the Minister of Finance and the Minister of International Trade and Industry, including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. The allowance is only given on capital expenditure incurred on industrial buildings, plant and machinery directly used for the purpose of the promoted activities or the production of the promoted products. The benefit under the program is provided subject to approval by the Approval Committee.

Examination by the Authority

181. It is noted that Sections 26 to 29 of the Promotion of Investments Act, 1986 provides for Investment Tax Allowance program. Promoted activities and promoted products are granted capital allowance. Out of the total capital expenditure, 60% of the capital expenditure is granted as allowance and can be deducted against 70% of statutory income for 5 years. Remaining income can be taxed at normal income tax rate. Even for companies that incur the qualifying expenditure, the Approval Committee retains the discretion to reject the applicant seeking benefit under this program.

182. At the stage of desk verification for the Government of Malaysia, the Authority had sought clarification on programs administered under sections 26-29 of the Promotion of Investment Act, 1986 (Program No. 5) and 127 (3A) of the Income Tax Act, 1967 (Program No. 19). Based on the information provided, the Authority is convinced that the response filed by M/s Robin Resources under the heading of Program No. 5 pertains to Program No. 19.

183. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is limited to certain enterprises engaged in promoted activities/products as per the Promotion of Investments (Promoted Activities and Promoted Products) Order, 2012 and are approved by the Approval Committee. A company that has received income tax exemption from Pioneer Status cannot avail benefit under this program. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

184. However, M/s Segamat Panel Board has submitted in its Questionnaire response that the Government of Malaysia approved the program to M/s Segamat Panel Board on 10 August, 2004 but no benefit was availed in the POI and M/s Robin Resources has also submitted that it has not availed any benefit under this program, accordingly, it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

Program No. 6: Reinvestment Allowance

Submissions by the Petitioners

185. The petitioners submitted that the said program is administered by the Inland Revenue Board Malaysia. Schedule 7A of the Income Tax Act, 1967 and the Public Ruling No. 6/2012 grants a reinvestment allowance at the rate of 60% on the qualifying capital expenditure incurred by the company and can be offset against 70% of its statutory income for the year of assessment. It is also given for a period of 15 consecutive years beginning from the year the first reinvestment is made. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is available to enterprises that are in operation for at-least 3 years and are undertaking qualifying projects (expanding, modernizing or automating its existing business in respect of manufacturing).

186. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

187. The Government of Malaysia submitted that tax exemption may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product, as determined by the Minister of Finance and the Minister of International Trade and Industry, including an activity/product which is of national and strategic

importance to Malaysia. To avail the program, (1) the business must have been in operation for not less than 36 months, and (2) the company/person must have incurred, in the base year for year of assessment, capital expenditure on a factory, plant or machinery used in Malaysia for the purpose of a qualifying project. The allowance is provided for fifteen consecutive years of assessment beginning from the year of assessment for the basis period in which a claim is made. Since it is not linked to export conditions, not specific and is generally available, it is not a countervailable subsidy.

Examination by the Authority

188. It is noted that a company or a person resident in Malaysia is granted Reinvestment Allowance if the company is in operation for 3 years and has incurred capital expenditure on factory, plant and machinery for qualifying project. Deduction is granted from 70% of statutory income for 60% of such capital expenditure. Re-investment allowance can be claimed for 15 years beginning from the year of assessment in which a claim is made. Inland Revenue Board is responsible for administration of this program.
189. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. Even though the subsidy program is not limited to promoted activity, still the subsidy program is specific because it is available to enterprises that are in operation for at-least 3 years and are undertaking qualifying project (expanding, modernizing or automating its existing business in respect of manufacturing). Therefore, the Authority holds this program as countervailable.
190. The responding producers/exporters have submitted in their Questionnaire Response that they have not availed the benefit under the program. Hence, it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

Program No. 7: Accelerated Capital Allowance

Submissions by the Petitioners

191. The petitioners submitted that the said program is administered by the Inland Revenue Board Malaysia. The Income Tax (Accelerated Capital Allowance) (Information and Communication Technology Equipment) Rules 2018 grants an allowance which shall be equal to one-fifth of the capital expenditure incurred for the purchase of any information and communication technology equipment. The amount equal to the allowance is further deducted from the company's taxable income. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is available only to enterprises that incur a qualifying expenditure as per the relevant law and does not qualify for reinvestment allowance on account of expiry of 15 years period of eligibility.
192. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.
193. The benefit received under the program is such that it would flow down to the PUC. Moreover, money is fungible and the company has the discretion to use it for any of its business segments. In a CVD investigation, the subject of the investigation is the company as a whole and not the product. The “de-minimis” rule is not applied to a program but on an exporter-wise basis.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

194. The Government of Malaysia submitted that the Accelerated Capital Allowance provides allowance which shall be equal to one-fifth of capital expenditure incurred for the purchase of any information and communication technology equipment. The program is not a countervailable subsidy since it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available.
195. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. submitted that the program is not countervailable since it is neither prohibited nor specific. The benefit was received for the Company as a whole and not specific for the PUC.
196. It has been submitted that the petitioners' submission on countervailability has no basis. The GOM further stated that the program is available to all companies and those that meet the eligibility criteria can claim the ACA. The subsidy margin calculated under this program is negligible and no duty should be recommended.

197.The margin under the program as per the disclosure statement is negligible and no countervailing duty should be recommended.

Examination by the Authority

198.It is noted that the program provides for capital allowance i.e., an allowance which shall be equal to one-fifth of the capital expenditure incurred for the purchase of any information and communication technology equipment. The program allows the company to write off the allowance from its taxable income.

199.It is further noted that the program provides for capital allowance i.e., deduction of capital expenditure from statutory income to promoted activity after the expiry of 15 years of reinvestment allowance period. The program allows to write off the total capital expenditure within three years, i.e., an initial allowance of 20 percent in the first year and an annual allowance of 40 percent in the next two years.

200.The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is available to certain enterprise carrying out promoted activity that qualify for using this allowance and does not qualify for re-investment allowance on account of expiry of 15 years period of eligibility incurring the qualifying expenditure. Therefore, the Authority holds this program as countervailable program.

201.It is noted that as per the Questionnaire response filed Robin, the company has not availed the benefit under the said scheme, whereas M/S Segamat Panel Boards has received the benefit. The Authority has quantified the subsidy margin based on the information submitted by the M/S Segamat Panel Boards. The subsidy margin determined has been provided in the table below.

Program No. 8: Tariff Related Incentives

Program No. 13: Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components

202.The benefit provided under program No. 8 and Program No. 13 are the same. Hence, both these programs are analysed together.

Submissions by the Petitioners

203.The petitioners submitted that the said program is administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD) and the Malaysian Investment Development Authority (MIDA). Section 14(2) of the Customs Act, 1967 grants a full exemption from import duty on raw materials/components provided they are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s). The exemption applies for the production of finished products whether meant for the export or domestic market. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to enterprises that use raw materials that are not available locally.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

204.The Government of Malaysia submitted that the program involves evaluating duty exemption on raw material/component for qualified manufacturers. The same is done by a committee established with representatives from MoF, MITI, RMCD, and MIDA. To qualify for the same, the raw materials/components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premises. The program is not countervailable since it conforms to the provisions of Annexes I, II, and III of the ASCM.

Examination by the Authority

205.It is noted that the program is administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD) and the Malaysian Investment Development Authority (MIDA). The program provides import duty exemption on raw material/component to approved manufacturers. Exemption is granted when the raw materials/components are not locally available and used directly in the production of the finished product at the approved manufacturer's premise(s).

206. It is further noted that the program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is specific because it is limited to enterprises that use raw materials that are not available locally. Therefore, the Authority holds this program as countervailable program.

207. It is also noted that benefit has not been availed by any of the cooperating producers/exporters under this program, therefore it is decided not to impose any countervailing duty against them under this program.

Program No. 9: Allowance for Plants and Machinery

Submissions by the Petitioners

208. The petitioners submitted that the said program is administered by the Inland Revenue Board Malaysia. Schedule 3 of the Income Tax Act, 1967 grants a capital allowance (CA) amounting to 20% of the company's qualifying expenditure on machinery or plant i.e. relief for wear and tear of fixed assets for business in the year of assessment. The CA is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is specifically beneficial to sectors having high capital expenditure and meets the eligibility criteria.

209. The benefit received under the program is such that it would flow down to the PUC. Moreover, money is fungible and the company has the discretion to use it for any of its business segments. In a CVD investigation, the subject of the investigation is the company as a whole and not the product.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

210. The Government of Malaysia submitted that capital allowance is deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. It is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income in arriving at the statutory income. The program is not a countervailable subsidy since it is not linked to export conditions, not specific and it is generally available.

211. M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. and Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. submitted that the program is not countervailable since it is neither prohibited nor specific. The benefit was received for the company as a whole and not specific for the PUC.

212. The exporters stated that the program is neither specific nor contingent on exports. The GOM further stated that the program is available to all companies and those that meet the eligibility criteria can claim the Capital Allowance.

Examination by the Authority

213. It is noted that capital allowance provides deductions for qualifying expenditure on machinery or plant. It is given to enterprise that incurs the qualifying expenditure. It is calculated for a year of assessment and is deducted from the adjusted income from the business in arriving at the statutory income. It is calculated on a straight-line method on the basis of a prescribed rate of allowance.

214. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is specific because though it is generally available as per the law, it would benefit those companies that have high capital expenditure in practice. Therefore, Authority holds this program as countervailable.

215. It is noted as per the Questionnaire responses filed by both M/s Segamat Panel Board and M/s Robin Resources that they have availed the benefit under this subsidy program. Accordingly, it is noted that countervailing duty should be imposed against this subsidy program to M/s Segamat Panel Board as well as M/s Robin Resources. The Authority has quantified the subsidy margin based on the information submitted by M/s Segamat Panel Board and M/s Robin Resources in their Questionnaire Responses.

Program No. 10: Incentives for Manufacturing and Manufacturing related Services in East Coast Economic Corridor

Submissions by the Petitioners

216. The petitioners submitted that the said program is administered by the Inland Revenue Board Malaysia and the East Coast Economic Region Development Council. The Income Tax (Exemption) (No. 4) Order, 2016 grants a tax exemption to companies located in the East Coast and engaged in a production process that leads to value

addition subject to the approval from the Approval committee. The tax exemption can be in the form of a customized incentives based on merit of each case, or 100% income tax exemption for 10 years from the year the company derives statutory income, or 100% income tax exemption amounting to a qualifying capital expenditure (Investment Tax Allowance) for 5 years, or stamp duty exemption on land or building acquired for development. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific as it is limited to promoted products and also specific to region i.e., enterprise whose project is located in the east coast economic corridor.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

217. The Government of Malaysia submitted that tax exemptions may be granted to any company intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product, as determined by the Minister of Finance, including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia. In order to avail the benefit (1) the project should be located in the East Coast of Malaysia, (2) have value added, and (2) have level of technology as measured by the Managerial, Technical and Supervisory (MTS) Index. The benefit is further subject to approval by the Approval Committee.
218. The Government also submitted that changes will be made to the program since it is committed to adopt the Forum on Harmful Tax Practices program under the OECD.

Examination by the Authority

219. It is noted that full income tax exemption is granted under this program to the company whose project is located in the East Coast Economic Corridor and is intending to participate in a promoted activity or to produce a promoted product including an activity/product which is of national and strategic importance to Malaysia.
220. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to promoted products and also specific to region i.e., enterprise whose project is located in the East Coast Economic Corridor. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.
221. However, none of the producers of the subject goods are found to be located in the East Coast Economic Corridor. Hence, it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters under this program.

Program No. 11: Drawback on Import duty, Sales tax and Excise duty

Submissions by the Petitioners

222. The petitioners submitted that the said program is administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD). Sections 93, 95, and 99 of the Customs Act, 1967 grants drawback on import duty, sales tax and excise duty that have been paid may be claimed by a manufacturer if the parts, raw materials or packaging materials are used in the manufacture of goods for export within a year based on conditions stipulated in the acts. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program was found specific by the DA and countervailable in the Final Findings of the CVD investigation on “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

223. The Government of Malaysia submitted that the program provides a duty import refund on imported goods subsequently re-exported. The program is not countervailable since it conforms to the provisions of Annexes I, II, and III of the ASCM. The Panel Report in EU-Countervailing Measures on certain Polyethylene Terephthalate from Pakistan (DS 486), which was later upheld by the Appellate Body, held that products can be countervailed only to the extent that remission of duties obtained by a company is in excess of the duties accrued on the imported inputs.

Examination by the Authority

224. It is noted that the program is administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD). Sections 93, 95, and 99 of the Customs Act, 1967 grants drawback on import duty, sales tax and excise duty that have been paid may be claimed by a manufacturer if the parts, raw materials or packaging materials are used in the manufacture of goods for export within a year based on conditions stipulated in the acts. The program provides

import duty refund on goods that are subsequently re-exported. In absence of any evidence to show that the program provides for permissible tax remission, it is determined that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is export specific. Therefore, the Authority holds this program as countervailable program.

225. However, it is noted that benefit has not been availed by any of the cooperating producers/exporters under this program, therefore it is decided not to impose any countervailing duty against them under this program.

Program No. 12: Sales Tax Exemption

Submissions by the Petitioners

226. The petitioners submitted that the said program is administered by the Royal Malaysian Customs Department (RMCD). The Sales Tax (Persons Exempted from Payment of Tax) Order, 2018 grants an exemption from payment of sales tax to specific persons listed under the Order. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is available only to persons listed under the Order.

227. The benefit received under the program is such that it would flow down to the PUC. Moreover, money is fungible and the company has the discretion to use it for any of its business segments. In a CVD investigation, the subject of the investigation is the company as a whole and not the product.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

228. The Government of Malaysia submitted that there are persons or manufacturers who are exempted from paying sales tax on importation and purchase of locally manufactured goods under the Sales Tax (Persons Exempted from Payment of Tax) Order, 2018. The exemptions are classified into three schedules under the Order.

229. M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. and Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. submitted that the program is not countervailable since it is neither prohibited nor specific nor export contingent. The benefit was received for the Company as a whole and not specific for the PUC.

230. The GOM further stated that the program is available to all companies and those that meet the eligibility criteria can claim the sales tax exemption.

Examination by the Authority

231. It is noted that the program, is administered by the Royal Malaysian Custom Department. The program provides an exemption from payment of sales tax is granted to those persons enlisted under the Sales Tax (Persons Exempted from Payment of Tax) Order, 2018. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is available only to persons listed under the Order. Therefore, Authority holds this program as countervailable program.

232. It is noted as per the Questionnaire responses filed by both M/s Segamat Panel Boards and M/s Robin Resources that they have availed the benefit under this subsidy program. Accordingly, it is noted that countervailing duty should be imposed against this subsidy program to M/s Segamat Panel Board as well as M/s Robin Resources. The Authority has quantified the subsidy margin based on the information submitted by M/s Segamat Panel Boards and M/s Robin Resources in their Questionnaire Responses.

Program No. 14: Double Deduction for Promotion of Exports

Submissions by the Petitioners

233. The petitioners submitted that the said program is administered by the Inland Revenue Board Malaysia. Section 41 of Promotion of Investment Act, 1986 read with Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules 1986 grant an exemption on expenses incurred for the purpose of seeking opportunities, or in creating or increasing a demand for the export of Malaysian manufactured goods or agricultural products from income tax. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on export performance and is limited to enterprises engaged in export promotion activity.

234. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

235. M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. has failed to provide reasons for non-availment of the program despite being eligible for the same.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

236. The Government of Malaysia submitted that the program is applicable to all resident trading, manufacturing or agricultural companies in respect of expenses incurred for the purpose of seeking opportunities or in creating or increasing demand for the export of Malaysian manufactured goods or agricultural products.

237. Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. submitted that the program is not countervailable since it is neither prohibited nor specific. The benefit was received for the Company as a whole and not specific for the PUC.

238. It has been submitted that benefit is not automatic, and an application is required for the same. M/s Segamat Panel Boards has never got any benefit from it.

Examination by the Authority

239. It is noted that the program is governed by Section 41 of the Promotion of Investments Act, 1986 and Rule 4(2) of the Income Tax (Promotion of Exports) Rules, 1986. Under the program, double deduction from income is provided to enterprise involved in manufacturing, trading and agricultural activities for expenses incurred for promotion of export.

240. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit is the difference between the amount of income tax paid after double deduction and the amount of income tax that would have been payable in absence of such double deduction. The program is also specific because it is contingent on export performance and is limited to enterprise engaged in export promotion activity. The Authority, therefore, holds this program as countervailable.

241. It is noted as per the Questionnaire responses filed by M/s Robin Resources that the company has availed the benefit under this subsidy program. However, no such benefit has been availed by M/s Segamat Panel Boards. Accordingly, it is noted that countervailing duty should be imposed against this subsidy program for Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. The Authority has quantified the subsidy margin based on the information submitted by Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. in its Questionnaire Response.

Program No. 16: Incentives for Small and Medium Enterprises

Submissions by the Petitioners

242. The petitioners submitted that the said program is administered by the Inland Revenue Board Malaysia. Schedule 1 of the Income Tax Act, 1967 grants a special tax rate for a resident company with paid up capital of RM2.5 million and below at the beginning of the basis period. Such companies have an income tax rate of 18% on the first RM500,000 chargeable income and 24% on the subsequent chargeable income. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to small and medium scale enterprises.

243. M/s Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. has failed to provide reasons for non-availment of the program despite being eligible for the same.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

244. The Government of Malaysia submitted that a special tax rate, at 18% for the first RM 500,000 chargeable income and 24% for subsequent chargeable income, is granted for a resident company with paid up capital of RM 2.5 million and below at the beginning of the basis period. The company should also not be part of a group of companies where any related party has a paid-up capital more than RM 2.5 million.

Examination by the Authority

245. The Authority notes that under this program, preferential income tax rate is provided for SMEs i.e., enterprise with paid up capital of RM 2.5 million and below. The chargeable income tax on the income up to RM 500,000 is 18% and that above RM 500,000 is 24%.

246. The program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific because it is limited to small and medium scale enterprise. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

247.The Audit Record submitted by the responding producers/exporters shows that the income tax has been paid at the normal income tax rate and hence no benefit has been availed by them. In view of the above, it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

Program No. 17: Allowance for Increased Export

Submissions by the Petitioners

248.The petitioners submitted that the said program is administered by the Inland Revenue Board Malaysia. The Income Tax (Allowance for increased exports) Rules, 1999 grants an allowance which is equal to 10% of the value of increased exports of the manufactured products where the products exported attained at least 30% of value added, or 15% where the products exported attained at least 50% of value added, or 10% of the value of increased exports of agricultural produce by the company. Such allowance is given against seventy percent of statutory business income of the company. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

249.The Government of Malaysia submitted that a resident manufacturing company or agricultural company that exports in the basis year for a year of assessment is given an allowance for increased exports. In case of manufactured products, the allowance is determined as follows:

- 10% of the value of increased exports of the manufactured products of the company where the products exported attained at least 30% of value added;
- 15% of the value of increased exports of the manufactured products of the company where the products exported attained at least 50% of value added.

Examination by the Authority

250.It is noted that a resident manufacturing company or agricultural company that exports manufactured products or agricultural produce is to be given an allowance for increased exports. The allowance is equivalent to 10% or 15% of the value of increased exports of the manufactured products by the company. Allowance will be given against 70% of the statutory business income.

251.The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due. The program is also specific because it is contingent on export performance. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

252.However, as no benefit has been availed by the cooperating producers/exporters under this program, therefore, it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters under this program.

Program No. 18: Tax Exemptions for Exporters in Free Trade Zones

Submissions by the Petitioners

253.The petitioners submitted that the said program is administered by the Free Zone Authority and the Customs Authorities. The Free Zone Act, 1990 and the Free Zone Regulations, 1991 grants an exemption on payment of tax/duty for goods and services that may be brought into, produced, manufactured or provided in a free zone declared under Section 3(1) of the Free Zone Act, 1990. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific as it is limited to promoted products and also specific to region i.e. enterprise whose project is located in the free zone.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

254.The Government of Malaysia submitted that goods and services of any description except those specifically and absolutely prohibited by law may be brought into, produced, manufactured, or provided in a Free Zone without payment of any duty/tax.

Examination by the Authority

255.The Authority notes that the program is administered by the Free Zone Act, 1990 and the Free Zone Regulations, 1991. Free zones are managed by Free Zone Authorities appointed by the Minister of Finance to administer,

maintain and operate a free zone. Goods and services of any description except those specifically and absolutely prohibited by law, may be brought into, produced, manufactured or provided in a free zone without payment of any duty/tax.

256. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is available to enterprise located in free zone. Authority has already determined that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from import duties. Therefore, Authority holds this program to be countervailable.
257. The Authority notes that neither of the responding producers/exporters are located in any of the Free Trade Zones. Hence, they are not eligible to avail the benefit under the program. In view thereof, it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this subsidy program.

Program No. 19: Investment Tax Allowance

Submissions by the Petitioners

258. The petitioners submitted that the said program is administered by the Malaysian Investment Development Authority (MIDA) and the Inland Revenue Board Malaysia. Section 127 (3A) of the Income Tax Act, 1967 grants an Investment Tax Allowance (ITA) provided on merits of certain case such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country. The ITA is further allowed to be deducted from the taxable income of the company. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to enterprises that meet the eligibility criteria and is approved by the Approval Committee.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

259. The Government of Malaysia submitted that an Investment Tax Allowance may be granted to any company based on the merits of certain cases such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country. Companies may avail the program subject to approval of their application submitted to the MIDA. Despite meeting all the eligible criteria, the application may be rejected by the Approval Committee.

260. M/s Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. submitted that the program is not countervailable since it is neither prohibited nor specific. The benefit was received for the Company as a whole and not specific for the PUC.

Examination by the Authority

261. The Authority notes that the program is administered by the Malaysian Investment Development Authority (MIDA) and the Inland Revenue Board Malaysia. Under the program, an Investment Tax Allowance (ITA) is provided on merits of certain case such as capital intensive, capable of generating significant linkages, import substitution, high value added, technology, green technology, job creation, contribution to the development of manufacturing support services and spillover effect to the country. This allowance is further deducted from the taxable income of the company. The program, hence, provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific since it is available to only those enterprises that incurred the qualifying expenditure. As per Government of Malaysia the said benefit is received by the cooperating exporters. Hence, the Authority holds this program as countervailable.

262. It is noted as per the Questionnaire responses filed by M/s Robin Resources under the heading "Program No. 5" that they have availed the benefit under this subsidy program. Accordingly, it is noted that countervailing duty should be imposed against M/s Robin Resources under this subsidy program. The Authority has quantified the subsidy margin based on the information submitted by M/s Robin Resources in its Questionnaire Response.

Program No. 20: Provision of Standing Timber for Less Than Adequate Remuneration

Submissions by the Petitioners

263. The petitioners submitted that the said program is administered by the State Forestry Department. The Government of Malaysia controls nearly all of Malaysia's harvestable forests and they are leased to companies

for logging on which a stumpage rate is levied. Sections 60, 61 and 75 of the National Forestry Act, 1984 together with Rules 22 and 23 of the State Forest Rules provide for stumpage charges lower than the market benchmark for stumpages. The government also provides a replanting subsidy to support rubberwood plantation and dependent industries. The government has also maintained a ban on exports of rubberwood. The program provides a financial contribution in the form of provision of goods for less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is primarily beneficial to enterprises that use timber as a raw material.

264. As per the website information of the responding producers from Malaysia, rubber wood & tropical mixed wood are used as raw material for the production of the PUC.
265. "Forest produce" as per the National Forestry Act is an inclusive definition and rubberwood is nowhere specifically excluded under it. If no royalty is charged on rubberwood, as per the interested party, it further proves subsidies.
266. The royalty charged by the State Authorities is discretionary and disregards market principles. Hence, charging a royalty in return for logging is in itself a distortion of the forestry sector in Malaysia.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

267. The GOM and responding producers/exporters has stated that the Authority should reject the new alleged subsidies which were alleged at the time of written submissions, which is against ASCM. Rubberwood is not covered within the definition of 'forest produce' under the relevant legislation. There is no royalty collected on rubberwood and hence, no waiver was possible.
268. Rubberwood is not covered within the definition of 'forest produce' under the relevant legislation.
269. There is no royalty collected on rubberwood and hence, no waiver is possible.
270. SPB purchased Wood/Power/Land/Gas from open market and from private entities.

Program No. 21: Government Prohibition of Log Exports

Submissions by the Petitioners

271. The petitioners submitted that the said program is administered by the Ministry of Plantation Industries and Commodities. Under the National Timber Industry Policy 2009-2020, a complete log export ban exists in Sabah since 2018 and in Peninsular Malaysia since 1985. Sarawak has a log export ban on 80% of its production since 1988. A temporary nationwide export ban on rubber wood also has been in place since 2017. Imposition of export restraints distorts the domestic market for logs and makes them available to downstream industries at less than adequate remuneration. The program, hence, provides a financial contribution in the form of provision of goods for less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is primarily beneficial to enterprises that use timber as a raw material.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

272. The GOM and responding producers/exporters has stated that the Authority should reject the new alleged subsidies which were alleged at the time of written submissions, which is against ASCM. None of the responding producers/exporters has availed the benefit.
273. M/s Robin Resources has submitted that all kind of wood is procured from open markets, and they truly reflect the market value at that point of time. The wood vendors are privately owned companies and not from government agency. They do not obtain any kind of government grants or subsidies. Moreover, wood procured are not like timber size logs obtained from the forest. Wood is mainly sourced from rubber wood plantation where the plantation owners want to replant their rubber trees, or mixed wood is procured from various sawmill factories where they process the timber logs and all the waste from their production lines is sold as raw materials for fiberboard production. Thus, any Government interference in such resource is totally incorrect.
274. SPB purchased Wood/Power/ Land/Gas from open market and from private entities

Examination by the Authority

275. The Authority notes that program no. 20 & 21 relates to the series of the measure taken by Government of Malaysia to regulate, monitor and control forestry sector in Malaysia. Since effect of these programs results in timer being provided at less than adequate remuneration, it is considered appropriate to combine these programs and examine them collectively for the purpose of present investigations.

276. The GOM and responding producers/exporters has stated that the Authority should reject the new alleged subsidies which were alleged at the time of written submissions. The Authority notes that during the course of investigation the Authority may investigate into any other program of the subject countries which may be revealed during the course of the investigation as actionable subsidy.
277. The Applicants contended that the Government of Malaysia controls nearly all of Malaysia's harvestable forest through the National Forestry Act, 1984. Section 19 of the Act allows the State Authorities to grant licenses to entities for taking forest produce, which includes trees and parts thereof, from the permanent reserve forests and state land. Granting of licenses including area covered under it and renewal of licenses are at the discretion of the State Authorities. According to section 61 of the Act, on collection of the forest produce, the licensee is required to pay a royalty at the rate fixed by the State Authorities. The Act also empowers the State Authorities to even remit, commute or waive the royalty in order to encourage the utilization of any species of the forest produce which is otherwise uneconomical.
278. The Authority notes that GOM's control on the forestry sector through proper legislation shows that there is a substantial barrier to entry for new market participants and that the GOM had the capacity to both maintain and increase its market share. The export ban restricts the product within the nation and, accordingly, control prices of wood in Malaysia.
279. As per the National Forestry Act, the definition clause includes "Forest produce" which incorporates *(i) trees and all parts or produce not hereinafter mentioned of trees; (ii) plants including climbers, creepers and grasses, and all parts or produce of such plants; (iii) silk, cocoons, honey and wax and edible bird's nests.* Further it says *(c) the following whether found in or brought from a permanent reserved forest, State land, mining land, reserved land or alienated land: timber, fuelwood, charcoal, getah, getah taban leaves, wood oil, bark, extracts of bark, damar and atap.* Further, as per section 61 and 62(1) of National Forestry Act, "*Royalty shall be payable to the State Authority in respect of all forest produce taken at the rates laid down in the royalty rate list as published in the Gazette by the State Authority and Notwithstanding section 61, the State Authority may reduce, commute or waive any royalty in respect of, or exempt from royalty, any forest produce or class of forest produce taken.*"
280. The Act further defines timber as "*timber" includes trees when they have fallen or been felled, and all wood whether or not cut up, fashioned or hollowed out for any purpose.*" The Authority notes that the Act neither exclusively mentions about the rubberwood nor expressly excludes rubber wood from timber. Hence, Authority has no reason to consider that rubber wood is not included within the forest of Malaysia.
281. As far as Government prohibition of log exports is concerned, the petitioners have alleged that the said program is administered by the Government of Malaysia. A ban on round (unprocessed) log exports was re-introduced in 2001, ostensibly to address the problem of over-exploitation. Further, it is noted that Malaysian Government has completely put an export ban on rubberwood. Through the imposition of export ban/prohibition the Government entrusted/directed domestic forestry/harvesting companies to provide low priced inputs (logs/wood) to the downstream industries. Specifically, the log export ban allowed the companies under investigation to purchase inputs (log/wood) from forestry/harvesting companies below market prices.
282. It is noted that the royalty charged by the State Authorities is discretionary and with disregard for market principles. The responding producers/exporters of Malaysia have submitted that they use rubberwood as their raw material. The Authority found that even Malaysia is having an export ban on logs. By imposing such targeted export restraints, the GOM puts domestic downstream producers into an economically irrational situation, which constrains them into selling their goods for a lower price than they could obtain in the absence of this policy. The measures at issue achieved the desired effect to distort the domestic market of wood in the subject country and to depress the price to an artificially low level to the advantage of the downstream industry.
283. The program provides a financial contribution in the form of wood at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific since it benefits those downstream industries that use wood as their primary raw material. In view of the above, the Authority holds this program countervailable.
284. To determine the quantum of the subsidy margin, the Authority looked for the appropriate benchmark whereby it was found that New Zealand is one of the largest exporters of logs globally. The Authority considered export price of logs from New Zealand as an appropriate benchmark as compared to import price from New Zealand.. The actual procurement rate of wood has been considered as per the exporters questionnaire response.

Considering the appropriate conversion rates, the subsidy margin determined has been provided in the table below.

Program No. 22a: Provision for Land at Less Than Adequate Remuneration**Submissions by the Petitioners**

285. With regard to land, the program is administered by the GOM. Under the program, a 30% discount for land premium is provided if the project for which land is provided is completed and operations commenced within 36 months from the date of land alienation, and a 50% discount for land premium if the project is completed and operations commenced within 36 months from the date of land alienation. The program provides a benefit in the form of revenue forgone that is otherwise due. The program is also specific since it is enterprise specific. The Authority has quantified the subsidy margin for the program, it can be presumed that the financial records submitted by the producers/exporters show benefit being availed. Hence, the Authority is requested to uphold the same.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

286. GOM requested to exclude the scheme as it is beyond the scope of investigation. According to the 9th Schedule of the Federal Constitution, land and land ways resources comes under purview of the state which in turn means that each state government has the authority to legislate on land matters under the state secretary office. the selling rate of land will be based on the current market value during the particular time. Any individual company/party cancel purchase land.

287. It has been submitted by the responding exporters that they purchased land from private entities at market rates prevalent at the time of purchase.

288. In 1994 M/s Robin Resources bought freehold land from private owner in open market environment at open market price. For any transaction locally, selling prices are determined by seller and buyer without any intervention of government authority. M/s Robin Resources is located in a state which is in the eastern region of peninsular Malaysia which is less developed and far away well-developed cities. Moreover, the population is also less than these well-developed as well as infrastructure is also not good. With these factors, definitely the land price in this area is cheaper than those well developed with good infrastructure that is located in the western region of peninsular Malaysia.

289. None of the responding producers/exporters has availed the benefit.

Examination by the Authority

290. The Authority notes that the program is administered by the State Authorities of Malaysia. Section 76 of the National Land Code, 1965 allows the State Authority to alienate State land on payment of a consideration in the form of annual rent/premium. However, section 76(c) permits the State Authorities to exempt the payment of premium in any case they find fit. The power to exempt premium is not regulated by any law or regulation and is based on the discretion of the State Authority.

291. The program provides a financial contribution in the form of provision for industrial land at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is specific since the benefit is provided at the discretion of the government/authorities and not regulated by any law or regulation. Therefore, the Authority holds this scheme as countervailable.

292. According to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules,1995, in case of subsidized provision of goods and services by the Government the difference between the amount paid by the firm and the adequate remuneration in relation to the prevailing market conditions will be the subsidy amount. The expense incurred by the responding producers/exporters on land has been taken from the Audit Reports filed along with their questionnaire responses. The average commercial land prices for the industrial areas in Malaysia has been taken as the appropriate benchmark. The subsidy margin calculated has been provided in the table below.

Programme no. 22b: Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration**Submissions by the Petitioners**

293. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Malaysia and State-Owned Enterprises. The Government provides subsidized electricity through Power Purchase Agreements and discounts on land premiums. With regard to electricity at LTAR, the prices of natural gas, which is the primary source of power in Malaysia, are statutorily regulated for electricity sector. Hence, power is available to producers of the

PUC at LTAR. The same was examined in previous investigations on “float glass” and “tampered glass” and found countervailable. The program provides a financial contribution in the revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to specific enterprises and regions.

Submissions by Government of Malaysia/other interested parties

294. GOM requested to exclude the scheme as it is beyond the scope of investigation. Natural gas to end users at transmission segment (high pressure) is supplied by PETRONAS while at distribution segment (low pressure) is supplied by Gas Malaysia Bhd. PETRONAS is a government-owned company while Gas Malaysia Bhd is a private company.
295. The scheme is not applicable as both the responding producers, M/s Segamat Panel Boards Sdn Bhd and M/s Robin Resources (Malaysia) Sdn Bhd are not consumers of natural gas during investigation period.
296. Electricity supply to the end customers (i.e. domestic, commercial, and industrial) is through Tenaga Nasional Berhad for Peninsular Malaysia. Tenaga Nasional Berhad is a public-listed company. GOM stated that there are 3 producers of electricity in Malaysia (under Suruhanjaya Tenaga’s purview): a. Tenaga Nasional Berhad (TNB), for Peninsular Malaysia; b. NUR Power Sdn Bhd (NUR), for Kulim Hi-Tech Industrial Park, Kedah; and c. Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB), for Sabah and WP Labuan. TNB is a public-listed company, NUR is a private-owned company, and SESB is a private-owned company. Electricity is not provided by the Government. However, the price of electricity is regulated by the Government. Incentive-Based Regulation (IBR) within the framework for overall electricity pricing policy. The purpose of this framework is for Energy Commission to regulate the revenues and tariffs of electricity utility in Peninsular Malaysia. Under the IBR framework, the electricity tariff is charged for the provision of regulated services (the electricity). This framework allows electricity utility to recover an allowed revenue, representing the estimated efficient costs (including financing costs) of providing the regulated services.
297. However, the responding exporters have submitted that Tenaga Nasional Bhd (TNB) is the sole electricity supplier in Malaysia. The main utility in production is electricity/power. The sole electricity supplier in Peninsular Malaysia is a listed company in Stock Market, Tenaga Nasional Bhd (TNB). There is no other alternative, and the rates they charged to Industrial consumers are the same regardless of the factory premise or location. For the mega electricity consumers such as steel mill, they are in the position to negotiate with TNB for special tariffs by entering into Special Agreements. The companies with much lesser electricity consumption do not warrant them to have special agreements with TNB. The responding exporters, therefore, do not enjoy any economic benefits from electricity supplier.

Examination by the Authority

298. The power supply in Malaysia is mainly through natural gas and coal. Authority notes that supply of gas is governed by Gas Supply Act, 1993. This program allows regulated and more favorable rates of natural gas prices for industrial sector including the electricity sector. It is noted that the GOM admittedly regulates the prices of gas supplying companies namely, PETRONAS and Gas Malaysia Berhad (GMB) which in turn supply gas to the end users at reduced rates. The difference is then recovered by the said company from the GOM. Thus, the Authority is of the view that there is a direct financial contribution by the GOM. Further, the response of GOM itself states that:

“The government has also prescribed the Incentive Based Regulation (IBR) framework, which sets the base tariff for industrial customers for three years from January 2017 to December 2019. This IBR framework allows changes in the gas costs to be passed through via the Gas Cost Pass-Through (GCPT) mechanism every six months. GCPT is the mechanism to pass through the gas cost differential which incurred due to the difference between gas cost forecasted in base tariff and actual gas cost. GCPT is implemented every 6 months in January and July. The rate will be either a rebate or surcharge”

299. As regards the contention of the GOM that the responding exporters are not natural gas consumers during period of investigation and the program is not available to them, the Authority notes that the GOM has also not denied the existence of the subsidy element in the gas pricing mechanism which is supplied to the industrial producers. The Authority further notes that it is not necessary that a subsidy is made available to the concerned enterprise directly for it to be countervailable. In this context, it would be appropriate to refer to the definition of “subsidy” under Section 9(1) of the Customs Tariff Act, 1975, which reads as under:

9(1)Where any country or territory pays, bestows, directly or indirectly, any subsidy upon the manufacture or production therein or the exportation therefrom of any article including any subsidy on transportation of such article, then, upon the importation of any such article into India, whether the same is imported directly from the country of manufacture, production or otherwise, and whether it is imported in the same condition as when exported from the country of manufacture or production or has been changed in condition by manufacture, production or otherwise, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, impose a countervailing duty not exceeding the amount of such subsidy.

Explanation. - For the purposes of this section, a subsidy shall be deemed to exist if—

(a) there is financial contribution by a Government, or any public body [in the exporting or producing country or territory], that is, where –

- i. Government practice involves a direct transfer of funds (including grants, loans and equity infusion), or potential direct transfer of funds or liabilities, or both;*
- ii. Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (including fiscal incentives);*
- iii. a Government provides goods or services other than general infrastructure or purchases goods;*
- iv. a Government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions specified in clauses (i) to (iii) above which would normally be vested in the Government and the practice in, no real sense, differs from practices normally followed by Governments; or....*

300. From the above, it is clear that if a government ‘entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in points (i), (ii) and (iii) which would normally be vested in the government, and the functioning, in no real sense, differs from functions normally carried out by governments in terms of paragraph i-iii of Section 9(1)(a) of the Customs Tariff Act, 1975, then it is deemed to be a subsidy. These provisions mirror Article 1.1(a)(1)(iv) and (iii) of the SCM Agreement. Therefore, any program which allows even the private bodies to provide Gas for less than adequate remuneration to the industry, is covered by the definition of “subsidy” in terms of the above provisions.

301. The Authority notes that electricity in Malaysia is produced from gas. The prices of gas supplying companies namely, PETRONAS and Gas Malaysia Berhad (GMB) are regulated by GOM. Hence, gas is available to PETRONAS and Gas Malaysia Berhad at a rate below the market rates.

302. Further, the electricity distribution in Malaysia is regulated under the Electricity Supply Act, 1990. Under the Act only those persons licensed by the Energy Commission shall supply electricity. Hence, such bodies are entrusted with governmental functions and act as public bodies. According to section 26 of the Act, the suppliers of electricity may charge a tariff as approved by the relevant Ministry. However, as per section 29 of the said Act, consumers of electricity are allowed to enter into Special Agreements with the suppliers of electricity whereby the tariffs may be specified as per the agreements. Also, it has been admitted by GOM that the prices of electricity in Malaysia is regulated. The Authority notes that the Government of Malaysia regulates the prices of gas as well as electricity which is different from the market prices for industrial users. Further, this scheme provides benefit to enterprises who procure electricity which is gas generated.

303. The companies under investigation are beneficiaries of such subsidization. The program is specific and provides a financial contribution in the form of provision of electricity at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. Therefore, the Authority holds this program as countervailable and it is also noted that countervailing duty should be imposed against the responding exporters under this program.

304. To determine the quantum of the subsidy margin, the Authority looked for the appropriate benchmark. The Authority has relied upon the prices provided as per the website of ‘globalpetrolprices’. The actual electricity tariffs paid by the responding producers as per the additional questionnaire response has been considered to determine the subsidy margins. Considering the methodology above, the subsidy margins have been determined for the responding exporters/producers has been provided in the table below.

Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd.

305. Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. is a producer/exporter of subject goods in Malaysia. Robin Resources filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

306. Authority examined the response filed by Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. and upon examination requested information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. had disclosed in its questionnaire response that it had availed

allowance on plant and machinery, sales tax exemption, double deduction for promotion of exports, and investment tax allowance. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in provision for land, wood and electricity at LTAR were availed by Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. As a result, benefit was conferred to benefit was conferred to Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd. in the form of various subsidies.

307. Authority has verified the information provided by Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

308. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 9	Allowance for Plants and Machinery	***%	0-10
2	Program No 12	Sales Tax Exemption	***%	0-10
3	Program No 14	Double Deduction for Promotion of Exports	***%	0-10
4	Program No 19	Investment Tax Allowance	***%	0-10
5	Program No 20	Provision for standing timber at LTAR	***%	0-10
6	Program No 22a	Provision for Land at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
7	Program No 22b	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Segamat Panel Boards Sdn. Bhd.

309. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. is a producer/exporter of subject goods in Malaysia. Segamat filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

310. Authority examined the response filed by Segamat and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. had disclosed in its questionnaire response that it had availed accelerated capital allowance, allowance on plant and machinery and sales tax exemption. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in provision for land, wood and electricity at LTAR were availed by Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. As a result, benefit was conferred to Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. in the form of various subsidies.

311. Authority has verified the information provided by Segamat Panel Boards Sdn. Bhd. and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

312. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 7	Accelerated Capital Allowance	***%	0-10
2	Program No 9	Allowance for Plants and Machinery	***%	0-10
3	Program No 12	Sales Tax Exemption	***%	0-10
4	Program No 20	Provision for standing timber at LTAR	***%	0-10

5	Program No 22a	Provision for Land at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
6	Program No 22b	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
Total Subsidy		***%	10-20	

313. Countervailing duty for all other producers/exporters from Malaysia has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating party, for the subsidies availed by them and based on facts available for other subsidy programs.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 7	Accelerated Capital Allowance	***%	0-10
2	Program No 9	Allowance and Plants and Machinery	***%	0-10
3	Program No 12	Sales Tax Exemption	***%	0-10
4	Program No 14	Double Deduction for promotion of Exports	***%	0-10
5	Program No 19	Investment Ta Allowance	***%	0-10
6	Program No 20	Provision for standing timber at LTAR	***%	0-10
7	Program No 22a	Provision for Land at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
8	Program No 22b	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
Total Subsidy		***%	10-20	

Sri Lanka

F.7. Examination of Subsidy programs alleged by the Petitioners

(i) Program No. 1: National Building Tax Exemption (Indirect Tax)

Submissions by the Petitioners

314. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Sri Lanka. Section 3 and Schedule 1 of the Nation Building Tax Act, 2009 grants an exemption to tax levied on import of machinery when they are imported for the purpose of manufacture of goods for exports. The amount exempted is the applicable turnover of exports or the value of imports of machinery used. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports. The program was analyzed by the US DOC and found countervailable in the anti-subsidy investigation on “certain new pneumatic off-the-road tires (off road tires) from Sri Lanka.

Submissions by Government of Sri Lanka/other interested parties

315. The Nation Building Tax (NBT) is an indirect tax applicable on domestic consumption of goods and services. It was imposed vide the Nation Building Tax Act No. 9 of 2009 and subsequently amended several times. NBT is payable by every person (individual, company, body of persons) or partnership who (i) imports any article (unless exempted) into Sri Lanka, (ii) carries on business of manufacturing any article other than those exempted, (iii) carries on business of wholesale or retail of any article (other than those application under previous heading), and (iv) carries on the business of providing any service.

316. According to (i) and (ii) of Part I of the First Schedule to the Act, any article exported by the manufacturer of such article and import of raw materials for the production of articles to be exported is exempted from NBT. The same is applicable irrespective of product exported.

317. The program does not amount to a subsidy under the ASCM by virtue of footnote 1 of the agreement. The remittance is applicable to all exporters irrespective of the product. Footnote 1 states that the exemption of exports from indirect taxes, as defined under footnote 58, is not a financial contribution. The same principle is also provided in the Ad Note to Article XVI of the GATT. Annex I(g) of the ASCM states that such remittance of indirect tax levied is not a subsidy if it does not exceed those levied for production and distribution of like products for domestic consumption. The remittance under this Program does not exceed this level. The program is also not specific since it does not benefit a specific industry or sector. The producer of the PUC in Sri Lanka is not liable to pay NBT as it is applicable only for domestic consumption of goods and services. Additionally, the Nation Building Tax was abolished with effect from 1 Dec 2019.

Examination by the Authority

318. The Nation Building Tax (NBT) is an indirect tax applicable on domestic consumption of goods and services imposed vide the Nation Building Tax Act No. 9 of 2009. NBT is payable by every person (individual, company, body of persons) or partnership who (i) imports any article (unless exempted) into Sri Lanka, (ii) carries on business of manufacturing any article other than those exempted, (iii) carries on business of wholesale or retail of any article (other than those application under previous heading), and (iv) carries on the business of providing any service.

319. According to (i) and (ii) of Part I of the First Schedule to the Act, any article exported by the manufacturer of such article and import of raw materials for the production of articles to be exported is exempted from NBT. In absence of any evidence to show that the program provides for permissible tax remission, it is determined that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is contingent on export. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

320. However, since none of the producers/exporters of subject goods from the subject country have responded, hence the Authority has not quantified the subsidy margin under this program.

(ii) Program No. 2: Exemptions for Custom Duties on Capital and Intermediate Goods

Submissions by the Petitioners

321. The petitioners submitted that the said program is administered by the Industries & Services Directorate, Sri Lanka. Scheme TIEP-IV grants an exemption from customs duties levied on import of capital or intermediate goods when they are imported for the purpose of manufacture of goods for exports. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports.

322. Though a claim on non-availment of the program was made by the Government of Sri Lanka, the government as well as the Sri Lankan exporters has not cooperated with the instant investigation and the claim is made without any supporting evidence.

Submissions by Government of Sri Lanka/other interested parties

323. An exemption on custom duties on imported capital and intermediate goods for manufacture of products and services for exports is provided by the Industries and Services Directorate under the Temporary Import for Export Processing (TIEP-IV) scheme. The same is applicable to capital goods involved in production process, intermediate goods, other essential equipment, transport equipment, and handling equipment. The program provides a 100% exemption of Customs Duty in case of exporters who export 50% or more of their output and indirect exporters who supply 50% or more of their output to direct exporters.

324. The Government of Sri Lanka submitted that the only exporter of the PUC into India, i.e., Merbok, was operating under the BOI Act until January 2019 and under TIEP-IV scheme thereafter. Under the BOI regime, Merbok was entitled to duty free access to import raw materials and the same was available to all companies in BOI status. The Company benefited from the scheme from January 2019 and not before that.

Examination by the Authority

325. The Authority notes that the program is administered by the Industries & Services Directorate, Sri Lanka as per Scheme TIEP-IV. Under the program, an exemption to customs tax levied on import of capital goods involved in

production process, intermediate goods, other essential equipment, transport equipment, and handling equipment when they are imported for the purpose of manufacture of goods for exports is provided. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is deemed specific since it is contingent on exports. Therefore, the Authority holds this program as countervailable. Since none of the producers/exporters of subject goods from the subject country have responded, the Authority has quantified the subsidy margin under this program on the basis of facts available.

(iii) Program No. 3: Income Tax Concessions for Specified Undertakings

Submissions by the Petitioners

326. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Sri Lanka. Section 51 read with Schedule 5 of the Inland Revenue Act, 2006 grants a concessional income tax rate for companies engaged in the export of “non-traditional products” identified under the Act. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports.
327. Though a claim on non-applicability of the program was made by the Government of Sri Lanka, the government as well as the Sri Lankan exporters has not cooperated with the instant investigation.

Submissions by Government of Sri Lanka/other interested parties

328. According to section 51 & 52 of Inland Revenue Act No. 10 of 2006, any company that carries on any specified undertaking and the taxable income of that company for any year of assessment includes any qualified export profits and income, such part of the taxable income of that company for that year of assessment as consists of such qualified exports profits and income shall, notwithstanding anything to the contrary in this Act, be chargeable with income tax at the appropriate rate specified in the Fifth Schedule to this Act.
329. The Government of Sri Lanka submitted that the only exporter of the PUC into India, i.e., Merbok, has been incurring losses since 2014 and hence, not liable to pay income tax. This makes the program not applicable.

Examination by the Authority

330. The Authority notes that Section 51 of the Inland Revenue Act, 2006 grants a concessional income tax rate for companies engaged in the export of “non-traditional products” identified under Schedule 5 of the Act. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is deemed specific since it is contingent on exports and is exclusively provided to manufacturers of “non-traditional products” as per the Act. Therefore, the Authority holds this program as countervailable. However, since none of the producers/exporters of subject goods from the subject country have responded, hence the Authority is not able to quantify the subsidy margin under this program.

(iv) Program No. 4: Income Tax Exemptions for Undertakings with High Investment

Submissions by the Petitioners

331. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Sri Lanka. Section 17A of the Inland Revenue Act, 2006 grants an exemption on payment of income tax for a period dependent on the amount of investment made for the production and export of “non-traditional products” identified under the Act. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports.
332. Though a claim on non-applicability of the program was made by the Government of Sri Lanka, the government as well as the Sri Lankan exporters has not cooperated with the instant investigation.

Submissions by Government of Sri Lanka/other interested parties

333. Section 17 of the Inland Revenue Act provides for income tax holidays depending on the investment made by the undertaking. The section has been amended several times subsequently. Accordingly, manufacture, production, or processing of non-traditional goods for export have been included as activities in which investment can give rise to tax holiday as per the law.
334. The Government of Sri Lanka submitted that the only exporter of the PUC into India, i.e., Merbok, has been incurring losses since 2014 and hence, not liable to pay income tax. This makes the program not applicable.

Examination by the Authority

335. The Authority notes that section 17A of the Inland Revenue Act, 2006 grants an exemption on payment of income tax to companies engaged in the production and export of “non-traditional products” identified under the Act. The period for which the exemption is granted is dependent on the amount of investment made. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is deemed specific since it is contingent on exports and is exclusively provided to manufacturers of “non-traditional products” as per the Act. Therefore, the Authority holds this program as countervailable. However, since none of the producers/exporters of subject goods from the subject country have responded, hence the Authority is not able to quantify the subsidy margin under this program.

(v) Program No. 5: National Fertilizer Subsidy Scheme

Submissions by the Petitioners

336. The petitioners submitted that the said program is administered by the Ministry of Plantation Industries of the Government of Sri Lanka. The scheme provides fertilizers for rubber plantations at subsidized rates. The program provides a financial contribution in the form of provision for goods at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to the rubber plantation sector.

337. Though a claim on non-availment of the program was made by the Government of Sri Lanka, the government as well as the Sri Lankan exporters has not cooperated with the instant investigation.

Submissions by Government of Sri Lanka/other interested parties

338. Sri Lanka introduced agricultural subsidies for promoting agriculture and is provided for all crop sectors and sub-sectors. The subsidy is generally available and provided for all crop sectors and sub-sectors. Therefore, the program is not specific. It is available to all engaged in the agricultural sector. It does not benefit the rubber producers specifically and not provided to exporters. Hence, the subsidy is neither an export subsidy nor actionable as per the ASCM. The benefit is also too remote and not passed on to the fiberboard producers. The only exporter of the PUC into India, i.e., Merbok, is not registered with the administering authority to access the program.

Examination by the Authority

339. The Authority notes that Ministry of Plantation Industries of the Government of Sri Lanka provides significant amounts of subsidy to the rubber planters in the form of fertilizer subsidy. Being the primary raw material in the production of the PUC, this program indirectly allows its procurement of rubber wood at a subsidized rate.

340. The program provides a financial contribution in the form of provision for goods at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is specific since it is provided exclusively to the agriculture sector. Therefore, the Authority holds this program as countervailable. However, since none of the producers/exporters of subject goods from the subject country have responded, hence the Authority is not able to quantify the subsidy margin under this program.

(vi) Program No. 6: Subsidies for Rubber plantation

Submissions by the Petitioners

341. The petitioners submitted that the said program is administered by the Rubber Development Board under the Ministry of Plantation Industries of the Government of Sri Lanka. The scheme provides grants in installments at various stages of a plantation depending on the size and also ensures a guaranteed support price. The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to the rubber plantation sector.

342. Though a claim on non-existence of the program was made by the Government of Sri Lanka, the government as well as the Sri Lankan exporters has not cooperated with the instant investigation.

Submissions by Government of Sri Lanka/other interested parties

343. There are two schemes administered by the Rubber Development Board and provided exclusively to rubber growers for new planting as well as replanting. The fiberboard producers in Sri Lanka use rubber logs which are a

waste from the rubber industry. They are purchased at throw away prices at the end of the lifetime of the tree. But the purchase is not influenced by the scheme.

344. The subsidy is provided at an early stage of a rubber tree which has an economic life of 25-30 years. When calculated at the end of the said economic life of the rubber tree, value of the subsidy received is negligible given the erosion in value of money over time. The benefit is too remote and not passed on to the fiberboard producers. Hence, the subsidy does not exist.

345. Where a subsidy is granted to a different (upstream) entity than the exporting entity, an investigating authority must have evidence, and must determine based on that evidence, that any subsidy granted to the first entity passed through to the exporting entity. Otherwise, no subsidy to the exporting entity can be said to exist.

(vii) Program No. 7: Government Prohibition on Log Exports

Submissions by the Petitioners

346. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Sri Lanka. The Government of Sri Lanka has put in place a complete log export ban since 1990. Imposition of export restraints distorts the domestic market for logs and makes them available to downstream industries at less than adequate remuneration. The program, hence, provides a financial contribution in the form of provision of goods for less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is primarily beneficial to enterprises that use timber as a raw material.

a. Submissions by Government of Sri Lanka/other interested parties

347. Government of Sri Lanka does not maintain a ban on export of timber logs. The only requirement for exporting logs is to obtain a license.

Examination by the Authority

348. The Authority notes that program no. 6 & 7 relates to the series of the measure taken by Government of Sri Lanka to regulate, monitor and control rubber plantation and wood ban. Since effect of these programs results in wood being provided at less than adequate remuneration, the Authority has combined these programs and examine them collectively for the purpose of present investigation.

349. The Authority notes that the Rubber plantation subsidy is administered by the Rubber Development Board. As admitted by GOSL, the Rubber Development Board currently implements two schemes, which are for the benefit of rubber growers, one for re-planting and the other for new planting. Fiberboard manufacturing uses rubber logs, which is a waste of the rubber industry at throw-away prices, at the end of the economic life (25-30 years) of a rubber. Further the Authority notes that Rubber Replanting Subsidy Act. No 16 of 1953 (as amended time to time) is an Act to provide for the establishment of a fund for the purpose of subsidizing the replanting of rubber estates and rubber small holdings and the processing of raw rubber including the purchase of machinery and equipment used in the processing of raw rubber. Small holders or rubber plantation companies who registered their holdings in the Rubber Development Department (RDD) are eligible to get the subsidy. Accordingly, the holders are required to prove the ownership of the land before getting registered with the department. Complete rubber plantation is controlled by the Government of Sri Lanka.

350. Further, the Authority notes that, GOSL formulated National Forest Policy for conservation of forests, which has been amended time to time. Later on, due to rising concerns of deforestation, the Forestry Sector Master Plan of Sri Lanka in 1986 and Forest Ordinance regulation or special legal provision were enacted for imposing log ban. The Forest Department is the main institution entrusted with the administration of major parts of the forest areas. As per the Sri Lankan customs website, Export Control License is required for *Timber, i.e., Wood (including logs and sawn timber) classified under H.S. Chapter 44 excluding coconut shell charcoal, household utensils of wood and rubber wood.*

351. The Authority took note of the website information of the leading exporter of the subject goods from Sri Lanka, M/s Merbok MDF Lanka (Pvt) Ltd, which states “*All wood processing industries are reliant on forest resources, either directly or indirectly. Forest resources in the form of wood fiber provide the basic raw material for the manufacturing of MDF. Merbok utilises waste wood, sawmill waste and residual plantation logs that are harvested and replanted cyclically.*” Authority also found that Merbok is also engaged in its own plantation

program through its highly successful small holder tree-planting program. Particular attention has been paid to meeting and exceeding stringent environmental regulations set by authorities.

352. The Authority notes that while, such export control (and other export restrictions) may somewhat curtail over-exploitation of Sri Lanka's forests but also depress the domestic prices of logs, thereby assisting downstream processors of such products which leads to subsidization.

353. The Authority further notes that the Government of Sri Lanka through the imposition of export control leads to low priced inputs (logs/wood) to companies in the downstream industries. The export control which has induced log suppliers to sell logs domestically at suppressed prices has benefited Sri Lankan downstream wood processing industries.

354. The program provides a financial contribution in the form of goods at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific since it benefits those downstream industries that use logs/wood as their primary raw material. Hence, the program is de facto available only to a limited number of industries. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

355. However, since none of the producers/exporters of subject goods from the subject country have responded, hence the Authority has quantified the subsidy margin under this program on the basis of facts available.

Program No. 8: Electricity at Less Than Adequate Remuneration

Submissions by the Petitioners

356. The petitioners submitted that the electricity is provided in Sri Lanka at less than adequate remuneration.

Submissions by Government of Sri Lanka /other interested parties

357. The Government of Sri Lanka has not made any submissions on the allegation of electricity at less than adequate remuneration.

Examination by the Authority

358. During the course of investigation, the Authority has come across the Electricity provided at LTAR, as per the allegation submitted by applicants in their submissions. The Authority sought requisite information in form of additional questionnaire from the interested parties.

359. The Department of Electrical Undertakings was established in 1926 by the government for electricity generation and transmission in Sri Lanka. The Ceylon Electricity Board (CEB) was later established in 1969 by an act of parliament to be responsible for the generation, transmission and distribution of electricity in the country. Later in 1983, the government established the Lanka Electricity Company Limited (LECO) to undertake electricity distribution in the outer suburbs of Colombo and in selected areas in the western and southern parts of the country. The Electricity Act of 2009 paved the way for the effective regulation of the sector by the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL).

360. At present, the CEB and independent power producers are involved in the generation of electricity. While the CEB is the main system operator of the country, the power generated by the independent power producers is also procured by the CEB under purchase agreements. Hydro power plants and coal power plants are the major contributors to electricity generation in Sri Lanka. Small hydro, wind other Non-Conventional Renewable Energy (NCRE) power plants also contribute to the electricity generation. Thermal power contribution to the national electricity supply has been higher than that of hydro power.

361. As per the Electricity law 2009, Section 5 (2) (d)- pricing policy is determined by the Minister of Sri Lanka. CEB is the main system operator of the country, the power generated by the independent power producers is also procured by the CEB under purchase agreements. As per publicly available information industrial tariff rate in Sri Lanka is subsidized and is below the market prices.

362. The Authority notes that the Ministry of Power and Energy has vested its authority in its affiliated institutes namely Ceylon Electricity Board and Lanka Electricity Company Limited (LECO). LECO is a government owned and controlled utility of Sri Lanka that takes care of the general energy facilities of the island. The Ministry of Power, Energy & Business Development is the responsible ministry above the LECO. The Government has vested its powers to exercise its functions based on formal indicia of government control and it is

seen that it has been exercised in a meaningful way, hence these are public bodies. Hence, the Authority finds that the electricity sector in Sri Lanka is distorted and not based on market principles which enables the producers of the PUC to procure electricity at less than adequate remuneration. Hence, the Authority notes that countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this program.

363. However, since none of the producers/exporters of subject goods from the subject country have responded, hence the Authority has quantified the subsidy margin under this program on the basis of facts available.

Summary of Subsidy programs from Sri Lanka

364. Since none of the producer/exporter from Sri Lanka has filed a questionnaire response, the Authority has determined the countervailing duty for all the producers/exporters of the subject goods from Sri Lanka based on facts available.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 2	Exemption of Import Duty	***%	0-10
2	Program No 6 & 7	Provision for standing timber at LTAR	***%	0-10
3	Program No 13	Provision for Electricity at LTAR	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Thailand

Program No. 1: Exemption/Reduction of Import Duties on Machinery

Submission by the Petitioners

365. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Sections 28 and 29 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants an exemption/reduction on import duty applicable on imported machinery. The benefit provided is such that it would flow down to the PUC. Money is fungible and therefore the company can decide to use the benefit on any of its business segments. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder. The investment project should also fall within the list of activities eligible for investment promotion.

366. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The same is requested to be upheld in the instant case.

367. Several responding exporters including M/s Vanachai Group Public Company Limited, M/s Vanachai Panel Industries Co. Ltd., M/s Metro MDF Co. Ltd., M/s Advance Fiber Co. Ltd., M/s Wisewoods Co. Ltd., M/s Panel Plus MDF Co. Ltd., M/s S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, and Agro Fiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment. Moreover, M/s Panel Plus Co. Ltd., M/s S. Kijchai Enterprise, M/s Advance Fiber Co. Ltd., and M/s Vanachai Panel Industries Co. Ltd. have all expanded capacities or added new plants in the AUL period. Hence, they should have availed benefit under the said program.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

368. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including exemption for payment of import duties on machinery used in BOI-promoted projects under Section 28. The section provides exemption from payment of import duties on machinery under approved investment projects. Under the new

investment promotion scheme introduced by the BOI in January 2015, the incentive package is granted according to investment activity, instead of investment zone. The change in 2015 does not affect the incentive package any company, including the companies under investigation, receives under the zoning system prior to 2015. The eligibility to receive the BOI incentives is not specific as it is not limited to certain industries or certain enterprises. The benefit is neither provided on the import of machinery for the production of export goods nor on the use of domestic goods over imported ones. The program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of the previous finding in continuous copper final finding will be a violation of the principles of natural justice.

369. The Authority has not examined in terms of SCM Agreement there is no industry or market segment excluded from the scope of the program or not eligible to seek approval of BOI. The program is not specific.

370. M/s Metro MDF Co. Ltd. and M/s Advance Fibre Co. Ltd. submitted that the exemption is only granted for import of machinery not assembled in Thailand. Further, Panel Plus MDF submitted that the benefit under the program is provided to the company as a whole and not specific to the PUC.

371. It has been submitted that as per the WTO Panel Report in Canada – Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, the benefit in a CVD investigation should be examined from the perspective of the recipient. The WTO Panel Report in EC – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft is also relied on. Not countervailable as per ASCM and CVD Rules. The benefit for Vanachai Group is nil since the machines have completed their depreciation cycle before the POI.

Examination by the Authority

372. The Authority notes that Investment Promotion Act, 2002 (the Act) provides for certain rights and benefits to promoted entities/projects/activities (Investment Promotion Package Scheme). Section 16 of the Act prescribes that the Board of Investment (BOI) will make an announcement designating the types and sizes of investment activity eligible for benefit specified under the Act.

373. Section 28 of the Investment Promotion Act, 2002 provides an exemption from payment of import duties on machinery under approved investment projects. Section 30 of the Act provides for reduction (not exceeding ninety percent) of import duty on raw materials and not for exemption/ reduction of import duty on machinery. The program provides for a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. Therefore, Authority holds this program as countervailable.

374. The Authority notes that the Questionnaire Responses filed by Metro MDF Co. Ltd., Wisewoods, and S. Kijchai show that benefit was availed by them under the program. The Authority holds that countervailing duty should be imposed against aforementioned producers/exporters under this program. None of the other responding producers/exporters were found to have availed the benefit under the program.

375. The Authority has determined the subsidy margin based on the information provided in the records submitted by the responding producers/exporters. The subsidy margin thereby calculated is provided in the table below.

Program No. 2: Exemption of Import Duty on Raw Material Imported for use in Production for Export

Submission by the Petitioners

376. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Section 36 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants an exemption on import duties applicable on (i) raw and essential materials imported for use specifically in producing, mixing, or assembling products or commodities for export, and (ii) items imported for re-export. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder. Furthermore, it is also export contingent and hence, deemed specific.

377. The USDOC in the Final Affirmative Determination in the CVD investigation on imports of Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from Thailand found all programs pertaining to the Investment Promotion Act, 1977 administered by the Board of Investments to be countervailable. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods”

from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The same is requested to be upheld in the instant case. The Authority had found in the said investigation that the Government of Thailand could not provide any explanation or evidence to show how a mechanism operates to ensure no excess benefit is provided under the program. A previous finding of the USDOC is not binding on the DGTR. The Authority may diverge based on their factual conclusions.

378. Several responding exporters including M/s Vanachai Group Public Company Limited, M/s Vanachai Panel Industries Co. Ltd., M/s Metro MDF Co. Ltd., M/s Advance Fiber Co. Ltd., M/s Wisewoods Co. Ltd., Panel Plus MDF Co. Ltd., M/s S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, and M/s AgroFiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

379. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including the following special rights and benefits under section 36: (1) Exemption of import duties on the raw and essential materials imported for use specifically in producing, mixing, or assembling products or commodities for export; and (2) Exemption of import duties on items which the promoted person imports for re-export.

380. The purpose of this program is to facilitate companies that are entitled to receive benefits under Section 36 by exempting import duty on raw or essential materials used in BOI-promoted projects. Under the new investment promotion scheme introduced by the BOI in January 2015, the incentive package is granted according to investment activity, instead of investment zone. The change in 2015 does not affect the incentive package any company, including the companies under investigation, receives under the zoning system prior to 2015. The eligibility to receive the BOI incentives is not specific as it is not limited to certain industries or certain enterprises. It is neither contingent upon export performance nor the use of domestic goods.

381. BOI has an effective system in place in order to ensure that the import quantity of the raw or essential materials are not exceeding the revolving maximum stock and to ensure that the companies do export those imported raw or essential materials as finished goods.

382. The exemption of import duty for the purpose of exports is permitted by the ASCM under Article 1. The BOI has an effective system to ensure no excess benefit is provided. The same observation was made by the USDOC in the CVD investigation on Glycine from Thailand. Hence, the benefit provided under the program is not countervailable. The Authority incorrectly countervailed the program in Copper case. Only the excessive benefit provided under the program, if any, can be countervailed as per the ASCM. Further, the program has not been availed by any of the responding producers/exporters. The program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of the previous finding in continuous copper final finding will be a violation of the principles of natural justice.

Examination by the Authority

383. The Authority notes that Section 36 of the Investment Promotion Act, 2002 provides for exemption from import duty on raw or essential materials used in BOI-promoted projects. Under this subsidy program, the products produced using duty free inputs are required to be re-exported or exported after undergoing mixing, assembling and production activity. This subsidy program is a part of investment promotion package scheme.

384. Government of Thailand has submitted that BOI has an effective system to ensure that companies export the imported raw material as finished goods and there is no excess benefit to the producer/exporters carrying out the promoted activity.

385. The Authority notes that M/s Wisewoods Co. Ltd. vide its EQR submission had admitted availment of subsidy on the raw materials used in the production of PUC. The Authority accordingly quantified the same for M/s Wisewoods Co. Ltd. However, through a later submission, the company informed that they had inadvertently reported benefit for import of raw materials while filing the questionnaire response, which was in fact never availed by them. To substantiate the same, they have submitted documents which show that import of raw materials by M/s Wisewoods Co. Ltd. were subjected to 'NIL' rate of duty and therefore, the Authority notes that M/s Wisewoods Co. Ltd. did not receive any subsidy and /or benefit for importing raw material.

386. The exemption of import duty for the purpose of exports is permitted by the ASCM under Article 1. However, only the excessive benefit provided under the program, if any, can be countervailed as per the ASCM. Government of Thailand has submitted that BOI has an effective system to ensure that companies export the imported raw material as finished goods and there is no excess benefit to the producer/exporters carrying out the promoted activity. Government of Thailand has not provided any explanation and has not provided any evidence to show how the mechanism operates under the BOI scheme to ensure that there is no excess benefit and that raw material that is imported duty free is used in the exported product. In absence of any evidence to show that the program provides for permissible tax remission, it is determined that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is contingent on export and is also limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. Hence, the Authority holds the program as countervailable.

387. Since none of the responding exporters have submitted any evidence regarding excess availment of the benefit under the said program the program. Accordingly, the Authority has decided not to impose any countervailing duty against the responding exporters under this scheme.

Program No. 3: Reduction of Import Duty for Raw or Essential Materials

Submission by the Petitioners

388. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Section 30 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants a reduction of up to 90% on import duty applicable on raw or essential materials for the purpose of producing, mixing, or assembling in a promoted activity. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder.

389. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The same is requested to be upheld in the instant case.

390. Several responding exporters including Vanachai Group Public Company Limited, Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Metro MDF Co. Ltd., Advance Fiber Co. Ltd., Wisewoods Co. Ltd., Panel Plus MDF Co. Ltd., S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, and AgroFiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

391. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including reduction of import duties not exceeding ninety percent of the normal rate on raw or essential materials imported for the purpose of producing, mixing, or assembling in the promoted projects, each time for a period not more than one year from the date prescribed by the BOI provided that such raw or essential materials are not being produced or originated domestically in sufficient quantity to be acquired for use in such projects.

392. The purpose of this program is to facilitate companies that are entitled to receive benefits under Section 30 by reducing import duty on raw materials or essential materials used in BOI-promoted projects. The GOT submitted that the program provides a benefit on raw materials or essential materials imported for producing goods sold in the domestic market. Thus, the program can cause no injury to the Indian domestic industry and hence, irrelevant to the investigation. The eligibility for the program is not specific as it is made available on a voluntary basis and entities that wish to avail the benefit shall apply for the same. Moreover, none of the companies under investigation received the benefit under Section 30.

393. It has been submitted that no producer from Thailand received financial contribution/ benefit under this program. The program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of the previous finding in continuous copper will be violation of the principles of natural justice.

Examination by the Authority

394. The Authority notes that Section 30 of the Investment Promotion Act, 2002 provides for reduction of import duties not exceeding ninety percent of the normal rate on raw materials or essential materials which are imported into Thailand for the purpose of producing, mixing, or assembling in the promoted projects, each time for a period not more than one year from the date prescribed by the BOI provided that such raw materials or essential

materials comparable in quality are not being produced or originated within Thailand in sufficient quantity to be acquired for used in such project. The subsidy program is part of the investment promotion incentive package.

395. The subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. The Authority, therefore, holds this program as countervailable.

396. However, since none of the responding producers/exporters have availed benefit under this program, hence it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

Program No. 4: Exemption of Corporate Income Tax for BOI-Promoted Activities

Submission by the Petitioners

397. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Section 31 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants an exemption of corporate income tax levied on net profit earned from a promoted activity for a period not more than eight years. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. In case a company is suffering losses, the program provides for carry forward of the losses and hence, benefit can be availed at a subsequent period. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder.

398. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The same is requested to be upheld in the instant case.

399. Several responding exporters including Vanachai Group Public Company Limited, Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Metro MDF Co. Ltd., Advance Fiber Co. Ltd., Wisewoods Co. Ltd., Panel Plus MDF Co. Ltd., S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, and Agro Fiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

400. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including exemption of corporate income tax on the net profit derived from the BOI-promoted projects for a period of not more than eight years from the date income is first derived from such activity under Section 31. In case loss is incurred, the BOI may grant permission to deduct such annual loss from the net profits accrued after the expiration of the period of exemption for a period of not more than five years from the expiry date of such period. Under the new investment promotion scheme introduced by the BOI in January 2015, the incentive package is granted according to investment activity, instead of investment zone. The change in 2015 does not affect the incentive package any company, including the companies under investigation, receives under the zoning system prior to 2015. The eligibility for the program is not specific as it is made available on a voluntary basis and entities that wish to avail the benefit shall apply for the same. The program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of the previous finding in continuous copper final finding will be a violation of the principles of natural justice. Vanachai Group has not availed Program No. 4 for Thailand.

401. Metro MDF Co. Ltd. and Advance Fibre Co. Ltd. submitted that the program is not specific since the eligibility criterion is wide. It has been submitted by Panel Plus MDF that they incurred losses in BOI promoted activities and the program was not utilized. M/s Vanachai Group Public Company Ltd. has also submitted that out of their three certificates of BOI, two of them have expired long back in 1998 and 1999 respectively whereas one of the BOI certificates will expire in 2022. In addition to it, the company has also submitted that since they have incurred losses during the POI for the BOI promoted activity, hence is not eligible for Corporate income tax reduction under the said scheme.

Examination by the Authority

402. The Authority notes that the subsidy program is one of the benefits provided under the investment promotion package scheme. As per Section 31 of the Investment Promotion Act, 2002 provides exemption from corporate

income tax to eligible entities. Exemption from income tax is not available for more than eight years from the date income is first derived from such activity. Further in the case where a loss has been incurred during the eligible period in which exemption of corporate income tax was available, the BOI is empowered grant permission to the promoted person to deduct such annual loss from the net profits accrued after the expiration of the eligible period of exemption of corporate income tax for a period of not more than five years from the expiry date of such period. The promoted person may choose to deduct such loss from the net profit of any one year or several years.

403. The Authority notes that the program provides a financial contribution in the form of revenue foregone which is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. Therefore, Authority holds this program as countervailable.

404. The Authority notes that the Questionnaire Response filed by M/s Wisewoods Co. Ltd. shows that benefit was availed by them under this program and has provided information with regard to amount of subsidy received during POI.

405. It is also noted that the records submitted by M/s Metro MDF disclose that the benefit under the program was availed by them in the year 2016 but was utilized during the POI.

406. As submitted by M/s Vanachai Group Public Company Ltd, the Authority notes that the company was issued three BOI certificates out of which two of them have expired in 1998 and 1999 respectively whereas one of the BOI certificates will expire in 2022. In addition to it, the company has also submitted that since they have incurred losses during the POI for the BOI promoted activity, hence is not eligible for corporate income tax reduction under the said scheme. However, as per the records submitted by the company, the Authority notes that they have received income tax exemption though not under BOI certificate.

407. Similarly, the records submitted by M/s Green Fiber Company Ltd. show that they have received income tax exemption though not under BOI certificate.

408. The Authority notes that M/s Advance Fiber has not utilized the benefits granted under the said scheme as the BOI certificate has already expired and no additional income tax exemption was received by the company during the POI.

409. Furthermore, the records submitted by Vanachai Panel Industries Company Limited along with the Questionnaire Response shows that benefit was not availed by the responding exporter under the said program.

410. The Authority further notes that as per records submitted, M/s Panel Plus Co. Ltd., M/s Panel Plus MDF Company Ltd., M/s Agro Fiber Company Ltd. and have not availed the benefit under this scheme.

411. In view of the above, the Authority has determined the subsidy margin based on the information provided in the records submitted by the responding producers/exporters. The subsidy margin thereby calculated is provided in the table below.

Program No. 5: Reduction of Income tax in Investment Promotion Zones

Submission by the Petitioners

412. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Section 35 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants a 50% reduction of corporate income tax to enterprises engaged in a promoted activity and located in a promoted location/zone for a period not more than five years, after the period provided under section 31. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder. Furthermore, it is also region specific because the benefit is available only to enterprises located in promoted locations/zones.

413. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The same is requested to be upheld in the instant case.

414. Several responding exporters including Vanachai Group Public Company Limited, Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Metro MDF Co. Ltd., Advance Fiber Co. Ltd., Wisewoods Co. Ltd., Panel Plus MDF Co. Ltd., S. Kijchai

Enterprise Public Company Limited, and Agro Fiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

415. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including a 50 percent reduction of the corporate income tax on the net profit derived from the promoted activity under Section 35(1). The incentive is provided for a period of not more than five years, commencing from the expiry date referred to under paragraph one or two of Section 31, or from the date income is first derived from the promoted activity in the case where the promoted person is not granted exemption of corporate income tax.
416. The purpose of the program is to facilitate companies that are entitled to receive benefit under Section 35(1) by granting 50 percent income tax deductions in certain locations or zones. The eligibility to receive the BOI incentives is not specific as it is not limited to certain industries or certain enterprises. It is neither contingent upon export performance nor the use of domestic goods. None of the companies under investigation utilized the benefit under Section 35(1) during the POI.
417. It has been submitted that no producer from Thailand received financial contribution/ benefit under this program. The program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of the previous finding in continuous copper final finding will be a violation of the principles of natural justice.

Examination by the Authority

418. The Authority notes that 50% reduction is available from normal rate of corporate income tax on the net profit derived from promoted activity. Exemption of corporate income tax have already been countervailed by the Authority in other programs. Therefore, Authority notes that no additional countervailing duty should be imposed against the responding exporters under this subsidy program.

Program No. 6: Additional 25 percent deduction of the Cost of Installation or Construction of Facilities

Submission by the Petitioners

419. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Section 35 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants a deduction of 25% of the cost incurred for the installation or construction of facilities used for a promoted activity from the taxable income of the company. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder. Furthermore, it is also region specific because the benefit is available only to enterprises located in promoted locations/zones and carrying out promoted activity.

420. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The same is requested to be upheld in the instant case.

421. Several responding exporters including Vanachai Group Public Company Limited, Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Metro MDF Co. Ltd., Advance Fiber Co. Ltd., Wisewoods Co. Ltd., Panel Plus MDF Co. Ltd., S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, and Agro Fiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

422. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including permission to deduct from the net profit an amount not exceeding 25 percent of the cost of installation or construction of facilities used in the promoted activity under Section 35(3). In addition to normal depreciation, deductions from the net profit of any one year or several years within 10 years from the date income is first derived from the promoted activity may be made. Under the new investment promotion scheme introduced by the BOI in January

2015, the incentive package is granted according to investment activity, instead of investment zone. The change in 2015 does not affect the incentive package any company, including the companies under investigation, receives under the zoning system prior to 2015. The eligibility to receive the BOI incentives is not specific as it is not limited to certain industries or certain enterprises. It is neither contingent upon export performance nor the use of domestic goods.

423. Metro MDF Co. Ltd. and Advance Fibre Co. Ltd. submitted that the program is not limited to any particular enterprise or industry and is available to a wide range of economic activity and hence, is not specific. The program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of the previous finding in continuous copper final finding will be a violation of the principles of natural justice.

Examination by the Authority

424. The Authority notes that section 35(3) of the Investment Promotion Act, 2002 provides for the reduced income tax through deduction from net profit of amount not exceeding 25% of cost of installation or construction of facilities used in the promoted activity. The benefit under this subsidy program is equal to the difference between the amount of tax that would have been payable in absence of such deduction and the amount of income tax actually paid. The subsidy program is part of the investment promotion incentive package.

425. The subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and benefit is thereby conferred. Subsidy is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. Authority has already noted that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority notes that no additional countervailing duty should be imposed against the responding exporters under this subsidy program.

Program No. 7: Double Deduction available for Companies in Investment Promotion Zones

Submission by the Petitioners

426. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Section 35 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants a deduction on income tax, an amount double the cost incurred for transportation, electricity and water supply with respect to a promoted activity located in a promoted location/zone. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder. Furthermore, it is also region specific because the benefit is available only to enterprises located in promoted locations/zones.

427. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable. The same is requested to be upheld in the instant case.

428. Several responding exporters including Vanachai Group Public Company Limited, Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Metro MDF Co. Ltd., Advance Fiber Co. Ltd., Wisewoods Co. Ltd., Panel Plus MDF Co. Ltd., S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, and Agro Fiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

429. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant investment promotion incentives, including permission to deduct for the purpose of assessing corporate income tax an amount double the costs of transportation, electricity, and water supply incurred by the promoted person in the operation of the promoted activity under Section 35(2). The eligibility to receive the BOI incentives is not specific as it is not limited to certain industries or certain enterprises. It is neither contingent upon export performance nor the use of domestic goods. None of the companies under investigation receive the benefit under Section 35(2).

430. The programs administered by the BOI are not specific as per the ASCM. They are available broadly throughout the economy and not limited to a particular entity, geographical region, or segment of the industry. The WTO AB Reports in US – Upland Cotton and US – Anti-Dumping and Countervailing Duties (China) are relied on. The

program should be examined on the facts and circumstances of each case. A blanket application of the previous finding in continuous copper final finding will be a violation of the principles of natural justice.

Examination by the Authority

431. The Authority notes that under this program, benefit is provided in the form of double deduction of transport, electricity and water expenses for computing total income for the purpose of income tax. This subsidy program is part of the investment promotion incentive package.

432. The Authority notes that the subsidy program provides financial contribution in the form of revenue foregone, which is otherwise due and the benefit is thereby conferred. The benefit under this subsidy program is equal to the difference between the amount of tax that would have been payable in absence of double deduction and the amount of income tax actually paid. The subsidy program is also specific because it is limited to promoted enterprise carrying out promoted activity. Authority has already noted that countervailing duty should be imposed against subsidy program granting exemption from income tax. Therefore, Authority notes that no additional countervailing duty should be imposed against the responding exporters under this subsidy program.

Program No. 8: Exemption of Income Tax – Dividends

Submission by the Petitioners

433. The petitioners submitted that the said program is administered by the Board of Investment (“BOI”). Section 34 of Investment Promotion Act, 2002 (IPA) and the guide to Board of Investment, 2018 grants an exemption on income tax levied on dividends derived from a promoted activity is granted to juristic persons. Hence, the benefit can be availed by the companies under investigation and ultimately injure the domestic industry. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific because it is available only to a limited number of enterprises that hold a promotion certificate issued under the same legislation on meeting all the eligibility criteria provided thereunder and derives dividend income from promoted activities.

434. Several responding exporters including Vanachai Group Public Company Limited, Vanachai Panel Industries Co. Ltd., Metro MDF Co. Ltd., Advance Fiber Co. Ltd., Wisewoods Co. Ltd., Panel Plus MDF Co. Ltd., S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, and Agro Fiber Co. Ltd. have received Investment Promotion Certificates from the BOI and hence eligible to avail the program. Despite the same, they have not provided reasons for non-availment. M/s Advance Fiber Co. Ltd., M/s Metro MDF Co. Ltd., M/s Wisewoods Co. Ltd., and M/s Panel Plus MDF Co. Ltd. have themselves disclosed that they are eligible to avail the benefit under the program.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

435. The Investment Promotion Act, 1977 (IPA), enacted by the Government of Thailand, created the investment promotion program and authorized the BOI to grant exemption of income tax on dividends derived from the promoted activity under Section 34. As Section 34 benefits shareholders of the company, not the company itself, it does not cause injury to Indian domestic market in any way. Therefore, the benefit of Section 34 is not relevant to this investigation. Under the new investment promotion scheme introduced by the BOI in January 2015, the incentive package is granted according to investment activity, instead of investment zone. The change in 2015 does not affect the incentive package any company, including the companies under investigation, receives under the zoning system prior to 2015. The eligibility to receive the BOI incentives are not specific as it is not limited to certain industries or certain enterprises. It is neither contingent upon export performance nor the use of domestic goods. M/s Metro MDF Co. Ltd. and M/s Advance Fibre Co. Ltd. submitted that benefit, if any, is not granted to the company but the shareholders of the company. It has been submitted by M/s Panel Plus MDF that the program benefits the shareholders of the company and not the company itself. M/s Panel Plus MDF did not benefit in the POI since the BOI promoted activity was in losses and dividends were NIL. The Thai exporters have either not availed any countervailable subsidy or the amount of subsidy, if any, is below *de minimis*. The responding producers/exporters have not availed any benefit under the said scheme.

Examination by the Authority

436. The Authority notes that section 34 of the Investment Promotion Act, 2002 authorizes the BOI to grant exemption of income tax on dividends derived from the promoted activity. According to the relevant legal provision, the benefit is provided to juristic persons and hence, to shareholder companies. Contrary to the submissions by the

Government of Thailand that the program cannot injure the domestic industry, since the benefit is enjoyed by shareholders/individuals, any of the companies under investigation can avail the benefit under the program. The Authority holds the said program as countervailable. However, since none of the responding producers/exporters have availed benefit under this program, hence it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

Program No. 9: VAT Exemption on Exports

Submission by the Petitioners

437. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Thailand. Section 80 of the Revenue Code, 2016 grants a zero rate on VAT on export of goods and services and the supply of goods and services between bonded warehouses or enterprises located in free zones. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is export contingent and hence, deemed specific. Furthermore, it is also region specific.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

438. According to the Section 80/1 of the Revenue code, the following businesses among a few other qualifying ones shall use the zero rate value added tax calculation: (1) export of goods which is not exempt from value added tax under Section 81(3); (2) sale of goods or provision of services between bonded warehouses, between business persons which carrying on business in Customs free zone whether they be in the same zone or not, or between bonded warehouses and business person carrying on its business in Customs free zone prescribed by the Director-General.

439. The Government of Thailand also submitted that the same program was addressed by the Authority in the final finding in Anti-subsidy investigation concerning imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam and found not countervailable.

440. It has been submitted that the program provides remission of tax on exported goods. The program is not countervailable as per the ASCM and the CTA. No duty was imposed on the same in the Copper case.

Examination by the Authority

441. It is noted that section 80 of the Revenue Code, 2016 provides for payment of value added tax by business person engaged in sales of goods or services. However, this value added tax rate is zero for certain specified enterprises.

442. It is noted that this subsidy program provides for exemption from value added tax on export of goods. The subsidy program provides for remission of tax on exported goods which is otherwise borne by the like product when destined for domestic consumption in accordance with footnote 1 of the SCM Agreement and Section 9B(b)(i) of the Customs Tariff Act. Therefore, Authority notes that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this subsidy program.

Program No. 10: Short Term Export Credit Insurance

Submission by the Petitioners

443. The petitioners submitted that the said program is administered by the Export-Import Bank of Thailand. The program protects the exporters' foreign receivables against non-payment risks. In case of defaults in payment, the loss is compensated as per conditions mentioned in the insurance policy. The program is extended to SMEs only. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due since it provided insurance at a discounted premium rate and a benefit is thereby conferred. The program is export contingent and hence, deemed specific.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

444. Export Credit Insurance facilities protect exporter's foreign receivables against non-payment risks. In case of payment defaults caused by overseas buyers, EXIM Thailand compensate for the loss according to conditions specified in the insurance policy. The risks covered include commercial risks as well as political risks.

445. It has been submitted that no producer from Thailand received financial contribution/ benefit under this program and no countervailable benefit is provided.

Examination by the Authority

446. The Authority notes that the program is administered by the Export-Import Bank of Thailand. The Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a state-owned specialized financial institution under the Ministry of Finance's supervision established to act as the Thai government's export credit agency (ECA). It was established by the Export-Import Bank of Thailand Act, 1993 (B.E. 2536) which took effect on 7 September 1993. The EXIM Bank is the government mechanism in supporting and enhancing Thai entrepreneurs' competitiveness in global trade and investment. The Ministry of Finance injected capital to enhance the Bank's capability to fulfill its mission as a state-run specialized financial institution with a mandate to promote and support Thai exports, imports, and investments, both domestic and overseas. In September 2009, the Ministry of Finance increased the Bank's capital which was earmarked for export promotion through export credit insurance under the Strong Thailand Scheme 2012. The service helps safeguard exporters against non-payment risk by overseas buyers, thereby boosting exporters' confidence in their business expansion in the main or emerging markets. The EXIM Bank currently follows the Master Plan 2017-2027 which was framed as a result of the Thai government's agenda to realign Thai exports to 'New Frontiers with high economic growth rates' which includes India. The Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) as the government's specialized financial institution has remained committed in pursuing its role as a key mechanism to drive Thailand's international trade and investment strategies. Export-Import Bank of Thailand continued developing the organization in line with the changing trade and investment environment with the main objective to perform as a government mechanism in supporting and enhancing Thai entrepreneurs' competitiveness in global trade and investment.
447. The Authority notes that the Exim bank is a public body entrusted with governmental functions and is vested with authority to exercise governmental functions, based on formal indicia of government control and evidence showing that it has been exercised in a meaningful way, hence it is a public body. Exim bank provides financial help in form of protecting exporter's foreign receivables against non-payments risks.
448. The program provides for financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit conferred on the recipient is equivalent to the difference between the fee paid by the recipient for availing guarantee from EXIM Bank and the fee that would have been paid to any other commercial bank for such guarantee. The subsidy program is also specific because it is contingent on export. The Authority holds the said program as countervailable. However, none of the responding producers/exporters have provided any evidence regarding availment of benefit under the scheme. Hence the Authority notes that no countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this scheme.

Program No. 11: Medium- and Long-term Export credit Insurance**Submission by the Petitioners**

449. The petitioners submitted that the said program is administered by the Export-Import Bank of Thailand. The program protects the exporters' foreign receivables against non-payment risks. In case of defaults in payment, the loss is compensated as per conditions mentioned in the insurance policy. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due since it provided insurance at a discounted premium rate and a benefit is thereby conferred. The program is export contingent and hence, deemed specific.
450. The responding exporters have received loans from banks within the country at preferential rates. The lending interest rate depends upon the credit rating of the company whereby the lending bodies exercise discretion and provide preferential loans. The Authority should take cognizance of the subsidized loans and quantify the same.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

451. Medium and Long-term Export Credit Insurance covers against default of payment caused by commercial and political losses relating to overseas trade transactions i.e. export of goods and services including credits and loans to overseas buyers/borrowers. No loans are offered by the EXIM Bank. It has been submitted that no producer from Thailand received financial contribution/ benefit under this program. The letter submitted by the EXIM Bank specifically shows that no benefit was availed under this program by Vanachai Group or Panel Plus Group. The case is not fit for resorting to facts available when the Thai exporters have cooperated with the Authority. Rule 7(8) of the CVD Rules as per the DGTR Manual and Article 12.7 of the ASCM according to the Panel report in EC – Countervailing Measures on DRAM Chips are relied on.

452. For a loan to qualify as a subsidy, the same must originate from a government or public body and a benefit should be conferred through a lower interest rate than comparable loan in the market. No evidence regarding the same has been produced by the domestic industry. The loans taken by the Metro Group are from commercial banks and at market rates.

Examination by the Authority

453. The Authority notes that the program is administered by the Export-Import Bank of Thailand. As examined in Program no. 10 the EXIM BANK is a public body entrusted with governmental functions and is vested with authority to exercise governmental functions, based on formal indicia of government control and evidence showing that it has been exercised in a meaningful way, hence it is a public body. Exim bank provides financial help in form of protecting exporter's foreign receivables against non-payments risks.

454. The program provides for financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and benefit is thereby conferred. The benefit conferred on the recipient is equivalent to the difference between the fee paid by the recipient for availing guarantee from EXIM Bank and the fee that would have been paid to any other commercial bank for such guarantee. The subsidy program is also specific because it is contingent on export and enterprise specific since the fee chargeable would also depend on the creditworthiness of the consumer company. The Authority holds the said program as countervailable. However, none of the responding producers/exporters have provided any evidence regarding availment of benefit under the scheme. Hence, the Authority notes that no countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this scheme.

OTHER SUBSIDY- LOANS

455. However, during the course of investigation, the Authority found that the as per the information submitted by M/s Green Fiber, M/s Agro Fiber, M/s Panel Plus, M/s Panel Plus MDF, M/s Vanachai Group, and M/s Vanachai Panel, loans were received by the companies from the financial institutions operating on the directions of Central Bank at lesser interest rates in comparison to prevailing market rates. Authority has taken note of the same and found that these loans are in the nature of financial contribution in the form of revenue forgone. These loans are enterprise specific as these loans are granted on terms more favorable than the recipient could actually obtain on the market. Hence the Authority holds the said program as countervailable.

456. There is a difference between the interest rate paid to that of the normal interest rate. Hence, the Authority notes that countervailing duty should be imposed against producers/exporters M/s Green Fiber Co. Ltd., M/s Agro Fiber Co. Ltd., M/s Panel Plus Co. Ltd., M/s Panel Plus MDF Co. Ltd., M/s Vanachai Group Co. Ltd., and M/s Vanachai Panel Co. Ltd. under this program.

Program No. 12a: Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration

Submission by the Petitioners

457. The petitioners submitted that the program is administered by the Government of Thailand. Nearly all of the harvestable forest land in Thailand is owned by the Government of Thailand and it grants logging rights to companies after charging a royalty which is not calculated based on market principles. The Government of Thailand also maintains high statutory export taxes on commodities including wood. This distorts the domestic market and makes wood which is an essential raw material to producers of the PUC at LTAR. As a result, it does not make any difference whether the raw material is procured from a state forest or private land. The prices for timber in Thailand are below international benchmark prices.

458. As per the information on the website of the responding producers/exporters from Thailand, rubber wood or eucalyptus is used as the raw material for the subject goods. For the purpose of obtaining rubberwood, the Government of Thailand together with the Forest Department has taken up increased responsibility in planting. Further, the Rubber Research Institute of Thailand and the Royal Forest Department's Forest Research Institute has collaborated for the same purpose.

459. The term 'prohibited wood' is not defined under the National Reserve Forest Act, 1971 as contended by the interested parties. However, the term "wood" is defined to include "all kinds of wood". Hence, rubberwood and other kinds of firewood fall within the scope of the Act.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

460. The price and supply of wood is not regulated by the GOT. Saw dust/ wood dust is used which is a waste from sawmill or wood processing plant for the production of the PUC. The National Reserve Forest Act, 1964 was amended in 2019 and redefines 'prohibited woods' to exclude all types of wood that grow in private land or those on public land after necessary approval of the Cabinet. Rubberwood or any kind of firewood doesn't fall under

the scope of ‘prohibited woods’ as per section 9. The Government of Thailand does not place any regulation on wood prices.

461. No benefit was received by the Metro Group as it sourced rubber wood consumed in the production of the PUC from unrelated suppliers not related or controlled by the government and grown on private plantations. Fiberboard manufacturers in Thailand are using the residue of logs, wastepaper, fiber etc. Panel Plus uses 100% rubber wood and is bought from the open market as per market price. The wood raw materials bought by the Vanachai Group are at market price traded between individual person in public. Agro Fiber and Green Fiber uses wood chips (eucalyptus chip, including bark but not exceeding 20% and size 25-40 mm) as per market forces through monthly bidding. Wisewoods procured their supply of rubber wood from domestic supplier. The prices of the same are as per market forces and faces high competition from other industries too. The determination of subsidy for LTAR program should be undertaken as per Annexure-IV of the CVD Rules.

462. The use of benchmark price based on New Zealand is objected to since no reasons have been provided for choosing the same. It contains all sorts of wood and logs, and rubber wood is not included in any of the categories included. Moreover, the Government of New Zealand controls all of the harvested forest. The export price of wood from New Zealand to India are not determined as per market forces. New Zealand wood prices cannot be compared to rubber wood at all. The Authority is required to reason the choice of benchmark in lines with the Appellate Body report in US – Carbon Steel (India). The alternative benchmarks suggested by the domestic industry are also inadequate. The adequate remuneration, if any, should be determined in light of the prevailing market conditions of the exporting country and not based on price of raw materials in any third country. The benchmark should be as per prevailing market conditions in the country of the provision. US – Coated Paper (Indonesia) is relied on.

Examination by the Authority

463. The Government of Thailand controls nearly all of Thailand’s harvestable forest. Various measures taken by the government have distorted the Thai domestic market for logs to the benefit of the downstream industries that use logs.

464. The Applicants contended that the Government of Thailand controls nearly all of Thailand’s harvestable forest through the National Reserve Forest Act, 1964. Section 15 of the Act states that logging in these forests shall be conducted only after obtaining a license from a competent officer under the Act. Granting of licenses including the beneficiary and period of validity of the licenses are at the discretion of the competent officer. According to the Act, the licensee is required to pay a royalty at the rate fixed by the Ministry of Natural Resources and Environment. However, according to section 5 of the Act, this royalty that is published through Ministerial Regulations from time to time cannot exceed the limit of 40 Bhat per cubic meter set forth in the schedule to the Act.

465. It is noted that the royalty charged by the relevant Ministry is discretionary and with disregard for market principles. Setting an upper limit to the royalty statutorily shows that the program aims to lower the price of timber in the domestic Thai market. The royalty charged is far less than the market rates of the timber. Hence, wood, which is the primary raw material in the fiberboard industry, is made available for procurement to the companies under investigation at rates below the market rate. Furthermore, the applicants for the license would be entities that either sell wood directly or use them as their raw material. Hence, the scope of the program is de facto limited to small number of industries.

466. The program provides a financial contribution in the form of goods at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific since the licenses are granted on a discretionary basis. Therefore, the Authority notes that countervailing duty should be imposed against the responding exporters under this subsidy program.

467. The Authority notes that GOT in its written submissions post the 2nd Oral Hearing have submitted that the fiberboard manufacturers are using the residue of logs, wastepaper, fiber, etc. for the manufacture of subject goods. However, in its response to the additional questionnaire, the government has responded that the exporters are using saw dust/ wood dust for the production of the PUC. However, the submissions of responding exporters in the EQRs as well as the information available on the websites of the responding exporters suggest that raw material used for the production of PUC are rubberwood, renewable rubberwood and eucalyptus wood.

468. To determine the quantum of the subsidy margin, the Authority looked for the appropriate benchmark whereby it was found that New Zealand is one of the largest exporters of logs globally. The Authority considered exports of log from New Zealand to India as an appropriate benchmark being representative as compared to import price from New Zealand to the subject countries. For those producers/exporters that have used wood chip as their raw material, the domestic prices in New Zealand for wood chip has been considered as the appropriate benchmark. The actual procurement rate of wood has been considered as per the exporters questionnaire response. Considering the appropriate conversion rates, the subsidy margin determined has been provided in the table below.

Program No. 12b: Provision for Land at Less Than Adequate Remuneration

Submission by the Petitioners

469. The Government of Thailand also grants land-based incentives in the form of exemption/reduction from payment of land rent to enterprises set up in areas of difficult socio-economic conditions and engaged in one of the encouraged sectors and located in specified zones or regions. Hence, the program is countervailable. The analysis of the Authority in the Disclosure Statement pertains to both raw materials (wood) and land at LTAR. There is no contradiction in the Authority's analysis in the Disclosure Statement.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

470. GOT does not provide land at LTAR. Treasury Department is responsible for governing, overseeing, and maintaining state property. Government provides supporting measures and other promotions for development of basic infrastructure, investment in supporting infrastructure and allocation of land for operation in SEZ. Treasury department uses auction process to allocate land in SEZs to government agencies and private sector as per set criteria. Up until now, there is no business operation in any location under SEZs. None of the producers/exporters of PUC are in SEZ or any other specific geographic area.

471. The land procured by the Metro Group was at a price far above the price guideline issued by the government. No land was purchased or leased from the government. The land purchased by the Panel Plus Group and Vanachai Group are as per the general purchase price. The land purchased by Agro Fiber, Green Fiber, and Wisewoods are not from the government but from private players as per prevailing market prices.

Examination by the Authority

472. For land procured by the manufacturing units at Less than adequate remuneration, the Authority notes that the Treasury Department of the Government of Thailand provides land on lease to enterprises investing in Special Economic Development Zones in 6 provinces. The beneficiary is required to pay a rent specified by the Board of Investment of Thailand and not one determined based on market principles. The program provides a financial contribution in the form of revenue foregone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is specific since it is provided to those companies investing in Special Economic Development Zones designated by the Government of Thailand. Therefore, the Authority holds this program as countervailable. However, there is no evidence on record to suggest that the responding producers have availed exemption/reduction in land rent. Hence, it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this program.

Program No. 13: Provision for Electricity for Less Than Adequate Remuneration

Submission by the Petitioners

473. The petitioners submitted that the program is administered by the National Energy Policy Council (NEPC) and the Energy Regulatory Commission (ERC). The program, enabled by the Energy Industry Act, 2007, provided differential prices for electricity to enterprises located in Provincial Electricity Authority (PEA) service areas as a result of the uniform pricing policy undertaken by the ERC. The inherent cost differentials in supplying electricity to Metropolitan and Provincial regions are completely disregarded by the ERC. Hence, the tariff determination process is inconsistent with market principles and distorts the domestic supply of electricity. The program provides a financial contribution in the form of provisions for goods or services at LTAR and a benefit is thereby conferred. The program is specific as it is provided only to enterprises in certain encouraged sectors and located in certain regions.

Submissions by Government of Thailand/other interested parties

474. The claim is incorrect and baseless. The price of electricity is uniform in nature and hence, not specific. The program does not qualify as a subsidy as per the ASCM. No countervailable benefit is provided. The program is not specific as it is provided to all businesses and industries.

475. PEA which distributes and sells electricity to manufacturing companies is operating at profit and is not providing electricity at LTAR. The state-owned suppliers, i.e., EGAT, MEA and PEA can enter into bilateral agreement with particular end-users for supply.
476. The rates charged by the three entities are to be approved by the ERC. ERC follows the Tariff Setting Policy for the same. The rate is published after approval from the ERC.
477. As per the Tariff Setting Policy during the POI, a uniform tariff policy is followed which provides same rate regardless of the location. Same wholesale tariff structure is followed for MEA and PEA. Retail tariff charged by MEA and PEA are same regardless of location or sector.
478. The prices charged covers government's operating costs and ensures reasonable returns.
479. Power tariff includes base tariff (investment costs including costs in power plants, transmission, distribution lines etc.), automatic tariff adjustment mechanism (fuel cost and power purchase cost), and VAT.
480. The power purchased by the Metro Group, Panel Plus Group, and Vanachai Group, as per their submissions, are from PEA and not at a subsidized rate. The same is determined by the PEA after taking into consideration peak charges, off-peak charges, demand charges, etc. The tariff depends on the type of entity, type of service, and time of use.
481. The benchmark relied on by the domestic industry for the quantification of the same is erroneous as it takes into consideration only off-peak hour rates issued by the PEA and ignores all additional charges. Since PEA is the only regulatory authority for electricity supply in provisional areas of Thailand, there cannot be any other benchmark.

Examination by the Authority

482. The Authority notes that under the Energy Industry Act, 2007, power supply in Thailand is undertaken by the Metropolitan Energy Authorities (MEA) and the Provincial Energy Authorities (PEA) and regulated by the Energy Regulatory Commission (ERC). ERC has undertaken a uniform tariff policy for the supply of electricity throughout Thailand. Though ERC is statutorily required to take into account all the costs involved while determining tariffs, ERC has disregarded the inherent cost differentials in supplying electricity to Metropolitan as well as Provincial regions. Hence, the Authority notes that the tariff determination process is inconsistent with market principles and distorts the domestic supply of electricity. The program provides a financial contribution in the form of electricity at less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The Authority notes that there is no uniform tariff and tariff depends on the type of entity and hence the program is specific. Therefore, the Authority holds this program as countervailable. Hence, the authority has quantified subsidy margins for the said scheme against the responding exporters/producers in the table below.

Advance Fiber Co. Ltd.

483. Advance Fiber Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Advance Fiber filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.
484. Authority examined the response filed by Advance Fiber and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in provision for wood and electricity at LTAR were availed by Advance Fiber. As a result, benefit was conferred to Advance Fiber in the form of various subsidies.
485. Authority has verified the information provided by Advance Fiber and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.
486. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 1	Exemption/Reduction of import duties on machinery	***%	0-10

2	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
3	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	0-10

Metro MDF Co. Ltd.

487. Metro MDF Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Metro filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

488. Authority examined the response filed by Metro and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Metro has disclosed in their questionnaire response that it has availed exemption on corporate income tax. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in provision for wood and electricity at LTAR were availed by Metro. As a result, benefit was conferred to Metro in the form of various subsidies.

489. Authority has verified the information provided by Metro and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

490. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 4	Exemption of Corporate income tax for BOI	***%	0-10
2	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
3	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	0-10

Wisewoods Co.Ltd.

491. Wisewoods Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Wisewoods filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

492. Authority examined the response filed by Wisewoods and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Wisewoods has disclosed in their questionnaire response that it has availed exemption on import duty on machinery and corporate income tax. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in provision for wood and electricity at LTAR were availed by Wisewoods. As a result, benefit was conferred to Wisewoods in the form of various subsidies.

493. Authority has verified the information provided by Wisewoods and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

494. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 1	Exemption/Reduction of import duties on machinery	***%	0-10
2	Program No 4	Exemption of Corporate income tax for BOI	***%	0-10
3	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
4	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Green Fiber Co. Ltd.

495. Green Fiber Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Green Fiber filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

496. Authority examined the response filed by Green Fiber and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. The Authority determined that the subsidy programs resulting in exemption of corporate income tax, preferential loans and provision for wood and electricity at LTAR were availed by Green Fiber. As a result, benefit was conferred to Green Fiber in the form of various subsidies.

497. Authority has verified the information provided by Green Fiber and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

498. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 4	Exemption of Corporate income tax for BOI	***%	0-10
2	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	10-20
3	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
4	Other Subsidies	Loans	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Agro Fiber Co. Ltd.

499. Agro Fiber Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Agro Fiber filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

500. Authority examined the response filed by Agro Fiber and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Agro Fiber has stated in their questionnaire response that they have not availed any countervailable subsidy. However, the Authority determined that the subsidy programs resulting in preferential loans and provision for wood and

electricity at LTAR were availed by Agro Fiber. As a result, benefit was conferred to Agro Fiber in the form of various subsidies.

501. Authority has verified the information provided by Agro Fiber and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

502. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
2	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
3	Other Subsidies	Loans	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Panel Plus MDF Co. Ltd.

503. Panel Plus MDF Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Panel Plus MDF filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

504. Authority examined the response filed by Panel Plus MDF and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in preferential loans and provision for wood and electricity at LTAR were availed by Panel Plus MDF. As a result, benefit was conferred to Panel Plus MDF in the form of various subsidies.

505. Authority has verified the information provided by Panel Plus MDF and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

506. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
2	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
3	Other Subsidies	Loans	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Panel Plus Co. Ltd.

507. Panel Plus Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Panel Plus Co filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

508. Authority examined the response filed by Panel Plus Co and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Panel Plus

Co. Ltd. had disclosed in its questionnaire response that none of the subsidy programs are applicable to them since they do not produce the PUC. However, Panel Plus Co purchases fibreboard from its related party, laminates them and sells the product. It is noted that laminated fibreboard falls within the scope of the PUC. Hence, the Authority determined that the subsidy programs resulting in preferential loans and provision for wood at LTAR were availed by Panel Plus Co. As a result, benefit was conferred to Panel Plus Co in the form of various subsidies.

509. Authority has verified the information provided by Panel Plus Co and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

510. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
2	Other Subsidies	Loans	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	0-10

Vanachai Group Public Co. Ltd.

511. Vanachai Group Public Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Vanachai Group filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

512. Authority examined the response filed by Vanachai Group and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. The Authority determined that the subsidy programs resulting in exemption of corporate income tax, preferential loans, and provision for wood and electricity at LTAR were availed by Vanachai Group. As a result, benefit was conferred to Vanachai Group in the form of various subsidies.

513. Authority has verified the information provided by Vanachai Group and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

514. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 4	Exemption of Corporate Income Tax for BOI	***%	0-10
2	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	10-20
3	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
4	Other Subsidies	Loans	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

Vanachai Panel Industries Co. Ltd.

515. Vanachai Panel Industries Co. Ltd. is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Vanachai Panel filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

516. Authority examined the response filed by Vanachai Panel and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in preferential loans and provision for

wood and electricity at LTAR were availed by Vanachai Panel. As a result, benefit was conferred to Vanachai Panel in the form of various subsidies.

517. Authority has verified the information provided by Vanachai Panel and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

518. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	10-20
2	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
3	Other Subsidies	Loans	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

S. Kijchai Enterprise

519. S. Kijchai Enterprise is a producer/exporter of subject goods in Thailand. Kijchai filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

520. However, it is noted that S. Kijchai Enterprise has failed to provide a meaningful summary of the confidential submissions in the form of Non-confidential version submitted to the Authority. The Authority notes that such a limited submission has impeded the opportunity for the other interested parties to make meaningful comments on the Exporter Questionnaire response filed by the aforementioned company. The Authority, therefore, holds to reject the response filed by the above company. Accordingly no individual subsidy margin rate can be determined for S. Kijchai Enterprise. Subsidy margin determined for all other producers/exporters from Thailand is being made applicable for S. Kijchai Enterprise.

521. No other producer/exporter from Thailand has filed questionnaire response. Countervailing duty for all other producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available and countervailability of the respective programs. The subsidy margins are given in the table below.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 1	Exemption/Reduction of import duties on machinery	***%	0-10
2	Program No 4	Exemption of Corporate income tax for BOI	***%	0-10
3	Program No 12a	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	10-20
4	Program No 13	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	10-20
5	Other Subsidies	Loan	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	20-30

Vietnam

(i) Program No. 1: Import Duty Exemptions on Imports of Raw Materials for Exporting Goods

Submissions by the Petitioners

522. The petitioners submitted that the said program is administered by the General Department of Vietnam Customs (GDVC). The Law of Import and Export Duty, 2016, Decree No. 134/2016/NĐ-CP, Decree No. 08/2015/NĐ-CP,

and Circular No. 38/2015/TT-BTC grant an exemption on payment of import duty levied on import of goods directly used in the production of goods for exports. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports.

523. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

524. The Government of Vietnam submitted that it pursues a policy of exemption of import duty for imported raw materials used for exporting production. The policy is regulated by the Law on Export and Import Duty and is applied to every form and type of business throughout the country.

525. The amount of exemption is equal to the amount of duty corresponding to the value of imported materials actually used in the production of the finished goods that are exported. The amount is determined or declared at the time of reporting to Customs on the use of imported raw materials in accordance with Decree 08/2015/NĐ-CP, and Circular 38/2015/TT-BTC. Though several companies under investigation from Vietnam imported raw materials from countries including Malaysia, China, Thailand, India, and Korea, there was no duty payable as per the China-ASEAN Free Trade Agreement and ASEAN-India Free Trade Agreement.

Examination by the Authority

526. The Authority notes that the program is administered under the Law on Import and Export Duty, 2016, Decree 08/2015/NĐ-CP and Circular 38/2015/TT-BTC. The program provides for exemption on import duty on raw materials used in the manufacture of exported product. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is contingent on export. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

527. The responding producers/exporters have stated in their Questionnaire Responses that they have either not imported any raw materials or imported them under an FTA where the duty payable is NIL. It is noted that no benefit was availed by any of the cooperative producers/exporters, hence it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this program.

(ii) Program No. 2: Import Duty Exemptions on Imported Raw Materials in Non-Tariff Zones

Submissions by the Petitioners

528. The petitioners submitted that the said program is administered by the General Department of Vietnam Customs (GDVC). The Law of Import and Export Duty, 2016 grants an exemption on payment of import duty levied on import of raw materials into Non-Tariff Zones established by decisions of the Prime Minister. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports and is available only to enterprises located in the Non-Tariff Zones.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

529. The Government of Vietnam submitted that according to Article 16 of the Law on Export and Import Duty, the import duties levied on goods manufactured, processed, recycled, assembled in a free trade zone without using imported raw materials or components will be exempted when they are imported into the domestic market. It is also submitted that none of the companies under investigation from Vietnam are located in non-tariff zones.

Examination by the Authority

530. The Authority notes that the program is administered under the Law on Import and Export Duty, 2016. The program provides for exemption on import duty levied on goods manufactured, processed, recycled, assembled in a free trade zone when they are imported into the domestic market. The program provides for financial contribution in the form of revenue foregone and benefit is thereby conferred. The subsidy program is also specific because it is provided to enterprises located in Non-Tariff Zones. Therefore, Authority holds this program as countervailable.

531. The responding producers/exporters have stated in their Questionnaire Responses that they have either not imported any raw materials or imported them under an FTA where the duty payable is NIL. It is noted that no benefit was availed by any of the cooperative producers/exporters, hence it is noted that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this program.

(iii) Program No. 3: Import Duty Exemption on Imports of Spare Parts and Accessories for Companies in Industrial Zones

Submissions by the Petitioners

532. The petitioners submitted that the said program is administered by the General Department of Vietnam Customs (GDVC). The Law of Import and Export Duty, 2016, Law of Investment No. 67/2014/QH13, Decree No. 134/2016/NĐ-CP, and Appendix I and II of Decree No. 118/2015/NĐ-CP grant an exemption on payment of import duty levied on import of goods to create fixed assets for companies subject to investment preferences and geographic areas. These imported goods include machinery and equipment, components, parts, spare parts of machinery and equipment, special-use vehicle in a technology line directly used for a manufacturing project, and building materials that cannot be domestically-produced. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is only available to companies engaged in preferred investment activities and located in areas/zones identified under the Law of Investment No. 67/2014/QH13.

533. FSC Corporation and Kim Tin have expanded capacities or added new plants in the AUL period. Hence, they should have availed the program providing import duty exemption on capital goods.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

534. The Government of Vietnam submitted that the import duty exemption is not limited to companies in industrial zones. However, a general exemption of import duty on import of equipment and machinery for the creation of fixed assets subject to investment preferences exists. Appendix I to Decree 118/2015/NĐ-CP identifies sectors eligible and Appendix II identifies geographical areas eligible for investment preferences. There is no law which mandated availment of programs in any case.

535. There is no countervailable benefit being provided since the imports made by the responding producers/exporters are under FTAs and the import duty payable is NIL. Hence, no revenue is forgone by the government for such imports.

Examination by the Authority

536. The Authority notes that the said program is administered by the General Department of Vietnam Customs (GDVC). Under the program, an exemption is granted on import duty levied on import of equipment and machinery for the creation of fixed assets. The exemption is granted to eligible sectors enlisted under Appendix I to Decree 118/2015/NĐ-CP and eligible investment programs enlisted under Appendix II to Decree 118/2015/NĐ-CP.

537. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is only available to companies engaged in eligible sectors and subject to investment preferences of the government. Therefore, the Authority holds that this program as countervailable.

538. Questionnaire response filed by M/s MDF VRG shows that benefit is received by them under this subsidy program and therefore the Authority notes that countervailing duty should be imposed against this subsidy program to M/s MDF VRG.

539. M/s Kim Tin MDF Joint Stock Co. has stated in their Questionnaire Response that they have not imported any spare parts and accessories. Hence, it is noted that no benefit was availed by M/s Kim Tin MDF Joint Stock Co. Co. Ltd. and it is noted that no countervailing duty should be imposed against them under this program.

(iv) Program No. 4: Reduction of Corporate Income tax

Submissions by the Petitioners

540. The petitioners submitted that the said program is administered by provisional tax departments. Law of Investment No. 67/2014/QH13, Law on Enterprise Income Tax No. 14/2008/QH-12 and Decree No. 124/2008/NĐ-CP, and Decree No. 12/2015/NĐ-CP grant a reduction or exemption on payment of corporate income tax for a definite period or for the whole duration of implementation of an investment project identified under List A or Appendix to the Decree No. 164/2003/NĐ-CP or located in a geographical area identified under

Decree No. 08/2006/NĐ-CP. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is only available to companies engaged in investment projects or located in geographical area enlisted under the relevant laws.

541. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

542. The Government of Vietnam submitted that since 2009, the legal provisions for corporate income tax are in the Law on Enterprise Income Tax, No. 14/2008/QH-12 and the implementation is detailed under Decree No. 124/2008/NĐ-CP (replaced by Decree No. 218/2013/NĐ-CP with the same application). Under Article 15 of the Decree, a rate of 10% is applicable for 15 years to enterprises newly established in geographical areas identified under Article 15.1(a) and a rate of 20% for 10 years to those enterprises newly established in geographical areas identified under Article 15.4. Further Article 16 provides for tax exemption and reductions as follows:

- Tax exemption for 4 years and a 50% reduction in payable income tax for next 9 years for newly established enterprises (1) of socialized domains, and (2) located in geographic areas with specially difficult socio-economic conditions or in geographical areas enlisted under Article 16.1(b).
- Tax exemption for 4 years and a 50% reduction in payable income tax for next 5 years for newly established enterprises (1) of socialized domains, and (2) located in geographic areas with specially difficult socio-economic conditions or in geographical areas enlisted under Article 16.2.
- Tax exemption for 2 years and a 50% reduction in payable income tax for next 4 years for newly established enterprises in geographical areas enlisted under Article 16.3.

543. Kim Tin MDF Joint Stock Company submitted that the program is neither prohibited nor specific.

Examination by the Authority

544. The Authority notes that under the program, a reduction or exemption on payment of corporate income tax is granted. The period and extent to which the reduction/exemption is granted is subject to geographical location and the investment made. While Article 15 of the Decree 124/2008/NĐ-CP grants preferential income tax rate depending on the geographical location of the newly established/hi-tech enterprise, Article 16 of the Decree 124/2008/NĐ-CP also grants an exemption/reduction in income tax depending on the geographical location of the newly established enterprise. The eligible geographical areas are enlisted under the Decree as geographical areas with specially difficult socio-economic conditions. There is no application or approval required to avail the benefit under the program. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific since it is provided to those companies located in designated areas/zones and undertaking investments as enlisted. Therefore, the Authority holds that this program should be held as countervailable.

545. M/s. MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Co. in their Questionnaire Response, has disclosed that one of its plants is eligible to claim the benefit under the program but no benefit was availed. The records submitted by the company discloses that the concessional income tax was paid by them. It is also noted from the Questionnaire response filed by Kim Tin MDF Joint Stock Co. that the company has availed benefit under this subsidy program. In view of the above, the Authority notes that countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this program.

546. The Authority has quantified the subsidy margin based on the information submitted by the responding producers/exporters. The subsidy margin determined has been provided in the table below.

(v) Program No. 5: Exemption or Reduction of Import Tax

Submissions by the Petitioners

547. The petitioners submitted that the said program is administered by the Government of Vietnam. Law No. 67/2015/QH13 and Article 15 of Law of Investment No. 67/2014/QH13 grant a reduction or exemption on payment of import duty levied on imports of fixed assets, raw materials, supplies, and spare parts. The benefit is available to investment projects (i) enlisted under Clause 1 of Article 16 of the Law, or (ii) with investment of at

least VND 6,000 billion, (iii) located in administrative divisions enlisted under Clause 2 of Article 16 of the Law, or (iv) located in rural areas employing at least 500 workers, or (v) engaged in science and technology. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is only available to companies engaged in projects or located in geographical area enlisted under the relevant laws.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

548. M/s MDF VGR Quang Tri Wood Joint Stock Company submitted that exemption of duties under Free Trade Agreements are non-countervailable as held by the US authorities in the anti-subsidy investigation on imports of “Citric Acid and certain Citric Salts” from Thailand.

Examination by the Authority

549. The Authority has already determined that those programs that grant an exemption/reduction on import duty should be subject to countervailing duties. Therefore, it is noted that no additional countervailing duties should be imposed against this subsidy program.

550. While M/s MDF VRG stated in their Questionnaire Response that the imports made by the company was duty free, M/s Kim Tin MDF Joint Stock Co. in its questionnaire response has submitted that no benefits were claimed under this program. In view of the above, it is decided not to impose countervailing duty against any of the responding producers/exporters under this scheme.

(vi) Program No. 6: Exemption and Reduction of Land & Water Rent

Submissions by the Petitioners

551. The petitioners submitted that the said program is administered by local tax authorities. The land in Vietnam is completely owned by the government. The final findings in welded pipes and tubes as well as Continuous Cast Copper Wire Rods are relied upon. Law on Land No. 3/2003/QH-II, Law on Land No. 45/2013/QH13, and Decree No. 46/2014/ND-CP grant subsidized land and water rates and subsequently reduction or exemption of the same. The benefit is available to enterprises (i) located in geographical areas/regions with difficult socio-economic conditions or (ii) engaged in investment projects in special cases or encouraged industries. The program provides a financial contribution in the form of revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is only available to companies engaged in projects or located in geographical area enlisted under the relevant laws.

552. The program was previously examined by the Authority in the Final Findings of anti-subsidy investigation on imports of “Continuous Cast Copper Wire Rods” from Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam and found countervailable.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

553. The Government of Vietnam submitted that it pursues a policy of exemption and reduction of land rent for companies who have investment projects in geographical regions or areas with specially difficult socio-economic conditions in order to encourage investment in such regions. It is also applicable to investment projects in special cases like construction of housing for poor workers etc. as well as in encouraged industries. Such encouraged geographical regions, encouraged industries and special cases are specified under Decree 46/2014/ND-CP. The program is not contingent upon export performance or domestic over imported goods.

554. Kim Tin uses leased land for which rent has been paid in full during the POI. The Company holds four possessions of land and rent for each was paid as determined by the Decision of the People's Committee of Binh Phuoc Province. Since Kim Tin uses a dry process for manufacturing the PUC, water usage is negligible. For other purposes, the water used is from ground water sources. On the other hand, the land used by MDF VRG is leased and the water is bought from Quang Tri Irrigation Engineering Management One Member Limited Company, which is an industrial water supplier and general service enterprise, and Dong Ha Clean Water Enterprise. There exist no schemes for exemption of water charges. MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Company submitted that the program is neither prohibited nor specific. No subsidy was availed by the responding producers for the same.

Examination by the Authority

555. The Authority notes that the program is governed by Law on Land No. 3/2003/QH-II, Decree 142/2005/ND-CP dated 14th November 2005, Law on Land No. 45/2013/QH13, and Decree No. 46/2014/ND-CP. Exemption or reduction is provided on land and rent to companies who have investment in and located in geographical regions or areas such as designated areas/zones which are as per Decree 46/2014/ND-CP.

- 556.The Authority sought further information on Land and water distribution mechanism by the GOV and the responding producers/exporters. whereby it was mentioned that....
- 557.MDF VRG has submitted that the company has land on lease and the details of some exemption on land rent payment is already provided in the EQR under the concerned program. The company has further stated that it has paid water rent for the POI and also for all other periods and there are no such schemes wherein the water charges are exempted. The contention on water rent has no basis. The payment details of water bills have been provided along with the EQR as a separate annexure.
- 558.Kim Tin has responded that it has land on lease and the company has paid full rent during the POI. Such payment details and also some exemption on land rent payment in the past which has no relevance in the present investigation is all already provided in the EQR under the concerned program no. 6. The land used by Km Tin MDF JSC is through 04 possessions and the land rent is different for each possession. Such rents are based on the Decision of the People's Committee of Binh Phuoc Province.
- 559.Kim Tin has the allegation of subsidy for water. The Company follows a dry process in the manufacture of the subject goods and the use of water in production of subject goods is NIL or negligible. Even the water used for general purposes in the premise are from own ground water sources and the same does not come under any exemption program of the Government.
- 560.Questionnaire response filed by M/s. MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Co. shows that the company has been availing reduction on land rent under this subsidy program. However, no such exemption was claimed on water rent. M/s Kim Tin MDF Joint Stock Co. has stated in their Questionnaire Response that their water consumption is negligible/nil in the POI and that no reduction/exemption in land rent was availed in the POI. However, the records submitted by the company shows that concessional land rents were paid by them.
- 561.Private ownership of land is not permitted in Vietnam and the people hold all ownership rights with the State as the administrator. However, the laws of Vietnam allow ownership of a right to use land. This right is called the Land Use Right (“LUR”). Land and water surface rent exemptions and reductions apply to a number of investment projects which satisfy certain conditions such as investment in encouraged sectors or certain fields of business and/or encouraged geographical locations.
- 562.Since market is distorted as regards to land price, therefore the Authority is not in a position to accept the land prices prevailing in the country.
- 563.The Authority has, therefore, analyzed comparable market-based prices in another country at a comparable level of economic development within the geographic vicinity of Vietnam.
- 564.The program provides financial contribution in the form of provision of goods or services at less than adequate remuneration. The program is also specific because it is region specific. The Authority, therefore, holds this program as countervailable and also notes that countervailing duty should be imposed against responding producers/exporters under this subsidy program.
- 565.The Authority has quantified the subsidy margin based on the information submitted by the responding producers/exporters. The subsidy margin determined has been provided in the table below.
- (vii) Program No. 8: Investment Credit by Vietnam Development Bank**
- Submissions by the Petitioners**
- 566.The petitioners submitted that the said program is administered by Vietnam Development Bank (VDB). Article 5 of Decree No. 75/2011/NĐ-CP together with Circulars by the Ministry of Finance provide credit for investment at a preferential rate to investors having a project on the list of projects entitled to the loan, having implemented the investment procedure, having 20% owner's equity and sufficient capital to implement the project. The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is only available to enterprises meeting the eligibility criteria as per the relevant laws.
- 567.The responding exporters have also received loans from banks within the country at preferential rates. The Authority should take cognizance of the availment of the subsidized loans and quantify the same. Even though the interest-rate for short term loan is universally lower, the exporters need to provide evidence that those paid by the

exporters are in accordance with benchmark prescribed as per central bank or World Bank or IMF and that there is no element of discretion or preferential treatment.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

568.The Government of Vietnam submitted that Article 5 of Decree 75/2011/NĐ-CP authorizes the Vietnam Development Bank to provide investment credit to investors having investment projects on the list of eligible projects in Appendix I of the Decree. The Decree was replaced by Decree 32/2017/NĐ-CP on 15 May 2017.

569.No benefit under the program was availed by the responding producers/exporters. The interest rates paid by the responding producers/exporters for long-term loan is on par with the prevailing interest rate in Vietnam as per World Bank data. The interest rates for short-term loans are universally lower and no subsidy can be presumed. Additionally, there is no compensatory arrangement on interests.

Examination by the Authority

570.The Authority notes that the program is administered by the Vietnam Development Bank (VDB) which is a state policy bank established by Decision 108/2006/QĐ-TTg dated 19 May 2006. It was established to execute the state development investment and export credit policies as regulated by the Government. The organizational and operational regulations of VDB are in accordance with the Decision No. 1515/QĐ-TTg dated September 3rd, 2015 by the Prime Minister. Financial mechanism of VDB is executed in accordance with the Decision No.44/2007/QĐ-TTg dated March 30th. The Vietnam Development Bank is recognized as legal entity. The operation of VDB is for not profit oriented purposes. VDB and other state-owned banks in Vietnam are a public body because it is owned and controlled by the Government of Vietnam and exercises Governmental authority.

571.Under this program, credit is provided for investment at a preferential rate provided the investment project is one that is enlisted to be entitled for the loan. The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds and a benefit is thereby conferred. The benefit is equivalent to the difference in interest charged by the VDB against that charged by an ordinary commercial bank for the same project. The program is also specific as it is only available to those companies investing in projects enlisted under the relevant law. Therefore, the Authority holds this program as countervailable.

572.The responding producers/exporters merely stated in their Questionnaire Responses that they have not availed any investment credit from the VDB. The records submitted by the responding producers/exporters show that no loans were received by them from VDB.

573.However, the Authority notes that the responding producers/exporters have received loans at concessional interest rates from the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (“VietinBank”). The Authority notes that the VietinBank was established on 26th March 1988 after its separation from the State Bank of Vietnam in accordance with Decree No. 53/HDBT by the Ministers Council. Vietinbank is majority owned by the State Bank of Vietnam. The Authority notes that the state-owned banks are vested with authority to exercise governmental functions is based on formal indicia of government control and evidence showing that it has been exercised in a meaningful way, hence it is a public body. Hence, the Authority notes that countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this program.

574.According to the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules,1995, in case of subsidized loans the amount of benefit is the difference between the amount that the firm receiving the loan pays on the VietinBank loan and the amount the firm would pay on a comparable commercial loan which the firm could actually obtain from the market. The amount of loan and the interest actually paid by the responding producers/exporters is taken from the records provided by them along with their questionnaire responses. The lending interest rate in Vietnam for the POI as provided by the World Bank has been taken as the appropriate benchmark interest rate for a commercial loan. The subsidy margin thereby calculated is in the table below.

(viii) Program No. 9: Export Credit by Vietnam Development Bank

Submissions by the Petitioners

575.The petitioners submitted that the said program is administered by Vietnam Development Bank (VDB). Decree No. 32/2017/NĐ-CP together with Circulars by the Ministry of Finance provide credit at a preferential rate to exporters and foreign importers who have contracted to trade in any goods enlisted in the list of items eligible for

the same. The program provides a financial contribution in the form of direct transfer of funds and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is contingent on exports.

576. The responding exporters have also received loans from banks within the country at preferential rates. The Authority should take cognizance of the availment of the subsidized loans and quantify the same.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

577. The Government of Vietnam submitted that Article 5 of Decree 75/2011/NĐ-CP authorizes the Vietnam Development Bank to provide export credit to eligible exporters. However, the Decree was replaced by Decree 32/2017/NĐ-CP on 15 May 2017 and the whole export credit program terminated. However, those contracts entered into before the termination is still valid.

Examination by the Authority

578. The Authority notes that the program is administered by the Ministry of finance had specified certain enterprises eligible for credit loans. Vietnam Development Bank provides loans for investment projects and contracts on export/import of Vietnamese goods which have an impact on the capital. A pre-requirement set-up by the bank is that the financial plans and repayment plans shall be appraised by them beforehand. The Authority has already determined that VDB is a public body. It has also been determined that countervailing duty should be imposed against credit provided by VDB. Therefore, Authority holds that no additional countervailing duty is required to be imposed against this program.

579. The responding producers/exporters merely stated in their Questionnaire Responses that they have not availed any export credit from the VDB. The records submitted by the responding producers/exporters show that no loans were availed by them from the VDB.

580. Loans availed from the VietinBank have already been held as countervailable and quantified under Program No. 8 as explained above.

Other programs

(ix) Program No. 10: Provision of Standing Timber for Less Than Adequate Remuneration

Submissions by the Petitioners

581. The petitioners submitted that the said program is administered by the State Forest Department and General Department of Tax under the Ministry of Finance. The Government of Vietnam owns nearly all of Vietnam's harvestable forests and they are leased to companies for logging on which a severance rate is levied. The Law on Royalties No. 45/2009/GH12 together with Resolution No. 928/2010/UBTVQH12, Decree No. 50/2010/NĐ-CP and Circular Nos. 105/2010/TT-BTC and 32/2009/TT-BTC provides for stumpage charges lower than the market benchmark for stumpages. The intervention of the government in the forestry sector through regulation distorts the domestic market for timber allowing the producers of the subject goods in Vietnam to purchase raw materials, i.e., wood at prices lower than international prices. The program provides a financial contribution in the form of provision of goods for less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is primarily beneficial to enterprises that use wood as a raw material. As per the information on the website of the responding producers/exporters of Vietnam, they use eucalyptus as their raw material. The price of its procurement should be compared with an international benchmark for the same wood type.

582. The Trade Policy Review, which the domestic industry had submitted, is prepared by the WTO Secretariate based on the report submitted by the Government of Vietnam. Hence, it has high evidentiary value.

583. Article 14(d) of the ASCM allows the use of out-of-country benchmarks. In case of market distortion due to government measures, the use of domestic price as benchmark is inappropriate. New Zealand is an appropriate benchmark for log/timber/wood provided at LTAR due to its high level of economic freedom, prudent and transparent financial regulations, low subsidies and private property rights. New Zealand is also the largest exporter of roundwood in 2019 while India was the 8th largest importer in the same year. However, the benchmark is too conservative and there exists other alternative benchmark which may be more appropriate.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

584. Trade Policy Review of Vietnam to the WTO cannot be the legal basis for determining subsidy since it is merely a hearsay evidence. The evidence provided by the petitioners also does not have any reference to local procurement. M/s. MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Co. purchases its main raw material, i.e., wood from the local market from unrelated suppliers. The producers in Vietnam do not use timber as their input.

585.Kim Tin procured their raw material (wood) from private local suppliers. MDF VRG procured raw material (wood) from local individual households at a suitable price based on prevailing conditions. No subsidy was availed by the responding producers/exporters for the same.

586.The use of benchmark price based on New Zealand is objected to since no reasons have been provided for choosing the same. It contains all sorts of wood and logs, and rubber wood is not included in any of the categories included. Moreover, the Government of New Zealand controls all of the harvested forest. The export price of wood from New Zealand to India are not determined as per market forces. New Zealand wood prices cannot be compared to rubber wood at all. The benchmark should be as per the prevailing market conditions in the country of provision. The WTO decision in US – Coated Paper (Indonesia) is relied on. As found in the Appellate Body Report in US – Softwood Lumber IV, out of country benchmark can only be adopted when the price of the resource is distorted in the subject country due to Government's predominant role in providing such goods.

(x) Program No. 11: Government Prohibition of Log Exports

Submissions by the Petitioners

587.The petitioners submitted that the said program is administered by the Ministry of Industry and Trade. Circular No. 88/2011/TT-BNNPTNT listed agricultural, fisheries, and forestry products to be subject to export prohibition. The Government of Vietnam also imposes export taxes on rubber and wood. Imposition of export restraints distorts the domestic market for logs and makes them available to downstream industries at less than adequate remuneration. The program, hence, provides a financial contribution in the form of provision of goods for less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is primarily beneficial to enterprises that use timber as a raw material.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

588.No submissions were made by the Government of Vietnam/other interested parties with regard to this program.

Examination by the Authority

589.The Authority notes that program no. 10 & 11 relates to the series of the measure taken by Government of Vietnam to regulate, monitor and control forestry sector in Vietnam. Since effect of these programs results in wood being provided at less than adequate remuneration, it is considered appropriate to combine these programs and examine them collectively for the purpose of present investigations.

590.The petitioners submitted that the program no. 10 is administered by the State Forest Department and General Department of Tax under the Ministry of Finance. Vietnam's harvestable forests are primarily owned by the Government of Vietnam through Forest Management Boards and State Forest Companies. According to Law on Royalties No. 45/2009/GH12, enterprises are allowed to exploit the natural resources on these state forests and a tax is collected on the output. The rate of tax collected is prescribed under the statute. The responding cooperative producers/exporters have disclosed in their Questionnaire Response that they use firewood as their raw material. The tax collected on firewood is 1-5% of the output. The Authority notes that the tax collected by the relevant Ministry is discretionary and with disregard for market principles. The tax collected is far less than the market rates of the wood.

591.The petitioners submitted that the program no. 11 is administered by the Ministry of Industry and Trade. Circular No. 88/2011/TT-BNNPTNT listed agricultural, fisheries, and forestry products to be subject to export prohibition. Through the imposition of export restraints, the Government of Vietnam entrusted/directed domestic forestry/harvesting companies to provide low priced inputs (logs/wood) to companies in the downstream industries. The measures at issue achieved the desired effect to distort the domestic market of wood/timber/log in the subject country and to depress the price to an artificially low level to the advantage of the downstream industry

592.The Authority notes as per the information submitted and as also available on websites of responding producers/exporters that they use eucalyptus (firewood) as their raw material for production of the PUC.

593.Hence, wood, which is the primary raw material in the fiberboard industry, is made available for procurement to the companies under investigation at rates below the market rate. The program provides a financial contribution in the form of provision of goods for less than adequate remuneration and a benefit is thereby conferred. The program is also specific since it benefits those downstream industries that use logs/wood as their primary raw

material. Hence, the program is *de facto* available only to a limited number of industries. Therefore, the Authority notes that countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under this subsidy program.

594. To determine the quantum of the subsidy margin, the Authority looked for the appropriate benchmark whereby it was found that New Zealand is one of the largest exporters of logs globally. The Authority considered exports of logs from New Zealand to India as an appropriate benchmark being representative as compared to import price from New Zealand to the subject countries. The actual procurement rate of wood has been considered as per the exporters questionnaire response. Considering the appropriate conversion rates, the subsidy margins for Program no. 10 and 11 have been determined and provided in the table below.

(xi) Program No. 12: Land Preferences for Enterprises in Encouraged Industries or Industrial Zones under Decree 142

Submissions by the Petitioners

595. The petitioners submitted that the said program is administered by the People's Committee of the Government of Vietnam. The land in Vietnam is completely owned by the government. The final findings in welded pipes and tubes as well as Continuous Cast Copper Wire Rods are relied on. Decree No. 142/2005/NĐ-CP provides for rents on land leased from the People's Committee of Can Tho at rates below the market rates. The program provides a financial contribution in the revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is available only to enterprises located in the specific geographic area.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

596. No submissions were made by the Government of Vietnam/other interested parties with regard to this program.

Examination by the Authority

597. The Authority notes that the program is governed by Decree 142/2005/NĐ-CP. Exemption or reduction is provided on land rent to companies who have investment in identified regions and investment projects for encouraged industries as specified under the Decree 142/2005 and succeeding Decree 46/2014.

598. The program provides financial contribution in the form of provision of goods or services at less than adequate remuneration. The program is also specific because it is region specific and is limited to certain encouraged sectors. Therefore, the Authority holds this program as countervailable. However, the subsidy is subsumed in Program 6 that has already been quantified by the Authority.

(xii) Program No. 13: Government Provision of Land for Less Than Adequate Remuneration and Exemptions or Reductions from Land and Water Rents

Submissions by the Petitioners

599. The petitioners submitted that the said program is administered by the State Government of Dong Nai and its civic authorities. The land in Vietnam is completely owned by the government. The final findings in welded pipes and tubes as well as Continuous Cast Copper Wire Rods are relied on. Decree No. 46/2014/NĐ-CP, Decree No. 123/2017/NĐ-CP, and Law No. 45/2013/QH13 provides for exemption or reduction in land and rents. The land and water rents are exempted when it is used for construction of houses for workers in industrial zones which are approved by competent authorities. The exemption is for 3 years for domains entitled to investment incentives and for 11 years for domains entitled to special investment incentives. A 50% reduction on land rent is provided to cooperatives that use the premises for business and production activities. The land and water rent for land and water surface leased for agriculture, forestry, aquaculture or salt making is reduced by a corresponding rate when 40% of the yield is damaged by a disaster or conflagration. The program provides a financial contribution in the revenue forgone that is otherwise due and a benefit is thereby conferred. The program is also specific as it is available only to enterprises that meet the eligibility criteria prescribed.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

600. No submissions were made by the Government of Vietnam/other interested parties with regard to this program.

Examination by the Authority

601. The Authority has already held that countervailing duty should be imposed against provision of land at less than adequate remuneration. Therefore, Authority further notes that no additional countervailing duty is required to be imposed against the responding exporters/producers under this program.

602. Hence, the subsidy margins for the responding producers/exporters have been quantified in the table below.

Program No. 14: Electricity at Less Than Adequate Remuneration

Submissions by the Petitioners

603. The petitioners submitted that the electricity is provided in Vietnam at less than adequate remuneration.

Submissions by Government of Vietnam/other interested parties

604. Power was procured by both Kim Tin and MDF VRG from private suppliers in the area at price fixed by them.

No subsidy was availed by the responding producers for the same. The Government of Vietnam has not made any submissions on the allegation of electricity at less than adequate remuneration.

Examination by the Authority

605. During the course of investigation, the Authority has come across the Electricity provided at LTAR, as per the allegation submitted by applicants in their submissions. The Authority sought requisite information in form of additional questionnaire from the interested parties. The Government of Vietnam has not provided any submissions in this regard. The responding exporters have, in their questionnaire response, have submitted that they have procured electricity at market price.

606. The Authority notes that the electricity sector in Vietnam is regulated by the Electricity Law which is amended and revised from time to time. The Electricity Regulatory Authority of Vietnam (ERAV) was established in 2005 which, among other responsibilities, advise on electricity tariffs in the country. The law prescribes an Average Retail Tariff (ART) based on which the power tariff is levied. Though the ART has been revised several times in the past, the Authority finds that the same has not been proportionate with the fluctuations in costs and inflation. As per a report published by the World Bank in March 2020, the ART in 2019 was around 8 US cents/kWh while the same should have been 12 US cents/kWh to recover the costs fully.

607. Further, the generation, transmission and distribution of electricity in Vietnam is almost entirely controlled by the state-owned corporate group, Electricity Vietnam (EVN) along with its affiliated companies. EVN is not listed on a stock exchange and does not have the liberty to issue new equity. As per the Annual Report 2018 of EVN, the company is "*entrusted (by the government) with the mission of ensuring sufficient electricity for national socio-economic growth.... and serves the Government as an important macro regulatory tool for national economic development*". The sub-optimal returns earned by these companies due to government regulation of electricity tariffs are partly compensated by state support for EVN in the form of tax incentives, guarantees, loans with favourable terms from state-owned banks, and subsidies for strategic projects. The Authority notes that the state-owned enterprise, EVN is vested with authority to exercise governmental functions is based on formal indicia of government control and evidence showing that it has been exercised in a meaningful way, hence it is a public body. Hence, the Authority finds that the electricity sector in Vietnam is distorted and not based on market principles which enables the producers of the PUC to procure electricity at less than adequate remuneration. Hence, the Authority holds that countervailing duty should be imposed against the responding producers/exporters under this program.

608. To determine the quantum of the subsidy margin, the Authority looked for the appropriate benchmark. The Authority relied upon the prices provided as per the website of 'globalpetrolprices'. The actual electricity tariffs paid by the responding producers as per the additional questionnaire response has been considered to determine the subsidy margins. Considering the methodology above, the subsidy margin determined for the responding exporters has been provided in the table below.

Kim Tin MDF Joint Stock Co

609. Kim Tin MDF Joint Stock Co. is a producer/exporter of subject goods in Vietnam. Kim Tin filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

610. Authority examined the response filed by Kim Tin and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. Kim Tin has disclosed in their questionnaire response that it has availed reduction on corporate income tax. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in reduction in land rent, loans received by Vietnam Development Bank, and provision for wood and electricity at LTAR were availed by Kim Tin. As a result, benefit was conferred to Kim Tin in the form of various subsidies.

611. Authority has verified the information provided by Kim Tin and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

612. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 4	Reduction of Corporate income tax	***%	0-10
2	Program No 6, 12 & 13	Exemption and Reduction of Land and Water Rent	***%	0-10
3	Program No 8	Investment Credit by Vietnam Development Banks	***%	0-10
4	Program No 10 & 11	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
5	Program No 14	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Co.

613. MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Co. is a producer/exporter of subject goods in Vietnam. MDF VRG filed the questionnaire response and provided information regarding the subsidy programs availed by them.

614. Authority examined the response filed by MDF VRG and upon examination requested further information from them and also verified the information provided in the response to the extent deemed necessary. MDF VRG has disclosed in their questionnaire response that it has availed reduction on land rent. Additionally, the Authority determined that the subsidy programs resulting in reduction in corporate income tax, loans received by Vietnam Development Bank, and provision for wood and electricity at LTAR were availed by MDF VRG. As a result, benefit was conferred to MDF VRG in the form of various subsidies.

615. Authority has verified the information provided by MDF VRG and determined subsidy margin for programs for which benefit was received or accrued during the POI. Wherever the relevant information was not provided by the exporter, Authority has relied on facts available to determine the subsidy margin.

616. The table below provides name of the subsidy programs, and the corresponding subsidy margin.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 3	Exemption of Import of Spare Parts	***%	0-10
2	Program No 4	Reduction of Corporate income tax	***%	0-10
3	Program No 6, 12 & 13	Exemption and Reduction of Land and Water Rent	***%	0-10
4	Program No 8	Investment Credit by Vietnam Development Bank	***%	0-10
5	Program No 10 & 11	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
6	Program No 14	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	-	-
		Total Subsidy	***%	10-20

617. Countervailing duty for all other producers/exporters from Vietnam has been determined based on the highest of the subsidy margins for the cooperating party, for the subsidies availed by them and based on facts available for other subsidy programs.

SN	Program No.	Name of the Schemes	Subsidy Margin %	Range %
1	Program No 3	Exemption of Import of Spare Parts	***%	0-10
2	Program No 4	Reduction of Cooperate income tax	***%	0-10
3	Program No 6, 12 & 13	Exemption and Reduction of Land and Water Rent	***%	0-10
4	Program No 8	Investment Credit by Vietnam Development Bank	***%	0-10
5	Program No 10 & 11	Provision for Raw Material (Wood) at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
6	Program No 14	Provision for Electricity at Less Than Adequate Remuneration	***%	0-10
		Total Subsidy	***%	10-20

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the Domestic Industry

618. The submissions made by domestic industry are as follows:

- a) The Designated Authority is requested to cumulatively assess the effect of such imports as (a) the amount of subsidization in relation to the imports from each country is more than one per cent ad valorem; (b) the volume of imports from each country is not negligible and (c) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.
- b) Cumulative assessment appropriately includes Thailand and Indonesia due to its share and volume in imports, similar trends in imports, similar grades of PUC, interchangeability of the products, comparability of sales channel, and competition between them and the other subject countries.
- c) Demand for the subject goods has increased throughout the injury period in India.
- d) Imports from the subject countries have increased over the injury period in absolute terms. Imports from subject countries have also increased in relation to production and consumption. Imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
- e) Comparison of cost of production, selling price of the domestic industry and landed price of imports shows that landed price of subject imports is significantly below the cost of production and selling price of the domestic industry in the proposed POI. Further, whereas the costs of the domestic industry increased during the POI, the Domestic Industry was forced to reduce the selling price. The imports are supressing and depressing the prices of the Domestic Industry.
- f) The capacities with the Domestic Industry have increased considering the present and potential Demand for the product in the Country. The production of the Domestic Industry improved with the increase in capacities.
- g) The capacity utilization of the domestic industry declined significantly during the period under investigation. The capacity utilization has declined further thereafter due to COVID situation.
- h) With regard to Greenpanel not achieving optimum production due to capacity addition, the Company achieved higher capacity utilisation than average utilisation achieved.

- i) The sales of the Domestic Industry declined in 2016-17, thereafter improved in 2017-18 and the POI with the increase in capacities. The Capacity utilization rates remained low. The DI could have sold more considering the capacity addition and high demand but could not do so because of the subsidised imports. The decline in capacity utilization is due to inability to sell higher volumes due to subsidised imports.
- j) The market share of the Domestic Industry improved marginally with the increase in capacities and production.
- k) The per unit profits have more than halved during the injury period. This is due to the decline in selling prices caused by the price undercutting by subject imports. The profitability improved in 2016-17 and 2017-18, thereafter declined severely in the POI.
- l) The PBIT, Cash Profits and Return on Investment all declined severely over the injury period. Even if level of depreciation before POI is considered, cash profits of the domestic industry still decline.
- m) The productivity per day, employment numbers and wages all improved with the increase in capacities. The inventories with the Domestic Industry truly reflect the condition of the market, whereby despite a roaring demand for the subject goods, the stocks with the Domestic Industry have increased by more than 4 times over the injury period.
- n) The negative growth in all price parameters during the POI showcases that the Domestic Industry is suffering injury.
- o) Annexure III of AD Rules should not be applied in CVD investigations for determination of non-injurious.
- p) Imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the volume of imports has increased significantly. Since imports are occurring at low prices, the domestic industry had to reduce its prices in order to sell increased volumes. The price pressures being felt by the domestic industry is because of subsidized imports. Price undercutting caused by the subsidized imports is preventing the domestic industry from increasing its prices.
- q) The price suppression and depression effect of subsidized imports from subject countries has resulted in significant erosion in profitability of the domestic industry. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of subsidized imports. The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of economic parameters. Injury to the domestic industry is due to subsidized imports in the country. Imposition of anti-subsidy duties is imperative.
- r) The Domestic Industry cannot afford to bear any further setbacks in the form of its performance with regard to the product under consideration.
- s) With regard to the argument that NIP is inflated due to the high cost of production in Greenpanel AP plant and Century compared to others, given the age of the plant, other plant costs are not representative.
- t) With regard to the argument that the NIP for all Indian producers should be similar if they are all affected by imports does not have legal or factual basis.
- u) With regard to the argument that cost of sales should be normated for injury analysis, the same does not have any legal basis.
- v) The subsidised imports need not be the only reason for injury. The fact that there are other reasons does not affect the causal link. While the Annual Report of the Petitioners focus only on the POI, the Authority focusses on the entire injury period. Moreover, the Annual Report is concerned about the overall performance of the Company while the DA is only concerned about its domestic operations.
- w) If only internal competition impacted the DI, then its market share should not have declined. The Annual Reports say MDF is replacing plywood and not the other way around.
- x) Increase in debt owed is not in the nature of “other factors” causing injury.
- y) The claim that the injury is due to internal deficiency is unsubstantiated.
- z) ADD and CVD are meant to address unfair practices. The PUC for the previous investigations were different.

- aa) Though there is a parallel SSR investigation on the PUC, the injury suffered by the DI is due to low priced imports which is a result of dumping and/or subsidies. The DI has not sought relief beyond the injury margin and there is no bar on simultaneous investigations. Reliance is placed on CESTAT order in Suncity Sheets Pvt. Ltd v. UoI.
- bb) The injury to the domestic industry has to be seen as it is and not in ideal conditions. The CESTAT order in M/s Nipol Zeon Co. Ltd., Japan v. Designated Authority is referred and relied on.

H.2. Submissions by other interested parties

619. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:

- a) Applicants are misusing and enjoying protection since 2009, which shows that the injury is due to the internal deficiencies and not on account of the imports. Import volume has declined and import prices have increased. At the same time, DI's cost increased, price and profitability declined. This shows cost increase is due to capacity expansion.
- b) Capacity additions, prudent level of capacity utilisation, and increase in production and sales show absence of volume effect and injury. Slight decline in price and profitability cannot be linked to subject imports.
- c) The CVD Rules does not require the Designated Authority to conduct the injury analysis from the base year to POI.
- d) The petitioners have attempted to mislead the Authority by comparing prices of all products to the import prices without considering PCN. The petitioners have not suffered any price suppression or depression.
- e) Economic indicators in the NCV shows productive capacity increased by 174% in POI, which increased production by 61% in the same period. Sales improved by 49% in the POI. The Petitioners hired 181% more employees compared to base year. Productivity per day continued improvement and peaked at 171 index points in the POI.
- f) Though profitability dropped by 59%, it is not caused by the imports from Indonesia. On the other hand, it was due to increase in costs (depreciation and amortisation expenses and interest/ finance cost which raised significantly in POI due to capacity additions). Profitability of the Domestic Industry has increased despite the alleged increase in price undercutting during 2016-17 and 2017-18. Decline in profitability during the POI occurred mainly due to the higher finance costs and depreciation expenses.
- g) Domestic Demand has increased by 35 indexed points and Indian producers have been able to capture the market and increased their sales by 44 indexed points.
- h) Petitioners are misleading Authority on price undercutting and price suppression/depression by comparing selling price by total import price without consideration to differences in prices of PCNs.
- i) Slight dip in price and profitability parameters cannot be linked to the imports from the subject countries. It is because of significant capacity additions and unhealthy price competition among the domestic producers.
- j) The DI made significant capacity additions over the years and the POI. The decline in capacity utilisation in the POI should be considered along with significant increase in capacity. Production and sales (both domestic and exports) have increased including through the POI.
- k) The capacity additions have caused additional costs to the DI, and impacted the ROCE. The costs also increased because of increase in interest costs and wages as a result of declining productivity.
- l) Finance cost increased by 80 indexed points in 2 financial years, Depreciation and Amortization expenses increased by 114 indexed points during the same period. Cash profits increased substantially throughout the injury period, except POI, due to the finance and depreciation expenses.
- m) An inverse relationship exists between the selling price of the DI and the import price. Imports from the subject countries declined (by 11%) and prices increased (by 4%) during the POI compared to the previous year. The import price does not have any suppressing effects on the DI. Market share of imports from subject countries

has declined in the POI compared to the previous year by 6% which has benefitted the DI.

- n) Volume of imports from Thailand has declined relative to increase in demand for subject goods in India. The import price of subject goods from Thailand has increased from 24,206 Rs/MT during 2017-18 to 26,274 Rs/MT during the POI. In comparison, the cost of DI has only increased by 5 indexed points. Therefore, there is no price undercutting. Thailand intends to increase price over Cost of DI, but low selling price of DI and prices from other import sources have impacted possible price increase.
- o) Import price of Indonesia is 23-25% lower than Thailand. Moreover, the new entrants have a low domestic sales price. Thailand imports have declined because it finds the Indian market unviable due to low prices in the market.
- p) The AB Report in *US-Lamb* described “serious injury” as a “very high standard of injury”. The AB Report in *US-Wheat Gluten* ruled that serious injury means an overall impairment in the position of the DI and all factors relevant to the overall situation of the DI should be included in the authority’s determination.
- q) Injury if any, is from other sources such as Malaysia and Vietnam, whereby the imports have increased significantly.
- r) The benefits received by Panel Plus MDF & Panel Plus Company, Vanachai Panel & Vanachai Group are insignificant and could not have caused injury.
- s) Cumulative Assessment cannot be undertaken as under Annexure I of the CVD Rules. Thailand is the only country with declining imports in the POI and increasing price. Imports from Indonesia have declined significantly in both absolute and relative terms. Cumulation of injury is not appropriate.
- t) Merbok MDF Lanka Pvt Ltd. is only one known exporter of the PUC into India from Sri Lanka and the Company has been operating at a loss in recent years. Production volumes have been decreasing during the injury period.
- u) Annexure – III calculation of NIP, should be applied.
- v) Share of imports of Sri Lanka is merely 3.97% of total imports, as per Rule 16(d) of the Rules, no developing country having share under 4% of the total imports can be considered for imposition of duties. Investigation has not been initiated against Brazil with 3.23% despite lower prices.
- w) Authority is requested to normate cost of sales not only for NIP, but also for injury analysis as cost is inflated due to capacity additions.
- x) Authority is requested to evaluate project report of second plant at Green Panel and its projections given to the financial lenders.
- y) The Petition filed by domestic Industry shows various factors that indicate breach of the causal link:
 - i. Imports declined and import prices increased during the POI while volume parameters for the DI improved.
 - ii. Imports did not have an adverse effect on the price of the DI. There is an inverse relationship between the selling price of the DI and the import price. The price of the DI was impacted by internal price competition.
 - iii. Increase in costs was caused by increase in capacity. Capacity additions also caused increase in interest cost and wages.
 - iv. Fall in profitability is due to fall in productivity.
 - v. Injury to the DI is due to internal competition and competition from plywood which is a substitute for the PUC. Extracts from the 2018-19 Annuals Report of Century Plywood show competition from the unorganised sector, the organised sector, and at last, foreign competition.
 - vi. Issues with regard to raw material availability which affects profitability. A down time in the Indian real estate industry etc also impacted domestic producers.

- vii. Authority requested to segregate injury to the domestic industry due to intrinsic factors such as introduction of new production capacity, intense competition by new market players and other factors highlighted in the annual reports.
 - viii. Rushil operated at optimum levels in the POI and suffered losses in the laminates business, as per the financial reports.
 - ix. As per Annual Report of Century MDF was the biggest driver of business. Company had a low level of production, but revenue increased 161%. Capacity was increased and production started in the second half of the POI. Not expected to reach optimum level of production.
 - x. Annual Reports of the Applicant producers is an integral document for the investigation. It is stated that the Indian producers are suffering injury on account of shortage of raw material, competition between Indian producers and other factors.
 - xi. Greenpanel Rudrapur plant and Rushil have well established production without exceptional start-up costs whereas cost of production of Greenpanel AP plant and Century is disproportionately high. Such increased costs have inflated NIP for these two plants. Had the imports adversely impacted the Indian producer, the NIP of all the Indian producers should have been similar for all the domestic producers.
 - xii. Expectations of dealers/distributors for further price cuts resulted in increase in inventories with the DI. The same cannot be attributed to the imports.
 - xiii. Authority is requested to analyze the impact of substitutable products, which has a direct impact on the sales and sale prices of the subject goods.
 - xiv. In a parallel sunset review investigation on subject goods (with a slight variation), the domestic industry has claimed to have suffered the injury on account of dumped imports from China, Malaysia, Thailand, and Sri Lanka.
- z) The Applicants have included Sri Lanka as a subject country to prove non-existent injury. The cumulation of injury is in violation of anti-subsidy rules. The requirement of adequacy and accuracy as per the anti-subsidy rules have not been complied with. Share of Sri Lankan imports is below de minimis and hence ineligible. The Authority has not initiated the investigation against Brazil (since it accounts for only 3.23% imports) despite lower prices than some of the subject countries.
- aa) There is a significant decline in Indonesian imports in absolute as well as relative terms. Cumulation of injury is not appropriate.
 - bb) The cost of sales should be normated since the actual cost is inflated due to capacity additions. The capacity expansion has distorted the entire picture. The same is to be analyzed. The project report of the second plant of Green Panel is to be analyzed.
 - cc) Imports from the subject countries declined in POI compared to the previous year and import prices increased in the same period. Alleged subsidized imports were not in a position to impact the DI. The slight dip in profits and profitability cannot be linked to the imports. The DI has been able to increase their volume parameters and hence, the market share.
 - dd) The DI has not suffered any injury as seen from volume and price parameters. Some temporary adversities have been projected due to huge capacity additions which does not warrant CVD measures.
 - ee) There is no volume injury to the DI due to imports from Thailand since the volume of imports from Thailand has declined relative to increase in demand in India, and improvement in production, capacity utilization, and market share of the Applicants. Volume of imports from Thailand has not increased in absolute or relative terms.
 - ff) There is no price injury to the DI due to imports from Thailand. The export price for Thailand has increased and there is no price undercutting due to the same. The Thai exporters were prevented from increasing prices due to low prices of Indian producers and imports from other sources. There is negative price suppression and depression.

- gg) Thailand is the only source among the subject countries from which the volume of imports has declined relative to total imports, production, sales as well as market share. The import price from Indonesia is significantly lower than that of Thailand and hence, they set the market price.
- hh) The DI has claimed an inflated NIP. The cost of production for Century Plyboard and Greenpanel AP plant is disproportionately and exceptionally high. The same is due to commencement/addition of production capacity during the POI and not due to imports. They should be rationalized in line with the NIP of other producers.
- ii) Petitioner's argument that NIP should not be calculated as per the AD Rules is flawed since a fair process for determining NIP should exist, the CVD rules require that the CVD must not exceed amount adequate to remove the injury to the DI, and past practice of the Authority shows application of the AD rules.
- jj) In case the Applicants have used logs for timber in manufacturing subject goods, then the same is the reason for injury since timber is much more expensive than residue.
- kk) The Annual Reports of the Applicants show that (i) significant capacity additions resulted in aggravated price cuts, (ii) they also impacted industry volumes badly since dealers were anticipating price cuts, (iii) they triggered lower realization and significant margin pressure in MDF segment, (iv) the margin pressure is short term, and (v) plywood is a substitute of MDF.
- ll) As per the Annual Reports, the Indian producers are suffering injury on account of shortage of RM, competition between Indian producers, and other intrinsic factors.
- mm) Greenpanel set up new production capacity in Andhra Pradesh to cater to export market. The injury to Greenpanel due to higher cost of production at Andhra Pradesh should not be attributed to the domestic operations or alleged imports.
- nn) Capacity utilization declined due to significant capacity addition. Market takes time to absorb capacity additions. Hence, the injury is due to the capacity additions.
- oo) The reduction in selling price is due to severe competition among the domestic producers and down time in Indian real estate industry.
- pp) The companies also face challenges in RM availability. The expectation of price reduction by dealers/distributors led to price cut which resulted in increase in inventories.
- qq) Finance cost and depreciation cost increased due to increase in capacity.
- rr) The addition of capacities has impacted profitability and ROCE.
- ss) The cost increase is driven by increase in interest cost, increase in wage factor as a result of poor productivity.

H.3. Examination by the Authority

620. The submissions made by the interested parties have been analysed to examine the injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject country.
621. As regards the issues of analysis of the injury parameters, it is noted that the same are addressed in the subsequent paragraphs while making injury analysis.
622. As regards the issue of capacity expansion, it is noted that the Domestic Industry has increased its capacity to cater the increased demand in the country.
623. As regards the submission that alleged injury to the Domestic Industry is due to other reasons and there is no injury as per statements in annual reports of the constituents of the Domestic Industry, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory to establish that the subsidized imports from subject countries has caused injury to the Domestic Industry.
624. Rule 13 of the Subsidy Rules deals with the principles governing the determination of injury which provides as follows:

“13. Determination of injury.-

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the causal link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if—

- (i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and
- (ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.”

I. Cumulative Assessment

625. Annexure-I para (4) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-subsidy investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- (a) the amount of subsidization established in relation to the imports from each country is more than one per cent ad valorem and the volume of imports from each country is not negligible and
- (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

626. It is noted that:

- a. The amount of subsidy established in relation to the imports from each country is more than one per cent and
- b. the volume of imports from each subject country is above *de-minimis* and
- c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.

627. In view of the above, it is considered appropriate to cumulatively assess the effects of subsidized imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.

II. Volume Effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

i. Assessment of Demand

628. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of all Indian producers and imports from all other countries. It is seen that demand has increased over the injury period. The demand so assessed is as follows—

Demand in India	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Sales of Domestic Industry	CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	119	149
Sales of Other Indian Producers	CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	104	119
Imports from- Subject Country	CBM	1,79,805	2,19,031	3,44,199	2,95,472

Indonesia	CBM	47,051	37,905	35,953	36,343
Malaysia	CBM	23,869	46,049	53,447	73,707
Sri Lanka	CBM	23,263	17,247	20,590	13,854
Thailand	CBM	38,764	27,208	70,922	48,352
Vietnam	CBM	46,859	90,622	1,63,287	1,23,216
Imports from other countries	CBM	40,015	38,584	40,055	35,855
Total Demand in India	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	107	132	140

ii. Imports volumes and share of the imports from subject country.

629. With regard to volume of the subject imports, it is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Summarized position for the same is as below:

Import Volume	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Imports from- Subject Country	CBM	1,79,805	2,19,031	3,44,199	2,95,472
Indonesia	CBM	47,051	37,905	35,953	36,343
Malaysia	CBM	23,869	46,049	53,447	73,707
Sri Lanka	CBM	23,263	17,247	20,590	13,854
Thailand	CBM	38,764	27,208	70,922	48,352
Vietnam	CBM	46,859	90,622	1,63,287	1,23,216
Imports from other countries	CBM	40,015	38,584	40,055	35,855
Total Import Volume	CBM	2,19,820	2,57,615	3,84,254	3,31,327
Subject Country Imports in relation to					
Imports	%	81.80	85.02	89.58	89.18
Production	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	115	164	114
Consumption	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	114	145	118

630. The Authority notes that the total volume of subject imports from the subject country has increased till 2017-18 and has marginally declined thereafter during period of investigation. However, the volume of imports from subject countries have increased as compared to 2015-16 and 2016-17. The imports from the subject countries in relation to production and consumption has also increased as compared to the base year.

III. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

631. With regard to the effect of subsidized imports on prices, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

i. Price Undercutting

632. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the

domestic industry during the injury period. The price undercutting has been determined for the POI separately for each PCN produced by the domestic industry and thereafter for the product under consideration as a whole. Summarized position for the same is given in the table below:

Particular	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Net sales realization	Rs/CBM	***	***	***	***
Subject Country as a whole					
Landed price of imports	Rs/CBM	17,061	14,415	13,828	14,294
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	25-35	45-55	55-65	35-45
Indonesia					
Landed price of imports	Rs/CBM	17,824	15,584	14,734	14,821
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-30	35-45	50-60	30-40
Malaysia					
Landed price of imports	Rs/CBM	17,076	14,654	15,680	15,907
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	25-35	45-55	40-50	25-35
Sri Lanka					
Landed price of imports	Rs/CBM	19,498	18,005	17,511	17,803
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	15-25	25-35	10-20
Thailand					
Landed price of imports	Rs/CBM	15,805	14,001	12,911	12,982
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	35-45	50-60	70-80	50-60
Vietnam					
Landed price of imports	Rs/CBM	16,117	13,246	12,955	13,292
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	35-45	50-60	70-80	50-60

633. It is noted that the landed prices of the subject goods from each of the subject countries were below the selling price of the domestic industry showing price undercutting being caused by the subsidized products from the subject countries during the injury period including the POI.

ii. Price suppression and depression

634. In order to determine whether the subsidized imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the changes in the costs and prices over the injury period has been considered. The position for the same is shown in the table below.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Cost of Sales	Rs/CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	100	107
Selling Price	Rs/CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	102	93
Net Sales Realisation	Rs/CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	101	91
Landed Price from subject countries	Rs/CBM	17,061	14,415	13,828	14,294
Trend	Indexed	100	84	81	84

635. Comparison of cost of production, selling price of the domestic industry and landed price of imports shows that landed price of subject imports is below the cost of production and selling price of the domestic industry in the POI. Further, whereas the costs of the domestic industry increased during the POI, however, instead of raising the selling prices in proportion with the increase the costs, the Domestic Industry was forced to reduce the selling price due to high volume of imports in the country at lower prices. The imports are suppressing and depressing the prices of the Domestic Industry.

iii. Price Underselling/ Injury Margin

636. The non-injurious prices of the subject goods have been worked out and the same has been compared with the landed value of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. The price underselling/ injury margin has been determined separately for each PCN and thereafter for the product under consideration as a whole.

637. It is noted from the table below that the price underselling/ injury margin is positive, indicating that the imports have entered the market at injurious prices.

638. The injury margin for cooperative producers/exporters and others are evaluated as under:

Country	Particulars	Non-Injurious Price (NIP)	Landed Price	Injury Margin		
				US\$/CBM	US\$/CBM	%
Thailand	Vanachai Group Public Company Ltd. and Vanachai Panel Industries Co. Ltd.	***	***	***	***	50-60
	Panel Plus Co. Ltd. and Panel Plus MDF Co. Ltd	***	***	***	***	25-35
	Metro MDF Co., Ltd. and	***	***	***	***	25-35

	Advance Fiber Co., Ltd.					
	Agro Fiber Co.,Ltd.	***	***	***	***	1-10
	Green Fiber Co., Ltd	***	***	***	***	Negative
	Wisewoods Co. Ltd	***	***	***	***	25-35
	Any Other	***	***	***	***	55-65
Malaysia	Segamat Panel Boards Sdn. Bhd	***	***	***	***	30-40
	Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd	***	***	***	***	35-45
	Any Other	***	***	***	***	40-50
Vietnam	MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Company	***	***	***	***	15-25
	Kim Tin MDF Joint Stock Company	***	***	***	***	40-50
	Any Other	***	***	***	***	40-50
Indonesia	PT. Sumatera Prima Fibreboard	***	***	***	***	20-30
	PT. Mukti Panel Industri	***	***	***	***	35-45
	Any Other	***	***	***	***	40-50
Sri Lanka	Any Other	***	***	***	***	15-25

IV. Economic parameters relating to the domestic industry

639. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

i. Production, capacity, capacity utilization and sales

640. The position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization, domestic sales and export is as under:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Installed Capacity	CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	137	273

Production Quantity	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	108	128	167
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	108	94	61
Domestic Sales	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	100	119	149

641. It is noted from the table above that:

- a. The domestic industry has enhanced its capacity in 2017-18 and in the POI. The domestic industry submitted that the capacities were increased having regard to present and potential demand for the product in the country.
- b. The production and sales of the Domestic Industry has also increased with the increase in its capacities.
- c. The capacity utilization of the domestic industry increased in 2016-17 but declined in 2017-18 and further during period of investigation.

ii. Market Share

642. The market share of the domestic industry and imports over the injury period is as under:

	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	94	90	107
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	98	79	85
Imports from- Subject Countries	%	***	***	***	***
Other Countries	%	***	***	***	***
Total Demand	<i>Indexed</i>	100	100	100	100

643. It can be seen that the market share of the domestic industry improved marginally with the increase in its capacity and production.

iii. Profit or loss, cash profits and return on capital employed

644. The profit position of the domestic industry in terms of profit or loss, cash profits and return on investment is as under:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Cost of Sales	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	96	100	107
Selling price	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	98	102	93
Profit before tax	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	109	107	39
Profit before Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	100	108	127	58

Profit before interest and Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	122	71
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	138	86
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	66	24

645. It is seen from the table above that:

- a. The profit of the domestic industry improved in 2016-17, then declined marginally in 2017-18 and thereafter declined in the POI.
- b. The PBIT and Cash Profits of the domestic industry increased till 2017-18 and declined during period of investigation.
- c. The Return on investment followed the same trend as profits. The domestic industry's return on capital employed has gone down to ***% in 2018-19 from ***% in 2015-16. Therefore, there has been a decline in return on capital employed over the injury period and the POI.

iv. Inventories

646. The data relating to inventories of the subject goods is as follows-

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Inventory – Average	CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	151	344	448

647. It is noted from the table above that the average inventories with the domestic industry has increased by more than 4 times over the injury period despite increase in demand for the subject goods.

v. Employment, wages and productivity

648. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity during the injury period is provided in the table as under:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	202	281
Productivity per day	CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	119	146
Productivity per Employee	CBM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	64	60
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	146	244

649. It is noted that the employment, wages and productivity of the Domestic industry have improved over the injury period.

vi. Ability to raise capital investment

650. It is seen that the domestic industry has enhanced capacity for the subject goods over the period, making capital investment. However, despite increase in demand, the capacities are lying underutilized which is an impact of subject imports. This has impacted the ability of the applicants to raise its capital.

Conclusions on Injury

651. The Authority notes that the imports have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and have had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry. The price underselling/injury margin of each of the responding producers from subject countries is also positive. The capacity utilization of the domestic industry has declined. It is seen that the domestic industry is suffering from underutilized capacities, despite increase in demand. Further, the profits, cash profits, PBIT and return on capital employed of the domestic industry has declined significantly over the injury period. Inventories with the domestic industry has increase significantly over the injury period. Accordingly, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury

V. Causal Link

652. It has been examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry and the same is as follows:

a. Volume and prices of imports from third countries

653. The imports from other countries are either insignificant in volume or at higher prices.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

654. It is noted that there is no contraction of demand. On the contrary, overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period. Further, there have been no changes in the pattern of consumption which could have caused injury to the domestic industry.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

655. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d. Developments in technology

656. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate any change in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance of the domestic industry

657. The injury information has been considered separately for domestic and exports, to the extent the same could be segregated.

f. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

658. The Authority has considered data only in relation to the product under consideration.

VI. Factors relevant for causal link

659. It is noted that: -

- a. The imports of subject goods in the country are at low prices than the domestic industry prices.
- b. Subsidized imports from subject countries are coming into India in substantial volumes.
- c. The imports are undercutting the prices of the domestic industry,
- d. The price suppression and depression effect of subsidized imports from subject countries has resulted in deterioration in profitability of the domestic industry.
- e. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are a result of subsidized imports.

Conclusion on Causal Link

660. It is noted as under:

- a. Subsidized imports from the subject countries have been imported into India in substantial volumes during the POI
- b. Imports have undercut the prices of the domestic industry during the injury period.

c. Performance of the domestic industry has deteriorated during POI in terms of capacity utilization, profits, cash profits and ROI. Inventories with the domestic industry has increased significantly.

661. The Authority therefore holds that there is a causal link between the subsidization of the subject goods and the injury suffered by the domestic industry.

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

662. The disclosure statement was issued by the Authority on 21.04.2021 disclosing essential facts of the case and inviting comments thereon from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under.

Submissions by Domestic Industry

663. The following submissions have been made by domestic industry:

- i. None of the Sri Lankan producers/ exporters has filled the questionnaire response. Therefore, the subsidy margins should be re-fixed at the levels of previous disclosure
- ii. The subsidy margin for FSC Vietnam Corporation has not been determined in the Disclosure Statement.
- iii. S. Kijchai Enterprise has disregarded the instructions by the Authority and filed a non-confidential response just by stating “refer to confidential version”. The questionnaire responses filed by Advance and Metro are excessively confidential without proper reasoning. A non-confidential version of the Importer Questionnaire Response by Thamarapally was never served onto the domestic industry. The response of S Kijchai’s, Wisewoods Co. Ltd and Thamarappally was rejected in the recent anti-dumping duty findings against imports of MDF below 6mm as well because of excessive confidentiality. Responding producers/exporters had availed certain programs and the same was suppressed by them in their EQR’s.
- iv. The Authority is requested to consider the alternatives proposed by the Domestic Industry other than the prices of export of logs from New Zealand to India.
- v. Only Thamarapally has filed a response and they also showed no commitment with the investigation post filing of their response. Further, no user has participated in the investigation. The lack of opposition from users in India show that they do not consider significant adverse impact on them as a result of the present investigation. Further, it is in the consumers’ interest to have a competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to fair priced imports.
- vi. Consideration of actual cost of production instead of NIP is appropriate in a CVD case, considering that the issue under consideration is a countervailable benefit being extended by the exporting countries.
- vii. The imposition of anti-subsidy measure on imports of product under consideration would be in the interests of domestic manufacturers. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive domestic production.. The subject goods manufacturing industry is a labour-intensive, capital intensive and provides large-scale employment. The eventual impact of duty on the cost of the eventual end products will be insignificant.
- viii. Due to widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to rely more on the domestic production capacities. Further, being agro-based, the product has significant potential to increase farmers’ income.
- ix. The Authority is requested to quantify Program Nos. 4, 6, 8, 9, and 10 for Indonesia, Program Nos. 1-6, 8, 10, 11, 16, 17, and 18 for Malaysia, Program Nos. 1, 3, 4, and 5 for Sri Lanka, Program Nos. 2, 3, 8, 10, 11, and 12b for Thailand, and Program Nos. 1 and 2 for Vietnam.
- x. The Authority is requested to hold Program 3 for Indonesia as countervailable.
- xi. The duty for group companies should be cumulated.
- xii. The domestic industry has suffered injury due to the subsidized imports from the subject countries

Submissions by other Interested parties

664. The following submissions have been made by other interested parties

- i. Program No. 1 and 2 programs are not countervailable within SCM Agreement as the DGTR failed to be established in both disclosure statements that these two programs entailed any financial contribution or did it confer any benefit to Indonesian producers of PUI. The GOI's policies through these two programs are very general nature as the GOI applies its function as the government. The GOI never determines to whom the private seller should sell their rubber woods, let alone to determine the price. The GOI applies no sanction for any failure to conclude a transaction if it is commercially not feasible; it is possible that no transaction can be concluded. The provision of goods at LTAR SCM Agreement requires the existence of a government entrusted body that is mandated or directed to provide the production material at LTAR, which cannot be established by the DGTR.
- ii. The second Disclosure Statements even made no single evaluation of factors related to the very fact that there is a difference between (1) logs and woods, (2) logs and leftover woods; (3) log and leftover rubber woods.
- iii. As there exists significant availability of rubber words from private parties, the DGTR should rely only on their price and cannot therefore use New Zealand as alternative of benchmarking. Therefore, the DGTR cannot draw the conclusion that such prices are a consequence of subsidy or benefit given by the GOI.
- iv. In Program No. 3 and 4, the GOI agrees with the DGTR that no countervailing duty should be imposed against the responding exporters/producers under these two programs.
- v. In Program No. 5 the master list program is available across sectors. It is not limited by region therefore is not specific and not countervailable.
- vi. In Program No. 6,7,8,9 and 10 the GOI fully agrees with the DGTR's conclusion that none of the responding producers/exporters have availed benefit under these five programs.
- vii. Program no. 11a the Indonesian producers of PUI acquired their land from the private parties and it has nothing to do with the GOI. Further, the benchmark of Factory prices in Tangerang is not appropriate as it is very far from the location of the companies under investigation which is in Sumatra Island. The cooperating producers did not procure the factory land from GOI nor does it belong to the GOI.
- viii. In Program No. 11b the GOI submits that Indonesian producers of the PUI do not use coal in their production process. PLN is carrying out public service to whole Indonesian Industry and society. It does not serve specific industry.
- ix. The Authority well recognises that responding producers/exporters of Indonesia do not use coal in their production process. However, coal is available to PLN at a rate below the market rates. The program is specific since the benefit of coal at cheaper rates is available to the only power supplier in Indonesia which ultimately makes it possible for PLN to provide electricity to consumers at a subsidized rate.
- x. Subsidy calculation method must be carried out transparently and adequately described by DGTR and here should be only one subsidy rate for each program.
- xi. An objective examination of relevant economic parameters shows that India's domestic industry is not suffering material injury during the injury period.
- xii. Countervailing measure should not be imposed unless it is determined that there are subsidized imports, injury to a domestic industry, and a causal link between the subsidized imports and the injury that shall be supported with evidences.
- xiii. The manner in which the new programs are included without following any due process is a serious violation of fair procedural aspects.
- xiv. Program No. 20, 21 and 22 were not initially listed in the petition and Notice of Initiation. . Insertion of additional programmes without undergoing the rightful clarification process with GOM and the Malaysian Domestic Industry are afterthoughts..
- xv. DGTR totally disregarded GOM responses and resorted to the Petitioner's skewed allegations and misleading evidences.
- xvi. GOM's response also indicate that DGTR had pre-judged the outcome of the case, regardless of the responses and cooperation provided by interested parties.

- xvii. The Petition lacks adequate and accurate evidence and does not meet legal requirements as stipulated under the WTO ASCM.
- xviii. Injury suffered by Petitioners may be self-inflicted and has no linkage to imports of PUC from Malaysia.
- xix. There are no any other subsidy schemes specific to the sector concerned hence there is no valid reason for GOM to provide response under other subsidy schemes.
- xx. The Rubber Replanting Subsidy Act No. 36 of 1953 is established for the purpose of developing the local rubber industry and this law had been introduced long time before the establishment of the fiber board industry in Sri Lanka. Therefore, GOSL denies the fact that the fiberboard industry currently in operation has benefitted from the alleged rubber planting subsidy.
- xxi. Licensing procedure of exporting rubber logs has been established in Sri Lanka according to the Imports and Exports Control Act No. 01 of 1969 and operated by the controller of import and exports of the GOSL. The said laws were not implemented with the objective of providing benefits to the fiberboard industry.
- xxii. One of the intentions of the GOSL by the legislation was to reduce deforestation in the country but not providing benefit to fiberboard industry.
- xxiii. Electricity is considered as a public utility in Sri Lanka and therefore it is considered as a responsibility of the government to ensure that every citizen of the country has access to electricity.
- xxiv. Provision of electricity by the government ceases to be specific because it is sufficiently and broadly available throughout the economy as not to benefit a particular limited group of producers of certain products.
- xxv. Authority has neither recorded nor evaluated the information that was provided by RTG in its questionnaire response. Authority has also violated the SCM Agreement by including “Other Subsidy – Loans” within the scope of the investigation as the Authority has neither initiated the investigation nor include the same in the new subsidy allegation questionnaire.
- xxvi. Authority has not provided the benchmark price adopted for determination / quantification of subsidy margin.
- xxvii. Programs No. 1-8 are not specific and therefore, do not qualify as subsidy in terms of the SCM Agreement.
- xxviii. In Program No. 1, 3 and 4, the criteria for granting are equally on a voluntary basis, not on a selective rationale and are open to all enterprises in an industry-wide coverage manner and not specific and hence is not countervailable.
- xxix. In Program No. 2 RTG strongly confirms that the benefit under Section 36 is in accordance with/ applicable under the SCM agreement. It is not countervailable as Section 36 operates like duty drawback.
- xxx. In Program No. 5, 9 and 12b the Authority proposed not to recommend levy of duty. The RTG requests the Authority to confirm the same in the final findings. The RTG also extends cooperation and undertakes to furnish information/data, as requested by the Authority.
- xxxi. Program Nos 6 and 7 are not specific. Companies apply for BOI investment promotion on a voluntary basis. The Authority proposed not to recommend levy of duty under these programs.
- xxxii. Program No. 8 does not cause any injury to Indian domestic market since the exemption of income tax on dividends derived from the promoted activity under Section 34 is benefited only to shareholders of the company and not to the company. The Authority proposed not to recommend levy of duty under this program.
- xxxiii. In Program No. 10 EXIM bank provides the export credit insurance to all sizes of business including micro enterprises, SMEs and large corporations registered in Thailand without any specific industry. The Authority proposed not to recommend levy of duty under this program.
- xxxiv. In Program No. 11 the Authority’s evaluation/understanding is completely erroneous as EXIM bank does not offer loans under this program. Instead, this program provides long-term credit insurance for exports, and EXIM bank has no Indian buyers. The Authority proposed to hold that this program is not countervailable. The RTG extends cooperation and undertakes to furnish information/data, as requested by the Authority.

- xxxv. In Program No. 12a for privately- owned forest areas, there is no obligation to pay stumpage /standing timber fee. There is no financial contribution by the RTG in form of wood/raw material for producing / exporting the PUC. Rubberwood, renewable rubberwood and eucalyptus wood are not prohibited wood.
- xxxvi. As the price and harvesting of wood in New Zealand is regulated by the Government, the export price of wood from New Zealand to India cannot construe as an appropriate benchmark.
- xxxvii. In Program No. 13 Provincial Electricity Authority and Electricity Generating Authority of Thailand is operating at profit and therefore, not supplying electricity below cost.
- xxxviii. Plyboard should be included within the scope of PUC as it is like product to fibreboard and the same is made up of wood fibers bonded with raisins and other organic substances.
- xxxix. Petitioners have not provided any intelligible information with respect to their production or market share and the Authority has also not disclosed their share in India's domestic production.
- xl. The Petitioners have claimed all information like demand, production quantity, sales quantity, etc. as confidential and provided only the indexed numbers.
- xli. Conversion of CBM into MT may not reflect the actual volume and prices of imports since CBM and MT do not have a linear relationship for conversion.
- xlii. Petitioners have not suffered any volume injury on account of exports from Thailand, or any price suppression or depression since the Petitioners have been able to move the domestic selling prices commensurate to the cost of sales.
- xliii. The Authority should determine Consolidated Margin for Agro Fiber Co. Ltd. and Green Fiber Co. Ltd.
- xliv. The Authority has either not considered various critical arguments and submissions raised by the respondents or the same has not been dealt with.
- xlv. There is inappropriateness in using the prices of logs/premium wood from New Zealand as benchmarking the appropriate prices of "rubber wood waste in Indonesia", submission regarding the Ministry of Commerce itself distinguishing Rubber wood and Timber wood in its document titled National Rubber Policy 2019, the nature of Program No. 1 being taxation proves that it is not a financial contribution.
- xlvi. The procurement of land by respondents from Farmers under Program No. 11 being non-applicable.
- xlvii. The Authority did not provide adequate opportunity to all the interested parties to effectively defend their rights and interests in accordance with India's WTO obligations, Indian CVD Rules, and the vital principles of natural justice.
- xlviii. The Authority has used benchmarking in multiple instances to compute subsidy margin for wood, land and electricity. However, none of the benchmarks used for computing the subsidy margins for the respondents have been provided .
- xlix. The Authority has stated in paragraphs 41 and 42 that it can add a new scheme not included in the initiation notification, at any stage of the investigation. It is submitted that the Authority is bound to follow due process of law after such new schemes are added in the investigation, which was not followed in the present investigation. Even after adding the new scheme, the Authority did not provide the interested parties including the exporters adequate opportunity to submit information, rebut the alleged subsidies under such schemes, and an opportunity of hearing to address the Authority on all such newly added issues.
1. Program No. 1 & 2 - The Authority has noted in paragraphs 70 and 71 of the Disclosure Statement that since the Respondents are using rubberwood waste/residue, taking the prices of rubberwood instead of the prices of rubberwood waste/residue would be misleading and lead to false calculations. Even after such agreement, the Authority took a contradictory stand by using timber prices prevailing in New Zealand. Despite such acknowledgement and subsequent use of the same, the ratio calculated by the Authority and the basis of such calculation have not been shared with the Respondents.
 - ii. The Disclosure Statement does not contain the required country-wise price underselling / injury margin analysis, which needs to be a part of the disclosure statement in accordance with the Rules as well as the consistent practice of the Authority.

- iii. The Authority proposes to determine a highly inflated and skewed subsidy duties for the respondents on the basis of certain illogical, illegal, and misconceived premise.
- iv. The approach of the Authority to combine Schemes 1 and 2 for the purpose of subsidy calculation is erroneous, illegal and the specific provisions of ASCM because schemes 1 and 2 are independent to each other and are distinct in operation and function. While Scheme No. 1 pertains to the allegation of the petitioner with respect to “provision for standing timber at LTAR”, Scheme No. 2 pertains to the government prohibition on log exports in Indonesia. Schemes 1 & 2 have been presented by the petitioner in the NCV version as separate schemes and the Respondents also responded to them separately. Thus, there was no occasion for the Authority to combine all the aforementioned schemes for the purpose of subsidy determination.
- lv. The Authority has erroneously concluded and determined the countervailability of the schemes 1 & 2 vis-à-vis the respondents.
- lv. Program no. 1 & 2 are not applicable on them as the said scheme is specific to timber users, and the Respondents do not use standing timber at all for producing the PUC, and procure the raw material, i.e., rubberwood waste/residue from private plantations.
- lvi. Further, the scheme does not provide any financial benefit by the GOI, but rather authorizes the government to collect tax or revenue in the form of “stumpage fees”. The “stumpage fees” payable to the Government of Indonesia are incidence of taxation by the GOI, and not a case of subsidy.
- lvii. As regards the export ban and other export restrictions on logs, by no stretch of imagination can an export ban / restriction be regarded as a subsidy. The WTO Panel has already clarified this in United States – Measures treating exports Restraints as Subsidies (WT/DS194/R), wherein the Panel concluded that an export restraint as defined in this dispute cannot constitute government-entrusted or government-directed provision of goods in the sense of subparagraph (iv) and hence does not constitute a financial contribution in the sense of Article 1.1(a) of the SCM Agreement.
- lviii. As regards the Program no. 5, the Authority despite noting that the program is specific to only those enterprises that meet the eligibility criteria prescribed by the Government, no such examination has been undertaken by the Authority to suggest that the Respondents meet such criteria and/or are eligible for such benefit.
- lix. As regards Program no. 11a, the Authority has proposed to impose Countervailing Duties on the basic premise that ‘factory land’ was provided to the respondents at LTAR. Such an allegation was never raised by the applicants at any stage of the investigation. Therefore, the inclusion of the present program and the proposal of Countervailing Duties therein is in direct violation to the principles of natural justice.
- lx. The Respondents have procured the land directly from private parties and not directly or indirectly from the Government. The evidence of the purchase of land from farmers has already been placed on record as a part of the earlier submissions made by the respondents. Therefore, the whole basis of the Authority for considering this scheme countervailable for the respondent is incorrect and no subsidy margin can be recommended for scheme no. 11a. Moreover, no reason has been provided in the disclosure statement as to how the program no. 11a is specific to an enterprise or industry or group of enterprises or industries. Therefore, the disclosure statement did not adhere to the criteria prescribed under Article 2 of the ASCM with respect to the countervailability of the present program.
- lxi. As regards the benchmarking the factory land price, it is submitted that the price of some arbitrarily chosen industrial land in Tangerang cannot be considered as an appropriate benchmark. In the recently concluded investigation of Flat Rolled Products of Stainless Steel (FPSS), the Authority has also not recommended any subsidy margin in the context of land procurement.
- lxii. The Authority has falsely held scheme no. 11b to be countervailable and suggested subsidy margin, which clearly shows that the Applicants have not availed any benefit of electricity at subsidized rates. There is no evidence or merit to that effect, and the Authority has also failed to substantiate its observation with any evidence.

- lxiii. The legal standards under Article 2 of ASCM have not been met, which requires that a program to be countervailed needs the findings of specificity “to an enterprise or industry or group of enterprises or industries”. In this regard, the conclusion of the Authority in para 141 stating that the program ensures that coal is available to only power supplier in Indonesia (PLN), there is no findings of specificity viz. “an enterprise or industry or group of enterprises or industries” as required under Article 2. In this regard, the WTO Panel in US- Upland cotton stated that some subsidies are broadly available and widely used throughout an economy and are therefore not subject to the Agreement's subsidy disciplines.
- lxiv. The Disclosure Statement relies upon an arbitrary source to benchmark prices to compute subsidy margin and relied upon the prices provided as per the website of ‘global petrol prices’. There is nothing in the disclosure statement to indicate that any step has been taken by the Authority to verify the authenticity and veracity of the information available on the said website.
- lxv. Authority examined that the coal is available to PLN at prices below the market rates, it is submitted that there is merely a ceiling on the price at which PLN shall procure coal, without receiving any financial benefit as such. There is no compulsion that coal has to be necessarily supplied at this price. PLN is free to procure coal from thousands of private suppliers /miners in the country. It needs to be appreciated that PLN is a huge buyer of coal and is in a position to get coal at better prices. Please also note that even the ceiling price fixed for the PT Bukit Asam is based on the formula of production cost plus margin which covers profit and risk of the mining company in the minimum amount of 15% and the maximum amount of 25% of total production cost. Therefore, coal is not made available to PLN at less than market value.
- lxvi. The applicant has not suffered any injury on account of the imports from Indonesia, and any injury suffered by the applicant is on account of factors other than the imports of the subject goods from the subject countries.
- lxvii. The injury information provided in the application corroborates with the Industry overview provided in the Rushil Decor Limited’s Annual Report for POI which clearly established that the imports from subject countries have not caused any injury to the applicant as the capacity utilization of the applicants declined due to significant capacity addition (Increased by 173% in the POI as compared to the base year) made by them during the POI. In other words, the that addition of capacity from 180000 CBM to 540000 CBM i.e., twice the existing capacity has resulted in lower utilization.
- lxviii. The excessive addition of capacity has also caused an increase in the inventories.
- lxix. Any decline in the net sales realization of the Domestic Industry is due to the internal competition and because of the excess supply in the market. The significant capacity additions by the Indian industry ultimately triggered to lower realizations and significant margin pressure in the MDF Segment. However, this phenomenon is of short term in nature and the situation will stabilize soon.
- lxx. The Authority has not provided any details with respect to the calculation methodology and calculations to arrive at subsidy margin. Metro Group vide email communication dated April 21, 2021 requested the DGTR to share such calculations. The DGTR has only provided the landed value figures and actual subsidy margin figures for Metro Group but did not provide information regarding benchmark figures for instance the exact wood product from New Zealand for Program 12 (a), source of the information along with a complete calculation sheet (excel) for calculating subsidy margin for Program 12 (a) and Program 13. The Hon’ble Supreme Court in Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority & Ors, has noted that the DGTR is required to disclose the details of the calculations computed on the basis of data submitted by the interested parties themselves and cannot claim confidentiality on such information. The principle applies even in cases where the DGTR has sought to rely on information from other public sources such as in this case, the information regarding benchmark prices and calculation of the subsidy margin.
- lxxi. Thai Program 12 (a) has been erroneously countervailed: To the extent the DGTR’s analysis regarding Program 12 (a) is the same as First Disclosure Statement, Metro Group reiterates its submissions in paragraphs 63 – 68 of its Comments on the First Disclosure Statement. DGTR has failed to take into consideration Metro Group’s submissions in its Comments on the First Disclosure Statement. Metro Group specifically submitted that DGTR’s observation in paragraph 466 of the Second Disclosure Statement (which is the same as paragraph 322 of the First Disclosure Statement) regarding royalty in Thailand not exceeding the limit of 40 Bhat per cubic meter set forth in the schedule to the National Reserve Forest Act,

1964 is incorrect because the National Reserve Forest Act, 1964 was amended in 2016 and the timber royalty rate is currently 400 Baht per cubic meter.

- lxxii. The DGTR offers no source for its statement that prices in New Zealand are free from government intervention. In any event, the DGTR offers no rationale as to why New Zealand prices of wood chips can be taken as benchmark for rubberwood and eucalyptus wood for Thailand. In particular, the DGTR offers no analysis of: (i) why New Zealand can be taken as an appropriate benchmark despite different levels of economic development of the two countries; (ii) what adjustments, if any, the DGTR undertook to adjust the price of wood chips for rubberwood.
- lxxiii. The Authority has failed to take into consideration the information provided by Metro Group in its additional questionnaire response filed on March 31, 2021 whereby the details of all its purchases of rubberwood and eucalyptus wood during the POI, including quantity purchased, value, and unit price and established that it does not procure rubberwood/eucalyptus wood from the government or any government-controlled authority and purchases them at market rates. The Authority also failed to acknowledge or disclose this essential fact as part of the Second Disclosure Statement in accordance with Rule 18 of the CVD Rules. The DGTR has simply made a conclusionary statement and declared Program 12 (a) as countervailable and has not even provided the calculation methodology based on which it calculated the subsidy margin.
- lxxiv. Thai Program 13 has been erroneously countervailed: Metro Group reiterates its submissions from its Comments on the First Disclosure Statement and that the DGTR has failed to disclose calculation methodology adopted to arrive at subsidy margin. The DGTR's analysis with respect to Program 13 is incorrect due to the following reasons:
- lxxv. DGTR has not provided any evidence or analysis with respect to Program 13 being a countervailable subsidy. For instance, the DGTR has incorrectly noted that benefit is specific because the benefit is enjoyed by those consumers that are provided a uniform tariff policy in the provincial service areas. This is incorrect. In fact, there is no uniform tariff and tariff depends on the type of entity, type of service, and time of use after taking into consideration peak charges, off-peak charges, demand charges, etc.
 - a) Provincial Electricity Authority ("PEA") is the sole supplier and distributor of power to all the users of electricity in key provinces in Thailand and no evidence on record shows that the tariff from the PEA is at subsidized rates.
 - b) The DGTR has not taken into consideration Metro Group's previous submissions including the information provided in the additional questionnaire response that Metro Group purchases electricity at arm's length prices and like the practice in several other countries including India, electricity tariffs in Thailand are regulated by statutory bodies or government authorities and tariffs are fixed at market rates.
 - c) The DGTR has also failed to disclose the benchmark price used to arrive at the conclusion that electricity is purchased at prices lower than market rates, or the methodology used to calculate the subsidy margin.
- lxxvi. The notice seeking information on the newly alleged subsidy programs was clearly a failed attempt to remedy the due process violations it had already committed with a predetermined conclusion.
- lxxvii. Metro Group pre-empted the DGTR's approach and highlighted in its response dated March 31, 2021 that the additional questionnaire was issued only to put a gloss of due process on an inherently flawed investigation and violation of principles of natural justice cannot be remedied through tokenism or a gloss of ostensibly following processes when a quasi-judicial authority is already predisposed. The pre-determined approach of the DGTR is further confirmed by the fact that the Second Disclosure Statement is largely a reiteration of the First Disclosure Statement (with certain limited incremental changes) and that the DGTR has not taken into consideration any of the information provided by Metro Group in its additional questionnaire response.
- lxxviii. The scope of the PUC does not include Hardboard.
- lxxix. Program No. 2 is a permissible tax exemption program in accordance with Annex I (i) of the SCM Agreement and paragraph (i) of Part-1 of Annexure III of the CVD Rules. Accordingly, Program No. 2 is not countervailable.
- lxxx. DGTR must disclose the total Indian production figures and percentage share of the Petitioners' production for interested parties to meaningfully comment on standing on the Petitioners.

- Ixxxii. DGTR failed to address Metro Group's submissions regarding injury assessment being conducted in the cubic meters (i.e., CBM) and on Domestic Industry not suffering injury on account of imports of PUC from Thailand.
- Ixxxiii. Robin used Rubber wood and that is not a notified forest produce. Company procured rubber wood as per the price determined by the market and no Government interference as envisaged in the ASCM was evident. Wood at less than fair value is an unsubstantiated observation, and request the Authority to reverse the margin under program 20.
- Ixxxiv. With regard to Kim Tin, Program No 6, 12 & 13 shows a substantial margin, which doesn't have basis of such calculation, it is only requested that the Authority may crosscheck the calculations. Program No 10 & 11 also did not bestow any benefits to the Company.
- Ixxxv. With regard to MDF VRG, Program No 10 & 11 did not bestow any benefit on the Company and the wood was purchased at market rates.
- Ixxxvi. With regard to Vanachai Group and Vanachai Panel, margins found under Program No 12a are not justified. The Companies purchased wood at market rates and no Government supplied the wood at less than fair value as envisaged in ASCM.
- Ixxxvii. The performance of the domestic industry has improved tremendously in the post POI period. Imports from subject countries declined in the POI over the previous year coupled with an increase in price which shows declining trend of imports with positive price increase.
- Ixxxviii. Significant capacity additions by the domestic industry, very prudent level of capacity utilization, increase in production, increase in sales shows absence of any volume effects and injury.
- Ixxxix. Slight decline in price and profitability parameters during the POI cannot be linked to price of imports from subject countries in any manner.
- xc. The petition shows various factors which evidence breach of causal link which is not considered in not addressed properly in the Disclosure.

Examination by the Authority

- 665. As regards the contention of the Domestic Industry that subsidy margins for Sri Lanka should be re-fixed at the levels of previous disclosure, the Authority notes that it has quantified the subsidy margins for all the subject countries including Sri Lanka following uniform principles.
- 666. As regards consideration of actual cost of production instead of NIP, the Authority considered it appropriate to follow the principles laid down in Anti-Dumping Rules at Annexure III, consistent with the methodology applied in previous anti-subsidy investigations.
- 667. As regards the contention that the Authority has either not considered various critical arguments and submissions raised by the respondents or has not dealt the same, the Authority notes that the present determination is based on due and appropriate consideration of various submissions made by the interested parties at various stages of the investigation at relevant paragraphs of this Final Finding. The Authority has been constrained to rely on facts available at a number of places in view of insufficient information from the interested parties.
- 668. As regards distinction between Rubber wood and Timber wood, the Authority notes that the responding exporters/producers from Indonesia have misconstrued the relevant text of the National Policy document. The word "timber" has been used for various kinds of wood, including rubber wood. Further, the responding exporters have projected, without establishing the same, as if entirety of their production is out of rubberwood waste/residue.
- 669. The Authority also notes that reports, national laws, policy documents of various countries suggest that rubberwood is considered as a part of timber and is being used in the downstream industries which also include fiberboard.
- 670. On the submission of responding exporters/producers from Indonesia regarding use of "rubberwood waste/residue from private plantations", the Authority notes that the exporter has not provided sufficient information in the form

of consumption record that entirety of its purchase is from private plantations and entirety of its production is from rubberwood waste/residue. In this regard, it is noted that even if the procurement were from private parties, the series of measures taken by GOI is such that they amount to directing / entrusting private parties to provide logs/ wood at less than adequate remuneration.

671. With regards to contention made by responding exporters/producers from Indonesia regarding procurement of land under Program No. 11, it is noted that the Authority has already recorded in the finding above that the benefit received on procurement of land for plantation under Program No. 11 is already subsumed in program no 1 & 2.
672. With regard to the claim of non-adherence to the principle of natural justice, the Authority notes that due process has been followed and all the interested parties were given ample opportunities at every stage of the investigation to submit the requisite information and defend their rights and interests. The Authority notes that two oral hearings were held and two disclosure statements issued by the Designated Authority in the present investigation. The exporters were issued even another questionnaire after issuance of first disclosure statement to provide additional relevant information and the same has been duly considered in the present determination. It is further noted that the information regarding addition of new schemes was available to interested parties from the stage of written submissions after the 1st oral hearing. However, none of the interested parties chose to respond to the allegation regarding availment of the said schemes. Interested parties got the opportunity to present their views on the same in the 2nd Oral hearing as well.
673. The Authority has relied upon the actual information of the responding producers/exporters to the extent necessary and disclosed the same in the disclosure statement.. The Authority has clearly specified all the relevant information and basis in the disclosure statement and the interested parties had enough opportunity to comment on the same.
674. The interested parties also contended that additional questionnaires should have been provided to submit responses on the new schemes. The Authority, in this regard, notes that the original questionnaire issued to the interested parties itself specifically contained a detailed annexure with respect to 'other subsidy schemes' and it was also instructed that even if some of the programs are not listed by the applicant but are existing in the subject country, the responding party should respond fully to the questions in respect of them.
675. The Authority notes in this regard that the interested parties had obligation to bring on record, on their own, relevant information with regard to these schemes/programs. It is not appropriate on the part of the interested parties to withhold relevant information themselves by not commenting on the submissions made by the domestic industry. and then allege non-adherence of due process.
676. Nonetheless, the authority provided further opportunity to respond to each program even if some of them were not listed by the applicant and sent additional questionnaire with relevant Annexure as per the requests of interested parties to provide requisite information.
677. With regard to the submission by responding exporters/producers from Indonesia that they are using rubberwood waste/residue, the Authority notes that it has taken due cognizance of this fact and found it appropriate in such cases to consider the estimated price of the logs on the basis of the ratio of the prices of the waste/residue to the prices of fresh logs. . This was then compared with the benchmark adopted by the Authority, whereby the Authority found element of subsidy and hence the appropriate subsidy margin has been quantified. Wherever the exporters have used chip as a raw material, the Authority has used benchmark price of chip to have fair comparison.
678. With regards to contention of non-disclosure of calculation methodology, it is noted that the Authority has duly taken into consideration the type and form of wood utilized by a particular producer/exporter. The Authority notes that provision of wood at LTAR provides a benefit equal to the difference between the actual & benchmark price , whereby the actual cost of wood species and the consumption factor is adopted as provided by the responding exporters in their questionnaire response to quantify the subsidy margin.
679. With regard to the issue raised in respect of the country wise price underselling/injury margin, it is noted that the same is already provided in the findings above.
680. With regard to the allegation that the Authority has proposed to determine a highly inflated and skewed subsidy duties for the respondents on the basis of certain illogical, illegal, and misconceived premise, the Authority notes

that the CVD margins are based on calculations and facts established during the investigations. The subsidy margins arrived at are in fact much lower than the claims made by the domestic industry.

681. With regard to submission of responding exporters/producers from Indonesia that export ban / restriction cannot be regarded as a subsidy, the Authority notes that the Appellate Body in United States – Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea stated that if government has a more active and affirmative role than mere intervention to create incentive or possibility of financial contribution, it can result in entrustment or direction and consequently grant of countervailable subsidy. It is thus seen that WTO Panel's view in US-Measures Treating Export Restraints as Subsidies is narrow, while Appellate Body view is more relevant and appropriate in the facts and circumstances of the present case.
682. As regards countervailability of price paid for factory land, it is noted that the exporter as well as government of Indonesia have not contended either countervailability or existence of benefit. The interested parties were already made aware of the subsidy in the form of concessional price for the land. It is only a variant of land utilised by the exporter. While responding to questionnaire, the exporters have not provided relevant information. The domestic industry had raised this concern in their post hearing written submissions. The exporters have not disclosed relevant information appropriately in regard to availment of this program at any stage despite having been given several opportunities. The Authority is thus constrained to record these findings on the basis of facts available.
683. With regard to the contention that coal is not made available to PLN at less than market value, it is noted that Govt. of Indonesia has admitted supplying coal to PLN. Further, consideration of the price with benchmark shows that a benefit has occurred.
684. With regard to contention of reliance upon an arbitrary source to benchmark prices to compute subsidy margin, the Authority notes that none of the interested parties (barring domestic industry) provided any evidence that could be used as benchmark for the purpose of the present investigations. The interested parties limited themselves to mere arguments on absence of countervailability or benefit. In the absence of any benchmark information from the interested parties, the Authority relied upon the most appropriate benchmark for relevant inputs based on facts available. The Authority notes that as per the GlobalPetrolPrices.com website, it publishes the most wide-ranging, reliable and up to date information on retail energy prices around the world including motor fuel prices and electricity prices. For Electricity prices, GlobalPetrolPrices.com tracks the national average in about 150 countries. It collects data from the price offers of electricity/ power supplying companies/ organization and produce a national average that takes into account the market shares of those companies/ organizations and the relative population of regions within the country.
685. With regard to contention of the responding exporters of Thailand that the current timber royalty rate is 400 Baht per cubic meter, the Authority notes that a typographical error had crept in and the same has now been corrected. However, this does not, in any way, alters the fact that the intervention of the government in the forestry sector through regulation and price ceiling distorts the domestic market for timber allowing the producers of the subject goods in Thailand to purchase raw materials, i.e., wood at prices lower than international prices which has been dealt with by the Authority in findings above. .
686. With regard to contention of the responding producer/exporter from Thailand that wood has been procured at market rates, the Authority notes that it has duly considered the actual data/information provided by the interested parties in their response to additional questionnaire for computation of subsidy margins. The Authority notes that various measures taken by the government have distorted the Thai domestic market for logs to the benefit of the downstream industries that use logs.. Hence, wood, which is the primary raw material in the fiberboard industry, is made available for procurement to the companies under investigation at rates below the market rate.
687. With regard to submission of responding exporters/producers from Thailand for electricity at LTAR, the Authority notes that there is contradiction in the submission made by the GOT and the responding exporters with regard to the supply of electricity at less than adequate remuneration. The Authority has based its examination as per facts presented by the interested parties. Furthermore, it is found that Provincial Electricity Authority ("PEA") is the sole supplier and distributor of power to all the users of electricity in key provinces in Thailand and the tariff determination process is inconsistent with market principles and distorts the domestic supply of electricity. The program provides a financial contribution in the form of electricity at less than adequate remuneration. .
688. With regards to the contention that Advance Fiber that utilised the benefit under Program No. 1., the Authority has duly rectified/corrected the same at relevant Para of these Findings.

689. With regard to the contention that substantial subsidy margins have been found for programs which were never availed by the companies, in particular, alleged benefits on inputs such as wood, land and electricity, it is noted that during the course of investigation, the Authority found that the inputs such as wood, land and electricity are being provided to the producers/exporters of the subject goods at less than adequate remuneration. Hence the same has been quantified by the Authority considering the appropriate benchmarks.

690. With respect to the contention of exporters/producers of Vietnam regarding land at less than adequate remuneration, the Authority notes that this program provides benefit equal to the difference between the market rate and the actual rate of land procured by the producer/exporters in Vietnam. To calculate the per-square-meter benefit, the Authority has compared the per-square-meter price to the benchmarks and multiplied the per-square meter benefits by the area of the factory land of particular exporter.

691. With regard to the contention that Vietnamese producers/exporters have purchased wood at market price, the Authority found that the measures adopted by the GOV achieved the desired effect to distort the domestic market of wood/timber/log and to depress the price to low level to the advantage of the downstream industry. Hence, wood, which is the primary raw material in the fiberboard industry, is made available for procurement to the companies under investigation at rates below the market rate.

692. With regard to the contention that producers/exporters of Thailand have purchased wood at market price, the Authority notes that wood, which is the primary raw material in the fiberboard industry, is made available for procurement to the companies under investigation at rates below the market rate.

693. With respect to the contention of the Government of Thailand regarding inclusion of "Other Subsidy – Loans" within the scope of the investigation, the Authority notes that it is entirely within its rights to incorporate any subsidy scheme discovered during the course of investigation.

694. As regards arguments on injury it is noted that the Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions. All parameters of injury need not show deterioration. While some parameter may show deterioration, some may show improvement. The Designated Authority has considered all injury parameters and thereafter concluded whether the domestic industry has suffered injury or not. The overall position of the domestic industry has been evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

Indian Industry's Interests and Other Issues

695. The Authority notes that anti-dumping duty has been recommended for the part of the product under consideration in the parallel anti-dumping investigation. Therefore, the Authority is required to ensure that (i) no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization in accordance with Section 9B(l)(a) of the Customs Tariff Act and Article VI:5 of GATT 1994 & (ii) the antidumping duty and countervailing duty put-together should not exceed the injury margin because India follows a lesser duty rule, which provides that anti-dumping duty and/or countervailing duty will be equal to the injury margin if such injury margin is lesser than dumping margin and/or subsidy margin.

696. Therefore, to ensure compliance with both the aforementioned requirements, the Authority noted in the final findings of anti-dumping duty investigations against the same product that "the amount of anti-dumping duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of anti-dumping duty and the countervailing duty payable, if any. If the anti-dumping duty is less than the countervailing duty payable, the differential amount would be in the negative and no anti-dumping duty shall be collected in such case".

697. Authority considered whether imposition of proposed CVD shall have adverse public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.

698. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

699. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

Conclusion and Recommendation

700. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:

- a) Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited, Century Plyboards (India) Ltd. and Rushil Decor Limited constitute domestic industry within the meaning of Rules 2(b) and satisfy the criteria of standing in terms of Rules 6(3) of the CVD Rules
- b) The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-subsidy Rules
- c) the Applicants have filed the present investigation for imposition of anti-subsidy duty on Fibreboard. The Applicants have never requested imposition of anti-subsidy duty on Plyboard and the information of the same is not on records. Therefore, the same is outside the scope of the present investigation.
- d) Considering the level of subsidies provided by the Government in subject countries, the subsidy margins of each of the subject countries is above de minimus and significant.
- e) The Domestic Industry has suffered material injury. The Authority notes that the imports have increased significantly in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and have had a suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry. The price underselling/injury margin of each of the responding producers from subject countries is also positive. The capacity utilization of the domestic industry has declined. It is seen that the domestic industry is suffering from underutilized capacities, despite increase in demand. Further, the profits, cash profits, PBIT and return on capital employed of the domestic industry has declined significantly over the injury period. Inventories with the domestic industry has increase significantly over the injury period
- f) The domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. The domestic industry has suffered injury due to subsidization of the subject goods.
- g) none of the users have provided any information on impact of CVD duty. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of CVD on the user industry with verifiable information.

701. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of subject countries and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal links in favour or against thereof. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

702. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of five (5) years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive countervailing duty of an amount equivalent to the difference between the quantum of countervailing duty calculated at the rate mentioned in column (7) of the said Table, and anti-dumping duty payable, if any, is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of the subject goods from the subject countries.

DUTY TABLE

S.No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount as a % of CIF Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	4411	Fibreboard*	Thailand	Any country including Thailand	M/s Vanachai Group Public Company Ltd. and M/s Vanachai Panel Industries Co. Ltd.	18.54
2	4411	Fibreboard*	Thailand	Any country including Thailand	M/s Panel Plus Co. Ltd. and M/s Panel Plus MDF Co. Ltd.	11.47
3	4411	Fibreboard*	Thailand	Any country including Thailand	M/s Metro MDF Co., Ltd. and M/s Advance Fiber Co., Ltd.	8.29
4	4411	Fibreboard*	Thailand	Any country including Thailand	M/s Agro Fiber Co., Ltd. and M/s Green Fiber Co., Ltd.	NIL
5	4411	Fibreboard*	Thailand	Any country including Thailand	M/s Wisewoods Co., Ltd.	13.90
6	4411	Fibreboard*	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than at serial number 1 to 5	27.52
7	4411	Fibreboard*	Any country other than Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia & Sri Lanka	Thailand	Any producer	27.52
8	4411	Fibreboard*	Malaysia	Any country including Malaysia	M/s Segamat Panel Boards SDN BHD	10.52
9	4411	Fibreboard*	Malaysia	Any country including Malaysia	M/s Robin Resources (Malaysia) SDN BHD	15.95
10	4411	Fibreboard*	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than at serial number 8 & 9	18.08
11	4411	Fibreboard*	Any country other than Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia & Sri Lanka	Malaysia	Any producer	18.08

12	4411	Fibreboard*	Vietnam	Any country including Vietnam	M/s MDF VRG Quang Tri Wood Joint Stock Company	14.46
13	4411	Fibreboard*	Vietnam	Any country including Vietnam	M/s Kim Tin MDF Joint Stock Company and M/s FSC Vietnam Corporation	12.36
14	4411	Fibreboard*	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer other than at serial number 12 & 13	19.13
15	4411	Fibreboard*	Any country other than Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia & Sri Lanka	Vietnam	Any producer	19.13
16	4411	Fibreboard*	Indonesia	Any country including Indonesia	M/s PT. Sumatera Prima Fibreboard	14.77
17	4411	Fibreboard*	Indonesia	Any country including Indonesia	M/s PT. Mukti Panel Industri	13.69
18	4411	Fibreboard*	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than at serial number 16 & 17	15.78
19	4411	Fibreboard*	Any country other than Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia & Sri Lanka	Indonesia	Any producer	15.78
20	4411	Fibreboard*	Sri Lanka	Any country including Sri Lanka	Any Producer	12.37
21	4411	Fibreboard*	Any country other than Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia & Sri Lanka	Sri Lanka	Any Producer	12.37

* The product under consideration accordingly is, “fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances”, Fibreboards is a type of engineered wood product that is made out of wood fibers. Types of fibreboard include medium-density fiberboard (MDF) and high-density fiberboard (HDF). Following are excluded from the scope of product under consideration

a) Flooring boards

b) Sunmica

- c) *Insulation board*
- d) *Coir boards*
- e) *Jute fibre board*
- f) *Moulded Door Skin*

J. FURTHER PROCEDURE

703. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. and Designated Authority